

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

# भारत का वैधानिक

एवं

## राष्ट्रीय विकास

(सन् १६०० से सन् १९१९ तक)

लेखक

गुरुमुख निहाल सिंह

एम० एम-सी० (इकॉनॉमिक्स) लन्दन, वार एन्ड गै  
अध्यक्ष, दिल्ली-प्रदेश विधान-सभा

अनुवादक

सुरेश शर्मा, एम० ए०



१९५२

आत्माराम एण्ड सन  
प्रकाशक तथा पुस्तक-विप्रेता  
काश्मीरी गेट  
दिल्ली ६

# आमुख

कितने ही वर्षों से मुझसे अपन 'Landmarks in Indian Constitutional and National Development' का हिंदी-संस्करण निकालने को कहा जा रहा था और हिंदी के देश की राष्ट्रभाषा एवं भारतीय प्रजातन्त्र की राजभाषा और साथ ही कुछ माध्यमिक शिक्षा मंडलों तथा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा और परीक्षा का माध्यम स्वीकार होने पर यह माँग और भी अधिक हो गई है। मुझे यह कहने हुए हर्ष है कि अब मेरे लिए श्री सुरेश शर्मा एम ए तथा श्री रामलाल पुरी के सहयोग से यह संस्करण निकालना संभव हो गया है। हिंदी-अनुवाद के लिए मैं श्री मुरेश शर्मा का कृतज्ञ हूँ और इसके प्रकाशन का दायित्व लेने के लिए मैं श्री आत्माराम एड सम के मंचालक श्री पुरी का आभारी हूँ।

×

×

×

×

१५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भारतीय इतिहास का यह युग, जो सन् १६०० में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना से आरम्भ हुआ था अब समाप्त हो गया है और एक नया युग आरम्भ हो गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य सम्पूर्ण ब्रिटिश युग (१६००-१९४७) के भारत के वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास का विवरण देना है। इस अध्ययन को दो खंडों में बाँटा गया है—(१) सन् १६०० से १९१९ तक और (२) सन् १९१९ से १९४७ तक। सन् १९५० के मध्य में प्रथम खंड के द्वितीय संस्करण के प्रकाशित होने के समय मैंने यह आशा की थी कि मैं १९५० के अन्त तक द्वितीय खंड को पूरा लिख लूँगा। किंतु मुझे इस बात का खेद है कि अन्य कार्यों के दायित्व के कारण उस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सन् १९५१ के अन्त में पहले, द्वितीय खंड को पूरा करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार, प्रस्तुत खंड में भारत में अंग्रेजी राज्य की कहानी, माष्ट कोर्ड सुधारों तक ही हो पाई है।

×

×

×

×

पहला खंड अंग्रेजी में पहली बार १९३३ में प्रकाशित हुआ था। उस समय से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीति-विज्ञान के अध्ययन में, भारत के वैधानिक इतिहास का अध्ययन एक अविभाज्य अंग हो गया है। अतः, वैधानिक इतिहास के अध्ययन के महत्त्व को सविस्तार समझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक समस्याओं का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में

अन्य दो पुस्तकें हैं—(१) Sapre: "Growth of the Indian Constitution and System of Administration", (२) C. L. Anand. "History of the Government of India", Part II इन पुस्तकों में भारतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न भागों का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है किंतु उनमें राष्ट्रीय जीवन की चर्चा नहीं की गई और उनको वैधानिक इतिहास की पुस्तक नहीं कहा जा सकता। सन् १९१८ की भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है और उसमें भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं के विकास का काफी अच्छा वर्णन किया गया है।

पिछली दशाब्दी में भारतीय वैधानिक इतिहास पर तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं—(१) Keith. "Constitutional History of India", (२) Punniyah: "Indian Constitutional History" और (३) Shri Ram Sharma. "Constitutional History of India" पिछली पुस्तक सबसे बाद का प्रकाशन है और उसका वर्णन प्रकाशन के समय तक का है। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलैंड ने भारतीय वैधानिक समस्या पर अपनी रिपोर्ट के पहले दो भागों में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। इनके शीर्षक हैं—"The Indian Problem, 1813-1933" और "Indian Politics, 1936-1942"

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बन्ध में कितनी ही पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। संभवतः इनमें सबसे पहली पुस्तक श्री सर बर्नार्ड लोवेन् की 'The History of the Indian Nationalist Movement.' यद्यपि उस पुस्तक का लेखक उस समय ऑक्सफोर्ड में भारतीय इतिहास का अध्यापक था किंतु उस पुस्तक में ऐतिहासिक वर्णन का अभाव है। डॉ. टोपा की "The Growth and Development of National Thought in India" नामक पुस्तक भी असन्तोषप्रद है। डॉ. टोपा ने आदि काल से १९१९ तक के विकास का विवरण देने का प्रयत्न किया है। किंतु यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। इसके अतिरिक्त उस पुस्तक में विशेषकर उसके अन्तिम भाग में यह ध्यान स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय विचार-धारा का इतिहास लिखा है अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन का। विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास पर पुस्तकें लिखी हैं—राजपतराय "Young India", अम्बिकाधरण मजूमदार "Indian National Evolution", श्रीमती एनी बीसेंट 'How India Wrought for Freedom', प्रधान "India's Struggle for Svaraj", एस एस कबीर "India's Fight for



Freedom' और डॉ पट्टाभि सीतारामय्या 'वाट्स का इतिहास'। राष्ट्रीय आन्दोलन को समनने में बहुत से राष्ट्रीय नेताओं और ब्रिटिश शासकों की आत्मकथाओं अथवा जीवनीया ने भी बहुत बड़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में ये पुस्तकें उल्लेखनीय हैं—सर मुर्रेन्द्रनाथ बनर्जी, 'A Nation in Making', महात्मा गांधी, 'आत्म कथा, जवाहरलाल नेहरू 'मेरी कहानी', मुनापचन्द्र बोस 'An Autobiography', और लार्ड लिटन, लार्ड रिपन, लार्ड कर्जन, लार्ड मिन्टो सर फ्रीरोज शाह मेहता लोकमान्य तिलक, देशबन्धु सौ आर दास, मि एन ए जिता, सर फ्रान्सेइस, मोगाना अब्दुलकलाम आजाद और महात्मा गांधी की जीवनीया। अन्तिम पुस्तक के संयुक्त लेखक हैं पोलक, ब्रेन्मफोर्ट और पेथिक लारें। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की माँग पर भी प्रकाश डालने वाली कई पुस्तकें हैं जिनमें निम्न लिखित विशेष महत्व की हैं—नुमान 'Muslim India', स्मिथ 'Modern Islam in India', अम्बेदकर 'Thoughts on Pakistan', राजेंद्रप्रसाद 'संश्लिष्ट भारत', अमोल मेहता और अच्युत पटवर्धन 'Communal Triangle in India', बेनोप्रसाद 'The Hindu Muslim Question', और अन्तरी, 'Pakistan, The Problem of India.'

तीन प्रकार के प्रकाशन और हैं जो भारत के वैधानिक इतिहासकार के लिए बड़े महत्व के हैं—(१) वार्षिक पर्यालोचन और सामयिक रिपोर्टें, (२) वनेटियों और कमीशनों की रिपोर्टें और (३) राजनीतिक लेखकों और विदेशी नाबियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें। पहले वर्ग में भारत की नैतिक और नौतिक प्रगति के सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्टों की गणना है। ये रिपोर्टें सन १९१८ से १९३५ तक 'India in..... (वर्ष की मूल्या)' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुईं। इसी श्रेणी में 'The Indian Annual Register' को भी गणना है जिसका कलकत्ता से एम. एम. मिश्र ने प्रकाशन किया। दूसरे वर्ग में निम्नलिखित प्रकाशनों की गणना है—भारतीय निष्प्रेम्भीकरण कमीशन की रिपोर्टें, विभिन्न लोक-सेवा आयोगों की रिपोर्टें, माष्ट फोर्ट रिपोर्टें, हृष्ट-कमेटी रिपोर्टें, मुहोमैन कमेटी रिपोर्टें, गोड मेड-यग्निदों की कार्यवाही; सन् १९३३ का मुद्रा-सम्बन्धी श्वेत-पत्र; सन् १९१९ और १९३५ के मुद्रा-विषयकों पर पार्लियामेंट की अनुष्ठान प्रवर समितियों की रिपोर्टें, साइमन कमीशन की रिपोर्टें और उनके विस्तृत परिशिष्ट; और १९१९ तथा १९३५ के मुद्राओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित की दृष्टि विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टें। तीसरे वर्ग में निम्न लिखित लेखकों की पुस्तकों की गणना है—हेनरी नेविन्सन, सर विलेम्पाइन गिरोट, सर हेनरी काटन;

सर विलियम वेडरबर्न, सर सिडनी लो और कमांडर केनवर्थ; फेनर ब्रॉकवे और निकॉलस बेवरले; एडवर्ड टामसन और जी टी गैरेट; शुस्टर और विण्ट, ब्रेल्सफोर्ड और फेण्डरेल मून, बार्टन और कोटमैन, रक्षत्रुक विलियम्स और एल एस एस ओ मॉली, क्यूमिम्स और उर्फे; हिवम और पार्किन; विफिय और रालिन्सन।

और बहुत सी पुस्तकें, रिपोर्टें, समाचार-पत्र आदि हैं, जिनको मैंने भारत के वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास की कहानी को पूरा करने में उपयोगी पाया है। उन सबका यहाँ उल्लेख करना सम्भव नहीं है। पुस्तक की पाद टिप्पणियों में मैंने यथा स्थान उनके प्रति कृतज्ञता स्वीकार की है।

×

×

×

×

अगले पृष्ठों में भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार का, देश में ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के विकास; भारत में राजनीतिक जीवन के आरम्भ और उसके उत्थान, देश के शासन में हाथ बटाने के लिए भारतीय माँग के आरम्भ और उसकी वृद्धि; राष्ट्रीय आन्दोलन और अपनी आकांक्षाओं एवं आदर्शों के लिए राष्ट्रीय सपन, मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म और उसके विकास, पाकिस्तान की माँग और देश के विभाजन, भीषण साम्प्रदायिक दंगे और सामूहिक निष्क्रमण; फूट डालकर राज्य करने की नीति, ब्रिटिश सरकार के दमन और सुधार; अहिंसात्मक असहयोग अथवा सत्याग्रह की पद्धति के विकास और सफल प्रयोग, शान्ति के साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपलब्धि, और ब्रिटेन के साथ मित्रता और कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनाये रखने का, काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस वर्णन के सिलसिले में तथ्यों की तह में जाने का और उद्देश्यों तथा मनोवृत्तियों के विश्लेषण का प्रयत्न किया गया है और विभिन्न कारणों अथवा पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही विभिन्न युगों की परिस्थितियों का भी उचित रूप से उल्लेख किया गया है। इस उद्देश्य के लिए आर्थिक और सामाजिक तथ्यों तथा आन्दोलनों का विवरण भी दिया गया है जिसका देश के वैधानिक इतिहास में अन्यथा कोई स्थान नहीं था। इतने पर भी यह सम्भव है कि कुछ लोगों के अनुसार कितनी ही बातें छोड़ी हुई प्रतीत हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैंने इस बात का अधिकाधिक प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य से सगत कोई तथ्य और विवरण छूट न जाय।

मैं इस पुस्तक में निर्णय देने से दूर रहा हूँ। मैंने तथ्यों को वैज्ञानिक रूप में, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है, मैंने निन्दा अथवा स्तुति के दायित्व को निश्चित नहीं किया।

प्रस्तुत खंड दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में नागर में कम्पनी के राज्य का वर्णन किया गया है। वह वर्णन, सशिक्ष है; वह परिचायक के रूप में है और इसके द्वारा भारत-सरकार के राजनीतिक एवं प्रशासनीय विचार को पूर्ण किया गया है। इसी कारण भारत की प्रांतीय सरकारों पर पार्लियामेंट और मंत्रियों के नियंत्रण, मन्त्रिमन्त्रियों के नियंत्रण और नियंत्रण आदि विषयों की ओर विचार रूप में ध्यान आकर्षित किया गया है।

दूसरे भाग का शीर्षक है 'भारत में ब्रिटिश राज्य, जिसे परम्परा के अनुसार ही मान्यता दी गई है।' कम्पनी के मत से दूसरे भाग का वैधानिक दृष्टि से सही शीर्षक है 'भारत में प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्प्रदाय का विकास।' इसी की दृष्टि से यह शीर्षक अनुविधानिक या व्यापक पुस्तक के दूसरे भाग के प्रथम पृष्ठ के आरम्भ में उसे रचने में बड़ी कठिनाई थी।

दूसरे भाग को तीन स्वामाधिक और सुसंरचित युग में विभाजित किया गया है—सन् १८६१ से १८९२ तक, सन् १८९२ से १९०९ तक, और सन् १९०९ से १९१९ तक। प्रत्येक युग की प्रशासनीय एवं वैधानिक महत्व की घटनाओं का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया है और साथ ही उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर दिया गया है। वैधानिक परिवर्तनों और राष्ट्रीय प्रगति के कारणों पर उचित रूप से प्रकाश डाला गया है। सभी मर्म में प्रगति के लिए उद्यम, उसके स्वरूप, प्रभाव और परिणामों का वर्णन किया गया है; उस युग की सारी उपलब्धियों को बताया गया है।

यह वर्णन सुगमसुचारु न होकर विषमालुनायक भी हो सकता था, किन्तु मेरे विचार से सुगमसुचारु वर्णन अधिक स्वामाधिक और उपयोगी है। उसमें अधिक स्पष्टता है और घटनाओं का प्रवाह सरलता से समन्वित हो सकता है। दूसरे खंड में अगले दो युगों—सन् १९१९ से १९३५ तक और १९३५ से १९४७ तक—की बातें हैं। जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, न यह आशा करता हूँ कि दूसरा खंड सन् १९५१ के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

X

X

X

X

राजनीति-विज्ञान, इतिहास और भारतीय वैधानिक सम्प्रदायों के विद्वानों के अनिरुद्ध, सार्वजनिक सम्प्रदायों के विद्वानों और राज्यों के लिए भी प्रस्तुत पुस्तक को उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। मैंने विषय को, क्या सामर्थ्य, स्पष्टता और सरलता के साथ प्रस्तुत करने की चेष्टा की है किन्तु मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि वैधानिक सुनिश्चितता की ओर भी ध्यान न पड़े। जैसा कि मैंने जगह कहा है, "निश्च विद्यालय व्यवस्था विचारों का आधार है और प्रोफेसर के लिए यह एक गौरव की बात है कि वह जोमल विषयों को भी पूर्ण स्पष्टता

और स्पष्टता के साथ समझाता है ।' इस पुस्तक में मैंने उसी भावना को सर्वोपरि स्थान दिया है ।

×

×

×

×

काशी-विश्वविद्यालय के बहुत-से मित्रों और सहयोगियों के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ । यह दुःख की बात है कि आज उनमें से कुछ व्यक्ति इस सप्ताह में नहीं हैं । मुझे इस बात का विश्वास है कि बनारस के मेरे मित्र और सहयोगी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने में उनके नामों का उल्लेख नहीं कर रहा । भेद-भाव न करने की दृष्टि से मैं रामजस कॉलेज, दिल्ली के अपने तत्काल सहयोगी को भी बिना नाम लिये ही धन्यवाद दूँगा । यहाँ पर मैं केवल अपने भाई सन्त निहाल सिंह और उनकी सहघर्मिणी श्रीमती कैथिलीन निहालसिंह के ही नामों का उल्लेख करूँगा—उनके प्रति मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ और उनकी आदर और श्रद्धा के साथ मैं इस पुस्तक को समर्पण करता हूँ, जिसकी लिखन में मैंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किये हैं ।

अन्त में, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस खंड में जो कुछ भी दोष हो, उनके लिए मैं स्वयं ही उत्तरदायी हूँ ।

कॉलेज ऑफ कामर्स,  
दिल्ली । }

गुरुमुख निहाल सिंह

# विषय-सूची

## भाग १

### भारत में कम्पनी का राज्य

( पृष्ठ १ से पृष्ठ ८२ तक )

#### अध्याय

- १/ ब्रिटिशवासियों का आगमन
- २/ ब्रिटिश राज्य का आरम्भ
- ३/ द्वैध शासन का युग
- ४/ कम्पनी के अन्तिम दिन

## भाग २

### भारत में ब्रिटिश राज्य

( पृष्ठ ८३ से पृष्ठ ४१९ तक )

	नेधि सत्याओ का आरम्भ	८५
६	शासन और राजनीति में परिवर्तन	९७
७	वैधानिक विकास	१०४
८	वित्तीय निक्षेपण और स्थानीय स्वशासन	११५
९	भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ	१२४
१०	१८९२ का भारतीय परिषद् एक्ट	१३६
११	शासन तथा सविधान से सम्बन्धित परिवर्तन	१४०
१२	धार्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ	१५१
१३	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वैधानिक एवं क्रांतिकारी	१६७
१४	दमन और सुधार	१९३
१५	मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ	२०७
१६	मॉर्ले-मिण्टो सुधार १९०९	२३१
१७	शासन तथा सविधान से सम्बन्धित परिवर्तन	२५१
१८	क्रान्ति और दमन	२७३
१९	वैधानिक आन्दोलन	३०१
२०	मोन्टेफोर्ड सुधारी	३२३
२१	विच्छिन्नता की वृद्धि	३७३
२२	अमृतसर का हत्याकाण्ड	३८९

# भाग १

भारत में कम्पनी का राज्य

साथ ही अपनी रक्षा के लिए सीमिन<sup>१</sup> किन्तु मगस्थ, ममुद्री मेना रखने का अधिकार मिला। आरम्भ में अधिकार-पत्र १५ वर्षों के लिए था। यह अवधि बीतने पर फिर से जारी किया जाता, यह परीक्षण करने के बाद कि राजभुजा और मबंभाधारण के हितों को कोई क्षति तो नहीं पहुँचनी, दो वर्ष का नोटिस देकर अधिकार-पत्र नयाप्त किया जा सकता था।

लन्दन-कम्पनी एक 'रेगुलेटड'<sup>२</sup> कम्पनी की तरह आरम्भ हुई। वह 'ज्वाइण्ट स्टॉक' कम्पनी नहीं थी। कम्पनी के नाय न जा सकते पहुँची ममुद्री यात्राएँ हुईं वह पूषक् यात्राएँ थी, मयुक्त यात्राएँ नहीं थी। उन यात्राया में केवल उन्हीं सदस्या को लाभ हुआ, जो स्वयं ही अपनी इच्छा में उन यात्राया में सम्मिलित हुए। किन्तु सन् १६१० में मयुक्त पूँजी की आवश्यकता अनुभव की गई और सब सदस्या ने साझेदारी में पूँजी लगान के लिए कहा गया। आरम्भ में यह साक्षा निश्चित और सीमिन अवधि के लिए था।<sup>३</sup> सन् १६५७ में पहली बार सदस्यों ने स्थायी मयुक्त पूँजी के लिए धन दिया और कम्पनी को एक ज्वाइण्ट स्टॉक कारपोरेशन बना दिया।

## (२)

अधिकार-पत्र से सुरक्षित, लन्दन कम्पनी अपन अत्यन्त घटनापूर्ण जीवन में भागे बड़ी। एक स्थायी आंग्ल-भारतीय व्यापार की नींव रखने के लिए उसने भारतीय समुद्र-तट के महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों पर फँकड़ी बनाना और इन्हीं बनाना आरम्भ किया। कम्पनी द्वारा स्थापित सबसे पहला व्यापारिक बन्दरगाह था-

- १ कम्पनी को अधिकार-पत्र (चार्टर) में 'छ अच्छे जहाज और छ अच्छी लडाकू नावें' और उनके लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री, शस्त्र आदि और पाँच सौ नाविक रखने का अधिकार मिला।

Mukherjee Indian Constitutional Documents  
Vol. I., page 14.

२. "ऐसी कम्पनी के सदस्य कुछ ऐसे नियमों के अधीन थे जो सबने सम्बन्धित थे और कुछ मुविधाओं के लिए सबको अधिकार था लेकिन प्रत्येक सदस्य अपनी निजी पूँजी पर कायम व्यापार था और कोई मयुक्त पूँजी नहीं था।"

Ilbert - Govt. of India Historical Survey,  
page 7.

३. "अवधि पर समाप्त होने वाली साझेदारी में, समय आने पर, भागों का विभाजन हो जाता।"

The Cambridge History of India, Vol. V., page 89.

सूरत<sup>१</sup>, जहाँ उसे सम्राट् जहाँगीर से जमीन और कुछ दूसरी सुविधाएँ मिली थी। सन् १६१६ में मछलीपट्टम में एक फँकट्टी स्थापित की गई। सन् १६३३ में (महानदी डेल्टा में) एक फँकट्टी हरिहरपुर में खोली गई। सन् १६४० में सेण्ट जार्ज का किला मद्रास में बनाया गया। सन् १६५० में कम्पनी को बंगाल के शासक से, उस प्रान्त में व्यापार करने, फँकट्टी बनाने आदि का अधिकार मिला (जो बंगाल जीतने पर औरंगजेब के शाही प्रतिनिधि ने बना रहने दिया)। फलतः शाही बन्दगाह हुगली पर एक फँकट्टी खोली गई लेकिन नये शाही प्रतिनिधि शाहस्ताखा के विरोध के कारण कम्पनी विसंघ प्रगति नहीं कर सकी। सन् १६८६ में जॉब चारनॉक को हुगली छोड़ना पड़ा और मुतनती, जहाँ वर्तमान कलकत्ता स्थित है, आना पड़ा। १६९० में वहाँ एक फँकट्टी बनाई गई। १६६९ में राजा चार्ल्स द्वितीय ने राजसत्ता के नाम से १० पौंड वार्षिक लगान पर बम्बई द्वीप और बन्दगाह भेंट किये। इस प्रकार भारत के समुद्र-तट के महत्वपूर्ण स्थान सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक कम्पनी को प्राप्त हो गए। इन स्थानों से कम्पनी अपना व्यापार और अपने दूसरे धंधे सुविधा के साथ कर सकती थी।

### (३)

किसी कम्पनी को एकाधिपत्य देना, आजकल, नागरिकता के साधारण अधिकारों पर प्रबल आघात समझा जा सकता है किंतु वह समय विशेषाधिकार और एकाधिपत्य का था और विदेश-व्यापार के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि अधिकांश जनता को गिने-बुने लोगों की कारपोरेशनों<sup>२</sup> का एकाधिपत्य मानना पड़ता। जैसा कि इल्बर्ट ने सकेत किया है “पूर्वा व्यापार की सफलता से चलाने के लिए यह आवश्यक था कि ऐसी समितियाँ बनाई जायें जो देशी राजाओं से समझौता और सौदा करने में, अपने नौकरों में अनुशासन बनाये रखने में और अपने यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों को जवाब फेंकने में समर्थ हों। स्वतन्त्र या अनधिकृत व्यापारी अपनी निर्बलता

१ कम्पनी की पहली दो यात्राएँ भारत के लिए नहीं हुईं बरन् आचीन (सुमात्रा), बान्तुम (जावा), और मौलुकास के लिए हुईं। तीसरी यात्रा में बान्तुम के मार्ग में सूरत पर रुकने की व्यवस्था हुई (२४ अगस्त १६०८)। लेकिन शाही फरमान १६१३ में मिला और उस समय सूरत में स्थायी फँकट्टी खोली गई।

२ आन्ल रूसी व्यापार का एकाधिपत्य १५५३-५८ में रूसी कम्पनी को और भूमध्य सागर के व्यापार का एकाधिपत्य १५८१ में लोवेण्ट कम्पनी को दिया गया था।



के कारण, विदेशियों की दवा पर रहता और अपने उत्तरदायित्व से विहीन होने के कारण अपने देशवासियों के लिए नुक़्त का कारण हो सकता था।<sup>१</sup>

(५)

फिर भी लन्दन-कम्पनी के प्रति आरम्भ में ही ईर्ष्या और रोष की भावना आपन हुई और उसे देशों तथा विदेशी<sup>२</sup> अनधिकृत व्यापारियों और प्रतिद्वन्द्वियों ने परेशान किया। उसकी पहली मुठनेड़ हुई अनाडा-कम्पनी से। इस कम्पनी को उसके सत्यापक सर विलियम कोर्टीन के नाम पर कोर्टीन एसोसिएशन भी कहते थे। सर कोर्टीन ने अपने प्रभाव और अपनी पहुँच द्वारा चार्ल्स प्रथम से अधिकार-पत्र प्राप्त कर लिया था। इन कम्पनी ने अनाडा (मैडगास्कर) में एक बस्ती बसाई थी। कुछ समय तक इसने बड़े जोरो से व्यापार चलाया और लन्दन-कम्पनी को नारो सति पहुँचाई। अन्त में एक समझौता हुआ और अनाडा-कम्पनी, लन्दन-कम्पनी में मिला ली गई। गृह-युद्ध का भी कम्पनी को स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा<sup>३</sup> लेकिन विजेता ने उसकी रक्षा की। उसने देशों और विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों के साथ कम्पनी के सगठो का निजदारा किया और १६५७ में एक नया अधिकार-पत्र दिया और साथ ही उसे एक स्थायी समुक्त पूंजी की कम्पनी के रूप में बदल दिया।<sup>४</sup>

नये अधिकार-पत्र ने नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ५ पाँड प्रवेश-शुल्क और कम्पनी की पूंजी में कम-से-कम १०० पाँड देकर, उसका सदस्य हो सकता था किन्तु कम्पनी के साधारण अधिवेशन या 'जनरल कोर्ट' में मत वही व्यक्ति दे सकता था जिसका पूंजी में साझा ५०० पाँड या उससे अधिक हो। १००० पाँड के साझेदार कनेटियो अथवा 'कोर्ट ऑफ़ डाइ-रेक्टर्स' की मददस्वता के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे। इनमें से प्रतिवर्ष आठ सदस्यों की अवधि समाप्त होती। गवर्नर और रिप्ली गवर्नर का

१. Ilbert : Historical Survey, page 9.

२. विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों से सघर्ष के सम्बन्ध में पृष्ठ ९ और १० देखिये।

३. पार्लियामेंट के राउल्डहेड अर्थोप्योगिस्टन बिल ने कम्पनी से बरात ५००० पाँड का ऋण लिया।

४. १९ अक्टूबर १६५७ के अधिकार-पत्र ने कम्पनी को एक स्थायी समुक्त पूंजी बनाने के लिए जोर दिया। इन प्रकार हटर के शर्तों में कम्पनी, "मध्यराशीन व्यापार-मध्य के दुर्बल अवशिष्ट से जागत आधुनिक ब्राइट स्टॉक कम्पनी" के रूप में बदल दी गई।

कार्य-काल घटा दिया गया जो अधिक-से-अधिक लगातार दो वर्ष के लिए सीमित था ।

चार्लस ड्रिश्ये के प्रत्यागमन के बाद कुछ समय तक कम्पनी की समृद्धि की धूम रही । यह चढ़ाव सत्रहवीं शताब्दी की नवीं दशाब्दी में अपने सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँचा । उस समय कम्पनी का निर्देशन सर जोशिया चाइल्ड के महान् व्यक्तित्व द्वारा हो रहा था । उसी समय सन् १६८८ का प्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ।<sup>१</sup> किन्तु १६८८ की त्रासति के बाद कम्पनी के लिए स्थिति बिगड़ गई ।

कम्पनी के प्रतिद्वन्द्वियों ने क्रांति और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाया और एक प्रबल विरोध का समझन किया । १६९१ में पार्लियामेंट ने सुदूर पूर्व के व्यापार की सफलता और उस व्यापार को एक उजाड़पट स्टॉक कम्पनी के हाथ में बने रहने देने की उपयोगिता को स्वीकार किया, और लन्दन-कम्पनी को उसके प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा बनाई हुई नई कम्पनी में मिला देने का प्रस्ताव किया गया । लेकिन बहुत बड़ी रिवर्से<sup>२</sup> देकर सर जोशिया चाइल्ड ने १६९३ में कम्पनीका अधिकार-पत्र फिर से जारी करा दिया ।

सन् १६९३ के अधिकार-पत्र के अनुसार कम्पनी की पूंजी बड़ाकर ७,४४,००० पाँड कर दी गई, किमी एक व्यक्ति का अधिकतम साझे १०,००० पाँड पर सीमित कर दिया गया और हर १००० पाँड की पूंजी<sup>३</sup> पर एक वोट के अनुसार किसी एक साझेदार के लिए अधिक-से-अधिक १० वोट की सीमा निश्चित कर दी गई । १००० पाँड देने वाले साझेदार

१. सन् १६८८ का प्रस्ताव . "हमारी आय में वृद्धि हमारे ध्यान का विषय है . . . उतने ही ध्यान का जितना कि हमारा व्यापार, अपने व्यापार में बाधाओं और दुर्घटनाओं के समक्ष उसी से बल बनाये रखना है, उसी से हमें अपने को भारत में एक राष्ट्र बनाना है ।"

२. सन् १६९५ में हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सामने रखे गए कम्पनी के गुप्त खर्च के हिसाब के अनुसार २३,४६९ पाँड सन् १६८८ और १६९२ के बीच खर्च किये गए और १६९३ में ८०,४६८ पाँड खर्च किये गए ।

*Thakore: Indian Administration to the Dawn of Responsible Government.*

३. सन् १६९८ के अधिकार-पत्र द्वारा एक वोट के लिए ५०० पाँड के साझे का नियम हो गया और अधिकतम वोटों की संख्या ५ कर दी गई ।

कमेटियों के चुनाव के लिए खड़े हो सकने थे<sup>१</sup>; लेकिन गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होने के लिए ४००० पौंड का साक्षा होना आवश्यक था। सारे स्थान-परिवर्तनों का उल्लेख एंव रजिस्टर में किया जाना था। इस रजिस्टर का सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मुलभ रक्खना था। मयूकन पूंजी का भुगतान केवल इक्कीस वर्षों के लिए था।<sup>२</sup>

अधिकार-मन फिर से मिलन के कारण लन्दन-बम्पनी का बल बड़ा और उसने पूर्वी द्वीप समूह के लिए जाने वाले रेट्रिज जहाज का रोक लिया। बम्पनी ने इस व्यवहार पर आपत्ति की और प्रस्तुत पार्लियामेंट के सामने आया। हाउस ऑफ़ बामन्स ने १६९४ में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, "कि इंग्लैंड की सारी प्रजा को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का समान अधिकार है, जब तक कि पार्लियामेंट के एकट द्वारा ही उस पर रोक न लगा दी जाय।" इस प्रकार उस समय के लिए लन्दन-बम्पनी का एकाधिपत्य तोड़ दिया गया। साथ ही लार्ड मैक्लि के राजा में मदद के लिए यह निर्णय कर दिया गया कि, "लाक सभा के अतिरिक्त और कोई सत्ता किसी व्यक्ति या समुदाय को सत्तार के किसी भाग में व्यापार करने के लिए एकाधिपत्य अथवा विगपाधिकार नहीं दे सकती।"

सन् १६९४ के प्रस्ताव से व्यापारिक एकाधिपत्य प्रदान करने का अधिकार राज-मद से हटकर पार्लियामेंट में आ गया। अब एक एकट के लिए तत्कालीन अर्थ-मन्त्री ( चांसलर ऑफ़ दी एक्सचेकर ) मि माण्डगु द्वारा, पुरानी और नई दोनों बम्पनियाँ, लोक सभा में पयल करने लगीं। माण्डगु को घन की बड़ी भारी आवश्यकता थी और दोनों बम्पनियों के बीच व्यापार का एकाधिपत्य "नीलाम पर रख दिया गया।"<sup>३</sup> पुरानी बम्पनी ने पहले ही रिस्वत में बर्त-वर्त रकम खर्च की थी और हाल में ही फ़ाम में युद्ध के समय में बड़ा भारी घाटा उठाया था और वह ४ प्रतिशत व्याज पर केवल ७,००,००० पौंड का ऋण दे सकती थी और वह भी पूर्वी बटाकर १५,००,००० पौंड करने

१ सन् १६९८ में बढ़ाकर २००० पौंड कर दी गई।

२ Ilbert : Historical Survey, page 26.

३ "(विगोपाधिकारों के बदले में राज्य के लिए ऋण लेने की) यह व्यवस्था हमने अच्छी थी जिसमें व्यापारियों को विगोपाधिकार राजाओं को नेंट देने और मन्त्रियों को रिस्वत देने में मिलने थे और इन्हे अगले पीढ़ी में बहुत पछावा मिलना था।" Ilbert : Historical Survey, page 28.

की अनुमति मिलन पर। किन्तु नई कम्पनी २० लाख पौंड उबार देन को प्रस्तुत थी। माण्डगु को इतन की ही आवश्यकता था। पर नई कम्पनी की व्याज की दर ८ प्रातान थी। पार्लियामन्ट बिल रखा गया जिसके अनुसार सरकार के लिए २० लाख पौंड ऋण की माँग की गई। उसके बदले में ऋण देन वाला को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था।<sup>१</sup> पुरानी कम्पनी को उसके अधिकार पत्र के अनुसार ३ बर अर्थात् सितम्बर १७०१ तक समय देना था। जब पुरानी कम्पनी ने यह अनुभव किया कि एकाधिकार और किसी प्रकार नहीं बच सकता तो वह सारी रकम का प्रबंध करने के लिए तयार हुई किन्तु यह प्रस्ताव देर से आया। नई कम्पनी को एकाधिकार देन वाला बिल पार्लियामन्ट के दाना भवना से स्वीकृत हो गया और जुलाई १६९८ में उस राजकीय स्वीकृति मिल गई।

सन् १६९८ के एक न ऋण देन वाला को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे अपनी पूँजी के परिमाण के अन्तर्गत अलग-अलग अथवा राजकीय अधिकार-पत्र के अधीन<sup>२</sup> संयुक्त रूप से व्यापार कर सकते ह। अधिकार न पिछली बात का पसंद किया और परिणामतः ५ सितम्बर १६९८ को शाही अधिकार पत्र द्वारा दी इंगलिश कम्पनी ट्रिनिटी दि ईस्ट इंडीज नाम की नई कम्पनी बनी। उसका प्रबंध २४ डाइरेक्टर्स को सौंपा गया। वे लोग अपने में से ही एक अध्यक्ष (चेयरमन) और एक उपाध्यक्ष नियुक्त करते। इस सम्बंध में एक ध्यान देने की बात यह है कि पहली कम्पनी की तरह इस कम्पनी के लिए कोई पक्का प्रवेश गुल्म नहीं था।<sup>३</sup>

सन् १६९८ के एक वन जान के फलस्वरूप दोनों कम्पनियों में घातक प्रतिद्विद्धता हुई जिसमें सचाई के साथ व्यापार करने के सारे नियमों की अवहेलना की गई। पुरानी कम्पनी को अनुभव था और साथ ही नई कम्पनी में कुछ स्वायत्ती भी थी। कारण यह था कि भविष्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी कम्पनी ने नई कम्पनी की २० लाख पौंड की पूँजी में ३१५००० पौंड दिए थे। दूसरी ओर सन् १७०१ में पुरानी कम्पनी के बन्द होने तक नई कम्पनी प्रतियोगिता कर सकती थी। किन्तु इसी बीच स्थिति बड़ी बिगड़

१ Foster Chapter IV, Cambridge History of India, Vol V, pages 98 99

२ Ilbert Historical Survey, page 28

३ Foster Chapter IV, Cambridge History of India, Vol V, pages 98 99

हो गई। नई कम्पनी को बसाधारण क्षति होने लगी। उसने लिए एकमात्र उपाय पुरानी कम्पनी से किसी प्रकार समझौता करना था। इस प्रकार लार्ड गोडोल्फिन ने हस्तक्षेप से समझौता हुआ। उसने अनुसार दोनों कम्पनियाँ अपनी सम्पत्ति के मूल्य आँके जाने के बाद, बराबर के साझे में एक हो जाने की तैयार हो गई। सन् १७०० ने इस समझौते के अनुसार "पुरानी कम्पनी को सात वर्ष तक पयक् सत्ता बनाने रखने की अवधि मिली, किन्तु इंगलिश कम्पनी के नाम से व्यापार संप्रवर्ण रूप से चलने की व्यवस्था थी। इस मुमुक्षु व्यापार का लाभ दोना के लिए था और उसका निर्देशन २४ सदस्यों के हाथ में होता था—१० सरस्य पुरानी कम्पनी द्वारा छांट हुए और १० नई कम्पनी द्वारा। सात वर्ष बीतने पर पुरानी कम्पनी को अपने अधिकार-मन्त्र छोड़ देने की शर्त थी" और नई कम्पनी दो यूनाइटेड कम्पनी ऑन् मर्चण्ट्स ऑन् इंगलैंड ट्रेडिंग टु दी ईस्ट इंडीज नाम से व्यापार चलायी।

सन् १७०० के समझौते में कुछ झगड़े उठ खड़े हुए और कठिनाइयाँ सामने आईं। इनका निपटारा करने के लिए १७०७ में एक एक्ट बनाया गया। इसके द्वारा नई कम्पनी से सरकार को बिना व्याज के १० लाख पौंड का एक अतिरिक्त ऋण देने के लिए कहा गया। इस प्रकार कुल ३२ लाख पौंड पर व्याज की दर घटकर केवल ५ प्रतिशत रह गई। बदले में इंगलिश कम्पनी के विशेषाधिकार १७२६ तक बढ़ा दिए गए। साथ ही इस कम्पनी को उन व्यापारियों से, जिन्होंने १६९८ में व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने का निश्चय किया था, उनका व्यापार खरीद लेने का अधिकार दिया गया। दोनों कम्पनियों के प्रमुख प्रश्नों की हल करने के लिए लार्ड गोडोल्फिन मध्यस्थ नियुक्त किये गए। उन्होंने नवम्बर १७०८ में अपना निर्णय दिया। मार्च १७०९ में पुरानी कम्पनी ने अपने अधिकार-मन्त्र पुरानी को सौंप दिए। इस प्रकार लडन-कम्पनी के पृथक् अस्तित्व का अन्त हो गया। नई कम्पनी ने अपने उपर्युक्त नाम से पुरानी कम्पनी का काम हाथ में ले लिया और अपना घटनापूर्ण एवं समृद्धिशाली जीवन आरम्भ किया।

१. Ilbert : Historical Survey, page 30.

२. लीवर ने यूनाइटेड कम्पनी का विधान इस प्रकार दिया है: "कम्पनी उन सब व्यक्तियों की थी जिनका दस्तावेज २० लाख पौंड की पूंजी में हिस्सा था। प्रत्येक पुरुष या स्त्री को, जिसका बचने या दूसरे नाम में ५०० पौंड का साझा था, वोट देने का अधिकार था। वह मास्को की नोटिंग में, जिसे चार्टर द्वारा 'जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' का नाम दिया गया था,

(५)

यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी का जन्म और औरगजैव के महान् मुगल व्यक्तित्व का अवसान, ये दोनों बातें एक ही साथ हुईं। यह एक ऐसा सयोग था जिसका आगे चलकर भारत के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत में अपना प्रभुत्व जमाने से पहले यूनाइटेड कम्पनी को यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों, विशेषकर फ्रांस और साथ ही भारतीय शासकों के प्रबल विरोध का सामना करना था।

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में ही पुर्तगालवासियों की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। १६४८ में मन्स्टर की संधि के अनुसार भारत में पुर्तगालवासियों का अधिकार पश्चिम तट पर दीव, दामन और गोवा पर ही रह गया था।<sup>१</sup> १६४८ के बाद पूर्व में पुर्तगाल वालों का महत्त्व समाप्त हो गया था।

हॉलैंड वालों से सत्रह अर्धशताब्दी तक चला। १६२३ में एम्बायना में हॉलैंड वालों ने सब अंग्रेजों को मार डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि लंदन-कम्पनी स्पाइस द्वीप के साथ व्यापार से हट आई और उसने अपनी शक्ति भारतीय व्यापार में केन्द्रित की। १६५४ में वेस्टमिन्स्टर की संधि के अनुसार क्षति-पूर्ति के रूप में कम्पनी को ८५,०००<sup>२</sup> पाँड मिले। (क्रोमवेल के अधीन) ब्रिटेन और हॉलैंड में तीन बरस युद्ध होने के बाद यह संधि हुई थी। अन्त में फ्रांस ने यूरोप में हॉलैंड की शक्ति को कुचल दिया और

विवाद में भाग ले सकता था। प्रोप्राइटर्स को २००० पाँड के साझेदारों में से २४ डाइरेक्टर चुनने होते थे। काम करने के लिए कम-से-कम १३ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। समुक्त रूप से उनका नाम था 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स'। चार्टर के अनुसार हर तीन महीने बाद कोर्ट की मीटिंग होती अनिवार्य थी। कम्पनी के शासन के लिए नियम बनाने को एक बनेटी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी। वह नियम-कानून उतने ही मान्य थे जितने कि पार्लियामेंट के नियम, बशर्ते कि वह किसी एक्ट के प्रतिकूल न हो।" Auber - The Rise and Progress of British Power in India page 13

१. ये स्थान अब भी पुर्तगाल वालों के अधिकार में हैं किन्तु १५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र होने के बाद उनका मविव्य भारत और पुर्तगाल, दोनों देशों की सरकार के विचाराधीन है।
२. इसमें से क्रोमवेल ने कॉमन वेल्थ सरकार के लिए ५०,००० पाँड उधार के लिए।

१६९७ में रिसर्विक् की मधि होने पर पूर्व में हॉलैण्ड वालों का व्यापारिक प्रभुत्व भी समाप्त हो गया।

### (६)

इस प्रकार मद्रास घटनाओं में डचों के दो यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वी मंदान से निकल गए किन्तु फ्रांसीसी अभी जमे हुए थे। भारत के पूर्वी तट पर मद्रास के निकट पाटिचेरी और कन्नकत के निकट चन्द्रनगर में उन्होंने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली थी।<sup>१</sup> स्थानीय फ्रांसीसी शासकों ने भारतीय शासकों से मित्रता बढ़ाई और फलन देश में अपनी शक्ति और प्रभुता जमान में मगल हुए।

फ्रांसीसिया और अंग्रेजों में प्रभुता के लिए साम्प्रतिक संघर्ष १७४१ में डुप्ल के पाटिचेरी के शासक (गवर्नर) नियुक्त होने पर आरम्भ हुआ। यह संघर्ष २० वर्ष तक चला। पहले आठ वर्षों में अर्थात् १७४९ तक फ्रांसीसिया का पक्ष प्रबलतर रहा। कलाद्व द्वारा आर्कांट जीत लेने पर पासा पलट गया किन्तु अन्तिम रूप से फ्रांसीसी शक्ति अंग्रेजों द्वारा कन्नकत का जीत के बाद ही २१ जनवरी १७६० का पराजित हुई।

### (७)

इस बीच बंगाल में महत्वपूर्ण घटनाएँ घट रही थीं।

बंगाल के नये नवाब मिर्जासुद्दौला ने अंग्रेजों की अकड़ और शत्रुतापूर्ण हरकतों<sup>२</sup> में चिढ़कर १७५६ में कन्नकत पर बढ़ाई की। गवर्नर (डेव) और मुख्य सैनिक अधिकारी ने किले का उससे भाग्य पर छाट दिया—और स्वयं भागकर हुगली में ब्रिटिश जहाजों पर पहुँच गए। मामूली लड़ाई के बाद फोर्ट विलियम की सेना ने हथियार डाल दिए और डकैत हाल<sup>३</sup> की कथित घटना हुई। कलाद्व

१ यमन, हरिकल और माही—इन तीन म्यानों पर भारत में फ्रांसीसी अधिकार और बना हुआ है। १९ जून १९४९ को चन्द्रनगर में भारत में विलियम के लिए मन द दिया है। दोष चार फ्रांसीसी अधिकारों के प्रश्न पर दोनों सरकारों में वार्तालाप चल रही है।

२ Keith Speeches and Documents on Indian Policy. Vol 1, page 3.

३ ब्लैक होल के विषय में इतिहासकारों के विवाद में पड़ने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अधिकांश भारतीय और कुछ अंग्रेज और विदेशी इतिहासकार यह मानते हैं कि यह घटना कभी हुई ही नहीं; यदि हुई तो नगण्य रूप में। अन्यथा कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल के पास बंगाल कॉमिल में जो कागज भेजे जाते थे उनमें इसकी चर्चा अवश्य होती। फ्रांसीसी भारत के एक नूतन गवर्नर-

और वाटसन मद्रास से हालत सँभालने और क्षति-पूर्ति करने के लिए भेजे गए। उन्होंने तुरन्त ही वजबज के किले को अपने अधीन किया और २ जनवरी १७५७ को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। एक सप्ताह बाद हुगली का किला भी जीत लिया गया। क्षति-पूर्ति करने के आवार पर नवाब के साथ संधि भी की गई।

क्लाइव ने कलकत्ते में बसकर नवाब के मन्त्रियों के साथ पट्टव रचने शुरू किये। उस नवाब के सेनानायक मीर जाफर के साथ एक संधि की। क्लाइव ने घोखे और जालसाजी<sup>१</sup> से अमीचन्द को उसके इनाम के मामले में ठगा। इस प्रकार अपनी स्थिति दृढ़ करके क्लाइव नवाब की सेना से मुर्शिदाबाद के पास टक्कर लेने के लिए बढ़ा। पलासी में युद्ध हुआ। नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला बेप बंदलकर भागा, पर पकड़ा गया और बन्दीखाने में डाल दिया गया। बाद में मीर जाफर के एक लडके ने उसको मार डाला। अंग्रेजों ने संधि का पालन किया और २७ जून १७५७ को मीर जाफर नवाब घोषित कर दिया गया।

### (८)

सन् १७६१ तक अंग्रेजों ने परिस्थितियों को अपने बस में कर लिया। उन्होंने फ्रांसीसियों को और सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दक्षिण में और पूर्व में उनकी शक्ति सर्वोपरि थी। मराठों से, जो उस समय भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, उन्हें अपनी साम्राज्यवादी योजनाओं के लिए खतरा हो सकता था। किन्तु उनके भाग्य से, १७६१ में पानीपत की हार से मराठों की दशा बहुत बिगड़ गई। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए मार्ग खुला हुआ था।

क्लाइव ने भारत में ब्रिटेनवासियों का भविष्य स्पष्टता के साथ देखा उसने अपने साम्राज्य की नींव बड़ी चतुराई और दृढ़ता के साथ रखी। शीघ्रता से विस्तार करने और सशस्त्र विजय की नीति अपनाने के स्थान पर वह बड़ी सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ा, एक स्थान पर कुछ भूमि का अधिकार लिया तो किसी दूसरे स्थान पर मालगुजारी जगाहने का काम लिया

जनरल भातिनो, जो उस समय के इतिहास के अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं, यह मत देते हैं कि जब तक नये प्रमाण न मिले, ब्लैक होल की घटना को सिद्ध करने के लिए, उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं।

- १ कुछ अंग्रेज लेखकों ने क्लाइव का कलकत्ते के लिए पूर्वी देशों के रहने वालों की नैतिकता पर आघात किया है। उनके अनुसार क्लाइव ने उन्हीं लोगों की चाल अपनाई। किन्तु इससे कोई सफाई नहीं होती, एडमिरल वाटसन ने उसे ऐसा नहीं समझा।



ताकि कोई बल विरोध न उठ सके हो और भारतवर्षी विदेशियों को मार भगाने के लिए मुगलिन न हो उठें। क्लाइव ने बड़ी कुशलता के साथ म्यति को सँभाला। उसने दिल्ली के मुगल सम्राट की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की। उसने सम्राट से कम्पनी को सरकार देने की, हँसरावाद से कर्नाटक पृथक् करने की, और बंगाल में कम्पनी को दीवानों का अधिकार देने की माँग की। उसने बंगाल को सरकार के साथ मिलाने के लिए चरार के राजा के प्रदेशों पर अधिकार नहीं किया वरन् राजा को मनाकर राजी कर लिया। उसने बक्कर के बाद अवध की छीना नहीं वरन् नवाब को अपना साथी बना लिया। वह मराठों से लड़ा नहीं वरन् उड़ीसा में उनके चौथ के अधिकार को स्वीकार कर लिया। दक्षिण में पेशवा के विरुद्ध शक्ति का मजबूत करने के लिए उसने निजाम से मित्रता कर ली। इन प्रकार उसने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थिति को सुदृढ़ किया और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी।

## दूसरा अध्याय

# ब्रिटिश राज्य का आरम्भ

(१)

सन् १७६५ में दीवानी का अधिकार मिल जाने से कम्पनी के मालिकों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। भविष्य की मुनहनी कल्पनाओं से उनकी आँखें चौंधिया गईं। क्लाइव के अनुसार १७६५ में बंगाल का कुल मालगुजारी ४० लाख पौंड थी और सारे व्यय निवालाकर कम्पनी की बिगुड आय १६,५०,००० पौंड थी। १७६७ में कम्पनी के स्टॉक की दर बढ़कर २६७ और लाभांश १२½ प्रतिशत हो

१. प्रो० कीथ लिखते हैं 'मौर कामिभ के प्रबल विरोध से क्लाइव को इस बात का भय था कि वहाँ देशी लोग, यूरोपीय साधियों के अभाव में अपने ही साधनों से, अपने उस प्रमाद को छोड़कर, जो यूरोपीय सहायकों की उपस्थिति में था, अंग्रेजों के विरुद्ध, मुगलिन होकर विक्ट युद्ध न करें।' Keith in his preface to 'Speeches and Documents on Indian Policy.

२. क्लाइव ने १७५९ में अंग्रेजों के लिए बंगाल की सूबेदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पिट को अपने दृष्टिकोण पर लाने का प्रयत्न किया था। Keith's Speeches and Documents on Indian Policy.

गया। कम्पनी के कर्मचारी अपने साथ बड़ी भारी सम्पत्ति ले गए और इंग्लैंड में अपने नाम की बस्ती और प्रदेश बनाकर 'नवाबों' की भाँति जम गए।<sup>१</sup> हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ने राजसत्ता के लिए वांछित धन पाने का सुअवसर देखा और कम्पनी पर यह धन देने का दायित्व ढालकर उन्होंने अपने निर्वाचकों की दृष्टि में अपने-आपको ग्याय्य ठहराया। किन्तु ४००,००० प्रति वर्ग का मूल्य<sup>२</sup> लेकर और बदले में कम्पनी को भारत के अधिकृत प्रदेशों<sup>३</sup> पर यथावत् अधिकार बनाये रखने की अनुमति देकर वे (हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य) कुदासन के प्रति डॉक्टर वचान के नाने<sup>४</sup> एक भयंकर विश्वास-घात के अपराधी बनें। जब से माण्डगु को उक्त योजना<sup>५</sup> सूझी यूनाइटेड कम्पनी ने अवधि बीतने पर अधिकार-पत्र फिर से प्राप्त करने के लिए हर बार धन दिया था। इस प्रकार १७५० तक कम्पनी ने ३ प्रतिशत ब्याज पर राजसत्ता को ४२ लाख पौंड ऋण दिया था। १७६७ में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। उसमें दो वर्ष तक ४ लाख पौंड प्रतिवर्ष के हिसाब से धन देने की भाँति थी। बदले में कम्पनी को उसी अवधि के लिए मालगुजारी और प्रादेशिक अधिकार बनाये रखने की अनुमति थी। १७६९ में यह समझौता पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

## (२)

इस बीच भारतीय परिस्थिति अत्यन्त अटिल होती जा रही थी। कम्पनी के अधिकार तीन प्रेसिडेंसियों में थे। हर प्रेसिडेंसी की अपनी सरकार थी—गवर्नर और कौन्सिल—नृत्क और स्वतन्त्र। प्रत्येक का लन्दन में डाइरेक्टरो से

१ नवाब के वर्णन के लिए देखिये Disraeli's Sybil, Chapter III.

२ इस प्रकार राजसत्ता ने भारत से होने वाली धन-प्राप्ति में अपना हिस्सा जताया और भारतीय प्रदेशों की सत्ता के नियंत्रण करने का अधिकार भी जताया। . . .

३ Keith: Speeches and Documents on Indian Policy, Vol I, page XI.

४ बर्क ने कहा कि मन्त्रियों ने ४ लाख पौंड के मूल्य में इस रक्त-पात, इस बलात्कार, इस दुष्टता, इस शोषण को उचित ठहरा दिया था। इस अपराध-कार को स्वीकार करने के बाद फिर कोई बुराईयाँ नहीं सुनी गईं। . . Roberts Chapter X, Cambridge History of India, Vol. V, page 183.

५. Keith: Speeches and Documents on Indian Policy. Vol. I, page 9.

मीथा सम्बन्ध था। डाइरेक्टरो द्वारा बम्पनी के ऊँचे कर्मचारियों में से गवर्नर और कौंसिल के सदस्यों की नियुक्ति होती थी। इन सदस्यों का मर्यादा १२ से लेकर १६ तक होती। इनमें से कुछ सदस्य बट्टवा अनुपस्थित होते। केन्द्र से दूर, देश के भीतरी भागों में फैँवट्टियाँ उनके आधीन थीं। मन्ना गवर्नर और कौंसिल में मनुक्त रूप से निहित थी और उनका नियंत्रण बहुतन पर था। कौंसिल के सदस्यों के बिचरे रहने के कारण, काम का टग से चलाना बहुत कठिन हो गया था। इस कारण कयादव का कौंसिल के कामों को एक छोटी टूट्ट कमेटी को सौंपने का अधिकार दिया गया।

न्याय के सम्बन्ध में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कठिनाईयाँ अनुभव की जा रही थी। १७५३ के अधिकार-पत्र द्वारा प्रसीडेंसी के नगरा वलिय मेयर के न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। इन न्यायालयों का उन दूर-पियनों पर, जो इन नगरा में रहते ■ या उनसे सम्बन्धित फैँवट्टियों में रहते थे, दीवानी, फौजदारी और धार्मिक अधिकार था।<sup>१</sup> लेकिन उस समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रसीडेंसी में अंग्रेजों की मर्यादा का बड़ गट्ट थी। इंगलैंड के कानून के अनुसार कलकत्ते के मेयर के अधिकार-क्षेत्र से बाहर उन्हें दंड देने का बम्पनी को कोई हक नहीं था, जब तक कि वह इंगलैंड वासिन न पहुँचें, लेकिन उस हालत में मासियों की गवाही न मिलती।<sup>२</sup> यह अनुभव दिया गया कि इन कठिनाईका हल प्रान्त में एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) स्थापित करने में ही हो सकता है।

गवर्नर और उसकी परिषद् (कौंसिल) के अमीन सिविल और सैनिक कर्म-चारी थे। इनका मुगियों, दलालों और व्यापारियों में वर्गीकरण था। उनका वेतन हास्यास्पद रूप से कम था। पाँच साल में काम करने वाले मुन्ती को केवल १० पौंड प्रतिवर्ष मिलते। परिषद् के सदस्य को ८० पौंड प्रतिवर्ष मिलते और गवर्नर को ३०० पौंड प्रतिवर्ष। परन्तु उनकी ऊँची आमदनी अनाधारण थी। अनुभव ने उन्हें गरीब आदमियों से भेंट, रिश्तत और नजराना लेने की बला में निपुण बना दिया था। लेखा के शब्दों में, "देशी आदमियों ने इससे पहले ऐसे अनाधार का अनुभव नहीं किया था जो इतना पूर्ण, इतना कुशल और इतना निर्मम हो।" पूरे जिले को किसी समय मनुद्ध और शत्रु आवाद थे, जब विलकुल उजड़ गए थे। ऐसा देखा गया कि अंग्रेज व्यापारियों का दल रित्ताई पड़े ही

१. Yusuf Ali : The Making of India, pages 218-19

२. सन् १७७३ की पार्लियामेंटरी कमेटी के अनुसार सन् १७५७-६६ की अवधि में इस प्रकार ६० लाख पौंड जनता से बलान् बसूल किये गए थे। और जाकर से कयादव को जो धन मिला वह इसके अतिरिक्त था।

गाँव तुरन्त लाली कर दिए जाते, दुकानें बन्द कर दी जाती और सड़कें घेरिए हुए भागने वालों से भर जाती। १७७०-७१ में फसल न होने के कारण बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा उस समय जनता का कष्ट चरम सीमा पर पहुँच गया। किन्तु कम्पनी के कर्मचारी इतने निर्दय और इतने निर्लज्ज रूप से लालची थे कि उन्होंने जनता के कष्टों से लाभ उठाया और अकाल की स्थिति का निज के लिए धन बढ़ोरने में उपयोग किया। कम्पनी के कर्मचारियों की लूट-मार इतनी नियमित थी और जनता के कष्ट इतने अविश्व थे कि अन्त में पार्लियामेंट के सदस्यों को कुछ करने के लिए बाध्य होना पड़ा।<sup>१</sup> हाउस ऑफ कॉमन्स में कर्नल बर्गोयन के प्रस्ताव पर १३ अप्रैल १७७२ को ३१ सदस्यों की एक छँटी हुई कमेटी की नियुक्ति की गई। इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के काम और उसकी व्यवस्था की जाँच करने का भार सौंपा गया।

इस बीच कम्पनी की स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही थी, वह बड़ी तेजी के साथ दिवालियेपन की ओर बढ़ रही थी। अगस्त १७७२ में कम्पनी के पदाधिकारियों ने अपना व्यय न चला सकने की असमर्थता को स्वीकार किया और लार्ड नॉर्थ से ऋण माँगा। बलिहारी हैं कम्पनी के कर्मचारियों की लोभुसता को जिसके कारण कम्पनी की आय तेजी से घट गई। प्रदेशों के बड़-जाने एक बड़ी सेना बनाये रखने और जब-जब युद्ध में भाग लेने के कारण उसका व्यय बहुत बढ़ गया था। हाल ही में हैदराबाद के हाथों दक्षिण में हारकर कम्पनी को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी थी। अगले तीन महीनों में आवश्यक भुगतान करने के लिए कम्पनी के पास १२,९३,००० पौंड की कमी थी। राजस्व का ऋण ही कम्पनी को नष्ट होने से बचा सकता था।

१. Horace Walpole ने लिखा है "अत्याचार और लूट-मार के ऐसे दृश्यों से हृदय काँप उठता है। सोने की लोलुपता में हम स्पेनवासियों की तरह हैं और उसे प्राप्त करने में हॉलैंडवासियों की तरह परिश्रुत हैं।
२. "कम्पनी के अधिकारियों ने अतुल सम्पत्ति एकत्रित की थी। सर्वसाधारण के हृदय में यह सदेह था कि इन नवाबों ने यह सम्पत्ति अनुचित ढंग से प्राप्त की थी। इंग्लैंड में इन कर्मचारियों का सम्पत्ति के कारण राजनीति पर प्रभाव पड़ता था। साथ ही यह सदेह था कि किसी व्यापारिक संस्था के लिए अपने नाम पर प्रादेशिक सर्वोच्च सत्ता हाथियाना वहाँ तक न्यायोचित था। इन सब उपयुक्त कारणों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के कामों की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और हाउस ऑफ कॉमन्स ने कम्पनी के भारतीय शासन की जाँच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमीटी नियुक्त की।" Kalc: Indian Administration, pages 17 and 18 से अनूदित।

२६ नवम्बर १७७२ को पार्लियामेंट खुलने पर लाई नॉर्थ ने कम्पनी की वस्तु स्थिति की जाँच करने के लिए एक गुप्त कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। कमेटी ने बड़ी जल्दी ही अपनी पहली रिपोर्ट दी। दिसम्बर १७७० में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और उसमें कम्पनी को भारत में निरीक्षण के लिए कमीशन भेजने से रोक दिया गया।

गुप्त कमेटी अपना काम करती रही और उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट मई १७७३ में दी। उसके फलस्वरूप पूर्वी प्रदेशों के शासन के नियन्त्रण का निर्णय किया गया। १० मई को बर्नल बर्गोयन और सर विलियम मेरेडिथ<sup>१</sup> ने भारतीय शासन की तीखी आलोचना की। १८ मई को लाई नॉर्थ ने अपना प्रसिद्ध बिल पेश किया जो बाद में १७७३ का रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। कम्पनी की वार्षिक कठिनाइयाँ का हल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट और पास किया। इस एक्ट के द्वारा १४ लाख पौंड का ऋण ४ प्रतिशत व्याज पर सरकार द्वारा दिया गया। ऋण लौटा देने तक ४ लाख पौंड प्रतिवर्ष का वार्षिक भुगतान छोड़ दिया गया। ऋण वापिस होने तक कम्पनी को ६ प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित करने से रोक दिया गया। जब तक बॉण्ड का ऋण घटकर १५ लाख पौंड न हो जाय, लाभांश ७ प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता था। कम्पनी का हर छ महीने बाद जाँच के लिए ट्रेजरी (अर्थ-विभाग) को अपना आय-व्यय का हिसाब देने को कहा गया।<sup>२</sup> कम्पनी को भारत-स्थित कर्मचारियों के बिल स्वीकार करने की वार्षिक सीमा ३ लाख पौंड कर दी गई और उसको ब्रिटेन में बने माल को अपनी सीमा के अन्दर ब्रिटिश वस्तुओं में निर्यात करने की सीमा भी निर्दिष्ट कर दी गई।<sup>३</sup>

( ३ )

कम्पनी (एक व्यापारिक मस्या) के राजनीतिक सत्ताहयियाने के अधिकार पर आरम्भ से ही आपत्ति की गई थी और पार्लियामेंट के हस्तक्षेप करने को कहा गया था। किन्तु कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक अधिकार के दुरुपयोग के प्रमाण एकत्रित होने पर, कम्पनी द्वारा प्रादेशिक सत्ता बनाये रखने के विरोध

१. सर विलियम मेरेडिथ के शब्दों में, "ये व्यवसायी नरेश हमेशा ही खतरनाक हैं। इनका बेचने का नियम इच्छानुसार अधिक-से-अधिक मूल्य लेना है और कम करने का नियम इच्छानुसार कम-से-कम दाम देना है। Chuni Lal Anand . History of Government in India, Part II, page 14 से अनूदित।

२. Ilbert, Historical Survey, page ३०

में भावनाएँ बहुत प्रबल हो गईं। कम्पनी से राजनीतिक अधिकार छीन लेने के प्रयत्न किये गए पर कोई सफलता नहीं मिली। विन्तु जब कम्पनी ने आर्थिक सहायता के लिए पार्लियामेंट के सामने हाथ पसारते तो इस अवसर का भारतीय शासन के नियन्त्रण करने के लिए लाभ उठाया गया।

सन् १७७३ के एक्ट का वैधानिक महत्त्व बहुत बड़ा है। कारण, उसने निश्चित रूप से कम्पनी की राजनीतिक कार्यवाहियों को स्वीकार किया। दूसरा कारण यह है कि उस समय तक जो कम्पनी के निजी प्रदेश सभसे जाते थे<sup>१</sup>, उनमें सरकारी ढाँचा किस प्रकार का हो, यह निश्चित करने के लिए पार्लियामेंट ने अपने अधिकार पर पहली बार जोर दिया। तीसरा कारण यह है कि भारतीय सरकार का ढाँचा बदलने के लिए पार्लियामेंट ने जो बहुत से एक्ट बनाए उनमें यह सबसे पहला था। सन् १९१९ के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट के आमुख में यह बात अन्तिम रूप से और बड़ी दृढ़ता से स्पष्ट की गई कि भारतवासियों के लिए किस प्रकार का विधान उचित और आवश्यक है, उसे निर्दिष्ट करने और लागू करने का एक-मात्र अधिकार पार्लियामेंट को है।

सन् १७७३ में 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' और 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स', गृह सारकार (होम गवर्नमेंट) के अंग थे। डाइरेक्टर्स की कुल संख्या २४ थी। प्रतिवर्ष इनका चुनाव होता जिसमें ५०० पाँड के साझेदार मत दे सकते थे और २००० पाँड के साझेदार खड़े हो सकते थे। नीति की दृढ़ता, स्थिरता और क्रमबद्धता की दृष्टि से डाइरेक्टर्स का कार्य-काल छोटा था। उनको पुनर्निर्वाचन की दृष्टि से बहुत से प्रोप्राइटर्स को प्रसन्न रखना पड़ता था और इस प्रकार वे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के अनुचित प्रभाव से दबे रहते थे। १७७३ के एक्ट ने उन्हीं प्रोप्राइटर्स को अधिकार दिया जो निर्वाचन-तिथि से १२ महीने पहले से साझेदार हो और जिनका हिस्सा १००० पाँड हो। इस एक्ट ने निर्देशको (डाइरेक्टर्स) का कार्य-काल बढ़ाकर ४ वर्ष कर दिया। उनमें से चतुर्थांश अपनी अवधि समाप्त करके प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते। इस एक्ट में डाइरेक्टर्स को यह कहा गया कि सिविल और सैनिक विषयों पर सपरिषद् गवर्नर-जनरल के जो पत्र या सुझाव आवें उन्हें राज्य-मन्त्री के सामने रखा जाय और आय-व्यय व्यवस्था के संबंध में जो पत्रादिक हो उनकी प्रतियाँ ट्रेजरी (अर्थ-विभाग) के सामने रखी जायें। भारत की सारी सरकारों को, निर्देशको के आदेशों का पूरी तरह पालन करना

१. कुछ मान्य और प्रभावशाली व्यक्तियों के अनुसार सन् १७७३ का एक्ट एक उबरदस्ती का अधिनियम था जिससे एक व्यक्तिगत संस्था के अधिकारों और उसकी सम्पत्ति पर सत्क्रमण होता था।

या और कम्पनी के हितों से सम्बन्धित सारे विषयों पर उन्हें बराबर सूचित रखना था ।

एक्ट बनने से पूर्व तीनों प्रेसिडेन्सियाँ एक-दूसरे से पूषक् और स्वतंत्र थीं । उनका लन्दन में बोटें ऑफ डाइरेक्टर्स से सीधा संबंध था । सन् १७७३ के एक्ट ने भारत के एकीकरण के लिए पहला पग उठाया । उनमें बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी के लिए एक गवर्नर-जनरल और चार सदस्यों की एक परिषद् नियुक्त की । इनको "उक्त प्रेसिडेन्सी की सिविल और सैनिक सरकार पर वे सारे अधिकार दिये जो पहले गवर्नर और परिषद् को प्राप्त थे ।"<sup>१</sup> इस प्रेसिडेन्सी में तत्कालीन रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे । साथ ही गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् को मद्रास, बम्बई और बेंगलूर<sup>२</sup> प्रेसिडेन्सियों पर सरकारों व्यवस्था, युद्ध छेड़ने और सन्धि करने के क्षेत्र में नियंत्रण और निरीक्षण करने का अधिकार दिया । किसी असाधारण परिस्थिति में अथवा लन्दन से निर्देशकों के आदेश होने पर ही उपर्युक्त नियम का अपवाद हो सकता था । सपरिषद् गवर्नर को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया । साथ ही उन्हें यह हिदायत भी दी गई कि वे कम्पनी की सरकार, काम या उसके हितों से संबंध रखने वाली सारी बातों से, साथ ही अपने क्षेत्र में बनने वाले सारे नियम-उपनियमों से सपरिषद् गवर्नर-जनरल को परिचित रखें । उत्पन्न करने वाले सपरिषद् गवर्नर को, सपरिषद् गवर्नर-जनरल अधिकार-च्युत कर सकता था ।<sup>३</sup>

एक्ट में पहले गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के चार सदस्यों का नाम दिया गया था । गवर्नर-जनरल के पद के लिए वारेन हेस्टिंग्स का नाम था और परिषद् के लिए लेफ्टिनेंट-जनरल क्लेवरिंग, जार्ज मॉन्टगु, रिचर्ड वॉल और फिलिप फ्रैंसिस का । इनको पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था । बोटें ऑफ डाइरेक्टर्स<sup>४</sup> द्वारा आपत्ति और प्रतिनिधित्व करने पर हिंड्र मैजेस्टी (इंग्लैंड-नरेश) द्वारा ही इनको पद-च्युत किया जा सकता था । पहले पांच वर्ष बाद बोटें ऑफ डाइरेक्टर्स को नियुक्तियाँ करने का अधिकार था ।

१ Clause VII, East India Company Act, 1773 (Geo. III, c 63)

२. बेंगलूर या माड्रैसो फोर्ट नुमात्रा में है । १८२४ की लन्दन-संधि के अनुसार यह हॉलैंड वालों को सौंप दिया था । Footnote 1, page 46, Ilbert Historical Survey.

३. Clause IX of the East India Company Act 1773

४. Clause X of the Act.

प्राधिकार समुच्चय रूप से गवर्नर-जनरल और परिषद् में निहित था। किसी विषय पर निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत का नियम था। परिषद् के किसी सदस्य की अनुपस्थिति, पद-च्युति अथवा मृत्यु की दशा में बराबर मन होने पर गवर्नर-जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था।

सपरिषद् गवर्नर-जनरल को कम्पनी की फोर्ट विलियम की बस्ती और उसके आधीन फ़ैक्ट्रियो और अन्य स्थानों की सुव्यवस्था और सिविल सरकार<sup>१</sup> के लिए ऐसे सारे नियम, अधिनियम, अध्यादेश (Ordinances) बनाने और जारी करने का अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के कानूनों के विरोध में न हों। यह नियमादि सर्वोच्च न्यायालय की सहमति और स्वीकृति से वहाँ पर निबधित होने और प्रकाशित होने पर ही लागू समझे जाते। भारत या इंग्लैण्ड के किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की प्रार्थना पर सपरिषद् इंग्लैण्ड-नरेश को उनको रद्द कर सकता था।<sup>२</sup>

१७७३ के एक्ट ने हिज मैजैस्टी (इंग्लैण्ड-नरेश) की चार्टर द्वारा फोर्ट विलियम पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया। इसमें एक प्रधान न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते जो इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड के पाँच वर्ष से अधिक अनुभव वाले बैरिस्टरो में से हिज मैजैस्टी द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जाते। इस न्यायालय को दीवानो, फौजदारी, जल-सेना सबधी और धर्म-सबधी क्षेत्रों में न्याय करने का अधिकार दिया गया। उसे सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से सगत वेतन पर क्लर्क और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के ही अधीन सारे सरकारी कागज, प्रमाण-पत्र और अभिलेख रखने की व्यवस्था थी।<sup>३</sup> उसे न्याय करने और चार्टर द्वारा दिये गए अधिकारों को व्यवहार में लाने के लिए विधि-नियम बनाने का अधिकार था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहने वाली सारी ब्रिटिश प्रजा इस न्यायालय के क्षेत्र में थी। हिज मैजैस्टी की इस प्रजा के किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध उसे अपराध, दुर्व्यवहार, अन्याचार के आरोप और अभियोग पर न्याय करने का अधिकार था।<sup>४</sup> बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहने वाले किसी 'देशी आदमी' से ५०० रुपये से अधिक की लिखित लेन-देन के सबंध में झगडा होने पर,

१. Clause XXXVI of the Act.

२. Clause XXXVI of the Act

३. Clause XIII of the Act

४. Clause XIV of the Act.



यदि लेखे में न्यायालय में विवाद ले जाने की शर्त हो तो, सर्वोच्च न्यायालय हिड मैजेस्टी की प्रजा के अभियोगों और उनकी कार्यवाहियों को सुन सकता था और उन पर निर्णय कर सकता था। 'निवासियों' के विरुद्ध दूसरे सिविल अभियोगों के बारे में (अर्थात् उन अभियोगों में जब वादी और प्रतिवादी में झगडा होने पर विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की शर्त न हो) न्यायालय का क्या अधिकार होगा इस सम्बन्ध में एक्ट में कोई निर्देश नहीं है। साथ ही निवासियों के ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध अभियोगों के बारे में भी एक मौन है। न्यायालय का अधिकार मौलिक अभियोगों का भी था और असील सुनने का भी।

कलकत्ते में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के पक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अभियोगों का निर्णय करता। उसकी अपील सपरिपद् इयलंड-नरेश से की जा सकती थी।

गवर्नर-जनरल अथवा उसकी परिपद् के किसी सदस्य के किसी अपराध के विरुद्ध न्यायालय को कोई आक्षेप या अनियोग सुनने या निर्णय करने का अधिकार नहीं था। बगाल, बिहार अथवा उड़ीसा में उनमें से किसी के द्वारा राजद्रोह अथवा भयंकर अपराध उत्पन्न किए अपवाद थे। गवर्नर-जनरल, उसकी परिपद् के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी काम या न्यायालय में चलने वाले किसी अनियोग के सिलसिले में बन्दी नहीं बनाए जा सकते थे। यह छूट केवल सिविल अभियोगों के ही लिए थी।

२६ मार्च १७७४ के अधिकार-पत्र द्वारा ऐसा न्यायालय बनाया गया। सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट सहायक न्यायाधीश नियुक्त किये गए।

गवर्नर-जनरल, उसकी परिपद् के सदस्य और उक्त न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया और उनका यह कर्तव्य था कि वे फोर्ट विलियम की बस्तियों और उससे अधीन फौकियों के लिए शांति-व्यवस्थापकों की तरह वर्ष में चार बार अधिवेशन करें और अगिलेख-न्यायालय का काम करें।

सन् १७७३ के एक्ट ने भारतीय विधान में उपर्युक्त सुगोचन करने के अतिरिक्त इस बात का भी प्रयत्न किया कि भारत में कर्मचारियों में से रिदवतखोरी और दूसरी बुराइयाँ दूर हो जायें।

एक्ट ने गवर्नर-जनरल, उसकी परिपद् के सदस्यों और न्यायालय के न्यायाधिशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार की भेंट लेने, आर्थिक पुरस्कार लेने और (यूनाइटेड कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त) किसी व्यापार

और सोदे में सम्मिलित होने को मना कर दिया।<sup>१</sup> “कोई सरकारी सिविल अथवा सैनिक कर्मचारी अथवा यूनाइटेड कम्पनी का कर्मचारी भारत के किसी राजा, नवाब या उसके मंत्री या प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई भेंट, उपहार अथवा पुरस्कार नहीं लेगा।”<sup>२</sup> इस आदेश का उल्लंघन करने वाला को दंड में, प्राप्त हुए धन का, दूना धन देना होता और उसे भारत से हटाकर इंग्लैंड भेज दिया जाता। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मालगुजारी लगा देने वाले, निरीक्षण करने वाले या और दूसरे ब्रिटिश नागरिक कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते थे। कोई ब्रिटिश नागरिक १२% ध्याज से अधिक दर ऋण नहीं दे सकता था। कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों पर, जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा सर्वसाधारण के प्रति विश्वास-घात, सार्वजनिक धन अथवा सम्पत्ति के गबन, अथवा कम्पनी को धोखा देने के दोषी ठहराए जाते, जुर्माना किया जा सकता था और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था या इंग्लैंड भेजा जा सकता था। यदि कोई गवर्नर-जनरल, गवर्नर-परिषद् का सदस्य, न्यायाधीश एक्ट के विरुद्ध कोई अपराध करता और किसी दुर्व्यवहार अथवा अपराध का दोषी कहा जाता तो इंग्लैंड के राजकीय पत्र द्वारा उसके अभियोग का निर्णय करके उसको दंड दिया जा सकता था।

गवर्नर जनरल, परिषद् के सदस्यों और न्यायाधीशों को लालच न हो इस उद्देश्य से उनको बड़ा वेतन देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल का वेतन २५००० पाँड प्रतिवर्ष था, परिषद् के प्रत्येक सदस्य का वेतन १०००० पाँड प्रति वर्ष था, मुख्य न्यायाधिपति का वार्षिक वेतन ८००० पाँड था और अन्य न्यायाधिपतियों का वार्षिक वेतन ६००० पाँड था।

( ४ )

जब एक्ट संशोधन के लिए हाउस ऑफ कामन्स के समक्ष आया तो मिस्टर वाउटेन राउज ने कहा कि एक्ट का उद्देश्य तो अच्छा था किंतु उसने जो व्यवस्था की वह अपूर्ण थी। इस अपूर्णता का मुख्य कारण यह था कि पार्लियामेंट को जिस समस्या का हल करना पड़ रहा था वह उसके लिए एक नए ढंग की थी। यह ब्रिटेनवासियों का सामान्य था कि दोष जो कितने ही थे और भयंकर थे, घातक सिद्ध नहीं हुए।<sup>३</sup>

१. Clause XXIII of the Act.

२. Clause XXIV of the Act.

३. उसने (१७७३ के एक्ट ने) ऐसा गवर्नर जनरल बनाया जो अपनी परिषद् के समक्ष अशक्त था, उसने ऐसी कार्यपालिका बनाई, जो सर्वोच्च न्यायालय के

दूसरे पहली बात तो यह थी कि एकट ने सपरिपद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकार-क्षेत्र और पारस्परिक सम्बन्ध का स्पष्ट नहीं किया। गवर्नर जनरल के कुछ अधिकार तो बंगाल के मुगल प्रान्तपनियों के थे जिनको पार्लियामेंट द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए न्यायपालिका पर रोक लगाने के उद्देश्य से पार्लियामेंट ने सपरिपद गवर्नर जनरल के विधान को निषिद्ध करने का असाधारण अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में निहित कर दिया। क्षेत्राधिकार<sup>१</sup> की अस्पष्टता ने बंगाल में धराजकता-जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। सपरिपद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय का झगड़ा चार बातों पर था —

झगड़े की पहली बात तो यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय देश के सारे निवासियों के नाम आज्ञा-पत्र जारी कर सकने और उनके अभियोग मुनने का अपना अधिकार जताते थे। सपरिपद गवर्नर जनरल ने सफलतापूर्वक इसका विरोध किया। परिपद की आज्ञानुसार सिपाहियों के एक अत्ये ने एक न्यायाधिकारी और उसके साधियों को कासीजटा-केस नाम से प्रसिद्ध अभियोग में आज्ञा-पत्र जारी करने से रोक दिया। इंग्लैंड में अधिकारियों ने परिपद के इस व्यवहार पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की सम्बन्ध यह अनुभव करने के कारण कि एकट न्यायालय के विरोध में था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है।<sup>२</sup> न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहाँ मामलों तक सीमित था जिनमें दोनों पक्षों ने झगड़े की दिशा में न्यायालय के समक्ष जाना स्वीकार किया हो। इस कारण न्यायालय को इस बात का कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी अभियोग को बलान अपने सामने लाय।

झगड़े की दूसरी बात थी कम्पनी के मालगुजारी उगाहने वालों के ऊपर क्षेत्राधिकार के बारे में। ये लोग अपने काम के निम्नसिले में ज्यादानी करते। यहाँ न्यायालयों का पक्ष प्रबल था। एकट ने कम्पनी के कर्मचारियों के ऊपर न्यायालय को यह अधिकार दिया था और चाहे कम्पनी के अधिकारियों को यह बात कितनी ही अरुचिकर क्यों न हो, कम्पनी के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और

---

आगे अशक्य थी, ऐसा न्यायालय जिन पर देश की शान्ति और भलाई का कोई दायित्व नहीं था। Report on Indian Constitutional Reform 1918, page 17 से अनूदित।

१ C.L. Anand : Introduction to the History of the Government of India, Part II, page 22.

२ Ilbert : Historical Survey, pages 54 to 56.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७।

कोई दूसरा मार्ग नहीं था। पर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका एक्ट से कोई हल न हो पाता—कौन लोग कम्पनी के सेवक थे? क्या काम करने वाले कम्पनी के आधीन थे? प्रमाण देने और सिद्ध करने का दायित्व किस पर था? उदाहरण के लिए, क्या जमींदार और मालगुज्दार कम्पनी के सेवक थे? न्यायालय के अनुसार वे कम्पनी के सेवक थे। वित्तु स्वयं वे व्यक्ति और कम्पनी के मुख्य अधिकारी न्यायालय का यह मत मानने को तैयार नहीं थे।

झगड़े की तीसरी बात यह थी कि न्यायालय कम्पनी के न्यायाधिकारियों द्वारा सरकारी हैसियत से किये गए कामों के विरुद्ध अभियोग-निर्णय करने का अधिकार जताता था। न्यायालय ने पटना प्रान्तीय परिषद् के अधिकारियों के कुछ कामों के विरुद्ध, जो उन्होंने न्यायाधिकारियों की हैसियत से किये थे, एक भारतीय वादों के पक्ष में क्षति-पूर्ति का निर्णय किया था। कम्पनी के न्यायाधिकारियों को इस प्रकार दंडित करने में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार के अन्तर्गत काम कर रहा था। प्रश्न केवल यह था कि क्या उक्त काम वस्तुतः न्याय-सम्बन्धी कर्तव्य-पालन करने से किये गए थे या नहीं? सर जेम्स स्टीफेंस के मतानुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उचित और नियमानुसार मान्य था।

झगड़े की चौथी बात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय, प्रान्तीय या प्रादेशिक न्यायालयों<sup>१</sup> का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। प्रान्तीय न्यायालयों द्वारा समय पर मालगुजारी न देने वाले गिरफ्तार अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आज्ञा-पत्र (*Writ of Habeas Corpus*) से मुक्त कर दिया। एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक जिले के कोषाध्यक्ष को जो सबन के अपराध में प्रान्तीय न्यायालय की आज्ञानुसार बन्दी था, उपर्युक्त आज्ञा-पत्र से मुक्त कर दिया। इस आज्ञा-पत्र का विरोध करने वाले और प्रान्तीय न्यायालय का पक्ष लेने वाले कम्पनी के न्यायवादी (मुस्तार) को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दिया, “हम तुम्हारी प्रान्तीय परिषद् और उसके प्रमुख को नहीं जानते, हम उसे परी प्रदेश के राजा का भी बन्दी बता सकते हैं।” सर्वोच्च न्यायालय और छोटे न्यायालयों के झगड़े को दूर करने के लिए बारन हेस्टिंग्स ने सर ऐलिनाइम्पी को सदर दीवानी अदालत<sup>२</sup> का भी जज नियुक्त करके उन्हें छोटे न्यायालयों की अपील सुनने और उनका निर्णय दुहरा देने का अधिकार दे

१. इन न्यायालयों के वर्णन के लिए इसी अध्याय का उपभाग ८ देखिये।

२. सदर दीवानी अदालत बंगाल में कम्पनी का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय था। हाईकोर्ट्स-एक्ट ने सदर दीवानी अदालत और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को मिलाकर एक कर दिया।

दिया। किन्तु इस प्रकार इम्पी कम्पनी के सेवक हो गए और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति में यह बात असंगत थी। इम्पी द्वारा सदर दीवानी अदालत के जज के भाते कम्पनी से बहुत बड़ा वेतन स्वीकार करने से यह स्थिति और भी बिगड़ गई।

दूसरी बात यह थी कि १७७३ के एक्ट ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि सर्वोच्च न्यायालय किस विधि (कानून) का प्रतिपादन करे। क्या वह प्रतिवादी के हिंदू, मुसलमान या अंगरेज होने के अनुसार उसके व्यक्तिगत कानून का प्रतिपादन करे या सब मामलों में अंगरेजी कानून को ही मान्यता दे? जी न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे वे अंगरेजी विधि में कुशल थे और उसी परम्परा से सुपरिचित थे। भारतीय कानूनों, रीतियों और परम्पराओं में वे बिल्कुल अपरिचित थे। उनके परिचित होने के लिए वे इच्छुक या उन्मुख भी नहीं थे। वे पूरी तरह अंगरेजी न्यायविधि को काम में लाने लगे। देशवासी घबरा उठे। “आश्चर्य-चकित और डरे हुए बंगाल-निवासी नए न्यायालय की आज्ञा (Decree) जारी करने के लिए कलकत्ते से संवहो मील दूर अंगरेज अमीन और उनके सहायक दल का दृश्य देखते और कुछ समझ न पाते।” इन अमीनों को यहाँ के रीति-रिवाजों का तो पता नहीं था। वे जबरदस्ती स्त्रियों के कमरों में, पूजाघरों में घुस जाते। जिन देव-मूर्तियों की पीठियों से पूजा होती आई थी उनको वे अपवित्र हाथों से खींचकर आज्ञा जारी करने के उद्देश्य से एवत्रित किये हुए सारे सामान के ढेर में डाल देते।<sup>१</sup> इससे बड़ा उद्देग और क्षोभ हुआ। यदि सुपरिपद् गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप न किया होता और पार्लियामेंट ने १७८१ का संशोधन एक्ट न पारित किया होता तो उसके बहुत भयंकर परिणाम होते।

एक्ट में तीसरी दोष की बात यह थी कि गवर्नर जनरल, अपनी परिपद् की दया पर छोड़ दिया गया था। परिपद् के सदस्यों में से केवल एक (मि. बार्वेल) को ही भारतीय शासन का कुछ अनुभव था। दूसरे सदस्यों को भारतीय स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी। कम्पनी और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध धाराएँ लिये हुए वह भारत में आए। शासन के बारे में उन्होंने अपनी योजनाओं और अपने विचारों को उन्होंने पहले से ही निश्चित कर रखा था। उन्होंने एक साथ काम करने और सारी शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने का निश्चय कर लिया था। जब तक यह गुट बना रहा गवर्नर जनरल और बार्वेल भी बेदम थे। उन तीनों

१. C. L. Anand: History of Government in India, Part II, pages 19-20.

का विरोध इतना असावधान और अटल था कि १७७६ में वारन हेस्टिंग्स त्याग-पत्र देने के लिए बड़ी गम्भीरता से सोचने लगे। लन्दन में अपने प्रतिनिधियों को स्थिति के अनुसार त्याग-पत्र देने का उन्होंने अधिकार भी दे दिया। कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और दूसरी नियुक्ति करने की कार्यवाही की। किंतु इसी बीच क्लेवरिंग की मृत्यु हो गई। वारन हेस्टिंग्स ने सुरन्त हो अपने दिये हुए अधिकार को हटा लिया और सर्वोच्च न्यायालय का यह मत ले लिया कि त्याग-पत्र अमान्य था। अब वारन हेस्टिंग्स निर्णायक वोट से उस गुट को हरा सकता था। इस कारण इतने बड़े वेतन के पद को छोड़ने की अब उसे कोई इच्छा नहीं थी। उसे अपने पद पर बने रहने की स्वीकृति मिल गई पर भविष्य में इसकी रोक के लिए १७९३ और १८३३ के पार्लियामेंट एक्ट में नियम बनाकर व्यवस्था कर दी गई। गवर्नर-जनरल का त्याग-पत्र उसी समय मान्य होना अब विलेज द्वारा उसकी पुष्टि हो।

अन्त में कम्पनी की गृह-सरकार के विधान में १७७३ के एक्ट ने जो परिवर्तन किये, वे दोष-रहित नहीं थे। मतदान के लिए बर्हता (Qualification) उठा देने के कारण १२४६ छोटे साक्षीदार मतधिकार से वंचित हो गए और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स पर स्थायी रूप से एक मुट्ठी-भर व्यक्तियों का आधिपत्य हो गया। सन् १७८१ की प्रवर-समिति (Select Committee) की रिपोर्ट के अनुसार : "कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से सम्बन्ध रखने वाले सारे नियमादि, दो सिद्धांतों पर (जो कितनी ही बार भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं) अवलम्बित थे। एक तो यह सिद्धांत कि छोटे समुदाय में कुम्बवस्था और छिन्नता के बिह्व मरुका होती है, दूसरा यह कि सम्पत्तिसालियों का चरित्र दृढ़ और उज्ज्वल होता है।" १ मिस्टर राबर्ट्स कहते हैं कि कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के विधान में परिवर्तन करने वाला संघ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। ३

( ५ )

सन् १७७३ के एक्ट के व्यवहार में आने पर कुछ ही वर्षों में पार्लियामेंट का ध्यान उस के दोषों की ओर आकर्षित हुआ। सन् १७८१ में दो कमेटीयाँ नियुक्त की गयीं। एक को तो भारत में न्याय-व्यवस्था की जाँच करने का काम सौंपा

१. यद्यपि कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के चौथाई सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, किंतु हर बार प्रायः वही लोग फिर चुन लिए जाते थे।

२ Cambridge History of India, Vol V, page 119

३. Roberts - Cambridge History of India, Vol V Chapter X.

गया, दूसरी को पिछले कर्नाटक-युद्ध के कारण और तटवर्ती शासन की दशा पर रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया। पहले कमेटी ने उसी साल अपनी रिपोर्ट दी जिसने पञ्चस्वरूप सन् १७८१ का संशोधक एक्ट बनाया गया।

१७८१ के एक्ट ने १७७३ के एक्ट के कुछ दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया।

इस एक्ट में पहली बात तो यह थी कि कम्पनी के कर्मचारी सरकारी हेंसियस से जो काम करते थे उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल और परिषद् के सदस्या को व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से अपने पदाधिकार से किये जाये के सिलसिले में (बशर्त कि उनकी आज्ञाशा से ब्रिटिश नागरिकों को क्षति न पहुँचती हो) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट मिल गई। इसी प्रकार मालगुजारी बमूल करने वाला को मालगुजारी बमूल करने के मामले में छूट मिल गई। अन्त में, छोटे न्यायालयों के न्यायाधिकारियों की न्याय-कार्य से सम्बन्धित कार्यों के कारण अपराधी नहीं बनाया जा सकता था।<sup>१</sup>

सन् १७८१ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि कम्पनी के सेवका और देशवासियों के ऊपर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया। कलकत्ते के सारे निवासियों पर न्यायालय को अधिकार दिया गया, पर प्रतिवादी का व्यक्तिगत (घर्मगत) कानून से निपट करने का नियम बनाया गया। अपने भारतीय सेवका के नाम-अवसाय आदि के रजिस्टर रखना, कम्पनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। कम्पनी के सेवका, ब्रिटिश अधिकारियों और भारत में रहने वाले अन्य ब्रिटिश नागरिकों पर न्यायालय का अधिकार जमीन या माल के उत्तराधिकार और व्यापार को छोड़कर अन्य दीवानी मामलों में था। यदि कोई व्यक्ति जमींदार है या मालगुजारी देता है, या खेत जोतता है या उसे किसी सेवा या क्षति-पूर्ति के बदले में कुछ पेन्शन या धन मिलता है या जिसे लगान उगाहने के बदले में कुछ सामान मिलता है या उसे वहाँ पर स्थानीय अधिकार मिला है तो केवल इसी कारण वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आ सकता।<sup>२</sup> दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को कम्पनी का सेवक नहीं माना जा सकता।

तीसरी बात जो १७८१ के एक्ट ने स्पष्ट की—वह यह थी कि सर्वोच्च

१. पटना अभियोग के प्रतिवादी सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा वादी की क्षति-पूर्ति के आश्वासन पर मुक्त होते और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सपरिषद इंग्लैंड-नरैस से अपील करने की स्वतन्त्र थे।
२. Ilbert : Historical Survey, page 56.

न्यायालय किस विधि (कानून) का अनुसरण करेगा। एकट ने सुनिश्चित दावों में यह नियम बनाया कि जमीन, लगान या सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अथवा किसी समझौते का निर्णय, यदि दोनों पक्ष मुसलमान हैं तो मुसलमानी विधि और परम्परा से होगा, यदि दोनों पक्ष हिंदू हैं तो हिंदू विधि और परम्परा से होगा, यदि एक मुसलमान और दूसरा हिंदू है तो प्रतिवादी के धर्मगत कानून से होगा। दूसरे शब्दों में विदेशी कानून के स्थान पर प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून के अनुसार निर्णय करने का नियम बनाया गया। साथ ही यह बात स्पष्ट कर दी गई कि न्यायालय को भारतीय धर्म, रीति-रिवाज, परम्पराओं, सामाजिक नियमों में, जिनमें पिता और गृहपति का अधिकार भी सम्मिलित है, साथ ही जाति के नियमों का (चाहे वे सब बातें अगरेजों न्याय के अनुसार असंगत और अपराधपूर्ण ही क्यों न हों) आदर करना चाहिए। साथ ही आज्ञाप्ति और विधि को कार्यान्वित करने में देश के निवासियों की धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं का आदर करने का आदेश दिया गया। उन से सम्बन्ध रखने वाले नियम उपनियमों को राजकीय स्वीकृति के लिए राज्य-मन्त्री के सम्मक्ष रखने को कहा गया।

एकट ने चौथी बात यह की कि उसने सपरिपद् गवर्नर जनरल या उसकी किसी समिति द्वारा छोटे न्यायालयों के निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार माना। ५००० पाँड तक के दीवानी मामलों में सपरिपद् गवर्नर जनरल का निर्णय अन्तिम होता और वह अपील और अभिलेख का न्यायालय था। ५००० पाँड से अधिक के लिए सपरिपद् इंग्लैंड-नरेश से अपील का नियम था, मालगुजारी बसूल करने में जो अपराध हुए हों, यदि उनका दंड मृत्यु या गिरफ्तारी न हो तो ऐसे मामलों में सपरिपद् गवर्नर जनरल मालगुजारी के न्यायालय का काम करता।

अन्त में, १७८१ के एकट ने शान्तीय न्यायालयों और परिपदों के लिए समय-समय पर विनियम बनाने का अधिकार दिया। यदि इन विनियमों को सपरिपद् इंग्लैंड-नरेश दो वर्ष के अन्दर रद्द न कर दे तो ये स्थायी रूप से मान्य होते। यह कोई नया अधिकार नहीं था। स-परिपद् गवर्नर जनरल ने सन् १७७२ में बंगाल में न्याय-संचालन के लिए विनियम बनाए थे। १७७३ के एकट ने सपरिपद् गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार दिया था पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें निषिद्ध कर सकता था। सपरिपद् गवर्नर जनरल और न्यायालय के तीनों सम्बन्ध के कारण १७७३ के एकट के बाद नए विनियम बनाना कठिन हो गया था। अन्त में १७८० में सपरिपद् गवर्नर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति और वहाँ निबन्धन कराए बिना ही विनियम बनाने का निश्चय किया। सन् १७८० में सपरिपद् गवर्नर जनरल ने शान्तीय न्यायालयों



के न्याय-कार्य के लिए अतिरिक्त विनियम बनाए और नियमों की एक दुहराई हुई संहिता (Code) जारी की। इस संहिता और अतिरिक्त विनियमों का सर्वोच्च न्यायालय में न निबन्धन कराया गया और न उनकी स्वीकृति ही ली गई। १७८१ के एक्ट ने सपरिपद् गवर्नर जनरल के इस कृत्य की पुष्टि की और उन्हें इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेने और वहाँ निबन्धन कराने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया।

( ६ )

१७८१ के एक्ट ने सपरिपद् गवर्नर जनरल की स्थिति को दृढ़ किया; एक्ट की धाराओं ने बिबादास्पद प्रश्नों का उसके पक्ष में निर्णय किया। इस एक्ट की स्वीकार करने से पहले जो कमेटियाँ<sup>१</sup> नियुक्त हुई थी उनकी रिपोर्टें भारत में कम्पनी के प्रदेशों की न्यायपालिका और न्याय-व्यवस्था के और उसके शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए निरूपेण रूप से प्रतिबल थी। हाउस ऑफ कॉमन्स ने हेस्टिन्स और इम्पी को वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव रखोकार किये किंतु 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' ने पार्लियामेंट और 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स'<sup>२</sup> की इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें अपने-अपने पदों पर बना रहने दिया। डडास ने जो विरोध में था, ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार इंग्लैंड-नरेश को कम्पनी के प्रमुख सेवकों को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को बहुत बड़े अधिकार सौंपे गए। किंतु इस प्रस्ताव ने स्वीकार होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इससे इतना अवश्य हुआ कि मन्त्रि-मंडल कुछ करने के लिए प्रेरित हो गया।

मन्त्रि-मंडल के विधेयक को फॉर्म ने प्रस्तुत किया और हाउस ऑफ कॉमन्स में वह पहली बार २० नवम्बर १७८३ को पढ़ा गया। उस समय जो

१. उपर्युक्त पुस्तक का पृष्ठ ३५ देखिये (Ilbert : Historical Survey, p. 35)

२. बाद में हेस्टिन्स पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा महाभियोग लगाया गया। वह ऐतिहासिक मुकदमा १३ फरवरी सन् १७८८ से २३ अप्रैल १७९५ तक चला। हेस्टिन्स डूट गया। इसके दो दफ्तों में यह सिद्धांत मान्य हुआ कि "नैतिकता के नियम सब जगह एक-से हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो काम इंग्लैंड में रिश्वतखोरी, अत्याचार या बलात्कार समझा जाता है वह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और शेष समार में कुछ और समझा जाय।" Impeachment of Warren Hastings; Keith's Speeches and Documents on Indian Policy, Vol I, page 144

व्यवस्था थी उसको फॉक्स ने अराजकतापूर्ण बनाया। उसने सुधार के लिए कम्पनी के गृह-सरकार और विदेशों में कम्पनी के कर्मचारियों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने और कम्पनी को सरसकता की राजसत्ता और मन्त्रियों को सौंपने का प्रस्ताव किया। फॉक्स ने 'कोर्टे ऑव प्रोपर्टी' और 'कोर्टे ऑव डाइरेक्टर्स' दोनों को तोड़कर कम्पनी का शासन-संचालन सात कमिश्नरों की एक मंडली को सौंपने का सुझाव रखा। इस मंडली को भारत में कम्पनी के अधिकारियों को नियुक्त करने, पद-व्युत्त करने और साथ ही कम्पनी की आय-व्यय और उसके व्यापार-संचालन का अधिकार देने की योजना थी। इस विधेयक (Bill) का प्रबल विरोध हुआ। ग्रेनविल, पिट, विल्बरफोर्स तथा अन्य व्यक्ति ने इसको तीव्र आलोचना की। फिर भी हाउस ऑव कॉमन्स में २०८ मत पक्ष में और १०२ मत विपक्ष में मिलने के कारण इसको स्वीकृति मिल गई।<sup>१</sup> किंतु हाउस ऑव लॉर्ड्स ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। पिट ने अधिकार पाने पर सन् १७८४ के एक्ट द्वारा भारतीय समस्या का हल करने का प्रयत्न किया। इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के भारतीय शासन की 'गृह'-व्यवस्था में दुहरी सरकार की स्थापना हो गई। इस व्यवस्था में कितने ही दोष थे और छोटी-छोटी बातों में इसमें कितने ही परिवर्तन हुए, पर गदर के बाद इंग्लैंड की राजसत्ता द्वारा भारतीय शासन अपने हाथ में लेने के समय तक मूलतः यही व्यवस्था बनी रही।<sup>२</sup>

### ( ७ )

१७८४ के एक्ट की पूर्वा करने से पहले यहाँ पर सुविधाजनक होना कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो शासन-व्यवस्था स्थापित की थी, उसका एक संक्षिप्त वर्णन कर दिया जाय। १७६५ से पहले बंगाल का नवाब या सूबेदार दीवान और निजाम दोनों के ही काम करता था। निजाम की हँसियत से सेना और दंड-न्यायालय दोनों ही नवाब के आधीन थे, दीवान की हँसियत से मालगुजारी का काम और दीवानी न्याय

१. पिट ने पहला विधेयक १७८४ के आरम्भ में ही प्रस्तुत किया था पर विरोधियों ने, जो बहुमत में थे, उसे अस्वीकार कर दिया। यह बात २५ मार्च १७८४ के विघटन (dissolution) से पहले की है।

२. "पिट के १७८४ के एक्ट से स्थापित दुहरी सरकार, जिसकी कार्य-पद्धति बड़ी उलझी हुई थी और जिसमें रोक-थाम की विशद व्यवस्था थी, मूलतः १८५८ तक बनी रही।" Ilbert : Historical Survey, pages 66 and 67 से अनूद्धित।

उसके आधीन थे। १७६५ में मुगल सम्राट् द्वारा दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिल गई थी। यद्यपि निजामत नाम के लिए अब भी नवाब के हाथों में थी, किन्तु उसका वास्तविक नियंत्रण कम्पनी के हाथों में था—क्योंकि नवाब कम्पनी के हाथों में कठपुतली की तरह था। १७६५ की फरवरी में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई और कम्पनी ने उसके दूसरे अवयव लहरे को गद्दी पर बिठा दिया। इन प्रकार कम्पनी को दीवानी ती सम्राट् से मिली और निजामत सूबेदार से।<sup>१</sup>

आरम्भ में कम्पनी ने दीवानी और निजामत दोनों को पुराने भारतीय ढंगों के ही हाथों में रहने दिया। कम्पनी का ऊपर से नियंत्रण और निरीक्षण था। मुग़लदाबाद का अंग्रेज़ रेज़िडेंट फ्रैंसिस सादरुल्लाह, मुहम्मद रज़ा खाँ द्वारा नारे शासन का निरीक्षण और नियंत्रण करता। मुहम्मद रज़ा खाँ छोटा नाझिम और साथ ही छोटा दीवान था। १७६९ में कम्पनी ने दिल्ली में छोटे भारतीय वर्ग-धारियों का काम देखने के लिए कुछ निरीक्षक नियुक्त किये। १७७० में इन ज़िलानिरीक्षकों के अतिरिक्त मालगुजारी के नियंत्रण के लिए पटना और मुग़लदाबाद में दो बोर्ड बनाए गए। इन मंडलियों (Boards) का, पुराना दीवानी अधिकार प्राप्त करने के नाते, पहले अधिकारियों की तरह, मालगुजारी और न्याय दोनों में क्षेत्र था।<sup>२</sup> इन निरीक्षकों और मंडलियों ने कलकत्ता-सरकार से स्वतन्त्र और जोखिमपूर्ण ढंग अपनाया। इनको कुचल देने के उद्देश्य से १ अप्रैल १७७१ को कलकत्ते में परिषद् ने अपने-आपको राजस्व-कमेटी बनाया और उस नाते से प्रान्तीय छोटे अधिकारियों को अपना पत्र-व्यवहार और लेखा भेजने का आदेश दिया।<sup>३</sup>

वरन हेस्टिंग्स ने १७७२ के वसन्त में दीवानी का काम संभाला। उसने अनुभव किया कि पुरानी व्यवस्था दीयपूर्ण थी। और उससे अन्याय और अत्याचार होता था। उसने कलकत्ते की राजस्व कमेटी और पटना और मुग़लदाबाद की मंडलियों को तोड़ दिया। उसने मालगुजारी-व्यवस्था का फिर से संगठन करने के लिए नए विनियम जारी किये। कलकत्ते में एक सर्वोच्च राजस्व-सभा बनाई गई। इसमें नारे परिषद्, राजस्व बोर्ड की हैसियत से काम करती। हर ज़िले में उगाही का काम करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की व्यवस्था की

१. P. E. Roberts . History of British India, page 159

से सर जेम्स स्टीफ़ेन के एक वक्तव्य का अनुवाद।

२. P. E. Roberts : History of British India, page 159.

३. Monckton Jones Warren Hastings in Bengal, 1772-1774, page 288.

गई। उसने जिला-निरीक्षकों को कलक्टर (उगाही करने वाला) बना दिया और उसके काम की पड़ताल के लिए उसने एक भारतीय नायब दीवान की राजस्व कार्यपालिका में सहायता के लिए नियुक्ति की। कलक्टर सारी आशाएँ जारी करता, उन पर कम्पनी की मुहर होती और सारी निधि उसके हाथों से राज्य-कोष में आती। सारे लेखों का दीवान के यहाँ निबन्धन होता और कलक्ते के राज्य-कोष में उस सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र रिपोर्ट आती।”<sup>१</sup>

“कलक्ते में परिपद्, राजस्व बोर्ड को हँसियत से सप्ताह में दो बार काम करती, कलक्टरों को आवश्यक आदेश देती और लेखों की पड़ताल करके उसको स्वीकार करती।”<sup>२</sup>

१७७२ की इस योजना से कलक्ता की परिपद् पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया। इसी कारण १७७४ में प्रान्तीय परिपदों की व्यवस्था बनाई गई। कई जिलों को मिलाकर कमिश्नरी या डिवीजन बनाये गए। हर कमिश्नरी के लिए एक मुख्य अधिकारी और परिपद् बनाई गई। इस तरह के ६ डिवीजन थे और ६ प्रान्तीय परिपदें थीं। हर डिवीजन में लेखा रखने के लिए और स्थानीय भाषा में अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए दीवान की नियुक्ति की गई और उसके आधीन, पहले की तरह हर जिले में एक नायब दीवान बनाया गया।<sup>३</sup> समय-समय पर जिलों के काम की पड़ताल करने के लिए जिलों में निरीक्षक भेजे जाते। सर्वोच्च परिपद् में मतभेद होने के कारण प्रान्तीय परिपदों का समुचित नियन्त्रण नहीं था। १७७६ में वारन हेस्टिंग्स ने प्रान्तीय परिपदों का फिर से संगठन किया किंतु कलक्ता में सारे अधिकार केन्द्रित करने के अपने अन्तिम सुधार में उसे सफलता सन् १७८१ में ही मिल सकी।

“१७८१ में हेस्टिंग्स राजस्व कार्य में अपना सुधार पूरा कर सका। प्रान्तीय परिपद् और कलक्टर हटा दिये गए और राजस्व शासन चार आदमियों—एड्वॉक, शोर, चार्टर्स और क्रॉफ़्ट्स—की कमेटी को सौंप दिया गया। वह लिखता है—‘उनका कोई नियत वेतन नहीं है। और कोई परिलब्धि (perquisites) न लेने की उन्हें शपथ है। इसके बदले में वे विशुद्ध उगाही का १% कमीशन

१. Monkton Jones : Warren Hastings in Bengal, page 289.

२. Monkton Jones : Warren Hastings in Bengal, page 289.

३. Monkton Jones : Warren Hastings in Bengal, page 291.

अथवा बलकत्ते में जमा किये हुए परिमाण पर दूना कमीशन पायेंगे। इस प्रकार कम्पनी के लिए उमे बहुत बड़ी बचत की आशा थी। इस वर्ष राजस्व में २७ लाख की वृद्धि होगी और व्यय में १२ लाख की बचत होगी, कुल मिलाकर ३९ लाख की प्राप्ति।”<sup>१</sup>

(८)

बारन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी उगाहने के लिए ही पुराने भारतीय ढाँचे का उपयोग नहीं किया बल्कि उसने पुरानी न्याय-व्यवस्था का भी पूरा उपयोग किया। उसके अनुसार भारतीय न्याय और व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त थे। मीकटन जोन्स के शब्दों में, “बारन हेस्टिंग्स के दृष्टिकोण से सबसे आवश्यक बात यह थी कि देशी न्याय-व्यवस्था और लिखित अथवा अलिखित न्याय-नियमों को जिनके बिना सर्वसाधारण अभ्यस्त थे ज्यों-का-त्यों बना रहने दिया जाय।”<sup>२</sup> उसने उस व्यवस्था को पुराने और पूरे रूप में नहीं रहने दिया किन्तु परिवर्तन में विवेक और सूझ से काम लिया। इस उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई जो १७७२ की न्याय-योजना के नाम से परिचित है।

बारन हेस्टिंग्स ने जिले की न्याय और दूसरे कामों के लिए शासन की इकाई बनाया। हर जिले में एक दीवानी और एक दंड-न्यायालय होता।<sup>३</sup> इस उद्देश्य के लिए उसने उस समय की ‘दरोगा अदालत दीवानी’ का जो प्रान्तीय दीवानी के नाम से अधिक प्रसिद्ध थी दीवानी मामलों के लिए उपयोग किया और फौजदारी अदालत का अपराध और नदर-आचार के लिए।<sup>४</sup> हर न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र सुनिश्चित था।<sup>५</sup> जिले का यूरोपीयन कलक्टर स्थानीय दीवानी न्यायालय

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९२।

२. उपर्युक्त पुस्तक के पृष्ठ ३११ से अनूदिन।

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२।

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२-१३ — (i) प्रान्तीय दीवानी अदालत के अधिकार-क्षेत्र के तीन शीर्षक थे — (अ) सम्पत्ति, वाम्पक्षिक अथवा व्यक्तिगत; (ब) उत्तराधिकार, विवाह और जातीय झगड़े, और (ग) ऋण, समझौता, लगान आदि। जमींदारी और तालुकेदारी का उत्तराधिकार इस सूची के बाहर था। उन्हे ममापति और परिषद के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था। (ii) फौजदारी अदालत के अधिकार क्षेत्र के शीर्षक — (अ) हत्या, चक्रेती, चोरी, आदि (ब) बड़े अपराध, जालनाजी, झूठी गवाही, और (ग) मार-पीट, झगडा, व्यभिचार, धान्ति और व्यवस्था को भंग करने वाला कोई काम। सम्पत्ति उध्वन करने अथवा प्राण-दंड देने के लिए बलकत्ते के बड़े न्यायालयों से पुष्टि होना आवश्यक था।

का समापति होता, अथवा प्रान्तीय पारपद् प्रमुख होती। साथ में समापति और परिपद् द्वारा नियुक्त भारतीय दीवान और दूसरे पदाधिकारी होते। फौजदारी न्यायालयों के समापति भारतीय अधिकारी ही होते, दो मौलवी न्याय नियम बताने को होते, अग्रेज-अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार था।<sup>१</sup> जिले के इन न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय न्यायालयों को तोड़ दिया गया। हर परगने में मुख्य किसान (मुखिया) को जहाँ के तहाँ १० रुपये के मूल्य तक के छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया। इन लोगों को दंड देने या जुर्माना करने का अधिकार नहीं था। जिले के नए न्यायालया में स्वयं इन लोगों के विरुद्ध, ठाँले छगे बक्सों में लिखकर शिकायत की अर्जी डाली जा सकती थी।<sup>२</sup>

वारेन हेस्टिंग्स ने जिले के न्यायालयों के ऊपर, अपील के न्यायालय बनाए—कलकत्ते के सदर न्यायालय। सदर दीवानी अदालत में गवर्नर और परिपद् के दो सदस्य होते। इनकी सहायता करने को अर्थ-विभाग का दीवान होता और साथ ही मुख्य कानूनगो होता। सदर निजामत (फौजदारी) अदालत में नाजिम का प्रतिनिधि, एक मुसलमान न्यायाधीश समापति होता जिसे न्याय नियमों पर मुसलमान मौलवियों से सहायता मिलती। समापति और परिपद् को निजामत-अदालत पर निरीक्षण का अधिकार था।

१७७२ की न्याय-योजना से केन्द्र और जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था का फिर से संगठन ही नहीं हुआ बल्कि उसने कुछ साधारण नियम बनाकर न्याय-कार्य को सुधारने का भी प्रयत्न किया। इनमें से मुख्य बातें ये थी—

(१) हर छोटे-बड़े न्यायालय में कार्यवाही का अभिलेख रखा जाय।

(२) अभियोगों के लिए एक अवधि निर्दिष्ट कर दी जिसके बाद पुरानी शिकायतों को फिर से उखाड़ा नहीं जा सकता था।

(३) कानूनी 'चौथ' और बड़े जुर्मानों की प्रथा को तोड़ दिया गया।

(४) साहूकार के अपने ही बाद के विषय में न्यायाधिकार निर्दिष्ट करने के स्वत्व का अवरोध, जैसे अगोदार और कानूनगो के विषय में।

१ Weitzmann: Warren Hastings and Philip Francis, page 60.

२. Monkton Jones: Warren Hastings in Bengal, page 315

(५) विवाद-ग्रस्त सम्पत्ति के मामलों को तय करने के लिए मध्यस्थ द्वारा निर्णय करने को प्रोत्साहन ।<sup>१</sup>

भारत हेरिडियम को इस व्यवस्था से, इस बात के अतिरिक्त कि जलद्वारों के हाथों में इनकी शक्ति केन्द्रित हो गई थी, सतोष था । सन् १७७४ में प्रांतीय परिषद् बनाकर यह दोष दूर कर दिया गया । लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है प्रांतीय और जिला-न्यायालयों के काम में १७७३ के एक्ट के अनुसार स्थापित किया हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप होता रहता था । फिर भी यह व्यवस्था चली रही । विनियमों की नई संहिता में, जो १७८० में जारी की गई, इस व्यवस्था को स्थान दिया गया । १७९३ में दुहराकर जो संहिता बनाई गई उसमें भी इसकी पुष्टि की गई ।

## तीसरा अध्याय द्वैध शासन का युग

(१)

एक विविध संयोग से कम्पनी ने द्वैध या दोहरी शासन-व्यवस्था की स्थापना द्वारा भारत में प्रादेशिक प्रभुता की प्राप्ति भी किया और खो भी दिया । कनाइब ने १७ अगस्त १७६५ के फरमान से, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमाएँ मिली थी और इस प्रकार दोहरी शासन-व्यवस्था<sup>२</sup> की स्थापना हुई थी, कम्पनी के लिए प्रादेशिक अधिकार प्राप्त किया था । १७८४ के एक्ट द्वारा पिट ने दो प्राधिकारी—‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ और ‘बोर्ड ऑफ टाईरेक्शंस’ बनाए और कम्पनी को भारतीय मामलों की व्यवस्था के सर्वोच्च और अन्तिम नियंत्रण से वंचित कर दिया ।

१७८४ के एक्ट ने ‘प्रिवी काउंसिल’ के सदस्यों में से छह कमिशनर नियुक्त

१. Monkton Jones: Warren Hastings in Bengal, page 314.

२. वह व्यवस्था “जिसमें कम्पनी को देश के राजस्व पर, सैन्य शक्ति पर पूरा अधिकार था, किन्तु न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, न्यायालय के द्वारा दूसरे हाथों में छोड़ दिया गया था ।” Ilbert : Historical Survey, page 38.

करने के लिए हिज़ मैजिस्टी (इंग्लैंड नरेश) को प्राविष्ट<sup>१</sup> किया। इनमें से एक 'चान्सलर ऑफ दि एम्पवेयर' (अर्थ-मन्त्री) होता और एक कोई सा राज्य-मन्त्री होता। 'वॉर्ड ऑफ कंट्रोल', जो उक्त कमिशनरो की मडली से बनाया गया,<sup>२</sup> 'वोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स' के भी ऊपर था। व्यवहारत 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' का अतिक्रमण कर दिया गया।<sup>३</sup> यह बोर्ड मन्त्रि-मंडल से अनु-बन्धित था और शासन में प्रत्येक परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता। "उक्त राज्य-मन्त्री, उसकी अनुपस्थिति में उक्त अर्थ-मन्त्री, दोनों की ही अनुपस्थिति में, उक्त कमिशनरा में से अधिकार में सबसे बड़ा सदस्य बोर्ड का समापति होता।"<sup>४</sup> 'यदि उपस्थित सदस्य में मतभेद होता और दोनों पक्ष बराबर होते तो वह निर्णायक वोट दे सकता था।'<sup>५</sup> एक्ट के अनुसार गण-भूति (Quorum) के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। इन कमिशनरा का कोई वेतन नहीं था, वे कोई अनुग्रह<sup>६</sup> नहीं कर सकते थे। किंतु सुदूरपूर्व में ब्रिटिश प्रदेशों के राजस्व, वहाँ की सैनिक एवं असैनिक सरकार से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक कार्य और प्रत्येक विषय में इन कमिशनरो को निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार था। इस बोर्ड को कम्पनी के हर एक नागर, जाते और अभिलेख<sup>७</sup> देखने का अधिकार था। बोर्ड के माँगने पर वाञ्छित उदाहरण अथवा उसकी

१ Clause 1 Act of 1784, Keith Speeches and Documents, vol I, page 96

२ इसका नाम था — "Commissioners for the Affairs of India" 18873

३ 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स' की कार्यवाही की 'वोर्ड ऑफ कंट्रोल' की पुष्टि मिलने के बाद 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' उसको रद्द नहीं कर सकता था। Herbert Historical Survey, page 45 और C L Anand History of Government in India, part II, page 27

४ व्यवहारत अधिकार में बड़ा सदस्य समापति होता है।

५ Clause II of the Act, Keith Speeches and Documents, vol 1, page 96 1918 के

६ Clause 4 उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९७ .०९.

७ Clause XVII of the Act "इस एक्ट की चिक, पृष्ठ १०२ इस बोर्ड को उक्त यूनाइटेड कम्पनी के किसी कर्मचारी के का अधिकार नहीं होगा" उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १०२ से



प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती थी।<sup>१</sup> कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स या उसकी किसी कमेटी द्वारा, भेजे हुए आदेश या पार्स हर्ड रिपोर्ट या उसकी कार्यवाही और प्रस्ताव आदि सभी को यह बोटें देना सूचना था।<sup>२</sup> बोटें को डाइरेक्टर्स के आदेशों का संशोधन करने का अधिकार था। उन दशा में डाइरेक्टर्स अपने भारत के अधिकारियों को संशोधित आदेश ही भेज सकते थे। बाद में १८५८ के एक्ट में जो अधिकार भारत-मन्त्री को दिये गए बोटें को लगभग वे सभी अधिकार कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स और भारत में कम्पनी के अधिकारियों के ऊपर प्राप्त थे। वस्तुतः १७८४ के एक्ट का छठा खंड (Clause VI) बाद के विधानों में लगभग उन्हीं शब्दों में दोहरा दिया गया है।<sup>३</sup>

साधारणतया 'बोटें ऑफ कंट्रोल' अपने आदेश और निर्देश, बोटें ऑफ डाइरेक्टर्स के द्वारा ही भेजता। किन्तु कुछ मामलों में कम्पनर अपने आदेश और निर्देश गुप्त कमेटी को भेज सकते थे। यह गुप्त कमेटी डाइरेक्टर्स द्वारा अपने-आप में से ही चुने हुए<sup>४</sup> तीन सदस्यों की होनी। कमेटी उन आदेशों को दूसरों को बताए बिना ही भारत की सम्बन्धित सरकारों के पास भेज देती।<sup>५</sup>

यद्यपि डाइरेक्टर्स-मंडल का भारत-सरकार पर सन् १८५८ में इंग्लैंड की राजसत्ता के हाथों में आने तक बहुत बड़ा प्रभाव बना रहा किन्तु जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है अन्तिम नियन्त्रण इस नए बोटें के हाथों में आ गया। सन् १९१८ में भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में यह लिखा गया है—“हमको इस परिणाम पर नहीं पहुँचना चाहिए कि 'बोटें ऑफ कंट्रोल' के समाप्ति की प्रभुता के कारण डाइरेक्टर्स के हाथों में कोई वास्तविक नियन्त्रण नहीं रहा। उनकी रीति अब भी गुढ़ थी, साधारणतया उपपन्न करने (Initiative) का अधिकार अब भी उन्हीं के हाथों में था; अनुभव-ज्ञान उन्हीं के पास था। यद्यपि वैधानिक उत्तरदायित्व सरकार पर था किन्तु अन्त तक

१ Clause VI of the Act, Keith : Speeches and Documents, vol I, page 97.

२ Clause XI उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९८.

—e II Sub-section 2 of the Consolidated Govt.

३ Monro's Act. Bose : Working Constitution of India, page 14.

४ वह क्लause VI of the Act, Keith : Speeches and Documents, vol. I, page 101.

न्यायालय V उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १००

शासन की अधिकांश छोटी-छोटी बातों पर, उनके विस्तार पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव बना रहा ।<sup>१</sup>

१७८४ के एक्ट से भारत का एकीकरण एक पग और आगे बढ़ा । एक्ट ने बम्बई और मद्रास के सपरिषद् गवर्नरों के ऊपर सपरिषद् गवर्नर-जनरल के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित किया । एक्ट के खंड ३१ में यह कहा गया है कि सपरिषद् गवर्नर-जनरल को, “विभिन्न प्रेसिडेंसियों और वहाँ की सरकारों का राजस्व, सेना, भारतीय सत्ताओं से युद्ध और संधि के मामलों में अथवा डाइरेक्टर्स मंडल से निर्दिष्ट विषयों में निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देश करने का अधिकार होगा ।”<sup>२</sup> सपरिषद् गवर्नर-जनरल के ऊपर डाइरेक्टर्स मंडल को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था ।

१७८४ के एक्ट से गवर्नर-जनरल और गवर्नरों की परिषदों के विधान में भी परिवर्तन हुआ ।<sup>३</sup> हर परिषद् के तीन सदस्य होने, उनमें सेनापति भी एक सदस्य होता । नियुक्तियाँ अब भी कौर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के हाथों में थीं किंतु राज-सत्ता की कम्पनी के सेवकों को पद-व्युत्तर करने या वापिस बुलाने<sup>४</sup> का अधिकार था । कम्पनी के प्रदेशों को पहली बार “ब्रिटिश भारतीय प्रदेश”, “इस (ब्रिटिश) राज्य के प्रदेश” कहा गया ।<sup>५</sup>

कम्पनी को अपनी व्यवस्था ठीक करने को कहा गया । साथ ही राज्य-विस्तार और विजय की योजनाओं को छोड़ देने और ‘अनावश्यक सेवकों का अवच्छेद’ करने को कहा गया । “भारत में राज्य-विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के प्रतिकूल” बताया गया ।<sup>६</sup>

अन्त में १७८४ के एक्ट ने इस बात की भी पहली ही अच्छी व्यवस्था की कि जो अप्रैज भारत में अपराध करें उन पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाकर न्यायानुसार दंड दिया जाय । ऐसे अभियोगों के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया गया । इसमें तीन जज और चार लार्ड और छ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते ।

१. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918 के पृष्ठ १८, पैराग्राफ ३१ का अनुवाद ।

२. Clause XXX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०९.

३. Clause XVIII and XIX of the Act उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०२

४. Clause XXII उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०४

५. Clause I उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९६

६. Clause XXXIV उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १११.

सन १७८४ के एक्ट से मुख्य बात यह हुई कि देश के शासन का वास्तविक अधिकार 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के समापति को दे दिया गया।<sup>१</sup> इसके बर्द कारण थे : पहले समापति सर हेनरी डण्डास पिट के मित्र थे और वे आरम्भ से ही बोर्ड के अधिकारों को मनवा सकते थे। डाइरेक्टर्स, जिनकी साधारण आय तो कम थी और जिनकी मुख्य प्राप्ति अनुग्रह करने (नौकरी आदि दिलाने) में थी, बोर्ड को इस डर से अप्रसन्न नहीं कर सकते थे कि वही उनके रहें-सहें अधिकार भी न छीन लिये जायें। बोर्ड के समापति को, पार्लियामेंट को बोर्ड वापिक हिसाब नहीं देना पड़ता था और वह लगभग उत्तरदायित्व निहित था।<sup>२</sup> यद्यपि पिट ने इस बात का ध्यान रखा था कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की स्थिति और प्रतिष्ठा ज्यों-की-त्यों बनी रहे किन्तु उपर्युक्त कारणों ने बोर्ड और उसके समापति को बहुत शक्तिशाली बना दिया।<sup>३</sup>

इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन एक निरन्तर बदलती रहने वाली परिपद में निहित हुआ।<sup>४</sup> वारन हेस्टिंग्स के उपाधिकाारी मिस्टर मैजिस्ट्रेट के दुर्बल शासन में इस व्यवस्था ने दोष विशेष रूप से स्पष्ट हुए। मिस्टर मैजिस्ट्रेट सबसे पुराने और अधिकार में सबसे बड़े अधिकारी थे, किन्तु उनमें और कोई योग्यता नहीं थी। बाद में जब लॉर्ड क्लैवेलिस से<sup>५</sup> गवर्नर-जनरल बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन करने और अपने अधिकार

१. यद्यपि एक्ट ने अधिकार बोर्ड को मयुक्त रूप में दिया था किन्तु वह समापति के हाथों में केन्द्रित हो गया। प्रो डॉडवेल लिखते हैं, "यह परिवर्तन बिना किसी दुर्भावना के नहीं हुआ। डडाम आरम्भ से ही प्रमुख स्थिति में था। यह बात सबको, विशेषकर लॉर्ड सिडनी को, बुरी लगी। उन्होंने भारत में स्कॉटलैंडवासियों के प्रति डडाम के भेद-भावपूर्ण व्यवहार पर आपत्ति की। सन् १७८६ में इस परिवर्तन को कानूनी रूप देने का प्रयत्न किया गया। डडाम ने कहा कि इस प्रकार आपका सेवक केवल वस्तुतः ही नहीं बल्कि घोषित रूप में भी भारत के लिए राज्य-मन्त्री माना जायगा। किन्तु इस कार्यवाही को कानूनी रूप देने के लिए समापति को अपने साधियों की स्वीकृति अनिवार्य थी।

२. मन्नि-मडल में उसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व पर थी।

३. *Thalore Indian Administration to the Dawn of Responsible Govt.*, page 42

४. *Chesney - Indian Polity*, page 19

५. डडाम ने लॉर्ड क्लैवेलिस को भारतीय शासन के लिए ससार-नर में सब

बढ़ाने के लिए कहा। फलतः १७८६ में एक एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार असाधारण स्थिति में गवर्नर-जनरल—साथ ही गवर्नरों को भी—अपनी परिपद की स्वीकृति लिये बिना ही निर्णय करने का अधिकार दिया गया। साथ ही लार्ड कॉर्नवालिस को स्वयं ही गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों पदों का काम सँभालने का प्राधिकार मिला। एक्ट ने यह नियम भी बनाया कि सेनापति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जिसने भारत में कम से कम बारह वर्ष तक सेवा न की हो, गवर्नर-जनरल या उसकी परिपद का सदस्य नियुक्त न किया जाय।

पिट ने सन् १७८४ के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डाइरेक्टर्स के अलग-अलग अधिकारों को जान-बूझकर निश्चित नहीं किया था और विरोध दान्त करने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिस के दोहरे अर्थ हो सकते थे। किंतु जब विधेयक स्वीकार होकर एक्ट बन गया तो डाइरेक्टर्स को प्रसन्न रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई और मजिस्ट्रल ने अपना वास्तविक उद्देश्य प्रकट करना आरम्भ किया। फॉक्स की ही तरह पिट का उद्देश्य भी यही था कि कंपनी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाय और भारतीय शासन का वास्तविक नियंत्रण कमिशनरों के बोर्ड को सौंप दिया जाय। इसी दृष्टि से जोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारों को एक्ट में साधारण किंतु विस्तृत रूप में रखा गया था। आरम्भ से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने दूढ़ और कठोर ढंग अपनाया और डाइरेक्टर्स के ऊपर अपनी श्रेष्ठता और अपना अधिकार जताया। अगले तीन वर्षों में कई बार मतभेद हुए। यदि कभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को झुकना भी पड़ा तो यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया कि डाइरेक्टर्स की जो कुछ भी सत्ता थी वह केवल श्रेष्ठतर शक्ति के निष्पत्ति यत्र के ही रूप में थी। सन् १७८४ में एक गम्भीर और महत्वपूर्ण मतभेद हुआ। दोनों मंडलों के बीच का यह मतभेद १७८८ के अभिधायक (Declaratory) एक्ट ने समाप्त किया।

से उपयुक्त व्यक्ति बताया "यहाँ किसी खोई सम्पत्ति की क्षति-पूर्ति नहीं करनी थी, किसी लालच की भूल नहीं मिटानी थी, किसी दरिद्री व्यवस्था नहीं करनी थी, किन्हीं भूखे आधितों का मुँह नहीं भरना"।  
Quotation by Thakore from Mill & Wilson. History of India, Vol. V, Chap. IX, in Indian Administration from the Dawn of responsible Government

44 का अनुवाद।

१ Ilbert : Historical Survey, pages 67-68.

•मीमालय

‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ ने कम्पनी के व्यय पर (घाटी) ब्रिटिश सेना को भारत भेजा था। डाइरेक्टर्स ने बोर्ड के इन अधिकार पर आपत्ति की। बोर्ड ने सन् १७८४ के एक्ट के अन्तर्गत अपना यह अधिकार बताया और फलतः भारत में चार शाही सैन्य-दल भेजे और उनका व्यय भारतीय राजस्व के हिस्से में डाल दिया। डाइरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और साथ ही सैन्य-दल को भेजने की आवश्यकता और उनसे औचित्य पर भी आपत्ति की। उन्होंने सन् १७८१ के एक्ट की उन धाराओं का सहारा लिया जो रद्द नहीं हुई थीं। इनके अनुसार कम्पनी उन्हीं सैन्य-दलों का व्यय देने को बाध्य हो जा सकती थी जिनकी कि उसने स्वयं मांग की हो।

पिट ने ऐसे विवादों को सुझा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से एक अधिषायक विधेयक प्रस्तुत किया। उसके अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अन्तिम अधिकार दे दिया गया। डटास के मत से इस अधिकार के बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक निरर्थक सत्ता थी।<sup>१</sup> उस विधेयक का विरोध किया गया। यह कहा गया कि व्यय करने के अनियमित अधिकार का अपेक्षित यह होगा कि कम्पनी की व्यावसायिक निधि राजनीतिक उद्देश्यों<sup>२</sup> के कारण बिलकुल खल हो जायगी। भारत में सैन्य-दल भेजने के विरुद्ध दो आपत्तियाँ की गईं। एक तो यह कि कम्पनी को जिनगी सेना की आवश्यकता थी, उतनी उसके पास मौजूद थी। साथ ही इंग्लैंड से सेना भेजने की अपेक्षा, कम्पनी के लिए भारत में ही सेना तैयार करने में कम व्यय होता था। दूसरी आपत्ति यह थी कि राज-सत्ता के लिए ऐसी सेना बनाए रखना, जिसके लिए पार्लियामेंट से व्यय स्वीकार न किया गया हो, अवैधानिक था। इसके अतिरिक्त शाही सेना भेजने से भारत में सैन्य-संगठन का काम बढ़ित हो जाता, क्योंकि इस तरह कम्पनी की सेना और शाही सैन्य-दल एक मूल में आ जाते थे।

पिट और डटास ने इन आपत्तियों से मुलजने का प्रयत्न किया। प्रधान मंत्री ने समस्त राजकीय स्थल और जल-सेना को असतोपजनक स्थिति की ओर धेतरके वैधानिक प्रश्न को समाप्त कर दिया। “वर्तमान प्रश्न पर विचार करने में होगा, वैधानिक कानून ने महत्वपूर्ण वित्तु दोषयुक्त नाग की ओर ध्यान पेंत करना और उसका सुधार करना।<sup>३</sup> भारत में दो प्रकार के सैनिक संगठन २. <sup>१</sup>नाई की पिट ने स्वीकार किया और उसने पार्लियामेंट के भवन में कहा

३. The

Res. History of India, Vol V, page 78

४. Chesil, पृष्ठ ७५

५. डटास पुस्तक, पृष्ठ ७९.

कि भारत में सारी सेना (इंग्लैंड की) राज-सत्ता के ही आधीन होनी चाहिए और साथ ही यह भी कहा कि इस सुधार के लिए योजना तैयार हो रही है। सच बात तो यह थी कि पिट और डडास दोनों ही भारत की सारी शक्ति राज-सत्ता अर्थात् मन्त्रि-मंडल को हस्तान्तरित करने पर तुले हुए थे। पार्लियामेंट और डाइरेक्टर्स की स्पष्ट इच्छा के विरोध में, उनकी नीति भारत में राजनीतिक शक्ति के विस्तार के पक्ष में थी।

मन्त्रि-मंडल द्वारा इस प्रकार अनन्त शक्ति हथियाने के प्रयत्न से काफी विरोध उठ खड़ा हुआ। संदेह के कारण उसके प्रति सतर्कता भी बड़ी। उन्हें शान्त करने के उद्देश्य से पिट ने कुछ ऐसी धाराएँ जोड़ दीं जिनसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कुछ अधिकार कम होते थे। बोर्ड एक सीमा के अन्दर ही सैन्य-बल भेज सकता था। बोर्ड को पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाने अथवा किसी सेना के बदले उपदान देने का अधिकार नहीं था जब तक कि पार्लियामेंट और डाइरेक्टर्स की स्वीकृति न हो। डाइरेक्टर्स को पार्लियामेंट के सामने कम्पनी के आय-व्यय का वार्षिक लेखा रखना होना था।

इस प्रकार १७८४ के एक्ट का अर्थ बताने का प्रयत्न समाप्त हुआ। पार्लियामेंट का यह काम नहीं है कि वह नियमों का अर्थ बताए, यह काम न्यायपालिका का है। किंतु अभिधायक विधेयक में यही उल्टी बात है। उसके अनुसार वह नियम, जिसको धाराओं से सीमित किया गया हो अथवा वह नियम जिसको इस प्रकार सीमित न किया गया हो, दोनों एक ही बातें हैं।<sup>१</sup>

## (२)

लॉर्ड क्लैवेलैंड जब भारत आए तो वह गवर्नर-जनरल भी थे और सेनापति भी थे। कुछ विशेष स्थितियों में किंतु पूर्ण सद्बुद्धि के साथ, उन्हें अपनी परिपक्वता को उपेक्षा करने का अधिकार भी था। वह टीपू के साथ एक बड़ी लड़ाई में पराजित हुए। इस लड़ाई का उन्होंने स्वयं बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया। उसमें मालाबार और सलेम के वर्तमान जिले और मदुरा जिले के कुछ भाग जीतकर मद्रास प्रेसीडेंसी में मिला दिए गए।

१७८६ के एक्ट ने गवर्नर-जनरल को परिपक्वता की उपेक्षा करने का अधिकार तो दिया, किंतु उससे परामर्श करना अनिवार्य था। १७९१ में एक एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार गवर्नर-जनरल बुद्धि समाप्त होने के तीन महीने बाद तक विना परिपक्वता के नाम-सह-सहकार्य नहीं कर सकते थे। इसके अन्तर्गत अधिकार बना दिया गया।

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ८०.

२. Chesney: Indian Polity, page 22.

भारतीय इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन स्मरणीय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में आने पर असाधारण अविकार दिने गए थे। कॉर्नवालिस के नाम के साथ यह अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ था — “वह व्यक्ति जो अमेरिका में पराजित हो चुका था।”<sup>१</sup> भारत में कॉर्नवालिस ने सात वर्ष की अवधि में केवल एक बड़ी लड़ाई ही नहीं जीती<sup>२</sup> वरन् ब्रिटिश भारत की शासन, राजस्व और न्याय-व्यवस्था में बड़े महत्वपूर्ण सुधार भी किये।

समयान्तर मन्त्रों द्वारा सुधार भारत की सैनिक एवं सिविल नौकरियों में सम्बन्धित था। पेंसनों के शब्दों में भारतीय सार्वजनिक सेवा विभाग, “अनेक दोषों से भरा हुआ था।”<sup>३</sup> मिस्टर विन्सेंट स्मिथ बनारस के रेजीडेंट का उदाहरण देते हैं, जिसकी वार्षिक आय ४०००० पीट थी।<sup>४</sup> असली वेतन बहुत कम था। इस प्रचलित कदाचार का मुख्य कारण डाइरेक्टर्स का वह व्यावसायिक दृष्टिकोण था जिसके अनुसार वे स्वार्थ में अल्प वेतन दिलाना चाहते थे। उन्हें इस बात की कोई चिन्ता न थी कि परिणाम का परिमाण क्या होता है।<sup>५</sup> लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह सब ठीक कर दिया। उन्होंने उचित वेतन दिये और दूसरे प्रकार की आय वजित कर दी। अपने ही उदाहरण से उन्होंने सार्वजनिक सेवा और न्याय का स्तर ऊँचा किया।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सार्वजनिक सेवा का नैतिक स्तर ही ऊँचा नहीं किया वरन् शासन-व्यवस्था का भी फिर से संगठन किया। फिर से जिलों के क्षेत्र बनाए, और जिले को भारतीय शासन की इकाई बनाया। हर जिले की माल-गुजारी व्यवस्था के लिए एक कलक्टर नियुक्त किया जिसको न्यायाधिकार से अलग रखा। हर जिले में एक दीवानी न्यायालय था जिसका समस्त एक

### १. Smith: Oxford History of India—Quotation from Macshman.

(लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेवा की अक्टूबर १७८१ में अमेरिका के सटवर्ती यॉर्क नगर में हथियार टाटने पड़े थे) page ५५८.

२ सन् १७९२ की शोरणपट्टम संधि से मैसूर युद्ध समाप्त हुआ।

३ Chesney: Indian Polity, page २३.

४ Smith: Oxford History of India, page ५५७.

५ उपर्युक्त पुस्तक, एक पृष्ठ।

६. लॉर्ड कॉर्नवालिस ईमानदार, परिश्रमी शासक थे। उन्होंने श्री रणमट्टन की

४ संधि में कोई आधिक साझा लेना अन्वीकार कर दिया। उपर्युक्त पुस्तक के

५ पृष्ठ ५७४ से अनूदित।

६. डडास

यूरोपीयन जज होता। उसको मजिस्ट्रेट का अधिकार होना और वह पुलिस का नियंत्रण भी करता। भारतीय दरोघा के आधीन, जो स्वयं जिला जज के आधीन होता था, पुलिस-मंडल होता। फौजदारी न्याय प्रान्तीय अदालतों द्वारा कार्यन्वित होता।

यह विचित्र बात है कि जिस तर्क से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मालगुजारी और न्याय-विभाग को अलग किया उसी के अनुसार न्याय और कार्यपालिका को अलग नहीं किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलक्टर को न्यायाधिकार से अलग कर दिया, किंतु जिला जज को न्यायाध्यक्ष और पुलिस दोनों का ही काम दे दिया।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी न्याय के लिए तीन प्रकार के न्यायालय बनाए। सबसे पहले तो बड़े नगरों और जिलों में स्थानीय न्यायालय थे। बड़े नगरों में मुन्सिफ और अमीन के न्यायालय थे। जिनमें पचास रुपये तक के मुकदमों का निर्णय होता। इससे अधिक और २०० रुपये तक के लिए रजिस्ट्रार का न्यायालय था। हर जिले में एक यूरोपीयन जज के आधीन जिला-न्यायालय था। यह जज पद में कलक्टर से बड़ा होता। उसकी सहायता के लिए एक काजी होता और एक पंडित होता, जो क्रमशः मुसलमानी-न्याय अथवा हिंदू-न्याय में दक्ष होता। जिला-न्यायालय का मौलिक अधिकार भी होता और अपील सुनने का अधिकार भी होता। यह अपील उन अभियोगों पर होती जो मुन्सिफ या रजिस्ट्रार द्वारा तय किये जा चुके थे। दूसरे प्रकार के न्यायालय केवल अपील के लिए थे। इनको प्रान्तीय न्यायालय कहा जाता। इनमें से एक कलकत्ता के निश्चित था, दूसरा पटना में था, तीसरा ढाका में और चौथा मुसिदाबाद में। इनमें से प्रत्येक न्यायालय में तीन जज होने, एक रजिस्ट्रार होता, एक या अधिक सहायक होने और भारतीय कानूनों को जानने वाले तीन व्यक्ति होते—एक काजी, एक मुफ्ती, और एक पंडित। इनमें छोटे न्यायालयों की अपील सुनी जाती। १००० रुपये तक के मामलों में इनके निर्णय अन्तिम होते। १००० रुपये से अधिक के मामलों की कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी। कलकत्ता के न्यायालय को सदर दीवानी अदालत भी कहते थे। वह न्यायालय गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के सदस्यों से निर्भर होता। इनकी सहायता को एक मुख्य काजी, दो मुफ्ती, दो पंडित, एक रजिस्ट्रार और कुछ दूसरे कर्मचारी होते। ५०००० रु० से अधिक मूल्य के मामलों की प्रिवी काउंसिल (सपरिपड् इंग्लैंड-नरेथ) से अपील की जा सकती थी।

फौजदारी न्याय चार प्रान्तीय न्यायालयों के आधीन था। ये न्यायालय एक मंडल से दूसरे मंडल में परिभ्रमण करते और अपील सुनते। ये न्यायालय



वर्ष में चार बार कड़कता में, वर्ष में दो बार हर जिले में और प्रान्तीय केन्द्र में हर महीने में एक बार न्याय-कार्य करने। हर मजल के काम के लिए प्रान्तीय न्यायालय दो हिस्सों में बँट जाता था। एक दल में एक जज और उसके साथ में रजिस्ट्रार और मुफ्ती होता, दूसरे दल में अन्य दो जज, काजी और दूसरा सहायक होना। मजल के इन न्यायालयों के ऊपर सदर निजामत अदालत थी जिसमें गवर्नर-जनरल, उसकी परिषद् के सदस्य और सहायता के लिए एक काजी और दो मुफ्ती होते। इन प्रान्तीय न्यायालयों और सदर निजामत अदालत के अतिरिक्त हर जिले में शान्ति के न्यायाधिकारी (Justices of the Peace)<sup>१</sup> होते। ये अपने क्षेत्राधिकार के अनियोग में १५ दिन की जेल या २०० रुपये तक जुर्माना कर सकते थे।

अन्त में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस-व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयत्न किया। पुलिस के अधिकार ज़म्मेदारों को मिले हुए थे जिनके अपने सशस्त्र अनुयायी होते। सहूरो में बोनबाल होते, इनके भी अपने सशस्त्र अनुयायी होते। इन व्यक्तियों को पुलिस के अधिकारों से अचित कर दिया गया। हर जिले को वृत्तों में बाँट दिया गया। इनमें से प्रत्येक वृत्त लगभग २० मील का था। हर वृत्त के लिए जिला जज एक दरोज़ा नियुक्त करता और इसकी सहायता को सशस्त्र आदमी होते। बट-बट नगरों को विभागों में बाँटा गया। प्रत्येक विभाग एक दरोज़ा और उसके सशस्त्र आदमियों के आधीन होता। दरोज़ा और उसके सहायक जिला जज के आधीन होते, जो जिले का मुख्य न्यायाधिकारी होता और साथ ही जिले की पुलिस का निरीक्षण और नियंत्रण करता।

शासन के क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किये, उनमें तीन बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो है कि यद्यपि कर्मचारियों के वेतन काफ़ी बढ़ाये गए और उन्हें किसी तरह की पीस, कमीशन, बँट आदि लेने से रोक दिया, किन्तु भारतीय सहायकों और नौकरों को अब भी बहुत थोड़ा वेतन दिया जाता। कभी-कभी तो उन्हें कोई वेतन दिया ही नहीं जाता बल्कि प्रीस दी जाती या उपदान दिया जाता। रजिस्ट्रार, अमीन, या मुफ्ती के लिए कोई वेतन नहीं था। उन्हें हर रुपये में एक आना प्रीस का मिलता। दरोज़ा का वेतन केवल २५ रुपये मासिक था। हर डाकू या लुटेरे को पकटने पर १० रुपये और मिलते। चोरी किये हुए माल को फिर से प्राप्त करने पर कुछ कमीशन मिलता। परिणाम यह हुआ कि दरोज़ा बदमाशों की अपेक्षा भले आदमियों के लिए अधिक आकर्षक

१. जिला जज, रजिस्ट्रार और अमीन—ये सब भी शान्ति के न्यायाधिकारी थे।

चीज बन गए।<sup>१</sup> दूसरी बात यह है कि यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह आदेश दिया था कि अब तक सपरिपद गवर्नर-जनरल द्वारा जो विनियम बनाये गये हैं, उनको त्रुटिपूर्ण करके सार्वजनिक जानकारी<sup>२</sup> के लिए छापकर प्रकाशित किया जाय, किन्तु भारतीय न्याय-नियमों की संहिता बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। पड़ितों और काजियों की सम्मतियों में अन्तर और विचलन हो सकता था। "हर एक चीज अस्पष्ट और अनिश्चित थी और फलतः मनमानी थी।"<sup>३</sup> अन्त में तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन से भारतीयों को विधिवत् दूर रखने की नीति अपनाई।<sup>४</sup> मार्शमैन के अनुसार यह लॉर्ड कॉर्नवालिस की बहुत बड़ी गलती थी और अब इस नीति के अविवेक और अनौचित्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं।<sup>५</sup>

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया जो उनके सारे सुधारों में सबसे अधिक महत्व का था। यह सुधार मालगुजारी व्यवस्था से सम्बन्धित था। कुछ समय पहले<sup>६</sup> तक इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किन्तु अब अधिकांश लेखक उसे बहुत बड़ी भूल बताते हैं। सन् १७९३ में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी व्यवस्था का बन्दोबस्त किया और सन् १७९५ में बनारस डिवीजन का बन्दोबस्त किया। यह स्यायी बन्दोबस्त की

१ Smith The Oxford History of India, page 570.

२ Sapre The Growth of the Indian Constitution and Administration, page 135

३ Mill History of British India, Book VI page 432

४ Chesney . Indian Polity, page 25.

५ प्रो डाडवेल लिखते हैं कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने में किसी भी दुस्तर कठिनाईयाँ थी। सन् १७९१ के एक्ट के अनुसार, "५०० पौंड से अधिक वेतन, परिलब्ध और आय के किसी पद के लिए उसी व्यक्ति की निम्न हो सकती हो जो कम-से-कम तीन साल तक कम्पनी की सेवा में रहा हो।" प्रो डाडवेल आगे लिखते हैं कि यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ५०० पौंड प्रति वर्ष से अधिक आय के किसी पद पर किसी भारतीय को नियुक्त किया भी होता तो वह अवर्ष होता, क्योंकि एक्ट के अर्थानुसार कोई भी भारतीय, कम्पनी का सेवक नहीं था।" Cambridge History of India Vol. V, page 319 से अनूदित।

६ इस स्यायी बन्दोबस्त के विवेचन के लिए पढ़िय—R. C. Dutt. History of Early British Rule in India

व्यवस्था थी। सर जान शोर ने बन्दोबस्त का विरोध किया। लेकिन लॉर्ड कॉन-  
वालिस ने शोर, जो उम्र विषय के विरोध थे, का मत न मानकर, जल्दी ही  
स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था कर दी। हाल में इस व्यवस्था की बड़ी तीखी  
आलोचना हुई है।

### (३)

लॉर्ड कॉनवालिस का शासन-काल समाप्त होने के समय कम्पनी के  
अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रश्न पार्लियामेंट के सामने आया।  
सन् १७७३ में इस अधिकार-पत्र की फिर २० वर्ष के लिए वृद्धि की गई थी।  
अब यह अवधि समाप्त हो रही थी। इस अवसर पर इंग्लैंड के व्यापारियों और  
व्यवसायियों ने पूर्वीय वाणिज्य की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन खड़ा किया। किन्तु  
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपनी योजना बड़ी चतुराई से  
तैयार की थी। उन्होंने पूर्वीय वाणिज्य और रोपण (पाँच वाली शक्ती) पर  
रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाइरेक्टर्स की एक कमेटी नियुक्त की। यह रिपोर्ट  
अन्तिम अवसर पर हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत की जाती। इस बीच २५ फ़रवरी  
सन् १७९३ को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समापति सर हनरी डेविस ने भारतीय  
व्यवस्था की पूर्णतः सतोषजनक स्थिति पर पार्लियामेंट-भवन में एक वक्तव्य  
दिया और यह जताया कि उस व्यवस्था से सबको लाभ होगा। इस प्रकार  
अधिकार-पत्र को फिर से जारी कराने के लिए चतुराई से मार्ग तैयार किया गया।  
पिछले उस समय अपनी शक्ति के शिखर पर थे और राष्ट्र का स्वार्थ पास के साथ युद्ध  
की समस्या में केन्द्रित था। भवन के सामने अधिकार-पत्र का प्रश्न आने से कुछ  
पहले यह युद्ध आरम्भ हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में डेविस और पिछले को  
इस अधिकार-पत्र का फिर से जारी कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी।  
परिणामस्वरूप १७९३ का एक्ट बना और कुछ साधारण से संशोधनों के  
बाद बीस वर्ष के लिए कम्पनी के एकाधिपत्य को फिर स्वीकृति दे  
दी गई।

### (४)

१७९३ का एक्ट बहुत बड़ा था। उसने बहुत से पहले नियमों को रद्द  
कर दिया और कानून का एकीकरण किया, किन्तु उसने बहुत से परिवर्तन और  
संशोधन नहीं किये।

पहली बात तो यह थी कि पूर्व में कम्पनी के व्यावसायिक एकाधिपत्य  
को बीस वर्ष की अवधि और मिला गई। अगरेज व्यापारियों और निर्माताओं के  
विरोध को दान्त करने के लिए ३००० टन के परिमाण तक व्यक्तिगत व्यापार

के लिए अनुमति दी गई। किंतु इस अधिकार पर इतने प्रतिबन्ध<sup>१</sup> थे कि व्यापारियों ने इस नये खुले हुए लाभहीन मार्ग<sup>२</sup> को उपयोग में न लाने का ही निश्चय किया।

B-152  
A 172

इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और सहायकों को भारतीय राजस्व से वेतन देन की व्यवस्था की। इस प्रकार वह अमंगल द्वार आरम्भ हुआ, जो अपने अवांछित परिणाम<sup>३</sup> के साथ सन् १९१९ के एक्ट लागू होने तक बना रहा। इस एक्ट के अनुसार बोर्ड के दो छोटे सदस्यों के लिए प्रिन्सीपल काउंसिल का मेम्बर होना अनिवार्य नहीं था।

तीसरी बात यह हुई कि एक्ट ने कितनी ही बड़ी धाराओं में, कम्पनी के राजस्व का नियन्त्रण किया। १२,३९ २४१ पौण्ड की वार्षिक वृद्धि का अनुमान किया गया। इसमें से ५ लाख पौण्ड कम्पनी के ऋण के भुगतान में जाते और ५ लाख पौण्ड लाभांश को ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १० प्रतिशत करने में खपते। कम्पनी को २० लाख पौण्ड के ऋण का, २०० प्रतिशत के भाव के हिस्से से १० लाख पौण्ड की पूंजी (Stock) के आधार पर प्रबन्ध करना था। इन नई पूंजी के लाभांश के लिए १ लाख पौण्ड अलग कर दिए गए। किंतु अनुमानित वृद्धि बस्तुतः हुई नहीं और ब्रिटेन को ५ लाख पौण्ड का अपना वार्षिक भाग प्राप्त नहीं हुआ। सामेदारों को, लाभांश बढ़कर ८ से १० प्रतिशत हो जाने के कारण, अवश्य लाभ हुआ।

एक्ट ने चौथी बात यह की कि भारत की शासन-व्यवस्था में कुछ थोड़े से सुधार किये। हर प्रेसिडेन्सी की परियद की कार्य-पद्धति का विनियमन किया गया और गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परियद के परामर्श की उपेक्षा कर सकने का अधिकार दिया गया। अन्य प्रेसिडेन्सियों के शासन पर नियन्त्रण करने

१ व्यक्तिगत व्यापार के लिए जो अनुमति मिली "उसमें सैन्य-सामग्री के आयात पर प्रतिबन्ध था। यही प्रतिबन्ध कपड़े पर था। इसके अतिरिक्त सामान को कम्पनी के गोदामों में रखने और कम्पनी के भाव पर बेचने की भी शक्ति थी" Mill History of British India, Book VI, page 8 से अनूदित।

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४

३ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देन का मुख्य परिणाम यह हुआ कि पार्लियामेंट के नियन्त्रण के अवसर बहुत घट गए, क्योंकि हर विभाग के व्यय के लिए रकम स्वीकार करने के समय पर ही पार्लियामेंट में उस विभाग के काम की जाँच और आलोचना होती है।

का गवर्नर जनरल को जो अधिकार था उसे पुष्ट किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जब स्वयं गवर्नर जनरल किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में उपस्थित हो तो वहाँ का गवर्नर और सारा शासन उसवे आधीन होगा। गवर्नर जनरल, गवर्नरों, सेनापति और कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को अपने पद की अवधि में भारत से बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती थी। यह नियम सन् १९२५ में पार्लियामेन्ट के एक विशेष एक्ट द्वारा बदला गया। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में जाने के समय, अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए, वह परिषद् के किसी सदस्य को उप-सभापति नियुक्त कर सकता था जो उसके स्थान पर काम करता। अब सेनापति<sup>१</sup> डाइरेक्टर्स द्वारा विशेष रूप से परिषद् का सदस्य नियुक्त किये जाने पर ही उसका सदस्य हो सकता था अन्यथा नहीं।

एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय का जल-सेना पर जो क्षेत्राधिकार था, उसे सद्दूर समुद्रों तक बढ़ा दिया। साथ ही एक्ट के अन्तर्गत, सिविल सर्विस के कर्मचारियों, चान्ति के न्यायाधिकारियों और प्रेसिडेन्सी के नगरों के लिए समार्जक नियुक्त करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कर लगाने का अधिकार दिया। बिना अनुज्ञप्ति (License) के मादक द्रव्य के विनियम पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

इसके अतिरिक्त एक्ट की अन्य धाराएँ एकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने वाली थी।

### ( ५ )

सन् १७९३ के एक्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि "भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना, इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, इच्छा और उसके मान के प्रतिकूल है।" 'कोर्टे ऑफ डाइरेक्टर्स' को भी अपने<sup>२</sup> कारणों से विजय और विस्तार की यह नीति पसन्द नहीं थी। किन्तु परिस्थितियों के प्रवाह और भारत में उपस्थित अधिकारियों की आकांक्षाओं के कारण व्यवहार में ठीक उलटी नीति अपनाई गई। लार्ड वेल्सली ने गवर्नर जनरल की हैसियत से अपने ७ वर्ष के कार्य-काल में कम्पनी के प्रदेशों का बहुत बड़ा विस्तार किया। गजब, सिंध और नेपाल को छोड़कर लगभग सारा भारत, ब्रिटिश प्रभुता के क्षेत्र में आ गया।

१. केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों का पद एक साथ मिला था।

२. डाइरेक्टर्स विजय और प्रादेशिक विस्तार की नीति से इस कारण असहमत थे कि उसमें बड़ा भारी खर्च होता था और कम्पनी का लाभ कम होता था।

लार्ड वेल्डली की इन लहाइयो से कम्पनी का ऋण बहुत बढ गया । ५ वर्ष में वह दूना हो गया और १८०५ में उसका परिमाण २१० लाख पौण्ड हो गया । इसका वार्षिक व्याज २७,११,००० पौण्ड था ।<sup>१</sup> कम्पनी के व्यापार में भी गिराव आया । सन् १८०८ में अपने कोष की स्थिति के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स बहुत व्यग्र हुए और स्थिति संभालने के लिए पार्लियामेण्ट से अपील की । कम्पनी का सरकार पर १२ लाख पौण्ड उधार था । अपने प्रार्थना-पत्र में कम्पनी ने इस परिमाण को सौटाने के लिए कहा और साथ ही अपने सुगठान करने के लिए इतने ही परिमाण का ऋण माँगा । घन के अनुदान के सम्बन्ध में भारतीय मामलो की वस्तुस्थिति की जाँच करने के लिए ११ मार्च १८०८ को एक कमेटी नियुक्त की गई ।<sup>२</sup> १३ जून को रिपोर्ट प्राप्त हुई और कम्पनी को पुराने हिसाब में १५ लाख पौण्ड की रकम दिया जाना निश्चित हुआ । सन् १८११ में कम्पनी को १५ लाख पौण्ड का ऋण स्वीकार हुआ और सन् १८१२ में उसे प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर २० लाख पौण्ड का ऋण उपाहने की अनुमति मिली । जून १८१२ में पार्लियामेण्ट ने कम्पनी को २५ लाख पौण्ड का एक ऋण और दिया ।<sup>३</sup>

सन् १८०८ की कमेटी कम्पनी की वस्तुस्थिति की जाँच का काम पाँच वर्ष तक करती रही और उसने पाँच रिपोर्टें तैयार की । इनमें से पाँचवी रिपोर्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी । जुलाई १८१२ में इसे प्रकाशित किया गया और इल्बर्ट के अनुसार, "भारतीय भूमि-व्यवस्था पर उसे अब भी प्रामाणिक माना जाता है और तत्कालीन पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी उसका काम सबसे अधिक प्रामाणिक है ।"<sup>४</sup> इस प्रकार पार्लियामेण्ट के सामने अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रश्न आने से पहले भारतीय व्यवस्था की पूरी-पूरी जाँच की जा चुकी थी ।

सन् १८१३ में अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने के समय मुख्य विवादास्पद प्रश्न यह था कि कम्पनी के व्यावसायिक विशेषाधिकारों को जारी रहने दिया जाय या नहीं । उस समय कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं था ।

१ Mill and Wilson . History of British India, vol VII, pages 485-486

२. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १६३.

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४५४-४५५.

४. Ilbert : Historical Survey, page 73

उस समय तक कम्पनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त था। जहाँ तक चीन के साथ व्यापार का सम्बन्ध था मॉन्टे-मडल उसे अब भी कम्पनी के हाथ में रखना चाहता था। इस प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण कारण यह था कि चीन के साथ व्यापार बड़ी विविध परिस्थितियों में होता था। चीनी सरकार विदेशियों के सम्पर्क के प्रति अत्यन्त ईर्ष्यालु थी। व्यापार केवल एक बन्दरगाह तक ही नहीं चलूँ एक (हाऊ मामन) दौरे तक ही सीमित था। इस प्रकार अन्य चीन वास्तव्य के लिए विदेशियों के सम्पर्क निषिद्ध था। अब वहाँ प्रतिद्वन्द्विता<sup>१</sup> के लिए कोई दाव ही नहीं था। दूसरी ओर इस बात का भय था कि नए अग्रज व्यापारियों की अननितता या असाबधानी के कारण वहाँ चीनी अधिकारी प्रतिद्वूल न हो जायें और पन्त<sup>२</sup> उनके साथ व्यापार बिजुबुड ही बन्द न हो जाय। इस प्रकार चाय का जाना बन्द हो जाता। अंग्रेज अन्त<sup>३</sup> चाय को अत्यन्त अभ्यस्त हो गई थी और उससे न जान से जलता में बड़ा तीखता अनुभव किया जाता। साथ ही सरकार का खान पर<sup>४</sup> चीना-दाल<sup>५</sup> से ४० लाख पौण्ड की वार्षिक आय होती थी। इस प्रकार चीन के साथ व्यापार बन्द होने के राजस्व को बड़ी भारी क्षति पहुँचती। इन सब बातों को सोचकर सरकार ने आरम्भ से ही कम्पनी के इस एकाधिकार की बनाए रखने का निश्चय कर लिया था।

भारत के साथ व्यापार की स्थिति दूसरी थी। कम्पनी के दिग्गदियों का भारतीय व्यापार के एकाधिकार के प्रति ही विशेष आपत्ति थी। सारे ब्रिटेन में व्यापारियों, निर्माताओं और जहाजों के मालिकों ने आन्दोलन खड़ा कर दिया था। लन्दन, ब्रिस्टल, ग्लोस्टर, ग्लाउगो, मंचेस्टर, शेफाल्ड, नॉटिङ्गम, ब्लैकबर्न आदि अनेक नगरों ने पार्लियामेन्ट के पास प्रार्थना-पत्र भेजे थे। उनमें यह निवेदन किया गया कि कम्पनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार की फिर अनुमति न दी जाय और उस व्यापार के लिए सारे ब्रिटिश प्रजा की समान रूप में स्वतन्त्रता दी जाय। प्राधियों ने इस बात पर जोर दिया कि हर ब्रिटिश नागरिक को बिना रोक-टोक, बाधित्य और व्यापार करने का समान अधिकार है। उन्होंने एडम स्मिथ के लर्क उद्धृत बिने और एकाधिकार के विराय तथा स्वतन्त्र व्यापार के धर्म की विवेचना की। इस एकाधिकार को तोड़ने

१ Mill and Wilson History of British India, vol VII. page 512.

२. Sir G. Stimson - Considerations on the China Trade —Quoted by Mill and Wilson - History of British India. Vol. VII pages 511 and 512.

में ब्रिटेन के लिए चार लाभ बताए गए — (१) ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग का विस्तार; (२) भारतीय व्यापार के यूरोप और अमेरिका के अन्य देशों की ओर विकसित होने पर प्रतिरोध, (३) व्यापारिक मूल्य में—विशेषकर यातायात और पण्यशाला के मूल्य में कमी, (४) ब्रिटेन में भारतीय कच्चे माल का सस्ता आयात।<sup>१</sup> कम्पनी ने उत्तर में इन लाभों को वास्तविक बताया। भारतीय व्यापार बिल्कुल लाभदायी नहीं था और भारतीयों के स्वभाव और आपस के कारण भविष्य में कोई विस्तार संभव नहीं था। डाइरेक्टर्स ने बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत किया और कहा कि भारत के साथ स्वतन्त्र व्यापार से कम्पनी नष्ट हो जायगी और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त हो जायगा। उनके मत का कारण हेस्टिंग्स, टेनमाउथ, माल्कम और मुनरो जैसे बड़े पदाधिकारियों ने समर्थन किया। किन्तु जैसा कि मिल के ब्रिटिश भारतीय इतिहास में विस्मय ने संकेत किया है, भारतीय व्यापार के लिए स्वतन्त्रता उपर्युक्त कारणों से नहीं दी गई वरन् यह निर्णय तो नेपोलियन की आक्रांतियों से ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग की जो दुर्गति हो रही थी उससे बचाने की आशा से किया गया।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो विवाद हुआ, उसमें तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए — (१) भारत में ब्रिटिश उपनिवेश बनाने की वाछनीयता अथवा अवाछनीयता, (२) कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का, भारतीय जनता और उद्योगों पर प्रभाव, (३) भारत में (ईसाई) धर्म प्रचार की आवश्यकता और उपयोगिता।

कम्पनी के कर्मचारियों ने भारत में यूरोपियन बस्ती बसाने के कारण प्रत्याशित भयकर परिणामों का चित्र खींचा। वारन हेस्टिंग्स ने कहा कि ये (यूरोपियन) वहाँ के निवासियों का अपमान करेंगे, उन्हें लूटेंगे और उन पर अत्याचार करेंगे और इंग्लैंड के कोई भी कानून उनको व्यवहार से न रोक सकेगा।<sup>२</sup> जैसा कि हल्वर्ट ने कहा है, कम्पनी के समर्थकों का भय निराश्रय नहीं था किन्तु उसको अत्यन्त उग्र भाषा में अतिरंजित करके प्रकट किया गया था। बाद में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार एक कठोर अनुज्ञप्ति व्यवस्था के अनुसार यूरोपियनों को बसाने के लिए भारत जाने की अनुमति मिली। उन्हें

१. Mill and Wilson History of British India, vol VII, pages 424 and 485

२. Ilbert Historical Introduction to the Government of India, page 75.



क्षेत्राधिकार में रोक दिया गया। साथ ही उन्हें म्यानीय गानन के पूर्णोपयोगों और भारतवासियों के सम्पर्क से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का पालन करने को कहा गया।<sup>१</sup>

दूसरी बात जो पार्लियामेंट में कही गई थी वह मुक्त व्यापार से भारतीयों को होने वाले लाभ के सम्बन्ध में थी। भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुओं पर इंग्लैंड के दातार में रोक लगी हुई थी या उन पर बहुत बड़ा कर लगा हुआ था। जैसा कि डा० साह ने अपनी पुस्तक (*History of Indian Tariffs*, page 105) में कहा है, तब यह था कि "भारत के साथ मुक्त व्यापार का अर्थ या उद्देश्य, इंग्लैंड और भारत के बीच मुक्त व्यापार नहीं था। वह तो ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार के विरोध में एक स्वार्थलिप्त दुहाई थी।"

अन्त में पार्लियामेंट भवन में और बाहर भी, धर्म-प्रचार के नेताओं ने प्रबल आन्दोलन किया। ये लोग भारत के मति-यूजर्स में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ चाहते थे। बिल्वरफोर्स तथा अन्य व्यक्तियों ने भारतवासियों का नीपण धिक् साँचा। यद्यपि मि० मार्श और लार्ड टेनमाउथ ने भारतवासियों की धार्मिक आस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की पुरानी नीति का आग्रह भाषा में प्रतिपादन किया, किन्तु सरकार को झुकना पड़ा। यह कहा गया कि इस देश (इंग्लैंड) का यह कर्तव्य है कि वह भारतवासियों के हित और सुख का प्रभाव के और उनके धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी ज्ञान का प्रसार करे। जो व्यक्ति इस उद्देश्य से भारत जाना चाहें उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इस प्रकार इल्वर्ट के शब्दों में, "धर्म-प्रचार के पीछे राय (पीछे लगाने वाला) दिखाई पड़ता है, दोनों के ही प्रति कम्पनी के कर्मचारी ईर्ष्या से।"<sup>२</sup>

सन् १८१३ के एक्ट ने कम्पनी के अधिकार-धन को फिर जारी कर दिया। एक्ट ने अन्तिम प्रस्तावों राज-सत्ता में निहित की किन्तु भारतीय प्रदेशों और उनके राजस्व को कम्पनी के ही हाथों में रहने दिया। साथ ही चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कम्पनी के एकाधिकार की अवधि २० वर्ष के लिए और बढ़ा दी।

इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि जब ब्रिटिश व्यापारियों को, एक्ट में उल्लेख किये हुए कुछ प्रतिपत्तियों के अन्तर्गत, माधारण भारतीय व्यापार के लिए

१. See the 13th resolution—Appendix X. Mill and Wilson, *History of British India*, vol. VII, page 608.
२. Ilbert: *Historical Survey*, page 72 से अनूद्धित।

स्वतन्त्रता दे दी। एकट ने डाइरेक्टर्स को और उनके मना करने पर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल को इस बात का अधिकार दिया कि जागृति, सुधार अथवा किसी दूसरे बंध उद्देश्य से भारत जाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाय। बिना अनुज्ञप्ति लिये हुए भारत जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सकता था।

एकट ने तीसरी बात यह की कि उसने भारतीय राजस्व का किस प्रकार उपयोग हो, इसका विनियमन किया। सबसे पहला दायित्व सेना को बनाए रखने का था, दूसरा दायित्व व्याज देने का था। राजस्व के व्यय का तीसरा अधिकरण असेनिक एंव व्यावसायिक कार्यालयों को बनाए रखने का था। कम्पनी के ऋण को घटाने की भी व्यवस्था की गई। कम्पनी और राष्ट्र में वचन के बटवारे का अनुपात क्रमशः एक और पाँच निश्चित किया गया। कम्पनी को, व्यावसायिक और प्रादेशिक लेले, पूषक् और स्पष्ट रखने के लिए कहा गया।

एकट ने चौथी बात यह की कि कम्पनी की आय से वेतन पाने वाली सेना की संख्या २९००० निश्चित कर दी। एकट ने कम्पनी को इस सेना के लिए नियम, विनियम आदि बनाने, उसके लिए युद्ध-सामग्री तैयार करने और सेना-न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार दिया।

एकट ने पाँचवी बात यह की कि बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के अधीक्षण और निर्देशन के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित कर दिया। साथ ही भारत की स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, कर लगाने का प्राधिकार दिया। ये सरकारें कर न देने वालों को दण्ड दे सकती थी।

एकट की छठी बात कम्पनी के सैनिक एंव असेनिक कर्मचारियों के शिक्षण की व्यवस्था थी। हेलवरी कालेज और एडिस्कोम्ब सैन्य शिक्षण-केन्द्र को चलाने की व्यवस्था की गई और उन पर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल का प्राधिकार कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और भारत में अन्य स्थानों के कालेजों को भी बोर्ड के विनियमन में कर दिया। भारत में यूरोपियों के धार्मिक हित के लिए एक विशाल और तीन अन्य बड़े पादरियों की नियुक्ति की गई। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने और साहित्यिक सुधार और पुनरुत्थान के लिए और साथ ही ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये व्यय करने की भी व्यवस्था की गई।

एकट की सातवी बात अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो अभियोग होते, उनके लिए न्याय की व्यवस्था की;<sup>१</sup> जेरी, जलसूअरी और जाली सिक्के बनाने के लिए विशेष दण्ड का नियम बनाया गया।

१. विस्तृत वर्णन के लिए देखिय—Ilbert's Historical Introduction, pages 79-80.

( ६ )

लाहें वेन्जरी के तीन उपराधिकाओं को विवश होकर, किसी भी मूल्य पर, हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाना पड़ा। सर जार्ज बारलो ने मराठों को मन्त्र भारत के राजपूतों के साथ अपनी मनमानी करने को छोड़ दिया। लाहें मिट्टो न एक बीच का दर्रा अपनाया और इंग्लैण्ड के अधिकारियों की नीति को बदलने का प्रयत्न किया। उसने भारतीय महासागर में फ्रेंच द्वीप और हॉलैंड वागों के अधिकार से जावा द्वीप जीता। उसने सर चार्ल्स मैटकाऊ को बूटनीति द्वारा सन १८०९ में महाराजा रजजीवसिंह के साथ संधि करने में सफलता प्राप्त की। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश सीमा जमुना से आगे बढ़कर सतलुज तक पहुँच गई।

जब अक्टूबर १८१३ में लाहें हेस्टिग्स भारत में आया तो उसके सामने सात ऐसे झगड़े थे जिनके निणय के लिए समस्त युद्ध की आवश्यकता हो सकती थी। लाहें वेन्जरी ने स्थिति को एसा कर दिया था कि भारत में अंग्रेजों के लिए चुपचाप खड़े रहना असम्भव हो गया था। लाहें हेस्टिग्स ने वेन्जरी के काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का निश्चय किया।

लाहें हेस्टिग्स ने नेपाल को हराया और सन १८१६ की सुगौली की संधि से ब्रिटिश प्रदेश में कुमायूँ का क्षेत्र—जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले थे—और देहरादून का जिला (जिसमें ममूरी और बनमान शिमला जिले का कुछ भाग भी था) मिलाया। उनके बाद पिटारियों, पठानों और मराठा सरदारों से निपटने का प्रयत्न किया। हेस्टिग्स ने मराठों और पिटारियों से पठान सरदार अमीर खाँ को अलग कर लिया और उसे टोक का नवाब बना दिया और बाद में एक बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी सहायता से पिटारियों को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही महीनों में पिटारी नेता-बिहीन होकर पहाड़ी कोहों में भाग गए। हेस्टिग्स ने राजपूताने की बहुत सी बड़ी रियासतों से संधियों की ओर मराठा शक्ति को छिन-भिन्न करने का प्रयत्न किया। इस समय मराठे—पेशवा, भोंसले (अप्पा साहेब) और होळकर, ये सब—संयुक्त थे। कुछ ही समय में हेस्टिग्स सबको हराते में सफल हुआ। पेशवा की पेंशन बाँध दी गई। अप्पा साहेब को गद्दी से उतार दिया गया और उसके राज्य प्रदेश को छीन लिया गया। इन्दौर राज्य को घटाकर पट्टे का बना कर दिया गया। मिथिला राज्य अलग कर दिया गया और वह किसी का पक्ष न ले सकने के लिए विवश था। इस प्रकार लाहें हेस्टिग्स ने भारत में पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।<sup>१</sup>

१ सिगापुर का बन्दरगाह भी लाहें हेस्टिग्स के राज्य-काल में जीता गया। यह

( ७ )

लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन-काल शासन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए और साथ ही देशवासियों के प्रति अधिक उदार और सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति को फलटा, और न्यायाध्यक्ष तथा मालगुजारी उगाहने और शासन के काम को एक में मिला दिया। कलक्टर अपने जिले का मुख्य न्यायाध्यक्ष और साथ ही जिला-पुलिस का भी अध्यक्ष बना दिया गया। दरोगा का पद तोड़ दिया गया। उसका काम गाँव के मुखियाओं को सौंप दिया गया। गाँव का लेखा रखने वाले और तालियासी, अथवा गाँव के चौकौदार और साथ ही तहसीलदार, जमींदार, जमीन और कोतवाल सब उनकी सहायता करते।<sup>१</sup> लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न्याय के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया और उन्हें अधिक अधिकार दिये। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की प्रगति की ओर भी उसने काफी ध्यान दिया। उसी के राज्य-काल में कलकत्ता का हिन्दू-कॉलेज खुला ताकि हिन्दू लड़के यूरोप और एशिया की भाषाएँ सीख सकें और विज्ञान की शिक्षा पा सकें।<sup>२</sup> मार्शमैन ने श्रीरामपुर में ईसाई-धर्म-प्रचार के लिए एक बड़ा केन्द्र खोला। उसके लड़के जे० सी० मार्शमैन (इतिहासकार) ने वहाँ एक कॉलेज खोला, जो सन् १८२७ में एक विश्वविद्यालय बन गया।<sup>३</sup> सन् १८१८ में श्रीरामपुर से भारतीय भाषा में सबसे पहला समाचार-पत्र 'ससार दर्पण' प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था, इसका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था।

गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स के ही समय में समाचार-संपादन के नियन्त्रण के प्रश्न ने बड़ा महत्वपूर्ण रूप धारण किया। इस विषय पर सन् १८२२ में मद्रास के गवर्नर सर टॉमस मुनरो ने एक विस्तृत लेख लिखा। इस लेख ने उस समय के ही विधान पर प्रभाव नहीं डाला बल्कि बाद में भी ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया।

बन्दरगाह बड़ा था, उसकी स्थिति महत्वपूर्ण थी और वहाँ रोम की महत्वपूर्ण खानें थी।

१. Mill and Wilson History of British India, vol. VIII, page 533

२. Haveli. A Short History of India, page 238.

३. डेन्मार्क के राजा फ्रेडरिक प्रथम ने इस कॉलेज को डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार दिया और इस प्रकार उसे विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया। भारत के लिए यह सबसे पहला विश्वविद्यालय था।

सरकारी जाँच का नियम टूट जाने पर नये समाचार-पत्र अस्तित्व में आए। सन् १८१८ में मिस्टर जे. एस. बकिंघम ने 'कलकत्ता जर्नल' प्रकाशित किया। कुछ ही समय में उस पर सरकारी कोप हुआ। सन् १८२३ में संपादक को नोटिस पाने के बाद दो महीने के ही अन्दर भारत छोड़कर घले जाने को आज्ञा दी गई। समाचार-पत्रों के संपादन के विषय पर सरकार ने फिर विचार किया और सर टॉमस मुनरो के लेख पर विशेष रूप से ध्यान दिया। परिणाम यह हुआ कि सन् १८२३ में बंगाल के लिए और सन् १८२७ में बम्बई के लिए पहले से भी अधिक कठोर विनियम बनाये गए। सन् १८२३ के विनियमों का परिचय देने से पहले, सर टॉमस मुनरो के मत का संक्षिप्त वर्णन संगत होगा। सर टॉमस की दृष्टि में यूरोपीय समाचार-पत्रों के सम्पादन की समस्या बम्बीर नहीं थी। सर मुनरो ने लिखा "जहाँ तक केवल यूरोपियनों का प्रश्न है, चाहे वे सरकारी (कम्पनी के) नौकर हो या न हो, उनके सम्पादन-कार्य की स्वतन्त्रता अथवा उस पर प्रतिबन्ध से कोई विशेष हित या अहित नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।" फिर भी मुनरो ने प्रकाशन से पहले उनके समाचारों की जाँच करने और अपराधी सम्पादकों के भारत से बाहर भेज देने के अधिकार को बनाये रखने के लिए कहा। सर मुनरो की विशेष चिन्ता तो भारतीय समाचार-पत्रों के संपादन से सम्बन्धित थी। सर मुनरो ने लिखा — "यद्यपि यह सकट अभी दूर है किन्तु समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता दे देने पर यह अनिवार्य रूप से हमारे सामने आ जायगा।" उसका भारतीय सेना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और ब्रिटिश शक्ति को जलाऊ फेंकने के लिए प्रेरक होगा। "उससे जनता में स्वतन्त्रता की भावना फैलेगी और वे विदेशियों को भगाकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए प्रेरित होंगे।" सर टॉमस ने यह नियम बताया कि, "स्वतन्त्र समाचारपत्र और विदेशी शासन—ये दोनों बातें एक दूसरे की विलकुल विरोधी हैं और बहुत समय तक एक साथ टिक नहीं सकती।"\*

१. "The History of Press Legislation in India" :  
Modern Review August, 1913

२. उपर्युक्त

३. उपर्युक्त निबन्ध।

४. उपर्युक्त निबन्ध।

सर टॉमस के मन को मान्यता दी गई और नये विनियम १५ मार्च सन् १८०३ को निबन्धन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए। इन विनियमों के अनुसार सरकार से अनुज्ञप्ति लिये बिना न कोई प्रेस स्थापित हो सकता था, न कोई समाचार-पत्र निकाला जा सकता था और न कोई पुस्तक प्रकाशित की जा सकती थी। इन अनुज्ञप्ति-व्यवस्था के अनुसार छोटे हुए सारे समाचार-पत्र और पुस्तकें निरोक्षण के लिए सरकार के सामने रखी जातीं। सरकारों गजट में केवल एक सूचना निकालकर सरकार इन पत्रों और पुस्तकों का चलन रोक सकती थी। राजा राममोहन राय और श्री शारदानाथ टंगोर-जैसे विख्यात व्यक्तियों ने इन विनियमों के खेद बताने हुए उनको रद्द करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया। किन्तु विनियमों का निबन्धन बर दिया गया और वे ५ अक्टूबर १८२१ से बंध हो गए। सन् १८३५ में सर चार्ल्स मैटकाफ़ द्वारा फिर दोहराये जाने के समय तक वे बराबर लागू रहे। यद्यपि सर चार्ल्स मैटकाफ़ का कार्य-काल लॉर्ड विलियम बेंटिन्क के स्थायी उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक ही था किन्तु उसने बड़े साहस से काम लिया और लॉर्ड मैकाले की सहायता से १८३५ का एक्ट न० ११ बनाया। इस एक्ट में १८०३ और १८२७ के विनियमों को दोहराया गया और नारे ब्रिटिश भारत के लिए अनुज्ञप्ति और प्रकाशन से पहले सरकारी जांच की व्यवस्था को तोड़ दिया गया। उसके बदले इंग्लैंड की तरह साधारण निबन्धन का नियम बना दिया गया।

अब हम फिर गवर्नर-जनरल लॉर्ड हेन्स्टिम्स के राज्य-काल की घटनाओं के वर्णन पर आते हैं—अन्तिम महत्त्वपूर्ण घटना जमीन के बन्दोबस्त से सम्बन्धित थी। यह बन्दोबस्त भारत के विभिन्न भागों में—मद्रास, बम्बई और आगरा जिल्लों में—अस्थायी आधार पर किया गया। मद्रास और बम्बई के बन्दोबस्त में मुन्सि और एग्जिस्टेंट के नाम विनियम से उल्लेखनीय हैं।

लॉर्ड हेन्स्टिम्स का उत्तराधिकारी एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था। उनके शासन-काल में भरतपुर की हार और चम्पा-युद्ध (१८२४-२६) के अति-रिक्त और कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं हुई। यह युद्ध यदावू की संधि से समाप्त हुआ। इनमें मजालत और योजना की त्रुटियों के कारण बहुत से जीवन व्यर्थ हो गये हुए और बहुत सी सम्पत्ति बेकार हो बरबाद हुई।<sup>१</sup> यदावू की संधि से अंग्रेजों को एक बरोट रियासत और आसाम, अराकान और सालवीन नदी के पूर्व में मत्तवान प्रान्त के कुछ हिस्सों के साथ टेनाबरिम के प्रदेश मिले।

१. सन् १८३४ में बीर राजा के असाधारण व्यवहार के कारण युग को छोन लिया गया।

अगली दशाब्दि में शान्ति रही और मुबार हुए । कुर्ग<sup>१</sup> और दो अन्य महत्वहीन स्थानों के अतिरिक्त कोई नए क्षेत्र ब्रिटिश सीमाओं के अन्तर्गत नहीं मिलाये गए । लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती-प्रथा बन्द की गई और ठगी का दमन किया गया । बेंटिक के ही राज्य-काल में व्यय में वृद्धि की गई और अफीम के व्यापार में एकाधिपत्य के कारण राजस्व में वृद्धि हुई । कॉर्नवालिस द्वारा अंग्रेजी ढर्रे के प्रान्तीय न्यायालयों को बन्द किया गया और न्यायालयों<sup>२</sup> में फारसी के स्थान पर देश-भाषा को जगह दी गई । साथ ही न्यायपालिका और कार्यपालिका में भारतीयों की नियुक्ति की गई । भारतीय रियासतों की ओर बेंटिक की नीति, दुर्बल और अस्थिर थी । उसने मँसूर के प्रति नीति में दृढ़ता और शीघ्रता से अवश्य काम लिया । बहुत हद तक इसका कारण यह था कि वह इस विषय में इंग्लैण्ड के अधिकारियों की इच्छानुसार काम करने को उत्सुक था । उसके व्यवहार के प्रति केवल यही आपत्ति की जा सकती है कि जहाँ दीनता अहितकर थी वहाँ भी उसने दृढ़ता नहीं दिखाई ।<sup>३</sup>

१ Smith The Oxford History of British India, page 659.

२ Havell A Short History of India, page 241

३. विल्लेग्ट स्मिथ ने अपनी (उपर्युक्त) पुस्तक में इस नीति के परिणाम का जो वर्णन किया है उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है —

"अवध में मंत्री, हकीम मेहता का अंग्रेज-सरकार ने साथ छोड़ दिया और उसे राज्य से निकाल दिया । मिर्जाम के राज्य की दुर्व्यवस्था को चुपचाप देखा गया । अवधस्क होलकर को सहायता नहीं दी गई और वहाँ भी राज्य की दुर्व्यवस्था हुई । ग्वालियर में भयंकर भगड़े हुए, पर कोई बंदम नहीं उठाया गया । गायरुवाड ने धैर्य भाव धारण किया । राजपूत रियासतों को गृह-युद्ध में कले रहने के श्रोताह्वन दिया गया । उदयपुर में मुबार रोक दिए गए । जयपुर में नीति का अनर्थ में अन्त हुआ, अर्थात् वहाँ ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण किया गया जिसके कारण वहाँ का रेजीडेण्ट घुरी तरह घायल हुआ और उसका सहायक चलेक मर गया ।"

## चौथा अध्याय कम्पनी के अन्तिम दिन

( १ )

सन् १८३२ में कम्पनी के अधिकार-मन्त्र की अवधि फिर से घटाने का प्रश्न पार्लियामेंट में आने के समय तक इंग्लैंड का वातावरण बदल चुका था। विदेशों में व्यापार व क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का और इंग्लैंड में मानव-अधिकार के सिद्धान्त का प्रचार दिया जा रहा था। ७ जून १८३२ को सुधार विधेयक (Reform Bill) एक्ट बन गया और १८३३ में दसरा को सारे ब्रिटिश साम्राज्य में अवधि कर दिया। इस वातावरण में कम्पनी के लिए फिर से व्यापारिक एकाधिकार के अधिकार-मन्त्र की अवधि बढ़वाना समझ नहीं था। अतः सन् १८३३ के एक्ट न बदल पढ़ा जान यह विचार कि चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार का समाप्त कर दिया।

इस एक्ट का दूसरा काम ठन्गालीन भारतीय धायन के दो मुख्य दोषों में से एक को दूर करने का प्रयत्न था। पार्लियामेंट के सदस्य मिस्टर चार्ल्स शाफ्ट के धर्मों में यह दोष था, "व्यापारी और सार्वजनिक भुक्ता का ऐक्ट"।<sup>१</sup> एक्ट ने इस दोष को दूर करने के लिए कम्पनी से नुविदातूँ शीघ्रता<sup>२</sup> के साथ अपने व्यावसायिक कार-बार को दन्द करने, और जामदारों की भारतीय राजस्व से १०½ प्रतिशत लानाग देने और कम्पनी के स्टॉक को ब्रज करने के लिए १२० लाख पाउंड एकत्रित करने को कहा। किन्तु हाउस ऑफ कॉमन्स में मि० बकिंघम तथा अन्य सदस्यों का विरोध होते हुए भी पार्लियामेंट ने भारतीय धायन, कम्पनी को सौंप दिया। मि० बकिंघम ने इतने बड़े साम्राज्य के राजनीतिक धायन को एक जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी को सौंपना अवगत बताया और यह सुझाव दिया कि भारत की उदोष्य परिस्थ में, भारत में रहने वाले उद्येशों और साथ ही स्वयं भारतीयों के कुछ प्रतिनिधि मिले जायें ताकि स्व-शासन की व्यवस्था का बम-बे-बन आरम्भ तो हो हो जाय।<sup>३</sup>

१. C. L. Anand : Introduction to the History of Government in India, page 35 के एक टिप्पण का अनुवाद।

२. Section IV of the Act, Keith : Speeches and Documents, vol. I, pages 26-27.

३. C. L. Anand : An Introduction to the History of Government in India, page 38.



लॉर्ड मैकालि ने इस अवसर पर एक स्मरणीय वक्तृता दी और भारत में कम्पनी का शासन बनाए रखने के पक्ष का प्रतिपादन किया। मैकालि ने मिल को उद्धृत किया और प्रतिनिधि-सरकार की चर्चा को बेतुका बताया।<sup>१</sup> उसने इस बात को अस्वीकार किया कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स भारत में होने वाली बुराइयों पर कोई सक्रिय व्यवस्था बुराई रोक लगा सकेगा।<sup>२</sup> उसने कहा 'यह स्पष्ट है कि भवन के पास इन (भारतीय) विषयों का निर्णय करने के लिए आवश्यक समय नहीं है, न उसको आवश्यक जानकारी है और न उस जानकारी को प्राप्त करने का उद्देश्य ही है। हाल ही में उसके विधान में जो परिवर्तन हुआ है उससे वह ब्रिटिश जनता का अधिक सही प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने से आज भी वह इतना ही दूर है जितना कि पहले कभी था। भारत की तीन घमासान लड़ाइयों से यहाँ इतनी हलचल नहीं होगी जितनी कि इंग्लैण्ड की एक अपेक्षाकृत बहुत छोटी जगह की सिर फुटीवल से। कुछ ही सप्ताह पहले भारतीय राजस्व के विपक्ष में एक व्यक्ति के दावे का निर्णय किया था। यदि वह अंग्रेजों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न होता तो यह सभा-भवन मत-विभाजन के इच्छुक सदस्यों के लिए छोटा पड़ता। वह एक भारतीय प्रश्न था और इसी कारण हम गण-पूर्ति भी कठिनाई से कर सके। यहाँ तक कि जब मेरे माननीय मित्र 'बोर्ड ऑफ़ न्यूट्रोल' के सभापति ने अपना मनोरजक और अत्यन्त योग्यतापूर्ण वक्तव्य दिया और १० करोड़ मनुष्यों के शासन के लिए अपने प्रस्तावों को पस्तुत किया, तो उपस्थिति इतनी भी नहीं थी जितनी की किसी नई रेलवे लाइन खोलने अथवा घुगी की चौकी बनाने के समय होती है।'<sup>३</sup>

दूसरी ओर लॉर्ड मैकालि ने कहा कि "कम्पनी हिंग या टोरी दोनों में से किसी राजनीतिक दल से अथवा किसी धार्मिक मत या सम्प्रदाय से सम्बन्धित नहीं थी। उसके प्रति यह दोष नहीं मड़ा जा सकता था कि उसने कैथोलिक बिल (Catholic Bill) या सुधार विधेयक (Reform Bill) का पक्ष अथवा विपक्ष लिया। उसका काम करने का दृष्टिकोण अंग्रेजों राजनीति नहीं, बरन् बराबर भारतीय राजनीति रहा है। .... सारे आन्दोलनों के बीच कम्पनी विलकुल असन्दिग्ध रूप से निष्पक्ष रही है।"<sup>४</sup> भारत में उसके शासन

१. Keith : Speeches and Documents on Indian Policy, vol I, page 234

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३५

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३६-३७।

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३९-२४०.

का इतिहास और भारतवासियों के हित और कल्याण के लिए उसकी उत्तुक्ता, ये दोनों बातें प्रशंसनीय हैं। "विदेशी, नैतिक और स्वेच्छाचारी शासन में इतनी भलाई की भावना अल्प नही मिल सकती।"<sup>१</sup> लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में वह भारतीय शासन को कम्पनी के हाथों से हटा देने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड मैकाले के मन को पार्लियामेंट ने माना और कम्पनी को भारतीय प्रदेशों और उनके शासन का अधिकार फिर बीस वर्ष के लिए सौंप दिया।

सन् १८३३ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि हमने भारत में हमने के लिए जाने वाले यूरोपियों पर जो प्रतिबन्ध थे उन्हें समाप्त कर दिया और उन्हें जमीन का मालिक बनने के लिए कोई रोक-टोक नहीं रहने दी। किन्तु वहीं ये विदेशी भारतवासियों के धर्म और विश्वास आदि से छेद-छाड़ न करे और उनका अपमान न करे, इस उद्देश्य से भारतवासियों की रक्षा के लिए गवर्नर-जनरल को परामर्शवर्ती शक्ति के साथ नियम-विविनियम बनाने के लिए कहा गया।<sup>२</sup>

सन् १८१३ में यूरोपियों के भारत में हमने के प्रश्न पर विवाद के समय कम्पनी और उसके उच्च कर्मचारियों ने तीव्र विरोध किया था पर इस बार भारत के उच्च अधिकारियों ने यूरोपियों के वहाँ हमने की माँग का प्रबल समर्थन दिया। मर मैकाले और लॉर्ड वॉल्टेज दोनों ने भारत में यूरोपियों की हमने के लिए बे-रोक-टोक जाने देने के पक्ष का प्रतिपादन किया और उसके कितने ही लाभ बताए। एक लाभ तो यह बताया कि हमने भारतीय साम्राज्य की समृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा यह कि हमसे राजस्व में वृद्धि होगी और तीसरा यह कि हमसे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य अधिक सुदृढ़ होगा। सन् १८३९ की प्रवर-समिति ने भारत जाने वाले यूरोपियों पर ये प्रतिबन्ध हटाने के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक कारण प्रस्तुत किये जैसे, इंग्लैंड की विदेशी कच्चे माल के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता हो जानी, भारत में ब्रिटिश माल की माँग बढ़ जानी और इंग्लैंड की प्रेषित धन अर्थात् 'होम चार्जेज' का परिमाण बड़ जाना।<sup>३</sup> प्रवर-समिति के समक्ष कुछ भाषियों ने बे-रोक-टोक यूरोपियों को भारत में

१. Keith . Speeches and Documents on Indian Policy, page 249.

२. Article LXXXV of the Act.

३. इनी पुस्तक का पृष्ठ ४६

४. History of Indian Tariffs by Shah, pages 128-29.

जाने देने की नीति का खतरा बनाया और यूरोपीय उपनिवेश बनाने से देश-वासियों<sup>१</sup> का जो अहित होता उसकी ओर ध्यान दिलाया किन्तु मेटकाफ और वॉटकि का मत माना गया और भारत में जाने वाले यूरोपियनों पर से सब प्रतिबन्ध हटा लिये गए ।

सन् १८३३ के एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने निरिच्छ और स्पष्ट भाषा में यह उल्लेख किया, “मविष्य में किसी पद के लिए योग्यता<sup>२</sup> की हो कसौटी है” और “केवल अपने धर्म, जन्म-स्थान, जाति अथवा वर्ण के कारण उक्त (भारतीय) प्रदेशों का कोई निवासी अथवा हिज मैजिस्ट्री की प्रजा का कोई भी व्यक्ति, कम्पनी<sup>३</sup> के किसी भी पद या उसकी किसी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जायगा ।” उक्त शब्द के कारण लॉर्ड मॉले ने सन् १८३३ के एक्ट को सन् १९०९ से पहले पार्लियामेण्ट द्वारा बनाए हुए भारतीय एक्टों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया ।<sup>४</sup> एक बार नीति और स्वार्थ के सकीर्ण विचारों को हटाकर उदार मानवीय सिद्धान्तों को व्यक्त होने का स्थान दिया गया ।

पाँचवीं

नए एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने भारत के गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के विधान और अधिकारों में परिवर्तन किये । गवर्नर-जनरल की परिषद् में विधान कार्य के लिए एक विधि सदस्य और बढ़ाया गया । इस नए सदस्य को कार्यपालिका में कोई अधिकार नहीं था । सपरिषद् गवर्नर-जनरल के विधान-कार्य को भी बहुत बढ़ा दिया गया । जैसा कि सन् १८७२ के टेंगेर-व्याख्यानों में मिन्टर कैवेल ने सकेत किया, उस समय का सबसे बड़ा दोष विधान बनाने वाले और शासन करने वाले अधिकारियों का सघर्ष और विधान का अनिश्चित स्वरूप था । पहली बात तो यह थी कि “उस समय भारत में पाँच प्रकार के विधान लागू हो रहे थे ।”<sup>५</sup> हर प्रेसीडेन्सी को सरकार को

१. Major Basu: The Colonization of India by Europeans, pages 64 to 94.

२. Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol. I. Despatch of the Court of Directors, 1834, page 120

३. Clause LXXXVII of the Act

४. Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol I., page 120

५. Ilbert's Historical Introduction to the Government of India Quotation on page 84

नियम-विनियम बनाने का अधिकार था। सपरिपद गवर्नर-जनरल का विधान बनाने का अधिकार विलकुल अपर्याप्त था। सपरिपद गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए नियम-विनियम केवल भारतीय जनता और कम्पनी के सेवकों पर ही लागू होते थे किन्तु उनका भारत में बसे हुए अन्य अंग्रेजों और विदेशियों पर कोई अधिकार नहीं था। इसके अनिश्चित उनका सर्वोच्च न्यायालय पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। सन् १८३३ के एक्ट ने इन दावों को दूर करने का प्रयत्न किया। एक्ट ने ब्रालीय सरकार के विधान बनाने के अधिकार को हटा दिया और उन्हें केवल यह साधारण अधिकार दिया कि वे जिन विधानों और विनियमों को आवश्यक<sup>१</sup> और उपयोगी समझें उनको लिखकर सपरिपद गवर्नर-जनरल के पास भेज दें। इस प्रकार भारत में विधान बनाने का अधिकार सपरिपद गवर्नर-जनरल के हाथों में केन्द्रित कर दिया गया। इन विधानों का क्षेत्राधिकार सब व्यक्तिगत, न्यायालयों, स्थानों और वस्तुओं पर था। उक्त (भारतीय) प्रदेशों के प्रत्येक भाग का तथा सभी द्वारा कम्पनी से सम्बन्धित प्रत्येक देशी राज्य और कम्पनी के प्रत्येक मकान का इन विधानों में समावेश था।<sup>२</sup> राजसत्ता और पार्लियामेण्ट को प्रभुता का मनुचिन संश्लेष किया गया था।<sup>३</sup>

एक्ट में यह उल्लेख किया गया कि उक्त (भारतीय) प्रदेशों और वहाँ के निवासियों में सम्बन्धित उक्त सपरिपद गवर्नर-जनरल के हर कार्य और उनकी हर कार्यवाही का राजन, उसका उल्लेखन और नियंत्रण करने का पार्लियामेण्ट का पूर्ण और स्थायी अधिकार सुरक्षित है।<sup>४</sup> सपरिपद गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए विनियम जिनको कोई ओवर हाइरेक्टर्स ने अस्वीकार न किया हो, एक्ट कहता है। उन्हें पार्लियामेण्ट के सामने रखा जाता, किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि जिनो न्यायालय में उनका निवन्धन किया जाय और उनको प्रकाशित किया जाय। अन्त में अनिश्चितता समाप्त करने के लिए सपरिपद गवर्नर-जनरल को इन्डियन लॉ-कमीशन नाम से एक आयोग (Commission) बनाने का निर्देश दिया गया। इस कमीशन को स्थानीय परिस्थितियों<sup>५</sup> का ध्यान रखने हुए सामान के लिए सामान्य विधान बनाना था।

१ Clause 66 of the Act. Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol I, page 96

२ Clause XLIII of Act, Keith : Speeches on Indian Policy, Vol I, page 268

३. Clause XLIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६८।

४ Clause LI of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६९-२७०।

५. Clause LIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७१-२७२।

इस आयोग को उक्त प्रदेश की वर्तमान न्याय और पुलिस-व्यवस्था, उनके क्षेत्र-धिकार, नियम और उनकी कार्य पद्धति, लिखित अथवा प्रचलित दीवानी और फौजदारी विधान को जाँच करके सपरिपद् गवर्नर-जनरल को रिपोर्ट देनी थी। पहले विधान-आयोग के सभापति का पद लॉर्ड मैकाले को मिला। यह आयोग, जितनी आशा थी, उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) इस आयोग के ही परिश्रम का फल थी। यह सन् १८६० में स्वीकृत होने पर लागू हो गई। इस आयोग ने दीवानी और फौजदारी पद्धति को संहिताओं के लिए भी नींव तैयार कर दी।

एक्ट की छठी बात, बंगाल की अत्यधिक बड़ी प्रेसिडेन्सी को विभाजित करके दो प्रेसिडेन्सियाँ बनाने की व्यवस्था थी, किन्तु यह कार्यान्वित ही नहीं हुई। पहले तो इसे सन् १८३५ के एक्ट से निलम्बित कर दिया गया और बाद में सन् १८५३ के एक्ट से।

एक्ट ने सातवीं बात यह की कि उसने सपरिपद् गवर्नर-जनरल को भारत में गुलामों की दशा सुधारने और सारे भारत में गुलामी प्रथा (दास प्रथा) समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश किया।

एक्ट ने आठवीं बात यह की कि एक बिशप के स्थान पर तीन बिशप बनाए और बलूचეთ के बिशप को भारत का मेट्रोपोलिटन बिशप (लाट पादरी) बना दिया।

अन्त में एक्ट ने हेल्डरो में कम्पनी के कॉलेज में भारत के अर्सेनिक सेवकों के शिक्षण की व्यवस्था की और कॉलेज में प्रवेश के लिए विनियम बनाए।

## ( २ )

भारत में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय इस विषय पर एक दशवर्षी से प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों में विवाद चल रहा था। लॉर्ड मैकाले ने सार्वजनिक शिक्षा-कमेटी के सभापति नियुक्त होने पर, अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा प्रबल समर्थन किया। ७ मार्च १८३५ के प्रस्ताव द्वारा सरकारी निर्णय प्रकाशित हुआ "ब्रिटिश सम्प्रदाय का महान् उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार होना चाहिए और शिक्षा के लिए जो निधि है उसका सर्वोत्तम उपयोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में ही होगा।"<sup>१</sup>

लॉर्ड ऑकलैंड के राज्य-काल में प्रथम अफगान-युद्ध की विपत्ति, एक मुख्य घटना थी। यह युद्ध पारमर्स्टन की इस विरोधी नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। उसके उत्तराधिकारी के समय में अफगानिस्तान से बढ़ला लेने के लिए लड़ाई लड़ी गई

प्रोम और पेगू का सारा प्रान्त आ गया। साथ ही घटगाँव से लेकर सिंगापुर तक सारे समुद्र-तट पर ब्रिटिश अधिकार हो गया।

लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य को बढ़ाने के लिए केवल युद्ध-विजय का ही सहारा नहीं लिया बल्कि किसी देशी राज्य में उत्तराधिकारी न होने पर उस राज्य पर ब्रिटिश आधिपत्य जमा लेने की नीति से भी काम लिया। इस प्रकार डलहौजी ने सितारा, नागपुर, झाँसी, जंतापुर, साँभलपुर और कुछ दूसरी छोटी रियासतों पर अधिकार कर लिया। अवध पर अधिकार एक दूसरे ही प्रकार से—उच्छृङ्खल और मनमाने ढंग से—किया गया। सिक्किम को तत्कालीन राजा द्वारा डॉ० कम्पबेल और डॉ० हुकर को पकड़ने के अपराध के दण्डस्वरूप ले लिया गया। भद्रायाक सेना के निर्वाह के नाम पर निजाम से वरार को ले लिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को ८ लाख रुपये का वार्षिक भत्ता मिलता था। उसके दत्तक पुत्र को यह भत्ता देना अस्वीकार कर दिया गया। सन् १८५५ में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु का लाभ उठाकर, उसके कुटुम्ब के मान और उसके भत्ते को घटा दिया गया। संक्षेप में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रत्येक समब उपाय से ब्रिटिश राज्य और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया। सन् १८५७ के उत्थान में, डलहौजी की देशी राज्यों को छीनने की नीति भी कुछ अशो तक उत्तरदायी है।

डलहौजी एक अत्यन्त उत्साही और कर्मठ व्यक्ति था। उसने शासन के प्रत्येक विभाग के काम की देख-भाल की और बहुत से सुधार किये, भारत के सर्वोच्च शासन को विभागानुसार व्यवस्थित किया, बंगाल के लिए एक पृथक् उप-गवर्नर नियुक्त किया। उसने एक पृथक् सार्वजनिक निर्माण-विभाग बनाया और ग्राण्ड ट्रंक रोड बनवाने, सिंचाई के लिए नहरें निकालने और रेलवे-लाइन बिछाने के कामों को आरम्भ किया। उसने बिजली के द्वारा तार भेजने की व्यवस्था चलाई और डाक के लिए जापा आना प्रति पत्र की एक ही दर निश्चित की। सन् १८५४ के 'बुड डिस्पेंच' नाम से प्रसिद्ध आदेशों को पूरी तरह कार्यान्वित किया और देश की वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था की नींव रखी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय मेना के पुनर्संगठन का भी प्रबन्ध किया और इस विषय पर नौ विस्तृत लेख लिखे, (इन लेखों पर इंग्लैण्ड के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया)। लॉर्ड डलहौजी के कार्य-काल में ही कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि फिर बढ़ा देने का प्रश्न अन्तिम बार पार्लियामेण्ट के सामने आया।

( ३ )

अब तक कम्पनी के राज्य का विरोध अंग्रेजों ने ही किया था। या तो अंग्रेज व्यापारियों ने या अंग्रेज प्रगतिवादियों अथवा मानववादियों ने ही अधिकार-पत्र

की अवधि बढ़ाने में आपत्ति प्रकट की थी। किन्तु १८५३ में अधिकार-पत्र की अवधि बढ़ाने का विराय मुख्यतः भारतीयों ने किया। सन् १८३३ के एक्ट के विभाग न० ८७ ने भारतीयों में उच्च आशाओं का संचार किया था। कुछ नवयुवक भारत के बड़े पदों के लिए शिक्षित होने को इच्छुक हुए थे। भारत लौटने पर उन्हें बहुत निराशा हुई। जैसा कि गवर्नर-जनरल की परिपत्र के सदस्य और इटिबन ऑफ़ कमीशन के मनागनि मि. केंमेगन ने कहा,—“उन (सन् १८३३ का एक्ट बनने के पश्चात् के) बीस वर्षों में कोई भी देशी आदमी किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया गया जिसके लिए उसका एक्ट बनने में पहले अधिकार न हो।”<sup>१</sup> सीना प्रेसिडेन्सिया के निवासियों ने पार्लियामेण्ट के समक्ष, कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि न बढ़ाने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे। बंगाल के प्रार्थना-पत्र में दूधमामन को समाप्त करने, एक राज्य-सत्री नियुक्त करने और एक ऐसी भारत-परिपत्र, जिसमें कुछ सदस्य निर्धारित हों और कुछ नाम निर्दिष्ट हों, नियुक्त करने का निवेदन किया गया। इस प्रार्थना-पत्र में भारत के लिए एक विधान-मंडल बनाने, गवर्नर-जनरल की परिपत्र की सम्मति में काम करने, प्रेसिडेन्सियों की एक प्रकार की प्रान्तीय स्वायत्तता देना, छोटी नौकरियों का वेतन बढ़ाने और बड़े पदों का वेतन घटाने, सारी ब्रिटिश प्रजा को सिविल सर्विस का पान बनाने और उक्त सिविल सर्विस की परीक्षा द्वारा भर्ती करने का निवेदन किया गया।<sup>२</sup>

ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के दोनों सदस्यों ने सन् १८५० में जाँच के लिए कमेटीयों नियुक्त की और उनकी जाँच के आधार पर सन १८५३ का चार्टर-(अधिकार-पत्र) एक्ट तैयार किया।

इस चार्टर एक्ट ने सबसे पहली बात तो यह की कि उसने कम्पनी के अधिकारों को सिर जीवन-दान दिया और उसे हर मैजिस्ट्री (मैजिस्ट्री की गती) और उसके उपाधिकारियों की ओर में घरोहर के रूप में भारतीय प्रदेशों पर अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी। पहले अधिकार-पत्रों में यह अनुमति एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी, किन्तु इस बार उपर्युक्त अधिकार उस समय तक के लिए दिये गए जब तक कि पार्लियामेण्ट कोई अन्य व्यवस्था न करे।

१. C. L. Anand Introduction to the History of Government in India, Part I, page 41 के एक उद्धरण का अनुवाद।

२. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४२-४३।

सन् १८५३ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि डाइरेक्टर्स की सख्या को २४ से घटाकर १८ कर दिया गया। इनमें से ६ राज-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते।

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि गवर्नर-जनरल को बंगाल की गवर्नरी के काम से मुक्त कर दिया और बंगाल के लिए एक और गवर्नर को नियुक्त करने की व्यवस्था की। किन्तु नया गवर्नर नियुक्त होने के समय तक गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ कंट्रोल की स्वीकृति से एक उप-गवर्नर (Lieut.-Governor) नियुक्त कर दे। यद्यपि उप-गवर्नर की नियुक्ति तो सन् १८५४ में कर दी गई, परन्तु गवर्नर की नियुक्ति सन् १९१२ तक नहीं हुई।

एक्ट ने चौथी बात यह की कि हाल में देशी राज्यों को अधिकार में लेने के कारण जो प्रदेश-विस्तार हुआ था, उसके फलस्वरूप डाइरेक्टर्स को यह निर्देश दिया गया कि वे एक ऐसी नई प्रेसीडेन्सी बनायें, जिसकी शासन-व्यवस्था मद्रास और बम्बई की तरह हो। यदि ऐसा न हो तो एक उप-गवर्नर की नियुक्ति की जाय। इस विभाग में जो अधिकार दिया गया उसके अन्तर्गत १८५९ में पंजाब के लिए उप-गवर्नर की नियुक्ति की गई।

एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि गवर्नर-जनरल की परिषद् के विधि-सदस्य को परिषद् का पूरा सदस्य बना दिया। अब वह कार्यपालिका से सम्बन्धित परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता था और अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता था।

एक्ट ने छठी बात यह की कि भारत के लिए पहली बार एक पृथक् विधान-परिषद् बनाई। जैसा कि माण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने सकेत किया, अब पहली बार विधान (कानून) बनाने को सरकार का एक विशेष कार्य माना गया और उसके लिए एक विशेष उपकरण और पद्धति की आवश्यकता अनुभव की गई।<sup>१</sup> गवर्नर-जनरल की परिषद् का विधान-कार्य के लिए विस्तार किया गया। उसमें छ नये सदस्य बढ़ाये गए, जो विधान-सदस्य कहलाते। इस प्रकार विधान-कार्य के लिए परिषद् में १२ सदस्य होते—गवर्नर-जनरल, सेनापति, परिषद् के चार सदस्य और छ विधान-सदस्य, जिनमें से दो सदस्य कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय के अग्रेज जज (एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश) होते, और चार सदस्य, मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरे की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किये हुए सरकारी कर्मचारी होते। प्रांतीय सरकारों के इन प्रतिनिधियों

१. चतुर्थः यह एक पृथक् विधान-परिषद् नहीं थी। कार्यपालिका-परिषद् ही विधान-कार्य के लिए विस्तृत कर दी गई थी।



में से प्रत्येक को ५००० पौण्ड का वार्षिक वेतन मिलता। इस रूप में भारतीय विधान-मंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया। परिषद् का काम मौनिक और खुला हुआ होता। प्रत्येक विधेयक पर उचित रूप से विचार होना और उनका प्रवर-समिति में परीक्षण होना। 'परिषद् में कम-से-कम एक ऐसा सदस्य होना जिसे स्थानीय विपक्षी की जानकारी होती। साथ ही परिषद् में अंग्रेजी विधि का बहुत बड़ा बग होना।'<sup>१</sup> इन परिषद् ने अपने-आपको विधान-कार्य में सीमित नहीं रखा किन्तु उसने शिवायना की जाँच करने और उनको दूर करने वाली एक छोटी प्रतिनिधि-सभा का रूप ले लिया।<sup>२</sup> किन्तु उनका कोई प्रस्ताव बिना गवर्नर जनरल की स्वीकृति के विधि नहीं बन सकता था।

एक्ट ने मान्यता दी कि भारतीय विधि-आयोग की सिफारिशों की जाँच करने के लिए, अंग्रेज आयोगको के निवाय की नियुक्ति के लिए प्राधिकार दिया। (भारतीय विधि-आयोग इस समय तक टूट गया था।)

एक्ट ने जाटवी चान कम्पनी की आय में से बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की। हिज मैजिस्ट्री द्वारा वेतन के परिमाण का निर्दय होना। बोर्ड के नभारति व वेतन के बारे में यह कहा गया कि वह किसी प्रमुख राज्य-मंत्री के वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

अन्त में एक्ट ने डाइरेक्टर्स को भारतीय नियुक्तियों में अनुग्रह के अधिकार से वंचित कर दिया और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को इस सम्बन्ध में विनियम बनाने का निर्देश दिया। सन् १८५४ में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसका समापति लॉर्ड मैजिस्ट्री को बनाया गया। इस कमेटी ने विनियम बनाये। इनके अनुसार मिनिस्टर मन्त्रियों की जर्नी, परीक्षा में प्रतिस्पर्द्धिता के आधार पर होती। जनवरी १८५६ में हेल्वरी काउन्सिल के लिए शक्ति बन्द कर दिए गए। सन् १८५५ के इसी एक्ट<sup>३</sup> के अनुसार ३१ जनवरी १८५८ में कॉलेज बन्द करा देने का निर्देश दिया गया। कम्पनी ने स्वयं ही १८३३ में कॉलेज बन्द कराने की माँग की थी। उनका एक कारण तो कॉलेज का अत्यधिक व्यय था और दूसरा कारण

१. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, p. 3.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३९.

३. 18 and 19. Victoria C. 53. Ilbert: Historical Introduction, page 93.

यह था कि "विदेशों में नौकरी को जाने वाले नवयुवकों का सम्पर्क उन्हीं के जैसे दूसरे नवयुवकों तक सीमित कर देने में बहुत से दुष्परिणाम थे।"<sup>१</sup>

१८५४ में फालियामेंट ने एक एक्ट और बनाया, जिसका भारतीय शासन में महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुआ।<sup>२</sup> इस एक्ट ने सपरिषद गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार दिया कि वह कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल की अनुमति से, उद्घोषणा द्वारा, ईस्ट इंडिया कम्पनी के किसी प्रदेश के किसी भी भाग को अपने निजी अधिकार और प्रबन्ध में ला सकता है और उस भाग के शासन के लिए आदेश, निर्देश दे सकता है अथवा शासन की व्यवस्था कर सकता है।<sup>३</sup> इस अधिकार का चीफ कमिशनरों की नियुक्ति करने में उपयोग किया गया। ऐसे सारे अधिकार, जो केंद्रीय सरकार के लिए अनावश्यक थे, उन्हें प्रदान कर दिए गए। इसी एक्ट के अन्तर्गत आसाम, मध्य प्रान्त, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, बर्मा, ब्रिटिश बिलोचिस्तान और दिल्ली के लिए समय-समय पर चीफ कमिशनर बनाए गए। सन् १८५४ के एक्ट ने सपरिषद गवर्नर-जनरल को इस बात का भी अधिकार दिया कि डाइरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल की अनुमति से वह विभिन्न प्रान्तों की सीमाओं को निश्चित कर सकता है। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में गवर्नर-जनरल के पद में बंगाल के गवर्नर का पद न जोड़ा जाय।

( ४ )

लॉर्ड डलहौजी को दृढ़ विश्वास था कि वह अपने उत्तराधिकारी के लिए शान्तिपूर्ण भारत छोड़कर जा रहा था। उसे इस बात का भान भी नहीं था कि उसने असन्तोष के बीज बो दिए थे, जो कुछ समय में निश्चित रूप से अंकुरित होते और जो देश में ब्रिटिश राज्य के लिए एक भोषण सक्क का कारण हो सकते थे। लॉर्ड डलहौजी की लड़ाइयों और छीना झपटी से भारतीय सेना और शासक वर्ग दोनों ही अभ्यवस्थित और व्यथित हुए थे। आक्रामक यूरोपीय नई रियासतों से देशवासियों की पुरानी कट्टर वृत्तियाँ उमड़ उठी। ईसाई धर्म का, सरकारी आश्रय और सहायता के साथ सोत्साह प्रबल प्रचार हो रहा था। उससे लोगों को बलात् धर्म-परिवर्तन का भय और सन्देह हुआ। कैनिंग के इस

१. B. K. Thakore : Indian Administration to the Dawn of Responsible Government, page 62, के एक उद्धरण का अनुवाद.

२ 17 and 18. Victoria C. 53. Mukherji : Indian Constitutional Documents, Vol I, pages 132 to 134

३ उपर्युक्त पुस्तक, page 19 (XIX)

निर्णय ने बि, "बहादुर शाह" की मृत्यु के बाद सम्राट् का पद स्वीकार नहीं किया जायगा," उनको और उनके समर्थकों को बड़ा क्रोध और उत्तेजित कर दिया। इनके अतिरिक्त, नानासहब, झांसी की रानी और अन्य ऐसे सामन्त थे जिनको उनके अधिकारों में वंचित कर दिया गया था और जो चिढ़े हुए थे। ये सब उस समय की विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाने को तैयार थे।

द्वितीय स्थिति बड़ी दुर्बल थी। ब्रिटिश सत्ता का संगठन और वितरण बड़ा दोषपूर्ण था। सत्ता में अनुशासन की बहुत बड़ी कमी थी। महत्व के स्थानों (जैसे दिल्ली और इलाहाबाद) और साथ ही अधिकांश तोपों का अधिकार भारतीय हाथों में दिया हुआ था।<sup>१</sup> फारम की खाड़ी और चीन के लिए संन्य-दण्ड भेजे गए थे और भारतीय मोर्चों की विफलता बंगाल और उत्तरी पश्चिमी प्रान्त की स्थिति बड़ी दुर्बल थी। चर्वों के बालूयों का अच्छा बहाना मिला और २३ जनवरी १८५७ को बलकत्ते के पास मद्रास में विद्रोह आरम्भ हुआ। मार्च में बैरकपुर, अप्रैल में अम्बाला और मई में मेरठ लखनऊ और दिल्ली में उभार हुआ। मई में चारा और स्पट्टे फेंल गईं और बाकायदा लड़ाई होने लगी। इनके पांच मुख्य मोर्चे थे—दिल्ली, लखनऊ, बानपुर, रहलखण्ड और मध्यभारत जिसमें बुन्देलखण्ड भी सम्मिलित था। निम्नो खालियर के मर दिनकर राव, हैदराबाद के मर सालार जग, नसाल के सर जगबहादुर न समय पर सहायता दी। इस सहायता और कुछ ब्रिटिश अधिकाधिकारियों के शीर्ष में स्थिति को संभाल लिया गया। विद्रोह का दमन हुआ और विद्रोही दल परास्त हुआ। हारे हुए स्थानों को फिर से जीता गया और विद्रोह के नेताओं को दण्ड दिया गया, मार दिया गया अथवा बग़ा दिया गया।

फिर में व्यवस्था लाने में अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये जिनकी स्मृति भारतीय मन्त्रिण में विद्रोह के दमन के बहुत दिनों बाद तक चूमती रही और उनके ऐसे परिणाम हुए जिनके महत्व पर कुछ समय पहले तक ध्यान नहीं गया। "अंग्रेजों ने अपने बन्धियों को बिना अभियोग चलाये मार डाला और उनको मारने का दण्ड अत्यन्त बर्बरतापूर्ण था। मुसलमानों को सूजर की गाली में सी दिया, प्राण-दण्ड देने में पहले उन पर सूजर की चर्चें मली, और उनके शरीरों को जलाया और हिन्दुओं को स्वयं अपने-आपको अपवित्र और दूषित करने के लिए विवश किया।" उन्होंने दिल्ली और बाग़े आर के देहानों में हजारों असैनिक व्यक्तियों का बल कर दिया। जनरल नील ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुछ

१ Cambridge History of India, Vol V, page 607

२ Smith : The Oxford History of India, page 712

अपराधी गाँवों को नष्ट करने का निर्णय किया गया और ( फलतः ) वहाँ के सारे निवासियों का कत्ल कर दिया गया, और जहाँ-जहाँ हमारी (अंग्रेज) सेनाएँ गईं, वहाँ के निवासियों को बिना सोचे-विचारे जला दिया गया ।<sup>१</sup> लन्दन के 'टाइम्स' के तत्कालीन सवाददाता रसेल ने अपनी डायरी में ब्रिटिश सेनाओं की बर्बरता का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है । यहाँ विस्तृत उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है । उदाहरण के लिए उनमें से एक ही पर्याप्त होगा । हैदराबाद के अग्रिम सैन्य-दल के बारे में उसने लिखा है —

"उस दल का मुख्य अधिकारी (जनरल) नील का प्रतिस्पर्धी था और वह अपना पौरुष कम न समझता था—दो दिन में बयालीस आदमियों को प्राण-दण्ड दिया गया इस कारण कि प्रस्थान में सेना की ओर उनकी पीठ थी । जिन स्थानों पर उन्होंने विराम किया वहाँ के सारे गाँवों को जला दिया गया । कानपुर के हत्या-काण्ड के नाम पर इस उग्रता को न्याय नहीं ठहुराया जा सकता, क्योंकि ये घटनाएँ उक्त हत्या-काण्ड से पहले ही हुईं ।"<sup>२</sup>

ऐसी उग्रता को सहज ही विस्मृत नहीं किया जा सकता था । उससे जातीय कटुता की भावना चारों ओर फैली । कालान्तर में यह कटुता लुप्त हो गई होती, किन्तु समय-समय पर १९१९ की जालियान वाले बाग-जैसी निष्ठुरताओं ने उसे जीवित बनाये रखा ।

1858 का Act

(५)

१८५७ की घटनाओं के फलस्वरूप कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ । जैसा कि बाइट ने कहा कि, "उक्त प्रश्न पर राष्ट्र की आत्मा—अदमनीय रूप से—जग उठी और उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी को तोड़ देने का निर्णय किया ।"<sup>३</sup> प्रधान मंत्री लार्ड पामर्स्टन ने १२ फरवरी १८५८ को हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक प्रस्तुत करते हुए एक स्मरणीय वक्तृता दी और द्वैध शासन-व्यवस्था का अन्त करने के लिए अपने कारण बताए । कम्पनी के शासन का, लार्ड पामर्स्टन के अनुसार, सबसे बड़ा दोष उसकी नितान्त उत्तरदायित्वहीनता थी । "हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धान्त यह है कि सारे शासन-कार्य के लिए मंत्रि-मंडल का उत्तरदायित्व हो—पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व, जनमत के

१. Garret : An Indian Commentary, page 112
२. Russel Diary I, page 222, quoted by Garret I.C.S. (Rtd.) in an Indian Commentary, page 113
३. Speech of Lord Palmerston, Keith : "Speeches on Indian policy", vol. I, page 320.

राज-सत्ता को सौंपने पर कोई ऑव डाइरेक्टर्स को निणाल, निदलीय और विशिष्ट रोक की जगह पार्लियामेण्ट की अचालनीय और असमर्थ रोक होगी। लॉर्ड पामस्टन ने उत्तर में पार्लियामेण्ट की नीतिज्ञता, उसके विवेक और उत्तरदायित्व की ओर संकेत किया और साथ ही यह बताया कि भारत के "वे अधिकांश सुधार, जिन पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टर्स गर्व करने हैं, पार्लियामेण्ट में भारतीय शासन पर विवादों के परिणामस्वरूप ही हुए हैं।"<sup>१</sup> सर जार्ज कॉर्नवाल लेविस की भाषा और भी उग्र थी। उन्होंने कहा "मझे पूरा विश्वास है कि इस भूल पर कोई सम्य सरकार इतनी मूर्ख, विश्वासघातक, लोलुप और लुटरी नहीं हुई जितनी कि सन् १७६५ से १७८४ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार थी।"<sup>२</sup> उन्होंने कम्पनी का राजनीतिक स्वरूप जानने के लिए,<sup>३</sup> पार्लियामेण्ट के लेख और भवन की रिपोर्ट और प्रामाणिक पत्र देखने के लिए कहा। सन् १७८४ से पार्लियामेण्ट द्वारा नियंत्रण आरम्भ होने के ही बाद कम्पनी का शासन सहनीय हुआ था।

कम्पनी ने इस बात का संकेत किया था कि 'मन्त्री की सहायता के लिए भारतीय मामलों में प्रवीण नीतिज्ञों को परिपक्व अनिवार्य होगी।'<sup>४</sup> इसी सिलसिले में उन्होंने यह कहा था कि उनका कार्य के लिए कोई ऑव डाइरेक्टर्स से अधिक उपयुक्त कोई निकाय होना सन्देहास्पद है।<sup>५</sup> लॉर्ड पामस्टन ने परिपक्व की आवश्यकता को स्वीकार किया और कम्पनी द्वारा अनिवार्य बताई हुई बहुत सी बातों की प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की।

कम्पनी ने तीसरी बात यह कही थी कि एक राज्य मन्त्री को पद-नियुक्ति का अनुग्रहाधिकार देना सत्ते से खाली नहीं है। साथ ही कम्पनी ने अपने शासन में भारतीय कर्मचारियों की श्रेष्ठता का कारण यह बताया था कि उनका अनुग्रहाधिकार करने वाले व्यक्ति निर्दली रहे थे और उन्हें पार्लियामेण्ट में समर्थन अपेक्षित नहीं था।<sup>६</sup> लॉर्ड पामस्टन ने उत्तर दिया कि कार्पोरालिका सरकार को ऐसे कोई अतिरिक्त अनुग्रहाधिकार नहीं दिये जायेंगे जिसके कारण हाउस ऑव कॉमन्स को वैधानिक ईर्ष्या हो सके।<sup>७</sup>

१ Keith Speeches on Indian Policy, vol. I, page 349.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३४०

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१५

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२

५ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३३२

६ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३०७

७ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३२७

अन्त में कम्पनी ने यह कहा कि यदि विचाराधीन परिवर्तन उचित भी हों तो वह समय तो निश्चित रूप से उन (परिवर्तनों) के लिए अनुपयुक्त था। कम्पनी ने ऐसे परिवर्तनों का पालियामेंट में उन समय स्थगित कर देने के लिए निवेदन किया ताकि उनका हाथ व विद्रोह से कोई सम्बन्ध न जोड़ा जा सके। लार्ड पामस्टन ने उत्तर में कहा कि अगाधारण परिस्थितियों में ही शासन की अमुविधाओं की आग सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित होता है। हमारा (इस समय) भारत की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का उद्देश्य नहीं है, एक मुश्किल अधिक दक्षिणाधारी और अधिक कारगर शासन के स्थापना की स्थापित करने का जगह वर्तमान दुर्बल व्यवस्था को यथावत् बनाए रखने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, विचारकर एक ऐसे समय जबकि वही फिर से शान्ति स्थापित करने का कार्य अत्यन्त कठिन है। अन्त में पामस्टन ने कहा, 'मिडलान्ड जम्बुहाधिवार समय और बंधानिक सचट के आधार पर ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण हम इस विषयक को अविलम्ब स्वीकार न कर सकें।'<sup>१</sup> किन्तु इस विषयक को विधि-मुक्त में निवर्तित करने का अभी समय नहीं आया था। दूसरे वाक्य के कुछ ही समय बाद पामस्टन प्रधान मंत्री के पक्ष में हटा दिए गए। लार्ड टर्नर उनका उत्तराधिकारी हुए और मिस्टर डिब्रवायने हाउस ऑफ कॉमन्स बन गए।

नए मंत्रिमण्डल के लिए पामस्टन के मंत्रिमण्डल की ही नीति का अनुसरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ३० अप्रैल १८५८ को भवन में १४ प्रस्ताव स्वीकार किए। इनके आधार पर सरकार ने नया विधेयक तैयार किया। यही विधेयक भारत के श्रेयस्वर शासन के लिये १८५८ का एकट बन गया।

### (६)

१८५८ के एकट ने भारत के शासन की कम्पनी के हाथों से राज्य-सत्ता के हाथों में सौंप दिया। मंत्रिमण्डल में भारत का शासन 'हर मैजेस्टी' के नाम से, उसी के अधीन होना था<sup>२</sup> और भारत की आरा प्रादेशिक तथा अन्य आय हर

१ Keith: Speeches on Indian Policy. page 328.

२ जम्बुहाधिवार, पृष्ठ ३०८

३ Clause II of the Act. Keith Speeches on Indian Policy, page 370

मंजिस्ट्री के नाम में और उसी के आधीन प्राप्त की जानी थी और केवल भारत सरकार के ही कामों में उसका व्यय किया जाना था ।<sup>१</sup>

दूसरी बात यह हुई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के सारे अधिकार, हर मंजिस्ट्री के एक प्रमुख राज्य-मंत्री को हस्तान्तरित कर दिए गए । राज्य-सत्ता को एक पाँचवाँ राज्य-मंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । यह राज्य-मंत्री भारतीय शासन का नाम से भारत किन्तु इस ब्रिटिश राज्य-मंत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता ।

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि कुल १५ सदस्यों की एक भारत-परिषद् (Council of India) बनाई । इनमें से ७ सदस्य कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा निर्वाचित होते और शेष ८ सदस्य राज्य-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते । परिषद् के आधे से अधिक सदस्य—कम-से-कम नौ—ऐसे व्यक्ति होते जो कम-से-कम दस वर्ष तक भारत में रहे होते और जिन्हें नियुक्ति के समय भारत छोड़े हुए दस वर्ष से अधिक न हुए होते ।<sup>२</sup> भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति राज्य-सत्ता द्वारा की जाती । सदस्यों का कार्य-काल व्यव्यवहार पर या किन्तु पार्लियामेंट के दोनों भवनो की<sup>३</sup> प्रार्थना पर उनको हटाया जा सकता था । प्रत्येक सदस्य को भारतीय राजस्व से एक हजार दो सौ पौण्ड का वार्षिक वेतन दिया जाता ।<sup>४</sup>

परिषद् को राज्य-मंत्री के निर्देशान के आधीन, इंगलैंड में भारतीय शासन और पत्र-व्यवहार से सम्बन्धित सारा कार्य करना था ।<sup>५</sup> राज्य-मंत्री को परिषद् के समाप्ति का पद दिया गया था और उसे मताधिकार प्राप्त था ।<sup>६</sup> बराबर मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त निर्णायक मत दिया गया था ।<sup>७</sup> काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये समाप्ति परिषद् को कमेटियों में विभाजित कर सकता था ।<sup>८</sup> यदि परिषद् के अधिकांश सदस्य राज्य मंत्री के किसी

१ Clause II of the Act. Keith Speeches on Indian Policy, page 370.

२ Clause X of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७२

३ Clause XII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४.

४. Clause XIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४.

५. Clause XIX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७५

६ Clause XXI of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७५.

७. Clause XXIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७५

८ Clause XX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४

१) एक्ट ने पाँचवी बात यह की कि कम्पनी की स्थल और जल सेना को, राज्य-सत्ता के अधिकार में सौंप दिया। इनको "हर मंजैस्टी की भारतीय सेना और जलसेना समझा जायगा। इनका कार्य-क्षेत्र, उन्ही प्रदेशों में, उन्ही शर्तों पर और यथापूर्व वेतन, पेन्शन, भत्ता और विशेषाधिकार के अनुसार होगा। इनकी पदोन्नति भी उसी भाँति होगी जैसी कि उक्त कम्पनी की सेवा में होती।" भविष्य में भारतीय सेना में नई शर्तों के नियम और उसको शर्तें बदलन का राज्य-सत्ता को अधिकार दिया गया।

एक्ट ने छठी बात यह की कि उसने सपरिषद राज्य-मन्त्री के लिए पार्लियामेण्ट के दोनों भवन के समल गत वर्ष से पहले वर्ष का आधिक्य लेखा प्रस्तुत करने का नियम बनाया। इस लेखे के साथ में भारत को नैतिक और भौतिक प्रगति और स्थिति के प्रकटीकरण के लिए एक वक्तव्य भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।<sup>२</sup> एक्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध आरम्भ करने के लिए भारत में आदेश भेजने के तीन महीने के अन्दर ही पार्लियामेण्ट में उसका ब्यौरा दिया जाय। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय राजस्व का पार्लियामेण्ट के दोनों भवनों की स्वीकृति के बिना भारतीय सीमाओं के बाहर<sup>३</sup> किसी सैनिक काम के लिए उपयोग नहीं किया जायगा।

अन्त में १८५८ के एक्ट ने सपरिषद राज्य-मन्त्री को एक समुक्त निकाय बना दिया जो भारत और इंग्लंड में अभियोग का बादी अथवा प्रतिवादी हो सकता था।

( ७ )

भारत के श्रेष्ठतर शासन के लिए इस एक्ट को २ अगस्त १८५८ को राजकीय स्वीकृति मिली। १ सितम्बर को कौर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स को 'अन्तिम (और) गंभीरतापूर्ण सन्ना' हुई और कम्पनी ने "पूर्व में अपने सेवकों के नाम अन्तिम आदेश दिये," भारत स्थित अपने अधिकारियों को बहुत प्रशंसा की और अपने उद्योग और साहस, और अपनी चतुराई से बनाए हुए साम्राज्य को अपनी राज्य-सत्ता को इन हृदयस्पर्शी शब्दों में प्रदान किया—

"हर मंजैस्टी इस मूल्यवान उपहार को—इस विस्तृत भारत देश और वहाँ के परिपूर्ण करोड़ों निवासियों को स्वयं अपने नियंत्रण में ले किन्तु वे उस बड़ी

१ Clause LVII *Kenil Speeches on Indian Policy* page 380

२ Clause LVI उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७९

३ Clause IV of the Act उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३८०.



कम्पनी को ज़िम्मे उन्हें यह (उपहार) प्राप्त हुआ है विस्तृत न करें, और उस (कम्पनी) की सहायता में नीचे जान वाले पाठों को मुद्रा न दें।"<sup>१</sup>

इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य का अन्त हो गया।

---

<sup>१</sup> Smith The Oxford History of India page 707

## भाग २

भारत में ब्रिटिश राज्य

## युग १

( सन् १८६१ से १८९२ तक )

### पाँचवाँ अध्याय

## प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ

( १ )

सन् १८५८ के भारतीय शासन एक्ट के बनने से भारतीय इतिहास का एक बड़ा युग समाप्त हुआ और एक दूसरा बड़ा—ब्रिटिश राज्य का युग आरम्भ हुआ । १ नवम्बर १८५८ को इस हस्तान्तरण की राजकीय उद्घोषणा हुई । इस उद्घोषणा की भाषा सुन्दर और शालीन थी और वह उदारता, अनुग्रह, मित्रता और न्याय की भावना से परिपूर्ण थी । उसमें देशी राज्यों के शासकों को उनके अधिकारों, उनके मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का और सर्वसाधारण का धर्म की स्वतन्त्रता और न्याय के संरक्षण का आश्वासन था । साथ ही इस बात का विश्वास दिलाया गया कि किसी पद को नियुक्ति के लिए जाति और धर्म के कारण कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा और वह नियुक्ति केवल शिक्षा, योग्यता और उद्यमशक्ति के आधार पर होगी ।

( २ )

१८५७ के भारतीय विद्रोह का मुख्य कारण था शासकों और शासितों के बीच सम्पर्क का अभाव । जैसा कि सर सैम्युअल बहमद ने सकेत किया, परिपदों में भारतीयों का निर्देश करने की नीति ने सरकार को जनमत जानने के अवसर से वंचित कर दिया था । उक्त नीति के कारण ऐसी कोई भी सम्पर्क रेखा न थी जहाँ से दृष्टिकोण और उद्देश्य के सम्बन्ध में सरकार और जनता के पारस्परिक भ्रम दूर किये जा सकें ।<sup>१</sup> इसलिए सन् १८६० के अपने प्रसिद्ध लेख में सर वॉल्टर फ्रेयर ने परिपदों में देशवासियों को लेने पर जोर दिया ।

भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन् १८५८ में भी उठाया गया था, किंतु उस समय भी बहुत से देशवासी, अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध कर रहे थे । इसी कारण उस समय यह अधिकार देना अनौचित्य समझा गया । सन् १८७१ में पहली बार भारत में विधान-कार्य के लिए भारतीयों को साथ लेने की सलाह गई ।

१. C. L. Anand Introduction to The History of Govt. in India Part II, pages 72 and 73.

२. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918. page 38.

( ३ ) Act of 1861

भारत के वैधानिक इतिहास में १८६१ के भारतीय परिपद एक्ट के महत्त्व के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह, कि उसने गवर्नर-जनरल को विधान के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया, दूसरा यह कि उसने बम्बई और मद्रास की सरकार को फिर से विधान-कार्य का अधिकार दिया, और अन्य प्रान्तों में भी वैसे ही विधान-परिपद बनाने की व्यवस्था की। इस प्रकार विधान की उस नीति का आगम्य हुआ जिसके फलस्वरूप अन्त में प्रान्तों को सन् १९३७ में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता (Complete Internal Autonomy) प्रदान की गई। तत्कालीन भारत-मन्त्री सर चार्ल्स ब्रुड ने पार्लियामेंट में अपने आरम्भिक व्याख्यान में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न की विस्तृत विवेचना की किन्तु उस (प्रतिनिधित्व के अधिकार) की प्रदान करना नितान्त असंभव माना गया।<sup>१</sup> किन्तु देशों राज्यों के शासकों, सामन्तों और उच्च वर्ग के भारतीयों को "अपने अगुओं राज्य के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से"<sup>२</sup> विधान-कार्य में साथ लेना आवश्यक समझा गया।<sup>३</sup> अतः एक्ट में गवर्नर-जनरल को विधान कार्य के लिए कार्यपालिका-परिपद में कुछ अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्देशित कर लेने का प्राधिकार दिया गया।

सन् १८६१ के एक्ट ने एक बात जो यह की कि उसने गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका-परिपद में एक और—पाँचवाँ सदस्य बढ़ाया जो विधि वृत्ति से सम्बन्धित कोई न्यायकार अथवा वकील होना था।<sup>४</sup> परिपद के पाँच सदस्यों में से तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होने थे जो नियुक्ति से पहले भारत में कम-से-कम दस वर्षों तक सेवा कर चुके हों।<sup>५</sup> शेष दो में से एक सदस्य स्कॉटलैंड का कम-से-कम पाँच वर्षों का अनुभवो बैरिस्टर या एडवोकेट होना था।<sup>६</sup> भारत-मन्त्री को सेनापति को

१. Pradhan India's Struggle for Swaraj, page 45.
२. ६ जन १८६१ का सर चार्ल्स ब्रुड का व्याख्यान देखिये। Keith's Speeches and Documents on Indian Policy. Vol. II page 7.
३. Clause III of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१
४. Clause IX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५
५. Clause VI of the Act उपर्युक्त पुस्तक

(परिषद् का) अनाधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था। जिस प्रांत में परिषद् की बैठक हो रही हो, उसके गवर्नर अथवा उप-गवर्नर को अनाधारण सदस्य की तरह परिषद् में सम्मिलित करने की व्यवस्था भी की गई। एक्ट ने सरपंच गवर्नर-जनरल को, वेद से गवर्नर-जनरल को प्रत्यागित अनुपस्थिति के लिए परिषद् का समापन नियुक्त करने का प्राधिकार दिया। नये विधि और विनियमों पर अपनी स्वीकृति देने, न देने अथवा उनको संघाट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के अधिकार के अनिश्चित इस समापन को गवर्नर-जनरल के सारे अधिकार प्राप्त थे।<sup>१</sup> सरपंच गवर्नर जनरल को विधि और विनियम बनाने के अनिश्चित अपने सब अधिकार गवर्नर-जनरल को दे सकने का प्राधिकार दिया गया था।<sup>२</sup>

एक्ट ने गवर्नर-जनरल को परिषद् का काम नुसार रूप से चलाने के लिए नियम और जादेग बनाने का अधिकार दिया।<sup>३</sup> लॉर्ड बंनिंग ने इस अधिकार का उपयोग मामूली-मरफार में विभाग-व्यवस्था चलाने के लिए और विभागाध्यक्ष सदस्य (Member-in-charge of the Department) को अपने विभाग के छोटे बिजनेस का स्वयं तथा अधिक महत्वपूर्ण विषयों का बादनगर के परामर्श न निरद्वारा करने के लिए किया।<sup>४</sup>

सन १८६१ के एक्ट ने दूसरी बात यह भी कि उनमें <sup>विधि और निविद्यम</sup> बनाने के लिए बादनगर को परिषद् का विचार किया। परिषद् में अनिश्चित सदस्यों की संख्या छह से कम और बारह से अधिक नहीं होनी थी। इन सम्बन्ध में यह बात आवश्यक थी कि इन प्रकार नियुक्त किये हुए व्यक्तियों में गैर-मरफारों की संख्या छह से कम नहीं होनी थी।<sup>५</sup> अनिश्चित सदस्यों का कार्य-काल दो वर्ष था। सन् १८५३ के एक्ट के अनुसार बनाई हुई परिषद् द्वारा इजिप्ताए हुए कामों को ध्यान में रखते हुए, उस बार सर चार्ल्स वुड ने परिषद् के अधिकारों को सावधानी से सीमित और निर्दिष्ट कर दिया था।

१ Clause IX of the Act, Keith : Speeches and Documents on Indian Policy. page 25.

२ Clause VI of the Act. उपर्युक्त पुस्तक,

३ Clause VIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक

४ सन् १८५९ में लॉर्ड बंनिंग ने विभाग-व्यवस्था को आरम्भ तो कर दिया था पर उसके लिए कोई भी बंध निर्देश अथवा आपात्र नहीं था। सन् १८६१ के एक्ट में यह आपात्र मिला।

५ Clause XIX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८-२९

✓ प्रदत्त विधानाधिकार भी सङ्चित थे। गवर्नर जनरल की पूर्ण स्वीकृति के बिना सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, धर्म, सेना और जल सेना से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे। गवर्नर-जनरल को किसी प्रस्ताव को निषिद्ध करने का और अध्यादेश बनाने का पूर्ण अधिकार था।<sup>१</sup> किसी एक्ट को अमान्य करने का राज-सत्ता का अधिकार सुरक्षित था। राज-मता और पार्लियामेंट के साधारण अधिकार का स्पष्ट शब्दों में सरक्षण किया गया था।

१८६१ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने मद्रास और बम्बई की सरकारों को विधियों को बनाने और उनका संचालन करने का अधिकार फिर से प्रदान कर दिया। इस सम्बन्ध में कुछ विषयों<sup>२</sup> के लिए गवर्नर जनरल की पूर्ण स्वीकृति लेना आवश्यक था। गवर्नर-जनरल को इन विधियों को निषिद्ध करने का और राजसत्ता को भारत-मन्त्री के परामर्श पर<sup>३</sup> अमान्य कर देने का अधिकार था।

प्रांतीय विधान कार्य के लिए हर प्रसीडेंसी के गवर्नर को प्रसीडेंसी के महाधिवक्ता ( Advocate General ) को अपनी परिषद का सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। साथ ही परिषद के लिए अन्य अतिरिक्त सदस्य भी गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इनकी संख्या चार से कम और आठ से अधिक नहीं होनी थी। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि इस प्रकार नियुक्त किये हुए व्यक्तियों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या आध से कम नहीं होगी।<sup>४</sup> गवर्नर-जनरल को फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के बंगाल क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही विधान परिषद् बनाने के लिए निर्देश किया गया। इसके अतिरिक्त सपरिषद गवर्नर-जनरल को उत्तरी पश्चिमी प्रान्त और पंजाब नाम से प्रसिद्ध प्रदेशों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था कराने का अधिकार दिया गया।<sup>५</sup> २२मं जनवरी १८६२ में बंगाल के लिए, सन् १८८६ में उत्तर-पश्चिमी प्रान्त और अवध के लिए और सन् १८९३ में पंजाब के लिए, विधान परिषद की स्थापना हुई।

१ Clause XXII of the Act Keith : Speeches and Documents an Indian Policy page 30

२ भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व मुद्रा, डाक, तार, सेना, एक्स्च, प्रतिनिधित्व, और विदेश-नीति से सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए पूर्ण स्वीकृति लेना आवश्यक था।

३ Clause XXIX of the Act Keith : उद्धृत पुस्तक पृष्ठ ३५ और ३६

४ Clause 44 of the Act उद्धृत पुस्तक

कानून में गवर्नर-जनरल को विधान-सभों के लिए नये प्रान्त बनाने और इनके लिए उन्नावर्त नियम बनाने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर-जनरल को किसी प्रेसीडेंसी, प्रान्त या प्रदेश को विभाजित करने अथवा उनकी सीमाएँ घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया।

( १ )

सन १८६१ में पार्लियामन्ट ने दो महत्वपूर्ण एक्ट कोर बनाए। इनमें से (१) एक का नाम था १८६१ का इंडियन मिनिस्टर्स सर्विस एक्ट। इस एक्ट का मूल उद्देश्य कुछ नए नियुक्तियों का देय बनाना था। उस नियुक्तियों, १८६३ के अधिनियम एक्ट की शर्तों के विरुद्ध। मिल्स समय की आवश्यकताओं के अनुसार ही गई थी। मद्रास में लगभग सारी उच्च अर्सेनिज नियुक्तियों सिविल सर्विस के अदालतों के लिए भुगतान नहीं की गई थी। इन नियुक्तियों का एक परिशिष्ट में निर्देश दिया गया और इसमें कार्यपालिका-सचिव के सदस्य, भारत-सचिव और विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के विभागों के कार्याध्यक्ष (Secretary), मुख्य लेखाध्यक्ष (Accountant General) राज्य सचिव के सदस्य आदि के लिए बताया कि वे कितने वर्षों के लिए नियुक्त होंगे।

सचिव भारत-सभों द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार, सिविल सर्विस आयोगों का निर्माण में उच्च कलेक्टर सिविल सर्विस की शर्तों के लिए समान में प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रतिस्पर्द्धिता द्वारा छोट की जाती थी। सन् १८६० में परीक्षाओं के लिए अधिनियम लागू की अर्थात् को पठाकर २३ वर्षों और १८६६ में फिर पठाकर २३ वर्षों पर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि भारतीय नवयुवकों को कलेक्टर सिविल सर्विस में—और १८६६ के एक्ट के अनुसार पठन देग की शर्तों उच्च अर्सेनिज नियुक्तियों में प्रवेश करने के लिए प्राप्त कर दिया गया और इन नवयुवकों में पार्लियामन्ट और राज-सभा द्वारा दिये हुए शर्तों को ध्यान में रखकर ही गई। सरकारों भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में, भारतवासियों के लिए उच्च कृपागतियों में समान प्रयोग में समान करना समान नहीं था। इन सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि सन् १८६० में भारतीय परिषद् के पांच सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की गई थी

१. १८६३ के एक्ट के अनुसार परिषद्-सदस्य के पद के नीचे जो शर्तों अर्सेनिज नियुक्तियों प्रेसीडेंसी के सिविल सेवकों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। प्रत्येक कार्य-काल के अनुसार विनिर्दिष्ट थी। इन प्रतिष्ठितों को माना नहीं गया। उन्नीसवरी १८६१ के एक्ट से ऐसी नियुक्तियों को देय बनाने की आवश्यकता हुई।

और उसे भारतवासियों के प्रति पार्लियामेंट के आश्वासनों को पूरा करने के लिए मार्ग बनाने का काम सौंपा गया था। इस कमेटी ने एक मात्र समभव मार्ग की सिफारिश की कि सिविल सर्विस की भर्ती के लिए इंग्लैंड और भारत में सम-कालिक परीक्षा की व्यवस्था की जाय। सिविल सर्विस आयोगको के यह कहने पर भी, कि उन्हें उक्त व्यवस्था करने में कोई प्रत्याशित कठिनाई नहीं है, उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया।<sup>१</sup> इस सम्बन्ध में यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस विषय पर तत्कालीन भारत-सरकार ने जो सरकारी पत्र प्रकाशित किये थे उनमें १८६० की कमेटी की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं की गई थी।

(५)

१८६१ का दूसरा एक्ट या भारतीय उच्च-न्यायालय (Indian High Courts) एक्ट। सन १८३३ और १८५३ के एक्टों के अनुसार नियुक्त किये हुए विधि-आयोगको के परिश्रम के फलस्वरूप विधियों और पद्धतियों को संहिताबद्ध किया गया था। दीवानी पद्धति संहिता १८५९ में भारतीय दण्ड संहिता १८६० में और फौजदारी पद्धति संहिता १८६१ में बंध हो गई। सन १८६१ का भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट बनाकर भारत में न्याय-कार्य को सुधारने के लिए एक और महत्त्वपूर्ण पग आगे बढ़ाया गया। इस एक्ट ने राज-सत्ता को स्पष्ट सत्तों में कलकत्ता मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया। इनकी स्थापना पर पुराने सर्वोच्च न्यायालय और सदर दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के उनके क्षेत्र अधिकार तथा उच्च न्यायालयों को हस्तान्तरित होने थे। इन हर एक नए न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधिपति और अधिक-से-अधिक पन्द्रह अन्य न्यायाधिपति होने थे जिनमें से "मुख्य न्यायाधिपति सहित कम-से-कम एक तिहाई के लिए नियुक्ति से पहले बैरिस्टर होना आवश्यक था और कम-से-कम एक तिहाई के लिए क्वेन्टेड सिविल सर्विस का सदस्य होना आवश्यक था।"<sup>२</sup> अवशिष्ट स्थानों की पूर्ति ऐसे व्यक्तियों से होनी थी जो कम-से-कम पाँच वर्ष तक न्यायाधिकारी रहे हो तथा दस वर्ष तक वकील रहे हो। इन न्यायाधिपतियों का कार्य काल "हर मैजिस्ट्रेट के प्रसाद-पर्यन्त था।"<sup>३</sup> उच्च न्यायालयों को स्थापित करने के विभिन्न

१ Mr. Ramsay Macdonald's book. Government of India page 103

२ Clause II of the Act. Mukherjee: Indian Constitutional Documents, vol I page 391.

३ Clause IV of the Act उपर्युक्त पुस्तक।



राजकीय ज्ञान में उन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार व्यक्त किया जाता था। एक्ट ने पुराने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अनिश्चित, इन नये न्यायालयों को अपने अधीन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सब न्यायालयों का अधीन करने, उनके ज्ञान-मय मैगने अनियाय की हस्ताक्षरित करने और "उनके कार्य तथा उनकी पद्धति को निम्नलिखित करने के लिए निम्न बनाने का अधिकार भी दिया।"<sup>१</sup> अन्त में एक्ट ने हर मैजिस्ट्री को इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहर अपने भारतीय मामलों के अन्य किसी प्रदेश के लिए उक्त प्रकार के न्यायालय बनाने का अधिकार दिया।<sup>२</sup> सन् १८६६ में उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने के निमित्त इस अधिकार का उपयोग किया गया।

सन् १८६७ के भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट ने सरिपट्ट गवर्नर-जनरल को किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी प्रदेश या स्थान को दूसरे<sup>३</sup> न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्ताक्षरित करने का अधिकार दिया। सन् १८६५ के एक्ट ने सरिपट्ट गवर्नर-जनरल को देशी राज्यों में रहने वाला, सम्राज्ञी की ईसाई प्रजा की उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने का भी अधिकार दिया।

(६)

सन् १८६१ में एक एक्ट और बनाया गया जिसने ईस्ट इंडिया कम्पनी की यूरोपीय सेना को दूर करना समाप्त हो गई। इन यूरोपियों को नियमित सेना में सम्मिलित होने की अवकाश पद-मुक्त होने की कहा गया। इसका अर्थ भारत में ब्रिटिश सैन्य शक्ति को घटाना नहीं था। इसके स्थान पर १८५७ के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन में उनकी काफी बड़ा हिस्सा था।

१८५७ के भारतीय विद्रोह के समय भारतीय सेना में ४०,००० यूरोपियन और २,१५,००० भारतीय थे। ब्रिटिश राजकीय सैन्य दल की कुल संख्या २४,२६३ थी।<sup>४</sup> इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में कम्पनी के लगभग १५,००० ब्रिटिश सैनिक थे। कम्पनी की सेना के तीन यूरोपीय-दल थे—एक बम्बई प्रेसीडेंसी के लिए, एक बंगाल के लिए और एक मद्रास के लिए। इनकी स्वतंत्र रूप से, विभिन्न नियमानुसार भर्ती होती थी। कम्पनी के इन नियमित

१. Clause XV of the Act. Mukherji: Indian Constitutional Documents.

२. Clause CXI of the Act उद्धृत पुस्तक।

३. Clause III of the Act. उद्धृत पुस्तक vol. I, page 412.

४. Appendix I. The Army in India and its Evolution (Government Publication) page 195.

अन्य दलों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय और अनियमित<sup>१</sup> सैन्य-दल भी थे जो देश के विभिन्न भागों में तैयार किये गये थे।<sup>२</sup> कम्पनों के विभिन्न प्रकार के नियमित, अनियमित और स्थानीय सैन्य-दलों के अतिरिक्त, एक बहुत बड़ी दूरक देशों सेना घोरे-घोरे तैयार हो गई थी जो सभ्य पर ब्रिटिश सरकार के काम आ सकती थी। यह मेरा देशी राज्यों की थी और इसकी कुल संख्या १५,००० थी।<sup>३</sup>

१८५७ के विद्रोह से पहले हर प्रेसीडेन्सी का अपना स्वयं सैन्य-संगठन था। यदि युद्ध-काल में दूसरी प्रेसीडेन्सियों में लड़ने और सेवा करने के दायित्व को तद्विषय रूप से माना जाता था किन्तु हर प्रेसीडेन्सी की अपनी पृथक् सेना थी। आरम्भ से ही इन सेनाओं को कितनी ही बार दूसरी प्रेसीडेन्सियों में जाकर लड़ना पड़ा था किन्तु विभिन्न नियमानुसार भर्तों की हुई इन सेनाओं के तत्परता के सहयोग में कठिनाई होती थी। "बंगाल की सेना का वर्णानुसार विभाजन था और उसमें उच्च वर्णों के लोग भर्तों किये गए थे। किन्तु गम्भीर और महान्त के सैन्य-दलों में निम्न वर्णों के लोग<sup>४</sup> भी मिले हुए थे। कुछ प्रेसीडेन्सियों में सैनिकों को अपना कुटुम्ब अपने साथ रखने के लिए स्थान दिया जाता था और कुछ प्रेसीडेन्सियों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इन्हींलिए एक प्रेसीडेन्सी के सैनिक दूसरी प्रेसीडेन्सी में जाकर सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस सम्बन्ध में कई बार व्यवहार में आना भग की गई यहाँ तक कि कभी-कभी उसका रूप विद्रोहात्मक भी हो गया।<sup>५</sup> तथापि मेरा मैं अपने और भारतीयों का सम्बन्ध रहा मित्रतापूर्ण था। ब्रिटिश अधिकारियों को अपने सैनिकों में पूर्ण विश्वास था और उन्हें "भारतीय सैनिकों पर कोई सन्देह नहीं था। भारत के अधिकांश सैनिकों को सैनिकों के हाथों में थे।"<sup>६</sup>

१८५७ के बाद यह सब बदल दिया गया। १८५८ में पोल कमीशन नामक

१. अनियमित सेनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेना (पंजाब में) सिखों, पठानों और अन्य लड़ाकू जातियों से तैयार की गई थी। Strachey : India, Its Administration and Progress, page 477.

२. Chesney, Indian Polity, pages 285-286.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८६.

४. The Army in India and its Evolution, page 15.

५. The Army in India and its Evolution, page 17.

६. Strachey. India; Its Administration and Progress, 477.

सैनिकों के परस्पर सतुलन की नीति के फलस्वरूप की गई। मद्रास और बम्बई की सेनाओं के लिए अब भी स्थानीय और मिश्रित आधार पर भर्ती होती थी। किन्तु बम्बई के सैन्य-दलों में उत्तर भारत<sup>१</sup> के सिख और हिन्दुस्तानियों को भी मिला दिया गया।

२ पाँचवीं बात यह की गई कि यूरोपीय सैन्य-दल की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया गया। "यह निश्चित किया गया कि अनुपात में देशी सेना, यूरोपियन सेना के दूने से बहुत ज्यादा नहो होनी चाहिए और हर प्रकार के सेनाखाने पूरी तरह यूरोपीय हाथों में ही रहने चाहिए।"<sup>२</sup> भारत में ब्रिटिश सैनिकों की अधिकतम संख्या ८०,००० निश्चित कर दी। सन् १८७९ में इनकी वास्तविक संख्या ६५,००० और भारतीय सैनिकों की संख्या १,३५,००० थी।<sup>३</sup> "देश के सारे किण्वों पर" ब्रिटिश तोपखानों का आधिपत्य था। विभिन्न प्रकार की भारी तोपों को चलाने वाले सभी सैनिक यूरोपीय थे।"<sup>४</sup>

३ अन्तिम बात थी सैनिक-अफसरों की नियम संख्या के विषय में पुरानी व्यवस्था के दो दोषों का सुधार—एक तो विशिष्ट कार्यवश अफसरों के बाहर जाने पर उनकी अनपस्थिति में उनके कार्य-भार को उचित रूप से संभालने के लिए सुचारु व्यवस्था की गई, दूसरी बात यह कि सेवाओं में पदोन्नति की विभिन्नता को सुधारने के लिए तीन अफसर सैन्य-दल बनाए गये। सारे सेना के अफसरों को, चाहे वे किसी सेना या दल या किसी असैनिक पद पर काम करते हों, सम्बन्धित प्रान्त के अफसर दल का सदस्य होना आवश्यक था।

✓ सन् १८६१ का सैन्य-युनसंगठन १८६३ में सम्पूर्ण हुआ। कुछ वर्षों में यह अनुभव किया गया कि नई व्यवस्था भी दोष-रहित नहो थी। सन् १८७८-८० के अफगान-युद्ध के कारण स्थिति का फिर से परीक्षण करना आवश्यक हो गया। फलतः १८७९ में एक दूसरा आयोग<sup>५</sup> नियुक्त किया गया। इस आयोग की

zation 1879. Quoted by Strachey: India: Its Administration and Progress. page 480.

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८०

२. Report of the Commission, Strachey उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८०

३. Indian Army and its Evolution. page 21.

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९

५. यह कमीशन ईडन-कमीशन नाम से प्रसिद्ध है।

सैनिक-व्यय घटाने की गद्दे खोजने का और युद्ध की दृष्टि से भारतीय सेना को क्षमता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया।<sup>१</sup>

कमीशन को सिफारिश का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय घुड़-सवार सैन्य-दल आर मैदल सैनिका की टुकड़ियाँ में ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। साथ ही भारतीय सेना का घटाया गया और चार घुड़सवार सैन्य-दल और १८ पैदल सैन्य-दल तोड़ दिए गए। इसके अतिरिक्त हर घुड़सवार दल की शक्ति बढ़ाकर ४९९ के स्थान पर कुल ५५० कर दी गई और प्रत्येक पैदल सैन्य दल की शक्ति बढ़ाकर ७१२ के स्थान पर ८१२ कर दी गई।<sup>२</sup>

ईटन-कमीशन को सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश प्रेसीडेन्सी सेनाओं को बलुठ तोड़ देन के सम्बन्ध में थी किन्तु इसको सन् १८९५ तक कार्यान्वित नहीं किया गया। सैन्य नियंत्रण और संगठन के एकीकरण में सम्बन्धित परिवर्तनों का बर्ताना बाद के अध्याय में किया जायगा।<sup>३</sup>

कम्पनी के हाथों से राजसत्ता के हाथों में शक्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप ये परिवर्तन हुए १८५८ में कम्पनी की जल-सेना भी राजसत्ता की हस्तान्तरित कर दी गई किन्तु इस राजकीय (ब्रिटिश) जल-सेना में मिलाया नहीं गया बल्कि सन् १८६३ में उसका तोड़ दिया गया। यह निश्चय किया गया कि भारत की समुद्री रक्षा का दायित्व राजकीय (ब्रिटिश) जल-सेना पर रहे। भारत, ब्रिटिश राज्य काल में अपनी समुद्री रक्षा के लिए, सदैव (ब्रिटिश) राजकीय जल-सेना पर निर्भर रहा और उसने उच्च जल-सेना के निर्वाह के लिए १ लाख पाँड का वार्षिक असाइन दिया। पहले महायुद्ध के बाद एक राजकीय भारतीय जल-सेना (Royal Indian Marine) बनाई गई किन्तु उसका काम सेनाओं के यातायात, बन्दरगाहों के निरोक्षण और समुद्री मार्ग तक ही सीमित था।

१ The Army in India and its Evolution. page 21.

२ उपर्युक्त पुस्तक, page 21.

३ इसी पुस्तक का अध्याय १३ देखिये।

## छठा अध्याय

# शासन और राजनीति में परिवर्तन

( १ ) ✓

सन् १८६१ का विधान बड़े मौलिक महत्व का था। उसने १८६१ के एक्ट के माध्यम से भारतीय शासन के लिए एक पूरा ढाँचा तैयार किया, जो बाद में विधानों द्वारा बहुत से परिवर्तन किये जाने पर भी भारत में ब्रिटिश राज्य के अन्त तक बना रहा।

शासन के ढाँचे में पहला परिवर्तन १८६१ के भारत-शासन-एक्ट द्वारा किया गया। इसके अनुसार भारत में गवर्नर-जनरल के गठित होनेवाले स्थानों की पूर्ति करने का अधिकार दिया गया। परिषद के सदस्यों का कार्य काल भी पहले सदाचार पर्यन्त था, अब दस वर्षों के लिए निश्चित कर दिया गया।

सन् १८७० में एक और एक्ट बनाया गया। यह सन् १८७० के भारतीय परिषद एक्ट ( Indian Councils Act ) नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार पहली बात तो यह हुई कि सपरिषद् गवर्नर-जनरल को कुछ विषयों में विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। इनको विधान-परिषद् के समझ रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक्ट के विभाग न० १ को किसी प्रान्त या क्षेत्र पर लागू कर देने पर वहाँ को कार्यपालिका सपरिषद् गवर्नर-जनरल के समझ विनियमों के लेख और उनके प्रस्ताव करने के कारण प्रस्तुत कर सकती थी। उक्त लेखों को सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति मिल जाने पर वे नियम, विधान-परिषद् में प्रस्तुत हुए बिना और बिना उसकी स्वीकृति पाए ही, केन्द्रीय और म्यानीय सूचना-पत्रों (Gazettes) में प्रकाशित होने पर बंध हो जाने थे।

सन् १८७० के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि अपने यह नियम बनाया कि जिस प्रदेश में केन्द्रीय विधान-परिषद् की बैठक हो रही हो, वहाँ के उप-गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर को एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में परिषद् के काम में सम्मिलित किया जाय।

इस एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया कि यदि उसके मतानुसार भारत में अथवा उसके किसी भाग में, शान्ति,

१ सन् १८६५ के एक्ट के अनुसार सपरिषद् गवर्नर-जनरल का वैधानिक क्षेत्र-अधिकार पहले तो देशों राज्यों की ब्रिटिश प्रजा पर बढाया गया। बाद में १८६९ के एक्ट के अनुसार यह अधिकार सम्राट की सारी भारतीय प्रजा पर दे दिया गया चाहे कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो अथवा विदेश में हो।

सुरक्षा और ब्रिटिश हिता का कोई भ्रष्ट है तो वह अपनी परिपद के बहुमत के विरोध में भी उक्त वाता का प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को खे ड उठेन अथवा अस्वीकार कर सकता था (अथवा आवश्यकतानुसार) बंध और कार्या-  
निर्वाह कर सकता था। उन विषय के तथ्य और विरोध में अभिलिखित कारणों का दो या अधिक सदस्या को इच्छा पर भारत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था।

अन्त में एक्ट ने गवर्नर जनरल को सिविल सर्विस में भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार दिया। इन नियुक्त भारतीयों का इंग्लैण्ड की परीक्षा में सफल होने का आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन् १८६१ के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, सन् १८६० और १८६६ के परीक्षा-नियमों विनियमा और भारत को तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों ने देश-वासियों के लिए सहायक चरित्र में उच्चतर पद पाने के लिए द्वार बन्द कर दिया था। असन्तोष का दमन करने के लिए लॉर्ड लॉरेन्स ने विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ स्थापित की। इनका उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों को इंग्लैण्ड जाकर पढ़ने के लिए और भारत को सिविल सर्विस अथवा अन्य सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रत्येक छात्रवृत्ति में २०० पाँड प्रति वर्ष दिये जाते। किन्तु तत्कालीन भारत-मन्त्रा ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहीं किया और यह छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर दी गई। किन्तु जैसा कि सन् १८७० के एक्ट में उल्लेख किया गया है, सरकार ने इन बात की आवश्यकता अनुभव की—  
“कि प्रमाणित प्रतिभा और योग्यता के भारतीयों को सिविल सर्विस में भर्ती करने के लिए अधिक सुविधाएँ” प्रदान की जायँ। एक्ट के खंड न० ६ में दो हुई धाराओं का वायान्वित करने के लिए भारत-सरकार से नियम बनाने को कहा गया।

( २ )

भारत-सरकार को सन् १८७० में एक्ट की व्यवस्था रचिकर नहीं थी फलन भारत-मन्त्री द्वारा बार-बार अनुबोधन करने पर भी, उसने १८७१ तक इन विनियमों को नहीं बनाया। जब अन्त में ये विनियम बनकर इंग्लैण्ड पहुँचे तो राज-मत्ता के विधि-अधिकाारियों ने उनको एक्ट के उद्देश्य और उसकी भावना

१. Clause VI of the Act Mukherjee: Indian Constitutional Documents vol I page 235.
२. C. L. Anand History of the Government of India, part II page 255.

के विलकुल विच्छेद पाया। इन विनियमों में एक्ट<sup>१</sup> का अर्थ अत्यन्त सङ्कुचित कर दिया गया था। सन् १८७५ में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की सरकार द्वारा नये नियम बनाए गए। इन नियमों को सिविल सर्विस के न्याय-विभाग की एक या दो नियुक्ति के अतिरिक्त कार्यन्वित ही नहीं किया गया।<sup>२</sup> सन् १८७९ में भारत-सरकार ने एक (मि० रैमजे मैकडोनेल्ड के शब्दों में गृहित) राज-पत्र में भारतीयों के लिए कवेनेण्टेड सिविल सर्विस का द्वार बन्द करने का प्रस्ताव किया। वायसराय (लॉर्ड लिटन) ने इस राज-पत्र के साथ एक गुप्त पत्र में अपने मनोभावों को प्रकट किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया “कि इंग्लैंड और भारत, दोनों की ही सरकारें इस आशय का सन्तोषप्रद उत्तर देने में असमर्थ हैं कि उन्होंने प्रदत्त प्रतिज्ञाओं को पूर्ण रूप से<sup>३</sup> भंग करने के लिए प्रत्येक समभव उपाय का उपयोग किया है। . . . . . शिक्षित देशी व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और सरकार इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किसे बिना ही, उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन दे रही है। एक्ट की उन व्यवस्थाओं के अनुसार, जिन्हें इन देशी आदमियों ने पढ़कर हृदयगम किया है, यदि उन नौकरियों में, जो अब तक कवेनेण्टेड सिविल सर्विस के सदस्यों के लिए सुरक्षित रही हैं, किसी देशी आदमी को लिया गया तो पदोन्नति के निष्पक्ष नियमानुसार उसे उच्चतर पदों पर पहुँचने की आशा होगी और इस पदोन्नति के लिए उसका अधिकार होगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि ऐसी आशाओं और इन अधिकारों को न तो पूरा किया जा सकता है और न पूरा किया जायगा। हमको दो में से एक बात छाँटनी है—या तो हम उन पर रोक लगा दें या उन्हें धोखा दें और हमने कम-से-कम सोचा रास्ता छाँटा है। इंग्लैंड में परीक्षा का प्रबन्ध, और हाल ही में परीक्षार्थियों के लिए घटाई हुई आयु—ये सब ऐसे निश्चित और स्पष्ट छल हैं जो एक्ट को निरर्थक बना देते हैं।<sup>४</sup> फक्त लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के लिए कवेनेण्टेड सिविल सर्विस का द्वार बन्द करने का, और साथ ही १८७० के एक्ट की धाराओं का पालन करने के उद्देश्य से देशी लोगों के लिए एक अवगुठित नौकरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया। किन्तु

१. Quoted by Ramsy Macdonald in his Government of India, Page 103

२. Decennial Report on Moral and Material Progress, 8892, Extracts given by Chablan and Joshi : Readings in Indian Constitution and Administration page 361.

३. Ramsay Macdonald, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०४।

४. C.L. Anand : History of Government in India, part II. page 255 के एक उद्धरण का अनुवाद.

और कुछ वर्गों को अनुचित लाभ होगा। साथ ही यह कहा गया कि प्रतिवर्ष भूति करने के लिए कुछ गिने-चुने स्थान होयें और अधिकांश परोक्षार्थियों के असफल और निराशा होने से एक ऐसा असन्तुष्ट वर्ग बन जायगा जो सरकार के लिए व्यग्रता का कारण हो सकता है।<sup>१</sup> अन्त में आयोग ने “(भारत में स्थायी रूप से अंग्रेज अधिकारों वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालों) उक्त सर्विस की भर्ती अंग्रेजी सिद्धान्तों और शासन-दृष्टि के अनुकूल करने के महत्त्व पर जोर दिया।<sup>२</sup> सर जॉन स्ट्रेची ने वास्तविक कारण को अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट किया “हमारे उद्देश्य के बारे में किसी प्रकार का कपट नहीं है। यह उद्देश्य उन कार्यपालक पदों को—जिनकी सख्या बहुत नहीं है—अपने आदमियों के हाथों में रखना है। (भारत) देश में हमारा राज्य इन (आदमियों) पर और हमारी राजनीतिक और सैनिक शक्ति पर निर्भर है।”<sup>३</sup>

आयोग को स्पष्टतः एक ऐसी योजना की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था, कि जिसके अनुसार सिविल सर्विस में भारतीयों की विस्तृत और उच्चतर नियुक्ति के सम्बन्ध में, उन (भारतियों) के प्रति न्याय किया जा सके। आयोग की सिफारिशों पर क्वेनेस्टेड सिविल सर्विस नाम तोट दिया गया और समस्त लोक-सेवाओं को तीन श्रेणियों—साम्राज्यीय, प्रान्तीय और अधीन—में विभाजित कर दिया गया। सारे महत्वपूर्ण उच्च पद पहले श्रेणी के अन्तर्गत थे और इनके लिए नियुक्ति सपरिपद भारत मंत्री के आधीन थी। इनमें से अधिकांश पदों से भारतवासी, जातीय प्रतिबन्ध<sup>४</sup> अथवा नियम, विनियम<sup>५</sup> की व्यावहारिक कठिनाइयों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए थे। इंडियन सिविल सर्विस के लिए अब

१. Report of the Public Service Commission 1886  
page 49

२. उपर्युक्त रिपोर्ट।

३. Strachey India Its Administration and Progress  
page 54.

४. पुलिस परीक्षा में ब्रिटिश प्रजा के यूरोपीय व्यक्ति ही बैठ सकते थे।

५. सार्वजनिक निर्माण विभाग (P W D), वन-विभाग आदि के लिए या तो राजकीय इंजीनियरों अथवा हिल कालेज के स्नातकों की नियुक्ति जाती। इनका व्यवहार के लिए मढ़ा जाता किन्तु इनमें ब्रिटिश प्रजा के यूरोपीयों को ही प्रवेश मिल सकता था। विबुद्ध भारतीयों को प्रवेश पाने में बहुत कठिनाई होती। इसके बाद भी एक निश्चित अल्पसंख्यक प्रतिशत से अधिक संख्या में भारतीय नियुक्त नहीं किये जा सकते थे।





( ४ )

सन् १८७६ में राजकीय उपाधि एकट बनाकर १८५८ की वमी को पूरा किया गया। उस समय १८५८ में कम्पनी द्वारा भारतीय शासन को राज-पन्ना के हाथों में सौंपने के फलस्वरूप, इंग्लैण्ड की महारानी के पद और उसकी स्थिति में कोई (बैध) परिवर्तन नहीं किया गया था। उपर्युक्त उपाधि के अभाव में भारतीय शासको द्वारा एक सम्भ्रम का बराबर अनुभव किया जा रहा था और १८७५-७६ में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स (इंग्लैण्ड के राजकुमार) के आने के कारण एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।<sup>१</sup> अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार ने महारानी द्वारा एक नई उपर्युक्त उपाधि धारण करने के लिए प्रस्ताव किया। ऐश्वर्य-प्रेमी, साम्राज्यवादी डिजरायली को, जो उस समय इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री था, यह प्रस्ताव बहुत दया। फलन १८७६ का राजकीय उपाधि-एकट बना। इस एकट के अनुसार हर मैजेस्टी को पूरी उपाधि यह हुई "ईश्वरानुग्रहीता, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी, धर्मरक्षिका और भारत की सम्राज्ञी, विक्टोरिया ।"<sup>२</sup> (Victoria, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith and Empress of India )

इस एकट का एक परिणाम यह हुआ कि देशों राज्य, भारतीय साम्राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत आ गए और भारतीय शासको को बंध स्थिति बदल गई। वे सर्वोच्च सत्ता के भिन्न होने के स्वान पर मामूली आघात नरेश हो गए। देशों राज्यों के साथ संधि में जिन अन्तर्राष्ट्रीय विधि सिद्धान्तों को मान्यता दी गई थी, अब वे अमान्य हो गए। "सर्वोच्च सरकार को हिमा सरक्षित राज्य के आन्तरिक विषयों में सकाएण हस्तक्षेप करने और आवश्यकता होने पर शासक को भी बदल देने में अब कोई शिक्का नहीं रही।"<sup>३</sup>

१. सनपूजन पुरतक (Page XXVIII).

२. भारत की सम्राज्ञी के लिए भारतीय भाषा में कंनरे-हिन्द का उस समय उपयोग किया जिसका कारण उसका ऐतिहासिक और साम्राज्यवादी स्वरूप था।

३. Smith · Oxford History of India, Pages 739-40 से भारत-सरकार के १८९१ के एक प्रस्ताव का अनुवाद — भारत-सरकार (जो सम्राज्ञी का प्रतिनिधित्व करती हैं) और देशों राज्यों के (जो सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत हैं), पारस्परिक सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का कोई प्रश्न ही नहीं है। सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत देशों राज्य, प्रतिनिधि भारत-सरकार के आधीन हैं।

(५)

सन् १८६१-९० में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में, अन्तिम प्रदेश को अनुवर्धित किया गया। विनोन्ट रिमल के धन्दा में, "जब कुछ लेने को शेष ही नहीं रहा था।" विदेशी प्रभाव का दूर रमन के उद्देश्य में दो बड़े युद्ध लड़े गए। अफगान-युद्ध में रूस के प्रभाव का और बर्मा-युद्ध में जपान के प्रभाव को दूर रखना था।

१८५७ के विद्रोह के बाद भारत-भरदार ने कुम्भट निष्ठा की नीति का अनवरण दिया था जो उनके कारण अनुवर्धित में रूस का प्रभाव दूर कर दिया गया था। इसके निवारण के लिए लाई रिपन को गवर्नर-जनरल बनाकर भारत भेजा गया। उनमें कानून-अन में खेदा के महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार किया। अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध प्राप्त किया गया, जो नवम्बर १८७८ में आरम्भ हुआ। कुछ समय बाद शाहशाह विजय हुई जो २६ मई १८७९ की गुटमन की संधि में युद्ध समाप्त हुआ। उस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पिशीन जिला प्राप्त हुआ और अफगानिस्तान के (विदेश) सम्बन्ध ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। किन्तु यह संधि कुछ ही महीना में समाप्त हो गई। ३ नवम्बर १८७९ को काबुल में लखन-राजपूत का वन्दन कर दिया गया। फलतः दुष्कर एवं व्ययपूर्ण युद्ध आरम्भ दिया गया। अन्त में लाई रिपन ने अंग्रेजों के अनुरोधानुसार में समझौता किया, जो अधिक म्यामी मिद हुआ। इसके अनुसार अफगानिस्तान पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया जो पिशीन भी भारत-भरदार के अधिकार में रहा।

तीसरा बर्मा-युद्ध हिन्द चीन की ओर से घामोमी प्रभाव को दूर रखने के लिए लड़ा गया। यह केवल एक वर्षवारे तक चला और २५ नवम्बर सन् १८८६ को समाप्त हो गया। फलतः उत्तरी बर्मा ब्रिटिश अधिकार में आ गया और नरेण घाँवी का (बर्मा में) निर्वासित कर दिया गया।

### सातवाँ अध्याय

## वैधानिक विकास

१८६१-१८९२

(१)

सन् १८६१ और १८९० के बीच, भारत में वैधानिक महत्व को विनोती ही पड़ना शुरू हुआ। ब्रिटिश राजनराने और भारतीय नरेणों तथा जनता में पारस्परिक विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुए। सन् १८६९ में महाराजा विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र हर्ज रोबल हादनेस ड्यूक ओफ एडिनबरा भारत आए और १८७५-७६ में

सत्कालीन (ब्रिटिश) राजकुमार ने जो बाद में एडवर्ड सप्तम हुए सारे देश का पर्यटन किया और उन्हें जनता का उत्साहपूर्ण हादिक स्वागत प्राप्त हुआ। इसी समय में भारत-सरकार और गृह-सरकार में गंभीर मतभेद उठ खड़े हुए और फलतः वायसराय ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इस युग की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ ये हैं— १८७८ में वर्नाक्विलर प्रेस (समाचार-संपादन) एक्ट बना और रद्द हुआ, १८७८ में भारतीय शस्त्र एक्ट बना, कपास पर सीमा शुल्क समाप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों के न्याय और उनकी निष्पक्षता के प्रति विश्वास समाप्त हो गया, देश में आर्थिक निक्षेपण और स्वानीय स्वशासन के विस्तार की नीति विकसित हुई, इल्वर्ट बिल पर भीषण और आवेशपूर्ण विवाद हुआ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थापना हुई।

## ( २ )

१८५८ के एक्ट में गवर्नर-जनरल और भारत-मंत्री की पारस्परिक वैधानिक स्थिति को सुस्पष्ट कर दिया गया था। जैसा कि भारत-मंत्री ने १८७१ में एक राज-पत्र में कहा, "भारतीय विषयों के अंतिम नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार गृह-सरकार को है।" स्वयं भारत में व्यवस्था करने वालों की उच्च प्रतिष्ठा, "जुझे अधीनता के आवश्यक बंधन से तनिक भी मुक्त नहीं करती।" फिर भी १८७० तक व्यवहार में स्थिति बिलकुल भिन्न थी। (भारत के) स्थानीय शासक को बहुत बड़ी स्वतन्त्रता थी। सवार साधन की कठिनाइयों और देरी के कारण भारत मंत्री कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं कर पाता था और प्रायः वायसराय, इंग्लैंड के अधिकारियों के समक्ष वार्यान्वित प्रस्ताव के तथ्य प्रस्तुत करता था। वस्तुतः भारत का अधिकारी बर्ग भारत मंत्री को "वायसराय का प्रतिनिधि समझने लगा था जो उस (वायसराय) के कामों को इंग्लैंड की पार्लियामेण्ट और जनता को समझाना था।" किन्तु १८७० में इंग्लैंड से लाल सागर होने हुए भारत तक समुद्री सार की लाइन पूरी हो जाने पर स्थिति बिलकुल बदल गई। भविष्य में भारत-मंत्री के लिए भारत-सरकार का पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो गया और १८७० के बाद इंडिया ऑफिस (अर्थात् सचिपद भारत-मंत्री का कार्यालय) हर विषय में—कार्यपालिका और विधान में—सिद्धान्त और साथ ही व्यवहार की छोटी बातों में भी नियंत्रण

१ Report on Indian Constitution Reform 1918 pages 22 and 23 के एक उद्धरण का अनुवाद

२ Sir Bartle Frere, Quoted by Dodwell History of India

करने लगा। अठोर निष्पत्ति के कारण सधरों ने अस्वस्थ बने,<sup>१</sup> और बनी-बनी स्थिति इनकी विवश हो गई कि बादमराठों की स्थान-भक्त देने पड़े। १८७६ में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के साथ यही बात हुई।

( १ )

गृह-सुरक्षार और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार में उपयुक्त गंभीर मनोदय कानून के सोमा-गुन्ध लोहने के प्रयत्न पर हुआ। यह अभिलेख करते हुए दुःख होता है कि भारतीयों के लिए और किसी बात में इनकी स्पष्टता में अनेका के साथ और निष्पत्ति के प्रयत्नों को अछा और सोमना मिष्ट नहीं दिया किन्तु निष्पत्ति के सोमा-गुन्ध-अवधो इन विवाद में। लरादावर के स्वार्थ के लिए भारतीयों हितावा निष्पत्ति<sup>२</sup> के साथ जाल-बमकर बलिदान कर दिया गया।

भारतीय कानून-संशोधन की दृष्टि से जॉर्ज हार्बर मंचेस्टर के चेम्बरलैंड और बॉर्निंग (अवधमयी मनुष्य) ने अक्टूबर १८७९ में भारत-भवा का एन स्टाट-राय भेजा और उसमें सूत्र पर ६६ प्रतिशत और सूत्री बरते पर ५ प्रतिशत के सार्वभौम भारतीय आदान-गुन्ध का विरोध किया गया। साथ ही यह आक्षेप दिया गया कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम व्यापार बंद रहा है जो भारत और विदेश दोनों के ही अहित में है।<sup>३</sup> अन्त में उसी सोमा-गुन्ध साह देने का मौक़ा का ग़र। भारत-सुरक्षा न एन विविष्ट मनिन का विचारिता पर आदान-गुन्ध की दर घटाने का निर्णय किया और लम्बे रेशे वाली कानून पर ५ प्रतिशत आदान-गुन्ध लगाने के लिए भी अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु कानून पर सोमा-गुन्ध लाहने के लिए मना किया, क्योंकि "उससे देशी उद्योग का वस्तुतः कोई सरल्य नही हो सकता था।"<sup>४</sup> भारत-भवा और भारत-सुरक्षार ने एन-दूधरे को बड़े राज गाय-वध में, किन्तु दोनों की स्थिति बही रही। गृह-सुरक्षार का यह आक्षेप था कि कानून

१ विरोध पर उस समय जब भारत भवा और बाह्यगत विविष्ट राजनीतिक दशा के समर्थन हों, तथा लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लरादावर भारत-भवा।

२ सर जॉन स्ट्रैचो ने विधान-परिषद् में १८७७ में स्पष्ट कहा, "मंचेस्टर के हित, किन्तु कुछ पूर्ण अवसर करते हैं, केवल एन बंद और जाहज़ वगैरह के ही हित नहीं हैं बरन उनमें बरोहा अंग्रेज़ा का स्वागत है। मुझे यह कहने में कोई कष्ट नहीं है कि मेरी दृष्टि में, अपने देश के प्रति मेरे वर्तव्य से बहतर और कोई वर्तव्य नहीं है।" Bannerjee - Fiscal Policy in India, pages 75 and 76 से अनुरोध।

३ Report of Indian Fiscal Commission, 1922, page 88.

४ Bannerjee उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९०

सीमा-शुल्क से "भारतीय निरमाता को झूठा प्रोत्साहन मिलता था और उसका भारतीय और साम्राज्य के हितों पर गंभीर प्रभाव था।"<sup>१</sup> भारत-सरकार ने अपने मन-समयों के लिए तय और आकड़े बनाते हुए यह कहा, "कि (उक्त) शुल्क सरक्षणात्मक नहीं था, भारत-सरकार इतनी राजस्व-आय का बलिदान नहीं कर सकती थी, और सरकार का यह कर्तव्य है कि इस विषय पर विचार करते समय वह भारतीय हितों का ध्यान रखे और आय-शुल्क को तोड़ना इन हितों के विरुद्ध है।"<sup>२</sup> लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारतीय हितों का बलिदान करने को तैयार नहीं थे। फलन-तन्हे त्याग-पत्र देना पड़ा और उनका स्थान लॉर्ड लिटन ने लिया। नये वायसराय ने अपने अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रुचो की सहायता से ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट की आज्ञाओं का पालन किया। इस आज्ञा के अनुसार "भारत की आर्थिक परिस्थितियों में जैसे ही समभव हो कपास के माल पर वर्तमान सीमा-शुल्क को अविलम्ब" तोड़ देना था। इसके पालन के लिए वायसराय को अपनी परिषद् के बहुमत<sup>३</sup> को अवहेलना करना पड़ो। सर अर्सेकोन पैरो के मतानुसार वायसराय का यह कृत्य "अवैधानिक और मविष्य के लिए जोखिमपूर्ण उदाहरण था।"<sup>४</sup> भारत-शासन-एक्ट के विभाग न० ४१ के अनुसार वायसराय को केवल उस समय अपनी परिषद् के बहुमत को अवहेलना करने का अधिकार था जब उसकी सम्मति में, "ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा, शांति या उसके हितों को कोई संकट हो।"

वायसराय के कृत्य से भारत में जनमत अत्यन्त सुन्ध हुआ। "३ मई १८७९ को बम्बई में एक प्रतिष्ठित और बड़ी सभा हुई। उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया।"<sup>५</sup> भारत मंत्री की

१. Bannerjee Fiscal Policy in India पृष्ठ ७२
२. उदयकान्त पुस्तक, पृष्ठ ६८
३. Report of Indian Fiscal Commission 1922 page 95
४. परिषद् के चार सदस्यों के विरोधी अधिलेख ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य हैं।
५. Bannerjee Fiscal Policy in India page 84 के एक उद्धरण का अनुवाद।
६. Mody · Sir Pherozeshah Mehta vol I page 105  
भारत के यूरोपीय व्यापारी समुदाय ने भी वायसराय के कृत्य की तीव्र निन्दा की। उदाहरण के लिए बंगाल के व्यवसायी समुदाय ने गवर्नर-जनरल को यह लिखा कि यह अत्यन्त दुःख की बात है "कि श्रीमान् की सरकार को प्रजा के हितों और उनकी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध इंग्लैंड के अल्प

सरकार को पब्लिश्ड हुई और उसने दमन की नीति को अपनाया। फलस्वरूप उस वर्ष का वर्नाकुलर प्रेस (समाचार-संपादन) एक्ट बना और साथ ही भारतीय सशस्त्र एक्ट भी बनाया गया।

१३ मार्च १८७८ को वायसरॉय ने भारत-मंत्री के पास एक तार भेजकर सन् १८७० के आइरिश कोअर्शन एक्ट के नमूने पर एक समाचार-सम्पादन विधि बनाने के लिए तार द्वारा स्वीकृति भेजने का निवेदन किया। वायसरॉय ने अपने तार में उक्त विधि की रूप रेखा भी दी और "देशी समाचार-पत्रों की उग्र और अब प्रपक्ष रूप से विद्रोहोत्तेजक भाषा के कारण" स्थिति को भयावह बताया। दूसरे ही दिन अनुमति प्राप्त हो गई। उसी दिन विधेयक प्रस्तुत किया गया और दो घंटों में कानून बना दिया गया।

सन् १८७८ के इस एक्ट ने जो प्रायः 'गैंगिय (मुखावरोधक) एक्ट' नाम से प्रसिद्ध है, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वह—प्रान्तीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से— किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक को प्रतिभूति (Security) जमा करने अथवा धर्तनामा लिखने की आज्ञा दे सकता था— इस धर्तनामे के अनुसार वह मुद्रक या प्रकाशक ऐसी कोई बात मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता था जिससे सरकार के प्रति अमर्त्य की और विभिन्न जातियों में परस्पर घृणा की भावना उत्तेजित होने का भय हो। अवांछित प्रकाशन होने पर, सरकार को चेतावनी देने और मुद्रणालय और प्रतिभूति आदि को जब्त करने का अधिकार दिया गया। इसमें बचने का दूसरा मार्ग यह था कि मुद्रक सरकारी अधिकारी के ममक्ष पहले मुद्रण के बाद किन्तु प्रकाशन से पहले सारे लेख प्रस्तुत करे और उस अधिकारी द्वारा अस्वीकृत सारी बातों को निकालकर प्रकाशित करे ~~करे~~।

१८७८ का यह एक्ट सन् १८७० के आइरिश कोअर्शन एक्ट के (जो आयर्लैंड-वासियों से सबध रखता था) कहीं अधिक उग्र था। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायाधिकारी में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। सर अर्नेस्टोन् पैरो ने भारतीय परिषद् की कार्यवाही में अपने विरोध के अभिलेख में इसे, "एक प्रतिगामी, विवेकहीन और भविष्य में भारत की प्रगति के लिए घातक" प्रस्ताव बताया। "कोई साम्राज्यवादी विधि बनाने वाला, विरोधी समाचार संपादन का मूलोच्छेद करने के लिए इसमें अधिक घातक उपकरण नहीं बना सकता।" १

इस मुखावरोधक एक्ट का भारतीय शिक्षित-वर्गों में, विशेषकर बंगाल में जहाँ इसके कठोरता के साथ कार्यान्वित किया गया था, प्रबल विरोध हुआ।

बलवत्ते के टाउन-हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें ५००० व्यक्ति उपस्थित हुए। सभा ने उक्त का विरोध किया और उसे रद्द करने के लिए 'हाउस ऑफ कॉमन्स' से निवेदन किया। इंग्लैंड में मक्खि-महल के बदलने और भारत के लिए लॉर्ड रिपन के नये वादसूत्राय नियुक्त होने तक, यह बान्दोलन इंग्लैंड और भारत, दोनों ही स्थानों में चलता रहा।

लॉर्ड रिपन उक्त को रद्द करने के लिए उत्सुक थे किन्तु उन्हें परिणाम के अन्दर और बाहर करकारी विरोध का अतिव्यक्त करने में कुछ समय लगा और उन्हें "हई १८ थोर चान्से १० के दाय के भारतीयों जनदार-दल के तर्क ध्यान में आए" और अन्त में मत्स्यपरोक्ष एक्ट सन् १८८७ में बाहर रद्द हो गया।

प्रो० टॉडवेल का यह कथन सत्य है कि लॉर्ड रिपन का यह काम "और सब कामों से बड़ा काम" था।<sup>१</sup> क्योंकि मुनरो द्वारा बहुत पहले कहे हुए शब्दों के अनुसार, "स्वतन्त्र समाचार-पत्र और विदेशी शासन, ये दोनों बातें विरोधी हैं और बहुत समय तक एक साथ टिक नहीं सकती।"<sup>२</sup>

( ५ )

इस वर्ष का दूसरा दमनकारी एक्ट, भारतीय शस्त्र एक्ट था। इसके अनुसार भारतीयों की अनुशक्ति के बिना शस्त्र रखना, ले जाना अथवा उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध था। एक्ट की कार्यान्वित करने के लिए, अपराधियों को दंड दंड देने की व्यवस्था की गई।<sup>३</sup> इस एक्ट के अन्तर्गत बचाए हुए नियमों के अनुसार, यूरोपीय और अन्य गोरे लोग अथवा यूरोपियन और कुछ सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति एक्ट की शारदा से मुक्त कर दिए गए।<sup>४</sup> प्रेसीडेन्सी नगरों और

१. Lucien Wolf. Life of Lord Ripon Vol II. page III.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ११४.

३. Dodwell : History of British India. 1858-1918. pages 252-253.

४. एक्ट की शारदाओं का पालन न करने पर साधारणतया कारावास या जुर्माने का दोनो दंड की व्यवस्था थी। इस कारावास की अवधि तीन वर्ष तक हो सकती थी। किन्तु छिपाने या छिपाने का प्रयत्न करने की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष तक हो सकती थी। साथ में जुर्माना भी हो सकता था और दंड में केवल जुर्माना भी हो सकता था। Section X of the Act. F. C. Widge : Indian Arms Act XI. 1878. pages 47, 68 and 69.

५ See Schedule 1. of the Rules item 13, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ 130.



रगून में पुलिस कमिश्नरों को और ब्रिटिश भारत में जिलाध्यक्षों को अधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रार्थियों का पूर्वचरित जान लेने पर, एक नियत समय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इन व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति के बदले में नियत देय देना आवश्यक था।<sup>१</sup> इस नियम का बड़ी सफुचित भावना और कठोरता के साथ पालन किया गया और भारतीय नवयुवकों में भेद भाव किया गया। इन कारणों से साहसी भारतीयों को उक्त प्रस्ताव विशेष रूप से गर्हित लगा।

( ६ )

लॉर्ड रिपन की नीति उदार और जन प्रिय थी। उनके कार्य-काल में 'इन्वर्टेड बिल' नामक विधेयक पर भीषण और तीव्र जातीय विवाद हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य क्वेनेन्टेड सिविल सर्विस के भारतीय और अंग्रेजी सदस्यों के अत्यन्त अनुचित भेद-भाव को दूर करना था। तत्कालीन विधि के अनुसार प्रेसीडेन्सी नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहने वाले यूरोपियनों का अभियोग-परीक्षण केवल यूरोपियन मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकारी हा कर सकने थे। भारतीय मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकारी चाहे वह उस जिले के अन्य यूरोपीय अधिकारियों से पद में बड़ा भी होता, किन्तु वह उक्त अभियोगों का निर्णय नहीं कर सकता था। जैसा कि श्री आर सी दत्त ने कहा इस भेद-भाव के कारण भारतीय नफ़रतों की सत्ता बहुत क्षीण होती थी। बंगाल के उप-गवर्नर सर एशले ईडन ने स्वीकार किया कि "इस बात का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देता कि उपर्युक्त अनुभव और शिक्षण से जिला-मजिस्ट्रेट और जिला जज के पद पर प्रतिष्ठित, क्वेनेन्टेड सिविल के भारतीय सदस्यों को यूरोपियनों पर वह श्रेष्ठाधिकार प्राप्त न हो जो उक्त सिविल के अन्य सब सदस्यों का प्राप्त होता है।"<sup>२</sup> अतः लॉर्ड रिपन की सरकार ने इस झुड़ जातीय भेद-भाव को दूर करने का निर्णय किया और इस उद्देश्य के एक विधेयक का लेख बनाकर स्वीकृति के लिए इंग्लैंड भेजा। २ फरवरी १८८३ को यह विधेयक विधान-परिषद् में प्रस्तुत किया गया।<sup>३</sup>

यूरोपियनों ने सारे देश में विशेषकर बंगाल में बड़ा कोलाहल मचाया। "कलकत्ते के घबसायी इस प्रश्न से संबंधित नहीं थे, किन्तु वे भी उतने ही उग्र

१ See, Rule No. 30. ...

२. J. N. Gupta Life and Works of R. C. Dutt. page 94  
के एक उद्धरण का अनुवाद।

३ विस्तृत बगन के लिए देखिये Mody : Sir Pherozeshah Mehta Vol. II. pages 125-128 and Lucien Wolf. Life of Lord Ripon, Vol. II, pages 128-150.

हए जिनने कि इन प्रदन में मरखित बिहार के रोषक (Planters) । लॉर्ड रिपन के गन्तार-सम्मेलनों का बहिष्कार किया गया स्वयं लॉर्ड रिपन का अग्रमान किया गया । उनके विरुद्ध का भाव धारण किया गया था वह अग्रिम म्म में उन जोरनिवेधित भावना का छातक था जिने पश्चिमी हिन्दू ईश मन्त्र के अधिवासी न जन दासा को स्वयं इन के सम्बन्ध में प्रदर्शित किया था जपदा उन भावना का स्मरण करतथा था जिससे दक्षिण अमेरिका के अधिवासीमण, वहाँ के अधिवासीमण में ईनाई धम का प्रचार करतथा ।<sup>१</sup>

एक मन्त्रा सम्मेलन ईनाई गटे और सदा लागू स अधिक हयथा<sup>२</sup> एकत्रिज किया गया । बन्दन व डाउन हार म आन्ध्र भाग्योदा का रोप प्रकट करने वाले एक बिगाठ सदा हटे । इसमें ता व्यान्दान दिव गए उनको उग्रता, मौखिक की मारी मीमात्रा व परे थी । प्रयोडन्मों में अन्य मन्त्र स्थानों पर भी ऐसी ही ममार्ण हुई । आन्ध्र भाग्योदा समाचार-पत्रों का विपणनकर इयलिप्रमैव' की भाषा अग्रन्त भावक और विवेकगन्त हा गटे । इस आन्दोलन में स्वैच्छामैविकों (volunteers) की सामूहिक मन्त्र में पद-मण करने था उनजिन किया गया । कुछ व्यक्तिनों ने उदाहार म्मा में मैविक वर्ग की मनाबर्तिन हा भी परस्था । दूसरे मण्ठों में सता में अमजिन टन्त्र करतथा का भी प्रयत्न किया गया ।<sup>३</sup>

इस विरोध की लाडे रिपन के मन्त्रालयान नामन में मुविधा की दृष्टि में आवश्यकता थी, किन्तु म्माय हान हृण नी यह अग्रन्त महन्वपूर्ण अथवा अधिदम्प नहीं था ।<sup>४</sup> इनके विरोध में का उग्र भावनाएँ उठ गयी हूँ, उनका अनुमान करता बटिन है । लॉर्ड रिपन ने कहा, "यदि मुझे पता हांता कि क्या (परिणाम) होया तो मैंने अपने-आपका दम नूतान में नही बाटा होना ।"<sup>५</sup> लॉर्ड रिपन ने मनुमरी अधिवासीमों में परामर्श किया था पर ऐसा प्रनीत होता है कि मर हेनरी मेन<sup>६</sup> के अनिरिक्त अन्य व्यक्तिमों ने किनी प्रकार उपद्रव की आगवा नहीं की ।

१. Dodwell - History of India. 1858-1918, page 261.

२. Bannerjee A Nation in the Making, page 85

३. Lucien Wolf Life of Lord Ripon Vol II page 128.

४. उन्मुक्त पुष्पक, पृष्ठ १३६

५. उन्मुक्त पुष्पक, पृष्ठ १३५

६. वह भारत का परिषद् का सदस्य था और इन दिना पेरिस में था । परामर्श विम्वे जाने पर उसने जी लेख लिखा उसे भारत-मन्त्र-परिषद् में पढने के बाद वही रखकर भूल गए और वह माग्न नहीं भेजा जा मता । उसमें मैंने मे लिखा था, "यह भावनाओं का प्रदन है और वहाँ भावनाओं की प्रतिद्वन्दिता है ।

लॉर्ड रिपन ने कारणों की जाँच की थी और उसका यह निष्कर्ष था "न्यायाधि-  
पतियों का वेतन घटाने और मिस्टर मित्र को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति बनाने  
के कारण अभिवक्ता वर्ग में बड़ा झोम हुआ है और वह वर्ग सरकार को शक्ति  
पहुँचाने के अवसर के लिए अत्यन्त लालायित था। उक्त विधेयक का विरोध करने  
का विचार<sup>१</sup> कुछ अगरेज वॉरिस्टरो की न्याय-सभा के पुस्तकालय में सूझा था।"  
खुफिया विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष मि लैम्बर्ट के अनुसार कलकत्ते के पूंजी-  
पतियों को इस बात का भय हुआ कि चाय के बगीचे में काम करने वाले उनके गोरे  
अभिकर्ताओं के साथ, भारतीय जजों की अध्यक्षता में काम करने वाले कौजदारों  
न्यायालयों द्वारा, उच्च न्याय नहीं हो सकेगा। यरेखियन समुदाय, एडकी विधेयक  
के कारण चिन्ता हुआ था। इस विधेयक के अनुसार इजीनियरिंग कॉलेज में केवल  
शुद्ध एशियावासियों को ही दाखिला मिल सकता था। अपने सारे समाज द्वारा इन  
आक्षेपों के समर्थन के लिए, यूरोपीय स्त्रियों के लिए खतरे की आवाज उठाई।<sup>२</sup>

विधेयक के मूल रूप में सब जिला मजिस्ट्रेटों और जिला जजों को यूरो-  
पियनों के अभियोग-निर्णय का अधिकार दिया गया था। प्रेसीडेन्सी नगरों के  
बाहर प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बिना जाति-भेद किये,  
प्रथम श्रेणी के उन मजिस्ट्रेटों को, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, उक्त अधिकार दे दें।  
अगस्त १८८३ में भारत-सरकार को विधेयक में संशोधन करने के लिए भारत-  
मन्त्री की अनुमति मिल गई। इस संशोधन के अनुसार नए अधिकार केवल जिला  
मजिस्ट्रेटों और जिला जजों को देने का निश्चय किया गया। किन्तु विरोधियों को

जातीय भेद-भाव के कारण भारतीय जजों के अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता  
है, उससे वे अपने को अपमानित अनुभव करते हैं। देशी व्यक्तियों को  
अधिकार देने से यूरोपीय समुदाय संशुभित है क्योंकि उसे चिढ़े हुए भारतीयों  
द्वारा इस अधिकार के दुरुपयोग का भय है। यह कारण यूरोपीय भावनाओं  
के विस्फोट का वहना रहा है। वर्तमान प्रस्ताव के कारण ऐसा विस्फोट हो  
सकता है और तब हमें उसके औचित्य पर शका हो सकती है उपर्युक्त पुस्तक,  
पृष्ठ ३७९-३८१

१ Lucien Wolf *Life of Lord Ripon* Vol. II p. 130

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १३१। इस आवाज कास वैसे अधिक प्रभाव हुआ।  
मेरेडिथ टाउन सेण्ड ने टॉम ह्यथ को एक पत्र में लिखा, "क्या आप ऐसे  
देश में रहना चाहेंगे जहाँ आपकी शक्ति सारे जाधरों के हाथों में  
अपराध पर तीन दिन का कारावास हो सकता है, जहाँ न्यायाध्यक्ष देशी  
आदमी हो .... जो गोरे आदमियों का अपमान करने के लिए अवसरों  
की टोह में रहता हो।"

# वित्तीय निक्षेपण और स्थानीय स्वशासन

(१)

सन् १८३३ में ही भारत के समस्त वित्तीय अधिकार सपरिषद् गवर्नर-जनरल के हाथों में केन्द्रित थे। "सब प्रान्तों के सारे राजस्व की एक तिथि होती थी। सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा ही व्यय का प्राधिकार दिया जा सकता था।"<sup>१</sup> प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय उपकरों (cesses) के अतिरिक्त कोई अन्य कर लगाने अथवा ऋण उगाहने का अधिकार नहीं था। अतः भारत-सरकार की अनुमति के बिना, प्रान्तीय सरकारें न तो कर लगा सकती थी, न ऋण उगाह सकती थी और न व्यय ही कर सकती थी।

एक विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण देश में उक्त केन्द्रीकरण के बहुत से दोष थे। भारत-सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं का ज्ञान न के बराबर था और साथ ही उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि राजस्व के स्थानीय अधिकारों की किन प्रकार वृद्धि की जा सकती है। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रदेश केन्द्रीय राजस्व-कोष के समक्ष अपनी माँग रखने में अनुचित प्रतिद्वन्द्विता करते थे और उन्हें मितव्ययिता के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। जैसा कि सर जान स्ट्रेची ने कहा, "सार्वजनिक धन्य का वितरण भ्रष्ट होकर छीना-झपटी में परिवर्तित हो गया था, जो उग्रतम होता था इसी की जीत होती थी और उपयुक्तता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। स्थानीय मितव्ययिता से कोई स्थानीय लाभ नहीं होता था। अतः अपव्यय को रोकने के लिए उत्साह न के बराबर था। स्थानीय आय-वृद्धि से स्थानीय लाभ न होने के कारण, वहाँ की राजस्व-आय को बढ़ाने का प्रयत्न, न्यूनतम था।"<sup>२</sup>

इन व्यवस्था के दोषों की ओर कितने ही अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ था। जनरल डिकेन्स ने सन् १८६० में ही सुधार के लिए सुझाव दिया था। अर्थ-सदस्य मि लॉग ने सन् १८६१-६२ और १८६२-६३ में सरकारी बजट प्रस्तुत करने के समय अपने वक्तव्य में इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया था। सन् १८६७ में सर रिचर्ड स्ट्रेची ने प्रान्तीय वित्त के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित योजना भी बनाई थी, किन्तु इस विषय पर लॉर्ड मेयो ने समय तक कोई कार्यवाही नहीं

१ Strachey India, its Administration and Progress page 121.

२ The Report on Indian Constitutional Reforms 1918 page 69

होने के कारण अथवा पिछड़ेपन या अनुत्तम होने के कारण, जिन प्रान्तों का व्यय कम था, उन्हें, मितव्ययिता, दोनता अथवा पिछड़ेपन का दण्ड दिया गया।”<sup>१</sup>

इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि राजस्व की उगाही में मितव्ययिता लागू करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ अपनी आय के मितव्ययी उपयोग और समुचित विनयन में तो था, किन्तु राजस्व की उगाही में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। इसके अतिरिक्त आवकियों और मुद्राक (स्टाम्प) शुल्क में बड़ी घाँसेबाजी की जाती थी और उगाही में सरकार को राजस्व की हानि होती थी। अतः १८७७ की योजनानुसार लॉर्ड लिटन की सरकार ने उगाही में प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ निहित करने का प्रयत्न किया।

१८७७ की योजना को वाइसरॉय की परिपद के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रैची ने तैयार किया था। इस योजना के अनुसार व्यय के कुछ और शीर्षक भी प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिए गए। इनमें मालगुजारी, आवकारी, स्टाम्प, सामान्य शासन, लिखने का सामान, विधि और न्याय की गणना थी। इन सेवाओं के बदले में प्रान्तीय सरकारों का स्थायी अनुदान नहीं बढ़ाया गया वरन् प्रान्त में उगाही हुई राजस्व की कुछ मदों में उनका साझा कर दिया गया। आवकारी, रसीद, विधि, न्याय आदि कुछ अधिकरणों से प्राप्त होने वाली राजस्व-आय प्रान्तीय सरकारों को इस शर्त पर दे दी गई कि इन अधिकरणों की अनुमानित आय के एक निश्चित परिमाण से अधिक आय होने पर सर्वोच्च सरकार उस अतिरिक्त परिमाण का आधा भाग ले लेगी और घटा होने पर उसमें भी आधा साझा करेगी।<sup>२</sup>

प्रान्तीय सरकारों को वित्तीय नियंत्रण के अधिकार सौंपने का प्रयोग सुचारु रूप से चला। लॉर्ड रिपन, उनके अर्थ-सदस्य मेजर बोरिंग (बाद में लॉर्ड क्रोमर) तथा उनकी सरकार ने वित्तीय विषयों में प्रान्तीय उत्तरदायित्व को और अधिक बढ़ाने का निर्णय किया। यह निर्णय ३० सितम्बर १८८१ के प्रस्ताव द्वारा किया गया।

१८८२ की योजना के अनुसार निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था तोड़ दी गई और प्रान्तीय सरकारों को राजस्व की कुछ मदें पूरी तरह दे दी गई और कुछ अन्य मदों में उनका साझा कर दिया गया। राजस्व की मदों का तीन बर्गों में विभाजित किया गया — साम्राज्यीय, प्रान्तीय और विभाजित। प्रान्तीय वर्ग के राजस्व

१ Gyan Chand The Financial System of India, page 143.

२ Mukherjee Indian Constitutional Documents. vol. I. page LXI.

पर प्रान्ता को पूर्णाधिकार दिया गया और विभाजित वर्ग के राजस्व पर प्रांतीय और साम्राज्यीय सरकार को प्रायः समान अनुपात में अधिकार दिया गया। साम्राज्यीय शीर्षकान्तर्गत राजस्व, केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए था। मालगुजारी की साम्राज्यीय शीर्षक में गणना की गई थी, किन्तु प्रान्तीय आय में कमी होने पर उक्त मालगुजारी आय का एक निश्चित भाग दवर पूति करने की व्यवस्था की गई। साम्राज्यीय शीर्षक में सीमा शुल्क, डाक और तार, रेलवे, अफीम, नमक, उपहार, टक्साल, होम चार्ज और सैनिक विभाग की गणना थी। दीवानी विभाग और प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की आय पुनः रूप से प्रान्तीय थी। आवकारी रसीद, वन और निवन्धन की मदें दोनों में विभाजित थी। अनिश्चितता का समाप्त करने के उद्देश्य से १८८२ के प्रस्ताव द्वारा पंचवर्षीय बन्दीवस्तु की व्यवस्था चलाई गई। युद्ध और दुर्भिक्ष-सम्बन्धी असाधारण व्यय के बारे में साम्राज्यीय और प्रांतीय सरकारों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध को भी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया। साधारणतया, अत्यन्त असाधारण और वर्षान्तपूर्ण परिस्थितियों के अतिरिक्त युद्ध के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों से कोई माँग नहीं की जा सकती थी। दुर्भिक्ष-व्यय के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों की सीधे और समय पर सहायता करने के लिए वचन दिया गया। वामा और दुर्भिक्ष-पीड़िता की सहायता के लिए भारत-सरकार की १५ लाख पौण्ड की वार्षिक बाँट में से, प्रान्तीय सरकारों अकाल के लिए विशेष निधि संग्रह कर सकती थी।

इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। मन् १८८४ में प्रान्तीय वित्त के असाधारण चढ़ाव-उतारों को रोकने के लिए हर प्रान्तीय सरकार के आकलन अवशेष (Credit balance) की न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट कर दी गई। १८८९ की इस व्यवस्था का १८८७ में, १८९२ में और फिर १८९७ में नवीकरण किया गया और उसके निहित सिद्धांतों को यथावत् रखा गया। किन्तु प्रत्येक नवीकरण के समय पंचवर्षीय बन्दीवस्तु की व्यवस्था के मुख्य दोष सामने आये। १८९६ में सर्वोच्च विधान-परिषद् में बंगाल के उप-गवर्नर ने अपने भाषण में इन दोषों का इन शब्दों में वर्णन किया — "मैं, प्रति पाँच वर्ष बाद सशोधन करने की वर्तमान व्यवस्था का विरोध करता हूँ। प्रान्तीय भेड का गिराकर उसके ऊन को पूरी तरह उतार लिया जाता है और नये रोपे बड़ने तक उसे ठिठुराने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रान्तीय व्यवस्था का इतिहास साधारणतया इस प्रकार है—पहले दो वर्षों में कृपणता और मितव्ययिता बरती जाती है और नामा नो स्वर्गित किया जाता है, फिर दो वर्ष तक स्वाभाविक गति और विविधता काम किया जाता है और अन्तिम वर्ष में अवशिष्ट निधि का इस भय से अपव्यय किया जाता है कि कहीं सशोधन के समय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दान से

सर्वोच्च सरकार बचे हुए परिमाण को छीन न ले। यदि यह बात चरित्र को गिराने वाली नहीं है तो कम-से-कम अनुचित अवश्य है। मेरे सम्मति में सर्वोच्च सरकार को हर पाँच वर्ष बाद प्रान्तीय भेद को उपर्युक्त प्रकार से नहीं भूँडना चाहिए। यदि भारत-सरकार नवीनीकरण के हर अवसर पर यथासंभव कम परिवर्तन करे तो स्थानीय सरकारों का बहुत बड़ा हित होगा। वह आर्थिक निश्चितता, जो १८७० की वर्तमान योजना की एक मुख्य वस्तु थी, केवल इस प्रकार से ही व्यवहार में अनुभव की जा सकती है।<sup>१</sup>

( २ )

वित्तीय निक्षेपण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास को प्रोत्साहन देने की नीति का घनिष्ठ सम्बन्ध था। सन् १८७० के प्रस्ताव प्रवर्तकों ने यह आशा की थी कि स्वशासन के विकास के लिए नगरपालिका-संस्थाओं को बृद्ध करने के लिए और शासन-कार्य में भारतीयों और यूरोपियनों को अधिकाधिक साथ लेने के लिए, वित्तीय निक्षेपण की नीति से क्षेत्र विस्तृत होगा।

प्रेसीडेंसी नगरों में नगरपालिका सरकार १८७० से बहुत पहले से थी किन्तु अन्य नगरों में नगरपालिका-सरकार बनाने का प्रथम प्रयत्न सन् १८४२ के एक्ट नं. ६६ द्वारा किया गया। इस एक्ट के अनुसार "हर सार्वजनिक स्थान के निवासियों को स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से श्रेष्ठतर प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया।"<sup>२</sup> स्वेच्छा के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण किसी स्थान के दो सिद्दाई निवासियों के प्रार्थना-पत्र देने पर ही उक्त अधिकार का उपयोग किया जा सकता था। केवल एक नगर में उक्त प्रबन्ध किया गया किन्तु वहाँ के निवासियों ने कर देना केवल अस्वीकार ही नहीं किया बरन् उगाही करने वाले क्लर्क पर अनधिकार प्रवेश का अभियोग भी चलाया।<sup>३</sup> इस एक्ट को १८५० में रद्द कर दिया गया और भारत के विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका संस्थाएँ बनाने के लिए उसी वर्ष का एक्ट नं. २४ बनाया गया। सन् १८४२ का एक्ट, प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था से बहुत अप्रिय हो गया था। सन् १८५० के

१ Quoted by G. K. Gokhale in his evidence before Welby Commission of 1897. page 11 Appendix 1. —Speeches of Gokhale.

२ Moral and Material Progress Report 1882 Chabla-nu and Joshi Readings in Indian Administration page 400

३ Imperial Gazetteer of India Vol IV p 286

एक्ट में परोक्ष वर के लिए अनुमति दी गई। यह एक्ट भी अनुज्ञाप्रद था — "प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह एक्ट को किसी नगर में इस बात का विश्वास हो जाने पर ही कार्यान्वित कर कि नगर निवासों प्राथमिकता के पूरी तरह अनुकूल है। तदुपरान्त सरकार को मजिस्ट्रेट और कुछ अन्य व्यक्तियों को कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कमिश्नरों की सभा आवश्यकता पर निर्भर थी। इन कमिश्नरों को नियम बनाने के विस्तृत अधिकार दिये गए। इन्हीं अधिकारों के अन्तर्गत वह दूरी-दूर जो आजराज्य भारत में इतना प्रचलित है पहली बार वैध हुआ।" इस एक्ट का उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और बम्बई में ही विस्तृत रूप से काम उठाया गया। सन् १८६३ में राजकीय सभा समारंजन आयोग (Royal Army Sanitary Commission) ने अपनी रिपोर्ट दी। इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका एक्ट बनाए गए। बंगाल का एक्ट १८६६ में बना, मद्रास का १८६५ में, पंजाब का १८६७ में और उत्तरी पश्चिमी प्रान्त का १८६८ में। इन एक्टों के अनुसार नगरपालिका बनाने के लिए, निर्वाचन का उपयोग करने का प्राधिकार दिया गया किन्तु इसका उपयोग बस्तुतः केवल पंजाब और मध्यप्रान्त में हो किया गया। नवनिर्मित नगरपालिकाओं का मुख्य काम समाजन का मुद्धार था।

सन् १८७० के प्रान्तीय विधायक मन्त्रालय प्रस्ताव ने इसी नीति अपनाने की आवश्यकता की आशय व्यक्त किया कि उसके फलस्वरूप शिक्षा, समारंजन, निशुल्क चिकित्सा और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण के लिए निर्दिष्ट निधि की व्यवस्था द्वारा स्थानीय अभिवृद्धि, निरीक्षण और सावधानी को अभिव्यक्ति मिल सके। इस उद्देश्य के विभिन्न प्रान्तों में १८७१ और १८७४ के बीच नए नगरपालिका-एक्ट बनाए गए। इनमें अधिकांश वृद्धि के साथ निर्वाचन सिद्धांत के विस्तार की व्यवस्था की गई किन्तु केवल मध्य प्रान्त में ही सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत रूप में सफलता के साथ अपनाया गया। १८८२ के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव में १८७० की नीति के परिणामों का इन शब्दों में सारांश दिया गया है — "सन् १८७० के बाद बड़ी भारी प्रगति हुई थी। स्थानीय उपकरणों में बहुत बड़ी आय हुई थी और कुछ प्रान्तों में आय व्यवस्था को बिना किसी रोक-टोक के, स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया था। नगरपालिकाओं की संख्या और उपयोगिता में भी वृद्धि हुई थी। किन्तु देश के विभिन्न भागों की प्रगति में अब भी इतना बड़ा असाम्य



था कि उसके लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों का कारण नहीं दिया जा सकता। कुछ स्थानों में स्थानीय प्रबन्ध के लिए परिगृहीत सेवाएँ केन्द्रीय शासन के हाथों में सुरक्षित थी। सभी स्थानों में पुलिस-कार्य के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं से एक बड़े परिमाण में खर्चा लिया जाता था किन्तु उस पुलिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।<sup>१</sup>

लॉर्ड रिपन की सरकार ने अपने १८८१ के प्रान्तीय वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव के स्थानीय स्वशासन-विकास के विषय पर प्रान्तीय सरकारों की सम्मति आमंत्रित की थी। उसने अपने निम्नो प्रस्तावों को १० अक्टूबर १८८१ को प्रान्तीय सरकारों के पास भेजा और उनसे उस पर अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा। फलस्वरूप १८८२ का स्थानीय स्वशासन-सम्बन्धी प्रसिद्ध प्रस्ताव बना।

( ३ )

१८८२ के प्रस्ताव से भारत में स्थानीय स्वशासन कागजरूप से आरम्भ हुआ। स्थानीय स्वशासन के विकास का प्रतिपादन "शासन में सुधार के मुख्य उद्देश्य" से नहीं किया गया, वरन् इस कारण कि वह 'राजनीतिक और सामान्य जागृति के लिए एक उपकरण के रूप में वाछनीय था।' "कुछ समय बाद स्थानीय ज्ञान और अनुराग के कारण स्थानीय शासन में कुशलता स्वतः बढ़ेगी।" "सरकारी विभागों पर भार कम होगा और लोक-भावना से प्रेरित श्रिसित और वृद्धि-कर वर्ग को काम देकर नये कार्यालय खोलने की माँग पूरी होगी।" प्रस्ताव में कहा गया कि "सरकारी अधिकारियों ने विगत प्रयत्नों में सद्दुद्देश्य से प्रेरित होकर किन्तु बार-बार हस्तक्षेप करके इन प्रयत्नों को कुचल दिया था।" "तदुपरान्त प्रस्ताव ने भविष्य की नीति निर्धारित की।

पहली बात तो यह थी कि केवल बड़े या छोटे नगरों में ही नहीं वरन् सारे देश में स्थानीय मंडल बनाने थे। इन मंडलों की निम्नलिखित विधि और उनके निर्दिष्ट दायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था।<sup>२</sup> माध्य क्षेत्रों में स्थानीय परामर्श-समिति की जगह इन्हीं मंडलों को मिलनी थी। उनके कार्य में स्थानीय अनुराग बढ़ाने के लिए

१ Mukherjee. Indian Constitutional Documents. Vol. I page 639

२ Para 5 of the Resolution उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२, प्रस्ताव का छठा पैराग्राफ।

४ Mukherjee Indian Constitutional Documents Vol. I. page 643. Para 7.

५ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव का पैराग्राफ नं १०

और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए यह नियम बनाया गया कि, "इनमें से किसी मंडल का क्षेत्र किसी दशा में बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए।"<sup>१</sup> यह सुझाव रखा गया कि बड़े-से-बड़ा क्षेत्र, तहसील या ताल्लुका हो। इन स्थानीय मंडलों के ऊपर जिला-मंडल बनने थे। इन जिला-मंडलों को नियंत्रण के लिए कुछ अधिकार दिये गए।

५ दूसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में छोटे और बड़े नगरों में स्थानीय शासन के निर्वाह और विस्तार के लिए व्यवस्था की गई थी। नगरों के मंडलों को यथासंभव स्वतन्त्र रखना था, किंतु कुछ विषयों में जिला-परिषद के नियंत्रण-सम्बन्धी कुछ अधिकार हो सकते थे।

६ तीसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में यह निश्चित कर दिया गया था कि "सरकारी सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।"<sup>२</sup> इस प्रकार सहरों और ग्राम्य दोनों प्रकार के मंडलों में गैर-सरकारी सदस्यों का प्राधान्य होना था। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य-काल दो वर्षों के लिए निश्चित था।

७ चौथी बात यह थी कि सपरिषद गवर्नर-जनरल ने इस बात की सिफारिश की "कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,<sup>३</sup> निर्वाचन-व्यवस्था को अधिकाधिक व्यवहार में लाया जाय" साथ ही<sup>४</sup> हर प्रान्त को अपने लिए उपयुक्त व्यवस्था छांटने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रयोग करने का सुझाव दिया गया।"<sup>५</sup> यह कहा गया कि<sup>६</sup> साधारण मत, सन्निह मत, क्षेत्र विभागानुसार निर्वाचन, सारे नगर द्वारा निर्वाचन, न्यूनाधिक अर्हता द्वारा निर्वाचन, जाति और व्यवसाय के अनुसार निर्वाचन और साथ ही अन्य निर्वाचन-प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है।" प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया कि मंडल के भारतीय सदस्यों के नाम के साथ उनके कार्य-काल की अवधि में रायबहादुर अथवा खाँ बहादुर की सम्मानार्थ उपाधि व्यवहार में लाई जाय।

पाँचवीं बात सपरिषद गवर्नर-जनरल की यह इच्छा थी कि ग्राम्य और सहरों दोनों प्रकार के स्थानीय मंडलों के सभापति<sup>७</sup> यथासंभव गैरसरकारी

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents. पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव का पैराग्राफ नं० १०.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४५, प्रस्ताव का पैराग्राफ नं० १२.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४५, प्रस्ताव का पैराग्राफ नं० १३.

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४६ प्रस्ताव का पैराग्राफ नं० १४.

५ उपर्युक्त पुस्तक, Vol. I, p 649, para 19 of the Resolution.

व्यक्ति हो। उसका यह कहना था कि जब तक मुख्य कार्यपालिका-अफसर नगरपालिका और जिला-समिति के समापति होंगे तब तक इन समितियों द्वारा, उनके सदस्यों का, स्थानीय प्रबन्ध-कार्य के लिए कोई वास्तविक शिक्षण नहीं होगा। और उस समय तक गैरसरकारी सदस्य स्थानीय विषयों में कोई सक्रिय दिलचस्पी भी नहीं ले सकेंगे।<sup>१</sup> गैरसरकारी सदस्य जिले के कार्यपालिका अध्यक्ष के साथ भिड़ने की जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे।

अन्त में प्रस्ताव ने स्थानीय मंडलों के समुचित नियंत्रण की व्यवस्था की। यह नियंत्रण अन्दर से न होकर बाहर से होना था।<sup>२</sup> कार्यपालिका-अधिकारियों के लिए नियंत्रण के दो अधिकार सुरक्षित किये गए। पहला अधिकार तो यह था कि "कुछ कार्यवाहियों को मान्य बनाने के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक थी। न कामों में निम्न बातों की गणना थी—भूगणना, अधिकृत करो के अतिरिक्त अन्य कर लगाना, नगरपालिका-सम्पत्ति को हस्तान्तरित करना साम्प्रदायिक प्रश्नों से सम्बन्धित विषयों में हस्तक्षेप, सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले विषय, इत्यादि। दूसरा अधिकार यह था कि स्थानीय शासन विशेष परिस्थितियों में मंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता था और उसे रद्द कर सकता था। साथ ही किसी महत्वपूर्ण कर्तव्य की दीर्घकालीन उपेक्षा की दशा में स्थानीय शासन को मंडल का निरन्तरन करने का अधिकार दिया गया। जब तक उक्त उपेक्षित कर्तव्य का सतोषप्रद रूप से पालन न हो, तब तक मंडल का कार्य करने के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने की व्यवस्था थी।"<sup>३</sup>

सन् १८८३-१८८४ में, उक्त प्रस्ताव जारी होने के कुछ ही समय बाद, उसकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन एक्ट बनाये गए।

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents, पैरा १८, पृष्ठ ६४८-६४९

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४७-६४८, पैराग्राफ न १७

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४७-६४८, प्रस्ताव का पैराग्राफ न. १७

# भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरंभ

( १ )

भारतीय इतिहास में सन् १८६१ से लेकर १८९२ तक के युग का, राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के कारण एक स्थायी महत्व है। सन् १८८५ में, दिसम्बर के २८, २९ और ३० दिनांक को देश के विभिन्न भागों से ७२ प्रमुख भारत वासी, राजनीतिक काम के लिए एक सर्वसम्बन्धित कार्यक्रम निश्चित करने के उद्देश्य से बम्बई में एकत्रित हुए। 'भारतीय इतिहास में, इतना महत्वपूर्ण और व्यापक सम्मेलन, इससे पहले कभी नहीं हुआ था।'

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ के बारे में बितने ही कारण बताये गए हैं। लाला लाजपत राय के अनुसार इनमें से मुख्य कारण था—प्रवर्तका का साम्राज्य को छित होने से रोकने के लिए तीव्र इच्छा।

पिछली शताब्दी की आठवीं दशक में भारतीय स्थिति निश्चित रूप से विस्फोटक थी। १८७७ के दुर्मिष के बाद असन्तोष बराबर बढ़ रहा था। कांग्रेस के पिता, मि० ह्यूम ने देश के विभिन्न भागों के सरकारी प्रतिवेदनों (reports) को देखा था। इनके अनुसार सर्वसाधारण में असन्तोष उफान रहा था और उनकी उपद्रव बढ़ रही थी। यह संभव था कि शिक्षित वर्ग में से कोई बिडा हुआ नवयुवक आगे आकर जन-संगठन करने लगता और—“उसे राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत कर देता।”<sup>१</sup> कम-से-कम मि० ह्यूम के विश्वासानुसार भारत में एक भयंकर विस्फोट का तात्कालिक संकट निश्चय रूप से वर्तमान था। सर विलियम वेडरबर्न के अनुसार बम्बई-प्रेसीडेंसी के दक्षिण भाग में तो उपद्रव फूट भी पड़े। “इनका आरम्भ इधर-उधर की छोटी-छोटी हड़तियों से हुआ बाद में डाकुओं के इन दलों का दमन पुलिस की सामर्थ्य के बाहर हो गया, तब पूना का मारा सैन्य-दल उन्हें दबाने को भेजा गया। अधिक शिक्षित वर्ग में से एक नेता मिल गया, जो अपने-आपको शिवाजी द्वितीय कहता था। उसने सरकार का चुनौतिया दी और (बम्बई के गवर्नर) सर रिचर्ड टेम्पल के सिर के लिए ५०० रुपये का पुरस्कार घोषित किया और जिस

१. Chisol India page 80 से पहले अधिवेशन के सभापति श्री उमेश चन्द्र बनर्जी के व्याख्यान के एक उद्धरण का अनुवाद।

२. Lajpat Rai Young India pages 135-138

प्रकार से मराठा-शक्ति ने आरम्भ में अपने-आपको स्थापित किया था, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व करने का दावा किया।<sup>१</sup>

लाला लाजपतराय इस निष्कर्ष पर पहुँचे — 'अतः इन दोनों नेताओं (मि० ह्यूम और सर विलियम वेडरबर्न) के उद्बो में कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य, ब्रिटिश साम्राज्य को इस सकट से बचाना था।'<sup>२</sup>

यह असम्भव नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बचाने और साथ ही ब्रिटिश सम्पर्क से उत्पन्न शक्ति के निष्क्रमण के लिए कांग्रेस का सुरक्षा-छिद्र के रूप में उपयोग करने के विचार, सिविल सर्विस से निवृत्त, कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के मस्तिष्क में रहे हों। किन्तु यह विश्वास करना कठिन है कि दादा-भाई नौरोजी, डब्ल्यू. सी. बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, तैयबजी, रानाटे, तैलंग और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी—जैसे भारतीय नेता इस उद्देश्य से प्रेरित थे। जैसा कि लाला लाज-पतराय ने स्वीकार किया है, स्वयं मि० ह्यूम भी अन्य एवं उच्चतर उद्देश्यों से विशेष रूप से प्रेरित थे 'ह्यूम को स्वतन्त्रता का व्यसन था। दुःख और दरिद्रता के दृश्य से उनका हृदय बराह उठना था। भारतवासियों के प्रति अपने देशवासियों के 'नागरता-पूर्ण' व्यवहार से उन्हें बड़ा शोक होता था। इतिहास के गम्भीर अध्ययन से उन्हें यह बात भलीभाँति ज्ञात थी कि कोई भी सरकार, चाहे वह राष्ट्रीय हो अथवा विदेशी हो, सार्वजनिक भाँगी को केवल नीचे से दबाव पड़ने पर ही स्वीकार करती है। अतः वह यह चाहते थे कि भारतवासी अपनी स्वतन्त्रता के लिए 'प्रहार' करें। प्रथम आरम्भ था संगठन। फलतः उन्होंने संगठन के लिए मजना दी।'<sup>३</sup>

• इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की इच्छा का कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं था। वस्तुतः काफी समय से, कितनी ही शक्तिपूर्ण काम कर रही थी। उनके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय हुआ। सन् १८८० के पश्चात् इस आन्दोलन को जन्म देने वाली मुख्य बातों को छे शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) पश्चिम के राजनीतिक आदर्शों की प्रेरणा, (२) धार्मिक पुनरुत्थान और भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धाभाव, (३) आर्थिक असन्तोष और ब्रिटिश आवासना के पूर्ण न किये जाने के कारण निराशाभाव; (४) भारतीय समाचार-पत्रों का और साथ ही देशी साहित्य का

१ Lajpat Rai Young India. page 137.

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १३३.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ, १४१-१४२.

प्रभाव, (५) सचाय साधनों का विकास और सामाजिक दूरवारों का आनोदन, और (६) सामुदायिकता के उद्घन एवं बहुकारणपूर्ण व्यवहार के कारण, जातों भावनाओं में बदला की वृद्धि और नैतिकता का प्रभुत्व एवं अविवेकपूर्ण मान्य और हन भाग्य इत्यादि विचारों के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा आंग्ल भारतीयों द्वारा उद्घना और माटित तीव्र प्रचार का प्रदर्शन।

(h) भारत की राजनीतिक आगति में पश्चिमी शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनके द्वारा भारतवासी सर्वोत्तम अंग्रेजी विचारों के—मिल्टन, बर्क, मिड, मेकॉलि आदि के—ग्रन्थों के—सम्बन्ध में आग। पश्चिमी शिक्षा ने भारत-वासियों में स्वतन्त्रता राष्ट्रीयता स्वशासन आदि के जीवन-प्रेरक विचार भरे और फलतः उन्हें देश की राजनीतिक स्थिति से असन्तुष्ट कर दिया और वे स्वशासन संस्थाओं के लिए तथा नौकरियों में श्रेष्ठतर स्थानों के लिए मांग करने लगे। दूरदर्शी अंग्रेजों ने इस परिणाम को पहले ही प्रत्याशा की थी। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि "यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन वे (भारतवासी) यूरोपीय संस्थाओं के लिए मांग करेंगे" और आंग्ल इतिहास के लिए वह "अधिकांशतम सब का दिन" होगा।<sup>१</sup> साथ ही पश्चिमी शिक्षा ने समूचे भारत को एक राष्ट्र-भाषा का मूल्यवान् उद्घार दिया। इसी के माध्यम से भारतवासियों के लिए, पत्र-पत्र निकट आना, विचार व्यक्त करना और समाजों तथा समुदायों में मिलकर सर्वसम्बन्धित कार्यरत बनना, समन्वय प्रदान करना।

पश्चिम के साथ वास्तविक, व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण, अंग्रेजी शिक्षा के उच्च परिणाम और भी प्रखर हो उठे। भारतीय नवयुवक उच्च शिक्षा के लिए हार्वेर्ड शहर, साथ ही अन्य भारतवासी अन्य उद्देश्यों से विदेश गये। विदेशों में करने प्रवास से, वे भारतवासी, स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्य-विधि में विशेष रूप से परिचित हुए। इस प्रवास ने उन्हें स्वतन्त्रता का मूल्य मिलाया और उनके मस्तिष्क में दीनताओं एवं साम्य-मनोवृत्ति को दूर किया। विदेशों से लौटने वाले भारतीयों का यहाँ का दाम्पत्यपूर्ण वातावरण मजबूत था और वे उद्दिष्ट और असन्तुष्ट होन से। उनका यह अनुशीलन समासक निद्र होना था।

१ पश्चिमी शिक्षा के तात्कालिक परिणाम अच्छे नहीं थे। इस नई शिक्षा-मुच ने बहुत से तरंग भारतीयों को दिग्भ्रम अष्ट कर दिया और उन्हें अराष्ट्रीय बना दिया। वे बुरी यूरोपीय बातों का अनुकरण करने लगे। "अराष्ट्रिक मर्यादाओं और साथ ही विचार, रचि और चरित्र का असदम व्याप्त हो गया।"

2. Speeches of Lord Macaulay. July 10th 1833. Keith "Speeches and Documents on Indian Policy". Vol. I. page 265

( २ )

इसी दिशा में एक दूसरी बात का प्रभाव हुआ। यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और पुरानी भारतीय सस्कृति एवं सम्प्रदाय की प्रशंसा की। मैक्समूलर, मोनियर विलियम्स, रीय, सैमुन बर्नफ आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने "सस्कृत भाषा की सम्पन्नता एवं श्रेष्ठता का उसके ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्त्व का (संदेह में) भारतीय सम्प्रदाय के आधारभूत हिन्दू साहित्य का केवल पश्चिमी जगत् के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं भारत के लिए भी प्रकटीकरण किया।"<sup>१</sup>

इस सम्बन्ध में विभिन्न धार्मिक सुधारकों का काम और भी अधिक महत्त्वपूर्ण था। लोगो ने उस सार्ई को अनुभव किया, जो सन् १८६१-१८९२ के भारत और उस प्राचीन युग के भारत में थी, जब वेद और उपनिषद् प्रकट किये गए थे और जब अन्य धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की गई थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के पूर्वगामी एवं प्रेरक, धार्मिक सुधार-आन्दोलनों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, क्रिश्चियन और श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों का समावेश था। ये सुधार-आन्दोलन, मुख्यतः धार्मिक होने के साथ ही राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने भारतवासियों को अपने महान् उत्तराधिकार के प्रति सचेत किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की। धर्म ने राष्ट्रीयता का प्रेरित किया।

( ३ )

जैसा कि मि० गैरट ने कहा है, "राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग, हमेशा ही, कुछ हद तक आर्थिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से हुआ है।"<sup>२</sup> यह निर्विवाद सत्य है कि देश की आर्थिक स्थिति के हास ने और सरकार की अराष्ट्रीय आर्थिक नीति ने, भारतीयों के उच्च पदों से बहिष्कृत करने की नीति के साथ मिलकर, भारतवासियों में क्रिटिश विरोधी और राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने में बहुत बड़ा प्रभाव डाला।

विदेशी मशीन से बने माल के साथ प्रतिद्वन्द्विता न कर सकने के कारण, भारत के उद्योग-धर्म नष्ट हो गए थे और देश निर्धन होता जा रहा था। सरकार ने सख्त देने और सहायता करने के स्वार्थ पर, इंग्लैण्ड के स्वार्थ के लिए मुक्त व्यापार की नीति को जान-बूझकर अपमान्य और उन घण्टों के विनाश में सहयोग दिया। इस पुस्तक के सातवें अध्याय में कपास सीमा-शुल्क-सम्बन्धी विवाद का विवरण दिया जा चुका है। उक्त विवाद के कारण व्यावसायिक एवं उद्योग वर्गों की सद्भावनाएँ समाप्त हो गई थी। हस्तशिल्प नष्ट हो जाने के कारण घरेली (हथि) पर दबाव

१ Chirol India page 80

२ Gerrat: An Indian Commentary 119

( ४ )

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों ने, जिनके मालिक और सम्पादक भारतीय ही थे, राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न किया और उसका पोषण किया। देश के आगल भारतीय और भारतीय समाचार-पत्रों के बीच एक बड़ी खाई थी। आगल भारतीय पत्र राष्ट्रीयता-विरोधी थे और सदा सरकार का पक्ष लेते थे। वे शासक और शासित जातियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की नीति को व्यवहार में लाने के कट्टर विरोधी थे। दूसरी ओर भारतीय पत्र राष्ट्रवादी, सरकारी नीति के आलोचक और जातीय समानाधिकार के प्रतिपादक थे। इसके अतिरिक्त वे पत्र, देश का शासन और नियंत्रण करने के लिए भारतीयों के अधिकार का भी प्रतिपादन करते थे। सरकारी और अंतर-सरकारी आगल-भारतीयों का यह सामान्य आक्षेप रहा है कि भारतीय पत्रों का—विशेषकर अंग्रेजी भाषा के पत्रों का—दृष्टिकोण द्रोहत्मक रहा है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय पत्रों ने विभिन्न (संपादन सम्बन्धी) कानून और अध्यादेशों के दम पर बड़ी क्षति उठाई है और उन्होंने स्वदेश की वस्तु बड़ी सेवा की है। आरम्भ में कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था और उसका काम समाचार-पत्रों ने ही किया। उन्होंने अखिल वर्गों को अगामा और उनमें स्वदेश-भक्ति की भावना और राष्ट्रीय चेतना के बीज बोये। भारतीय पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीयता और राजनीतिक मूधार के पक्ष में निरन्तर प्रचार किया। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाना उचित होगा कि विभिन्न भाषाओं में—विशेषकर बंगला में—शोक-साहित्य के विकास ने महत्वपूर्ण काम किया। बकिमचन्द्र चटर्जी विरचित 'अमर मठ' को कुछ लोगो ने 'आधुनिक बंगाली देशभक्ति की गीता' कहकर पुकारा है। इसी पुस्तक में 'बन्दे मातरम्' गान पहली बार सामने आया। 'आनन्द मठ' ने बंगाल में आन्तिकारी राष्ट्रीयता की पाठ्य पुस्तक का काम किया।

( ५ )

आधुनिक मातायान के विकास ने भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता की। सचर साधनो ने विस्तृत देश को एक सूत्र में यूँय दिया और भौगोलिक ऐक्य सुस्पष्ट हो गया। अब, गुरेन्द्रनाथ बनर्जी के सिविल सर्विस-सम्बन्धी अखिल भारतीय दौरे की तरह, राष्ट्रीय पैमाने पर प्रचार करना, और अत्यधिक दूरी के कारण विच्छिन्न लोगो में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भरना संभव हो गया।

१८७७ में इंग्लैण्ड की महारानी द्वारा नई उपाधि धारण करने के समय, वाइसराय ने उसकी घोषणा के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार किया और इसमें सम्मिलित होने के लिए देश के प्रत्येक भाग से राजा, नवाब और सामन्त आदि आए। यह देखकर राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं को अखिल भारतीय सम्मेलनों का



विद्रोह के बाद, भारत में आने वाले अंग्रेज नवयुवकों के मस्तिष्क में भारतीयों के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएँ होती थी। वे, पंच के तत्कालीन हास्य-चित्रों के अनुसार<sup>१</sup> भारतीयों को ऐसा जन्तु समझते थे, जो आधा बन्मानुष और आधा नौग्रीवा, और जिसे केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता था, और जिसके लिए जनरल नील और उसके साथियों का घृणा और आतंक का व्यवहार ही उपयुक्त था। जब भारत आने पर वे अपने उन देशवासियों के सम्पर्क में आते थे जिन्हें विद्रोह के भयकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उनकी घृणा की भावनाएँ, दृढतर हो जाती थी। ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ स्वतन्त्रता के साथ घुलना मिलना और उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना असम्भव था। अतः उन लोगों ने अपनी छावनियाँ और बस्तियाँ अलग बनाई। साथ ही उन्होंने अपने लिए एक विचित्र व्यवहार-नीति बनाई। मि० गैरट के अनुसार इसके तीन महत्वपूर्ण सिद्धान्त थे एक तो यह कि एक यूरोपियन का जीवन, कितने ही भारतीयों के जीवन के बराबर था। दूसरा यह कि “प्राच्य देशवासी केवल भय को ही समझता था।” तीसरा यह, कि वे ब्रह्मा (भारत में) लोक हित के लिए नहीं, बल्कि अपने रयाग के फलों का स्वाद लेने के लिए, और साथ ही अपने निजी लाभ के लिए आये थे।<sup>२</sup> इन बातों के भयकर परिणाम हुए और भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच की खाई बराबर बढ़ती गई।

आगल-भारतीयों की मनमानी और आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष रूप से खटकती थी। १८७२ में मलेरकोटला के उपद्रव में, बिना अभियोग-निर्णय किये, ४९ सिखों को तोप से उड़ा दिया गया।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त और बहुत-सी ऐसी घटनाएँ बार-बार हुईं जिनमें अंग्रेजों ने भारतीयों की हत्या की अथवा उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया।<sup>४</sup> इन अपराधों के लिए या तो कोई दृढ़ ही नहीं दिया

---

गए। विद्रोह के बाद आत्म दैन्य की वह भावना आरम्भ हुई जो ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक थी। Garrat An. Indian Commentary, page 44

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४५

२ Garrat : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४४

३ Writes Sir Henry Cotton —“For my part I can recall nothing during my service in India more revolting and shocking than these executions

४. Theodore Morrison: Imperial Rule in India. page 280 से अनूदित उद्धरण —“बैरकपुर के एक प्रतिष्ठित वकील की बर्बरतापूर्ण दम से हत्या करने के अपराध में,

गया अथवा केवल साधारण-मा जुमाना कर दिया गया। उपर्युक्त बातों ने सब साधारण के मस्तिष्क में घृणा की ज्वाला को जीवित बनाए रखा। साथ ही सब कभी उपर्युक्त प्रकार की घटनाएँ होती या तो सरकारी और गैर-सरकारी मन्त्र अंग्रेज उनका समर्थन करते थे और आंग्ल-भारतीय पत्र उस आन्दोलन में बड़ा कर देने थे। इन बातों ने स्थिति और भी बिगड़ जानी थी। सर हेनरी कर्टन लिखते हैं "यदि किसी चाय के रोपक पर किसी अन्याय कुली को निर्दमनापूर्वक पीटने का अभिप्राय किया जाता है तो उसका निर्णय करने के लिए चाय के रोपकों को जूरी बनाई जानी है। यह जूरी स्वाभाविक रूप से अनियुक्त के पक्ष में होती है। यदि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से या अन्य किसी कारण से दोष निवृत्ति होगी तो अंग्रेजों का मारा जनमानस उस निर्णय की निन्दा करता है। आंग्ल-भारतीय समाचार पत्र अग्नि में आहुति डालने हैं और अपन पक्ष में उस विरोध को व्यक्त करते हैं। अपराधी के व्यय के लिए खर्चे को उगाही की जाती है। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सरकार के लिए स्मरण-पत्र तैयार किये जाते हैं और उनमें अनियुक्त के छुटकारे के लिए निवेदन किया जाता है।" इसका स्वाभाविक परिणाम था जातीय बढ़ता में वृद्धि। जैसा कि मि० पैरट न मकेत किया है, भारतीय राष्ट्रियता की बढ़ती में उक्त बढ़ती की भावना का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ।

( ३ )

लार्ड रिडिंग के राज्य-काल में ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुईं जिनके सम्बन्ध में भारत में जातीय विराय और बढ़ती की भावनाओं में वृद्धि हुई। साम्राज्यीय दरबार समारोह के समय, साम्प्रदायिक सैन्य भ्रमण की नयकर बठिनाइयाँ में मृत्यु में सघर्ष कर रहे थे। "इस दरबार के प्रतिष्ठित, काबुल पर स्वेच्छानुसार आक्रमण किया गया" और दूसरा अफगान-युद्ध हुआ, सभी आतंक के कारण सेना में बहुत बड़ी वृद्धि की गई और वैज्ञानिक हथियारों में सुरक्षा सीमा बनाने के लिए काफी धन खर्च किया गया, एक असह्य और निरपराध जनता का पूरी तरह निःशस्त्रीकरण किया गया (किन्तु सुरक्षितता को नहीं छूटा गया), देशों पक्षों का मुखा-

तापमान के तौल आदमी अनियुक्त हुए किन्तु उनको केवल मात्र वर्षों के बड़ा बागबास का दण्ड दिया गया। इस पर एक मैनिफेस्टो अधिकांशों ने कहा कि "सत्तार के अन्य किसी भाग में इन आदमियों को फाँसी की सजा दी जाती। इस पर लन्दन के एक पत्र ने कहा कि नाम जाने बिना यह विद्वान् करना फटित है कि भारत में ऐसा भी कोई अंग्रेज है जिसकी उक्त अधिकांशों की भी सम्मति है।"

रोधन किया गया, लकाशायर के स्वार्थ के लिए न्याय-सीमा-दुष्क का बलिदान किया गया।<sup>१\*</sup> उपर्युक्त सारी बातें भारतवासियों के लिए अत्यन्त अहंकार की और उनका प्रबल विरोध हुआ और उनके कारण, सर्वसाधारण में प्रचार और आन्दोलन के लिए विभिन्न भारतीय संस्थाओं का संगठन किया गया।

किन्तु अभी अखिल भारतीय संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए स्थिति परिपक्व नहीं हो पाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के लिए अभी इल्वर्ट विधेयक पर आंग्ल-भारतीय आन्दोलन, और शासन वर्ग के क्षुद्र स्वार्थ उसके जातीय अहंकार तथा उसकी उग्रता का प्रदर्शन होना आवश्यक था।<sup>२\*</sup>

( ८ )

इल्वर्ट विधेयक-मन्वन्धी विवाद में भारतीयों की असफलता ने प्रान्तों की जनता को जगाया और तीन प्रेसिडेन्सियों में पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक समस्याएँ काम कर रही थी, उनमें नया जीवन भर दिया। कलकत्ता के इंडियन एसोसियेशन ने १८३३ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें बंगाल के अधिकांश बड़े नगरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे 'राष्ट्रीय ससङ्ग की दिशा में प्रथम चरण' बताया गया। १८८४ में मद्रास महाजन सभा ने मद्रास में एक प्रान्तीय सम्मेलन किया। ३१ जनवरी १८८५ को बम्बई में एक सार्वजनिक सभा हुई और उससे फलस्वरूप बम्बई प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन अस्तित्व में आया। सन् १८७० में पूना में 'सार्वजनिक सभा' नामक संस्था बनी और उपयोगी काम करती रही। उसने "पश्चिमी भारत को जगाने में और साथ ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण काम किया।"<sup>३\*</sup> सन् १८८३ में एक मार्च को मि० ह्यूमन "कलकत्ता विश्वविद्यालय के

१. A C Mazumdar Indian National Evolution.

२ इसी पुस्तक के छठे और सातवें अध्यायों को देखिये। जातीय भेद-भाव को समाप्त न कर सकने का कारण यह बताया गया कि 'आंग्ल भारतीय जाति के मुसगठित और प्रबल विरोध का सन्तुलन करने के लिए सारे देश में प्रबल एवं संयुक्त समर्थन का जभाव था। A C Mazumdar Indian National Evolution, page 39 के एक उद्धरण से अनूदित।

३ Reported by Mr Wilfred Blant Quoted in Bannerji A Nation in the Making pages 86 87

४ Kellock Mahadeva Govind Ranade page 25

५ मि० ह्यूम भारत के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने १८८२ में सचिव से त्याग पत्र दे दिया था और वे शिमले में बस गए थे। वे 'इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता' के नाम से परिचित हैं।

स्वातन्त्र्य के नाम एक मुला पत्र सम्बोधित किया और उनसे राष्ट्रीय सेवा के लिए आत्मसमर्पण करने की अपील की। मि० ह्यूम ने इस पत्र में "इन शास्त्र पर जोर दिया कि मुक्त और स्वतन्त्रता के लिए, आत्म त्याग और निस्वार्थता ही विद्यमान ही निर्देश निम्नता हैं।" १ उनके बाद सन् १८८४ के दिसम्बर में, देश के विभिन्न भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले १० मते और मन्त्रे व्यक्तियों ने मद्रास में बीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास-महल पर एक बैठक की और राष्ट्रीय संस्था<sup>२</sup> बनाने का उद्देश्य मद्रास के विभिन्न भागों में काम करने का निश्चय किया। इनमें से अधिकांश व्यक्ति मद्रास में विद्यापीठ बनाने के लिए अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आए थे। लगभग इनो समय एक 'इण्डियन यूनिन' स्थापित हुई। १८८५ के मार्च में इस यूनिन ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया और आगामी बड़े दिन पर पूना में इस उद्देश्य से एक सम्मेलन बुलाया कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता परस्पर परिचित हो सकें और आगामी वर्ष के लिए विचार-विनिमय द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित कर सकें।"

इस विज्ञापन का प्रकाशित करने के पहले मि० ह्यूम ने वायसरॉय हाउस डफरिन से परामर्श कर लिया था और उन्होंने वायसरॉय के सुझाव पर उक्त संस्था को राजनीतिक रूप दिया था अन्वया उनका निजी विचार तो सामाजिक सम्मेलन के लिए एक मंच बनाने का था। हाउस डफरिन यह चाहते थे कि मद्रास इंग्लैंड के राजकीय विरोधी दल की नीति काम करे सरकार को यह बताने कि शासन में कहीं और क्या हाथ है और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है।"

विज्ञापन को प्रकाशित करके और नाथ ही सम्मेलन के लिए दिनांक (२८, २९ और ३० दिसम्बर १८८५) निश्चित करके, मि० ह्यूम, इंग्लैंड में उनके अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से, बहा गए। वास्तव में सम्मिलित होने के लिए वह समय पर भारत लौट आए। हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान पूना से हटाकर बम्बई कर दिया गया। इस प्रकार १८८५ के १८ दिसम्बर को, राष्ट्रीय महारव के राजनीतिक विषय पर विचार करने के लिए, इण्डियन नेशनल कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ।<sup>३</sup> इनमें देश के विभिन्न भागों के बहुरंग प्रतिनिधि

१ Mazumdar - Indian National Evolution. page. 47  
२ Annie Besant : How India wrought for Freedom page 1.

३. Mazumdar उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५१

४. लगभग इसी समय कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें केवल बंगाल

सम्मिलित हुए। उस समय के बाद कांग्रेस का अधिवेशन भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी एक महत्वपूर्ण केन्द्र में प्रतिवर्ष हुआ है।

कांग्रेस राष्ट्रीय सस्था थी और उसमें देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था। आरम्भ में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम थी<sup>१</sup> और तत्कालीन महान् मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद कांग्रेस से दूर थे, यहाँ तक कि उन्होंने बनारस के राजा शिवप्रसाद की सहायता से 'परम राजमन्त्री' की एक विरोधी सस्था बनाई थी।<sup>२</sup> अन्यथा कांग्रेस पूरी तरह लोक-प्रतिनिधि संस्था थी<sup>३</sup> और सन् १९०७ के विभेद तक, लगभग सभी प्रमुख भारतीय उसकी परिधि के अन्तर्गत थे। साथ ही, मि० ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, मि० एड्विड मूल और मि० नॉर्टन-जैसे अनेक योग्य एवं उदारमन आत्मा भारतीय भी कांग्रेस में सम्मिलित थे।<sup>४</sup> भारत की फूटके समय तक कांग्रेस एक उदार और नरमदली सस्था थी और

के ही नहीं बरन् उत्तरी भारत के मगरो—मेरठ, इलाहाबाद, बनारस से भी प्रतिनिधि आए। "सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और अमीर अली, मुख्य संगठनकर्त्ता थे। उन्हें बम्बई के सम्मेलन का जब पता लगा तो उस समय तक देर हो गई थी और बलकत्ता सम्मेलन का निमन्त्रण करना समय नहीं था किन्तु अगले वर्ष से वे लोग कांग्रेस में मिल गए और उसको हार्दिक सहयोग दिया।" Bannerjee. A Nation in the Making page 89-99

१. पहले अधिवेशन में दो मुस्लिम प्रतिनिधि आये, दूसरे में ३३ और छठे में १०७
२. मि० ह्यूम ने कांग्रेस-विरोधियों को तीन वर्गों में बाँटा—(१) आत्म-भारतीय अधिकारी और पत्र, (२) कुछ नासमझ किन्तु ईमानदार भारतीय, (३) कुछ अवसरवादी जैसे मुस्लिमवर्ग। मि० ह्यूम के अनुसार इस विरोध की प्रेरणा बाहर से फूट डालकर राज्य करने की नीति से विकसित हुए कुछ भ्रान्त अधिकारियों से मिली। उन्होंने विरोधी आन्दोलन को अस्वाभाविक और कुठिल बताया। Wedderburn Allam Octavian Hume Pages 71 to 73 से अनूदित।

३. ये प्रतिनिधि लोक-निर्वाचित नहीं थे। वे राष्ट्र के सर्वोत्तम विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे।

४. लाला लाजपत राय लिखते हैं, "इस आन्दोलन को एक अग्रज ने, एक अग्रज जपसराज के कुतूहल पर प्रेरित किया। यह आन्दोलन अन्तर से तूटो उठा था।" (Young India page 154 से अनूदित)। यह सच है कि मि० ह्यूम प्रमुख संगठनकर्त्ता थे। और लॉर्ड डफरिन के परामर्श से ही उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक रूप दिया। किन्तु यह भी सच है कि सन् १८८८ में डफरिन

सुधार और विस्तार किया जाय, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त और अवध, और साथ में पंजाब के लिए भी वैसी ही परिपदें बनाई जायें और, परिपदों को वजह पर चर्चा करने और "कार्यपालिका से शासन के प्रत्येक विषय पर प्रश्न करने" का अधिकार दिया जाय।<sup>१</sup>

पहले दो वर्षों तक कांग्रेस की कार्यवाहियों के प्रति सरकार की दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण रही, किन्तु १८८८ से उसकी नीति एकदम बदल गई। कारण यह था कि कांग्रेस भारत और इंग्लैंड—दोनों ही स्थानों—में बलवधिक ध्यान आकर्षित करने लगी थी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों की 'नगण्य सत्ता' की<sup>२</sup> प्रतिनिधि सत्ता बताया। इलाहाबाद के लिए निर्दिष्ट चौथे अधिवेशन के मार्ग में हर प्रकार की बाधाएँ डाली गईं और १८९० में सरकारी नौकरों को कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित न होने के लिए अनुदेश दिये गए।

तथापि लॉर्ड डफरिन ने परिपदों के सुधार के लिए कांग्रेस की माँग पर ध्यान देना आवश्यक समझा। उसने अपनी परिपद की एक कमेटी नियुक्त की और उसकी सहायता से, 'प्रान्तीय परिपदों के विस्तार के लिए उनका पद और कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए, उनमें निर्वाचन-सिद्धान्त अथवा पुर स्थापन करने के लिए और उनके राजनीतिक स्वरूप को विस्तृत करने के लिए एक योजना' तैयार की।<sup>३</sup> किन्तु संसद् व्यवस्था (Parliamentary System) के पुर स्थापन के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कार्यपालिका अब भी "किसी स्थानीय सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं की गई, वह यथापूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बनी रही।"<sup>४</sup> इसी कारण उक्त योजना में नाम निर्दिष्ट अंश का आधिक्य बनाये रखने की और साथ ही कार्यपालिका-अध्यक्ष को अपनी परिपद की उपेक्षा करने के अधिकार को व्यवस्था की गई।<sup>५</sup>

भारत-मंत्री ने उक्त योजना में और सब बातों का अनुमोदन किया लेकिन निर्वाचन सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। अस्तु, अभी भारत-मंत्री और भारत-

१ Resolution No. 3 —Besant, How India wrought for freedom page 13

२ Speech of Lord Dufferin at St Andrews Club Calcutta.

३ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 42

४ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 43

५ उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ४४

एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने उपरिपद गवर्नर-जनरल को सपरिपद भारत-मन्त्री के अनुमोदन से अतिरिक्त सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए विनियम बनाने और "उन विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए पद्धति निश्चित करने का अधिकार दिया।"<sup>१</sup> जैसा कि लॉर्ड किम्बरले ने कहा है, सरकार ने वाश्वासन दिलाया कि इस खण्ड के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल के लिए ऐसी व्यवस्था करना समभव होगा कि उसके अनुसार यह निर्वाचन द्वारा छीटे हुए व्यक्तियों में से नाम निर्देशन कर सकेगा।<sup>२</sup>

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने परिपदा को नार्पिक वित्तीय विवरण पर वर्चस्व रखने का अधिकार दिया—“प्रत्येक वर्ष हर वर्ष पर एक-एक करके माह देने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सरकार को वित्तीय नीति को पूर्ण एवं स्वतन्त्र समालोचना करने का अधिकार दिया।”<sup>३</sup>

अन्त में परिपदों के सदस्यों को गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों द्वारा निर्मित नियमों और प्रविधियों के अन्तर्गत सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।<sup>४</sup>

1. Clause I. Sub section 4 of the Act, Mukherjee : Indian Constitutional Documents, vol 5 page 227.

२ Keith : Speeches and Documents on Indian Policy vol. II page 60.

३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५६

४ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७

युग २  
(सन् १८९२ से १९०९ तक)  
ग्यारहवाँ अध्याय

## शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन

( १ )

भारत के वैधानिक विकास में अबला महत्वपूर्ण सीमाक है सन् १९०९ का भारतीय परिषद् एक्ट । इसमें लॉर्ड मोर्ले और लॉर्ड मिण्टो के नाम से संबंधित सुधार योजनाओं को रूपा दिया गया । सन् १८९२ से १९०९ तक के युग में किन्ने ही महत्वपूर्ण प्रशासनीय कार्य एक परिवर्तन हुए, इनमें से अधिकांश के साथ लॉर्ड कर्जन का नाम जुड़ा हुआ है । इन परिवर्तनों में मौलिक बात है सामान्य का बेन्दो-बंदी और अधिकारीकरण, किन्तु वित्तीय क्षेत्र में, पिछले युग में भारत की हुई निक्षेपण की नीति को ही व्यवहार में लाया गया । लॉर्ड कर्जन के राज्य-काल में एक ओर तो भारतवासियों के प्रति, साथ ही उनकी योग्यता और सचाई के प्रति अविश्वास था, और दूसरी ओर कुशलता एक निपुणता के लिए दृढ़ खोज थी, फिर चाहे परिणाम कुछ भी पवान हा । किन्तु इस युग १८९२-१९०९ की सत्रों अधिक महत्व की घटना यह थी कि लोगों में एक नई भावना का—आत्म-विश्वास और पीरप की भावना का और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए बलिदान करने की तत्परता का जन्म हुआ । इस युग के अन्तिम छ वर्षों में एक धारा थी आत्म-वाद और अराजकतावादी और दूसरी थी शौर्यपूर्ण राष्ट्रीयता-वादी जिसे नेता थे, श्री निलन, बरबिन्द घोष, बाबू विपिनचन्द्रपाल और लाला लाजपत राय । कांग्रेस दो दलों में बँट गई—नरम दली और उग्र दली, और ब्रिटिश सरकार ने उग्रता और कानि के ज्वार को रोकने के लिए नरमदली लोगों और मुसल-मानों को अपनी ओर मिलाने और परिषदों में सुधार करने की नीति अपनाई । ये सुधार, लॉर्ड मिण्टो सुधार के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

! ३० मिनम्बर १९०५ की लॉर्ड कर्जन ने अपनी विदाई के एक वशास्थान में कहा "एक शब्द में मेरे काम का परिचय पूछा जाय तो मैं कहूंगा, कुशलता । वही उद्देश्य है और वही हमारे शासन की कुजी है ।" Nevins ।  
The New Spirit in India. page 13 से अनूद्धित ।



( २ )

सन् १८९२-१९०९ के युग में सबसे पहली बात तो यह थी कि वित्तीय निश्रेयण की नीति को जारी रखा गया। लॉर्ड वर्जेन की सरकार ने सन् १८८२ की व्यवस्था के चौदह दोषों<sup>१</sup> को दूर करने के लिए सन् १९०४ में वर्ष-स्थायी बन्दोबस्त किया। इसमें प्रत्येक प्रान्त का राजस्व में साझा निश्चित कर दिया गया और साम्राज्यीय आवश्यकता की असाधारण परिस्थिति के अतिरिक्त इन साझे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। कालान्तर में अनुभव से यह पता लगने पर कि प्रान्तीय आवश्यकता की दृष्टि से उक्त बंटवारा अनुचित अनुपात में हुआ है तो उस दिशा में भी उन साझे में परिवर्तन हो सकता था।<sup>२</sup> यहाँ बंटवारा तत्कालीन आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था और विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए वार्षिक अनुदान की व्यवस्था थी। इससे तत्कालीन असामर्थ स्थायी कर दिया गया किन्तु अनिश्चितता दूर हो गई और अपव्यय के लिए अथवा वचत को समाप्त करने के लिए कोई लालच नहीं रहा। प्रान्तीय वचन को हथियाने की नीति छोड़ने के फलस्वरूप मितव्ययिता केवल संभव ही नहीं हुई वरन् उसे प्रोत्साहन भी मिला।

यह व्यवस्था सन् १९०४ में आरम्भ हो गई और सन् १९०६ तक यह सब प्रान्तों में लागू हो गई। अप्रैल १९०७ में इसे वर्मा में भी कार्यान्वित कर दिया गया। कुछ नगण्य परिवर्तनों के अतिरिक्त सन् १९१२ तक मूलतः यही व्यवस्था बनी रही।

( ३ )

इस युग में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत की सना का एकीकरण किया गया और मुद्रवालीन क्षमता की दृष्टि से उसका पुनर्संगठन किया गया। इसका ध्येय है लॉर्ड किचनर को जो, १९०२ से १९०९ तक भारत में सेनापति थे। यद्यपि सुधार-योजना को नवम्बर १९०३ में सरकार के समक्ष रखा गया था किन्तु वास्तविक पुनर्संगठन १९०८ तक पूरा नहीं हो पाया। इस दिशा में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १८९३ में मद्रास और बम्बई सेना एक्ट बना कर एक महत्वपूर्ण पग आगे बढ़ाया। इस एक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई की सेनाओं के सेनापतियों के पद तोड़ दिए गए, भारत की सारी सेना की एक सेनापति के आधीन कर दिया गया और सपरिषद् गवर्नर-जनरल को उसके नियंत्रण का अधिकार दिया गया।<sup>३</sup>

१. इसी पुस्तक का आठवाँ अध्याय देखिये। ये चार दोष थे—बोहराने के समय होने वाले झगड़े, अपव्यय, मालगुजारी की उगाही में अत्यन्त बढोढ़ता, और विभिन्न प्रान्तों की विषमता में वृद्धि।

२. Report on Indian Constitutional Reforms 1918 page 70

३. सेना के एकीकरण के लिए मार्ग तैयार किया जा चुका था। सन् १८६४ में

रहनी थी, अत्यधिक केन्द्रीकरण या और कामों में अतिशय विलम्ब होता था।<sup>१</sup> लॉर्ड कर्जन ने इस द्वैध नियंत्रण को तोड़कर, एक पृथक् उत्तरी सीमा प्रान्त बनाने का प्रस्ताव किया। इस नए प्रान्त के लिए, भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी एक चीफ कमिश्नर की व्यवस्था थी। इस प्रस्ताव को भारत मंत्री ने स्वीकार किया और मद्रास एडवर्ड सप्तम के जन्म दिन पर १९०१ में ९ नवम्बर को नया प्रान्त बन गया।

लॉर्ड लंसडाउन ने जाने से पहले सीमा प्रान्तीय प्रदेश पर पूर्ण नियंत्रण की प्रगतिशील नीति आरम्भ कर दी थी। कुछ सैनिक विरोधियों ने मिथु नदी पर सीमा बनाने की नीति का प्रतिपादन किया था। लॉर्ड कर्जन ने मध्य स्थिति को अपनाया। उसने अग्रिम मोर्चों के १५,००० ब्रिटिश अथवा नियमित सैनिकों में से १०,००० को वापिस बुला लिया और जन जाति क्षेत्रों (Tribal Territory) की रक्षा का काम उन्हीं में से तैयार किये हुए १०,००० अनियमित सैनिकों को सौंप दिया। उसने नियत अवधि के बाद इन जातियों को भत्ता में निश्चित रकम देने की व्यवस्था को अपनाया। बदले में इन लोगों का यह दायित्व था कि सड़का और घाटियों के मार्ग खुले रहें, उस क्षेत्र में शान्ति रखी जाय और अपराधियों का दंड दिया जाय।<sup>२</sup> ब्रिटिश क्षेत्र में लूट-मार के हमले रोकने के लिए अनियमित सैन्य दल की सहायता, सैनिक पुलिस की व्यवस्था थी। निकट के सुविधापूर्ण केन्द्रों में नियमित सैन्य-दल ये जो आदेश पाने पर अविलम्ब धावा बोलने को तैयार रहते थे। अन्त में मद्रास का सुधार किया गया और सैनिक यातायात की सुविधा के लिये मुख्य रूप से रेलवे मार्ग बनाए गये। इस प्रकार भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा-प्रवस्था सुदृढ़ की गई।

( ५ )

लॉर्ड कर्जन ने शासन के अन्य क्षेत्रों में भी केन्द्रीकरण की नीति को अपनाया। उसने गिना, कृषि, समाज, सिंचाई, पुरातत्त्व, खानों इत्यादि के विषयों में निरीक्षण और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की। उसने यह अनुभव किया कि सुनिश्चित एवं समान नीति के तथा केन्द्रीय नियंत्रण के अभाव में उपर्युक्त विषयों का शासन ठीक नहीं होता था। अतः उनके दोषों को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा, पुरातत्त्व, वाणिज्य, तथ्य और गुप्तचर कार्य—इनमें से प्रत्येक विभाग के लिए एक-एक डाइरेक्टर-जनरल की, कृषि और सिंचाई के लिए इंस्पेक्टर-जनरल की, समाज के लिए निरीक्षण की और खानों के लिये मुख्य निरीक्षक की, नियुक्ति की गई।

लॉर्ड कर्जन ने बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेंसी सरकारों की स्वायत्तता को

१ Ronaldshay. Life of Lord Curzon. Vol. II. page 134

२ Frazer. India under Curzon and After, pages 53-54.

सन् १९०४ के एक्ट में तीन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था—(१) विश्वविद्यालय का कार्य केवल परीक्षा देने तक ही सीमित न हो परन्तु वहाँ अध्ययन और अनुसंधान को सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाय—यह बात कई दशाब्दियों तक केवल एक आशा-मात्र ही रही, (२) विश्वविद्यालय और उसके अन्तर्गत कॉलेजों में घनिष्ठतर संबंध हो और कॉलेजों का कठोरतर नियंत्रण हो, और (३) सीनेट, सिण्डिकेट और फैकल्टी का आकार कम किया जाय। नई सीनेटों के ८० प्रतिशत सदस्यों के सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गए।

लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखने में ऐसा कि लॉर्ड रोनेल्डशे ने कहा है इस एक्ट ने आशाओं को पूरा नहीं किया—“सत्य इस बात को मानने के लिए विवश करता है कि वायसरॉय ने जितना समय और ध्यान दिया था उसकी तुलना में ‘‘‘‘ जो वास्तविक परिवर्तन हुए वे नहीं के बराबर थे।”<sup>१</sup>

खमीन और मालगुजारी, मुद्रा एवं व्यवसाय, सिंचाई, पुलिस, रेलवे-शासन और सरकारी शासन-सबकी सुधारों में लॉर्ड कर्जन को अधिक सफलता मिली।

शासन ढर्रवार हो गया था और उसमें गति एवं मुचरता का अभाव था। विचाराधीन प्रश्न पर इतनी रिपोर्ट और सम्मतियाँ लिखी जाती थी कि उन रिपोर्टों के बीच वास्तविक प्रश्न खो जाता था।<sup>२</sup> इसके कारण निर्णय में बहुत देर होती थी—एक विषय तो निर्णय के लिए इकसठ वर्षों तक लटका रहा। लॉर्ड कर्जन ने कितने ही सुधार सुमाये। उसने विभिन्न विभागों की अपने विषयों का व्यक्तिगत परामर्श द्वारा निपटारा करने की सलाह दी और साथ ही लम्बे विवादों से बचने, नोट लिखने का काम घटाने और शीघ्र निर्णय<sup>३</sup> करने के लिए कहा।

लॉर्ड कर्जन के अन्य सब प्रशासनीय सुधारों का वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं है किन्तु पुलिस और रेलवे-शासन-सबकी सुधारों का संक्षिप्त विवरण देना उचित होगा।

सन् १८६० के पुलिस-कमीशन की सिफारिशों के आधार पर १८६१ में पुलिस-व्यवस्था का पुनर्संगठन किया गया था। हर प्रान्त में पुलिस विभाग का साधारण प्रबन्ध एक इन्स्पेक्टर-जनरल के आधीन था। हर जिले में एक यूरोपियन सुपरिटेण्डेण्ट था और बड़े जिलों में उसके साथ एक यूरोपियन सहायक भी होता था। प्रत्येक जिला बृत्तों में बाँटा गया था और प्रत्येक बृत्त एक इन्स्पेक्टर के आधीन

१ Ronaldshay The Life of Lord Curzon page 195.

२ उपर्युक्त पुस्तक, Vol II, page 26.

३. Frazer. India under Curzon and After page 256

किया गया था। हर वृत्त को विनन हो जाना में बाँटा गया था और हर भाग का दायित्व एक हेट कान्स्टबल को दिया गया था। इन थानों के अन्तर्गत सार्वे और अन्य कान्स्टबल थे। ये सब नौकरियाँ आधीन नौकरियों के वर्ग में लिगे जानी थीं। डिग्न-मजिस्ट्रेट को निरीक्षण और प्रबन्ध के सामान्य अधिकार प्राप्त थे।

पुलिस-व्यवस्था के प्रति एक आम चिन्तावन था और सन् १९०२ में सर एण्ड्रयु मज्जर को अध्यक्षता में एक पुलिस-कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने विभिन्न सिफारिशों की जो १२७ शीर्षकों में बाँटी गई थी। अधिकार्य सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया और सन् १९०५ में उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया। कमीशन की मुख्य सिफारिशें ये थी—(१) पुलिस-मजदूरों में हंड कान्स्टेबल वर्ग में उच्चतर पदों के लिए पदानुक्रम द्वारा भर्ती न जो जाय बल्कि उस उच्च एवं पुष्ट वर्ग के लिए सीधी भर्ती जो जाय, (२) वेतन वृद्धि जाय, (३) पुलिस-मजदूरों में वृद्धि की जाय और पुलिस-कार्य के लिए गावा के वर्तमान अधिकार्यों का उपयोग किया जाय, (४) अक्रमरों और कान्स्टेबलों के लिए मिशन-शालाएँ खोली जाय, (५) जांच के टम में सुधार हो, (६) स्थानीय निरीक्षण और देख-भाल से काम का निर्णय किया जाय आकड़ों से नहीं (७) जपराधियों की गोज के लिए प्रान्तीय विभाग स्थापित किए जायें और साथ ही एक टाइटलर के आधीन एक केन्द्रीय विभाग हो।

सन् १९०५ के पुनर्गठन के फलस्वरूप पुलिस-शासन का व्यव, जो सन् १९०१-१९०२ में २६९१ ३४४ पौण्ड था, सन् १९११-१२ में बढ़कर ४५,०२,९९७ पौण्ड हो गया। किन्तु पुलिस-दल की कुशलता में वृद्धि इतनी अनुपात में नहीं हुई और वह अब भी पड़े की तरह अश्रिय बना रहा।

भारत में रेलवे-शासन भी कमजोर था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी मरणा के लिए रेलवे-विनोद सर टॉमस राबर्टसन को ट्रेलेंट से बुलाया। उसने रेलवे-शासन में जामूल सुधार करने की आवश्यकता बनाई। उसी की सिफारिशों के आधार पर सन् १९०५ में एक रेलवे बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड में सनापति के अनिरीक दो सदस्य और थे। सन् १९०८ में इस बोर्ड और उसके सहायकों को एक पुष्ट रेलवे-विभाग में परिणत कर दिया गया। इस विभाग का अपने अध्यक्ष द्वारा चायमराय में सीधा मकष था। उसके विन्तु अधिकार्य थे; और उसका अपना महागणक और मुख्य इंजीनियर था। यह विभाग वणिज और उद्योग के सदस्य के आधीन था।

१ कान्स्टेबल के लिए ८ र० प्रति महीने के न्यूनतम वेतन के लिए सिफारिश की गई किन्तु सरकार ने केवल ७ र० महीने वेतन देना निश्चित किया।

( ८ )

इस युग में वैधानिक महत्त्व की कई उल्लेखनीय घटनाएँ हुई। सन १८९३ में हाउस आफ कामन्स ने इंडियन सिविल सर्विस के लिए समकालिक परीक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली-दरबार हुआ और प्रिंस ऑफ वेल्स (राजकुमार) भारत में आए। सन १९०४ में और फिर सन १९०७ में भारतीय परिषद् एक बनाने कायसराय की परिषद् ने सदस्यों की स्थिति का और साथ ही भारत मंत्री और गवर्नर-जनरल के संबंध का स्पष्टीकरण हुआ।

समकालिक परीक्षाओं के प्रस्ताव के स्वीकृत होने का अर्थ श्री दादाभाई नौरोजी को हुआ जो उस समय हाउस आफ कामन्स के सदस्य थे। भारत मंत्री के अनुसार प्रस्ताव केवल एक चीज से स्वीकृत हुआ था। उसे सम्मति के लिए भारत भेजा गया था। किन्तु मद्रास सरकार<sup>१</sup> के अतिरिक्त केन्द्रीय और अन्य प्रांतीय सरकारों ने उसका प्रबल विरोध किया था।

२३ जनवरी १९०१ को महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई। लाड कब्रन ने उसके राज्य-काल की स्मृति में एक ऐसे स्मारक की स्थापना करने का निश्चय किया जिसमें विगतकालीन महत्त्वपूर्ण उपस्थानों का और साथ ही भविष्य<sup>२</sup> में उसी प्रकार की वस्तुओं का संग्रहालय हो। फलतः ५५०००० पौण्ड के व्यय पर कलकत्ता में प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल हाउस बना। लाड रोबर्ट्स के अनुसार मुग़लों के बाद वह भारत की सर्वोत्तम इमारत है और ब्रिटिश राज्य का सर्वोपरि वभवपूर्ण स्मारक है।<sup>३</sup>

लाड कब्रन ने एडवर्ड सप्तम से आगामी गिनिर में भारत आकर राज्याभिषेक दरबार करने का प्रस्ताव किया। किन्तु जब यह स्वीकार नहीं हुआ तो उसने एक साम्राज्यीय दरबार के लिए प्रस्ताव किया। यह वभवपूर्ण दरबार १ जनवरी १९०३ को हुआ। इसमें समस्त व्यय के अतिरिक्त १८०००० पौण्ड खर्च किए गए। देशी राज्यों ने जो अपरिमित धनोत्सर्ग किया वह अलग था।

इसी युग में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स और प्रिंसस भारत आए। बगमन के कारण देश में रोष छाया हुआ था और उस वातावरण के कारण अव्यवस्था का भय था किन्तु उनके उपलब्ध ने कोई अप्रसन्नता उत्पन्न नहीं हुई।

१ मद्रास-सरकार ने १८७८ के मुखबरीबक एक्ट का भी विरोध किया था।

२ Ronaldshay Life of Lord Curzon Vol II page 155

३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १६२

( ९ )

१८७४ के एक्ट की धाराओं के अनुसार कार्यपालिका निर्माण सदस्य की नियुक्ति (१८७५ में) की गई और उसी एक्ट के अनुसार (लॉर्ड बर्जस के माल में जाने पर) उस पद को नाट दिया गया। सन् १९०२ में वायसराय ने फिर (एक बार व्यवसाय और उद्योग-विभाग के लिए) परिषद का छठा सदस्य नियुक्त करने के लिए आग्रह किया। १९०४ के भारतीय परिषद एक्ट ने यह अधिकार दिया। एक्ट ने संसद् की गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका-परिषद् में एक छठा साधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस प्रकार व्यवसाय और उद्योग के लिए सन् १९०५ में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई।

सन् १९०७ में भारत-परिषद-एक्ट द्वारा भारत-परिषद् के विधान में भी परिवर्तन किया गया। इस एक्ट के अनुसार भारत-मंत्री को सदस्यों की इच्छा बढ़ाकर १४ करने का अधिकार दिया गया। मंत्री की शर्त में भी परिवर्तन किया गया और अधिकार का दस वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया। सदस्यों का वेतन १२०० पौण्ड प्रतिवर्ष से बढ़ाकर १००० पौण्ड प्रतिवर्ष कर दिया गया और कार्य-काल को भी १० वर्ष के स्थान पर ७ वर्ष कर दिया गया।

( १० )

सन् १८९० में विधान-परिषद् के आचार और अधिकारों में वृद्धि होने पर यह प्रश्न उठा कि क्या कार्यपालिका-परिषद् के सदस्य, विधान-मंडल में अपनी इच्छानुसार अपना मत प्रकट कर सकते हैं और क्या वे अवसर आने पर परम्परा विरोध कर सकते हैं? सन् १८९५ में २६ जून को भारत-मंत्री ने एक राज-पत्र द्वारा इस बात का अन्तिम रूप स निश्चित कर दिया और स्पष्ट शब्दों में यह सिद्धान्त रखा कि कार्यपालिका-परिषद्, कार्यपालिका और विधान दोनों ही कानों में समुक्त और सुदृढ़ हैं। “जबनाई हुई नीति, सारी सरकार की नीति है और उन एजेंसी की, जो शासन के सदस्य रहना चाहते हैं, उस नीति को स्वीकार करना चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।”<sup>१</sup>

अगले कुछ ही वर्षों में वायसराय की कार्यपालिका-परिषद् में गंभीर मतभेद उठ सके। ए और अन्य में लॉर्ड बर्जस ने त्याग-पत्र दे दिया। विवाद, एक ब्रह्मन्त महारक्षार्थी वैधानिक प्रश्न पर था कि देश की सामान-व्यवस्था में सेनापति की क्या स्थिति है? लॉर्ड विक्टर ने जो स्थिति अपनाई थी वह वैधानिक दृष्टि से गलत थी और व्यवहार में जोखिम से भरी हुई थी। जैसा कि लॉर्ड बर्जस ने कहा वह

१. Dumbell : Loyal India : A Survey of Seventy Years-  
pages 37 and 38

(किचनर) एक साथ, सेनापति और युद्ध-मंत्री दोनों ही होना चाहते थे। तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने सेनापति का वायसराय से अधिक पक्ष लिया।<sup>१</sup> भारत-मंत्री ने एक समझौते का प्रस्ताव किया। उसमें, वायसराय ने कुछ सशोधन किया और दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया।<sup>२</sup> किन्तु जब उसे कार्यान्वित करने का समय आया तो वायसराय को यह पता लगा कि भारत-मंत्री उसे उचित रूप में कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। वायसराय ने जनरल बॅरो का नाम सुझाया था किन्तु भारत-मंत्री ने उस सुझाव को अस्वीकार किया और एक अन्य व्यक्ति को रसद विभाग का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव किया। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड कर्जन ने तार द्वारा अपना त्याग-पत्र दे दिया। १२ अगस्त १९०५ के इस त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया गया और लॉर्ड मिण्टो को लॉर्ड कर्जन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

सन् १९०६ में १९ मार्च को जो व्यवस्था अन्तिम रूप से अपनाई गई, उसके अनुसार सेना विभाग को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। सेना-विभाग सेनापति के आधीन किया गया और सेना के रसद विभाग के दायित्व को नए सदस्य को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार सेनापति का काम अत्यधिक हो गया। सन् १९०९ में पर्याप्त काम न होने के कारण रसद-विभाग तोड़ दिया गया। उस समय सेनापति का काम और भी अधिक हो गया। जैसा कि मेसोपोटामियन-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा—किसी व्यक्ति के लिए सेनापति और परिषद् के सेना-सदस्य का काम एक साथ करना सम्भव नहीं था और युद्ध-काल में उसकी स्थिति और भी विकट थी। पहले महायुद्ध के समय में मेसोपोटामिया के विरुद्ध सैन्य-संचालन में यह बात दुःखद रूप से स्पष्ट हो गई। सैन्य-व्यय और सेना के भारतीयकरण की दृष्टि से भी स्थिति गंभीर थी। सैनिक नियंत्रण की अपेक्षा सिविल नियंत्रण में सैनिक व्यय घटाना और भारतीयकरण की गति बढ़ाना सरलतर था।

### ( ११ )

लॉर्ड कर्जन के त्याग-पत्र से भारतीय सरकार के दो अध्यक्षों के सदस्य का प्रश्न फिर सामने आ गया—एक ओर इंग्लैंड में वैध, अन्तिम सत्ता थी, और दूसरी

१. मूडान की विजय के बाद किचनर को राष्ट्रीय महारथी समझा जाता था और यह भय था कि उसके त्याग-पत्र देने से इंग्लैंड का मन्त्रि-मण्डल अपने पद पर टिक नहीं सकेगा।

२. समझौते में यह तय हुआ कि सेनापति के अतिरिक्त एक रसद विभाग का सदस्य होगा जो सैन्य विषयों पर सरकार के लिए हमारे परामर्शदाता का काम करेगा।

शासन को मुसल बनाने के लिए उत्सुक था तथापि वह इंग्लैंड और भारत में सार्वजनिक विश्वास और समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा।

लॉर्ड कर्जन के उत्तराधिकारी लॉर्ड मिण्टो का व्यक्तित्व उसके हाथ का था। मिण्टो की जीवनी में कहा गया है 'मिण्टो ने भारत मंत्रा के स्वभाव को चतुराई से समझ लिया और उसके सफटों से वचन के लिए अपने-आपको तैयार कर लिया। उसका उद्देश्य यह था कि धैर्यपूर्ण तर्कों और चतुरतापूर्ण मुझावा से मि. मालों को यह विश्वास हो जाय कि भारत सरकार की नीति का उपक्रमण उनके ही हाथों से हो रहा है।' <sup>१</sup> लॉर्ड मिण्टो के राज्यकाल समाप्त होने के समय उनका पारस्परिक संबंध कुछ खिच गए थे। इसका कारण था भारत सरकार पर गृह-संस्कार का कठोर नियंत्रण। लॉर्ड मिण्टो ने लिखा है 'जो लोग वस्तुस्थिति से परिचित हों वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक छोटी-म छोटी बात में भी हस्तक्षेप किया गया है।' <sup>२</sup> किन्तु मिण्टो की चतुराई शिष्टता और व्यवहार-कुशलता ने स्थिति को बचाया और लॉर्ड मिण्टो ने इन बातों में अपना काम निकाल लिया।

## बारहवाँ अध्याय

# धार्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ

( १ )

सन् १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आरम्भ हो गया था। उसी आंदोलन के फलस्वरूप पार्लियामेंट ने १८९० का भारतीय परिषद एक्ट बनाया। इस एक्ट के सुधारों ने कांग्रेस की सन्तुष्ट नहीं किया और उसने १८९३ में बड़े दिन पर अपने अधिवेशन के समय अपने असंतोष को व्यक्त किया। निर्वाचन व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था परिषदों के सदस्यों के अधिकार अत्यंत सीमित थे। चाइसराय की परिषद में अथवा प्लानीय परिषद में पञ्जाब को अपने प्रतिनिधि भजन का अधिकार नहीं दिया गया था, निर्वाचन के लिए जो नियम बनाए गए वे अनुचित थे—कुछ वर्गों का प्रतिनिधि भजन के अधिकार से विलुप्त बचित कर दिया गया था और कुछ जिलों को अत्यंत

१ Buchan Lord Minto pages 223 & 224

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२ ३१३



द्विज प्रतिनिधित्व दे दिया गया था।<sup>१</sup> निरन बनाने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि छूटे हुए लोग जहाँ तक मानव हो, स्वतन्त्र व्यक्ति न हों, वरन् ऐसे हो कि उनको सरकार ने प्रभावित किया जा सके।<sup>२</sup> गैरसरकारी सदस्यों को मन्त्रा दत्त बन गयी।<sup>३</sup> परिषदों के कार्य और अधिकार अत्यन्त सीमित थे। ऐसी दशा में राष्ट्रीय उत्थान के उद्देश्य से उत्तमोगी काम करने के लिए परिषदों में क्षम बहान मुहुचित था। वह काम बन राजनीतिज्ञ, सामाजिक एवं धार्मिक सम्प्रदायों के मुखान और भारतीय धर्मों के धारक हो किया जा सकता था।

राष्ट्रीय उत्थान एवं पुनर्जन्म के लिए काम करने वालों इन अन्य संस्थाओं में इन्डियन नेशनल कांग्रेस प्रमुख थी। प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्त में मिलित भारतीय, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ काम में और राष्ट्रीयता बनाने में अनुराग था, इन के प्रत्येक प्रांत के किसी महत्त्वपूर्ण नगर में एकत्रित होते थे। ये लोग राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर विशेषकर शासन, शिक्षा एवं अर्थ-व्यवस्था-संबंधी विषयों पर विचार-विनिमय करते थे और अपने दृष्टिकोण का विमोचन, तर्कमुक्त एवं राजनैतिक रूप से नापा में लिखे हुए प्रस्तावों द्वारा व्यक्त करते थे। भारतीय धर्मों में इन प्रस्तावों को और नेताओं के व्याख्यानो को प्रभावित किया जाता था और उनकी सना-लोचना को जाती थी। देश के महत्त्वपूर्ण नागरीय इन चीजों को पढ़ते थे, उन पर विचार करते थे और यह स्वाभाविक था कि इन बातों के उन लोगों का हृदय और मस्तिष्क प्रभावित होता था। यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि कांग्रेस के इन प्रस्तावों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं था और सरकार प्रस्तावित सुधार नहीं करती थी। परन्तु कांग्रेस के कार्य-क्रम-सिद्धान्त के लिए बहुत बड़ा महत्त्व था। मार्क्सविकि कामों में दिग्दर्शनी देने वाले लोगों की संख्या बढ रही थी और राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर उनका तैयार हो रहा था। सरकार के कामों पर ध्यान रखा जाता था और बीमारी शनाथी के पहले पांच वर्षों में उनके प्रति प्रबल विरोध उठ रहा हुआ। अन्ततः लोगों में एक नए जीवन का संचार हो गया था और

१. Resolution 1 of 1893 Besant. How India Wrought for Freedom page 177.

२. उदाहरण के लिए दम्बर में ६ स्थानों में से दो स्थान प्रयोगी व्यवसायियों को दिये गए थे किन्तु नागरीय व्यवसायियों को एक भी स्थान नहीं दिया गया था। निध को दो स्थान दिये गए थे किन्तु दम्बर-प्रेसीडेंसी के केन्द्रीय विधायन को, जिनमें पूना और सतारा थे, कोई स्थान नहीं दिया गया था।

३. केन्द्रीय विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या २४ थी। इनमें से १४ सरकारी सदस्य थे, ५ नाम निर्देशित गैर-सरकारी सदस्य और ५ निर्वाचित।

राष्ट्रीय आंदोलन विस्तृत होकर जन-आंदोलन के रूप में परिणत हो रहा था। इस समय राष्ट्रीयता में दो विचार-धाराएँ आरम्भ हुईं। इन दोनों में धार्मिक भावना समाई हुई थी। किंतु मार्ग दोनों का अलग था। दोनों ही विचार-धाराओं के नेता-गण साहसी व्यक्ति थे। उनमें आत्म-बलिदान और स्वतंत्रता की भावना थी, प्रबल देश-प्रेम था और विदेशी राज्य के प्रति तीव्र घृणा थी। पुराने कांग्रेसियों की भाँति उन्हें अंगरेजों की उदारता और सच्चाई में विश्वास नहीं था और न उनकी राजनीतिक भिक्षा-वृत्ति में ही कोई निष्ठा थी। उन्हें तो आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र कार्य में विश्वास था। इन नेतागणों की प्रेरक भावनाएँ एक ही थी, वे भारत और उसकी जनता के पश्चिमोत्थरण के विरुद्ध थे, वे प्रबल ही नहीं बरन उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत, जो फिर प्राचीन वैभव, समृद्धि एवं पवित्रता से परिपूर्ण हो। दोनों में भेद केवल मार्ग का था। उग्र दल का राजनीतिक आंदोलन में और ब्रिटिश बीजों और सत्ताओं के बहिष्कार द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में विश्वास था। वे सरकारी कार्यालय, न्यायालय और स्कूल आदि सब सत्ताओं के बहिष्कार के पक्ष में थे और वे उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्याय-मंडल, पंचायत, स्कूल आदि स्थापित करना चाहते थे। जानिकारी दल को पश्चिमी जातिकारी साधनों में, विशेषकर बम और पिस्तौल द्वारा आतंकवाद, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक ढकैतियों में विश्वास था।

( २ )

1885-1892

राष्ट्रीयता

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में नई राष्ट्रीयता के उदय के लिए कोई इस प्रकार का एक कारण नहीं दिया जा सकता कि उसके द्वारा पूर्व प्रतिष्ठा से व्युत्पन्न ब्राह्मण<sup>१</sup> वर्ग सक्ति हथियाना चाहता था अथवा इस राष्ट्रीयता के तल में केवल बग-भग का असंतोष था और लॉर्ड कर्जन के अग्रिम राज्य-काल के प्रति रोष था अथवा इसका कारण कांग्रेस के अब तक के साधनों की असफलता का अनुभव था। उक्त पिछले दो कारणों के अतिरिक्त और कई कारण भी थे जिनके फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ग्रहण की और उसमें दो—उग्र तथा जातिकारी—विचार-धाराएँ उत्पन्न हुईं।

पहली बात तो यह भी कि विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनका भारतीय मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। १८९६ में इटली को एबीसीनिया<sup>२</sup> के निवासियों ने परास्त किया और १९०५ में जापान ने रूस को हराया। इन दोनों

१ Chirol Indian Unrest. page X and XI and 40 & 43

२ "इटली की हार ने १८९७ में तिलक के आंदोलन में घृणावृत्ति दी"

Garrat. An Indian Commentary, page 134.

कट्टर लोगो में इसके प्रति बड़ा रोष था। सन् १९०४ में एक दूसरा एक्ट बना जिसके प्रति भारतीयों में बड़ी तीखी भावना जाग्रत हुई। यह एक्ट सरकारी गोप्य विषयों से संबंधित था। इस एक्ट में १८८९ के इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और १८९८ के एक्ट नं. ४ को दो दिसाओं में बढ़ा दिया गया था। सन् १८८९ के एक्ट में केवल सैनिक भेद देना ही दंडनीय था अब उसमें सिविल (असैनिक) विषयों का भेद देना भी दंडनीय कर दिया गया। साथ ही १८९८ के एक्ट में समाचार-पत्रों की समालोचना के संबंध में जिन बातों को अपराध बनाया गया था, उनमें यह जोड़ दिया गया कि ऐसी समालोचनाएँ, जिनमें विधि निर्मित सत्ता अथवा सरकार के प्रति अनास्था अथवा घृणा जाग्रत हो, दंडनीय हों। सन् १८९८ के एक्ट के अनुसार साम्राज्य अथवा ब्रिटिश भारत में विधि निर्मित सरकार के प्रति, अभक्ति की भावनाएँ उत्तेजित करने को अथवा उत्तेजित करने के प्रयत्न को राजद्रोह बताया गया था। भारतीय दंड संहिता में एक नया विभाग (नं. १५३ ए) जोड़ दिया गया था जिसके अनुसार बर्ग-ट्रेप को प्रोत्साहन देने वाले अपराधी दंडनीय थे।

लॉर्ड कर्जन की सीमा प्रांतीय और अफ़गानिस्तान तथा तिब्बत-संबंधी नीति से भी भारतवासी अप्रसन्न थे। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सैन्य-क्षय में बढ़ि के विरुद्ध थे। इन्हीं कारणों से वे चीन और दक्षिण अमेरिका के लिए भारतीय सेना भेजने के विरोधी थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजनाओं में भारतीय सेना के उपयोग के कारण भारतवासियों में तीव्र रोष था।

उपर्युक्त बातें अग्रिम तीखी तथापि सन् १९०५ और बाद के वर्षों के सरकार-विरोधी आंदोलन को जन्म देने के लिए ये बातें स्वयमेव अपर्याप्त थीं। इन सब बातों के साथ मौलिक बात यह थी कि वय-भय के संबंध में व्यापक विरोध के होते हुए भी लॉर्ड कर्जन की सरकार की मूढ़तापूर्ण एवं कृदिल दृढ़ता की नीति ने लोगों के रोष को चरम सीमा पर ला दिया था और परिणामस्वरूप वह आंदोलन फूट पड़ा।

( ३ )

सन् १९०५ में १६ अक्तूबर को, प्रकटित शासन में सुविधा और कुशलता के कारणों से वग-भग किया गया। यह सच है कि ८ करोड़ जनसंख्या का बंगाल प्राप्त एक अध्यक्ष—और वह भी एक उप-गवर्नर—के लिए बहुत बड़ा दायित्व था। किंतु यह बाल ध्यान में रखने योग्य है कि तत्कालीन बंगाल में बहुत से अ-बंगाली लोग थे। बिहार और उड़ीसा, तत्कालीन बंगाल के अन्तर्गत थे और उनकी जनसंख्या २ करोड़ १० लाख थी। शासन में कुशलता लाने की दृष्टि से बंगाल को ऐसे दो भागों में बाँटा जा सकता था जिनमें से एक बंगला बोलने वाला होता और दूसरा अन्य भाषाओं के बोलने वाला। वस्तुतः छह वर्ष बाद यह बात भी गई।

किन्तु सन् १९०५ के बंग भग के अनुसार स्वयं बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया। नये बंगाल की कुल जन-संख्या ५ करोड़ ४० लाख थी इसमें से बंग-भाषियों की संख्या केवल १ करोड़ ८० लाख थी। पूर्वी बंगाल और आसाम के नये प्रांत की कुल जन-संख्या ३ करोड़ १० लाख थी और इसमें २५ करोड़ बंगलाभाषी थे और १ करोड़ ८० लाख मुसलमान थे। स्पष्ट है कि इस विभाजन का उद्देश्य वस्तुतः शासन में सुविधा का नहीं था बल्कि यह तो बहुत कुटिल और गूढ़ था। जैसा कि लॉर्ड रोडरिक्स ने कहा है "प्रांत के जाग्रत वर्गों के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रियता की बहुत बड़ी दृष्टि पर आक्रमण किया गया था।"<sup>१</sup> जिस दंग से विभाजन की योजना बनाई गई और उसको कार्यान्वित किया, उससे और साफ ही इस विषय में लॉर्ड कर्जन के ध्यात्माना से यह स्पष्ट है कि वास्तविक उद्देश्य फूट डालकर राज्य करने की नीति के अनुसार लोगों को घर्ष के आधार पर विभाजित करना था और हिंदुओं और मुसलमानों में द्वेष भाव फैलाना था। श्री मजूमदार ने लिखा है "नई चेतना को कुचलने के लिए लोगों को परस्पर विभाजित करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन पूर्वी-बंगाल गये। वहाँ पर इसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई मुसलमानों की सभाओं में उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के ही लिए नहीं किया जा रहा था बल्कि उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा था जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी...।"<sup>२</sup> विभाजन के समर्थक ने भारतीय विरोध के लिए यह कारण प्रस्तुत किया है कि कफ़ील राजनीतिज्ञों और सपादकों को विभाजन के फलस्वरूप<sup>३</sup> भौतिक और राजनीतिक क्षति का डर था। किन्तु उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि इस आंदोलन की प्रेरक शक्ति एक प्रबल भावना थी।<sup>४</sup> मि. नेविन्सन ने लिखा है "रोप की मूल में भावना है और क्योंकि यह भावना है इसी कारण किसी भौतिक लाभ और शासन की सुविधा से इसकी क्षतिप्रति नहीं हो सकती।"<sup>५</sup> अतः यह कहना असत्य है कि आंदोलन के समर्थक भौतिक हितों से प्रेरित थे। दूसरी ओर अधिकांश

१ Ronaldshay Life of Lord Curzon. vol. I. page 332.  
२ A. C. Mazumdar Indian National Evolution, page 207.

३ Frazer India under Curzon & After page 384.  
Also Ronaldshay Life of Lord Curzon. vol. I. page 332.

४ Ronaldshay उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३२२

५ Nevins - The New Spirit in India. page 172.

जोगो के लिए प्रेरक शक्ति यह इच्छा थी कि सर्वसाधारण में ऐक्य और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे। साथ ही यह भी सच है कि पूर्वी बंगाल के बहुत से मुसलमानों को लॉर्ड कर्जन की बातों ने लुभा लिया और वे नए, मुस्लिम बहुमत प्रांत में अपने पुरस्कारों के स्वप्न देखने लगे। फिर भी केवल बंगाल में ही नहीं बरन् सारे देश में अधिकांश लोगों ने विभाजन का तीव्र विरोध किया। फलतः एक सुमगडित एवं अनुशासनपूर्ण प्रबल आंदोलन हुआ।

( ४ )

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में देश में अकाल, प्लेग आदि राष्ट्रीय विपत्तियों का सामना करने के लिए सरकार ने सतोषजनक नीति नहीं अपनाई। सरकारी आर्थिक नीति तो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी ही। परिणाम यह हुआ कि सरकार के प्रति रोष और भी अधिक बड़ा और साथ ही नई राष्ट्रीयता को रुष्टि मिली।

१८९६-९७ में बड़ा भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। ब्रिटिश राज्य काल में उस समय तक ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। सन् १८९७ के वसंतकाल में सहायता नाने वाले अकाल-पीड़ितों की संख्या ४० लाख से ऊपर पहुँच गई थी। मरने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। सहायता के लिए और मालगुजारी दोहराने के लिए सरकारी मशीन बड़ी धीमी गति से चल रही थी, कष्ट और कठिनाइयों से हाहाकार मचा हुआ था। बम्बई प्रांत में प्लेग की महामारी आरंभ हो जाने से दशा और भी बिगड़ गई। सन् १८९८ के अन्त तक अनिलिखित मृत्यु-संख्या १,७३,००० पर पहुँच गई जो सम्भवतः वास्तविक संख्या से बहुत कम थी। सरकार ने उपायों की सोत्साह अंगीकार किया, किंतु उन्हें कार्यान्वित करने का ढंग शल्लभ था। पूना के प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड ने ब्रिटिश सैनिकों से काम लिया। वे सैनिक मकानों में घुसकर पुर्ण्यो, स्त्रियों और बच्चों की जाँच करते थे और प्लेग का संदेह होने पर उन्हें अलग अस्पतालों में ले जाते थे। इससे लोगों में बड़ा रोष फैला। उपद्रव आरंभ हो गए। पत्रों में उग्र लेख लिखे गए। एक भावुक नवयुवक ने अग्रिय प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड को गोली से मार दिया। उसके साथी ने तत्काल पकड़े जाने के भय से लेफ्टिनेंट ऐपस्टर्न को गोली से मार दिया। ऐपस्टर्न, रैण्ड के पीछे एक गाड़ी में आ रहा था। इस काण्ड के बाद कठोर दमन और आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र इसका विशेष क्षेत्र था।

सारे देश में असंतोष का प्रबल ज्वार उमड़ रहा था। दुर्भाग्य से १८९९ में र्पा न होने के कारण भारत में फिर १८९९-१९०० में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। यह

दुर्भाग पहले ने भी अधिक नजर या और इनने पहले ने भी अधिक रंगे पीड़ित हुए।

उन कारणों की आपदाओं और कष्टों के कारण लोगों में बड़ा असंतोष हुआ और सरकार को विरोध रूप में दाप दिया गया। जनता के अनुसार उनके दुखों को उठ नगवान की वह आर्थिक नीति थी जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी। इस प्रकार सर्वनाधारण में अपने विदेशी शासकों के प्रति संतोषजनक बहुत बट गया।

सरकार की राष्ट्र-विरोधी आर्थिक नीति ने ब्रिटिश राज्य के प्रति सर्वनाधारण के सम्मुख में जो घृणा उत्पन्न और पुष्ट की उनके महाप के बारे में कोई कठिनायक नही थी जो नकली। विदेशी राज्य ने देश बचाने निर्धन ही गया था। इस वग म दादाभाई नौरोजी ग्लेसफोल्ड दन राणाडे, डॉ. एन. बाबा और नर दिक्षिपम दिगली के अनुमोदना और सत्ता न निर्धनता की उक्त स्थिति की विरोध रूप में स्पष्ट कर दिया था। नर दिवाडार मॉरिसन ने इस नव का प्रतिवाद करते का प्रयत्न भी किया किन्तु भारतीय नेताओं और पत्रों ने भारत से इंग्लैंड के लिए होने वाले द्रव्य-निकास से सर्वनाधारण को मली-भांति परिचित करा दिया था। भारत में ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण जनता का विदेशी शासकों की न्यायप्रियता और नबाई में ने विरोध उठ गया और ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ बढ़ गईं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है लॉर्ड कर्जन का कुशलता, केन्द्रीकरण और अधिकारीकरण के लिए विरोध मोह था। और स्वशासन और भारतीयकरण के लिए विरोध था। १९०४ में कर्जन ने भारतीयों के निराकरण को बड़े चुनने वाले दृष्ट से उचित टहराया। उसमें लोगों के लिए एक चुनौती चुनौती थी। उनसे कहा गया कि सर्वोच्च सिविल पद केवल अंगरेजों के ही लिए थे क्योंकि उनमें अपने पतृवाधिकार, पौषण और शिक्षा के कारण, शासन के लिए अनिवार्य, चरित्र-बल, शासन के सिद्धांतों का बोध और मनोयोग था। कुछ सिद्धि भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए समझन करने लगे।

इसी मदर्भ में ध्यान देने योग्य कुछ आर्थिक प्रश्न हैं जिनके संबंध में भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यावसायिक, औद्योगिक और वित्तीय स्वार्थों के लिए भारतीय हितों को निर्गुणता के साथ बलिदान किया। मन् १८९४ में जंगल-मोना सूत्र का विवाद फिर उठ खड़ा हुआ और वित्तीय आवश्यकताओं के कारण जो प्रतिग्रह का साधारण कर लगाया गया था उससे सूती माल की छूट देने पर बड़ा दादोहन हुआ। भारत-नशी ने इस कठिनाई को हल करने के लिए यह प्रस्ताव किया कि नई कर-सूची में विदेशों ने जाने-बोले सूती माल की सम्मिलित किया

जाय और उसका सन्तुलन करने के लिए २० न से ऊँचे माप के भारत में तैयार किये हुए मूल पर उत्पादन-कर लगाया जाय। भारतीयों का विरोध होने हुए भी दिसम्बर १८९४ में इस प्रस्ताव को बंध कर दिया गया। वित्तु लकाशायर को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि १८९६ में दो नये प्रस्ताव स्वीकार किये गए। एक के अनुसार सूती माल पर आयात-कर घटाकर  $3\frac{1}{2}$  प्रतिशत कर दिया गया और दूसरे के द्वारा भारतीय मिलों के सूती माल पर  $3\frac{1}{2}$  प्रतिशत का प्रत्यक्ष उत्पादन कर लगा दिया गया। भारत परियद् मे सर जेम्स पाइल और सर एलेक्जेंडर आर्चबुर्नोर्ट ने इन अरक्षणीय एकटो का विरोध करते हुए कहा "कि इस उत्पादन-कर से वस्तुतः कोई सन्तुलन नहीं होता या क्याकि भारतीय मिलों के मोटे सूती माल में और लकाशायर के बारीक माल में कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं थी, भारतीय बाजार में दोनों की माँग थी।" देश में बड़ा आंदोलन हुआ और अगरेजी राज्य के प्रति घृणा और तीक्ष्णता को बड़ा पोषण मिला।

भारतीय मद्रा और विनिमय का प्रबन्ध अगरेजी स्वार्थों के अनुसार होता था। भारतीय व्यापारी वर्ग इस कारण बड़ी कठिनाई अनुभव करता था। एक भारतीय लेखक ने भारतीय आलोचना को संकलित रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है — "ये आलोचनाएँ मुख्यतः, स्वर्ण रक्षित मान को भारतवर्ष में स्वर्ण पाट के रूप में रखने के स्थान पर, अन्य प्रतिभूतियों (Securities) में लगाने के विरुद्ध थी, रेलवे-व्यय के संबंध में सरकार की तत्कालीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उस रक्षित मान को काम में लाने के विरुद्ध थी, कागजी द्रव्य के रक्षित मान को, भारत से लन्दन के लिए स्थानांतरित करने के विरुद्ध थी, स्वर्ण मान की सुरक्षा के लिये सोने के स्थान पर चाँदी रखने के विरुद्ध थी, और ऊँचे भाव पर कौंसिल के विनिमय पत्रों के असीमित विप्रेषण के विरुद्ध थी। इस विप्रेषण के कारण भारत में सोने का धाना रुक गया या जिसके फलस्वरूप देश की आवश्यकता से अधिक मात्रा में, कागजी द्रव्य का परिचलन अनिवार्य हो गया था। इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि ७ करोड़ पाँड से अधिक परिमाण की भारतीय संपत्ति, भारत से लन्दन के लिये स्थानांतरित हो गई। इस भारतीय संपत्ति को अल्पव्यय व्याज पर लन्दन के शोधियों को उधार दिया गया जबकि भारत में रुपये की कमी थी यहाँ तक कि एक समय पर सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर भी ऋण उगाहना संभव नहीं था यद्यपि व्याज की दर अस्वाभाविक रूप से अधिक रखी गई थी।" इस नीति के विरुद्ध भारतवासियों में प्रबल रोष फैलना स्वाभाविक ही था, और भारतीय व्यापारी वर्ग का सरकार पर से विश्वास उठ गया।

१ Indian Year Book, 1931. page 860 के एक उद्धरण से अनूदित।

( ५ )

भारत में नई राष्ट्रीयता के जन्म और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा  
 पानेवाला कारण था भारतवासियों के प्रति आंग्ल भारतीयों का व्यवहार  
और आंग्ल भारतीय पत्रों का भारतीय विरोधी दृष्टिकोण और प्रचार।  
 इन दोनों में बिजनी ही बार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने अत्याचार  
 तोपा के साथ घातक भाग पीछे की और कई बार चाहत व्यक्ति मार भी गए किन्तु  
 गोरे अपराधी दंड से बच गए परन्तु उह बहुत सामारण-सा दंड दिया गया। लाड  
 बख्त न थोड ही समय में यह अनुभव किया कि इस प्रकार के अभियोगों से भारत  
 में ब्रिटिश राज्य के बन रहने के लिए बहुत बड़ा मुकद्दमा है और फलन ऐसे अभियोगों  
 ध्यान में आने पर उसने अपराधियों को दंड दिवान की व्यवस्था की। एक पात्र  
 योग में अपराधियों ने दो भारतीयों को हत्या की थी। उस समय में लाड बख्त न  
 भारत-वासी को अपने अधिकार में लिखा गया नह। इन अभियोगों के बारे में  
 आपने क्या किया है। किन्तु इनसे मेरी आत्मा तो कराह उठती है। \* उदात्त  
 के लिए इन दोनों पत्रों अभियोगों की चर्चा की जा सकती है। एक मामले में  
 ब्रिटिश सैनिकों ने एक देगी स्त्री को बग़ारदार से मार डाला। उस सैनिकों को  
कोई दंड नहीं दिया गया। यतना ही नह। वरन् स्पानीय सैनिक अधिकारियों ने सारे  
 मामले को दबा देने का प्रयत्न किया और स्पानीय सिविल अधिकारियों ने अपनी  
 उदात्तता से उनके प्रयत्नों का समर्थन किया। \* दूसरे अभियोग में सन १९०९  
 में सिमालहो में स्थित (9th Lancers) घुड़सवार दल के दो सैनिकों ने एक  
 भारतीय रसोइय को इतना पीटा कि वह मर गया। उस रसोइये का अपराध  
 यह था कि उसने जावे के लिए एक देगी स्त्री का प्रबंध करने के लिए मना कर दिया  
 था। पहले अभियोग में कोई पायवाही नह। की गई—लाड बख्त के हस्ताक्षर  
 करने पर केवल कुछ अनुज्ञासा सबंधी कामवाही की गई।

इन अपराधों और हत्याओं का होना स्वयं दुर्भाग्यपूर्ण था किन्तु इससे भी बुरी  
 बात यह थी कि आंग्ल भारतीय समाचार-पत्रों से ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता  
 था। वस्तुतः जातीय कटुता की भावनाओं को फैलाने में आंग्ल भारतीय पत्रों ने  
 जो काम किया वह अत्यन्त निंद्य था। लाहौर के सिविल एण्ड मिलिट्री गवर्नर-जैसे  
 महत्त्वपूर्ण पत्र भी लिखित भारतीयों को गालियाँ देते थे। \* व आंग्ल भारतीयों को  
 अपराध करने के लिए उत्तेजित करते थे इन पत्रों को इसके लिए कोई दंड नहीं दिया

१ Ronaldshay Life of Lord Curzon Vol II p 246

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ७१

३ लिखित भारतीयों को 'बाबल की ए', 'हीन जाति की ए', 'गुलाम'



जाता था। मि<sup>१</sup> 'किंग्सफोर्ड' नामक एक अग्रिम मजिस्ट्रेट को गोली मारने के प्रयत्न में दो अगरेज सित्रियों की मृत्यु हो गई। इस पर कलकत्ते के 'एशियन' ने लिखा, "मिस्टर किंग्सफोर्ड को अब एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। हमारा ऐसा ध्यान है कि वह पिस्तौल से निदाना मारने में होशियार है। हम मौजूर पिस्तौल की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ... हम आशा करते हैं कि मिस्टर किंग्सफोर्ड को अब बड़ा शिकार हाथ लगेगा। हम उनके से अवसर के लिए रुलवाते हैं। उनके निवासस्थान की ओर अथवा स्वयं उनकी ओर यदि कोई अपरिचित देशी आदमी आए तो उसको गोली मार देना उनके लिये पूर्ण रूप से न्याय्य है।"<sup>२</sup>

आरम्भ-भारतीय पत्रों में ऐसे लेख प्रकाशित होते थे और उन पत्रों को कोई वैध दंड नहीं मिलता था। इन लेखों के कारण कटुता की भावना बढ़ती थी और कभी-कभी हिंसा भी होती थी। भारतीय चरित्र पर उच्च पदों से जो कलक लगाया जाता था उसके कारण भारतीयों को बड़ा क्षोभ होता था। फरवरी १९०५ में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना दीर्घात भाषण दिया। उसमें उन्होंने पश्चिमी लोगों की सचाई की और प्राच्यवापियों की धूर्तता की गायी गई। उसी व्याख्यान में यह कहा गया कि भारत राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं है। सारे देश में त्रोष का उफान आया और विरोध में भारत के विभिन्न भागों में सभाएँ की गईं। वायसरॉय के शब्दों ने बहुत से बगाली नवयुवकों को उग्र-दल का समर्थक बना दिया।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके कारण भी भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ पुष्ट हुईं। आरम्भ में भारतवासी शर्तबन्ध मजदूरों की तरह दक्षिण अफ्रीका गये थे किन्तु उनके बाद में कुछ व्यापारी और अन्य व्यवसायी भी गये थे। दक्षिण अफ्रीका में, विशेषकर ओर उपनिवेशों में सभी भारतीय समाज से बहिष्कृत थे। उन पर व्यक्तिगत कर लगता था। शहरों के बाहर कुछ निर्दिष्ट स्थानों में "धूरी" पर उन्हें रहना पड़ता था।<sup>३</sup> कुछ उपनिवेशों में वे राज मार्ग पर नहीं चल सकते थे और न रेल के गहले और दूसरे दर्जे में यात्रा कर सकते थे। वे वहाँ का सोना नहीं रख सकते थे और न रात के ९ बजे के बाद

"घुडसवार मिसमों", "नीच जाति" आदि शालियाँ दी जाती थी—  
Nevinson 'The New Spirit in India', pages 17-18  
से अनुवादित।

१. Nevinson ; The New Spirit in India, page 229.

२. Besant 'How India Wrought for Freedom, page 280.

घर के बाहर रह सकते थे।<sup>१</sup> बन्तुन वहाँ रहने की जगहें इतनी अपमानजनक थीं कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने बोर प्रजातन्त्र से अपने झगड़े के कारणों में इन शर्तों को भी गणना की। एक अवसर पर उन्होंने कहा कि, "हमारी भारतीय प्रजा के इस अपमान से हमारा रक्त उबलने लगता है।" बोर युद्ध में ब्रिटिश विजय हुई किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ बरन् दगा और बिगड़ गई। सन् १९०७ में ट्रांसवाल में एगिप्टाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना। इसके अनुसार भारतीयों को अपराधी जाति की तरह बगुलिया की छाप दकर अपना निवधन कराना आवश्यक था। भारत-वासियों ने इन अपमानजनक नियम का जर्सीकार किया और महात्मा गांधी<sup>२</sup> के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। उन्होंने अपना निवधन कराने के लिए मना कर दिया और फलतः महात्मा गांधी और अन्य सहजा भारतीयों को कारावास दंड दिया गया। मरण कई वर्षों तक चला और उनमें भारतीयों का आर्थिक और नागरिक जीवन छिन हो गया।<sup>३</sup>

दक्षिण अफ्रीका की स्थिति की भारतवासियों के मस्तिष्क में प्रतिबिम्बित हुई। एक ओर तो महात्मा गांधी और उनके साथियों के साहसपूर्ण विरोध के लिए प्रशंसानाथ था, सत्याग्रहियों की महायत्ना के लिए सार्वजनिक चन्दे किये गये और देश के विभिन्न भागों में सहायता और सहानुभूति के लिए सभाएँ की गईं। दूसरी ओर भारतवासियों के माथ जो व्यवहार किया जाता था उसके प्रति रोष था। भारतवासियों की दृष्टि में गृह-सरकार और दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों की सरकारों में कोई भेद नहीं था। सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर मढ़ा गया और इस प्रकार देश में ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं में बहुत बड़ी वृद्धि हुई।

६

बीमवी शानाजी के आरम्भिक वर्षों में देश में जो नया जीवन दिखाई दिया उसके कुछ कारणों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त और भी कारण थे—स्कूलों और कॉलेजों का प्रभाव; कांग्रेस और भारतीय पत्रों के कई

१. Thompson The Reconstruction of India, page 76.

२. मिस्टर गांधी—जो उस समय इसी नाम से परिचित थे—आरम्भ में एक मुकदमे में १८९३ में दक्षिण अफ्रीका गये थे। नेटाल में भारतीयों की दशा देखकर उन्होंने बड़ी बसने का निश्चय किया। दरबन के पास उन्होंने एक बस्ती बसाई। वहाँ के निवासियों के लिए सरल और प्राथमिक जीवन का आदर्श था। वहीं गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धान्त का पहली बार प्रवर्तित किया।

३. Kohu History of Nationalism in the East, page 401.

दशान्दियों के आन्दोलन का प्रभाव; स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और श्रीमती एनी बेसेन्ट के महान् एवं धार्मिक व्यक्तित्वों का प्रभाव, और आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सियोमोंफिकल सोसाइटी तथा भारत सेवक समिति (Servant of India Society) आदि संस्थाओं के कार्यों का प्रभाव। वस्तुतः उस समय भारत में अनेकानेकी पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था। कला के नये केन्द्र खोले जा रहे थे, बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कवियों और द्रष्टाओं द्वारा भारतीय भाषाओं की सम्पन्नता बढ़ रही थी, तिलक और भडारकर जैसे व्यक्तियों के अनुसंधानों के फलस्वरूप ज्ञान की सीमाएँ बढ़ रही थी, भारतीय संगीत, प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व हो रहा था। पश्चिमी वस्तुओं और पश्चिमी पोशाक के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी रहन-सहन से विकर्षण हुआ। भारतीय वस्तुओं और भारतीय विचारधारा के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ। विदेशी सें भी स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की नई भावना दिखाई पड़ी। वस्तुतः १९०५ के राष्ट्रीय आन्दोलन को देश के धार्मिक पुनरुत्थान से प्रेरणा मिली। तिलक, अरविन्द, बारीन्द्र घोष, बिपिन चन्द्र पाल और राजपनराय—ये सब महत्वपूर्ण नेता धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थे। अरविन्द घोष इस युग की भावनाओं का और इस युग की विचारधारा का मूर्तमान स्वरूप थे। वे राजनीतिक जीवन में तीर की तरह आये और उसी बेग से लुप्त भी हो गये। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता, किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा भौतिक सुधार के किसी साधन से कही बड़ी चीज थी। उनकी दृष्टि में उसके चारों ओर एक ऐसा तेज पृष्ठ था जो मध्यकालीन सन्तों की दृष्टि में धर्म पर बलि हो जाने वालों के चारों ओर होता था।<sup>१</sup>

७

सन् १९०५ में नये राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस के तृण वर्ग को राजनीतिक मिश्रावृत्ति में आस्था मिट चुकी थी। लॉर्ड कर्जन के आधीन भारत सरकार की नीति ने कांग्रेस के स्वर की अवहेलना की और शिक्षित वर्ग को निरन्तर अपमानित किया तथा इस प्रकार कृष्ण राष्ट्रवादियों को उग्रवादी बना दिया। इन लोगों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं रहा था। ये लोग इस निश्चय पर पहुँचे थे कि प्रार्थनाभजनों द्वारा कुछ प्राप्त करना असम्भव है। इन लोगों की दृष्टि में विदेशी राज्य स्वयं अपमानजनक था। उनकी आत्म निर्भर स्वयम्भू कार्य में विश्वास था किन्तु अंग्रेजों

की उदारता और परोपकारिता से उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं थी। उन्होंने अपना वापस-वन निश्चित किया—विदेशी वस्तुओं का, विदेशी-सत्त्वों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और राष्ट्रीय सत्त्वों की स्थापना।

८

१९०५ में दहे दिना पर बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के समय नई भावना ने अपने आपका व्यक्त किया। मन् १९०४ के अधिवेशन का समापनित्व सर हर्नर बॉटन ने किया था। उन अधिवेशन में सर बॉटन के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल नियुक्त किया गया था और उसे वापस-रोप के समस्त अधिवेशन के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। किन्तु लॉर्ड कर्जन ने उस शिष्टमंडल से मिलना अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की अवहेलना की। फलतः यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश जनता को भारतवासियों के कष्टों से परिचित कराने के लिए श्री गोखले और लाया लाजपत राय का एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा जाय।

पुराने कांग्रेसियों का भारत के ब्रिटिश शासकों की स्थापनिका में से विरक्त उठ गया था किन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश जनता की धान्तरिक स्थापनिका में उनका विश्वास अब भी बना हुआ था। बारम्ब से ही उन्होंने इंग्लैंड में कांग्रेस के काम पर धोर दिया था। सन् १८८९ में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना हुई थी और उनके निर्वाह के लिए ४५००० रु स्वीकार किये गए थे। १८९१ में एक ब्रिटिश पार्लियामेण्टरी कमेटी का संगठन किया गया था। इस कमेटी की हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त करने का काम सौंपा गया था। पार्लियामेण्ट के सदस्यों और ब्रिटिश जनता को सही सूचना देने के लिए 'इंडिया' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। ब्रिटिश जनमत को शिक्षित और प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने मध्य-मय पर प्रमुख भारतीयों के शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजे थे। पहले शिष्टमंडल को मुले दनाय बनर्जी के आधीन १८८९ में इंग्लैंड भेजा गया था। दूसरा शिष्टमंडल १८९० में इंग्लैंड गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है एक शिष्टमंडल १९०५ में भेजा गया। किन्तु उसके सदस्यों की—और कम से कम एक सदस्य को तो निश्चय ही बड़ी निराशा हुई। ब्रिटिश जनता अपने निजी विषयों में व्यस्त व्यस्त थी; ब्रिटिश समाचार-पत्र भारतीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं थे और भारतीय समसत्ताओं को लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन था। लाया लाजपत राय ने बनारस अधिवेशन में अपने देशवासियों से कहा कि स्वतन्त्रता पाने के लिए उन्हें केवल अपने आप पर ही मरोका करना होगा।

इस मदेश का बनारस अधिवेशन के तरुण वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ा। उस समय तक बंगाल का विभाजन हो चुका था और विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार का आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। विषय समिति में महत्वपूर्ण मतभेद थे किन्तु पुराने राष्ट्रवादियों के झुक जाने से समझौता होगया। कांग्रेस शिविर में तरुण प्रतिनिधियों ने एक खुला सम्मेलन किया और एक नया राष्ट्रीय दल बनाया। इस दल ने कांग्रेस के अन्तर्गत रहना निश्चित किया और निष्क्रिय विरोध एवं राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के कार्यक्रम को अपनाया।

सन् १८९२ के बाद कांग्रेस ने फिर १९०५ में पहली बार राजनीतिक मुद्दों की माँग की। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय प्रतिनिधित्व देने के लिये माँग की गई और साथ ही वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद् और बम्बई तथा मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीयों को नियुक्त करने के लिये माँग की गई।<sup>१</sup>

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में १९०६ की कांग्रेस का विशेष महत्व है। इस अधिवेशन पर सभापति दादामाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की। नरम दल के कांग्रेसियों ने मुख्यतः तिलक<sup>२</sup> को सभापति न बनने देने के उद्देश्य से ८२ वर्ष के बूढ़े दादामाई नौरोजी को इंग्लैंड से विशेष रूप से बुलाया था। कांग्रेस में विच्छेद का भय था किन्तु दादामाई के कौशल ने और साथ ही जनमत ने स्थिति को बचा दिया। इस जनमत के कारण नरम दल के कांग्रेसी, उग्र दल के बहुत निवृत्त आ गये थे। नरम दल वालों के अनुसार बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा-सबधी स्वीकृत प्रस्ताव, आवश्यकता में कहीं अधिक कठोर थे। अतः अगले वर्ष सूरत में उन्होंने इन प्रस्तावों में सन्शोधन करने का प्रयत्न किया और वस्तुतः इसी प्रयत्न के कारण कांग्रेस में फूट पड़ी। सन् १९०७ में बड़े दिनों पर सूरत कांग्रेस की फूट के लिये कौन उत्तरदायी है यहाँ पर इस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों दलों में गंभीर मतभेद था और केवल शब्द परिवर्तन से वह मतभेद दूर नहीं हो सकता था। दोनों दल अपनी बात पर दृढ़ थे। एक को अपने बहुमत पर विश्वास था और दूसरे दल को अपने भविष्य और सार्वजनिक समर्थन पर विश्वास था। ऐसी परिस्थिति में फूट अनिवार्य थी। समझौते के लिए सारे प्रयत्न असफल रहे<sup>३</sup> और १९०७ में २७ दिसम्बर को उपद्रव और अव्यवस्था के अत्यन्त खेदपूर्ण वातावरण में अधिवेशन विच्छिन्न हो गया।

१ सन् १९०५ के अधिवेशन का प्रस्ताव न० २ Besant How India Wrought for Freedom, pages 432 and 433

२ Athalye - Life of Lokmanya Tilak, page 151

३ २७ दिसम्बर को सभापति ने निर्वाचन के बाद अपना आसन ग्रहण किया। तब

नरम दली नेताओं ने दूसरे दिन २८ दिसम्बर को कांग्रेस पडाल में पुलिस के संरक्षण में एक सम्मेलन किया। कुल १६०० प्रतिनिधियों में से इस सम्मेलन में १००० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनमें लाला लाजपत राय भी थे। लगभग १०० प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की एक कमेटी बनाई गई जिसे कांग्रेस का विधान तैयार करने का काम सौंपा गया। यह विधान १९०८ में तैयार हुआ। इसमें कांग्रेस कार्य के लिये पुरानी पद्धति और परम्परा को पुष्टि की गई और वैधानिक साधनों—वर्तमान शासन व्यवस्था में त्रमबद्ध सुधारों—द्वारा स्वराज्य प्राप्ति का पथ प्रकट किया गया।

इस पुनर्स्थापित कांग्रेस ने १९०८ के बड़े दिन के अवसर पर डा० रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में मद्रास में अपना अधिवेशन किया और इसमें ६०६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कांग्रेस, प्रचलित ढंग पर काम करती रही। प्रतिवर्ष बड़े दिन के अवसर पर वह देश के किसी महत्वपूर्ण नगर में अपना सम्मेलन करती थी और राजनीतिक सुधार के लिए तथा लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा ठीक करने के लिये अपनी मांग प्रस्तुत करती थी।

लोचमान्य तिलक एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को मंडे हुए। उसके लिये नियमानुसार एक दिन पहले सूचना दी जा चुकी थी परन्तु सभापति ने आज्ञा प्रदान नहीं की। तिलक मंच से नहीं हटे। नरम दल वालों ने उन्हें वहाँ से नीचे लीबना चाहा। उसी समय एक भराठी जूता मंच की ओर फेंका गया जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और कीरोजनाथ मेहता के लगा। कुछ ही बेर में बहुत से आदमी लाठियाँ लिये हुए दौड़ पड़े और वे जिस किसी को नरम दली होने का सन्देह करते, उसी को मारते। “भारतीय महिलाएँ पडाल से बाहर खिसक गईं, मंच के नेता भी खिसक गये—तिलक को उनके अनुयायी ले गये—किन्तु पडाल में बड़ा उपद्रव हुआ—कुसियाँ फेंक कर मारी गईं, लाठियाँ चली और बहुत से सिर फूट गये।” अन्त में पुलिस ने आकर पडाल को खाली करा दिया।

Nevinson : The New Spirit in India, pages 256-259

पर हस्ताक्षर करने की अपील की। इसी दंग की सभाएँ बंगाल में अन्य स्थानों पर हुई। उनमें स्वदेशी के प्रयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रस्ताव स्वीकार किये गए और बहिष्कार सबंधी प्रतिज्ञा की गई।<sup>१</sup>

इस आन्दोलन के होने हुए भी १६ अक्टूबर को विभाजन कर दिया गया। उस दिन सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया। बलकृष्ण के कार्यक्रम में चार बातें मुख्य थी - (१) राखी बघन-विभाजित प्रान्तों की एकता के प्रतीक स्वरूप पुरुषों की कलाइयों में लाल धागे बांधे गए, (२) हडताल और उपवास, (३) पेरिस के एक भवन (Hotel des Invalides) के नमूने पर एक 'फेड-रेशन हॉल' का चित्रात्मक। इस भवन में बंगाल के सब जिलों की मूर्तियाँ रखी जानी थी। पृथक् किये हुए जिलों की मूर्तियों को, फिर एक होने के दिन तक<sup>२</sup> ढका रखा था। और (४) बुनकर-उद्योग की महायत्ता के उद्देश्य से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना। इसके लिए सायकाल को एक सार्वजनिक सभा हुई और ७०००० रुपये तो सभास्थल में ही एकत्रित हो गए।

विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल और आसाम का नया प्रान्त बना। इस प्रान्त की राजधानी ढाका में बनाई गई और उसके लिए सर बैमफील्ड फुलर को उप गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। किन्तु आन्दोलन यथापूर्व गति से चलता रहा। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विधिवन्धु पाल जैसे नेताओं ने सारे नये प्रान्त का परिभ्रमण किया, विराट सभाओं में भाषण दिया और उपस्थित सबों से स्वदेशी और बहिष्कार की धपस ग्रहण कराई। राष्ट्रीय पत्रों द्वारा प्रबल प्रचार किया गया। बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी आन्दोलन फैल गया। सन् १९०५ के कांग्रेस अधिवेशन ने राजनीतिक बहिष्कार और आर्थिक स्वदेशी, दोनों बातों के लिए स्वीकृति दी। सन् १९०६ में इस स्वीकृति की और भी प्रबल भाषा में पृष्ठि की गई। दोनों आन्दोलनों की काफी सफलता मिली। इंग्लैंड से सूती और अन्य माल का आयात घट गया और भारत के बुनकर-उद्योग को और अन्य धंधों को बड़ा प्रोत्साहन मिला।<sup>३</sup> स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में ये आन्दोलन विशेष रूप

का प्रय नहीं करूंगा। ईश्वर शक्ति दे।" Bannerjee A Nation in the Making, pages 189-191

१ २० जुलाई और २६ अक्टूबर के बीच बंगाल में लगभग २००० सभाएँ हुईं।

२ Bannerjee उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१३.

३ पूर्वी बंगाल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार १९०५-०६ में बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनीं और विदेशी आयात में १६ प्रतिशत कमी हुई। १९०७ की मई में लन्दन के टाइम्स के अनुसार मैनचेस्टर से सूती वस्त्रों के आयात में

किया और सम्मेलन को भग कर दिया। सारे देश में इस पर विरोध समाएँ हुई।<sup>१</sup> कलकत्ते की एक सभा में राय नरेन्द्र नाथ सेन ने कहा कि इस दमन का एकमात्र परिणाम यह होगा कि नवयुवक अराजकतावादी हो जाएँगे। मद्रास की एक सभा में भारत मन्त्री से यह प्रार्थना की गई कि वे हस्तक्षेप करे और इस घटना से संबंधित अधिकारियों को दंड दें।<sup>२</sup>

किंतु पूर्वी बंगाल की सरकार ने अपना डर नहीं बदला। उसने केवल दमन की नीति को ही जारी नहीं रखा बल्कि जनता में फूट डालने और मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति को भी आगे बढ़ाया। मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और विभाजन विरोधी आन्दोलन में हिन्दुओं को प्रयत्न करने के लिये सर बेंफ़ील्ड ने हर प्रकार के उपायों का उपयोग किया। ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने आरम्भ में विभाजन को "पाशाविक व्यवस्था" बताया। उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे १ लाख पौण्ड का ऋण दिया गया। "बहुत से सरकारी पदों को मुसलमानों के लिये सुरक्षित रखा गया और कुछ स्थानों को उपयुक्त मुसलमान न मिलने पर रिक्त रखा गया।"<sup>३</sup> अधिकारियों की छेड़छाड़ तो केवल हिन्दुओं के ही लिए थी। उन्हें सरकारी पदों से दूर रखा गया। हिन्दू स्कूलों की सरकारी अनुमति और सहायता से वंचित किया गया। जब मुसलमान उपद्रव करते थे तो पुलिस अल्पाधिकारियों को दंड देने के लिये हिन्दू घरों पर छापा मारती थी। हिन्दू वस्तियों में गुरावा सैनिकों को सुरक्षा के लिये नियुक्त किया गया।<sup>४</sup> उप-गवर्नर ने इस बात की हसी करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया कि उनको अपनी दो परियों में मुस्लिम पत्नी अधिक प्रिय थी। "मुसलमानों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश अधिकारी उनके सब अत्याचारों को क्षमा कर देंगे।" मुसलमान मौलवी चारों ओर यह कहते फिरते थे कि हिन्दुओं के प्रति हिंसा करने के बदले में अथवा हिन्दुओं की दुकानें लूटने और हिन्दू विधवाओं को भगाने के बदले में मुसलमानों को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। एक लाख पुस्तिका प्रकाशित की गईं उनमें इन्हीं बातों का प्रतिपादन किया गया था।<sup>५</sup> कामिला, जमालपुर और ढाका आदि कई स्थानों में उपद्रव आरम्भ हो गए। ढाका में तीन दिन और तीन रात तक मुस्लिम उपद्रवियों का आधिपत्य रहा और उन्होंने घनी मारवाड़ी रत्नकारों को जी भरकर लूटा।<sup>६</sup>

१. Bannerji : A Nation in the Making, page 219

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३२

३. Nevinson The New Spirit in India, page 192

४. Nevinson 'The New Spirit in India, page 202

५. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९१

६. Mazumdar : Indian National Evolution, page 235



पिछले अध्याय में नये राष्ट्रीय दल, उसके सिद्धान्तों और उसके कार्यक्रम का उल्लेख किया जा चुका है।<sup>१</sup> इस समय भारत में विवेकानन्द के महान व्यक्तित्व की प्रेरणा में बहुत बड़ा हिन्दू पुनरुत्थान हो रहा था। इन दोनों (नये राष्ट्रीय, और हिन्दू पुनरुत्थान) आन्दोलनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और यह बात बंगाल में विशेष रूप से प्रकट हुई। जैसा कि सर बेल्लेष्टाइन शिरोल ने कहा है—  
 "इन नयी राष्ट्रीयता के मूढ़ घोष 'स्वदेशी' और 'स्वराज्य' हैं और उनका अर्थ केवल आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। उनका अर्थ विदेशी जाति, और विदेशी सभ्यता के आदर्शों के स्थान पर सामाजिक धार्मिक बौद्धिक और नैतिक क्षम में पुरानी हिन्दू परम्पराओं का समूह उत्थान करना है। इस विचार-धारा के कुछ प्रतिपादकों की हार्दिक सच्चाई के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। अरविन्द घोष की भाँति उनको यह दृढ़ विश्वास है कि 'देश की सारी नैतिक शक्ति हमारे साथ है' न्याय हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है और ईश्वरीय नियम जो सर्वोपरि है वह भी हमारे कार्य का न्याय्य ठहराता है।<sup>२</sup> बिपिन चन्द्र पाल लिखते हैं — भारत में राष्ट्रीय चेतना और आकांक्षा की पुनर्जागरण के कारण शक्ति उपासना के प्राचीन आदर्शों का पुनरुत्थान हुआ है। दुर्गा, काली, जगद्धात्री और भवानी आदि शक्ति की विभिन्न प्रतिमाओं का नया अर्थ दिया गया है। ये प्राचीन देवी और देवता आधुनिक मस्तिष्क में पुनः प्रतिष्ठित किये गये हैं और उनकी एक नयी ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय व्याख्या भारत की आत्मा और मस्तिष्क के समक्ष रखी गई है।"<sup>३</sup>

लोगों के मस्तिष्क पर, विशेषकर बंगाल के तत्पश्चात्तरूप पर इस नये राष्ट्रीय दल के नानाओं का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। सन् १९०६-१९०८ में इस दल की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और उसके प्रभाव ने बहिष्कार तथा स्वदेशी के आन्दोलनों को बहुत सहायता दी। इस दल के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षण सत्रायें चलाई गईं। कलकत्ता में एक कालेज चलाया गया। अरविन्द घोष इसके प्रिन्सिपल थे। मज और नर, दोनों के द्वारा दल जोरों पर प्रचार कर रहा था। बिपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष ने अपने मुख पत्र—'न्यू इण्डिया' तथा 'बन्धे मातरम्'—द्वारा प्रचल और प्रभावशाली भाषा में स्वतन्त्र भारत का आदर्श प्रस्तुत किया और धार्मिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों की व्याख्या की। बिपिन चन्द्र पाल के अनुसार डोमोनियन स्टेट्स

१ इसी पुस्तक का बारहवा अध्याय देखिये।

२ Chrool Indian Unrest, page 12.

३ B. C. Pal The Soul of India, pages 186-187.

स्वतन्त्रता के आदर्श को फैलाने का प्रयत्न किया था। सन् १९०५ में वे बंगाल छोड़ कर आये और उस समय तक उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि देश में विशुद्ध राजनीतिक प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होगा और सकटों का सामना करने के लिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण द्वारा ही समर्थ बनाया जा सकता है। उन्होंने 'युगान्तर' नामक पत्र चलाया और उसके द्वारा सर्वसाधारण में राजनीतिक एवं धार्मिक प्रचार किया। उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए १४-१५ नवम्बर कार्यक्रमों को तैयार किया। "हमारी दृष्टि मुद्गर भविष्य में कालि पर अभी हुई है और हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं"।<sup>१</sup>

बारीन्द्र घोष ने एक निबन्ध लिखा जिसके शीर्षक का भाव था 'भारत में गीता के उग का पुनरागमन'। इस लेख द्वारा उन्होंने अपने क्रान्तिकारी विचारों को समझाया। "श्रीकृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर-वचन होगा"। "वर्तमान परिस्थितियों में धर्म का हास और अधर्म का अभ्युदय श्रद्धागोबर हो रहा है। मुझी भर विदेशी लुटेरे करोड़ों भारतवासियों को बरबाद कर रहे हैं और भारत की संपत्ति को लूट रहे हैं। इस दासता के चक्र में अनगिनती लोगों को पसलियाँ चूर चूर हो गई हैं। भारतवासियों, डरो नहीं। ईश्वर निष्क्रिय नहीं रहेगा। वह अपने बचन का पालन करेगा। ईश्वर के शब्दों में दृढ़ विश्वास रख कर ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करो। हृदय में दिव्य ज्योति आने पर मनुष्य अमम्वव कार्य भी कर सकते हैं।"<sup>२</sup>

उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्यक्रम में ६ बातें बताई गईं। पहली बात तो यह थी कि पन्नों की सहायता से प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में दासता के प्रति नृणा जाग्रत कर दी जावे। दूसरी बात यह थी कि लोगों के मस्तिष्क से बेकारी और भूल का डर दूर कर दिया जावे और उनमें मातृभूमि और स्वतन्त्रता का प्रेम भर दिया जावे। इसके लिए संगीत और नाट्यकला को साधन बनाया गया। राष्ट्रीय वीरो और सहोदों के जीवन चरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के लिए कहा गया और साथ ही देश भक्ति से ओत प्रोत गानों को हृदयस्पर्शी सगुन द्वारा लोगों तक पहुँचाने के लिए कहा गया।<sup>३</sup> तीसरी बात यह थी कि शत्रु को प्रदर्शनों और आन्दोलन—वेन्देमातरम् जलूस, स्वदेशी सम्मेलन, बहिष्कार

१. सन् १९०८ को २२ मई का एक मजिस्ट्रेट के सामने बारीन्द्र घोष का वक्तव्य  
—Sedition Committee Report, 1918, page 20.

२. Chitrol - Indian Unrest, pages 90 and 91.

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ९३।

बंगाल में स्मृतिकारी अपराधों का इतिहास, उपर्युक्त दोनों घटनाओं से आरम्भ होता है। किन्तु आन्दोलन के आरम्भिक दिनों में ही एक और घटना हुई और उसके फलस्वरूप इंग्लैंड और भारत में बड़ा उद्वेग हुआ। स्मृतिकारी दल ने, मुजफ्फरपुर (बिहार) के जज मि. किम्सफोर्ड की हत्या करने का काम, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक अपने दो सदस्यों को सौंपा था। बिहार आने से पहले मि. किम्सफोर्ड कलकत्ता के मुख्य प्रसीडन्सी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन के कार्यक्रमों को कठोर दृष्टि दी थी। और इसके कारण वे अत्यन्त अप्रिय के नयमुक्तों को शारीरिक दण्ड दिया था।<sup>१</sup> और इसके कारण वे अत्यन्त अप्रिय हो गये थे। स्मृतिकारी दल ने उनकी हत्या करने का निश्चय किया। पहले तो उन्होंने एक बट विलक्षण उपाय में काम लिया। उन्होंने मि. किम्सफोर्ड से मांगी किसी पुस्तक को हथिया लिया। तदुपरान्त उन लोगों ने पुस्तक के पृष्ठों को बीच में से काट लिया और रिक्त स्थान में एक बम रख दिया और उसमें एक त्रिप्रण लगा दी ताकि पुस्तक खोलने पर बम का विस्फोट हो जावे। पुस्तक को पार्सल से मि. किम्सफोर्ड के पास भेज दिया गया किन्तु तुरन्त आवश्यकता न होने के कारण उन्होंने उस पार्सल को नहीं खोला। कुछ महीने बाद किसी स्मृतिकारी से यह भद प्रकट हो गया। इस उपाय का असफल हो जान पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को हत्या के लिए नियुक्त किया गया और वे बम लेकर मुजफ्फरपुर गये। मि. किम्सफोर्ड के बगले को ओर से एक गाड़ी आ रही थी और इन लोगों ने यह समझकर कि उसमें अत्यन्त अप्रिय मि. किम्सफोर्ड होंगे, उस बम को गाड़ी पर फेंक दिया। किन्तु उस गाड़ी में मिसेज कैनेडी और मि. कैनेडी नामक दो अग्रज महिलाएँ थी और उस बम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सन् १९०८ की ३० अप्रैल को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दो दिन बाद अपराधी पकड़े गये—प्रफुल्ल चाकी ने तुरन्त गोली मार कर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया। उसने हत्या का आरोप स्वीकार किया और उसको फाँसी दी गई। सर बैलेन्टाइन शिरोक लिखते हैं—“इस प्रकार वह बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिये राष्ट्रीय वीर और शहीद हो गया। विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों ने उसके लिये शोक की पोशाक पहनी, दो तीन दिन के लिये स्कूल बन्द कर दिये गये और उनकी स्मृति में श्रद्धाञ्जलियाँ

१ मुशील सेन नामक १५ वर्षीय विद्यार्थी को बेत से मारा गया। इस घटना से देश में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। Bannerjee A Nation in Making, page 248. इसके अतिरिक्त देखिये P. C Roy Life and Times of C. R. Das, page 51.

डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मि दमसुल आलम को गोली से मार दिया गया। यह पुलिस अधिकारी अलीपुर अभियोग के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ था।

क्रान्तिकारी दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये बड़ी कठोरता से काम लिया जाता था। किमी पर विश्वासघात का सन्देह होने पर उसे बड़ी निष्ठुरता से दण्ड दिया जाता था। नवम्बर १९०८ में तीन विश्वासघातियों को गोली से मार दिया गया। क्रान्तिकारी दल, पुलिस अधिकारियों को, अभियोग निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों को, सरकारी बकीला को और सरकारी गवाहा को आतंकित करने के लिये बड़ी दृढ़ता और निर्भयता से काम करता था। कितनी ही हत्याएँ और ठकैतियाँ हुईं। दमनकारी कानून, कठोर दण्ड, अथवा १९०९ और बाद में १९१९ के सुधार भी इन लोगों को उनके निश्चित मार्ग से विचलित नहीं कर सके। सन् १९०८ और १९०९ के विचाराधीन युग में हत्याआ और ठकैतियाँ की संख्या बढ़ती ही गई।<sup>१</sup> सन् १९०८ में ७ नवम्बर को बमाल के उप-मगवर सर एण्ड्रुऊ फ्रेजर की हत्या करने का प्रयत्न किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली। गोली मारने वाला पकड़ा गया उस पर अभियोग चला और उसे १० वर्ष के लिये कठोर कारावास दंड दिया गया।

५

सन् १९०६ से १९१० तक के वर्षों में क्रान्तिकारी केवल बंगाल में ही सक्रिय नहीं थे बल्कि वे भारत के अन्य प्रान्तों में और विदेशों में भी काम कर रहे थे। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है क्रान्तिकारी आन्दोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उसके फलस्वरूप मि० रैण्ड और लेफ्टिनेण्ट ऐम्स्टर्ड की हत्याएँ हुई थीं। इनके अनिरुक्त दामोदर चपेकर की गिरफ्तारी और दोष-सिद्धि के लिये सूचना देने वाले दो माइया की भी हत्या की गई थी। सन् १८९९ के बाद दक्षिण में प्रकटत पूर्ण शान्ति थी किन्तु क्रान्तिकारी काम को फिर आरम्भ करने के लिये महाराष्ट्र और लन्दन में भुक्त रूत से तयारिया हो रही थी। इस आन्दोलन के नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर बन्धु—गणेश और विनायक सावरकर।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा रैण्ड हत्या से किसी प्रकार संबंधित थे और वे चुनचाप इंग्लैंड सिखाए आये। सन् १९०५ तक तो बंदिबे हुए से रहे किन्तु उस वर्ष की जनवरी में उन्होंने लन्दन में इंडियन होम रुल सोसाइटी बनाई और एक पेंस का इंडियन सोशियोजोर्जिस्ट नामक मासिक पत्र निकाला। मिस्टर एस आर राना नामक एक सज्जन पेरिस में बस गये थे। उनके सहयोग में श्यामजी

१ विस्तृत वर्णन के लिये पढ़िये, Sedition Committee Report,

इस अवसर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दो सन्देश पत्र भेजे । एक सन्देश के शीर्षक में शहीदों का समर्पित किया गया था और दूसरे सन्देश में गम्भीर चेतावनी दी गई थी । इन सन्देशों को बिद्रोह दिवस की समारोह में पढ़ा गया और आग बुझाने में उनका वितरण किया गया और उनसे इन सन्देश पत्रों को पृथक् रूप में भारत भ्रमण की प्रार्थना की गई । जन १९०८ में इंडिया हाउस में एक व्याख्यान दिया गया । इस व्याख्यान में वम के प्रयोग को न्याय्य ठहराया गया और उन्हें बनाने की प्रशंसा बताई गई । लगभग इसी समय इंडिया हाउस के सदस्य रिवांस्वर से निराना व्याख्यान का अभ्यास भी करना लगा ।

धीरे धीरे इंडिया हाउस के सदस्य विनायक सावरकर के नेतृत्व को मानने लगे । सावरकर ने भारत में क्रान्तिकारी काम की तैयारियों को भी आगे बढ़ाया । फरवरी १९०९ में उसने २० नवीनतम प्रकार की पिस्तौलों का पासल बम्बई भेजा । इस पासल के साथ पिस्तौलों के कारतूस भी थे । इन चीजों को एक बक्स के झूठे तले के नीचे छिपा दिया गया था और इस बक्स का इंडिया हाउस के एक चतुर्भुज अमीन नामक रमोदय के मामान के साथ पासल किया गया था ।<sup>१</sup> ये पिस्तौलें अभिनव भारत समिति के सदस्यों के काम में आनी थी । यह समिति विनायक के बड़े भाई गणेश के नेतृत्व में काम कर रही थी । किन्तु पासल के भारत पहुँचने से पहले ही गणेश सावरकर को २ मार्च १९०९ को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया । पासल एक मित्र के नाम था जिस पहले ही फोन लिया गया था ।

गणेश सावरकर ने विरुद्ध यह आक्षेप था कि उन्होंने लघु अभिनव भारत मेला नामक धापक के अंतर्गत १९०८ के आरम्भ में भंडकान वाले कविताज्ञा का एक सकलन प्रकाशित किया था । अभियाग का अंतिम निणय बम्बई के उच्च न्यायालय ने किया । उसने जज के शब्दों में इस सकलन से इस बात का प्रचार होता था कि 'सत्कार हाथ में लो और सरकार को मित्र दो क्योंकि वह विदेशी और असाधारणी है' ।<sup>२</sup> ९ जून १९०९ को गणेश सावरकर को आजीवन देश निर्वासन का दंड मिला । विनायक को समुद्री तार द्वारा दंड की सूचना दी गई । रविवार २० जून को समिति की बैठक में विनायक विनाश रूप में उग्र था और उसने अप्रहो में बदला लेने की अपनी शपथ को दोहराया ।<sup>३</sup>

वर्गाल सर्वोच्च समाचारों ने भी इंडिया हाउस के सदस्यों को उत्तजित किया ।

१ Sedition Committee Report page 9

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९

राष्ट्र भी एक ही स्थान से प्राप्त होते थे तथापि एक समुदाय के सदस्य दूसरे समुदाय के सदस्यों से विलुल अपरिचित थे। गणेश सावरकर के हाथों में उनका नेतृत्व था और विनायक सावरकर उनका मित्र, प्रेरक और निर्देशक था। वह लन्दन से, टाइप की हुई प्रतियाँ बग बनाने के लिये हिदायत देता था और उनके लिये नातिकारी साहित्य भेजता था। वह विदेशों से रास्त्र भेजना था और उन्हें आतकपूर्ण कामों के लिये प्रेरित करता था।

निकट के देशों राज्या में भी अभिनव भारत समिति की उप शाखाएँ थी। ग्वालियर में एक नव भारत समिति थी। इसके २२ सदस्या पर सम्राट् के विरुद्ध युद्ध संगठित करने के अपराध में अभियोग चलाया गया। ग्वालियर पड्यत्र केस के इन अभियुक्ताओं को विभिन्न अवधियों के लिये कारावास दंड दिया गया।

अभिनव समिति की एक शाखा १९०७ से सतारा में काम कर रही थी। सन् १९१० में उसके तीन सदस्या पर सम्राट् के विरुद्ध पड्यत्र का परिचित आक्षेप लगाया गया। सतारा पड्यत्र केस के सभी अभियुक्तों का अपराध सिद्ध हुआ और उन्हें कारावास दंड दिया गया।

नातिकारी आन्दोलन, पश्चिमी भारत के विभिन्न भागों में फैल गया था। नातिकारियों के प्रभाव से गुजरात भी नहीं बचा था। नवम्बर १९०९ में अहमदाबाद में लॉर्ड और लेडी मिटो जिस गाडी में शहर में घूम रहे थे, उन्हें उठाने का प्रयत्न किया गया। दो नारियल बग फेंके गए पर वे फटे नहीं। बाद में उनमें से एक बग को कौतूहलवश एक पथिक ने उठाया और बिस्फोट के कारण उसका एक हाथ उड़ गया।

६

सन् १९०६ से १९१० तक के वर्षों में दक्षिण के नातिकारियों का काम उपर्युक्त रूप से चल रहा था। मद्रास प्रान्त भी सक्रिय था। अप्रैल १९०७ में बिपिन चन्द्र पाल ने व्याख्यान देने के उद्देश्य से मद्रास का परिभ्रमण किया था और स्वराज्य के आदर्श को प्रस्तुत करके नवयुवकों के मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया था। अरविन्द घोष के विरुद्ध राजद्रोह अभियोग में गवाही न देने के अपराध में बिपिन चन्द्र को अक्टूबर १९०७ में छ महीने का कारावास दंड दिया गया। मि पाल के दो मद्रासी प्रशंसकों ने १९०८ की ९ मार्च को उनके छूटने की प्रसन्नता में एक सभा की। उस सार्वजनिक सभा में स्वराज्य का झंडा फहराया गया और प्रत्येक विदेशी वस्तु के बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा की गयी। इन दोनों प्रशंसकों—मुब्रह्मण्यम् शिव और चिदम्बरम् पिलाई—को १२ मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन टिनेवली में भीषण उपद्रव हुआ। सरकारी सत्ता की अवहेलना की गई और सरकारी सम्पत्ति को जानबूझ कर नष्ट किया गया। उस नगर में सब-रजिस्ट्रार

सस्याजा में विद्यार्थी, विनापकर वगाली विद्यार्थी मुख्य कायकता थ। इनको आयरिश अमेरिकन फनियन्स का सहयोग प्राप्त था। इन की विचारधारा से अमेरिका में आकर बसने वाले अधिकांश भारतवासी प्रभावित हुए। य वह लग थ जिन्हान प्रगान्न तत् पर एशिया विरोधी आन्दोलन म कष्ट सह थ। इन में स कुछ लग सिख और पुरान सिपाही थ। यह बान कम महत्व की नही थी क्योंकि इन सैनिकों द्वारा उन संग्रह में जिन म पहले थ सैनिक काम करत थ अब सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था और कम म कम जिन वर्गों म भारतीय सना की भर्ती होती थी, उनको तो प्रभावित किया हो जा सकता था। तीन बप पूव सिपाहियों म जो पच बाट गय थ वे अमेरिका में ही छय थ।<sup>१</sup>

इसो अमेरिकन एसोसियशन मुख्यतः एक प्रचार मिति थी। इसके मुखपत्र का नाम का हिंदुस्तान था और यह नियत समय पर प्रकाशित होता था। किंतु यह इंडिया एसोसियशन का मायलैंड की जातिकारी सस्याजा के द्वय पर मगठन किया गया था और उसका मुख्य काम विम्फोर्का का अध्ययन करना और भारत को गुप्त रूप म दास्य भजना था। सर वैंग्नेनइन गिरोल के अनुसार इन दोनों सम्पाजा का भारत के विभिन्न स्थानों—दक्षिण बंगाल और पंजाब—की सस्याजा स सम्बन्ध था और उनका राजद्रोहपूर्ण समाचार पत्र और साहित्य मुद्रित और प्रकाशित करने वाला से पत्र-व्यवहार होता रहता था।

७

मन् १९०७ ८ म पंजाब का आन्दोलन वस्तुतः जातिकारी नहीं था। जैसा कि पंजाब के उप गवर्नर सर डनिजल ने उस समय कहा यह सब सच है कि १९०७ की गर्मिया में बहा की स्थिति गम्भीर थी। सारे प्रान्त में प्रबल असंतोष था और उसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में उपद्रव भी हुए। किंतु बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास की तरह पंजाब में आतंकवादी गुप्त समितियां नहीं थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन न पंजाब के विभिन्न वर्गों को अकस्मै दिया था। स्वामी दयानन्द की शिक्षा व पत्रस्वरूप हिंदू नवयुवकों में स्वतंत्रता और स्वदेशी की भावना को पनपन म सहायता मिली। भारतीय पत्र प्रबल प्रचार कर रह थ और कुछ पत्र तो वैधानिक सीमाओं को भी पार कर गय थ। उनके सम्पादकों और मुद्रकों पर अभियोग चलाया गया और उनको दंड दिया गया। आग्ल भारतीय पत्र जातीय घृणा और द्वय का प्रचार कर रह थ किंतु उनका विरुद्ध कोई भी रायवाही नहीं की गयी। लाहौर का सिविल और मिलिटरी मज्ज इन पत्रों का अग्रणी था।

१ Chitrol Indian Unrest, page 147

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १४७

वह निश्चित वर्गों के विरुद्ध उन्मूलन जेब लिखना था और उन्हें तरह-तरह की मारपीट देना था। उसने विद्रोह के मकड़ का हन्ना मचाया। उसमें बहा तब बहा गया कि विद्रोह की पचासवीं वर्ष गाठ पर (१० मई १९०३ को) अंग्रेजों के विरुद्ध नया व्युत्पान हागा। इस नूतन प्रचार पर विद्वान् किया गया और पत्राव के बर्दशहरों में अंग्रेजों की रक्षा के लिये प्रवन्ध किया गया और अग्रज निवासियों की किशोरों में रहने के लिये जगह दी गई। नविल्लिन ने लिखा है—“किन्तु इस भविष्यवाणी के होते हुए भी बर्द व्युत्पान नहीं हुआ।”<sup>१</sup>

किन्तु मई १९०३-०४ में पत्राव की स्थिति बड़ी गम्भीर हुई और इसके बर्दशारा थे। एक बार ना आरम्भ-भागीय पत्र भारत-विरोधी प्रचार चले जाँचों से कर रहे थे दूसरी ओर बंगाल का राष्ट्रीय आन्दोलन उमड़ रहा था। इसी समय जेब और अकाल का दौड़ा काय हुआ और सरकारी व विवेक-शून्य भूमि विषयक नीति अपना कर स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। अप्रैल १९०३ में ‘इटिया’ और ‘पत्रावी’ नामक दो भारतीय पत्रों पर अभियोग चलाया गया। ‘इटिया’ के मालिक और सम्पादन की पाब बर्ष का कारावास दंड दिया गया और मुद्रक को एक राजद्रोह-पूर्ण पत्र छापने के अपराध में दो बर्ष का कारावास दिया गया। यह पत्र अमरीका से आया था और इसमें भारतीय सेना की मडकाया गया था।<sup>२</sup> ‘पत्रावी’ ने एक बंगाल के मामले में सम्पादकीय बालोचना की थी। एक सरकारी अधिकारी ने दो गांव वाला से बलान् काम कराया था और बंगाल के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। अगस्त १९०३ के अनुसार ‘पत्रावी’ के मालिक को ६ महीने का कारावास दंड दिया गया और उनपर १००० रुपये जुर्माना किया गया और सम्पादन को छ महीने का कारावास दंड दिया गया और उनपर २०० रुपये जुर्माना किया गया। इस अभियोग का अन्तिम निर्णय लाहौर हाई कोर्ट ने १६ अप्रैल १९०७ को सुनाया। पत्रा लगने पर बड़ी भीड़ एकत्रित हुई और वह जेल जाते हुए बन्दीयों से मिली। उसी राह और उद्देश्य के कारण अन्त में एक उपद्रव हो गया।

आरम्भ में पत्राव के अगड़े भूमि विषयक थे।<sup>३</sup> लॉर्ड मिण्टो के जीवन लेखक ने इस बात को स्वीकार किया है कि “नहर उपनिवेशों में स्थानीय सरकार ने विवेक-शून्य नीति अपनाई और इसी के कारण अगड़े हुए।”<sup>४</sup> मालगुजारी को

१. Nevinson : The New Spirit in India, page 20.

२. Nevinson : The New Spirit in India, page 18.

३. पत्राव के कारणों के लिये देखिये—Lajpat Rai : Story of my Deportation Appendix B.

४. Buchan : Lord Minto : page 256.



काफ़ी बढ़ा दिया गया सभा उपनिवेशों में विगपकर जारी दोआव क्षेत्र में सिंचाई की दर को बढ़ा दिया गया और सब से बड़ी बात यह थी कि चेन्नै उपनिवेश में फिर से प्राप्त की हुई भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में सरकार ने अपने बचन का पालन नहीं किया। पञ्जाब विधान परिषद् में एक उपनिवेश विधायक शाधना से स्वीकार किया गया और उसके द्वारा १८९३ के एक्ट की शर्तों को बदल दिया गया। इन कार्रवाहियों का प्रबल विरोध हुआ। हम आन्दोलन के नेता मि अजीतसिंह और सैयद हैदर रिज़ा थे। उन्होंने आन्दोलन चलाने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम इंडियन पेट्रियट्स एसोसियेशन था। सारे प्रान्त में विगप कर प्रभावित क्षेत्र में सभाएं की गयीं। २२ मार्च १९०७ को लाहौर में एक सभा हुई। इसमें लाला लाजपत राय को बोले के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सरकारी कार्रवाहियों की आलोचना की और उन्हें बदलते हुए असतोष के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस सभा में मि अजीत सिंह ने भी व्याख्यान दिया। एक ही सभा में दोनों नेताओं ने भाषण दिया। समस्त इसी संयोग के कारण लाला लाजपत राय और मि अजीत सिंह—दोनों ही संजनों को सन १८९८ के पुराने और कुटिल विनियम के अन्तर्गत भारत से एक साथ निर्वासित कर दिया गया।

रावलपिंडी जिले में मालगुजारी में विद्रोह रूप से वृद्धि की गई। अप्रैल १९०७ में इस अत्यधिक मालगुजारी के विरोध में दो सभाएं की गयीं। दूसरी सभा २१ अप्रैल को हुई और इसमें मि अजीतसिंह प्रमुख वक्ता थे। जब मि अजीतसिंह की भाषा वस्तुतः उग्र हो गयी तो समाध्यक्ष लाला हसराम ने उन्हें रोक दिया परन्तु कुछ ही दिनों बाद समाध्यक्ष को और साथ ही २१ अप्रैल को सभा से सम्बंधित लाला अमोलक राम और लाला गुरदास राय नामक दो प्रतिष्ठित वकीलों को यह सरकारी सूचना दी गई कि भारतीय दंड संहिता की न १२४ ए और न ५०५ धाराओं के अन्तर्गत उन पर अभियोग चलाया जावेगा और इन लोगों को २ मई को ११ बजे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। लाला लाजपत राय अपने वकील मित्रों की सहायता सहित के लिए रावलपिंडी पहुँचे। इन सब के मतानुसार सूचनापत्र अर्बुद था और उन्होंने न्यायालय में उपस्थित न होने का निश्चय किया। परन्तु उन्होंने मि अजीतसिंह और मि बोधराज नामक दो नये वरिष्ठों को अपनी ओर से कार्रवाहियों में भाग लेने के लिए अधिकार दिया। २ मई को जिलाध्यक्ष के न्यायालय के सामने बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और हड़ताल करने वाले मजदूरों के कारण यह भीड़ और भी बढ़ गई। उस दिन सरकारी तोपखाने में रेलवे बकाना में और रायबहादुर सरदार बूटासिंह के निजी कारखाने में मजदूर लोग काम पर नहीं गए। जब ग्यारह बजे पर भी जिलाध्यक्ष नहीं आया तो

## चौदहवाँ अध्याय

# दमन और सुधार

भारत को १९०५-६ की घटनाओं के कारण भारतीय शासन के दोनों नये अध्यक्ष चिन्तित हुए। नवम्बर १९०५ में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो वाइसराय हो गये थे और दिसम्बर १९०५ में प्रगतिवादों जॉन मॉर्ले भारत मन्त्री हो गये थे। ६ जून १९०६ को मि जॉन मॉर्ले (बाद में लॉर्ड मॉर्ले) ने लाइ मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लॉर्ड्स, सिरोल सिडनी को जैसे प्रमुख लेखकों के दृष्टिकोणों को ओर ध्यान आकर्षित किया। ये लोग हाल ही में भारत में प्रवास करने आये थे और इन्होंने "बड़ा एक नई भावना को बढ़ते हुए और फैलते हुए देखा था।" इन लोगों का यह मन था कि भविष्य में यथा पूर्ववत् से भारत का शासन करना असम्भव है और सरकार को कांग्रेस सत्ता और कांग्रेस सिद्धांतों के साथ व्यवहार करना होगा।<sup>१</sup> इन्हीं विचारों को भारतीय नरम दल के दूरदर्शी नेता सन् १९०५ के कांग्रेस अधिवेशन के सभापति और 'भारत सेवक समिति' के संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ी कुशलता के साथ अत्यन्त प्रभावपूर्ण ध्वजा में व्यक्त किया था। मार्च १९०६ में सम्प्रजातीय विधान परिषद में बजट सम्बन्धी अपने ध्यानाधान में श्री गोखले ने लॉर्ड मिंटो से एक सार्वजनिक अपील की। "शिक्षित वर्गों को शान्त करने की समस्या को सुलझान में ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की परीक्षा होगी। उन्हें शान्त करने का केवल यही उपाय है कि उनको अपने देश के शासन में अधिकाधिक साथ लिया जावे।" परिषद के अधिवेशन के बाद श्री गोखले इंग्लैंड गये और भारत मन्त्री से कई बार मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि मि मॉर्ले को श्री गोखले की सद्भावनाएँ प्राप्त हुईं और कुछ सामान्य सुधारों के लिये उन्हें गोखले का समर्थन भी मिला।<sup>२</sup> भारत मन्त्री और वाइसराय में परामर्श होने के बाद यह

१ Morley Recollections Vol II, pages 172-174

२ Buchan Lord Minto, page 231

३ मि मॉर्ले ने १ अगस्त १९०६ की बैठ में गोखले ने कहा "अब आपकी दिशा में युक्त सुधारों के लिये अभूतपूर्व अवसर है इसके लिये केवल एक बात कहो और वह है आपके मित्रों का विरोध से आरम्भ किसी दायित्व में नहीं बाधना पर आप प्रयत्न करें। यदि मन्त्र और पत्र द्वारा आपके साथियों ने उद्देश्य की तो सब मिट्टी में मिल जायगा।" मि गोखले ने हार्दिक सहयोग दिया और उन्होंने भारत में अपने मित्रों

निश्चय हुआ कि भारत सरकार उक्त मुद्दारे का उपक्रम करे। इस सम्बन्ध में मि. मॉले व १५ जून १९०६ के पत्रोत्तर में लॉर्ड मिंटो ने लिखा, "भारत सरकार द्वारा उपक्रम करने की बात को मैं विशेष महत्व देता हूँ।"

इसके लिये लॉर्ड मिंटो ने मंत्र में पहली बात तो यह की कि उन्होंने दली कार्यकारिणी परिषद की अगस्त १९०६ में एक कमेटी नियुक्त की और एक ठेक द्वारा कमेटी का काम का उद्देश्य और उनका कार्य क्षेत्र बताया। "कमेटी को इन बिन्दुओं पर विचार करना था (१) देशो नरेशों की परिषद और यदि पर समय न हो ना बरा बादशाहों की विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, (२) बादशाहों की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति (३) केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व में वृद्धि, (४) बजट पर विचार प्रकट करने के लिये समय में वृद्धि और साथ ही सपोषित प्रस्तुत करने के अधिकार में वृद्धि।" इस कमेटी के अध्यक्ष सर ए. टी. ऐरहलहैं।

कमेटी ने अक्टूबर १९०६ में अपनी रिपोर्ट दी परन्तु बादशाहों की कार्यकारिणी में काम पर विचार करने में बहुत समय लगा जिस के फलस्वरूप मुद्दारे सम्बन्धी भारत सरकार का राजपत्र, भारत मन्त्री के पास सन् १९०७ की मार्च के अन्त में भेजा गया। मि. मॉले ने अपनी परिषद से तुरन्त ही परामर्श किया और भारत मन्त्री की स्थानीय सरकारों की सम्मति जानने के लिये कहा। स्थानीय सरकारों और जनता का मत जानने में एक वर्ष में अधिक समय लगा और इस प्रकार मुद्दारे के सम्बन्ध में १ अक्टूबर १९०८ से पहले कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

## २

दली दिना में देश के विभिन्न भागों में स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही थी। पूर्वी बंगाल और आसाम प्रान्त के जन-गवर्नर ने बड़े अविवेक और अज्ञेयता से काम लिया। लोगों की आनक्ति करने के उद्देश्य से उसने प्रान्त के बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों में गुरमा मीनका के जत्थों की स्थापित कर दिया। लॉर्ड मिंटो को "इस बात का पूरा विरोध था कि सर वेंम्प्टेन्ड के कौशलमूल्य शासन से बड़ा नापे

के लिये अत्यन्त अपायपूर्ण पद लिखा।" Morley Recollections-  
Vol II pages 181-182

१. Buchan : Lord Minto, page 234--letter dated 11-7-1906

२. Buchan Lord Minto, page 240

३. उद्धृत पुस्तक पृष्ठ, २२७.

सतरा या पर वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से इस लिये शिञ्जकते थे कि सरकार के आलोचक उसका गलत अर्थ अवश्य लगावेंगे। जुलाई १९०६ में एक घटना हुई जो वाइसरॉय अथवा भारत मन्त्री को विशेष रु। से अभिग्रहण नहीं थी। दो स्कूलों के विद्यार्थियों ने सिराजगंज में बड़ा उग्रनापूर्ण और उच्छृंखलतापूर्ण व्यवहार किया था। इस पर उप-गवर्नर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उक्त दोनों स्कूलों को बहिष्कृत करने के लिये कहा। भारत सरकार के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में यह काम अनिवार्यपूर्ण था और उसने सर बैम्फील्ड से अपना निवेदन वापिस लेने के लिये कहा। इस पर सर बैम्फील्ड ने वाइसरॉय को यह लिखा कि या तो स्कूलों को बहिष्कृत किया जावे अथवा उसका त्याग-पत्र स्वीकार किया जावे। लार्ड मॉल्ल ने लिखा है—“लार्ड मिंटो आन्दोलन के समय में उप-गवर्नर बदलने के विरोधी तर्कों के प्रति सजग थे किंतु यह बात प्रतिदिन अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि नये प्रान्त का शासन अविश्वसनीय है और उससे अन्य नई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं—अतः त्याग-पत्र स्वीकार किया गया, मने भी अपनी स्वीकृति तार द्वारा तुरन्त भेज दी।”

पंजाब की सरकार ने अपने यहां की स्थिति को विगाड़ लिया था। जैसा कि पहले<sup>१</sup> कहा जा चुका है पंजाब सगडे आरम्भ में भूमि विपयक थे। पंजाब सरकार ने कष्टों को कम करने और सगड के कारणों को दूर करने के स्थान पर बख़ोर व्यवहार से काम लेने का निश्चय किया और १८१८ के पुराने विनियमन ३ के अन्तर्गत लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को देश से निर्वासित करने के लिये भारत सरकार पर जोर डाला। लाला लाजपत राय का कई क्षेत्रों में प्रमुख स्थान था। वे एक धार्मिक सुधारक थे, धर्म समाज के नेता था और शिक्षा प्रसारक थे। वे परोपकारी थे और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। सर्वसाधारण और दुखी लोगों से उन्हें सच्चा प्रेम था। वे एक प्रमुख कांग्रेसी भी थे और नये उग्र दल के तीन महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। वे अंग्रेजों में और विशेष कर उर्दू में ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता थे। सरकार उनकी स्वतन्त्रता और उनके बढ़ते हुए प्रभाव से शक्ति हो गई थी। दूसरी ओर सभी—सहमत और भिन्नमत—देशवासी उन्हें सत्यशील और निस्वार्थ-प्रेरित देशभक्त मानते थे। उनके अनुसार वे सरकार के विरुद्ध पड़पत्र रचने में अथवा सैनिकों में राजद्रोह का प्रचार करने में अथवा अन्य कोई

१. Morley's Recollections, page 84.

२. इस पुस्तक का १३ वा अध्याय देखिये।

मुक्त काम करने में अक्षम थे ।<sup>१</sup> सरकारों नीति के सम्बन्ध में उनकी आराधना स्पष्ट और निष्पक्ष थी । भूमि विषयक आन्दोलन से उनका सम्बन्ध न बराबर था । इन सम्बन्ध में जबलपुर और उन्हाड़े सरदार अजीतसिंह के साथ एक सभा में भाषण दिया था । सरदार अजीतसिंह लायलपुर जिले के एक सतिहर और पट्ट उन्हाड़ बहुत कम लाग जानते थे । सन् १९०६-७ के भूमि विषयक आन्दोलन के एक प्रमुख मगधनकर्ता के नाते वे प्रसिद्ध हो गये । वे एक प्रभावशाली और साध ही उग्र बक्ता थे और अत्यन्त लोकप्रिय थे । सतिहर आन्दोलन के मोर्चे में बटन के क्षण सञ्चार का धबकाहट हुआ और उन रातों के लिये सरकार ने सरदार अजीत सिंह और लाला राजपतराय का निर्वासित करना ही उचित समझा । सन्निपद गवर्नर-जनरल ने इन दोनों सज्जनों का गिरफ्तार करके निर्वासित करने के लिये अनुज्ञा-पत्र दिया और ९ मई १९०७ को इन दोनों व्यक्तियों का निर्वासित करके माटल (बम्बे) भेज दिया गया । ११ मई १९०७ का वाइसरॉय ने एक अध्यादेश (Ordinance) प्रकाशित किया । इसके अन्तर्गत सावजनिक सभा आयोजित करने के अधिकार का बढावता से सीमित कर दिया गया । सभा का आयोजन करने वाला को सभा की तिथि से मात दस पहर सरकार का ज्ञापन कर सूचित करने के लिये कहा गया । मजिस्ट्रेट का सभाका का रखने का अधिकार दिया गया । सरकार द्वारा स्वीकृत सभाका में पुलिस के लिये उपस्थित रहने का नियम था । यह अध्यादेश सन्निपद गवर्नर जनरल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू किया जाना था । इस अध्यादेश का पत्राव और पूर्वी बंगाल में तुरन्त ही लागू कर दिया गया ।

लाला राजपतराय के निर्वासन से देश के विभिन्न भागों में बड़ा उद्वेग हुआ और उसने पल्लवस्वरूप उग्र वर्ग, विद्रोह कर बंगाल के तराई का उत्तेजित हुए और उन्होंने उग्रवाद हिंसा और आतंकवाद का अपनापा ।

- 
- १ लाला राजपतराय के निर्वासन के सम्बन्ध में श्री गान्धे ने सम्प्रदायिक विधान परिषद में कहा — “केवल पञ्जाब में ही नहीं बरने बाय प्रांता में भी सहस्राधिक लोग लाला राजपतराय का आदर्श करते हैं । उनका चरित्र उच्च बर्तित्व का है और उनके विचार पवित्र हैं । एस एक प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक मूल्यांकन और राजनीतिक कार्यकर्ता को जिसके सभी काम स्पष्ट और प्रकट रूप में हुए, बिना किसी अभिप्राय के देश में निर्वासित कर देने का कारण नारे दान के साथ आवश्यक और दुःख सहज बन हो गये ।” Page 43

Proceedings of the Indian Legislative Council, Vol XLVI 1907-8

दोनों बगालों की दशा पहले ही बिगड़ी हुई थी। सरकार विभाजन विरोधी आन्दोलन का निष्ठुरता से दमन कर रही थी और मुसलमानों का पक्ष ले रही थी। सरकार की इस नीति के कारण लोग वचन और कर्म दोनों में उग्र होते जा रहे थे। "कुछ बगालों पत्रों ने सब प्रतिबन्धों को दूर हटा दिया और वे शिष्टक छोड़ कर तीव्र आलोचना करने लगे।" १ बगाल सरकार ने इन पत्रों पर अभियोग चलाने का निश्चय किया। क्रमपूर्वक आक्रमण किया गया और सब से पहली चोट 'बन्दे मातरम्' पर हुई। यह अंग्रेजी का राष्ट्रवादी दैनिक पत्र था और इसके सम्पादक मडल में आधू अरविन्द घोष भी थे। सरकार ने अगस्त १९०७ में अरविन्द घोष और मुद्रक पर राजद्रोह का आरोप लगाया। सब लोग यह बात भली भाँति जानते थे कि अरविन्द घोष उक्त पत्र से तन, मन, धन, सभी से सम्बन्धित थे किंतु सम्पादक के नाम को प्रमाणित करने के लिये कोई साक्षी नहीं मिला। २ जब मि विपिन चन्द्र पाल को प्रमाण देने के लिये बुलाया गया तो उन्होंने कार्यवाहियों में भाग लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके मतानुसार अभियोग देश के हितों के विरुद्ध था। इस अपराध के लिय स्वयं मि. पाल पर अभियोग चलाया गया और उन्हें छ महीने का कारावास दंड दिया गया। अरविन्द घोष के विरुद्ध अभियोग नहीं चल सका और उन्हें छोड़ दिया गया। मुद्रक का दोष सिद्ध हुआ और उभे तीन महीने का कारावास दंड दिया गया।

लगभग इसी समय 'सध्या' और 'युगान्तर' नामक बगला के प्रभावशाली पत्रों के सम्पादक—श्री ब्रह्म धान्यव उपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्त—पर अभियोग चलाया गया। मि उपाध्याय ने एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने यह कहा — "मैं इस अभियोग निर्णय में भाग नहीं लेना चाहता। स्वराज्य का उद्देश्य ईश्वर-प्रेरित है और इस सम्बन्ध में अपने काम के लिये मैं देश के विदेशी शासकों के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। इन विदेशियों के स्वार्थ हमारे राष्ट्रीय विकास के मार्ग में विघ्नरूप हैं और ऐसा होना अनिवार्य ही है।" ३ ब्रिटिश न्यायालयों से असहयोग का यह सबसे पहला उदाहरण है। आगे चल कर गुप्तोत्तर असहयोग आन्दोलन में इस प्रकार का असहयोग एक सामान्य बात थी। उक्त अभियोग अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि बलकत्ते के कैम्बेल् अस्पताल में अभियुक्त की मृत्यु हो गयी। दूसरे अभियोग में मि दत्त अपने को दोष-मुक्त सिद्ध नहीं कर सके और

१. Ray The Life and Times of C. R. Das, page 55

२ उस समय कोई ऐसा कानून नहीं था जिस के अनुसार आजकल की तरह पत्रों को अपने सम्पादक का नाम प्रकट करना अनिवार्य हो।

३ Ray उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७

उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास दंड दिया गया। आले कुछ ही महीनों में 'गुमान्तर' पर चार मुकदम चलाये गये और हर बार सम्पादन और मूद्रक का कारावास दंड दिया गया जिन्हु पन बराबर प्रकाशित हुआ और बराबर प्रचार करता रहा।

एक बार ना बाल और पञ्जाब में ये अभियान चल रहे थे और दूसरी बार भारत सरकार एक विधायक (समाचार-पत्र सम्बन्धी) जगन् न बनान के लिये भारत मन्त्री पर जार दे रही थी। जुलाई १९०३ में इस विषय पर भारत से एक राजपत्र भेजा गया। लार्ड मॉले ने स्वीकार किया है कि इस राजपत्र ने उन्हें 'कैसा दिया'।<sup>१</sup> पर भारत सरकार कठोर और दमनकारी नीति को व्यवहार में लाने के लिये तुली हुई थी। भारत मन्त्री ने आरम्भ में विरोध किया। कई बार उन्होंने सरकारी सदस्य<sup>२</sup> के व्यवहार को तीव्र आलोचना की और उनके लिये गहिरे रूसी नाम चीनानिक्स (Technovicks) का उच्चारण किया। इसके बाद जब भारत सरकार ने राजद्रोहपूर्ण समाजों को रोकने के उद्देश से एक विधायक बनान के लिये लार्ड मॉले का अनुमति मांगी तो वह त्रास में उठ पड़े।<sup>३</sup> उन्होंने वाइमंगर का लिखा कि 'जिम लागू न आकरा एरन्डा के मुधारा में विरोध किया था और जिम लागू न लाहौर और रावर्गिजी के साइड का कहाना लखर उन मुधारा का रद्द करने के लिये कहा था, आज उन लागू की बातों पर रूसी भर भी ध्यान न बीजिये।' <sup>४</sup> उन्होंने प्रेषित प्रस्तावों का अनाधारता, प्रतिश्रियावादी और अनाबद्धक बताया और उन्हें निषिद्ध कर दिया। लेकिन अन्त में भारत सरकार को प्रबल एवं आप्रहूणां मांगा के आगे भारत मन्त्री को मुकना पड़ा।<sup>५</sup> भारत सरकार ने कई दमनकारी एक्ट बनाये और उन्हें देश में बगे कठोरता के साथ लागू किया।

३

राजद्रोह पूर्ण समाजों का रोकने वाला एक्ट १ नवम्बर १९०३ को बना। स्वयं गृह सदस्य के अनुसार इस एक्ट में दमन के लिये प्रचुर सामर्थ्य निहित थी।<sup>६</sup>

१. Morley's Recollections, Vol II, Page 226

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१४

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१-२३२—लॉर्ड मॉले का उत्तर पढ़ने योग्य है।

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१

५. भारत मन्त्री ने बड़ सक्काव के साथ अपनी इच्छा और आना के विरुद्ध स्वीकृति दी।

६. Proceedings of the Legislative Council, Vol XLVI Page 25

सभाओं का विनियमन करने के लिये ११ मई को जो अध्यादेश लागू किया गया था उसकी अवधि १० नवम्बर को समाप्त होने वाली थी क्योंकि विधि के अनुसार अध्यादेश केवल ६ महीने के लिये ही सीमित होना है। यद्यपि उम अध्यादेश के प्रतिबन्धों को जारी रखने के लिये कोई कारण नहीं था,<sup>१</sup> तथापि भारत सरकार ने १९०७ के एक्ट द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान करने का निश्चय किया। परिपट में कुछ सुधार किये लेकिन इनके पर भी एक उग्र रूप से दमनकारी था। एक्ट में भारत सरकार को उसे किसी भी प्रान्त में लागू करने का अधिकार दिया। किसी भी उद्देश्य के लिये २० से अधिक व्यक्तियों की सभा करने के लिये स्थानीय अधिकारियों को सभा की तिथि से तीन दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक था। सार्वजनिक सभा की परिभाषा इतनी विस्तृत की गयी कि उ के अनुसार व्यक्तिगत घटों में सामाजिक मिलन को भी सार्वजनिक सभा माना जा सकता था। इस बात से ही लॉर्ड मॉल्ले काप गये थे। उन्होंने लिखा कि सैन्य अधिकारियों के उपक्रम पर प्रेस कानून बनाना स्वयं एक नई और बुरी बात थी, पर व्यक्तिगत मिलन को सार्वजनिक सभा बना देने की बात तो उससे भी बड़ कर है।

"उप-नाबन्ध अथवा अन्य अधिकारी, किसी भी निर्दिष्ट धन में किसी भी व्यक्ति को जिसके विचारों से वह असहमत है, व्यापमान देने से रोक सकता है। इसके स्थान पर ईमानदारी से गला घोट देना अच्छा होगा।"<sup>२</sup> अधिकारियों का किसी भी सभा को रोकने और सभा में किसी भी बोलने वाले का मुह बन्द करने का अधिकार दिया गया था। ये अधिकारी सार्वजनिक शान्ति के नाम पर कोई भी प्रतिबन्ध लगा सकते थे। स्वीडिश सभाओं में पुलिस के आदमी भेजे जाने थे। जैसा कि सर रास बिहारी घोष ने कहा, इन उपायों द्वारा देश के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था।<sup>३</sup> प्रवर-समिति में दो महत्वपूर्ण सुधार हुए—एक तो यह कि एक्ट केवल तीन साल के ही लिए लागू रहना चाहिए और दूसरा यह कि एक्ट की धाराओं के अनुसार किसी स्थानीय सरकार द्वारा

१. इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री गोखले ने निम्नलिखित रस्य बनाये "पिछले ६ महीनों में पन्नाब और दिल्ली में केवल एक सभा हुई थी और उस के फलस्वरूप शान्ति और व्यवस्था में कोई बिघ्न नहीं पड़ा। पूर्वी बंगाल में केवल एक सभा हुई थी और फरीदपुर में विचारार्थी विषयो पर कठोर नियंत्रण के कारण प्रस्ताविन सभा का विचार छोड़ दिया गया था।
२. Morley : Recollections, Vol. II, pages 232-33
३. Proceedings of the Legislative Council, Vol. XLVI page 54-



निर्दिष्ट क्षेत्र में, यह एक्ट केवल छ महीने के लिए लागू होना चाहिए। किन्तु इन सुधारों से इस अत्यन्त दमनकारी एक्ट को बँटोरता में न तो कोई कमी हुई और न हो ही सकती थी। डा० रास बिहारी घोष के अनुसार इस एक्ट का किसी सम्य सरकार की विधि की अपेक्षा स्मॉ यूकेस (Ukase) से अधिक साहस्य था।<sup>१</sup>

## ४

नरमदगी नेताओं के पूर्व कथन के अनुसार<sup>२</sup> सरकार की दमनकारी नीति ने अमलाप को गुप्त धाराओं में ढकेल दिया। बहुत सी गुप्त समितियाँ बनी और बगावत नवयुवकों में प्रान्तिवारियों की समस्या बहुत बड़ गई। आतंकवादी अपराध प्रकट हुए। 'सरकारी तन्त्र घबराया और अपनी भूलों के परिणामों से उद्विग्न हुआ। उसने व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने के लिए एक के बाद एक बड़े विभिन्न दमनकारी उपायों से काम लिया, मार्बेजनिंग जीवन ठंडा पड़ गया और उसका विकास रुक गया।<sup>३</sup> सन् १९०८ की ८ जून को एक ही दिन में भारत सरकार ने दो अत्यन्त दमनकारी एक्ट बनाये—एक ता विस्फोटक पदार्थों एक्ट था और दूसरा समाचार-पत्र (अपराध-उत्तजक) एक्ट था। इनका बनाने के लिए परिपद की कार्य पद्धति व सामान्य नियमों का ठुकरा दिया गया। इसके अतिरिक्त उस दिन परिपद में कोई स्वतन्त्र भारतीय सदस्य भी उपस्थित नहीं था।

सन् १८८८ का विस्फोटक एक्ट अभी लागू था। उसकी म्हायना के लिए १८७८ का भारतीय शस्त्र एक्ट था। इन दोनों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थों से क्षति पहुँचाने वालों को आजीवन निर्वासन तक का दण्ड दिया जा सकता था। परन्तु भारत सरकार की दृष्टि में ये कानून अपर्याप्त थे और उसने इस कमी को पूरा करने के लिए और कम के उपयोग के कारण उत्पन्न हुई नई स्थिति का सामना करने के लिए सन् १९०८ का एक्ट बनाया।

नये एक्ट के क्षेत्र के अन्तर्गत विस्फोटकों के अतिरिक्त विस्फोटक बनाने वाले पदार्थों और उपकरणों की भी गणना थी। सन्देहात्मक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के पास उक्त कोई वस्तु प्राप्त होने पर १४ वर्ष के निर्वासन अथवा पाँच वर्ष के

१ Proceedings of the Legislative Council, Vol. XLVI, page 49

२ उपर्युक्त पुस्तक, Speech of Dr. Ghosh, page 53—"यह नीति एक उद्देश्य के लिए अवश्य समर्थ है—उससे गुप्त राजद्रोह व कीटाणुनाश का प्रचार होगा।"

३ Bannerjee A Nation in the Making, page 249.

कारावास का दण्ड था ।<sup>१</sup> जित विस्फोटों के कारण मृत्यु हो जाती थी उनसे एकटका कोई सम्बन्ध नहीं था—एसे मामला में हत्या के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता था अथ विस्फोटों के लिए बठोर दण्ड था ।<sup>२</sup> यदि वस्तुन कोई विस्फोट न हुआ हो किन्तु उसके लिए उद्देश्य या प्रयत्न का प्रमाण हो तो २० वर्षों के लिए निर्वासन और सात वर्षों के लिए कारावास का दण्ड था ।<sup>३</sup> अन्त में विस्फोटकों की तैयारी के लिए स्थान, वन सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायता देने वाल व्यक्ति अपराधी की ही भांति दण्डनीय था ।<sup>४</sup>

८ जून १९०८ का दूसरा एक समाचार पत्र (अपराध उत्तजक) एकट था । गृह सदस्य के अनुसार यह एक तनिक भी दमनकारी नहीं था भारतीय मत इसके विपरीत था । गृह सदस्य के दावा में इस एक का उद्देश्य 'हत्या अथवा सन १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एकट के अन्तर्गत किसी हिंसातुण अपराध' के लिए उत्तेजना देने वाले पत्रों का अस्तित्व मिटा देना था । अपराधी छापेखाना को जन्म करने का और पत्र के उच्छेद करने का नियम था ।<sup>५</sup> यदि जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति में किसी पत्र से हिंसात्मक कार्यों का उत्तेजना मिलता है तो उसके प्रस को एकट के अधिकार के धल पर वह जन्त कर सकता है । यदि किसी प्रस से उक्त आशय का कोई पत्र निकलन आता हो तो जिलायास को यह प्रतिबन्ध आना देने का अधिकार था कि सम्बन्धित व्यक्ति उसने समस्त उपस्थित होकर कारण व्यक्त करें कि वह आजा स्थायी क्या न कर दी जाव ।<sup>६</sup> यदि प्रस्तुत प्रमाण से जिला मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट हो कि समाचार-पत्र न अपराध किया है तो उक्त प्रतिबन्ध आजा स्थायी हो जा सकती थी<sup>७</sup> और वह (जिला मजिस्ट्रेट) किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रस तथा उससे सम्बन्धित अथ संपत्ति को बुरक करने का अधिकार दे सकता

१ Clause V of the Act Agarwala The Lawyers Vade Mecum for Criminal Courts Vol I, page 53

२ Clause III उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५१-५२

३ Clause IV उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५२ ५३

४ Clause VI उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५३

५ Clause LIL Ghosh Press and Press Laws in India, page 63

६ Proceedings of the Legislative Council, Vol XLVII, page 12

७ Clause III Ghose उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६३ ६४

८ Clause III उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६४

था।<sup>१</sup> विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा को त्थापी करने से पहले भी कृषी का वारंट दे सकता था।<sup>२</sup> भारत मन्त्री के हस्तक्षेप करने पर इस कृषी के विषय में<sup>३</sup> न्यायकुन कार्यवाही का दिवावा सा हो सकता था। आज्ञा के स्थायी बनाने के पन्द्रह दिन के अन्दर हार्दकोर्ट में अपील की जा सकती थी।<sup>४</sup> कन में एक ने प्रान्तीय सरकार का समाचार-पत्र के मुद्रक अथवा प्रकाशक की १८९९ के प्रेम तथा पुस्तक निबन्धन एक के अनुसार<sup>५</sup> को हुई घोषणा की रद्द करने का अधिकार दिया था, जिसके फलस्वरूप समाचार-पत्र का बंध अस्तित्व समाप्त हो जाता था।<sup>६</sup>

## ५

इस समय एक और नो परिपद में सीधता से ये एक बनाये जा रहे थे और दूसरी आर सरकार, विमान न० १०८ ए और १५३ ए के अन्तर्गत, भारत के लगभग सभी भागों में राजद्रोह के अभियोग चला रहे थे। निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों ने इतने बठोर दण्ड दिये कि स्वयं भारत मन्त्री न उन्हें "वीरग्न, अत्यन्त डर और अतृपित" बनाया।<sup>७</sup> ऐसा प्रयोग जाता है कि आत्मवादों अपराधों से कमचारि तन्त्र और आर-भारतीय बंध पवना गय य और इसी कारण उन्होंने प्रतिकार और अपरिमित दमन को नानि का प्रनिपादन किया। लाटें मॉर्टे ने इस नीति से मय-भीत हाकर विरोध किया चेतावना मनी—लेकिन सब व्यर्थ।<sup>८</sup> १९०८ में १४ जुलाई का उन्होंने लाटें मिटा का किया "राजद्रोह और अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जादिल बहला देने वाले दण्ड दिये जा रहे हैं उनके कारण मैं अत्यन्त चिन्तित और चकित हूँ। आज हो मैं यह पता है कि बम्बई में पर्यर फैलने वालों को ब्राह्म महीने का कारावास दण्ड दिया गया है। बम्बई यह अतिव्रमण है। तिनकेली-नृवी-कोरन वाले मामले में दो आशमियों को जो दण्ड दिया गया है वह अक्षणीय है—एक को आजीवन निर्वासन दिया है और दूसरे को दस वर्ष का कारावास। ये बातें चल नहीं सकती। ऐसी वीरग्न बातों का रक्षण करने के लिए मैं किसी भी दृष्टि पर

१. Clause IV उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६४-६५

२. Clause II उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६४.

३. Morley Recollections, page 260

४. Clause V, Ghose : उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६५.

५. Clause VII उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६५

६. Proceedings of the Legislative Council Vol XLVII, page 13

७. Morley. Recollections Vol. II pages 269-70.

## दमन और सुवार

सहमत नहीं हूँ। इसी कारण मैं इन गलतियों और मूलों की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ। हम व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन व्यवस्था लाने के लिए अत्यन्तिक कठोरता के उपयोग से सफलता नहीं मिलेगी, उसका परिणाम उलटा होगा और लोग बम का सहारा लेंगे।”

इस प्रकार केवल भारतीय नेताओं के ही अनुसार नहीं बरन् सर्वोच्च अधिकारियों के अनुसार भी बम का मार्ग, दमन की नीति का परिणाम था। लॉर्ड मॉर्ले तो वस्तुतः और भी आगे बढ़े। उन्होंने अशान्ति का सारा दायित्व कर्मचारों तथा कट्टर हिंसावादियों पर डाला। उन्होंने लॉर्ड मिंटो को लिखा “इस अशान्ति का दायित्व आप पर या मूझपर नहीं है, यह तो उन अतिविश्वासी और अत्यन्त-व्यस्त चीनोविनक्स (Tchinovniks) पर है जो पिछले पचास वर्षों से भारत का संचालन करते रहे हैं।”

और अब भी इन्हीं लोगों की जीत हुई। सन् १९०८ के राजद्रोह सम्बन्धी अभियोगों का वर्णन करना न तो यहाँ संभव है और न आवश्यक ही है। केवल कुछ अभियोगों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। मद्रास में तीन महत्वपूर्ण अभियोग हुए। तिनेवेली अभियोग, चिदम्बरम पिलाई और सुब्रह्मण्य शिव के विरुद्ध था। इसमें मद्रास के उच्च न्यायालय ने दण्ड घटाकर, दोनों को छ वर्ष के लिए निर्वासित किया। ‘इंडिया’ के सम्पादक श्री निवास आयंगर को पाँच वर्ष के लिए निर्वासित किया गया। ‘स्वराज्य’ के सम्पादक और मालिक ने सरकार से लिखित क्षमा माँगी लेकिन फिर भी उनपर अभियोग चलाया गया।<sup>१</sup> बंगाल में समाचार-पत्र (अपराध-उत्तेजक) एक्ट के अन्तर्गत ‘बन्धे मातरम्’, ‘युगान्तर’ आदि के विरुद्ध बार्देवाही की जा रही थी, ‘राजद्रोह’ के अभियोग जिन पत्रों का गला न घोट सके, उनके अस्तित्व को नये एक्ट के प्रहार ने समाप्त कर दिया। मध्य प्रान्त में एक पृष्ठ के एक देसी पत्र के सम्पादक हरी किशोर को पाँच वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया। और जहाँ वह पृष्ठ मुद्रित होता था, उस छापेखाने को ज्त कर लिया गया। समुक्त प्रान्त में ‘उर्दू ऐ-मोजल्ला’ के सम्पादक को दो वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया और उस पर ५०० रुपये जुर्माना किया गया—उस सम्पादक का अपराध यह था कि उसने भिस में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति की आलोचना की थी।

१ Morley : Recollections, पृष्ठ २६९-७०

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६३

३. क्षमा याचना के कारण इन लोगों को केवल ९ और छ महीने का कारावास दण्ड दिया गया। ‘हिन्दू’ (मद्रास) के सम्पादक ने लिखित क्षमा माँगी और भविष्य के लिए वास्तवसन् दिया। अतः उन पर अभियोग नहीं चलाया गया।

६

इतने पर भी दमन का प्याला पूरा नहीं भरा था। दिसम्बर १९०८ में भारत सरकार ने परिपद की एक ही बैठक में एक अत्यन्त दमनकारी एक्ट तैयार किया। इसका उद्देश्य जात-वादों अपराधों और अराजकतावादी पद्धतियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अभियोगों का शोध निष्पन्न करना था और साथ ही कुछ स्वयंसेवक सत्याग्रहियों को अवैध घोषित करना था। १९०८ के दण्ड विधि (संशोधन) एक्ट के दो भाग थे—पहले भाग में अराजकता सम्बन्धी अपराधों के लिए एक विशेष दण्ड से अभियोग-निर्णय की व्यवस्था की गई थी, दूसरा भाग सत्याग्रहों से सम्बन्धित था। पहले भाग के अनुसार मजिस्ट्रेट अभियोग-निर्णय के लिए अभियुक्त को अप्रतिपादित रूप से विशेष न्यायालय के सुपुर्द कर सकता था। यह विशेष न्यायालय हाईकोर्ट के तीन जजों से निर्मित होता था किन्तु वह जूरी से भिन्न था। परीक्षण से पहले साक्षियों की मृत्यु हो जाने की दशा में भी, उनका वक्तव्य मान्य था और तीनों जजों का निर्णय अन्तिम था। इस भाग की धाराओं के विषय में सर हार्वे एडमसन ने परिपद में कहा—“वस्तुतः तीन के स्वान पर एक अभियोग निर्णय होगा और वह एक ऐसे न्यायालय में होगा, जिसे, अपने अवमान को दण्ड देने का पूरा अधिकार होगा और जो विचाराधीन अभियोगों पर अनुचित आलोचना सहन नहीं करेगा।” दूसरे भाग के अनुसार, किसी भी सत्याग्रही को जो उसके मत से न्याय, व्यवस्था और शान्ति में हस्तक्षेप करती हो, सरकार अवैध घोषित कर सकती थी। अवैध सत्याग्रहों की बैठक में भाग लेने वालों को, अथवा उसके लिए चन्दा देने या लेने वालों को अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे सहायता देने वालों को एक्ट के अनुसार छ महीने तक का कारावास दण्ड दिया जा सकता था। अवैध सत्याग्रहों की समा आयोजित करने वालों को, अथवा आयोजन में सहायता देने वालों को अथवा आयोजन के लिए प्रोत्साहन देने वालों को एक्ट के अनुसार तीन वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया जा सकता था।

इस एक्ट के अन्तर्गत, उन सब स्वयंसेवक सत्याग्रहियों को जो बंगाल में सन् १९०२ से जनता की विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएँ कर रही थी, अवैध घोषित कर दिया गया क्योंकि सरकार को इस बात का सन्देह था कि वे सत्याग्रहों गुप्त रूप से शान्तिकारी आन्दोलन में भाग ले रही हैं। परन्तु कुछ ही समय में इन सत्याग्रहों का अस्तित्व मिट गया।

इस वर्ष का अन्तिम दमनकारी कृत्य अत्यन्त कठोर भी था। बंगाल के ९ प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तर्गत एक साथ देश

से निर्वासित कर दिया। ये लोग नरम दली नीति के लिए सुपरिचित थे। सर मुल्केन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं —

"दिसम्बर १९०८ में एक दिन प्रातःकाल लोगों को यह जानकारी आरम्भ हुआ कि अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, सनीपचन्द्र चटर्जी, शचीन्द्र प्रसाद दास और मुवाघ मालिक का १८१८ के विनियमन ०. ३ के अन्तर्गत देश से ब्रजमोहन कालेज से निर्वासित कर दिया गया है।" अश्विनी कुमार वाराणसी के नेता और संस्थापक थे, कृष्णकुमार मित्र ब्रह्ममज्ज के एक प्रमुख नेता थे और भी परिचित व्यक्ति उनका हाथ धरते थे, सनीप चटर्जी और शचीन्द्र वीर प्रसिद्ध स्वदेशी कार्यकर्ता थे और मुवाघ मालिक एक सम्पन्न और धनी घराने के सदस्य और सायतोल देशभक्त थे। इस निर्वासन से देश में बड़ा उद्वेग हुआ; और नरमदल तथा उग्र दल दोनों के ही लोगों ने, समान रूप से इस कृत्य को निन्दा की।

## ७

भारत सरकार एक ओर तो निष्ठुर दमन की नीति का अनुसरण कर रही थी और साथ ही वंचनात्मक एक शान्तिकारी, दानाही विचारधाराओं के उग्रवादियों को दवाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी और दूसरी ओर वह नरम दल वालों, मुत्तलमानों, जमींदारों और दर्या करेला का अपने पक्ष में लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा थी। १ अक्टूबर १९०८ के राजपत्र में इन प्रस्तावों का रूप दिया गया और उन्हें अगली डाक में भारत मन्त्री के पास भेज दिया गया। भारत परिषद को एक छोटी सी समिति ने भारत सरकार के इस राजपत्र का सावधानी से परीक्षण किया। उसके बाद पूरी परिषद ने उस पर विचार किया। अन्त में लॉर्ड मॉर्ले ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को रूप देना आरम्भ किया। ५ नवम्बर १९०८ का उन्होंने लॉर्ड मिटो को लिखा — "यह विषय गम्भीर है, आपका सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमका ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं कि उनसे न तो बर्मबारी तन्त्र कुपित हो, न आन्दोलन-भारतीय कुपित हों और साथ ही मुसलमान और दक्षिणपक्षी कांग्रेसी भी कुपित न हों। यह काम साधारण नहीं है।" लेकिन लॉर्ड मॉर्ले ने अपना काम पूरा किया और अपने राजपत्र को परिषद के समक्ष रखा और उसका अनुमोदन प्राप्त किया। "मन्त्रिमण्डल" के दो सदस्यों ने मतभेद प्रकट किया और यह मतभेद केवल सरकारी बहुमत के प्रश्न पर था।" ३ "आश्वासन मिलने पर मन्त्रिमण्डल ने भी अपनी स्वीकृति दी। ... उस

१ Bannerjee A Nation in the Making, page 249.

२. Morley : Recollections, Vol. II, page 281.

३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ २८२.

समय वह घरेलू महत्व के अविलम्ब कामों में फंसा हुआ था।" २७ नवम्बर १९०८ को यह राजपत्र भारत भेज दिया गया।

इसी बीच दो नवम्बर को, महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा की पचासवो वर्षगांठ पर, सम्राट एडवर्ड ने भारतीय जनता और देशी राज्या के शासकों के लिए एक राजकीय सन्देश भेजा और उसमें आगत राजनीतिक सुधारों का पूर्वाभास दिया। बाइसराय ने जोधपुर में एक विराट दरबार में उक्त सन्देश को पढ़कर सुनाया। वर्तमान उद्घोषणा ने सन् १८५८ के सिद्धान्त की पुष्टि की और उन्हें कार्यान्वित करने के प्रयत्नों का वर्णन किया और कहा —“आरम्भ से ही प्रतिनिधि सभाओं के सिद्धान्त को व्यवहार में लाया गया था और अब वह समय आ गया है कि .. उस सिद्धान्त को सबिधेक विस्तृत किया जा सकता है इन उद्देश्यों के लिए बड़े परिधम के साथ जो साधन बनाये जा रहे हैं वे उनकी कच्ची नहीं कहेंगे। निकट भविष्य में आप लोग उनसे परिचित हो जावेंगे।” १७ दिसम्बर १९०८ को लॉर्ड मॉल ने हाउस ऑफ़ लार्ड्स में एक विस्तृत व्याख्यान में सरकारी सुधार प्रस्तावों पर प्रकाश डाला और दोनों—१ अक्टूबर १९०८ के और २७ नवम्बर १९०८ के—राजपत्रों को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया। दिसम्बर के अन्त में—बाम-पक्ष से बिहीन—कांग्रेस ने मद्रास में अपना अधिवेशन किया और मौडें-मिटो योजनाओं का हार्दिक स्वागत किया। एक सक्रिय विवेक में इन प्रस्तावों को रूप दिया गया और भारत भर में २३ फरवरी १९०९ को उसे लॉर्ड भवन में प्रस्तुत किया। यही विवेक २५ मई १९०९ को भारतीय परिषद एकट बन गया।

पन्द्रहवां अध्याय

## मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ

१

एक ओर तो मि. मॉल और लॉर्ड मिटो में राजनीतिक सुधारों के विषय में कांग्रेस को अपने साथ लेने की आवश्यकता पर पत्र-व्यवहार हो रहा था और भारत

१. Morley: Recollections, Vol. II, page 283

२ सन् १९०८ की राजकीय उद्घोषणा Morley's Recollections Vol II के अन्त में एक परिशिष्ट के रूप में विस्तृत रूप से उद्धृत की गई है।

## मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ

को कुचलने के लिये प्रयत्नशील थे। श्री मुहम्मद नुमान लिखते हैं — “अंगरेजों को यह निश्चय हो गया था कि नई सत्ता के विस्तार तथा अस्तित्व के लिये मुसलमानों को कुचलना अनिवार्य है, अतः उन्होंने जान बूझ कर ऐसी नीति अपनाई जिससे मुसलमानों की आर्थिक बरबादी हो, प्रतिभा कुठित हो और उनका सामान्य पतन हो।”<sup>१</sup>

यद्यपि ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मुगल सम्राट से मिला था तथापि उसकी नीति आरम्भ से ही मुस्लिम विरोधी थी। स्थायी बन्दोबस्त के विषय के एक अधिकारी विद्वान मि. जेम्स ओ. विन्सेले लिखते हैं, कि इस बन्दोबस्त ने “हिन्दु उगाही करने वालों को (जो अब तक केवल महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे) ऊपर उठा कर खमीदार बना दिया। मुसलमानों के राज्य में जो सम्पत्ति मुसलमानों को मिलती, अब हिन्दुओं को उसी सम्पत्ति को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया।” साथ ही बंगाल में (और बाद में सारे देश में) सेना में मुसलमानों की भर्ती के लिये द्वार बन्द कर दिया गया, — सैनिक कार्य मुसलमानों का मनोवान्छित व्यवसाय<sup>२</sup> था।” कलकत्ते के तत्कालीन फारसी पत्र ‘बूरवोन’ के एक लेख के अनुसार, “बड़ी और छोटी सभी प्रकार की नौकरिया घीरे-घीरे मुसलमानों से छीन कर, अन्य जाति के लोगों को, विशेषकर हिन्दुओं को, दी जा रही हैं। हाल ही में मुन्दरबन के कमिश्नर के कार्यालय में कई स्थान खिन्न हुए। उनके लिये विज्ञापन में कमिश्नर ने कहा कि निवृत्तिप्राप्त केवल हिन्दुओं में से ही की जावगी।”<sup>३</sup> अन्य व्यवसायों में भी मुसलमानों की स्थिति बहुत गिर गई। “सन् १८५२ से १८६८ तक २४० भारतीयों को उच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुमति दी गई, इन में मुसलमान केवल एक ही था।”<sup>४</sup> भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प कुचलने के लिये जो नीति जान बूझ कर अपनाई गई थी, उससे भी मुस्लिम समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश शिल्पी तथा बुनकर लोग मुसलमान थे। अद्योक्त महता और अच्युत पटवर्धन लिखते हैं — “लेकिन मुसलमानों पर सब से बड़ा अन्याय शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। स्कूलों में फारसी और अरबी

१ Noman : Muslim India, page 23.

२ H. C. Bowen : Mohammedanism in India, page 45.

३ सन् १८७१ में बंगाल में गवर्नर की हुई नौकरियों की कुल संख्या २१४१ थी। इनमें मुसलमान ९२ थे, हिन्दु ७११ थे और १३६८ यूरोपियन थे।

Noman : Muslim India, page 22.

४ H.C. Bowen : Mohammedanism in India, page 45.



के लिये कोई स्थान नहीं था।<sup>१</sup> विगतनाश में धनी मुसलमानों द्वारा दान की हुई शिक्षण निधियाँ को अब उच्चतर शिक्षा के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया। यह शिक्षा मुसलमानों की आवश्यकताओं के लिये अनुपयुक्त थी और इस से अन्य लोगों को ही लाभ हुआ। विगत शताब्दी की सातवीं दशाब्दी में हुगली कलेज में लगभग ३०० विद्यार्थी थे इन में से केवल तीन मुसलमान थे।<sup>२</sup> मि. नुमान लिखते हैं — "सारांश यह है कि शिक्षण नीति के कारण मुसलमानों में बेकारी बढ़ी और मुसलमानों के लिये अन्य मार्ग बन्द हो गये। आर्थिक नीति ने भारतीय मुसलमानों को निधन बना दिया। सेना में उनकी सत्ता बहुत थोड़ी कर दी गई, और हस्तशिल्प को बुलन्द कर उन्हें असहाय बना दिया गया। १८५७ का विद्रोह इन्हीं नीतियों का परिणाम था और उस कोई माननीय चर्चा टाल नहीं सकती थी।"<sup>३</sup>

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अठारहवीं शताब्दी के पिछले त्रुपांश और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (बस्तुन आठवां दशाब्दी के आरम्भ तक) सरकारी नीति निर्दिष्ट रूप से मुसलमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में थी और उस नीति ने मुसलमानों को राजनीतिक एवं आर्थिक क्षय में नीचे गिरा कर उन्हें नैराश्य की ओर ढकेल दिया।

वहाबी नेतृत्व ने इस असन्तोष के वातावरण में मुसलमानों का संगठन किया और उनके राय का सरकार तथा उच्च वर्गों के विरुद्ध विद्रोह में परिणत कर दिया। वहाबी आन्दोलन आरम्भ में विद्रुह रूप से धार्मिक था और इसकी प्रेरणा अरब देश से मिली थी। सैयद अहमद शेर-बी हज करने के लिये मक्का पये थे और वे अरब में फँके हुए वहाबी आन्दोलन से प्रभावित हुए थे। सन् १८२० में भारत लौटने पर इस्लाम में सुधार और सुद्धि के उद्देश्य से उन्होंने वहाबी आन्दोलन आरम्भ किया। "उन्होंने अपने शिष्यों का सहायता से मुस्लिम जनता को ज्ञानशोर दिया और सारे देश में जोश का एह्रें दीठा था। इस आन्दोलन में इतना वेग था कि डा. हण्टर ने 'जैसे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक पुनर्स्थान' बताया है।"<sup>४</sup>

यह वहाबी आन्दोलन मूलतः धार्मिक होने हुए भी शक्तिशाली था और साथ ही सर्वप्रकार से सशक्त था। सर विलियम हण्टर के अनुसार वहाबी लोग

१ Mehta and Patwardhan: The Communal Triangle in India, page 87

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ८८

३ Noman - Muslim India, pages 26-27.

४ Mehta and Patwardhan: The Communal Triangle in India, page 95.

“प्रगतिवादी थे और अंधा की बातों पर हाथ रखते थे, राजनीति में यह लोग साम्प्रदायी और लाल प्रजातन्त्रवादी थे।”<sup>१</sup> इन लोगों ने बंगाल के निर्बल किसानों का संगठन किया, फरोदपुर, नादिया और चौबीस परगना में खेतियार विद्रोह का नेतृत्व किया। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की संख्या अस्सी हजार थी। ये लोग निम्नतम वर्गों के सदस्य थे और इन में परस्पर पूर्ण समता का व्यवहार था।

सरकार ने बहादुरी आन्दोलन का निष्ठुरता से दमन किया। लेकिन अन्तिम रूप से समाप्त होने से पहले इस आन्दोलन ने १८५७ के व्युत्थान को जन्म देने में सहायता दी। सर जॉन केरी के अनुसार, “विद्रोह के मुख्य चालक मुसलमान थे।” इसी अवधि में मि एच सी वाउन कहते हैं “ये मुसलमान निश्चित रूप से बहादुरी थे।”<sup>२</sup> सन् १८५७ के विद्रोह के बाद भी बहादुरी लोग सीमा प्रदेश में युद्ध करते रहे और उन्हें सारे देश से जन और धन की सहायता मिलती रही।<sup>३</sup>

सत्य तो यह है कि १८५७ के व्युत्थान का आधार अत्यन्त विस्तृत था किन्तु अंगरेजों की दृष्टि में न तो वह हिन्दु विद्रोह था और न वह राष्ट्रीय विद्रोह था वरन् वह मुस्लिम विद्रोह था और इसी कारण दमन करने में विशेष कोप मुसलमानों पर हुआ और कम से कम एक दशक तक सरकारी नीति मुसलमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में रही।

धीरे धीरे ब्रिटिश कर्मचारियों को भारतीय परिस्थिति के पूर्ण रूप से बदल जाने का भान हुआ और उन्होंने सरकारी नीति को उलटने की आवश्यकता अनुभव की। भविष्य में मुसलमानों की ओर से किसी संकट का भय नहीं था क्योंकि “विद्रोह (उनकी ओर से) प्रभुता पाने का अन्तिम प्रयत्न था और उसे पूरी तरह कुचल दिया गया था। भविष्य में केवल अपनी सक्ति के दल पर विद्रोह करने के लिये वे असमर्थ थे किन्तु प्रभावशाली वे अब भी थे। ऐसी दशा में उनके साथ सन्तुष्टापूर्ण व्यवहार छोड़ कर अब उन्हें अपने पक्ष में लेना अधिक उपयोगी था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, पूँजीवादी मध्यम वर्गों—मुख्यतः हिन्दुओं की ओर से अब राष्ट्रीयता का संकट दिखाई दे रहा था। बहुत से महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों ने, अंगरेजों और भारतीय मुसलमानों में मेल और मित्रता की आवश्यकता की ओर, सरकार और उच्चतर मुस्लिम वर्गों का ध्यान

१ Hunter . The Indian Mussalmans, page 206-7.

२ Mehta & Patwardhan . उद्यम पुस्तक, पृष्ठ १६

३ Mehta and Patwardhan : The Communal Triangle in India, page 96.

४ W. G. Smith : Modern Islam in India, page 196.

आकर्षित किया।<sup>१</sup> समस्त इन अधिकारियों में सबसे अधिक प्रभावशाली से सर विलियम हष्टरजिनकी पुस्तक 'दि इंडियन मुसलमान्स' सन् १८७१ में प्रकाशित हुई थी। अन्तु, कारण चाहे जो कुछ हो परन्तु १८७० के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ और धीरे-धीरे मुसलमानों के साथ मित्रता की नींव रखी गई। भारत में आग्ल-मुस्लिम मित्रता के लिये प्रयत्न करने वालों में सर सैयद अहमद और अलीगढ़ के एम ए ओ कॉलेज के प्रिन्सिपल बेक सा नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सर सैयद अहमद के पूर्वज ईरानी सन्त थे जिनका मुगल दरबार में बड़ी मान और प्रभाव था। सैयद अहमद को अपने जीवन के आरम्भ में ही यह निश्चय हो गया था कि भारत का भविष्य जोन मुगल साम्राज्य के हाथों में नहीं बरू अंगरेजों के हाथ में है।<sup>२</sup> मुगल सम्राट के महा नीतरी करने के म्यान पर उन्होंने सन् १८३७ में कम्पनी की नीतरी शुरू की। विद्रोह के समय के बिजनौर में सदा बसीन थे। इस समय तक बेगुम योग्य जज और प्राच्य सम्बन्धी एक महाविद्वान के नाते काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। दिल्ली के मन्वरों सहहरों और उन की कारीगरों के सम्बन्ध में सैयद अहमद ने 'आमारे मनबिवाल' नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका एक प्राचीनी विद्वान ने अनुवाद किया था और इसकी ओर काफ़ी ध्यान आकर्षित हुआ था। विद्रोह के समय उन्होंने अंगरेजों का पूर्ण साथ दिया और बितने ही अंगरेजों के प्राण बचाये।

विद्रोह के बाद सर सैयद ने अबनत मुस्लिम समाज के पुनरुत्थान और आग्ल मुस्लिम मित्रता के लिये काम करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने शेष जीवन में इन दोहरे उद्देश्यों के लिये अनाधार-दृढ़ता और निष्ठा से काम किया। अरबी जाति के उद्धान के लिये उन्होंने सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा का प्रतिपादन किया—और इन दिशाओं में उनका काम इतना प्रख्यात है कि महा उनका विस्तृत वर्णन करना आवश्यक नहीं है। केवल यह कहना ही पर्याप्त होगा कि अपने मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिये उन्होंने जो काम किया, अलीगढ़ का मुस्लिम विद्वविद्यालय उनका म्यार्द स्मारक है।

१. "वे मुसलमान जिनके राजनीतिक उद्देश्य हमारे उद्देश्यों से तद्वृष थे"—  
Sir John Strachey : India, its Administration and Progress, page 308.

२. An Indian Mussalman : Indian Muslims and Muslim Politics—An Article in the Hindustan Review, January 1909, page 51.

विद्रोह के कुछ समय बाद सर सैयद ने अपने सह धर्मावलम्बियों के माथे से राजद्रोह का कलक मिटाने के उद्देश्य से लॉयल मुहम्मडन्स ऑव इंडिया (भारत के अपने उद्देश्य के लिये काम करते रहे। उन्हें यह बात बली भाति ज्ञात थी कि जब तक मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक वैर है तब तक भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति भक्ति नहीं होगी और उस समय तक ईसाई शासन भी उन्हें राज-भक्त नहीं समझेंगे।<sup>१</sup> अतः उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक मेल करने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य के लिये उन्होंने एक पुस्तिका लिखी और उसमें यह बताया कि इस्लाम के एक अध्यादेश के अनुसार इस्लाम भतावलम्बी यहूदियों और ईसाइयों के साथ भोजन कर सकते हैं। ईसाइयों के धर्म ग्रन्थ बाइबल पर उन्होंने एक टीका लिखी जिसका उद्देश्य मुसलमानों और ईसाइयों के पारस्परिक भ्रमों को दूर करना था। और जब सर विलियम हटर की पुस्तक प्रकाशित हुई तो सर सैयद ने 'पायोनियर' में प्रबल एवं प्रत्युक्ति पूर्ण लेख लिखे। जस्टिस शाह दीन का कहना है कि इन लेखों से "बहुत से अविश्वासी अधिकारियों को भी विरवास हुआ और मुसलमानों की राजभक्ति पर जो सन्देह के बादल थे, वे कुछ ही समय में दूर हो गये।"<sup>२</sup> उसके बाद जब अलीगढ़ का एम ए बो कालिज स्थापित किया गया तो सर सैयद ने उस समय (सन् १८८७ में) लॉर्ड लिटन के समक्ष एक सम्बोधन पत्र प्रस्तुत किया और अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया—प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान में मेल हो, भारतीय मुसलमान, ब्रिटिश सम्राट के अनुरूप तथा उपयोगी प्रजाजन हो, और उन्हें—विदेशी राज्य की दीनपूर्ण दासता के कारण नहीं वरन् सुशासन से प्राप्त होने वाले बागीर्वादी के बोध से—राजभक्ति की प्रेरणा मिले।<sup>३</sup> इस प्रकार सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों में राजभक्ति की भावना भरने के लिये और साथ ही उनके लिये अंगरेज शासक की कृपा प्राप्त करने के लिये, यथासम्भव प्रयत्न किया।

३

१८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय सभी विचारशील व्यक्तियों के समक्ष यह प्रश्न था—सर सैयद अहमद क्या करेंगे? क्या वह कांग्रेस में सम्मिलित होंगे अथवा वह अपने अनुयायियों के साथ अलग रह कर राष्ट्रीय मोर्चे में फूट डालेंगे? कुछ बागसी जन आशायुक्त थे। सन् १८९० में

१ Shah Din Sir Syed Ahmed as a Political Leader, page 423 Hindustan Review, December 1905.  
 २ उपयुक्त प्रति—पृष्ठ ४१४  
 ३. Hindustan Review, Jan. 1909, page 53.

हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई बात स्पष्ट नहीं होती। किन्तु यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हम लोग एक ही देश के निवासी हैं, हम सब के शासन एक ही है और दुर्मिस के कारण हम लोग समान रूप से कष्ट उठाते हैं।<sup>१</sup>

उक्त बातों के कारण यह आशा की जाती थी कि उन भारतीय नेताओं को जो भारतीय राष्ट्र बनाने के लिये और साथ ही जनता की आवश्यकताओं, इच्छाओं और शिकायतों को व्यक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंच बनाने के लिये प्रयत्नशील थे, सर सैयद अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किन्तु अपनी अगोचर मानूनूमि की अपेक्षा अपनी जाति के लिये उनका प्रेम प्रबल मिट्ट दृष्टा और वे केवल एक साल पहले की अपनी इस दृढ़ धारणा को भूल गये कि "पारस्परिक विरोध से दोनों ही का नाश और पतन होगा।" उन्होंने कांग्रेस से केवल असहयोग ही नहीं किया बरन् बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिल कर एक सन्त्रि रूप से विरोधी सत्ता की स्थापना भी की।

इस विच्छेद पूर्ण कृत्य के कारणों पर विस्तृत रूप से विवाद किया गया है। सर सैयद के समर्थकों ने इसका दायित्व कांग्रेस के प्रचार की उद्यता पर डाला है। मुसलमान पिछड़े हुए थे और स्वभाव से जल्दी ही उत्तेजित हो जाते थे और ऐसी दशा में कांग्रेस के विनाशवा और एक दूसरे खुले विद्रोह का डर था। उससे मुस्लिम समाज को और सारे राष्ट्र को क्षति पहुंचती। इन बातों के अतिरिक्त उक्त समर्थकों के अनुसार कांग्रेस कार्यक्रम में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी।<sup>२</sup> दूसरी ओर सर सैयद के विरोधियों ने उनके पृथक् रहने का दायित्व अधिक स्वायत्तपूर्ण कारणों पर डाला है। इन लोगों के अनुसार सर सैयद अपनी जाति के लोगों को सरकार का कृपापात्र बनाना चाहते थे, अपनी जाति को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक राबभक्त जताना चाहते थे, और राष्ट्र के स्थाई हितों को क्षति पहुंचाने की जोखिम उठा कर भी अपनी जाति के अलकालीन स्वार्थों को प्रोत्साहित करना चाहते थे।

सर सैयद के साथ अलीगढ़ के कालेज में मौलाना शिबली ने पंद्रह वर्ष तक काम

१ Eminent Mussalmans (Nateson), पृष्ठ ३३

२. यह सब है कि सर सैयद के अनुसार विभूद एव साधारण निर्वाचन व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त थी। जनवरी १८८३ में सी पी स्थानीय स्वशासन विधेयक पर विधान परिषद में उन्होंने अपने विचार विस्तारपूर्वक प्रकट किये और यह बताया कि इस प्रकार के निर्वाचन में बहुत से महत्वपूर्ण दोष होंगे। उनका अभिप्राय यह था कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का नाक निर्दोषन किया जावे। यह कहना गलत है कि उस समय उन की दृष्टि साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों पर थी।

विद्या और उन्हीं के सामने सर सैयद प्रगतिशील राष्ट्रवादी से बदल कर प्रतिनिधि-शील सम्प्रदानवादी बने। मौलाना शिबली स्वयं राष्ट्रवादी थे और यह एक दुर्लभ की बात है कि उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन के कारणों को प्रकट करना "हमारे उद्देश्य के लिये अनिवार्य" माना। जन्म, "मौलाना नाहिव के उस समय का रहने का चाहें जो कारण हो अब समय ने हमें उनका उत्तर दे दिया है। सर सैयद की राजनीति में परिवर्तन का दायित्व अलीगढ़ बालिज के तत्कालीन यूरोपियन प्रिन्सीपल को कूट नीति पर था।" इन बातों को डिसेम्बर १८९९ में प्रिन्सीपल बेक के मरने पर सर जान स्ट्रेचर ने लन्दन टाइम्स के अपने लेख में मूक भाव से स्वीकार किया — यह एक एम अगरेज का देहावासन है जो एक दूर देश में साम्राज्य निर्माण के कार्यों में मगल्य था। उनको मृत्यु अपने कर्तव्य पद पर खड़े हुए एक सैनिक की भाँति हुई है। मुसलमानों को आरम्भ में मि बेक पर मन्देह था और उन लोगों ने मि बेक को ब्रिटिश जेदिया समझ कर उनका विरोध किया किन्तु थोड़े ही समय में उसने अपनी सूझाई और निस्स्वार्थता से उनके विरवान को प्राप्त कर लिया।<sup>१</sup>

प्रिन्सीपल बेक को अपने साम्राज्यवादी काम में सफलता मिली। उन्होंने सर सैयद की बहवा कर उनके हृदय में यह विरवात जमा दिया कि आगल-मुस्लिम गठ-बधन में मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी और राष्ट्रवादियों के साथ मिलने से उनके दुःख और बढ फिर बढ जायेंगे। इनके अतिरिक्त सर सैयद को इस बात का भी दृढ़ विरवान दिया गया कि सरकार का समर्थन करने से उनकी जाति की अनीति जनता के लिये किम्वद नृविद्या मिलेगी। इस प्रकार उनके असाधारण प्रभाव द्वारा मुसलमानों को—विरोध कर उत्तर भारत के मुसलमानों की—बदले से दूर रखा गया।<sup>२</sup> एक भारतीय मुसलमान ने लिखा है — "आत्म में सहारे की आवश्यकता

१. मौलाना शिबली ने सर सैयद के बारे में लिखा है कि प्रगति ने उन्हें सारे भारत का नेता बनने की प्रतिभा दी थी। किन्तु उनके चारों ओर के जमावरण ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में मुसलमानों को दूर खींच लिया। "ऐसा क्यों हुआ?" इसका उत्तर असाधारण है। "केवल यही नहीं बरन इसका उत्तर हमारे उद्देश्य के लिये अनिवार्य हो सकता है।" Ashok Mehta and Achut Patwardhan *The Communal Triangle in India*, pages 23 and 24 से अनुवादित।

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६१.

४. Mehta & Patwardhan: *The Communal Triangle in India*, page 24

## मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ

हो सकती थी किन्तु अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य आ जाने पर भी मुसलमान इस बात का साहस न कर सके कि वे राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से चलें। सरकार की मनोवृत्ति से पूरी तरह परिचित होने पर वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि कांग्रेस में सम्मिलित होने से उनकी मुक्ति सम्भव नहीं थी। वर्ग स्वायत्त, अविश्वास, जातीय घृणा, सरकार के वृथापात्र बनने की अभिलाषा और अपना पयक अस्तित्व बनाये रखने की भावना के कारण मुसलमानों और कांग्रेस वालों के बीच एक चौड़ी खाई धनी रही।

सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे वर्ष सर सैयद न मुस्लिम शिखण कांग्रेस (बाद में सम्मेलन) की स्थापना की। शिक्षित मुसलमानों का ध्यान और अनुराग केन्द्रित करने के लिये और साथ ही उन्हें कांग्रेस और राजनीतिक आलोचना से दूर रखने के लिये इस सस्या के अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के ही दिना में किये जाते थे। सर सैयद और उनकी जाति की राजनीति थी ब्रिटिश सरकार का समर्थन, उसके साथ सक्रिय सहयोग, ब्रिटिश सत्ता के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन और सरकारी कामों पर आलोचना की निन्दा।

४

सन् १८५९ की पंजाब सैन्य पुनर्गठन कमेटी की भाषा के अनुसार देशी आदमियों का परस्पर सतुलन करने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने १८६१ में भारतीय सेना में सबसे पहली बार लागू किया। केवल सर सैयद का ही नहीं बल्कि सैन्य अधिकारियों का भी यह विश्वास था कि १८५७ के विद्रोह का बल विभिन्न प्रान्तों, सम्प्रदायों, समुदायों और जातियों के लोगों की एक्य भावना में निहित था—सब लोग सेना में घुल मिल कर रहते थे। भविष्य में ऐसे विद्रोहों की सम्भावना मिटा देने के उद्देश्य से भारतीय सेना को वर्ग आधार पर फिर से संगठित किया गया। किन्तु अपनी सास जमाने के उद्देश्य से सिविल शासन में उचित नीति को व्यवहार में लाना आवश्यक समझा गया। सरकारी पदों के लिये नियुक्ति करने में और राजभक्ति के आधार पर पुरस्कार और उपाधि वितरण करने में विद्रोह के बाद दशाब्दियों तक, साधारणतया कोई जातीय भेद भाव नहीं किया गया। सर एल्फ्रेड लॉयल ने लिखा है—“हमको अनिवार्य न्याय और उपयोगिता के आधार पर उचित नीति को व्यवहार में लाना चाहिये। भारत में सामयिक एवं अल्पकालीन पक्षपात के कारण हम उक्त आधार को बराबर तोड़-मरोड़ नहीं सकते।

किया जा चुका है। यहाँ उस सत्र में कुछ और लिखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। अब केवल इस बात का विवरण करना शेष है कि १९०९ के सुधारों में मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की नीति किस प्रकार विवक्षित हुई।

५

जैसा कि पहले कहा जा चुका है १८८५-८६ में सर सैयद ने अविवाश मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने और शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिये प्रोत्साहित किया था। किन्तु अगले जीवन के अन्तिम दिनों में "सर सैयद ने कांग्रेस की माँगों के औचित्य को अनुभव किया। उन्होंने सरकारी परिपदों में अपने देश-वासियों की निम्न स्थिति को सीपेपन के साथ अनुभव किया यहाँ तक कि सुदूर भविष्य में भी शासकों और शासितों के बीच समान व्यवहार की बात उन्हें दुराशामान प्रतीत हुई।" इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उनके पुत्र सैयद महमूद से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे १८९२ में विवश बरके त्याग पत्र दिलाया गया था। अस्तु, कारण पाहे जो कुछ हो, सन् १८९३ में सर सैयद ने मुस्लिम हिन्दुओं के सरक्षण के लिये एक राजनीतिक सत्स्था स्थापित करना स्वीकार किया। इस सत्स्था का नाम था मुहम्मदन डिफेंस एसोसियेशन ऑफ अपर इंडिया। इसमें विभिन्न प्रान्तों के छठे हुए प्रतिनिधि लिये गये और सैयद महमूद तथा प्रिन्सीपल बेक इसके मंत्री बनाये गये। इस सत्स्था का उद्देश्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व द्वारा मुस्लिम हिन्दुओं की रक्षा करना और उनको प्रोत्साहित करना था। उसकी नीति भारत में ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ करने वाले उपायों का समर्थन करने की और मुसलमानों में राजमर्दिन की भावना फैलाने की थी—यह नीति आन्दोलन और राजनीतिक प्रचार के विह्वल थी। इस सत्स्था का मुख्य काम था मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई बनाये रखना और आगल मुस्लिम सहयोग को प्रोत्साहित करना। पि वेव के शब्दों में, "कांग्रेस का उद्देश्य देश की राजनीतिसत्ता को अंग्रेजों से हिन्दुओं को हस्तान्तरित करना है। उसकी मार्गें हैं—शास्त्र एकट को रद्द करना, सैन्य व्यय को घटाना और इस प्रकार सीमा प्रदेशीय मोर्चों को दुर्बल बनाना। इन माँगों के साथ मुसलमानों की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। इन आन्दोलन करने वालों से लड़ने के लिये और लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना रोकने के लिये अंग्रेजों और मुसलमानों का एक होना आवश्यक है। लोकतन्त्रीय शासन देश की आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के लिये अनुपयुक्त है। अतः हम सरकार के प्रति राजमर्दिन और आगल-मुस्लिम सहयोग का प्रतिपादन करते हैं।" १



देश के विभिन्न स्थानों में अन्य मुस्लिम समस्याएँ—जैसे अजुमने इस्लामिया और दग मेन्स मुहम्मदन एनोमिनेशन— अस्तित्व में आ गई थी। यद्यपि ये समस्याएँ राजनीतिक मामलों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेती थीं किन्तु वे मुख्यतः अराजकीय थीं। अलीगढ़ और अन्य भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाये हुए मुस्लिम काफ़ीरों की ही टक्की एक नियमित राजनीतिक समस्या की आवश्यकता अनुभव करने लगे थे। सितम्बर १९०१ में सर मुहम्मद शफी ने लाहौर के 'ऑर्डर' में बड़े लेख लिखे और एक भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने के विचार का प्रतिपादन किया। उसी वर्ष (१९०१ में) मुसलमानों के अरिस्तो के दृष्टि के दिय प्रांतीय और अखिल भारतीय वापसिशन बनाने के लिये यू. पी. में मिशनरिज की गई। किन्तु ये विचार कार्यान्वित नहीं हुए। अन्त में १ अक्टूबर १९०६ में प्रसिद्ध मुस्लिम लिट मण्डल के सदस्यों ने शिमला में विचार विनिमय किया और उसके पल्लवकल्प दिनांक १९०६ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाई गई।

मौलाना मुहम्मद अली ने सन् १९०३ में बताया—और यह नेत्र पहलें भी प्रकट था—कि उस लिट मण्डल का अन्तिम अग्रज सूत्रधारों के निर्देशानुसार किया गया था।<sup>१</sup> अलीगढ़ कॉलेज के प्रिन्सिपल ऑर्गनोस्ट<sup>२</sup> के द्वारा व्यवस्था की गई थी और उन्होंने शिमला में वादसराय के निजी महाजन बनल टनरय म्मिथ के साथ लिट मण्डल के संगठन और वादसराय के समस्त प्रस्तुत किये जाने वाले निवेदन पत्र के सवर में सारी बातें निश्चित कर ली थीं। अलीगढ़ में सर सयद के उत्तराधिकारी नवाब मोहम्मि-उस-मुलक और राजमन्त्र मुसलमानों के नेताओं का १० अगस्त १९०६ के पत्र में उस बातों की सूचना दी गई। पत्र इस प्रकार था —

“महामहिम वादसराय के निजी महाजन बनल टनरय म्मिथ ने मुझे बताया है कि महामहिम मुस्लिम लिट मण्डल ने भेंट करने के लिये सहमत हैं। उन्होंने यह कहा है कि महामहिम ने भेंट करने की अनुमति मागने के लिये आवश्यक-

India, pages 59-60

१ Congress Presidential Address Indian Annual Register 1924 Vol. II Supplement page 27

२ अपने मग्ने से पहले प्रिन्सिपल वेक ने अपने उत्तराधिकारी के लिये प्रवचन कर दिया था और उस प्रकार वेक का पद सर सियोटोर मॉग्मिन की मिला जो बाद में भारत परिषद के सदस्य हुए। उस समय मॉग्मिन का स्थान ऑर्गनोस्ट ने लिया। यह अग्रज भी मि वेक की नाति मुस्लिम हितों का उपाही समर्थक था।

नुसार एक पत्र उनके पास भेज दिया जावे। इस सबब में मुझे कुछ बातें उपयुक्त मालूम होती हैं। उस नियमानुसार पत्र में कुछ प्रतिनिधि मुसलमानों के हस्ताक्षर होने चाहियें। स्वयं शिष्ट मंडल में सब प्रान्तों के प्रतिनिधि होने चाहियें। तीसरी बात निवेदन पत्र से संबंधित है। मेरा सुझाव यह है कि हम उस पत्र का आरम्भ राजभक्ति की गंभीर अभिव्यक्ति द्वारा करें। बाद में हम स्वशासन की दिशा में सरकारी प्रयत्न की सराहना करें किन्तु उसी सबब में हम अपना यह भय भी प्रकट कर दें कि निर्वाचन सिद्धान्त मुस्लिम अल्प सख्यका के हिन्दु के प्रतिकूल होगा। तदुपरान्त किनबपूर्वक यह संकेत किया जाना चाहिये कि मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिये धर्मानुसार प्रतिनिधित्व देने अथवा नाम निर्देशन करने की व्यवस्था की जावे। इसके अतिरिक्त हमें यह भी कहना चाहिये कि भारत जैसा देश में जमींदारों को उपयुक्त महत्व देना आवश्यक है।

व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि नामनिर्देशन की व्यवस्था का समर्थन करके मुसलमानों के लिये हितकर होगा—निर्वाचन पद्धति के प्रयोग करने का समय अभी नहीं आया है। निर्वाचन द्वारा मुसलमानों के लिये उचित अनुपात में सत्ता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होगा। दृष्टिकोण के सबब में मुझे स्पष्ट भूमि में रखा जावे। यह दृष्टिकोण आपकी ओर से व्यक्त होना चाहिये। आप लोगों के लिए प्रस्तावित निवेदन पत्र तैयार कर सकता हूँ, अथवा दोहरा सकता हूँ। यदि इस पत्र को बम्बई में भाषावद्ध किया जावे तब भी मैं उसे देख सकता हूँ क्योंकि जैसा कि आप परिचित हैं, ऐसी बातों को मैं उपयुक्त भाषा में लिखना अच्छी तरह जानता हूँ। कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखिये कि समय अधिक नहीं है और प्रबल संगठन करने के लिये हम शीघ्रता करनी चाहिये।<sup>१</sup>

इस पत्र के आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और हिंडू हाईनम आग का नेतृत्व में विभिन्न प्रान्तों के ३५ प्रभावशाली मुसलमानों के एक शिष्ट मंडल का संगठन किया गया और इस शिष्ट मंडल ने १ अक्टूबर १९०६ को शिमला में वाइसरॉय से भेंट की। निवेदन पत्र मि आर्क बोल्ड के अनुसार ही तैयार किया गया था और उसे मुख्यतः मि सैयद हुसैन बिलग्रामी और सर अली इमाम ने लिखा था और संभवतः वह प्रिन्सीपल आर्कबोल्ड द्वारा दोहराया गया था। १ अक्टूबर १९०६ को शिमला में लॉर्ड मिण्टो के समक्ष जो पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह एक सच्चा और महत्वपूर्ण लेख्य था। उस में मुस्लिम वर्ग की

से सम्बन्ध होगा, मुस्लिम हितों और राजनीतिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होगा।" वह वाक्यावली इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे विस्तार पूर्वक उद्धृत करना उपयुक्त होगा। वाइसरॉय ने कहा —

"मैं आपके सम्बोधन का सार यह समझ पाया हूँ कि किसी भी प्रतिनिधित्व व्यवस्था में जिस में निर्वाचन प्रणाली को अपनाया अब्दा बढ़ाया जावे, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक समाज के रूप में होना चाहिए। आपने इस बात का संकेत दिया है कि बहुत से वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों से मुसलमानों के चुने जाने की आशा नहीं की जा सकती। यदि संयोगवश वह चुन भी लिया जाता है तो वह एक विरोधी बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आप लोगों को यह भाग उचित है कि मुसलमानों की स्थिति उन की सरवा क्षति से न आकी जावे बल्कि उसका भाग उन की राजनीतिक महत्ता और साम्राज्य सेवा के आधार पर की जावे। मैं आप से पूर्णतः सहमत हूँ। कृपया मुझे प्रत्यक्ष न समझावेगा, मैं किसी साधन या व्यवस्था का निर्देश नहीं कर रहा। किंतु आप की भांति मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस महादेश की विभिन्न जातियों की धारणाओं और परम्पराओं से असंबद्ध निर्वाचन व्यवस्था का भविष्य कुटिलता और असफलता से भरा हुआ है।"

इस प्रकार भारत में सम्राट् के प्रतिनिधि ने साम्प्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। लॉर्ड मंटो की जीवनी में मौलिक उद्देश्य की एक महत्वपूर्ण वाक्य में इस प्रकार प्रकट किया गया है — "इस व्याख्यान ने निःसंदेह रूप से मुसलमानों की राजद्रोही दल में भर्ती होने से रोक दिया; उपद्रव के बादल मझरा रहे थे और उन दिनों इस रोक का असाधारण मूल्य था।"

भारत सरकार को अपनी प्रतिनिधित्व योजना बनाने में पूरे दो वर्ष लगे और इस योजना में मुसलमानों के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को

१. An Indian Mohammedan - British India, page 486

२. Buchan : Lord Minto, page 244

३. Buchan : Lord Minto, page 244 यह लॉर्ड मंटो के व्याख्यान के सम्बन्ध में लॉर्ड माले के मत का अमिलेख करना उचित होगा। उन्होंने कहा, "मुस्लिम विवाद में अब मैं आपका अनुसरण नहीं करूँगा। मैं आप को यह याद दिलाता हूँ कि उनके असाधारण अधिकारों के बारे में आपके व्याख्यान ने ही यह मुस्लिम होजा खड़ा कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा निर्णय सर्वोत्तम था।" (Recollections, Vol II, page 325) इसी अध्याय में आगे चल कर लॉर्ड माले के प्रस्ताव की चर्चा की गई है।

रूप दिया गया। भारतीय विधान परिषद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भारत सरकार ने १ अक्तूबर १९०८ को भारत मन्त्री के पास अपना राजपत्र भेजा और उसमें लिखा — “हमने मुसलमानों की मांगों और हिंदुओं के दृष्टिकोण पर भली गति ध्यान दिया है। हमारे विचार में मुसलमानों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें चार निर्वाचन स्थान प्रदान किये जावें और जब तक निर्वाचन के लिए उपयुक्त प्रबन्ध न हो तब तक पाचवें स्थान के लिये नाम निर्देशन दिया जावे। अप्रिवन्त मुस्लिम जनसंख्या वाले चार प्रान्तों को—अर्थात् बंगाल, पूर्वी बंगाल तथा आसाम पञ्जाब और यू. पी. को—उक्त चार निर्वाचन-स्थान स्थायी रूप से प्रदान कर दिये जावें और पाचवें स्थान को पूर्णतः यथाक्रम सम्बद्ध और मद्रास में की जावे क्योंकि इन प्रान्तों में मुस्लिम जनसंख्या कम है।”<sup>१</sup> भारत सरकार के मतानुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में सभी प्रान्तों के लिए एक ही व्यवस्था अपनाना सम्भव नहीं था। राजपत्र में कहा गया, “हमारा यह मत है कि जिन प्रान्तों में नियमित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव सम्भव है, वहां उस व्यवस्था को अपना लिया जावे जहां निर्वाचन क्षेत्र नहीं बन सकते वहां मुस्लिम संख्याओं से लाभ उठाया जावे, और जहां उपर्युक्त दोनों बातें सम्भव न हों वहां सरकार नाम निर्देशन करे।”<sup>२</sup> प्रान्तीय परिषदों के लिए मुसलमानों को कुछ स्थान प्रदान दिए गए थे। इन के लिए भी पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गयी और निर्दिष्ट मालगुजारी अथवा आय-कर देने वालों को अथवा भारतीय विद्वत्विद्यालयों के पाच वर्ष में अधिक अवधि के निवन्धित स्नातकों को मताधिकार दिया गया।

मुसलमानों और जमींदारों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में लॉर्ड मॉर्ले ने भारत सरकार की योजना का अनुमोदन नहीं किया। भारतीय विधान मंडल के सम्बन्ध में अन्य जातियों के लिए प्रान्तीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों के लिए चुगी और जिला मंडलों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था थी। लॉर्ड मॉर्ले ने २७ नवम्बर १९०८ के अपने राजपत्र में इन प्रस्तावों का कई कारणों से विरोध किया। एक कारण तो यह था—और यह आपत्ति भारतीय राष्ट्रवादियों को भी थी—कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई अधिकारधिक चौड़ी होती जायगी। इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री की दो मुख्य आपत्तियाँ और थी। एक तो यह कि भारत सरकार के प्रस्तावों

१. Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 293.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४.

ने हिन्दुओं और मुसलमानों में द्वेषपूर्ण भेदभाव किया था, और दूसरा यह कि बहुत सी स्थितियों में मुसलमानों को दुहरा मताधिकार दिया गया था। इन दोनों को दूर करने के उद्देश्य से लॉर्ड मॉल्ले ने विभिन्न जातियों और वर्गों के अल्पसंख्यकों के चुनाव के लिए एक संयुक्त निर्वाचन मंडल की योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में विभिन्न जातियों और वर्गों के अनुपातानुसार उन्हीं विभिन्न जातियों और वर्गों के चुन हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन मंडल बनाने का प्रस्ताव किया गया। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि किसी निश्चित स्थान से तीन हिंदू और एक मुस्लिम प्रतिनिधि चुन कर भेजे जाने थे। ऐसी दशा में उपर्युक्त योजना के अनुसार तीन और एक के अनुपात में ७५ हिंदुओं और २५ मुसलमानों का निर्वाचन मंडल बनाया जा सकता था। इस मंडल की बनाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जैसे (१) निश्चित रकम से अधिक मालमजदारी देने वाले जमींदारों (२) ग्राम्य अथवा तहसील मंडलों के सदस्यों, (३) जिला मंडलों के सदस्यों (४) और नगरपालिका संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, इन क्षेत्रों के लिए निश्चित संख्या के अनुसार प्रतिनिधि चुनवाने की व्यवस्था थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों से बहुमत पाने वाले ७५ हिंदू और २५ मुसलमान चुने जाने थे। निर्वाचित मुसलमानों की संख्या २५ से कम होने की दशा में नाम निर्देशन द्वारा कमी को पूरा करने की व्यवस्था थी।<sup>१</sup> निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार था। इस प्रकार उपर्युक्त योजना के फलस्वरूप एक मुस्लिम और तीन हिंदू सदस्य चुने जा सकते थे।

लॉर्ड मॉल्ले ने अपनी इस योजना को भारत सरकार के समक्ष रखा और इस सम्बन्ध में उन्होंने ये ध्यान देने के योग्य शब्द लिखे — “यह सच है कि इस योजना में प्रारम्भिक निर्वाचक और अन्तिम रूप से निर्वाचित व्यक्ति के बीच बहुत बड़ी दूरी है, मायों ही यह पद्धति सरल प्रतीत नहीं होती। परन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए इसमें सरलतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। एक वोट की प्रणाली इस योजना को अनिवार्य अंग है, उसे सनोपप्रद रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है और निर्वाचक उसे समझ सकते हैं। साथ ही इस योजना में कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। इस योजना में सभी सम्बन्धित वर्गों सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रहेंगे और हिंदुओं की आलोचना का आधार मिट जावेगा—, दूसरी बात यह है कि इस योजना में एक ऐसे सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि उसके द्वारा विशेष वर्गों और संस्थाओं की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मांग का सामना किया जा सकता है,

उम वर्ष लीग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण त्यागपत्र देकर अलग हो गये ।

कांग्रेस की भांति अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी विभिन्न प्रान्तों में और साथ ही लन्दन में शाखाएँ बनाई गईं । लन्दन शाखा के अध्यक्ष ये सर सैयद अमीर अली । सविधान में लीग के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया —  
“(१) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावनाओं को बढ़ाना और सरकार के उद्देश्य तथा उस की नीति के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम पूर्ण धारणा हो तो उसे दूर करना, (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष मृदु भाषा में प्रस्तुत करना, (३) पहले दोनों उद्देश्यों को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये मुसलमानों और भारत की अन्य जातियों में मित्रता की भावनाओं का प्रसार करना ।”<sup>१</sup>

इस प्रकार लीग एक राजभक्त सस्था थी जिसका सगठन सरकार के समक्ष मुसलमानों की विशेष माँगें प्रस्तुत करने के लिए किया गया था । पहले दो वर्षों (१९०६ और १९०७) में लीग की केन्द्रीय समिति और प्रान्तीय शाखाओं ने अपने प्रस्तावों में केवल एक राग अलाप था और वह यह था कि मुसलमानों के हित में सरकारी उपहारों—नौकरियों और पदों—के प्रचुर वितरण का अनुग्रह किया जावे ।<sup>२</sup> परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, लीग का दृष्टिकोण अधिकाधिक स्वतन्त्र होना गया और वह माँगें पूरी न की जाने की दशा में अभक्ति के लिए धनकी भी देने लगी । सन् १९०८ में सर सैयद अली इमाम ने समापति के पद से अपने भाषण में शिक्षित मुसलमानों की ओर से कहा, “मान्भूमि के लिये हमारा प्रेम और आदर किसी से कम नहीं है ।” उन्होंने यह भी कहा कि व्यावहारिक राजनीति के महावपूर्ण प्रश्नों पर कांग्रेस और लीग में कोई भेद नहीं है ।<sup>३</sup> अन्तर मुत्स्यत उद्देश्य

१ Hindustan Review, April 1909, pages 346-347.

२ Hindustan Review, April 1909, page 350

३. उन्होंने १४ बातों की सूची दी —(१) न्यायपालिका और कार्यवाहिकी का पृथक्करण, (२) अपमानजनक और निवेष्टिक अभ्यादेशों का खंडन, (३) प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, (४) सार्वजनिक नौकरियों के उच्च पदों पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति, (५) समाजार्जन की व्यवस्था, (६) स्थानीय स्वशासन में सरकारी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग, (७) सैन्य व्यय में उचित कमी, (८) भारत की सामरिक जातियों के लिए स्वयं सेवकों की भांति लड़ने के अधिकार की मान्यता, (९) भारतीयों की सैनिक अफसरों के पदा पर नियुक्ति; (१०) होम चार्ज का समुचित

और पद्धति में था। कांग्रेस अधिवेशनिक दल पर स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी लोग प्रशासनिक सुधारों की मांग में मनुष्ट थी और वह चाहती थी कि एक उदार व्यवस्था में शिक्षित नागरिकों की स्वतंत्रता का वादा मिलाए में पूर्ण हों।<sup>१</sup> इस सम्बन्ध में मर जेम्स टमाम न कहा — क्या इन स्वशासन के आदर्शों ने लोगों को उत्तेजित नहीं कर दिया है ? उनके कारण लोगों में अर्थर्य आ गया है। मनुष्ट के अनाव में उन्नता आ गई है और इन उन्नता ने अराजकता, वम, गुप्त ममनियों और ह्दयों को जन्म दिया है।<sup>२</sup> इन लोग ने अपने लिए एक नम्र आदर्श निश्चित किया और शान्तिपूर्ण उन्नता का अपनाया।”

किन्तु साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनमें बड़ी बठोर नीति अपनाई और मार्गें पूरी न की जान का दगा में राजमन्त्रि और समर्थन की नीति छोड़ देन की धमकी दी। लोग न मयुक्त निर्वाचन मंडल की यात्रता का विरोध किया और विरुद्ध रूप में साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के दिए जोर दिया। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड और भारत में मर और पत्रों का सहामता में एक बड़ आन्दोलन का संगठन किया गया।<sup>३</sup> इंग्लैंड में मि अमोर जेम्स और मेजर मंथर हसन विरुद्धियों न लॉर्ड मॉर्ले को अपने पक्ष में लाने का उद्देश्य में लन्दन टाइम्स में पत्र लिखे। लेकिन जब इन पत्रों का कोई प्रभाव नहा हुआ तो एक डिप्टमटन का संगठन किया गया और उनमें भारत मन्त्री में भेंट की। लॉर्ड मॉर्ले का उत्तर कूट नीति पूर्ण था और उस में कोई बात निश्चित नहीं हाती थी। लॉर्ड मॉर्ले के अस्पष्ट आश्वासन से मनुष्ट न होने के कारण अखिल भारतीय मुस्लिम लीग फिर लॉर्ड मॉर्ले के पाम पहुँची।<sup>४</sup> और उसके समर्थन वही निवेदन किया जो लन्दन में लॉर्ड मॉर्ले के मामने किया जा चुका था। इस भेंट में लोग को सफलता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने मुस्लिम मार्गों का समर्थन किया, भारत मन्त्री म्रुव गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की योजना को स्वीकार कर लिया।

विभाजन, (११) मालगुजारी की सीमा, (१२) ग्राम समितियों की स्थापना, (१३) भारतीय शिक्षा और वधों का संरक्षण और उनका प्रोत्साहन, (१४) नासकों और नास्तियों के बीच समान व्यवहार। *Hindustan Review* April 1909 pages 350-351 में अनुवादित।

१. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ २५१.

२. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ २५४.

३. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ २५६.

एक ओर तो मुसलमानों की नई साम्प्रदायिक सत्ता पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग पर जोर दे रही थी और दूसरी ओर देश के राष्ट्रवादी—हिन्दू आर मुसलमान—नेता तथा समाचार-पत्र उसका प्रबल विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय और श्री सी बार्ड ज़िन्तामणि<sup>१</sup> दोनों ने बड़ी योग्यता के साथ राष्ट्रवादी पक्ष को प्रस्तुत किया और मुस्लिम मानों के अनौचित्य और उनकी कुटिलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धान्त को स्वीकार करने और साथ ही अल्पसंख्यकों को उनकी सच्चा शक्ति से अधिक प्रतिनिधित्व देने के दुष्परिणामों को बताया। कुछ देशभक्त मुसलमानों ने भी इन लोगों का समर्थन किया। सन् १९०८ में नवाब सादिक अली खा, वॉरिस्टर ने लखनऊ में कहा “इस योजना में वर्ण और धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त अत्यन्त कुटिलतापूर्ण है। मुसलमानों को यह सिद्धान्त ठीक नहीं है कि उनके और हिन्दुओं के राजनीतिक हित भिन्न हैं। मेरी अपनी सम्मति यह है कि स्वयं मुसलमानों के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धान्त कुटिलतापूर्ण है।”<sup>२</sup> उसी अवसर पर एक दूसरे मुसलमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा “भारत में एक राष्ट्र बनाने के प्रयत्न को निष्फल करने के उद्देश्य से यह कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। इस व्यवस्था से पारस्परिक विच्छेद को प्रोत्साहन मिलेगा दूसरी ओर सयुक्त क्षेत्र से निर्वाचित होने की दशा में पारस्परिक सम्पर्क घनिष्ठतर होगा।”<sup>३</sup> सन् १९११ में मि रैमंडे मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा —“मुस्लिम समाज के कुछ दूरदर्शी सदस्य अब इस बात को अवगत करने लगे हैं कि उनसे प्रतीती हो गई है। उनमें से कुछ लोगों ने बड़े तीक्ष्ण के साथ मुझे यह बताया कि किन प्रकार उनके कुछ नेताओं ने जागल-भाख्तीय अधिकारियों द्वारा रचे हुए अभिनय में सहयोग प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थी, अन्य कुछ लोग इस मत के हैं कि जो कुछ हुआ वह ठीक है लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी यह बोध हो रहा है कि आगे सतरा है और वे यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी लम्बी चौड़ी मार्ग न की होनी तो ज्यादा अच्छा होता।”<sup>४</sup>

मुसलमानों में चाहे जो मतभेद हो कि लोग की नीति बुद्धिमत्तापूर्ण थी अथवा

१ Hindustan Review, April 1909, page 320 to 336

२ उपर्युक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२३

३ उपर्युक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२४.

४ Macdonald The Awakening of India, page 129



नहीं किन्तु इन बातों में सभी नागरिक सहमत थे कि लोगों को एक होने में रोड़ने के लिये ब्रिटिश जनवादीतन्त्र ने बड़ी सहायता की चाहे चरम धर्म और इस प्रकार मुसलमानों को उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता में वञ्चित कर दिया था। अक्टूबर १९०९ के 'हिन्दुस्तान रिव्यू' में एक नागरिक मनमन्थन ने लिखा है—“हमें जाति-वादियों का मान में एक अवसर दृष्टि करना का प्रयत्न करना नहीं है।” उसी लेखक ने इस अवसर में यह सुझाव प्रकट किया—“इस प्रयत्न में यूनान की पौराणिक साधारणों के पंडितों का दर्शन्य पितामह मूल जाइंग और मान को एक दृष्टि अतिर ओर समान परिस्थिति का मानना करना पड़ेगा।”<sup>१</sup>

---

१. मि. मैकडोमल्टे लिखते हैं :—“यह कहना कठिन है कि जिनके अधिकांशिकों में इस भाँति की जान बूझ कर, कुछ काल कर गम्य करने के कृत्रिम उद्देश्य से अपनाया गया भारत की लोक-समस्या के वास्तव और असली भावों के प्रत्यक्ष अनुमान न कर सकने की दशा में यह उनकी एक अवसर मूल थी। लॉर्ड मिंटो के व्याख्यानों, उत्तर में लॉर्ड मॉन्टे के व्याख्यानों और सम्पूर्ण विरोधी राजपक्षी के उद्योग पर सभी प्रकार पढ़ना बाकी है।”—*The Awakening of India*, page 176

२. *Hindustan Review*, April 1909, page 357.

## सोलहवां अध्याय मॉर्ले-मिण्टो सुधार

१

भारत के नरम दली नेताओं ने मॉर्ले मिण्टी सुधारों का सोलहाह स्वागत किया लेकिन १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्न विनियमों की दिनाम्बर, १९०९ के क्राइस अधिवेशन में भी आलोचना की गई। इन विनियमों को १५ नवम्बर १९०९ के सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में रूप दिया गया था। उन पर अपना मत प्रकट करते हुए सर मुन्टरनाथ जेज्जी ने कहा 'इन नियमों और विनियमों ने सुधारों की यात्रा को बहुत निरवकाश कर दिया है।' <sup>१</sup> अस्तु, सुधारों—एक और विनियमों—के गुणों और दोषों का विश्लेषण करने में पहले स्वयं सुधारों की रूपरेखा का परीक्षण करना उपयुक्त होगा।

२

साहं मॉर्ले और मिण्टो के नामों से सम्बन्धित पहला महत्वपूर्ण सुधार यह था कि भारत मंत्री और वाइसरॉय, दोनों की परिषदों में भारतवासियों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी।

वाइसरॉय की कार्यवाहिकी परिषद् में किसी भारतीय को नियुक्त करने का प्रश्न पर माई १९०६ मॉर्ले मिण्टी ने अपनी परिषद् के कुछ सदस्यों के साथ सबसे पहली बार विचार किया था। वाइसरॉय ने सुधारों से सम्बन्धित समझौते से भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा। कमेटी के आठ सदस्य पक्ष में और आठ सदस्य विपक्ष में थे। लेकिन परिषद् में इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध हुआ—केवल एक सदस्य ने उसके पक्ष में अपना मत दिया। (किन्तु इसमें सर भी वाइसरॉय अपने मत पर दृढ़ रहे क्योंकि उनकी सम्पत्ति में निराश्रितों के विरोध का आना अत्यन्त तकोर्ण था। इन लोगों के अनुसार "अमाधारण उत्तरदायित्व के पक्ष पर किसी देशी आदमी का विश्वास करना अत्यन्त जायजपूर्ण था।" <sup>२</sup> इसके अतिरिक्त लॉर्ड मिण्टो ने सरकारी विरोध को विशेष महत्व नहीं दिया लेकिन इसी और परिषद् में भारतीय सदस्य की नियुक्ति न होना को दया में उन्हें देखो

१ Mrs. Besant How India Wrought for Freedom, page 495

२ लॉर्ड रिचमंड और सर डेविड इबेर्टसन ने प्रबल विरोध किया था।

३ Buchan Lord Minto, page 253

आन्दोलन का डर था। इस सम्बन्ध में भारत मंत्री और इम्प्लेंट के अन्य राजमन्त्री भारत परिषद् तथा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य और लॉर्ड रिपन तथा लॉर्ड एलिग्न जैसे व्यक्तियों की सम्मतियों की अपेक्षा करने का तयार नहीं था।<sup>१</sup> लॉर्ड मॉर्ले ने लॉर्ड मिंटो को लिखा “भारतीय सदस्य के सम्बन्ध में मुख्य विचारणीय बात है आपकी और मेरी परिषद् के सदस्य का दृष्टिकोण,<sup>२</sup> और दूसरी बात है आग्ल भारतीय कोष और भय के विकास की जोखिम।<sup>३</sup> लेकिन जुलाई १९०७ में लॉर्ड मॉर्ले ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पग बढ़ाने का निश्चय किया और अपनी परिषद् में एक या दो भारतीयों को नियुक्त करने का अपना उद्देश्य प्रकट किया। इसी विचार में अगस्त १९०७ में एक एकट द्वारा भारत परिषद् के मविधान में संशोधन किया गया और उम्मी मान में भारत परिषद् के लिए दो भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिए गए। ये सदस्य थे मि० एम० क० गुप्त और मैयद हसेन विल्ग्रामी। मि० गुप्त मित्राल सविन के सदस्य थे और मि० विलग्रामी एक योग्य, चालाक और राजभक्त व्यक्ति था।<sup>४</sup> अक्टूबर १९०६ को वाइसरॉय के समक्ष मुस्लिम शिष्ट मटल ने जा निवेदनपत्र प्रस्तुत किया था मि० विल्ग्रामी उनके लेखक थे और नियुक्ति के समय वे हंटराबाद के निजाम के प्रमुख परामर्शदाता थे।

लॉर्ड मॉर्ले ने अपनी परिषद् में दो भारतीयों की नियुक्ति को विशेष महत्व दिया। वाइसरॉय की कार्यकारिणी के लिए भारतीय सदस्य नियुक्त करना इसी दिशा में अगला कदम था और अब केवल समय का प्रश्न था।<sup>५</sup> अस्तु, २४ मार्च

१ लॉर्ड रिपन और लॉर्ड एलिग्न का विरोध इस आधार पर था कि भारतीय सदस्य स सैनिक और विदेशी भेदगुण न रह सकेंगे।

२ भारत परिषद् ने एकमत से इस प्रस्ताव का विरोध किया था।

३ Morley Recollections, Vol II, page 212.

४ लॉर्ड मॉर्ले ने अपनी परिषद् में दो भारतीयों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में १८ जुलाई १९०७ को लॉर्ड मिंटो को एक पत्र में बताया कि वाइसरॉय की परिषद् में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की दिशा में यह पहला कदम था। देखिये Morley Recollections, Vol. II, page 226

भारतीय दृष्टिकोण का हिन्दुस्तान रिव्यू (सितम्बर १९०७) में इस प्रकार व्यक्त किया गया—भारतीय जनमत और भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए एक दिशावादी किया गया है। दाहिने हाथ से जो दिया गया है उसे बाएँ हाथ से ले लिया गया है। वेस्टमिंस्टर के आग्ल-भारतीय मंदिर में उन लोगों का प्रवेश नहीं है जो भाग्य सरकार की हा में हा नहीं मिला

## माल मिष्टो सुधार

१९०९ को बंगाल के तत्कालीन महाधिवक्ता मि० एस० पी० सिन्हा की भारत सरकार का विधि सन्म्य निरुक्त किया गया। मि० सिन्हा बाद में सर सचिव और जतम लाइ सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हुए।

यह समझना गलत होगा कि इस निरुक्ति का विरोध नहीं हुआ जब १७ मि० १००८ को लाइ माउ न लाइ भवन में वाइसराय को कार्याकारिणी के लिए स्थान रिक्त होने पर किसी भारतीय को नियुक्ति करने के लिए अपना उद्देश्य पहली बार प्रकट किया तो उसका प्रबल विरोध किया गया इस पर लाइ माउ न वाइसराय को लिखा — यह सौभाग्य की बात है कि आपकी कार्याकारिणी में भारतीय सन्म्य नियुक्त करने के लिए मुक्त पारित्यामण की स्वीकृति प्राप्त करने की घटानिव आवश्यकता नहीं है म इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि लाइ भवन में स्वीकृति नहीं मिल सकती।

वाइसराय की कार्याकारिणी में एक भारतीय सन्म्य की नियुक्ति का विरोध केवल आंग्ल भारतीयों अधिकारियों और भारत मंत्री तथा वाइसराय का परिपक्षों के साथ ही नहीं किया बरन भारतीय मसलमानान भी किया। उन्हें इस बात का शर था कि यदि केवल एक भारतीय की नियुक्ति की गई तो वह व्यक्ति अवश्य ही हिंदू होगा। एक मुस्लिम गिण्टमडल ने भारत मंत्री से भ्रम की और दो भारतीयों की नियुक्ति के लिए मांग की ताकि उनमें से एक मुसलमान नियुक्त हो। लाइ माउ के मतानुसार यह प्रस्ताव अव्यवहार्य था—क्योंकि उस दशा में अग्रजों का अनपात आपत्तिजनक रूप से घट जान का भय था— और यह एक भवन्त गम्भार परिवर्तन था।

३

मन् १९०९ ने भारतीय परिषद् एकत का दूसरा मह बपूण सुधार, भारत का विभिन्न विभाग परिषदों से सम्बन्धित था।

यह सम्बन्ध में एक न पहली बात तो यह की कि उनमें प्रत्येक विभाग परिषद

मजने। इस समिति के लिए दत्त और गावले की तो बात ही क्या महान यह तब कि अमार अन्नी भा उपयोग सन्म्य न हो सकने। जिन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया उनसे विज्ञा प्रकार की धनि की आगवा नहा है तथापि एक विषय विधायक स्वीकार किया गया है परिषद की सन्म्य बनाई गई है ताकि विज्ञा अग्रज को भारताय के लिए अपना स्थान न छोड़ना पड।

१ Morley Recollections Vol II page 93

२ Indian Speeches of John Morley page 265

की सत्ता-शक्ति को बढ़ा दिया। एक्ट के विनियमों ने उनकी सत्ता इस प्रकार निश्चित की—महात्तीय विधान परिषद्, ६९, बंगाल विधान परिषद्, ५२, मद्रास, बम्बई और यू. पी.—प्रत्येक की विधान परिषद्, ४३; पूर्वी बंगाल तथा आसाम की विधान परिषद्, ८१, पंजाब विधान परिषद्, २५; बर्मा विधान परिषद् १९।<sup>१</sup> सन् १९११ में जब बंग नग रद्द किया गया<sup>२</sup> तो बंगाल के अतिरिक्त दो अन्य प्रान्त बनाए गए। इस परिवर्तन के बाद इन प्रान्तों की विधान परिषदों की सत्ता इस प्रकार थी—बंगाल, ५२, बिहार तथा उड़ीसा, ८६, और आसाम, २५। इनके अतिरिक्त सरकार के अध्यक्ष का प्रान्तीय विधान परिषद् के लिए विशिष्ट विधान कार्य में परामर्श देने के उद्देश्य से एक या दो विशेषज्ञों का नाम निर्देशन करने का अधिकार दिया गया।

प्रत्येक विधान परिषद् में तीन प्रकार के—(१) सरकारी, (२) निर्वाचित, और (३) नाम निर्देशन सदस्यकारी—सदस्य थे। उनकी कुलसंख्या सत्ता निम्न तालिका में व्यक्त की गई है। संख्याएँ सन् १९१२ के आधार पर हैं और उनमें सरकार के अध्यक्ष अथवा विशेषज्ञों की गणना नहीं की गई है।

विधान परिषद् का नाम	निर्वाचित सदस्य	नाम निर्देशित सरकारी सदस्य	सरकारी सदस्य	कुल संख्या
भारतीय				
मद्रास	२७	५	३६	६८
बम्बई	२१	५	२०	६६
बंगाल	२८	७	१८	६६
यू. पी.	२१	६	२०	५७
पूर्वी बंगाल तथा आसाम	१८	५	२०	४३
पंजाब	८	५	१३	६०
बर्मा	१	६	१०	२६
बिहार तथा उड़ीसा	१	८	६	१५
आसाम	२१	६	१८	४३
	११	४	९	२४

१. सन् १९०५ में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसे सन् १९११ में रद्द कर दिया गया और प्रान्तीय संसदों को फिर से निश्चित किया गया और तीन प्रान्त बनाए गए—(१) बंगाल; (२) आसाम, और (३) बिहार तथा उड़ीसा।

२. सन् १९०९ से पढ़ते परिषदों की संख्या इस प्रकार थी—महात्तीय

## मॉलें मिष्टो सुधार

सम्राज्यीय विधान परिषद् के सम्बन्ध में भारत सरकार का मौलिक प्रस्ताव यह था कि उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बराबर रखी जाय, ऐसी दशा में वादसराय अपनी वोट से पलड़ा झुका सकता था। किंतु भारत मन्त्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने केन्द्र में सरकारी बहुमत बनाए रखना आवश्यक समझा। हाँ, प्रांतीय विधान परिषदों के सम्बन्ध में लॉर्ड मॉलें ने भारत सरकार को सरकारी बहुमत का विचार छोड़ देने की सलाह अवश्य दी। लेकिन इसने दो कारण थे। पहली बात तो यह थी कि इन परिषदों के अधिकार बहुत सीमित थे और दूसरी बात यह थी कि प्रांतों के सरकारी अध्यापकों को इन परिषदों द्वारा स्वीकार किए हुए विधेयकों को निर्णय कर देने का अधिकार मिला हुआ था। तथापि निर्वाचित सदस्यों को केवल बगाल में ही बहुमत प्राप्त हुआ।

विनियमों में, नामनिर्देशित (गैर सरकारी) सदस्यों के सम्बन्ध में कोई विशेष अहंता निश्चित नहीं की गई। कुछ ऐसे हित थे जिन्हें निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता था अथवा जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। नाम निर्देशन का उद्देश्य ऐसे हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इसी दृष्टि से सम्राज्यीय विधान परिषद् के लिए यह निश्चित किया गया कि नाम-निर्देशित सदस्यों में एक व्यक्ति भारतीय व्यावसायिक समुदाय का प्रतिनिधि होना चाहिए, एक पंजाब का मुसलमान होना चाहिए और एक पंजाब का जमींदार होना चाहिए। सरकारी व्यक्तियों में कुछ लोग पदेन सदस्य होने थे और अन्य सदस्य सरकार के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाते थे। पदेन सदस्यों में सरकार के अध्यक्ष और कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की गणना थी। किंतु निर्वाचित सदस्यों के संबंध में बहुत स नियमों को बड़े परिश्रम के साथ बनाया गया—उन पर पृथक् रूप से विचार करना उपयुक्त होगा।

विनियमों में प्रत्येक विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट कर दिया था और यह संख्या वर्गों में १ से लेकर बगाल में २६ तक थी—जो बाद में बढ़ाकर २८ कर दी गई।<sup>१</sup> इन सदस्यों का प्रादेशिक क्षेत्रों में तो बहुत सीमित रूप में निर्वाचन होता था। भारत सरकार के अनुसार भारत की परिस्थितियों परिचयी देशों की परिस्थितियों से भिन्न थी और इस कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद्, २५, मद्रास, २४, बम्बई, २४, बगाल, २१, पू० पी०, १६; पूर्वी बगाल तथा आसाम, १६, पंजाब, १०; और बर्मा, १०।

१. अन्य आंकड़ों के लिए इसी अध्याय का तीसरा खंड देखिए।

## मॉल-मिण्टो सुधार

भारत और पश्चिमी देशों में कोई अन्तर नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी और दृष्टि से भी भारत और पश्चिमी देशों में और कोई ऐसा मौलिक अन्तर भी नहीं था जिसका तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या पर प्रभाव हो। स्वयं पश्चिमी देशों में भूमि और अन्य कुछ हितों को बहुधा अपवाप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, और धार्मिक अल्पसंख्यका—जैसे यहूदिया और प्रोटेस्टेंट देशों में रोमन कैथोलिक मनावलम्बियों—को अपवाप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और उह कभी-कभी तो किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। और इन में से किसी भी देश न कभी भी वग और सम्प्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति को नहीं अपनाया। किन्तु भारत सरकार के नियमानुसार भारत का विराट् परिस्थितियों के लिए वग और सम्प्रदाय के आधार पर विराट् निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता थी।

सन १९०९ के एकट सम्बन्धी विनियमों में तीन प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे—(१) साधारण निर्वाचन क्षेत्र—इन में प्रांतीय विधान परिषदों के अध्यक्ष नगरपालिका और जिला मंडला के गैरसरकारी सदस्यों की गणना थी, (२) वग निर्वाचन क्षेत्र—इन में (अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों का तथा (ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की गणना थी और (३) विशेष निर्वाचन क्षेत्र—इन में नगर पालिका कार्पोरेशनों विश्वविद्यालयों जागिरदार मंडला तथा बन्दरगाह मंडला की ओर रोकक तथा व्यापारिक हितों की गणना थी।

सम्राज्यीय विधान परिषद के २३ निर्वाचित सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होता था—(१) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से १३ सदस्य (बंगाल बम्बई मद्रास और पंजाब—इन में से प्रत्येक प्रांत से दो सदस्य और पंजाब बिहार तथा उड़ीसा आसाम बर्मा और मध्य प्रांत—इन में से प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य) प्रतिनिधि प्रांतीय विधान परिषद के गैरसरकारी सदस्यों द्वारा चुन जायें। (२) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल बम्बई मद्रास पंजाब बिहार तथा उड़ीसा और मध्य प्रांत—इन में से प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य) ३, (३) पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल से दो ३ और

- १ मध्य प्रांत की विधान परिषद् १९१४ में बनी, उस से पहले नगरपालिका और जिला बोर्डों के ५० प्रतिनिधियों के निर्वाचन मंडल द्वारा सदस्य का चुनाव किया जाता था।
- २ पंजाब के जमींदारों में से एक व्यक्ति को नाम निर्देशन द्वारा वाइसरॉय नियुक्त करता था।
- ३ इनमें से एक सदस्य को विशेष मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता था,

मद्रास, बम्बई बिहार तथा उड़ीसा, और यू. पी., इन में से प्रत्येक प्रान्त में से एक सदस्य) (४) विधायनिर्वाचन क्षेत्रों में दो सदस्य (एक बंगाल के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि और एक बम्बई के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि)।<sup>१</sup>

इसी प्रकार प्रान्तीय विधान परिषदों के सदस्य तीन प्रकार के (साधारण, वग और विशेष) निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते थे। उदाहरण के लिए बम्बई को विधान परिषद की सीजिये। उन में निर्वाचन सदस्यों की कुछ संख्या २१ थी और उनका चुनाव दो प्रकार हुआ था—(१) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आठ सदस्य—प्रान्त के चार विभागों में से प्रत्येक में एक नगरपालिका मंडलों का प्रतिनिधि और एक जिला बोर्डों का प्रतिनिधि<sup>२</sup>, (२) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों से तीन सदस्य—दक्षिण के सरदारों का एक प्रतिनिधि, गुजरात के सरदारों का एक प्रतिनिधि और मिथ जमींदारों का तथा जमींदारों का एक प्रतिनिधि, (३) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में चार सदस्य—बम्बई नगर से एक, प्रान्त के दक्षिणी विभाग से एक, उत्तरी विभाग से एक और केन्द्रीय विभाग से एक, और (४) विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से छह सदस्य—बम्बई कापेरिगन का एक प्रतिनिधि, बम्बई विश्व विद्यालय का एक प्रतिनिधि, बम्बई तथा अहमदाबाद के मिल मालिकों के दो प्रतिनिधि और बम्बई तथा कराची के चम्बर्स ऑफ कामर्स (वाणिज्य मंडल तथा भारतीय व्यापारियों के दो प्रतिनिधि।

✓ विनियमों में (क) निर्वाचन के अर्हताओं और (ख) मतदाताओं के लिए अर्हताओं भी निर्दिष्ट की गई थी। "ऐसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन के लिए

दूसरे सदस्य को यथाक्रम बंगाल के मुस्लिम जमींदारों और बंगाल के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता था।

- १ पंजाब के लिए पाइमरॉय एक मुसलमान को नाम निर्देशित करता था।
- २ ये वाणिज्य मंडल यूरोपीय थे, भारतीय वाणिज्य समुदाय के सदस्य का पाइमरॉय द्वारा नाम निर्देशन होता था।

- ३ प्रत्येक नगरपालिका और जिला बोर्ड के गैरसरकारी सदस्य अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक विभाग अथवा जमिंदारों के दो निर्वाचन मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते थे। प्रत्येक निर्वाचन मंडल, प्रान्तीय परिषद के लिए एक सदस्य चुनता था। अन्य कुछ प्रान्तों में जैसे बंगाल में प्रतिनिधियों का चुनाव नगर पालिका बोर्ड अथवा जिला बोर्डों की कामदनी के अनुसार होता था। बम्बई में हर नगरपालिका बोर्ड को प्रति १०,००० आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि और हर जिला बोर्ड को प्रति १ लाख आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। विभागीय निर्वाचन मंडल इन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होता था।



अभ्यर्थी होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन नहीं हैं, अथवा (२) सरकारी अधिकारी हैं, अथवा (३) स्त्री हैं, अथवा (४) विकृत मस्तिष्क हैं, अथवा (५) २१ वर्ष से कम आय का हैं, अथवा (६) दिवालिया हैं, अथवा (७) सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हैं अथवा (८) किसी बट न्यायालय द्वारा, छे महीने से अधिक कारावास अथवा देशनिर्वासन के उपयुक्त अपराध के फलस्वरूप, दंडित हैं, अथवा अपने सद्ब्यवहार के लिए जमानत से बंधा हुआ हैं, अथवा (९) बकायत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया हैं, अथवा (१०) कुर्याति और पूर्व चरित के कारण गवर्नर-जनरल द्वारा सार्वजनिक द्वितीय दृष्टि से निर्वाचन के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।" इत म से पिछले चार अर्द्धताओं की परिषद गवर्नर-जनरल के आदेश द्वारा दूर किया जा सकता था। भारतवासियों ने इस विनियम की तीव्र आलोचना की क्योंकि उसके अनुसार पिछले (१९०५-१९०९) के आन्दोलन में भाग लेने वाले लोग परिषदों के चुनाव के लिए सह होन से वंचित कर दिए गए थे। इन सामान्य अर्द्धताओं के अतिरिक्त, वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष अर्द्धताएँ निश्चित की गई थी।

इसी प्रकार मतदाताओं की अर्द्धताएँ निश्चित की गई थी। उनके अनुसार स्त्रियों, अल्पवयस्कों और विकृत मस्तिष्क के व्यक्तियों को किसी भी निर्वाचन में वोट देने का अधिकार नहीं था। (ब) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों और (ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक् रूप से अर्द्धताएँ निश्चित की गई थी।

(अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों की अर्द्धताएँ सम्प्रदायीय तथा प्रान्तीय परिषदों के लिए, हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए और विभिन्न प्रांतों के

१. विनियम न ४—देखिये Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol 1, pages 350-1.

२. सन् १९१४ के बाद अर्द्धता न (१) को भी स-परिषद गवर्नर-जनरल के आदेश से रद्द किया जा सकता है।

३. उदाहरण के लिए पूर्वी बंगाल की अर्द्धताओं को उद्धृत किया जाता है। "मताधिकार के लिए हिंदू जमींदार को ५०००) रु. मालगुजारी देने का नियम है लेकिन मुस्लिम जमींदारों को केवल ७५०) रु. मालगुजारी देने पर मताधिकार प्राप्त हो जाता है। हिंदू जमींदार को १२५० रु. उपहार देने पर मताधिकार मिलता है किन्तु मुस्लिम जमींदार को केवल १८८ रु. उपहार देने की आवश्यकता है। अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा आयकर देने वाले अथवा पेंशन पाने वाले मुसलमान को मताधिकार दिया गया है किन्तु हिंदुओं के लिए ये अर्द्धताएँ अन्यायपूर्ण हैं। मुसलमानों के साथ यह पक्षपात एक ऐसे प्रांत में है जहां वे

लिए विभिन्न थी। मराठाजीय परिषद् के लिए वही बड़े जमांदाज वोट दे सकते थे जिन को आय<sup>१</sup> एक निश्चित रकम में अधिक थी अथवा जो एक निश्चित रकम से अधिक मांगूझारी देने थे<sup>२</sup> अथवा जिन्हें उच्च उपाधियाँ मिली हई थी<sup>३</sup> अथवा जिन्हें अवैतनिक यशस्वी पद<sup>४</sup> प्राप्त थे। इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों के लिए मराठाजीय परिषदों की अपेक्षा कुछ नोची अहंताएँ निश्चित की गई थीं।

(ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की अहंताय भी मराठाजीय तथा प्रान्तीय परिषदों के लिए और विभिन्न प्रान्तों के लिए विभिन्न थी। उनमें से प्रत्येक का विवरण देना नभव नहीं किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रान्तीय परिषदों की अहंता मराठाजीय परिषद् के लिए मनमाना आ कीमत्या कम थी और उन मनमानाओं को सूची में उन लक्षणों की गणना थी जो निश्चित रकम में अधिक मांगूझारी देने थे अथवा प्रान्तीय परिषदों के सदस्य थे अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्य थे अथवा निश्चित अवधि में पढ़ने के स्नातक थे अथवा सरकारी पेशान पाते थे।

वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए अन्य अभ्यर्थियों की भाँति, उपयुक्त सामान्य अहंताओं के प्रतिनिधित्व, उनके वग विषयों की अहंतायें भी आवश्यक थीं।

इस विवरण को समाप्त करने में पहले कुछ अन्य बातों की ओर ध्यान दिलाना भी उपयुक्त होगा। स्वीकृत व्यवस्था में पहली बात तो यह थी कि परिषदों के सभी सदस्यों का अपना स्थान अंगीकार करने में पहले सम्राट् के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी, दूसरी बात यह थी कि सदस्यों का कार्यकाल मानागत तौर पर तीन वर्ष के लिए निश्चित था, तीसरी बात यह थी कि १९०९ के विनियमों में, भारत सरकार ने अपनी २८ अगस्त १९०७ की जानि और धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित योजना को रद्द नहीं दिया था; और अन्तिम बात यह थी कि १९०९ के एक्ट को व्यवहार में लाने के लिए जो विनियम बनाए गए थे वे लॉर्ड मिंटो के शब्दों में, "अन्यत् जटिल और असमपूर्ण थे।"<sup>५</sup>

बहुमूल्यक है।"—Macdonald : The Awakening of India, page 176

१. मद्रास में यह रकम १५००० रुपए थी।

२. साधारणतया यह रकम १०००० रुपए थी।

३. बंगाल में जिन लोगों को राजा और नवाब की उपाधियाँ प्राप्त थी उन्हें मताधिकार दिया गया था।

४. मध्यप्रान्त में अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी वोट दे सकते थे।

५. Quoted in R. S. Iyengar's Indian Constitution, page 155.

कारण यह था कि लॉर्ड मिटो के शब्दानुसार सरकार "सुधारों से लोक प्रतिनिधित्व को बर रखने के लिए बहुत चिन्तित थी। मैंने इस बात का भरसक प्रयत्न किया कि सुधारों से उसकी शलक भी न मिले। हम किसी भी प्रकार की ससद के पक्ष में नहीं हैं, हम परिपद् बनाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए हम ससद के ढग पर चुनाव के पक्ष में नहीं हैं।" १

दूसरे प्रकार नई परिपदों को जानबूझ कर दोषपूर्ण बनाया गया था ताकि सदस्यों की दृष्टि से भी उनमें और ब्रिटिश ससद (पार्लियामेंट) में कोई सादृश्य न हो। किन्तु इस से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारण एक और था। उसकी ओर पहले भी संकेत किया जा चुका है और उनकी शलक २४ अगस्त १९०७ के सरकारी लेख में भी मिलती है। २ वह कारण यह था कि "देशी आदमियों में परस्पर सतुलन बनाए रखने की नीति के" अनुसार, अंगरेज शासक, एकता की ओर प्रवृत्त भारतीय जनता को परस्पर असम्बद्ध विभागों में बांटना चाहते थे।

५

सन् १९०९ के भारतीय परिपद् एक्ट ने परिपदा के आकार और गैरसरकारी सदस्यों की सख्या में ही विस्तार नहीं किया बल्कि उसने भारत की विभिन्न सरकारों को परिपदों के कार्य-विस्तार के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया। इन नियमों ने परिपदों को राजस्व संबंधी वस्तुओं पर विचार करने का, उन पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विचार करने और उन पर वोट देने का अधिकार प्रदान किया।

सन् १९०९ के सुधारों से सार्वजनिक महत्व के, विशेषकर राजस्व संबंधी, विषयों पर विचार करने के अधिकारों की दिशा में विशेष प्रगति हुई। उदाहरण के लिए साम्राज्यीय विधान परिपद् में अर्थ सदस्य द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद कोई भी सदस्य उस वक्तव्य पर अपने प्रस्ताव के लिए सूचना दे सकता था। यह प्रस्ताव उस वक्तव्य के किसी भी निम्नलिखित विषय के संबंध में प्रस्तुत किया जा सकता था—कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन, कोई नया ऋण, नया स्थायी सरकार के लिए कोई अनिवार्य अनुदान। नियत नियमों को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, उस पर विचार होता था और परिपद् उस पर अपना मत प्रकट करती थी। इस प्रकार के सब प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रत्येक सीपेंज नयवा समूह पर दृष्टि रख से विचार करने की व्यवस्था थी। कोई भी सदस्य

१. R. S. Iyengar's Indian Constitution, पृष्ठ १५७

२ Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol I, page 262.

इन शीर्षकों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता था और परिषद् उन पर विचार करने की और अपना मन प्रकट करती थी। इन शीर्षकों की चर्चा समाप्त करने के बाद अर्थ मंत्री २४ मार्च अथवा उससे पहले किसी तिसरी को बजट प्रस्तुत करता था। विनोय विदग्ध के आकड़ा में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता था तो अर्थ मन्त्र्य उन पर प्रकाश डालता था और साथ ही यह भी बताता था कि परिषद् द्वारा स्वीकार किए हुए किसी प्रस्ताव को मान्यता क्यों नहीं दी गई।<sup>१</sup> तदुपरान्त कुछ बजट पर सामान्य रूप से विचार करने के लिए एक दिन निश्चित किया जाता था लेकिन किसी मन्त्र्य को उस पर किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, उस समय बजट के सम्बन्ध में परिषद् का मन भी नहीं लिया जाता था।<sup>२</sup> विनोय विषयों पर विचार करने के समय में मन्त्र्यों के अधिकारों पर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त दो प्रतिबंध और थे। पहला प्रतिबंध तो यह था कि सरकारों आय<sup>३</sup> और व्यय<sup>४</sup>, दोनों ही के कुछ शीर्षकों के संबंध में परिषद् को किसी प्रकार की चर्चा करने का अधिकार ही नहीं था, और दूसरा प्रतिबंध यह था कि परिषद् का अध्यक्ष किसी प्रस्ताव अथवा उसके किसी अंग को प्रस्तुत किए जाने से रोक सकता था। और उसे इन निषेध के लिये कारण बताने का आवश्यकता नहीं थी।<sup>५</sup>

नियमों के अनुसार मन्त्रालय विधान परिषद् को सार्वजनिक हित के सामान्य विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार करने का अधिकार था। इस अधिकार पर भी कुछ प्रतिबन्ध थे और अव्यक्त किसी ऐसे प्रस्ताव का जो उसके मन में

१. Rule No 21 (1). R. S. Iyengar : Indian Constitution, page ccii

२. Rule No 22 (2) उपर्युक्त पुनः

३. आय के निम्नलिखित शीर्षकों पर विचार करने का अधिकार नहीं था—  
मुद्राक शुल्क, सीमा शुल्क, देशी राज्यों के उपहार, निर्धारित कर, संघ राज्य, विभूट रूप से प्रान्तीय राजस्व—R. S. Iyengar : Indian Constitution, page ccii.

४. व्यय के निम्नलिखित शीर्षकों पर विचार करने का अधिकार नहीं था—  
व्यतिपत्ति, कृषि पर व्याज, धर्म सम्बन्धी व्यय, राजनीतिक व्यय, प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशन, राजकीय रेल मार्ग, सेना, जल सेना, संघ निर्माण, सुरक्षा, वैधानिक व्यय, विभूट रूप से प्रान्तीय व्यय,—Iyengar Indian Constitution, page ccii.

५. Rule No. 3 Ibid, page cci.

सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हो, निषिद्ध कर सजना था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए साधारणतया १५ दिन पहले सूचना देना आवश्यक था। सूचना एक नियत प्रपत्र पर लिख कर देनी होती थी। संसोधनों को विवाद के समय में प्रस्तुत किया जा सकता था। परिषद् को प्रस्ताव और संशोधनों पर मत प्रकट करने का अधिकार था। परिषद् द्वारा स्वीकार किए हुए प्रस्ताव सरकार के लिए सिफारिश के ढंग पर होते थे और सरकार उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र थी।

नये विनियमों ने प्रश्न करने के अधिकार को भी विस्तृत किया—प्रश्न करने वाले सदस्य को उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया गया।

इसी प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अनुपूरक प्रश्न करने और आर्थिक वक्तव्य पर विचार करने के अधिकार प्रत्येक प्रांतीय परिषद् के सदस्यों को भी प्रदान किए गये थे और इस सबध में पूरक रूप से विशेष नियम बनाए गए थे।

६

सन् १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट ने कार्यकारिणी परिषदों की रचना के सबध में भी निर्देश किया। भारत सरकार ने १९०८ के अपने राजपत्र के अन्तिम भाग में यह विचार प्रकट किया था—“अनुभव से हम सम्भवतः इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि बड़े प्रांतों में उपगवर्नरों की शासन शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करना बांछनीय है।” और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की महामत्ता के लिए उन प्रेसिडेंसियों की वर्तमान कार्यकारिणी परिषदों का विस्तार करना आवश्यक है।”<sup>१</sup> लॉर्ड मॉर्ले ने इस प्रश्न को अधिक सुनिश्चित रूप दिया और इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट से सुनिश्चित अधिकार प्राप्त करने के लिए उस अवसर को उपयुक्त अनुभव किया। भारत मन्त्री की इच्छा यह थी कि बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों में सदस्यों की संख्या का बड़ा बढ़ावा कर दिया जावे और उन में कम से कम एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जावे।<sup>२</sup> इस सबध में वे पार्लियामेंट से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय सदस्य की नियुक्ति के लिए व्यवहार द्वारा परपरा ढालने का विचार था, उसके लिए कोई वैधानिक व्यवस्था करने का उद्देश्य नहीं था। एक्ट (सन् १९०९) के विभाग २ (१) ने स-परिषद् भारत मन्त्री को प्रेसिडेंसियों के

१. Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 309.

२. Mukherjee . Indian Constitutional Documents Vol I. page 324.

गवर्नरों की परिषदों के लिए चार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया। लॉर्ड मॉर्टे के मतानुसार अन्य बड़े प्रान्तों के लिए भी कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने पार्लियामेंट में सभी उप-गवर्नरों के प्रान्तों के लिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना के निमित्त, एक मानान्वय अधिकार की मांग की और इसी आशय की एक धारा को भारतीय परिषद् विधेयक में जोड़ दिया। इस विधेयक को लॉर्ड मॉर्टे ने लॉर्ड मदन में प्रस्तुत किया किन्तु प्रबल विरोध के कारण विधेयक को सीधे ही में छाँड़ देना पड़ा। कुछ समय बाद जहाँ विधेयक को सुधोषित रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया और इस बार उसे दोनों भवनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस प्रकार पार्लियामेंट ने स-परिषद् गवर्नर-जनरल को भारत मंत्री की सहमति से बंगाल के लिए कार्यकारिणी परिषद् की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया। इन सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती थी। अन्य प्रान्तों के लिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने के संबंध में स-परिषद् गवर्नर-जनरल को और कोई प्रत्यक्ष अधिकार प्रदान नहीं किया गया। केवल इतना ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने अन्य किसी कार्यकारिणी परिषद् की स्थापना का रोकने व संबंध में करने अधिकार को सुरक्षित रखा। भारत सरकार को, भारत मंत्री का अनुमोदन मिलने पर भी अन्य किसी प्रान्त के लिए कार्यपालिका परिषद् की स्थापना करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में एक न निम्नलिखित निर्देश दिया — “स-परिषद् गवर्नर-जनरल को (बंगाल के विषय की भाँति), भारत मंत्री की सहमति से, उप-गवर्नरों के प्रान्तों में उन (उप-गवर्नरों) की सहायता के लिए — उद्घोषणा द्वारा कार्यकारिणी परिषद् स्थापित करने का वैध अधिकार होगा। किन्तु यह आवश्यक है कि उद्घोषणा करने से पहले, उसका मसविदा अधिवेशन के समय पार्लियामेंट के प्रत्येक भवन के समक्ष, कम से कम साठ दिन तक रखा जावेगा। यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले, दोनों में से कोई भवन, उस मसविदे अथवा उसके किसी भाग के विरुद्ध, पञ्चायत के समक्ष सम्मोचन प्रस्तुत करेगा है, तो उस (मसविदे) पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी किन्तु नया मसविदा बनाने का अधिकार पहले की ही तरह बना रहेगा।” दूसरे पक्षों में इसका अर्थ यह था कि एक ने सरकार को अन्य कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने का अधिकार तो दिया किन्तु साथ ही पार्लियामेंट के प्रत्येक भवन को उसे निषिद्ध करने का अधिकार भी दिया। उप-गवर्नरों की परिषदों के

१. Section 3 (2) of the Act. Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol. I, पृष्ठ २४७.

सदस्यों की नियुक्ति, सम्राट् की स्वीकृति से गवर्नर-जनरल द्वारा की जानी थी।

७

सन् १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट में किसी मन्त्रणा परिषद् की स्थापना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत सरकार ने अपने मौलिक प्रस्तावों में केन्द्र और प्रान्तों के लिए मन्त्रणा परिषद् की स्थापना के विचार को विशेष महत्व दिया था। बिधान परिषदों के अधिवेशन इनन कम होते थे कि "उन में विश्वस्त और आत्मीय रूप से परामर्श करना सम्भव नहीं था। साथ ही पद्धति की अटिच्छता के कारण अधिवेशन के लिए शीघ्रता से आयोजन करना भी सम्भव नहीं था।"<sup>१</sup> फलतः सम्राज्यीय तथा प्रान्तीय मन्त्रणा परिषदों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार सम्राज्यीय परिषद् में साठ सदस्य—विभिन्न प्रान्तों के चालीस बड़े जमींदार और बीस देशी नरेश—होने थे, सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होना था, और प्रस्तुत विषय पर परामर्श देने के अतिरिक्त परिषद् को कोई अधिकार नहीं दिया जाना था। प्रस्ताव में कहा गया कि "साधारणतया परिषद् की कार्यवाही गुप्त होगी और उस को प्रकाशित नहीं किया जावेगा किन्तु सरकार उचित समझने पर उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।"<sup>२</sup> इसी प्रकार प्रान्तीय मन्त्रणा परिषदें होगी। हर प्रान्त की परिषद् में, सम्राज्यीय मन्त्रणा परिषद् के लिए उस प्रान्त के सदस्यों के अतिरिक्त "छोटे जमींदारों, उद्योग धंधों, वाणिज्य समुदाय, पूँजीपतियों और वृत्तिमूर्त वर्गों"<sup>३</sup> के प्रतिनिधिगण होंगे।

मन्त्रणा परिषदों की स्थापना से संबंधित उपर्युक्त प्रस्ताव का भारतीय जनमत के नेताओं ने प्रबल विरोध किया। इन नेताओं ने प्रस्तावित मन्त्रणा परिषदों को केवल निरर्थक और छलपूर्ण<sup>४</sup> ही नहीं बरन कुटिलता युक्त भी बताया। उनको इस बात की आशंका थी कि ब्रिटिश जनमत को धोखा देने के लिए इन परिषदों का उपयोग किया जावेगा। "लाला लाजपत राय के देश निर्वासन जैम सरकारी कृत्यों की समस्त सिध्दित वर्ग निन्दा कर रहे हैं। इन कृत्यों के मध्य में प्रस्तावित मन्त्रणा परिषदों के समक्ष सरकारी प्रस्ताव रखे जावेंगे और सदस्यों को फुसला कर उन प्रस्तावों पर परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावेगा। तब सरकार उन

१ Section 3 (2) of the Act, Mukherjee Indian Constitutional Documents Vol. I, page 256

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३५६

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५९

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७३.

प्रस्तावों को प्रकाशित करेंगे और इस प्रकार अनभिज्ञ किन्तु सहज-विश्वासी ब्रिटिश जनता को धोखे में डालने का तथा संसार की आंखों में धूल झांकने का प्रयत्न करेंगी<sup>१</sup> किन्तु "यदि मन्त्रणा परिषद् साहज से काम लेती है और निन्दा का प्रस्ताव पास करती है, तो अंग्रेज शासक बड़े सरलता से अपने मन की समझ जेंगे और उस प्रस्ताव को प्रकाशित नहीं करेंगे।"<sup>२</sup>

देशी नरेशों तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भी मन्त्रणा परिषद् की स्थापना के प्रस्ताव का विरोध किया। तत्कालीन मद्रास सरकार भी इस प्रस्ताव के प्रबल विरोध में थी। देशी शासकों के विरोध का मुख्य कारण यह था कि प्रस्तावित परिषद् में उनके और बड़े जमींदारों को एक ही धेंगे में रखा जा रहा था। कुछ प्रान्तीय सरकारें भी देशी नरेशों के दृष्टिबोध से सहमत थीं। इस विरोध के कारण भारत सरकार ने अपना मौलिक योजना का छोड़ दिया और अक्टूबर १९०८ के गजपत्र में अपने संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। इनमें तीन बातें उल्लेखनीय थीं—(१) भारत सरकार ने एक छोटी (केन्द्रीय) परिषद् बनाने का विचार प्रकट किया, केवल देशी शासकगण ही इस परिषद् के सदस्य ही सक्ते थे, उनकी छोट बाइसरायों द्वारा होनी थी, उनका कार्यकाल बाइसरायों की सदिच्छा पर निर्भर था, और बाइसरायों उनमें अपनी इच्छानुसार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से परामर्श कर सकते थे<sup>३</sup>, (२) नई योजना में भारत सरकार ने ब्रिटिश भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक पृथक् परिषद् बनाने के प्रस्ताव को बौद्ध स्थान नहीं दिया और उनके विचार को उस समय के लिए स्थगित कर दिया, और (३) भारत सरकार ने उन प्रान्तों के लिये, जिनके अधिकांश इस पक्ष में हों, मन्त्रणा परिषद् की स्थापना करने के लिए निवारित की। इनका आकार भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट होता था किन्तु इनके सदस्यों की छोट "मेधा शक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव अथवा प्रतिनिधिपूर्ण स्थिति" के आधार पर मन्त्रित प्रान्तीय सरकार द्वारा होती थी।<sup>४</sup>

भारत मन्त्री ने इन प्रस्तावों को न तो पसन्द ही किया और न उनका समर्थन ही किया। उनके मन से, देशी शासकों की राजनीतीय मन्त्रणा परिषद् बनाने के अवध में, उन नरेशों के सम्मिलन की दृष्टि से, अथवा पूर्व-सरपत्र, प्रचार व्यवस्था

१. Mukherjee Indian Constitutional Documents, page 273.

२. Hindustan Review, September 1907, page 285.

३. Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 276.

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८१।



आदि की अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी<sup>१</sup> जिनकी सरलता से दूर नहीं किया जा सकता था। “यदि परिषद् के सम्मेलन करने का उद्देश्य नहीं है तो वह (परिषद्) बिलकुल निरर्थक होगी।” प्रान्तीय मन्त्रणा परिषदों के संबंध में लॉर्ड मॉलै का यह विचार था कि नई परिषदें—चाहे वे छोटी हो या बड़ी—निश्चित रूप से पुरानी विधान परिषदों के साथ प्रतिद्वन्द्वता करेंगी। “इसके अतिरिक्त यह संदेह भी किया जावेगा कि नई परिषदें, पुरानी परिषदों पर रोक लगाने के लिए बनाई गई हैं।”<sup>२</sup> लॉर्ड मॉलै के मतानुसार, भारत सरकार, महत्वपूर्ण नरेशों तथा विभिन्न स्थानों के, प्रमुख एवं प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ, नियमबद्धता से मुक्त रह कर निजी रूप से परामर्श करने की वर्तमान परम्परा को विकसित करके, अपने सभी प्रस्तावित उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती थी।

भारत मंत्री के विरोध के कारण भारत सरकार के प्रस्ताव का अन्त हो गया और इसका फल यह हुआ कि १९०९ के सुधारों में केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों के लिए मन्त्रणा परिषदों की योजना को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ।

१ Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 311.

२ उर्ध्वपत्र पुस्तक, पृष्ठ ३१२

## युग ३

(सन् १९०९ से १९१९ तक)

# सत्रहवाँ अध्याय

## शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन

१

ब्रिटिश राज्याधीन भारत के इतिहास में सन् १९०९ से १९१९ तक का युग सब से छोटा है, किन्तु उसका महत्त्व उसके वर्षों की सत्या के आधार पर नहीं आका जा सकता। वस्तुतः यह युग अत्यन्त महत्त्व की घटनाओं से परिपूर्ण है। इस युग में ब्रिटिश सम्राट ने—सम्राज्ञी और एक प्रमुख राज्यमन्त्री के साथ—भारत भूमि पर पहली बार पदार्पण किया, सम्राज्ञीय परिषदों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में भारत को पहली बार बराबरी का स्थान दिया गया, उप-भारत-मन्त्री के पद पर पहली बार एक भारतवासी की नियुक्ति की गई, तथा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना लक्ष्य उत्तरदायी राजनीतिक सभाओं की स्थापना करना बताया, और स्वायत्त स्वशासक प्रांतों के संघीय भारत का चित्र शक्ति पर उभरा हुआ दिखाई दिया। इसी समय में, जनता की इच्छाओं के अनुसार बंगाल के विभाजन में संशोधन हुआ, भारत की राजधानी बलकत्ते से दिल्ली के लिए स्थानान्तरित की गई और वहाँ एक नया सम्राज्ञीय नगर बसाने का निर्णय किया गया, और विभिन्न राजनीतिक सभाओं में—राष्ट्रवादियों के नरम और उग्र पक्ष और साथ ही मुस्लिम लीग में—ऐक्य हुआ और राष्ट्र के नेताओं ने परस्पर मिलकर राजनीतिक प्रगति के लिए एक सर्वमान्य योजना बनाई। इसी दशाब्दी में, ब्रिटिश राज्य की बल द्वारा उस्ताड फेंकने के लिए सन सत्तावन के बाद सब से बड़ा पड़्यन्त्र रचा गया, होम रूल (स्वशासन) प्राप्त करने के लिए और अयुक्त विधियों को कार्यान्वित होने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन आंदोलन किया गया, सिक्खों के तीर्थस्थान में एक ब्रिटिश जनरल की आत्मानुसार जलियावाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ, पंजाब में मार्शल-लों (फौजी कानून) की घोषणा की गई और शासन का काम फौजी अधिकारियों को सौंप दिया गया और दमन की अत्यन्त कठोर तथा अत्यन्त व्यापक नीति अपनाई गई। सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महा-युद्ध का भारत पर भी प्रभाव पड़ा और देश को धन और जन की बहुत बड़ी बलि देनी पड़ी; इसी समय इन्फ्लुएन्जा का भीषण प्रकोप हुआ और लोगों के कष्ट कई गुने बढ़ गए। इस महामारी के कारण कुठ ही सप्ताहों में दसियों लाख आदमी मर गये। इन मरने वालों की सत्या विभिन्न आंकड़ों के अनुसार साठ लाख से एक करोड़ तक थी। इन बातों के अतिरिक्त प्रशासनीय एवं सविधानीय महत्त्व के कितने

न वित्तीय कमिशनरों के पदा को और राजस्व मंडलों को तोड़ने की तथा कलकटरो और कमिशनरों के अधिकारों को बढ़ाने की सिफारिश की। कमिशन में प्रशा की जिला कमेटियों के हवा पर जिला मंत्रणा परिषदा की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव को श्री रमेशचन्द्र दत्त और श्री गोखले ने प्रस्तुत किया था।

कमीशन न साधारणतया प्रान्तों को १९०४ की अर्ध-स्थायी वित्तीय बन्दो-वस्त की व्यवस्था का अनुमोदन किया। उसके सबब में कमीशन ने कुछ सशोधनों और परिवर्तनों के लिए अपने सुझाव भी दिए। इनमें से अधिकांश सुझावों को सर-कार ने स्वीकार किया और १८ मई १९१० के प्रान्तीय वित्त सबधी अपने प्रस्ताव में उनको रप दिया।

भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों के साथ अने वित्तीय सबधा में, यथासंभव स्थिरता लाने के लिए उद्युक्त थी किन्तु प्रान्तीय बन्दोवस्त को स्थायी घोषित करने से पहले उसने कुछ वित्त बिजयताओं का और निष्केन्द्रीकरण कमीशन के सुझावों का परीक्षण करना आवश्यक समझा। भारत सरकार विभिन्न प्रान्तों के साथ विषम व्यवहार सबधी आक्षेपों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना यह था कि "प्रथम तो इस आक्षेप के अस्तित्व के विषय में ही मन्देह है—और यदि उसका कोई अस्तित्व है भी, तो वह केवल ऐतिहासिक है। "पच्चीस वर्षों के सौदे के फलस्वरूप एक ऐसी भूमि स्थापित हो गई है कि उसे कागजी लिखा पत्रों से दूर नहीं किया जा सकता।" इस बात का डा० ब्राह्मचन्द्र ने सफलतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया है। उनके अनुसार "सन् १९११ के बन्दोवस्त में किसी प्रकार का भी साम्य नहीं था।" अस्तु, भारत सरकार की धारणा के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में साम्य था और उसने कुछ अन्य त्रुटियों को दूर करने के बाद प्रान्तों के बन्दोवस्त को स्थायी कर दिया। पहली बात तो यह थी कि कुछ प्रान्तों में निश्चित अनुदान की रकम बहुत बड़ गई थी। भारत सरकार ने निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्रान्तों के बन्दोवस्त को दोहराया और राजस्व की कुछ मदों को पूर्णतः अथवा अंशतः प्रान्तीय शीर्षक में सम्मिलित कर दिया—इस प्रकार जंगलों की पूरी आमदनी प्रान्तों को दे दी गई, बम्बई को प्रान्तीय आवश्यकताओं की पूरी आमदनी पर अधिकार दिया गया और मध्य प्रान्त तथा यू पी को आवश्यकताओं की तीन चौथाई आमदनी पर अधिकार दिया गया, पंजाब को बाकी मालगुजारी पर अधिकार दिया गया और चम्पा को ५/८ भाग पर; और सिक्किम की प्रमुख राजनाओं में पंजाब का सांझा बंटकर पंचायत प्रतिशत कर दिया गया। निश्चित अनुदानों को इसी अनुपात में घटा दिया गया।

दूसरी बात यह थी कि निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफारिशों के अनुसार

साम्राज्यीय निधि में प्रान्तों को बड़े अनुदान देने की नीति को भी दोहराया गया। पुरानी नीति में केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक था, अनुचित विवरण होता था और कम आवश्यक कामों में धन का उपयोग होता था। इस पृष्ठ भूमि में कमीशन ने अनुदान देने के मस्ये में तीन निदानों को व्यवहार में लाने की सिफारिश की। (१) प्रान्तीय सरकारों की दृष्टियों का ध्यान रखा जावे, (२) ये अनुदान विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न कार्यों के लिए हो सकने हों, (३) उनके कारण केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने इन निदानों को स्वीकार किया और अनुदान मस्ये नए नियमों में उनको रूप दिया।

तीसरी बात यह थी कि भारत सरकार ने प्रान्तों के बजट के निरूपण के मस्ये में निषेधोक्ति का कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नए नियम बनाए। भविष्य में, विभाजित शीपोंको पर और राजस्व तथा व्यय की समीचीन त्वमें पर ही नियंत्रण किया जा सकता था। प्रान्तीय सरकारों को (केन्द्रीय सरकार के आधीन) अपने आवश्यक अर्थों में से निश्चित परिमाण में अधिक धन लेने का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारें घाट का बजट भी बना सकती थीं। किन्तु भारत सरकार की दृष्टि में स्वतन्त्र रूप में कर लगाने का अधिकार अथवा द्रव्य बाजार में प्रान्तीय ऋण उगाहने का अधिकार अव्यवहार्य था।

वित्तीय बन्दोबस्त स्थायी करने से पहले, भारत सरकार ने १९१२ के प्रस्ताव द्वारा उपर्युक्त परिवर्तन किए। किन्तु इनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं था। अधिकतर दीर्घ अवधि में यथावत थे। विभाजित शीपोंकी की और केन्द्रीय विवरण की पुरानी व्यवस्था बनी रही, प्रान्तीय व्यय का अनाम्य दूर नहीं हुआ, कर लगाने और ऋण उगाहने के स्वतंत्र अधिकार प्रान्तों को अब भी नहीं मिले। तयारी १९१२ के प्रस्ताव ने प्रान्तों के साथ वित्तीय बन्दोबस्त को स्थायी कर दिया।

३

भारतीय निषेधोक्ति का कमीशन की मस्ये में अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों, भारत में स्थानीय स्वशासन के विस्तार में सन् १८८२ के प्रस्ताव के अनुसार स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का पुनर्गठन और विस्तार करने के लिए प्रान्तों में नगरपालिका तथा स्थानीय स्वशासन एकट बनाए गए थे। किन्तु उनके फलस्वरूप अगले २५ वर्षों में नगरपालिका तथा ग्राम्य महलों में जो प्रगति हुई थी वह निराशाजनक थी। इस अल्प प्रगति के तीन मुख्य कारण थे। पहली बात तो यह थी कि 'स्थानीय आय बहुत थोड़ी थी और उस आय की मदें लचीली नहीं थी।'

१. सन् १९११-१२ में भारतीय नगरपालिकाओं की आय और उनकी मुख्य मदें इस प्रकार थी — जमीन और मकानों पर टैक्स १०,५६,०२० पौंड; चुगो ९,१५,१०१ पौंड; पानी ५,२६,१२७ पौंड; अन्य टैक्स ८,५९,१९२

दूसरी बात यह थी कि स्थानीय मामलों में न तो लोगों के अनुरोध में ही कोई विशेष वृद्धि हुई थी और न उन स्थानीय विषयों की व्यवस्था करने के लिए लोगों की मांगों में ही वृद्धि हुई थी।<sup>१</sup> तीसरी बात यह थी कि इन स्थानीय सत्थाओं पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था।<sup>२</sup>

भारतीय निष्केन्द्रीकरण समीक्षण ने इन दोषों को—यदि पूरी तरह नहीं तो कम से कम बहुत हद तक—दूर करने के लिए विचार ही मुद्राव दिए। किन्तु दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उन पर विचार और निर्णय करने में बहुत समय लगाया। फल यह हुआ कि सन् १९१५ में सरकारी नीति निश्चित होने के समय तक प्रस्ताव पुराने और असंगत हो गए। कुछ ही समय बाद राजनीतिज्ञ सुधारों का प्रदन उठाया गया और यह निश्चय किया गया कि स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में सबसे पहला और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा बड़ा कदम आगे बढ़ाया जावे। अतः भारत सरकार ने सन् १९१५ के अपने

पॉड, सरकारी अनुदान ५,९९,८५२ पॉड उसी वर्ष व्यय की मुख्य मदें इस प्रकार थी—मडकें ४८९,१९३ पॉड, अस्पताल आदि २६९,३०१ पॉड, शिक्षा २३८,४८७ पॉड, सार्वजनिक स्थानों और मडकों पर रोशनी २३५,४७७ पॉड।

ग्राम्य मंडलों की आय की मदें और भी संकुचित थी। उनकी आय की सबसे बड़ी मद भूमि संबंधी उपकर हैं....यह उपकर जमीन के बाधित मूल्य के सोलहवें भाग से अधिक नहीं होता। सरकार पूरक अनुदान द्वारा सहायता करती है। यह अनुदान उपर्युक्त आय का २५ प्रतिशत होता है। विशेष कामों के लिए सरकार विशेष अनुदान भी देती है। सन् १९११-१२ में २० करोड़ से अधिक लोगों पर ग्राम्य मंडलों का कुल व्यय ३३०,२६७० पॉड था।—देसिये—Material and Moral Progress Report 1911-12 pages 117 to 119

१ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 6

२ अधिकांश नगरपालिकाओं के अध्यक्ष जहाँ की सरकारी अधिकारों थे। सन् १९१५ में ६९५ अध्यक्षों में से केवल २२८ निर्वाचित और सरकारी व्यक्ति थे, ५१ नाम निर्देशित और सरकारी व्यक्ति थे, अन्य ४२२ सरकारी अधिकारी थे। लगभग सभी प्रान्तों में जिला मंडलों के अध्यक्ष जिलों के कलेक्टर थे।

को चुनना चाहता हो तो गैरसरकारी व्यक्तियों का स्पष्ट बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। बड़े शहरों में, अध्यक्ष के अनिश्चित, सरकार के अनुमोदन से मंडल द्वारा नियुक्त एक एग्जीक्यूटिव अफसर भी होना चाहिए। जिला मंडलों के संबंध में प्रस्ताव ने प्रान्तीय सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया कि उनके अध्यक्ष, यथासंभव निर्वाचित व्यक्ति हों। यदि यह संभव न हो तो गैरसरकारी अध्यक्षों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसी दशा में विशेष एग्जीक्यूटिव अफसरों की नियुक्ति भी की जाए। यदि कोई जिला मंडल इस नियुक्ति के व्यय को वधाना चाहता हो तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह गैरसरकारी बहुमत से सरकारी अफसर को अध्यक्ष-पद के लिए निर्वाचित करे।

प्रस्ताव ने तीसरी बात यह की कि उसने मंडलों के कर लगाने के अधिकार को थोड़ा-सा बड़ा दिया—अब ये मंडल, कानून द्वारा निश्चित सीमाओं के अंदर विभिन्न टैक्सों और उपकरों को घटा बड़ा सकते हैं। किन्तु शृणुप्रस्त मगरपालिकाओं के लिए, स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था।

विचाराधीन प्रस्ताव की चौथी बात यह थी कि उसने निष्केन्द्रीकरण कमीशन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि किसी नगरपालिका अथवा ग्राम्य मंडल को किसी सेवा के लिए व्यय करना पड़ता हो तो उस सेवा पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। यदि किसी सेवा पर सरकारी नियंत्रण रखना आवश्यक हो तो वह सेवा प्रान्तीय सरकार के आधीन होनी चाहिए।<sup>१</sup>

कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, प्रस्ताव ने पाँचवीं बात यह की कि उसने मंडलों को बजट बनाने की स्वतन्त्रता दे दी। “उन पर केवल यही नियंत्रण होना चाहिए कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा निश्चित, आकलन अवशेष के न्यूनतम परिमाण को बनाए रखें। इसके अनिश्चित स्थानीय सरकारों को दोषी नगरपालिकाओं को वर्तमान-मालन के लिए विवश करने का और शृणु के संबंध में नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए।”<sup>२</sup> प्रस्ताव के अनुसार कुछ और बातों में भी नियंत्रण की कमी हुई—जैसे विशेष कामों के लिए स्थानीय राजस्व के उपयोग के संबंध में, विशेष अनुदानों के संबंध में, सार्वजनिक निर्माण संबंधी व्यय के विषय में और स्थानीय प्रबन्ध के विषय में। किन्तु उनके निरीक्षण और नियंत्रण के संबंध में कमिशनरों और

१. Para 12 of the Resolution, Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 707.

२. Para 13, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०७-८.

साम्राज्यीय संघ को दृढ़ करना था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन बातों को अनुभव कर रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के कारण बहुत-से भारतवासियों की सम्भावनाएँ लुप्त हो गई थी और राजमन्त्रि की भावनाएँ अत्यन्त कम हो गई थी और ब्रिटिश संसद के प्रति विश्वास जमाने के लिए और राजमन्त्रि की भावनाओं को फिर से जगाने के लिए ब्रिटिश सम्भावनाओं के महत्वपूर्ण प्रदर्शन की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, उस उद्देश्य के लिए, इससे बढ़ कर कोई बात नहीं हो सकती थी कि ब्रिटेन के नये राजा और रानी का मुबल साम्राज्य और हिन्दू नरेशों की राजधानी दिल्ली में, भारत के सम्राट और सम्राज्ञी के नाम से सम्मानित किया जाय, और सम्राट (भारत के विगतवालीन सम्राटों की तरह) लोगों की शिकायतों को दूर करे और उन पर अनुग्रह करे, और भारतीय जनता तथा देशी शासकों की भेंट को स्वयं स्वीकार करे। अतः १२ दिसम्बर १९११ को दिल्ली में—सन् १९०३ के दरबार की अपेक्षा कहीं अधिक वैभवपूर्ण—दरबार करने का निश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त उस अवसर पर भारतवासियों की सम्भावना और राजमन्त्रि को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ घोषणाएँ करने का भी निश्चय किया गया।

दिल्ली-दरबार में सम्राट की तीसरी तथा अन्तिम घोषणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इस घोषणा के स्मरणीय शब्द इस प्रकार हैं—“भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से, भारत की प्राचीन राजधानी दिल्ली को स्थानान्तरित की जायगी और उसके साथ ही उस परिवर्तन के फलस्वरूप यथासम्भव सीमा से बंगाल को गवर्नर की प्रेसीडेन्सी बनाया जायगा, बिहार, छोटा नागपुर तथा उड़ीसा को सम्प्रिपद उप-गवर्नर का प्रान्त बनाया जायगा और बात्ताम को चीफ कमिश्नर का प्रान्त बनाया जायगा, और इस संघ में आवश्यक प्रशासकीय परिवर्तन किए जायेंगे। तथा प्रांतीय सीमाओं को फिर से निश्चित किया जायगा।”

बहुत-से लोग इन परिवर्तनों के विषय में थे और यदि उनका पहले से पता होता तो उन पर तीक्ष्ण और उग्र विवाद हुआ होता। स्वयं सम्राट द्वारा घोषणा करने के कारण इन परिवर्तनों के साथ कुछ श्रद्धा की भावना जुड़ गई थी, तथापि इंग्लैंड और भारत, दोनों ही स्थानों में, उनकी तीव्र आलोचना की गई।

भारत सरकार ने २५ अगस्त १९११ के अपने राजपत्र में इन परिवर्तनों का उपक्रमण किया था। उस राजपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रस्तावों को प्रांतीय स्वाधीनता के हित में प्रस्तुत किया गया था। “वर्तमान जटिल स्थिति



को मुद्रास्त्रान का मनबन्ध यही उद्देश्य है कि प्रान्तों को धीरे-धीरे अपिगपि स्वशासन का अधिकार दिया जाय। इस प्रकार काल में भारत में बहुत-सी सरकारें बन जाएंगी जो नारे प्रान्तीय विषयों में स्वाधीन होंगी। इन सबके ऊपर भारत-सरकार होगी जिसे कुशासन की दृष्टि में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, और जिसका कार्यक्षेत्र नागरिकता या साम्राज्यीय विषयों तक ही सीमित होगा। इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च सरकार किसी प्रांत विशेष की सरकार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।<sup>१</sup> किन्तु भारत में नया भारत सरकार के दिन-महम्मद ने राजपूत के उक्त वाक्या के मध्य में भारतवर्षियों की स्पष्ट व्याख्या की स्वीकार नहीं किया। लार्ड रिडवे के अनुसार, भारत की औपनिवेशिक दृष्टि पर स्वायत्त कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था। 'इस दिना में भारत का कोई नवित्य दिनांक नहीं देता।' <sup>२</sup> लार्ड रिडवे के दिन मंत्री नर विन्डियन मेजर ने जब श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी न १९११ के गवर्नर की नीति के अनुसार प्रान्तों को विनीय स्वाधीनता प्रदान करने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने श्री बनर्जी को "बड़ी आश्चर्यचकित" बताया।<sup>३</sup>

इस बातों से, और साथ ही निष्पेन्द्रोत्तरण कमीशन के साधारण प्रस्तावों की स्वीकार करने में भी भारत सरकार के सकार में, यह परिणाम निकलता है कि "प्रान्तीय स्वाधीनता" के उद्देश्य का—जब से जब भारत में और बादमराठों की कार्यक्षेत्रों परिषद् के सदस्यों की विचारधारा में—कोई विशेष महत्त्व नहीं था।<sup>४</sup>

इस सम्बन्ध में एक कारण और बताया गया है जो ज्यादा सही मालूम देता है—दम्पैड की लिबरल पार्टी सरकार ने ही बंगाल विभाजन के विरोध में की और लार्ड मॉले के वास्तविक विचार यही थे जो उन्होंने पद ग्रहण करने से कुछ समय पहले प्रकट किए थे। उन्होंने भारत मंत्री बनने के बाद, २९ फरवरी १९०६ के अपने व्याख्यान में, अपने विचारों को फिर प्रकट किया। वि० मॉले ने (जो उस समय तक लार्ड नहीं बने थे) कि "बंगाल का विभाजन एक निश्चित एवं वास्तविक तथ्य है किन्तु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह काम अधिकार

१. Para 3 of the Despatch, Mukherjee : Indian Constitutional Documents, vol. I, page 454.

२. Lovell : History of Indian Nationalism, page 89. Extract from the speech of 24th June 1912 in the House of Lords.

३. Bannerjee : A Nation in the Making, page 300.

## गासन तथा सविधान से संबंधित परिवर्तन

संबंधित लोगो की इच्छाओं के पूर्ण विरोध में हुआ है।<sup>१</sup> लाड माल न कबरी १९१२ में लाड भवन में इस बात को फिर स्वीकार किया कि उस समय विभाजन की तुरन्त रद्द करने के लिए कोई कदम न उठाने के कारण भेरे कितने ही मित्र कई महीनो तक मुझ से नाराज रहे थे।<sup>२</sup> किन्तु मि० माल की दृष्टि में विभाजन की तुरन्त रद्द करना अनौत्तियक्त था। वे सिविल सर्विस के सन्स्यो के साथ उलझना नहीं चाहते थे उन्हें मुधारो के सम्बंध में इन लोगो से काम लेना था। इसके अतिरिक्त उस समय विभाजन रद्द करने का लोगो पर यह प्रभाव होता कि लिबरल सरकार पिछली ब्रिटिश सरकार को भारत सम्बंधी सारी नीति बदलना चाहती है। लाड मालों ने कहा उस समय बंध रहने का एक कारण और था उस नीति के परिणामो पर अपना मत निश्चित करने के लिए हम पर्याप्त समय नहीं मिलता था।<sup>३</sup> अन्तिम बात यह थी कि दिसम्बर १९०६ में विभाजन रद्द करने का यह अर्थ लगाया जाता कि सरकार कोलाहल के आय शुरू गई।<sup>४</sup>

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लिबरल सरकार सन १९०६ में पद ग्रहण करने के समय से ही विभाजन रद्द करने के लिए चिन्तित थी और वह उसके लिए केवल उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थी। सन १९११ में उसे यह अवसर प्राप्त हुआ— हाल ही में एक नए वाइसरॉय ने पद ग्रहण किया था सन् १९०९ के मुधार कार्या चित हो चुके थे विभाजन विरोधी आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था और सम्राट तथा सम्राज्ञी राजभवन की भावनाओं को फिर से जगाने के लिए भारत जान वाले थे। ऐसे समय पर विभाजन रद्द करने का कृत्य सम्राट का अनुग्रह माना जाएगा और उसे सरकार की दुबलता नहीं समझा जाएगा। मुसलमानों को यह नीति कम आपत्तिजनक हो इस उद्देश्य से सरकार ने राजधानी को मुगलों के क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थानान्तरित करने का निश्चय किया। अर्थ कारणों से भी<sup>५</sup> राजधानी को कलकत्ते से हटाना वांछनीय था और उस परिवर्तन के लिए इस अवसर का लाभ उठाया गया।

१ लाड हार्डिंग ने मि० बनर्जी से पारस्परिक वार्तालाप में कहा था इस वय में आप लोगो को प्रांतीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी। —Bannerjee

A Nation in the Making, पृष्ठ ३००।

२ Speeches of John Morley pages 107 and 108

३ Lord Hardinge's Speeches, Vol I Appendix, page 505

४ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १०४

५ राजनैतिक दृष्टि से कलकत्ता की स्थिति वैज्ञानिक नहीं थी वहाँ से भारतीय रियासतो की सामरिक जातियों की और महत्त्वपूर्ण उत्तरी पश्चिमी सीमा

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली दरबार करने की और साथ ही भारतवासियों की, विशेषकर बंगालियों की, सद्भावना प्राप्त करने की नीति, लॉर्ड हाडिज के भारत आने से पहले ही इंग्लैंड में निश्चित कर ली गई थी और उस नीति के सम्बन्ध में लॉर्ड हाडिज का समर्थन प्राप्त कर लिया गया था। उनके कलकत्ता आने पर बंगाल के नेताओं ने विभाजन-विरोधी सभा करने का और उनके इस सम्बन्ध में लोगों की भावनाएँ जनाने का निश्चय किया। लॉर्ड हाडिज ने श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी की तुरन्त बुलाया और उन्हें सभा करने अथवा सार्वजनिक आन्दोलन करने के विचारों को छोड़ देने के लिए समझाया और उनके स्वान पर एक स्मारक प्रस्तुत करने की सलाह दी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे उस स्मारक पर भली-भाँति विचार करेंगे। सार्वजनिक सभा करने का विचार छोड़ दिया गया और स्मारक तैयार किया गया। इस स्मारक में बंगाल के २५ जिलों में से १८ जिलों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और उसे सन् १९११ में जून के अन्त में वाइसराय के पास भेज दिया। श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं, "विभाजन का सशोधन करने से सम्बन्ध में सरकार ने अपनी सिफारिशों को २५ अगस्त १९११ के राजपत्र में रूप दिया, स्मारक में जो तर्क दिए गए थे, उनमें से कुछ को सरकार ने स्वीकार किया और अपने राजपत्र में उनका प्रबल समर्थन किया।"<sup>१</sup>

राजधानी बदलने का और साथ ही विभाजन रद्द करने का इंग्लैंड और भारत दोनों ही स्थानों में विरोध किया गया, मुख्य आपत्ति, परिवर्तन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में थी। लॉर्ड कर्जन ने परिवर्तन के उपर्युक्त डग को अवैधानिक, तथा एक बृहद खिचरल सम्कार के लिए अवशोभनीय, बताया। लॉर्ड मिंटो के मतानुसार, भारत के प्रांतीय अधिकांश तथा इंग्लैंड के आंग्ल-भारतीय अधिकारियों के परामर्शों के बिना, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय करना गलत था। अन्य आक्षेपों के अनुसार, सरकार ने स्वार्थी, व्यक्तिगत लोगों के कृत्रिम तथा अस्वाभाविक आन्दोलन के सामने हार स्वीकार की थी और इन प्रकारपूर्वी बंगाल के राजमन्त्र मुमलमानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था।

प्रदेश की दूरी बहुत ज्यादा थी। "इसके अनिश्चित १९०७ के बंगाली वार्तिकारों आन्दोलन ने स्थिति को अत्यन्त जटिल बना दिया था; अन्य प्रांतों के विधायक मध्यम बलवत्ता आकर बंगाली विचारों से प्रभावित हो रहे थे।" तीसरी बात यह थी कि कलकत्ता में भारत सरकार की उपस्थिति के कारण प्रांतीय सरकार बिल्कुल नगण्य और अक्षर हो गई थी।"—

Indian Insistent by Sir Harcourt Butler, page 70-71 में अनूद्धित।

१. Bannerjee: A Nation in Making, page 85.

कलकत्ता से राजधानी हटाना, भारत में बसे हुए यूरोपियनों के हितों के विरुद्ध था। इस सम्बन्ध में विरोध का दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश सत्ता समुद्री-शक्ति पर निर्भर थी, इस दृष्टि से कलकत्ता को छोड़ना अयुक्त था। तीसरे आक्षेप का आधार, नई राजधानी दिल्ली का इतिहास था, वहाँ किन्ने ही साम्राज्यों का कब्रिस्तान था।<sup>१</sup> लॉर्ड कर्जन ने कहा, "वस्तुतः दिल्ली के इतिहास की ब्रितानी कम चर्चा की जाए, उतना ही अच्छा है।"<sup>२</sup>

इस प्रकार उक्त कारणों से सन् १९११ के राजपत्र की नीति का विरोध किया गया। लॉर्ड भवन में लॉर्ड मॉल और लॉर्ड क्रिजवे ने उनका प्रबल प्रत्युत्तर दिया और विरोध धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया। नई राजधानी बसाने के सम्बन्ध में लॉर्ड हार्डिज की सरकार ने लगभग ४० लाख पौंड के व्यय का अनुमान किया था।<sup>३</sup> दूसरी ओर लॉर्ड कर्जन ने १ करोड़ २० लाख पौंड के व्यय का अनुमान किया था।<sup>४</sup> आगे चल कर लॉर्ड कर्जन की बात पचावा सही निकली। वस्तुतः राजधानी को केन्द्रीय तथा निष्पक्ष स्थिति में लाने के निमित्त, भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह एक अत्यन्त बड़ा परिमाण था जिस को भयंकर कहने में भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

५

सन् १९११ के दिल्ली दरबार के प्रशासनीय परिवर्तनों को कार्यकारिणी-आदेशों और उद्घोषणाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार को पिछले विधानों के अन्तर्गत अधिकांश अधिकार प्राप्त थे, कुछ विषयों के लिए अनुपूरक विधान बनाने की भी आवश्यकता हुई।

सब से पहले तो भारतमन्त्री ने सन् १८५३ के एक्ट के विभाग न १६ के अन्तर्गत यह घोषणा की कि भविष्य में गवर्नर-जनरल, बंगाल की फोर्ट विलियम

१. For a study of this mentality read "1957", a novel by Hamish Blair.

२. Lord Hardinge's speeches, vol. I Appendix page 465.

३. लॉर्ड हार्डिज ने आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा बसाने के व्यय से नई राजधानी बसाने के व्यय की तुलना की। कैनबेरा बसाने का व्यय १ करोड़ ३० लाख पौंड था। इसी सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वाइसरॉय भवन और सेन्टेटेरियेट भवन का कुल व्यय लन्दन में बैंक ऑव इंग्लैंड की नई इमारत के अनुमानित व्यय के आधे से कुछ ही अधिक होगा।

प्रेसीडेंसी का गवर्नर नहीं होगा और उस प्रेसीडेंसी के लिए एक पृथक् गवर्नर की नियुक्ति होगी। १० मार्च १९१२ की उद्घोषणा द्वारा नई प्रेसीडेंसी का क्षेत्र फिर से निर्दिष्ट किया गया। मई १९०५ में बनला बोम्बेदागी जनता की जिन पाँच कमिश्नरियों को पृथक् किया गया था, उन्हें अब फिर पुनः प्रान्त के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार बंगाल की एक नई प्रेसीडेंसी बनाई गई।

२० मार्च १९१२ की दूसरी उद्घोषणा द्वारा बिहार तथा उड़ीसा का नया प्रान्त बनाया गया। इस प्रान्त के लिए एक उच्च गवर्नर, कार्यकारी परिषद् तथा विधान परिषद् की व्यवस्था की गई।

उत्प्रेक्षित दिनांक की सीमा में उद्घोषणा द्वारा आन्ध्र प्रदेश की एक नई कमिश्नर का प्रान्त बनाया गया।

आवश्यक अनिवार्य व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मई १९१२ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया।

इस एक्ट ने पहली बार ना यह की कि उनमें समाज के गवर्नर और दूसरी परिषद का बड़ी अधिकार प्रदान किए जो मन्त्रालय और कमेटी के गवर्नरों की और उनकी कार्यकारी तथा विधान परिषदों का प्रान्त थे।

एक नई दूसरी बात यह की कि उच्च विहार तथा उड़ीसा के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की ताकि १९०० के भारतीय परिषद् ऐक्ट की प्रावधानों के कारण उनका बनाई में विराम न हो।

अन्त में एक नया नया कमिश्नरों के प्रान्तों के लिये भी विधान परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान दिया। मई १९१२ के ऐक्ट के विभाग न ३ के अन्तर्गत जो विधान परिषदें बनाई गई—एक आन्ध्र के लिए (नवम्बर १९१० में) और एक मध्य प्रान्त के लिए (नवम्बर १९१३ में)।

मई १९१२ की एक उद्घोषणा द्वारा दिल्ली का एक छोटा-सा प्रान्त बनाया गया—इसमें नई राजधानी के बागों और का छोटा-सा प्रदेश सम्मिलित किया गया। इस प्रान्त के लिए एक नई कमिश्नर की व्यवस्था की गई। यह नई कमिश्नर मध्यपरिषद् गवर्नर-जनरल के अधीन होगा था।

मई १९१२ के प्रशासनीय परिवर्तनों के सम्बन्ध में सरकार ने भारतीय संविधान में सम्बन्धित विधियों को महिनावद्ध करने की आवश्यकता को अनुभव किया। ऐसे बहुत-से ऐक्ट थे जो अयुक्त हो गए थे और व्यवहार में भी नहीं आते थे, किन्तु वे रह-रही दिए गए थे; और भारत-सरकार के अधिकार विभिन्न विधानों

१०१ मार्च १९१२ को लॉर्ड कारमाइकेल को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया।

में बिखरे हुए थे और समय तथा धन का अपव्यय किए बिना उन अधिकारों को जानना अत्यन्त कठिन था। अतः जुलाई १९१५ में पार्लियामेंट ने एक कॉन्सॉलिडे-टिंग ऐक्ट बनाया।

सन् १९१५ के इस ऐक्ट का उद्देश्य उपयोग में आने वाली सब विधियों को एकत्र करके एक संहिता के रूप में प्रस्तुत करना था। इसी कारण उक्त ऐक्ट में पिछले विधानों में किसी प्रकार का संशोधन करनेवाले कोई खंड नहीं थे। "उसने सन् १७७० के बाद के ४७ ऐक्टों की व्यवहार में न आनेवाली धाराओं को रद्द किया और व्यवहार में आनेवाली अन्य सब धाराओं को एकत्र किया और उनको १३५ विभागों और ५ अनुसूचियों के एक ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत किया।

उक्त विधेयक पर जो बाद में सन् १९१५ का ऐक्ट बना, पार्लियामेंट ने, दोनों भवनों की एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी। उसके समक्ष कुछ ऐसे प्रस्ताव आए जो उसके मतानुसार ऐक्ट के क्षेत्र से बाहर थे और इसी कारण प्रवर समिति ने उनको स्वीकार नहीं किया। इन प्रस्तावों को एक नए संशोधनकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक सन् १९१६ में ऐक्ट बन गया।

सन् १९१६ के भारतीय शासन (संशोधन ऐक्ट) ने कुछ साधारण परिवर्तन किए। उनकी धाराओं के अनुसार देशी राज्यों के कुछ छूटे हुए लोग भारतीय सिविल सर्विस परीक्षाओं की प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे, देशी राज्यों और नेपाल प्रदेश के शासकों और निवासियों की सैनिक एवं अर्धसैनिक पदों पर नियुक्ति की जा सकती थी, देशी राज्यों के शासकों और निवासियों को विधान परिषदों के लिए नामनिर्देशित किया जा सकता था।

६

विचाराधीन समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऐक्ट और बनाया, जिसका भारत सरकार के सविधान से सम्बन्ध था। यह था सन् १९११ का भारतीय उच्च न्यायालय ऐक्ट।

सन् १८६१ और १८६५ के विधानों ने उच्च न्यायालयों के सविधान, उनके क्षेत्राधिकार और उनकी संख्या आदि को विनियमित किया था।

सन् १९११ के ऐक्ट ने मुख्य न्यायाधीश-सहित, सब न्यायाधीशों की संख्या १ सन् १९११ में भारत में चार उच्च न्यायालय थे—एक कलकत्ता में, एक बम्बई में, एक मद्रास में और एक इलाहाबाद में। सन् १८६५ के ऐक्ट में जो अधिकार दिया गया था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाने से समान हो गया था। अतः एक नया ऐक्ट बनाया गया और उसमें भविष्य के लिए उक्त धारा जोड़ दी गई।

को साम्राज्यीय तथा प्रान्तीय दोनों ही सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों का परीक्षण करके उनपर अपनी रिपोर्ट देनी थी—(१) भर्ती करने की प्रक्रिया और शिक्षण तथा परीक्षण की व्यवस्था, (२) सेवा, वेतन, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन की शर्तें, (३) यूरोपियनों की नियुक्ति पर प्रचलित प्रतिवन्ध और साम्राज्यीय तथा प्रान्तीय सेवाओं के विभाजन की वर्तमान व्यवस्था।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त कमीशन को सामान्य रूप से इन सार्वजनिक नौकरियों की आवश्यकताओं पर विचार करना था और उनमें उपयुक्त परिवर्तन के लिए सिफारिश करनी थी।

अगस्त १९१५ में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पि यद्दुर्हीम की रिपोर्ट अलग थी और इसे श्री गोखले का "पूर्ण अनुमोदन प्राप्त था, वस्तुतः इसे उन्हीं के परामर्श से तैयार किया गया था।"<sup>२</sup> किन्तु १९ फरवरी १९१५ को श्री गोखले का देहांत हो गया और इस पृथक रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर न हो सके।

रिपोर्ट को उस समय प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि सरकार, महायुद्ध के दिनों में, किसी विवाद में पड़ने से बचना चाहती थी। लेकिन जब महायुद्ध के शीघ्र समाप्त होने की आशा नहीं दिखाई दी, तो अन्त में उस रिपोर्ट को जनवरी १९१७ में प्रकाशित कर दिया गया। मोण्ट फोर्ड रिपोर्ट का कहना है कि, "उस समय तक महायुद्ध ने भारतवासियों की आशाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। (फलतः) रिपोर्ट की निन्दा की गई उसे विलुप्त अपर्याप्त बताया गया, रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को सतुष्ट करने के स्थान पर उसे और ज्यादा बिड़ा दिया।"<sup>३</sup>

कमीशन के सामने सब से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि सार्वजनिक नौकरियों के उच्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए। साम्राज्यीय सिविल सर्विस की अधिकांश शाखाओं के लिए साधारणतया यूरोप के लोगों में से भर्ती की जाती थी। जिन विभागों के लिए भारत में भर्ती की जाती थी, उनमें भी उच्चतर पदों के लिए यूरोपियनों, आंग्ल-भारतीयों और ईसाइयों को अधिमान दिया जाता था। ५०० रुपये प्रतिमास वयवा उससे अधिक वेतन के पदों पर भारतीयों का अनुपात केवल १९ प्रतिशत था। ८०० रुपये अथवा उससे अधिक वेतन के

- १ Islington Commission Report, 1912-15-17. page 2
२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ३९४,
- ३ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 5

पदों पर उनका अनुपात केवल १० प्रतिशत था।<sup>१</sup> वेतन में वृद्धि के साथ भारतीयों का अनुपात उन्नीस से घटता जाता था, यही तब कि ऐसे पर र जिन पर भारतीयों की कभी नियुक्ति ही नहीं हुई थी।

भारतवासियों ने यह उपाय सुझाया था कि इंग्लैंड तथा भारत, दोनों ही म्यांता में प्रतिभागितापूर्ण समकालिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए। कमीशन ने इस सुझाव का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनमें मतानुसार ऐसी व्यवस्था को अपनाते के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। कमीशन का तब यह था कि भारत के विभिन्न प्रांता और समुदायों में शिक्षण-सुविधाओं का पयाप्त और समान रूप में प्रसार नहीं हुआ था। इनके अनिश्चित दूसरा यह था कि भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में इंग्लैंड के स्कूलों और कॉलेजों की भांति चरित्र के विकास और उनके निर्माण के लिए कोई निश्चित सुरक्षा नहीं थी।<sup>२</sup> कमीशन की दृष्टि में सरकारी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था ने भी समस्या का हल नहीं हो सकता था। उनमें उच्चतर पदों में भारतवासियों के लिए एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखने के सिद्धांत का भी अनुमान नहीं किया। यह मचई कि इस प्रश्न पर विचार करने का उचित दृष्टिकोण यह नहीं था कि प्रत्येक विभाग में कितने भारतीय नियुक्त किए जाने चाहिए तथापि नि अनुरोधों का यह कहना बिल्कुल ठीक था, 'कि यूरोप में अधिकारियों का आयात, विद्युद् आवश्यकता से सीमित होना चाहिए।'<sup>३</sup> किन्तु कमीशन के सदस्यों का दृष्टिकोण दूसरा ही था और उन्होंने भारतीयों के लिए अनुपात निश्चित करने के सुझाव को काई मान्यता नहीं दी। इस सम्बन्ध में उनका एक तब का यह था "कि जातीय आधार पर अनुपात निश्चित करने का सिद्धांत अवांछनीय है" और दूसरा तब यह था कि "कि हम इस बात को जानते हैं कि न्यूनतम सीमा की प्रवृत्ति अधिकतम सीमा की ओर बढ़ने की हुका करती है।"<sup>४</sup> लेकिन इन तर्कों के होने हुए भी कमीशन ने निजी प्रस्ताव मुख्यतः जातीय भावनाओं पर अवलम्बित थे।

कमीशन का सबसे पहला प्रस्ताव तो यह था कि जिन नौकरियों के लिए साधारणतया भारत में मनों की जाती है, उनमें कुछ और नौकरियों को भी सम्मिलित कर दिया जाए। अपने दूसरे प्रस्ताव के अनुसार कमीशन ने अन्य नौकरियों

१ ये आठ सन् १९१३ के हैं—देखिए—Islington Commission

Report, pages 24 to 26

२ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ३०।

३ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ४११.

४ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ २६



को तीन वर्गों में विभाजित किया—(१) आई सी एस (भारतीय सिविल सर्विस), आई पी एस (भारतीय पुलिस सर्विस) आदि नौकरियाँ—जिनमें 'अधिकांश अपसरों की भर्ती यूरोप में की जानी चाहिए।' आई सी एस के ७५ प्रतिशत पदों के लिए इंग्लैंड में प्रतियोगिता-पूर्ण परीक्षाओं के द्वारा भर्ती की जानी थी। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु २४ वर्ष से घटा कर १९ वर्ष कर दी गई थी जिसके फलस्वरूप भारतवासियों के लिए इस द्वार से प्रवेश पाना असंभव हो गया था। अन्य २५ प्रतिशत पदों के लिए, भारत में निश्चित योग्यता के अभ्यर्थियों में से नामनिर्देशन होना था। पुलिस सर्विस के लिए भारत में निर्दिष्ट योग्यता केवल १० प्रतिशत अभ्यर्थियों की भर्ती होनी थी, धीरे धीरे यह अनुपात २० प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। (२) दूसरे वर्ग में शिक्षा डाक्टरी सार्वजनिक निर्माण आदि से सम्बन्धित नौकरियाँ की गणना थी इसमें यूरोप-वासियों और भारतवासियों दोनों की ही भर्ती करना वाछनीय समझा गया। (३) तीसरे वर्ग में वैज्ञानिक और टेक्निकल नौकरियों की गणना थी। भारत में टेक्निकल शिक्षा की समस्याएँ खुल जाँ पर कालान्तर में उक्त नौकरियों की भर्ती भारत में होनी थी किन्तु उस समय उनके लिए विदेशों में ही भर्ती की जानी थी।

य प्रस्ताव केवल अपमान ही नहीं था बल्कि ये ब्रिटिश जातीय श्रेष्ठता की धारणा पर और साथ ही कुछ नौकरियों में अंग्रेजों का बहुत बड़ा अनुपात बनाए रखने की नीति पर अवलम्बित था। ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके प्रकाशित होने पर भारत में सर्वत्र उनकी निन्दा की गई।

कमीशन ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने के लिए भी सिफारिश की, जिसका कुल जोड़ पि चौबाल के अनुसार, ८८ लाख रुपये से भी अधिक था। कमीशन के दो भारतीय सदस्यों ने इस बात को निर्विवाद रूप से सिद्ध भी किया कि भारत में इन सिविल अधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि में किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए कोई कारण नहीं था क्योंकि उनको पहले से ही जो वेतन, भत्ता, आदि दिया जा रहा था, बहु इंग्लैंड, सोलोन अथवा हावकांग की सिविल सर्विस की अपेक्षा वही अधिक था।

कमीशन की अन्य सिफारिशें टेक्निकल वर्ग की थी और उन पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, कमीशन की रिपोर्ट को भारत में समी जगह निन्दा की गई और उसे असतोषप्रद तथा अपमानजनक बताया गया। यहाँ तक कि भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट ने भी यह लिखना आवश्यक समझा कि, "अविष्य की नीति, (इंस्टीट्यूट कमीशन की) रिपोर्ट पर

अवलम्बित होनी चाहिए, किन्तु परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण हमारा यह मन है कि कुछ महत्त्वपूर्ण दिशाओं में उसके निष्कर्षों को लागू करना आवश्यक होगा।"<sup>१</sup>

८

सन् १९०९ से १९१९ तक के विभागाधीन युग में वैधानिक दृष्टि से विभिन्न महत्त्व की, एक घटना हुई—भारत को साम्राज्यीय सम्मेलन में, साम्राज्यीय युद्ध परिषद् में तथा शान्ति सम्मेलन के लिए ब्रिटिश साम्राज्यीय शिष्ट मंडल में, साम्राज्य के अन्य स्वशासक सदस्यों के साथ, (प्रकटन) बराबरी का स्थान दिया गया।

सन् १८८७ में, महारानी विक्टोरिया की जयन्ती मनाने के सम्बन्ध में औपनिवेशिक सम्मेलन के नाम से साम्राज्यीय सम्मेलन ने अपनी सब से पहली सभा की थी। उसी औपनिवेशिक सम्मेलन को सन् १९०७ में साम्राज्यीय सम्मेलन का नाम द दिया गया और उसके नए संविधान के अनुसार इसका मतलब था—सम्राट् सरकार तथा औपनिवेशिक सरकारों की, परस्पर सम्बन्धित विषयों पर विचार करने वाली सभा।<sup>२</sup>

पहला साम्राज्यीय सम्मेलन १९११ में हुआ और उससे अगला सम्मेलन १९१५ में होना वाला था, किन्तु महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण उसको अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन दिसम्बर १९१६ में हार्लैंड में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि सन् १९१७ के आरम्भिक महिनो में ही साम्राज्यीय सम्मेलन की मीटिंग की जाए और युद्ध परिषद् के लिए साम्राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए।

सितम्बर १९१५ में भारतीय विमान परिषद् में एक प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश की गई कि सम्राट् सरकार से, साम्राज्यीय परिषद् में भारत को नियमानुसार प्रतिनिधित्व देने के लिए निवेदन किया जाए।"<sup>३</sup> यद्यपि भारत एक स्वशासक देश नहीं था तथापि वाइसरॉय के मंत्रानुसार "भारत के विस्तार, उसकी जनसंख्या, सम्पत्ति, संघ्य सामर्थ्य और राजनयिक के कारण उसकी प्रतिनिधित्व की मांग उचित थी।"<sup>३</sup> फरवरी १९१७ में साम्राज्यीय युद्ध परिषद् और साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन, दोनों की सभाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत मन्त्री को आमंत्रित किया गया। "भारत मन्त्री" के सहस्रवर्ष करने के लिए भारत सरकार के

१. The Report on Indian Constitutional Reforms. 1918. page 149.

२. Mukherjee : Indian Constitutional Documents, vol. I. page 609

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६११

## शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन

तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया—हिब हाइनस बीकानेर नरेश माननीय सर जम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्र सिन्हा ।

साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाएँ अप्रैल १९१५ में हुईं और उनमें जय प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए—(१) साम्राज्यीय सम्मेलन के संविधान में उपयुक्त परिवर्तन किया जावे ताकि भविष्य के सम्मेलनों में भारत भी भाग ले सके और (२) युद्ध समाप्त होने के बाद बना नुक़्तों में भारत भी भाग ले सके और (३) युद्ध समाप्त होने के बाद बना ताकि (अ) इस बात को मान्यता दी जा सके कि विदेश-नीति और विदेश सम्बंध निश्चित करने के विषय में ब्रिटिश डोमिनियनों को और साथ ही भारत को समुचित अधिकार होना चाहिए और (ब) समय समय पर परामर्श करने के लिए और आवश्यकता होने पर मिल कर योजनानुसार कार्यवाही करने के लिए कारण व्यवस्था की जा सके ।<sup>१</sup> एक अन्य प्रस्ताव में समान पारस्परिक व्यवहार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और स्वशासक ब्रिटिश डोमिनियनों में भारतीया की स्थिति के बारे में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए आपन पर विचार करने के लिए सम्बंधित सरकारों से सिफ़ारिश की गई ।

साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाओं के अतिरिक्त साम्राज्यीय युद्ध परिषद् की बैठकें भी हुईं । सन १९१७ की १८ मई को ब्रिटिश प्रधान मंत्री न हाउस ऑफ़ कामन्स में यह बताया कि साम्राज्यीय युद्ध परिषद् की मीटिंग प्रतिबन्ध करने का निर्णय किया गया था लेकिन अविलम्ब साम्राज्यीय प्रश्न उपस्थित होने पर यह मीटिंग जल्दी भी की जा सकती थी । उसी अवसर पर उन्होंने निम्नलिखित व्यक्तियों को परिषद् का सदस्य बताया—संयुक्त राज्य का प्रधान मंत्री और साम्राज्यीय विषयों का संचालन करनेवाले उसके सहयोगी प्रत्येक ब्रिटिश डोमिनियम का प्रधान मंत्री जबवा उसका विशेष रूप से अधिकृत प्रतिनिधि और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ भारतीय जनता का प्रतिनिधि ।<sup>२</sup>

सन १९१८ में भारत सरकार ने (तत्कालीन उप भारत मंत्री) सर सत्येन्द्र सिन्हा को साम्राज्यीय युद्ध परिषद् में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया । साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर सत्येन्द्र के अतिरिक्त पटियाला नरेश को भी नियुक्त किया गया ।<sup>३</sup>

१ Keith Speeches of Indian Policy, vol II page 133  
२ Mukherjee Indian Constitutional Documents vol II page 617

३ साम्राज्यीय विधान परिषद् में एक प्रस्ताव द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की

## क्रान्ति और दमन

राष्ट्र सभ की सदस्यता कोई सामान्य की बात नहीं थी। वरन् वह सदस्यता उसके लिए एक वोल के रूप में थी। उन्हे राष्ट्र सभ के उद्देश्यों पर सदेह था—उनके अनुसार, शोषण करने वाले साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने सभ के रूप में अपनी गृहबन्दी की थी, और भारतीय प्रतिनिधित्व, भारत की अपेक्षा इम्पेड के लिए अधिक उपयोगी था क्योंकि भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था और जब पर ब्रिटिश नियंत्रण होता था। इस बात में कोई सदेह नहीं है कि ये आक्षेप बहुत हद तक सच्चे थे क्योंकि राष्ट्र सभ तथा साम्राज्यीय सस्थाओं की सदस्यता का वास्तविक लाभ उसी समय उठाया जा सकता था जब अन्य सदस्यों की भाँति भारत भी स्वाधीन हो। किन्तु दूसरी ओर यह तक भी बहुत हद तक सही था कि आरम्भिक बातों से चाहे कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ न दिखाई दे तथापि वे बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं।

## अठारहवाँ अध्याय

### क्रान्ति और दमन

१

लॉर्ड मॉन्टे अपनी सुधार-योजना को मित्रता और सम्भावना के वातावरण में कार्यान्वित करना चाहते थे। वह उन्होंने वाइसरॉय पर इस बात की आवश्यकता के अवसर में खोर दिया कि सुधारों के लिए वांछित वातावरण बनाने के उद्देश्य से कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जाय, जिससे सरकार का कृपा भाव प्रदर्शन हो। इस अवसर में उन्होंने बंगाल के निर्वासित व्यक्तियों को मुक्त करने का सुझाव दिया। किन्तु वाइसरॉय के मतानुसार, एक ऐसे समय पर जब भारत के विचारशील व्यक्ति का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था, राजनैतिक क्षेत्र में इन आशयजाले वालों को मुक्त करना अविवेकपूर्ण था।<sup>१</sup> भारत सरकार के प्रबल विरोध ने भारत मंत्रों को उस समय चुप कर दिया और किसी कृपापूर्ण कृत्य के स्थान पर एक बराबरकृतापूर्ण हत्या के बाद सुधारों का उपक्रम किया गया। सन् १९१० की २५ जनवरी को लॉर्ड मिंटो ने नई निर्वासित साम्राज्यीय विधान परिषद् का उद्घाटन किया लेकिन उससे एक ही दिन पहले पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट, रामसुल आलम को गोली से मार दिया गया था।<sup>२</sup> यह अधिकारी अलीपुर पड़वण अभियोग के सिलसले में बलकत्ता हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ

१ Buchan: Lord Minto, page, 392

२ इसी पुस्तक का तेरहवाँ अध्याय देखिए।

## क्रान्ति और दमन

पद्धति के साधारण नियमों को निरुन्धित करके, सरकार ने साम्राज्यीय विधान-परिषद् से जल्दी से एक बठोर प्रेस कानून बनवाया। यही कानून सन् १९१० के इंडियन प्रेस ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सन् १९१० के इस ऐक्ट में, सन् १८७८ के वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट की सारी गहिरी धाराएँ बर्तमान थी। किन्तु दो बातों में महत्त्वपूर्ण अन्तर था—नया ऐक्ट सब समाचार पत्रों पर लागू था चाहे वे पत्र भारतीय भाषाओं के हों अथवा अंगरेज़ी के और चाहे वे आँग्ल भारतीयों के हों अथवा भारतवासियों के, और दूसरा अन्तर यह था कि नए ऐक्ट की एक धारा के अनुसार हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी।

सन् १९१० के इस ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर मजिस्ट्रेट नए छापेखानों के मुद्रकों और साथ ही नए समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से (सन् १८६७ के प्रेस तथा पुस्तक निबन्धन ऐक्ट की धारा नं० ४ के अन्तर्गत उनसे अपने समस्त घोषणा कराने के बाद) कम-से-कम पाँच सौ और अधिक-से अधिक दो हजार रुपये की जमानत माँग सकता था। नए ऐक्ट के लागू होने के पहले से जो प्रेस काम कर रहे थे, और जो समाचार-पत्र निकल रहे थे, उनके सबब में भी ऐक्ट ने स्थानीय सरकारों को निश्चित प्राधिकार दिया। इसके अनुसार स्थानीय सरकारें उक्त छापेखानों के मुद्रकों अथवा उक्त समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से (यदि वे ऐक्ट के विभाग नं० ४ (१) के अन्तर्गत आने वाले लेखों को छापते या प्रकाशित करते हों), कम-से-कम पाँच सौ और अधिक-से-अधिक पाँच हजार रुपये की जमानत माँग सकती थी। ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर मजिस्ट्रेट, किसी प्रेस अथवा समाचार-पत्र की जमानत को (कारणों का अभिलेख करने के बाद), छोड़ सकता था अथवा इस सबब में अपनी किसी पिछली आज्ञा को रद्द कर सकता था अथवा उसे बदल सकता था।

१. आँग्ल-भारतीय पत्रों को सम्मिलित करने का व्यवहार कोई अर्थ नहीं था। वे राजद्रोह का प्रचार नहीं कर सकते थे और जातीय भेदभाव के प्रचार के तिलसिले में सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती थी।—देखिए इसी पुस्तक का बारहवाँ अध्याय—*धोर Paragraph 7 of the Report of the Press Laws Committee, 1921*
२. Section 3 (i) of the Act, Ghose Press and Press Laws in India, page 66.
३. Section 8 (1) of the Act. Ibid, page 69.

ऐक्ट ने अपन विभाग न ४ (१) के छै विस्तृत छहो<sup>१</sup> में आपत्तिजनक बातों की परिभाषा बताई। इन बातों का मुद्रण अथवा प्रकाशन होने पर स्थानीय सरकार जमानत ज्ञप्त कर सकती थी। सन् १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एक्ट<sup>२</sup> और उसी वर्ष का समाचार पत्र (अपराध उत्तजन) एक्ट<sup>३</sup> के अपराधों का सन् १९१० का एक्ट में फिर सम्मिलित किया गया। राजद्रोहपूर्ण प्रकाशन का परिभाषा इनकी विस्तृत कर दी गई कि उसमें देशी नरेशा, न्यायाधीशा, काय वारिणों जफ़्फ़रा और मार्जजनिव अविकारिया के विरुद्ध हस्त लिखने की भी गणना की जा सकती थी। मन्दाई की मेना में नौकरी करने वालों में अमर्ति फ़ैलान के अथवा नानिकारी कामों के लिए रपया बमूर करने के उद्देश्य में लाल को धमकाने व अथवा नानिकारी अपराध की खोज और गवाही में सहायता देने वाला का रोकने के सारे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयत्न, विभाग न ४ (१) की आपत्तिजनक बातों की परिभाषा में सम्मिलित थे। वस्तुतः इन विभाग न, समाचार-पत्रों के लिए सरकारी कामों की आलाचना करना असम्भव कर दिया था। किन्तु इससे भी ज़ग़ादा बुरो बान यह थी कि कोई प्रकाशन, विभाग न ४ (१) की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार साधारण न्यायालया के स्थान पर स्थानीय सरकार को दिया गया था।

यदि विभाग न ४ (१) के अनुसार स्थानीय सरकार ने किसी छापेखाने की अथवा किसी समाचार-पत्र की जमानत ज्ञप्त कर ली है और उस छापेखाने का मुद्रण<sup>४</sup> अथवा उस पत्र का प्रकाशन,<sup>५</sup> सन् १८६३ के प्रेस तथा पुस्तक निबन्धन ऐक्ट के विभाग न ४ के अनुसार फिर घोषणा करता है तो प्रत्येक को (मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार) कम-से-कम एक हजार रुपये की और अधिक-से-अधिक दस हजार रुपये की जमानत देनी थी। यदि स्थानीय सरकार के मतानुसार उक्त प्रेस अथवा उक्त पत्र, विभाग न ४ (१) के अन्तर्गत फिर अपराध करता है, तो वह सरकार उसकी जमानत को, छापेखाने को और समाचार-पत्र की सारी प्रतियाँ को और अन्य आपत्तिजनक प्रकाशना को ज्ञप्त कर सकती थी।<sup>६</sup>

१. Section 4 (i) of the Act, Ghose The Press and Press Laws in India, pages 67-68

२. इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये।

३. इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये।

४. Section 5 of the Act, Ghose The Press and Press Laws in India, page 68

५. Section 10 of the Act उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०

६. See sections 6 and 10 of the Act, Ghose : The Press and Press Laws in India pages 69—71.

## क्रान्ति और दमन

इसी सदन में ऐक्ट ने स्थानीय सरकारों को एक बात का अधिकार और दिया।<sup>१</sup> इस अधिकार के अनुसार स्थानीय सरकारें, कस्टम विभाग के किसी अफसर को अथवा किसी डाकखाने के प्रमुख कर्मचारी को यह आज्ञा दे सकती थी कि यदि उस अधिकारी को इस बात का सन्देह हो कि किसी पार्सल, बडल अथवा लिफाफे में कोई ऐसी चीज है जो विभाग न ४(१) के अन्तर्गत आपत्तिजनक है तो वह उस पार्सल, बडल, अथवा लिफाफे को रोक ले और उसे स्थानीय सरकार को सौंप दे।

अन्त में १९१० के इस ऐक्ट ने स्थानीय सरकार की आज्ञा रद्द कराने के लिए, हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया। इस अपील का निर्णय तीन न्यायाधीशों की विशेष सभा द्वारा होना था।<sup>२</sup> यह अपील जल्दी की आज्ञा के दो महीने के अन्दर ही इस आधार पर की जा सकती थी कि जिस विषय पर आपत्ति की गई है उसकी विभाग न ४(१) के अन्तर्गत गणना नहीं की जा सकती।

इस ऐक्ट को लागू करने के कारण, सन् १९०९ से १९१९ तक के विचारार्थीन युग में जो परिणाम हुए, उनका सक्षिप्त सकलित विवरण २ जुलाई १९१९ के उस समुद्री तार में दिया गया है जो इंडियन प्रेस एसोसियेशन के मंत्री ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री और भारत मंत्री के पास भेजा था — “इस ऐक्ट के अन्तर्गत ३५० छापेखानों को, ३०० समाचार-पत्रों को दंड दिया गया, ४०००० पौंड से अधिक की जमानतें ली गईं, ५०० से अधिक प्रकाशन बन्द किए गए। जमानत न दे सकने के कारण २०० प्रेस काम शुरू नहीं कर सके, १३० समाचार-पत्रों का प्रकाशन नहीं हो सका। (भारतवासियों के) ‘अमृत बाजार पत्रिका’, ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’, ‘हिन्दु’, ‘इंडिपेन्डेंट’, ‘ट्रिब्यून’ जैसे प्रमुख, प्रभावशाली अंगरेजों के पत्रों पर और वसुमती, स्वदेश मित्र, विजय, हिन्द वासी, भारत-मित्र’ जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों पर ऐक्ट की कठोर धाराएँ लागू की गईं। दूसरी ओर आर्य-भारतीय पत्रों के उद्य, उत्तेजक लेखों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।”<sup>३</sup> भारत सरकार पर, ऐक्ट के परिणामों के सवध में जांच करने के लिए जोर दिया गया लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। अन्त में यह विषय सन् १९२१ की नई विधान सभा के सामने आया और उसने जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की।

१ ऐक्ट के विभाग न १३ और १५ देखिये, *The Press and Press Laws in India* पृष्ठ ७१ और ७२

२ ऐक्ट का विभाग न १७—उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७२

३ ऐक्ट का विभाग न १८—उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७२

४. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३९-४०.

३-

प्रेस ऐक्ट का पारण करने के कुछ ही महीने बाद सरकारने एउ विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य सन् १९०७ के राजकोटपूर्ण मोर्निंग वरन ऐक्ट<sup>१</sup> के जीवन-काल को २१ मार्च १९११ तक बढ़ाना था—ताकि नए गवर्नर-जनरल को अपना पद-ग्रहण करने के बाद स्थिति को स्वयं देखने, उन पर अपना नया बाने और उक्त मध्य में अपनी निष्कारियों करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। सन् १९०७ का एक्ट पूर्ण समूह और पञ्चाङ्ग<sup>२</sup> का सत्वालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया था और वह समाधारण रूप से दमनकारी था। जैसा कि श्री गोखले ने विधान परिषद् में कहा<sup>३</sup> उक्त ऐक्ट को बढाव नतीजा के साथ और अनुचित रूप में लागू किया गया था। अगस्त १९१० तक स्थिति आज़ी मुनक चुकी थी और जैसा कि बादसरॉय और सरकारी सदस्यों ने स्वीकार भी किया था, वह स्थिति सबूतपूर्ण अवस्था असाधारण नहीं थी। अतः और सरकारी सदस्यों ने उस ऐक्ट का जीवन-काल बढ़ाने वाले विधेयक का विरोध किया क्योंकि आवश्यकता होने पर वह ऐक्ट फिर भी बनाया जा सकता था। लेकिन सरकार अपने निरवय पर जमी रही<sup>४</sup> और अगस्त १९१० में उक्त विधेयक का पारण हो गया।

सन् १९०७ का यह ऐक्ट मार्च १९११ में फिर भारतीय विधान परिषद् के सामने आया। इस बार सरकार ने ३१ मार्च के बाद उक्त ऐक्ट के लिए द्वितीय बीदन-

१. *The Press and Press Laws in India* नामक पुस्तक का चौदवाँ अध्याय देखिये।

२. सन् १९०७ की परिस्थितियों के बर्न के लिए इसी पुस्तक का तेरहवाँ अध्याय देखिये।

३. तीन दिना सम्मानों को बर्न करने का यह कारण दिया गया कि उनमें भारतीय एक प्रांतीय विधेयक पर विचार होगा। सभा करने की अनुमति देने से पहले प्रस्ताव मीने जाते थे। दलित वर्गों को अपनी सत्ताधिकारियाँ व्यक्त करने के लिये सभा करने की अनुमति नहीं दी गई।—देखिये—*Gokhale's Speech—Legislative Council Proceedings, Vol. XLIX. Page 30*

४. श्री मोनरो, मालवीन, म्बोलकर, चिन्हा, मन्मथ हन, सूबा राय आदि सब गवर्नरसारी सदस्य इस विधेयक के विरुद्ध थे।

५. "श्रीमान्, हम इस बात को भली भाँति जानते हैं कि जब सरकार किसी नीति को अपनाने का निश्चय कर लेती है तो इस परिषद् के गवर्नरसारी सदस्यों का मत उसे बदल नहीं सकता।"—देखिये *Gokhale's Speech—Legislative Council Proceedings, Vol. XLIX. Page 29.*



## क्रान्ति और दमन

दान देने का विचार नहीं किया किन्तु उसके स्थान पर और उसी उद्देश्य से एक नया, कम कठोर, स्थायी कानून बनाने का निश्चय किया। फलतः सन् १९११ के राजद्रोह पूर्णमीटिंग वर्जन ऐक्ट का आचमण पारण हुआ और उसे प्रविधान पुस्तक (Statute Book) में स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया गया।<sup>१</sup>

सन् १९११ के ऐक्ट ने सन् १९०७ के ऐक्ट के कुछ स्पष्ट दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। सबसे पहली बात तो यह हुई कि नया ऐक्ट, सन् १९०७ के ऐक्ट की जनरल की विनिर्दिष्ट अनुमति के बाद ही, किसी प्रदत्त अथवा प्रान्त में लागू किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पुराने ऐक्ट की एक धारा के अनुसार दोस से अधिक व्यक्तियों की प्रत्येक सभा को साप्ताहिक सभा माना जाता था। नए ऐक्ट में दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि उक्त धारा को छोड़ दिया गया। इसी ऐक्ट में तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि वर्जित सभाओं की परिभाषा देने वाले खण्ड न ४ में से किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये शब्दों को निकाल दिया गया। अब केवल वही सभाएँ वर्जित होती थीं जिनसे सार्वजनिक शान्ति भंग होने का डर हो। ऐक्ट में चौथा परिवर्तन यह था कि भविष्य में सार्वजनिक सभा करने की सूचना, पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस काम के लिए अधिकृत अन्य किसी मजिस्ट्रेट को देनी थी। इन परिवर्तनों को छोड़ कर, सन् १९०७ के ऐक्ट की धाराओं का सन् १९११ के ऐक्ट में यथायत् विधायन कर दिया गया।<sup>२</sup>

इन संशोधनों के बावजूद अधिकांश गैरसरकारी सदस्यों ने नए कानून का विरोध किया और उसे अनावश्यक, स्वेच्छापूर्ण और दमनकारी बताया। उसने कार्यकारिणी को विस्तृत, स्थायी एवं असाधारण अधिकार दिए जो देश के सार्वजनिक जीवन के लिए घातक थे।

४

इन दमनकारी प्रविधानों के पारण से भारतीय शान्तिकारियों के कामों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजनैतिक हत्याएँ और इकंतियाँ—विशेषकर पूर्वी बंगाल और कलकत्ता में—पहले ही की तरह होती रही। २४ जनवरी १९१० को कलकत्ता के हिण्टी सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस की हत्या हुई—उसकी चर्चा की जा चुकी है। मार्च १९१० में हावड़ा पड़ोस केस आरम्भ हुआ। उसमें ५० व्यक्तियों पर राजनैतिक हत्याओं का और सम्राट् के विरुद्ध पड़ोस रचन का अभियोग लगाया गया था।<sup>३</sup> जुलाई में हाका पड़ोस केस में ४४ व्यक्तियों पर फिर वही १ बाद में सन् १९२१ की रिप्रसिव लाज कमेटी की सिफारिश पर इस ऐक्ट का रद्द कर दिया गया।

२ इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिय।

३ Indian Sedition Committee Report, 1918, page 44

५

इस प्रकार भारत के श्रान्तिकारी अपराधों को रोकने में न तो सुधार ही सफल हुए और न १९१० और १९११ के दमनकारी कानून, किन्तु दमनकारी कानूनों की सामर्थ्य के सबध में सरकारी निष्ठा यथावन् बनी रही। मार्च १९१३ में सरकार ने भारतीय विधान परिषद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता में कुछ संशोधन करना था। यही विधेयक, बाद में सन् १९१३ का ज़ौबदारी कानून (संशोधन) ऐक्ट बन गया।

इस ऐक्ट ने पड़्यत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता में वृष्य स्थापित किया। उस समय तक यह अपराध भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित होने से किसी प्रकार छूट गया था, और गृह-सदस्य के अनुसार सन् १९१३ के विधेयक का उद्देश्य एक छूटी हुई बात की पूर्ति करना था। गृह-सदस्य ने यह भी कहा कि नया कानून, इंग्लैंड के कानून के ढंग पर ही बनाया गया था किन्तु ग़रसरकारी सदस्य इस बात को जानते थे कि उसे भारत में बड़ी कठोरता के साथ लागू किया जायगा और उसके दो कारण थे। मिस्टर एस एन बनर्जी ने पहला कारण यह बताया कि इंग्लैंड में अभियोगों का निर्णय जुरी द्वारा होता था और वहाँ पर न्याय का स्तर भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा ऊँचा था। और दूसरे कारण को मि जिन्ना ने इस प्रकार व्यक्त किया कि दोनों देशों की ज़ौबदारी-पद्धति भिन्न थी और वह इंग्लैंड में, अभियुक्त के प्रति कहीं ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण थी। मि जिन्ना ने यह भी कहा कि नए कानून राजसत्ता के विरुद्ध पड़्यत्रा पर ही लागू होने चाहिएँ—व्यक्तिगत पड़्यत्रों पर नहीं। प्रवर-समिति ने स्मिति का सरक्षण करने का प्रयत्न किया और ज़ौबदारी पद्धति संहिता में कुछ संशोधन भी किया।

सन् १९१३ के ऐक्ट की सब से ज्यादा महत्वपूर्ण बात, विभाग न १२० (अ) के अन्तर्गत, पड़्यत्र की परिभाषा थी—अन्य बातें गौण थी। परिभाषा इस प्रकार थी—

“जब दो या अधिक व्यक्ति, एक होकर (१) किसी अवैध काम को अथवा (२) किसी वंश काम को अवैध साधनों द्वारा, करने अथवा कराने के लिए सहमत होते हैं, तो उनका समझौता एक अपराधपूर्ण पड़्यत्र है। किन्तु अपराध करने अथवा कराने के समझौते के अतिरिक्त अन्य कोई समझौता अपराधपूर्ण पड़्यत्र नहीं है, जब तक कि समझौते के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिससे समझौता करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों का उद्देश्य प्रभावित होना हो।”

विभाग न १२० (अ) बन जाने से भारत की श्रान्तिकारी समितियों की

बढ़वार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। वन्नि भव तो यह है, कि अगले तीन वर्षों में देश में आन्तिकारी आन्दोलन तेजी से बढ़ा और उच्च की भाँसाएँ पत्राव प्रान्त तक फैल गईं।

६

सन् १९१२-१६ के वर्षों में आन्तिकारी आन्दोलन, बंगाल और पत्राव, बोना ही प्रान्तों में अपन दिखर पर पहुँच गया। बंगाल में पिस्तौल और बम की सहायता से राजनैतिक हत्या करने और राजनैतिक हर्षणियाँ डालने का प्रयत्न बयावन् बना रहा, और उनके अनिश्चित एक व्यापक व्युत्थान का निष्पन्न प्रयत्न भी हुआ। इस व्युत्थान की योजना जनन अभिवृत्तियों की सहायता से सँवार की गई थी। इस जनन-वगात्रों पद्धति का अथवा अराजकतापूर्ण हत्याओं और हर्षणियाँ का विम्वन बिबरन देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता क्योंकि सन् १९१८ की मिडोघन कमेटी रिपोर्ट के पृष्ठों में वह सग्लना से मिल सकता है। तथापि उनका स्रोत में वर्णन करना उचित और नग्न होया।

सन् १९१३ में बंगाल प्रान्त में आन्तिकारियों ने १६ अराजकतापूर्ण प्रहार किए—इनमें दस हर्षणियाँ थी जिन में दो हत्याएँ और अगस्त १९००० रुपये की लूट सम्मिलित थी। २७ मार्च का मिडहिट में बम द्वारा मि गॉर्टन ब्राई सी एस की हत्या करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु मि गॉर्टन के मकान तक पहुँचने से पहले ही बम फट गया और बम ले जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। २९ दिसम्बर को कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर में हँड वास्टेबिल हरिप्र देव को गोली से मार दिया गया। उसके दूसरे दिन मैमनसिंह में इम्पेक्टर बकिमचन्द्र चौधरी की बम द्वारा हत्या की गई। ९ दिसम्बर को मिदनापुर में अष्टुग्रहमान की हत्या करने का फिर असफल प्रयत्न किया गया और ३० दिसम्बर को हुगली जिले के एक घाने में बम फँका गया। सन् १९१४ में २९ अराजकतापूर्ण हत्याएँ—इनमें १६ हर्षणियाँ थी जिनमें कुछ हत्याएँ भी सम्मिलित थी। शोभा एड कम्पनी नामक कलकत्ता के बन्दूक अर्द्ध शस्त्रों के विनिर्मात्रों के यहाँ से, पिस्तौल और उनके कारतूसों के दस बक्खों की चोरी की गई। इन बक्खों में ५० मोडर पिस्तौलें थीं और उनके लिए ४६००० कारतूस थे। इनके अनिश्चित चार हत्याओं के सफल प्रयत्न किए गए—एक चटगाँव में, एक टाका में और दो कलकत्ता में। इनमें से कलकत्ता की पहली हत्या, खुफिया विभाग के इम्पेक्टर नृपेन्द्र घोष की थी, जिनको तीन प्रमुख मटका के एक केन्द्र पर ट्राम में उतारने के समय मारा गया था। एक व्यक्ति ने हत्या करनेवाले का पीछा किया किन्तु उसे भी मार

दिया गया। दूसरी हत्या २५ नवम्बर को हुई—डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट बसन्त चटर्जी के मकान में दो बम फेंके गए। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट तो बच गया लेकिन एक हैड कास्टेबल मारा गया और तीन आदमी घायल हो गए।

सन् १९१५, इस युग का सबसे ज्यादा कलुषित वर्ष था और उसमें कितनी ही डकैतियाँ और जनसन्तोष पैदा करने वाली हत्याएँ हुईं। बड़ी रकमों ले जानेवाले लोभो को, अमेरिका के ढग पर, पिस्तौल और मोटर कार की सहायता से आम सड़कों पर लूटा गया, और जर्मन-बगाली पड़पच का भी इसी वर्ष पता लगा। अकेले कलकत्ता शहर में ही दस अराजकतापूर्ण आघात हुए, इनमें से दो में, अमेरिकन ढग पर मोटर टैक्सी की सहायता ली गई। निरोध हालदार के अतिरिक्त, पुलिस-दरोना सुरेशचन्द्र मुकुर्जी, उप-दरोणा गिरोद वनर्जी तथा उपेन चटर्जी और एक कास्टेबल की हत्या की गई। कलकत्ता के इसी क्रान्तिकारी दल ने जिसका नेतृत्व अतीत मुकुर्जी और विपिन गंगुली के हाथों में था, कलकत्ता के बाहर पाँच आघात और किए। पूर्वी बंगाल में १६ आघात हुए—इनमें से तीन आघातों में सुयोजित हत्याएँ की गईं। पहली हत्या तो बामिला स्कूल के हेडमास्टर धरतु कुमार बसु की थी और दूसरी हत्या मोट्टे बिस्वास की थी जो मुखबिर हो गया था। तीसरी हत्या विशेष रूप से गहिरी थी। मंगलसिंह की पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट अतीत मोहन अपने बच्चे को गोद में लिये हुए, अपने घर में बैठे हुए थे, उन पर गोली चलाई गई और उसके फलस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। उत्तरी बंगाल में, सबसे पहला क्रान्तिकारी अपराध भी १९१५ में हुआ। रागपुर के एडिशनल पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट राय साहब नन्दकुमार बसु को, जो अपने घर पर ही थे, गोली से मारने का प्रयत्न किया गया, पर वे बच गए। उनके नौकर ने गोली मारने वाली का पीछा किया पर उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। हत्या के इस प्रयत्न के अतिरिक्त रागपुर जिले में एक डाका डाला गया और एक डाका राजबाही जिले में भी डाला गया—इन दोनों डाकों में लगभग ७५००० रुपये की सम्पत्ति लूटी गई।

सन् १९१६ में छ हत्याएँ की गईं, जिनमें बसन्त चटर्जी की हत्या भी सम्मिलित थी, और कुछ डाके डाले गए जिनमें से कई डाके असफल भी रहे। इसी वर्ष बहुत से लोगों को जिन पर क्रान्तिकारी होने का संदेह था, सन् १८८८ के विनियम न ३ के अन्तर्गत अथवा सन् १९१५ के डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया।<sup>१</sup> सन् १९१७ में कुल ९ आघात हुए, जिनमें से तीन को १९१६ में छोड़ दिया गया था। सन् १९१५ के ऐक्ट के अन्तर्गत २३८ व्यक्ति नजरबन्द किए गए थे—देखिये

हुए, जिनमें से दो में, पुराने नातिनारी नावियों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया—एक की अवैधता के अन्तर्गत पर और दूसरे की विश्वासघात के अन्तर्गत पर, पहली हत्या का प्रयत्न सफल हुआ किन्तु दूसरी हत्या के प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। इन हत्याओं के अतिरिक्त छ अर्बनिया का प्रयत्न किया गया जिनमें से एक अत्यन्त सफलपूर्ण थी। बर्लिन के जर्मानीपन स्मिथ में एक मराठा की दुकान पर रात के नौ बजे हमला किया गया जिसके फलस्वरूप दो आदमी मारे गए, दो घायल हुए और बहुत से बहुमूल्य रत्ना और आभूषणों को लूट लिया गया। इन प्रयत्न में एक हमला करनेवाला भी मारा गया।

बंगाल के अराजकतापूर्ण अपराधों के इस वर्णन को पूरा करने के लिए मन् १९१५ के जर्मन-बंगाली सहयोग की सशस्त्र चर्चा करना आवश्यक है।

### ७

विदेशों में रहनेवाले भारतीय नातिनारियों ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए महायुद्ध से लाभ उठाने का और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयत्न किया। भारत में व्यापक व्युत्थान होने की दशा में, यूरोप में अंग्रेजों की दक्षिण घटना स्वाभाविक था और जर्मन अधिकारियों ने इसी दृष्टिकोण में भारतीय नातिनारियों के लिए धन और दत्तों का प्रवर्णन करने के विचार को स्वीकार किया। इस दिशा में जर्मन-भारतीय सहयोग के लिए बर्लिन की 'इण्डियन नेशनल पार्टी' स्थापित की गई और इसे 'जर्मन जनरल स्ट्राफ' के साथ अनुवर्णित कर दिया गया। इस पार्टी के संगठनकर्त्ता थे मि पिलाई जो जर्मनी की इटलियनल ग्री इटलिया कमेटी के अध्यक्ष थे। अमेरिका की गहरा पार्टी के सम्पादन हर दमास, बरतुल्ला, तारतनाबदास, के० सी० पञ्चवर्ती और हेरम्यदान गुप्त आदि व्यक्ति इस नई पार्टी के सदस्य थे।<sup>१</sup> पार्टी ने बंगाल और पञ्जाब, दोनों ही प्रान्तों में समकान्ति व्युत्थान की योजना बनाई और उसके उपादन के निमित्त तीन केन्द्र बनाए। इनमें से एक केन्द्र बंगाल में, बंगाल के लिए था, दूसरा केन्द्र बर्मा में, अमेरिका से पञ्जाब को फिर लौटने वाले सिकता के लिए था, और तीसरा केन्द्र काबुल में, उत्तरी भारत के मुसलमानों के लिए था। अमेरिका में दो भारतीय नवयुवकों को भर्तन करने के लिए भेजा गया—संयेंद्र मेन को बंगाल में संगठन करना था और पिपले को बड़ी काम यू० पी० और पञ्जाब में करना था। नवम्बर १९१४ में वे अमेरिका से बतधता आए और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने लगे। मन् १९१५ के आरम्भ में

१. Indian Sedition Committee Report, 1918, page 119

## क्रान्ति और दमन

यूरोप से जितेन्द्र नाथ लाहिरी को भेजा गया और उसके द्वारा, सहायता के लिए निश्चित जर्मन वायवासन मिला।

बंगाल के श्रान्तिकारियों ने जितेंद्र मुकुर्जी और नरेंद्र भट्टाचार्य के नेतृत्व में, बंगाल में व्युत्थान के लिए जर्मन-योजना में सहयोग देने का निश्चय किया। नरेंद्र भट्टाचार्य को सी मार्टिन के बदले हुए नाम से बटाविया भेजा गया और उसका काम जर्मन अभिकर्ता थियोडोर हेल्फेरिख से मिलकर योजनाओं को सुनिश्चित करना था। 'मैवरिक' और 'हैनरी एस०' नाम के दो जहाजों से भारत के लिए शस्त्र और धन भेजने का निश्चय किया गया। बटाविया से आनेवाले इस सामान को छुड़ाने के लिए 'हैनरी एंड सन' नाम की जाली कम्पनी बनाई गई। यह अनुमान किया जाता था कि बंगाल की सेना से निपटने के लिये श्रान्तिकारी संगठन की शक्ति पर्याप्त होगी और दूसरे प्रान्तों की सैन्य-सहायता को रोकने के लिए यह निश्चय किया गया कि बंगाल को शप भारत से जोड़नेवाले तीन प्रमुख रेल मार्गों के बड़े बड़े पुलों को उड़ा दिया जाय। मुन्दरवन क्षेत्र में राय भगल नामक स्थान पर, बटाविया से आनेवाले सामान को उतारने की और उसको एक निकटवर्ती स्थान में जमा करने की व्यवस्था की गई। बाद में उसी स्थान से, इन हथियारों का श्रान्तिकारी संस्थाभा में वितरण होना था।

'मैवरिक' जहाज सैन फ्रान्सिस्को से रवाना हुआ और उसमें इरानियों के बेश में पाँच भारतीय श्रान्तिकारी, जहाज के परिचारकों के रूप में मौजूद थे, किंतु जहाज ने अपना नौभार नहीं लिया था। सोकोरो द्वीप के निकट 'मैवरिक' की 'एनी लासॉन' नामक स्कूनर (छोटा जहाज) से भट होनी थी। स्कूनर को न्यूयार्क से टोशर नामक जर्मन व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए हथियार साने थे और उक्त द्वीप के निकट 'मैवरिक' को सपने थे। 'मैवरिक' ने इन हथियारों को अपने तले में एक तेल के खाड़ी कुंड में छिपाने की व्यवस्था की थी। किंतु 'एनी लासॉन' की 'मैवरिक' से नियत समय पर भेट नहीं हो सकी और धन में वह लौटकर वाशिंगटन प्रदेश में एक स्थान पर पहुँचा, जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारियों ने उसके नौभार को जून १९१५ में पकड़ लिया। दूसरी ओर 'मैवरिक' जाया पहुँचा पर वह खाली था, बाद में उसे अमेरिका वापस भेज दिया गया।

'हैनरी एस०' को मनीला से रवाना होना था किंतु सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने शस्त्र आदि के उसके नौभार को पकड़ लिया और उसे वहीं उतरवा लिया। यह सामान चटगाँव (पूर्वी बंगाल) के लिए निर्दिष्ट था। इन प्रयत्नों के असफल हो जाने पर, शर्माई के जर्मन राजदूत ने हथियारों के

दो अन्य जहाज बेजने की व्यवस्था की। इनमें से एक का सामान हटिया में उतरना था और दूसरे का सामान बालासोर में उतरना था। किंतु वह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि इस बीच में भारत सरकार को सारे पड़्यत्र का पता लग गया और उसने उस पड़्यत्र को कुचलने के लिए समुचित प्रयत्न कर लिया। बंगाल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पकड़ने के प्रयत्न में दो ज्ञानिकारी मारे भी गए। इस पड़्यत्र से सम्बन्धित जो लोग घायाई में थे उन्हें वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन अधिकारियों ने अमेरिका के भारतीय ज्ञानिकारियों और उनके जर्मन-महादूतों पर सरकार की आर से दो मुकदमे चलाए—एक गिवागो में और दूसरा सैन फ्रान्सिस्को में।

८

उपद्रव का दूसरा केन्द्र पञ्जाब में था। सन् १९१३-१६ के बीच वहाँ का नातिकारी आन्दोलन, बंगाल के आन्दोलन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया।

सन् १९०३-०८ में पञ्जाब की स्थिति के सम्बन्ध में एक पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है, किन्तु उम समय वहाँ का आन्दोलन किसी भी रूप में नातिकारी नहीं था। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि पञ्जाब के ज्ञानिकारी आन्दोलन की नींव सन् १९०८ में रखी जा चुकी थी। सिडीरात कमेटी ने<sup>१</sup> और साथ ही सर माइकेल ओ'हायर<sup>२</sup> ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अराजकतापूर्ण आन्दोलन से लाला लाजपत राय का सम्बन्ध था और उन्हीं के मकान से हरदयाल ने नवयुवकों को अराजकता के पथ पर अग्रसर करने का काम आरम्भ किया था। किन्तु लाला लाजपत राय ने लिखा है—“महाराज बयान बिल्कुल झूठा है।”<sup>३</sup> वह अपने बचन की सवाई को सिद्ध करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा है कि हरदयाल शहर में एक किराये के मकान में रहते थे जो उनके मकान से लगभग एक मील दूर था। महत्त्व है कि वह मि० चटर्जी आदि अपने नवयुवक मित्रों के साथ कभी-कभी उनमें मिलते आते थे। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत है कि मि० अजीतसिंह, माडले में लौटने के बाद अराजकता पूर्ण आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे।<sup>४</sup> सन् १९०९ में वे ईरान भाग गए और वहाँ से पेरिस और जेनेवा होते हुए रिजो डी-जेनेरो (दक्षिण अमेरिका) चले गए। सर माइकेल ओ'हायर के अनुसार पहले महामुद्र के दिनों में मि० अजीतसिंह का अमेरिका की गदर पार्टों से

१. See pages 144 and 145 of the Report.

२. O'Dwyer: India as I Knew it, page 186.

३. Lajpat Rai: The Political Future of India, page 163.

४. इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

सम्बन्ध था। अस्तु, दूसरे महायुद्ध के दिनों में वे इटली में थे। १५ अगस्त १९४७ के बाद उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी गई। लेकिन १९४८ में उनकी मृत्यु हो गई।

जहाँ तक पंजाब के क्रान्तिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, यह बात अब निर्विवाद है कि हरदयाल उस आन्दोलन के वास्तविक संस्थापक थे। हरदयाल दिल्ली के रहने वाले थे और उनका विद्यार्थी जीवन बड़ा उज्ज्वल था। सरकार से उन्हें विदेश-छात्रवृत्ति मिली और १९०५ में वे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन् १९०७ में छात्रवृत्ति छोड़ कर वे भारत चले आए। विदेशी राज्य का अन्त करने के उद्देश्य का प्रचार किया। अपने काम के लिए उन्होंने लाहौर के दो नवयुवकों को भर्ती किया—एक तो मि० जे० एन० चटर्जी थे जो बाद में वॉरिस्टरी के अध्ययन के लिए इंग्लैंड को चले गए, और दूसरा नवयुवक था दीनानाथ जो बाद में मुखविर हो गया। उन्होंने इन नवयुवकों के शिक्षण का भार दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द का सौंपा। उन्होंने इन नवयुवकों के शिक्षण का भार दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द का सौंपा। उन्होंने इन नवयुवकों के शिक्षण का भार दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द का सौंपा। उन्होंने इन नवयुवकों के शिक्षण का भार दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द का सौंपा।

सन् १९१३ में सरकार को इस क्रान्तिकारी दल का पता लगा और उसके सदस्यों पर पड़पत्र का मुकदमा चलाया गया। यह अभियोग, दिल्ली पड़पत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। “मुकदमे के सिलसिले में जो गवाहियाँ सामने आईं, उनसे इस बात का संदेह होता है कि (बाइसराँय लॉर्डे हार्डिज पर बम फेंकने से सम्बन्धित) दिल्ली-कांड के लिए यही लोग उत्तरदायी थे। इन लोगों ने अत्यन्त उग्र तथा उत्तेजक पत्रें भी वाँटे थे। ये पत्रें कलकत्ता से प्राप्त किए गए थे। यह बात भी सिद्ध हुई कि इन्हीं लोगों की योजना ने अनुसार बसन्तकुमार दास ने १७ मई १९१३ को कुछ यूरोपीयों को मारने अथवा घायल करने के उद्देश्य से लाहौर के लारेंस गार्डन की एक सड़क पर बम रखा था। उस बम से एक भारतीय चपरासी की,



जो अंदरे में गाढ़बूट पर बा रहा था, मृत्यु हो गई थी।<sup>१</sup>

इन अंतराधानों के लिए कमिश्नरों की बड़ा बंदोब दंड दिया गया। बनौर बन्द, बबब विहारो, बान महुन्द और बगनुकुमार बान को फाँसी की बन्दा दी गई और दो को मान मान का बन्दोब बागवान-बंद दिया गया। जिन लोगों को फाँसी का दंड दिया गया था ' उनमें से दो न स्वयं कोर्ट अदालत गये रिवा था किन्तु वे पञ्चम में सम्मिलित थे।<sup>२</sup> जब विहारो भाग गए। मर माइकेल जो हापर ने लिखा है 'वह अब भी फरार हैं—जोने हाथ ही में मुना है कि वह टोकियो में है।<sup>३</sup> दूसरे महाबुद्ध के दिनों में वे मुनापबन्ध दोन के सम्पर्क में थे जिज्ञास इन्डियन वेंशनल जामी (जाजाद हिंद फौज) का संगठन बिचा भा और वर्धा में भारतीय प्रजातन्त्र की मामूली सरकार बनाई थी।

## ९

अपने तीन वर्षों में अमेरिका में देशान्तरवासी मित्रों के बहुत बड़ी सन्नाहें हो चुकी थी, पञ्जाब का जालिंधरी आन्दोलन और दुरावा शक्तिशाली हो गया। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मित्रों ने अमेरिका और मुद्रा पूर्व के लिए देशान्तर गमन बिचा। जौन बहुत से लोग थे जो बनावडा में बगने के लिए उन्मुख थे। लेकिन बनावडा ने अधिकारीगण उनके मार्ग में अनेक बाधाएँ डाल रहे थे। वे भविष्य में, भाग्यवाजियों को अपने देश में बगने के रोचने के निम्न तुल्य हुए थे। वेबल दटना ही नहीं, बरन् वे पहले बने हुए भारतीयों को भी अपना के लिए हर तरह के उपायों को काम में ला रहे थे। वहाँ बने हुए मित्रों को अपनी पत्नियों और बच्चों को भारत में लाने की आज्ञा नहीं थी। बनावडा में बगने के लिए जाने वाले हर एगिया निवासी का दो चले पूरे करना आवश्यक था। एक शर्त तो यह थी कि प्रत्येक देशान्तरवासी के पास २०० डाक्टर होने चाहिए और दूसरी शर्त यह थी कि अपने देश से बनावडा तक उनकी यात्रा परिष्कृत होनी चाहिए<sup>४</sup>। इसका अर्थ यह था कि भारतवासी बनावडा में बगने के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि भारत में सीधे बनावडा जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मज् १९१३ में बनावडा से तीन मित्र प्रतिनिधि आए और उन्होंने ब्रिटिश थोल्मिया में रहने वाले भारतीयों को शिक्षितों को दूर बगने के लिए भारतीय जनमत आपूर्त किया और भारत सरकार में यह अनुरोध बिचा कि वह इन सबब में उपयुक्त कार्यवाही करे। उन्होंने

१. Indian Sedition Committee Report 1918, page 144.
२. Lajpat Rai Political Future of India, page 173.
३. O' Dwyer: India as I Knew it, page 185.
४. Report of the Indian Sedition Committee, page 146.
५. विज्ञान जर्नेल के अनुसार ये लोग ग़दर पार्टी के सदस्य थे।

पञ्जाब सरकार के अध्यापक तथा चाइमरॉय, दोनों के भेंट हो। पञ्जाब के विभिन्न स्थानों में उन्होंने सार्वजनिक सभाएँ की। किन्तु कनाडा की सरकार ने अपने प्रति वशों में कोई परिवर्तन नहीं किया। सरदार गुरदीत सिंह<sup>१</sup> नामक एक विमुख समूह ने सार्वजनिक भावनाओं से प्रेरित होकर, पञ्जाब के विनिमय से बचने के लिए 'कोमागाटा मार्ग' नामक जापानी जहाज को किराये पर लिया और उसके द्वारा यात्रियों को हार्बर, सार्जि जति स्थानों से सीधे ब्रिस्बेयर पहुँचाने का विवरण किया। यह जहाज ४ अप्रैल १९१४ को हार्बर से रवाना हुआ और २३ मई को ब्रिस्बेयर पहुँचा और उसमें ३५१ सिक्ख तथा २१ पञ्जाबी मुसलमान थे। स्थानीय अधिकारियों ने यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया क्योंकि उनके अनुसार यात्रियों ने विनियमों का पालन नहीं किया था। निवेदन किया गया विरोध किया गया और जब ये बातें चल रही थी, जहाज को, अपना खेप किराया (२२००० डॉलर) भी दिया गया। यह किराया ब्रिस्बेयर के भारतीयों ने दिया था जिससे बाद में दो प्रमुख उपद्रवियों ने अपने हिस्से ले लिया।<sup>२</sup> जहाज को कनाडा-सट को छोड़ कर चले जाने की आज्ञा दी गई लेकिन सिक्खों ने आज्ञा का उल्लंघन किया। पुलिस को मार कर मचा दिया गया। तब जापानियों का पालन करने के लिए सरकारी जहाज में सड़क सैन्यदल भेजा गया। कनाडा की सरकार ने बापिरी यात्रा के लिए सनराफ भी व्यवस्था की और २३ जून १९१४ को कोमागाटा मार्ग ने कनाडा से एगिया के लिए यात्रा आरम्भ की। "इस समय तक यात्रियों का श्रेष्ठ बहुत बड़ गया था क्योंकि उन्होंने इस यात्रा के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया था।" प्रसन्न क्रान्तिकारी प्रभावों से यह श्रेष्ठ और भी बढावा बढ गया। क्रान्तिकारी दल ने ब्रिस्बेयर में जहाज पर सारी से दखल भिजवाने का प्रयत्न भी किया था।<sup>३</sup>

कोमागाटा मार्ग के बापिरी सौटन से पहले ही यूरोप में युद्ध आरम्भ हो गया। भारतीय अधिकारियों ने यात्रियों पर, बीच में किसी वन्दरवाह पर न उतरने की रोक लगा दी और उनसे सीधे मलक्का आने के लिए कहा। २९ नवम्बर को जहाज ने क्यूज में लगर डाला। इस समय तक 'भारत प्रवेश' अभ्यास चल रहा था। उसके अनुसार भारत सरकार, राज्य-सरकार की दृष्टि से आवश्यकता अनुभव करने पर, भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्कान्पना पर रोक लगा सकती थी। अभ्यास के अन्तर्गत सरकार ने सारे यात्रियों को एक

१ सरदार गुरदीत सिंह तिहापुर में बाहर बस गए थे और वे वहाँ से एक समूह लेकर थे।

२ Indian Sedition Committee Report, 1918, page 147.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४८

स्पेशल रेजिस्ट्री में रजिस्टर, भीषे पत्राचार बंद करने की आज्ञा दी। यात्रियों को बोटें किराया नहीं देना था। लेकिन 'मित्रों' ने गाड़ी में धूमने से इन्कार कर दिया और चलने में एक जट्टम के रूप में धूमन का प्रयत्न किया। उनको बलात् लौटाया गया। एकल उपद्रव हुए और दानो आग के आइसी भारे गए। बहुत से सिक्खों के पास जर्मरिचन रिवाल्वर थे। जलज के निष्ठे ६० आइसी, जिनमें १७ मुसलमान भी सम्मिलित थे। स्पेशल रेजिस्ट्री में पत्राचार था। उपद्रव में १८ सिक्ख भारे गए, बहुतों का उम्र समथर पर बाद में सिक्खाना कर लिया गया, और २९ आइसी, जिनमें मुस्लीम मित्र भी सम्मिलित थे, छात्रक हाजिर। जो लोग विरहवार हुए थे, उनमें से अधिकांश की अवस्था जनवरी में रूपन पर जाव की आज्ञा दे दी गई; २१ लोगों को जल में नहावन्द कर दिया गया।<sup>१</sup> इन प्रचार कर्ताओं के विनिर्दयी से बचने के प्रयत्न का अन्त हुआ।

१०

कोमागाटा मार्ग की घटना के कारण, ब्रिटिश सरकार के प्रति सिक्खों की भावनाएँ बड़ी ठीकी हो गई, मित्रों के अनुमान उनकी आसानी विपत्तियों के लिए ब्रिटिश सरकार द्विम्भवार थी। विदेशों में रहने वाले सिक्खों<sup>२</sup> पर मुद्र-गर्दी के आन्विकारी प्रचार का अब अधिक प्रभाव हो सकता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह पार्टी जर्मन सरकार की सहायता से भारत में क्रांति करने के लिए योजना बना रही थी।<sup>३</sup> पार्टी के आन्विकारियों ने निक्को पर पत्राचार बन्द होने के लिए जोर दिया और कहा कि वे उस सरकार को बलात् फेंकने के लिए सहायता दें जिनका आग्रह के प्रति उनकी पिछली नेवाओं के बदले उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया था। 'विदेशों में बने हुए बहुत-से भारतीयों पर प्रभाव पड़ा और वे कनाडा, अफगानिस्तान, फिलिपाइन, हावकांग और चीन से भारत लौट आए।'<sup>४</sup>

सन् १९१६-१९ में मुद्र पार्टी के प्रचार की तीव्रता बढ़ गई। हरदयाल ने ही रामचन्द्र, अनावरी और बरकतुल्ला की सहायता से मुद्र पार्टी का संगठन किया था और उसका प्रधान केन्द्र कैलिफोर्निया में था। पत्राचार में 'क्रांतिकारी आन्दोलन' का उपक्रम करने के बाद हरदयाल १९११ के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुँच था और सर्वोच्च (कैलिफोर्निया) में बस गए थे। वहाँ पर बसे

१. Indian Sedition Committee Report, 1918, पृष्ठ १९८।

२. कनाडा में लगभग ४००० सिक्ख बसे हुए थे। इनके अधिकांश संयुक्त राष्ट्र,

फिलिपाइन, हावकांग और चीन में भी बहुत-से सिक्ख बसे हुए थे।

३. इसी अध्याय में इसका वर्णन किया जा चुका है।

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९९।

५. इसी अध्याय के आठवें विभाग की देखिये।

हुए सिक्खों में एक प्रकार का क्रान्तिकारी संगठन पहले से ही काम कर रहा था। हरदयाल ने उसे शक्तिशाली क्रान्तिकारी केन्द्र बनाने के लिए अपना काम तुरन्त आरम्भ कर दिया। उन्होंने सारे संयुक्तराष्ट्र में प्रचार करने के लिए एक परिश्रम का संयोजन किया। सन् १९१३ में उन्होंने 'गदर' नामक एक पत्र 'युगान्तर आश्रम' से निकाला और उसे कई भारतीय भाषाओं में छापा। यह पत्र अमेरिका और सुदूर पूर्व में बसे हुए भारतीयों में और भारत के विभिन्न भागों और विभिन्न वर्षों में प्रचलित होता था। "गदर" की भाषा, ब्रिटिश-विरोधी और अत्यन्त उग्र होती थी, उसमें मानवीय मनोभावों को हर समय युक्ति से भड़काया जाता था, उसके प्रत्येक वाक्य में हत्या और विद्रोह का प्रचार होता था, और सभी भारतवासियों से भारत जाने के लिए आग्रह किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि वे भारत में अंग्रेजों की हत्या करें, सरकार के विरुद्ध क्रान्ति करें और हर सम्भव उपाय को काम में लाकर ब्रिटिश राज्य का अन्त करें"।<sup>१</sup> हरदयाल ने इस समाचार-पत्र की सहायता से और सार्वजनिक तथा निजी सभाओं में व्याख्यानो द्वारा पाठों के काम को आगे बढ़ाया। हरदयाल के लेख और व्याख्यान बड़े प्रभावशाली होते थे। १६ मार्च १९१४ को अमेरिकन अधिकारियों ने उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया। उन्हें जमानत पर जा चुका है<sup>२</sup>, इन लोगों ने ब्रिटेन में इंडियन नेशनल पार्टी का संयोजन किया और जर्मनी की सहायता से भारत में प्रबल क्रान्ति करने की योजना बनाई।

महापुद्गल के पहले तीन वर्षों में पञ्जाबके क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्देशन दो परस्पर अनवृद्ध केन्द्रों से हुआ, फलतः आन्दोलन की दो पृष्ठ धाराएँ थी—एक में तो मुख्यतः विदेशों से लौटे हुए सिक्ख थे<sup>३</sup> और दूसरी धारा में 'पैन-इस्लामिक' मुसलमान थे। सिक्खों का निर्देशन अमेरिका और सुदूर पूर्व से हो रहा था। इन लोगों की सहायता के लिए गदर पार्टी ने अमेरिका से पैसे को भेज दिया था। इस धारा को रामविहारी वोम का सहयोग भी प्राप्त था, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। रामविहारी वोम को दिल्ली पद्मन्य केस में फाँपी का दण्ड दिया गया था पर वे गिरफ्तार होने से पहले ही फरार हो गए थे। 'पैन इस्लामिक' पद्मन्य का निर्देशन-केन्द्र काबुल में था और इसके नेता थे बरकतुल्ला और महेन्द्र प्रसाद। इस पद्मन्य

१ Indian Sedition Committee Report 1918, pages 145-146.

२ इसी अध्याय के सप्तम विभाग को देखिये।

३ इनमें कुछ मुसलमान और कुछ हिन्दू भी थे।

के सम्बन्ध में आगे चर्चा की जाएगी।

११.

महापुद्गल आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद, बल्लभता, मद्रास और कोल्हा में, विदेशों में बने हुए मिक्को में भरे हुए जहाज आने लगे। सरकार को जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये लोग गदर पार्टी के अनुयायी हो गए थे और वे पञ्जाब में आन्ति करने के उद्देश्य से वापिस लौट रहे थे। २९ अगस्त १९१४ को 'विदेशियों' अध्यादेश इन लोगों पर लागू नहीं हो सकता था। अतः ५ नवम्बर १९१४ को 'मान्य प्रवेश' अध्यादेश बना कर जारी किया गया। इस अध्यादेश को सबसे पहले 'कोमागाटा मार्ग' जहाज के यात्रियों पर लागू किया गया।

२९ अक्टूबर को 'टोसा मार्ग' नामक दूसरा जहाज आया, इसमें १७३ यात्री थे, जिनमें से अधिकांश, अमेरिका और मुद्ररूप से लौटने के सिक्के थे। उसमें आन्तिकारी आन्दोलन के नेता भी थे, जिनमें से प्रत्येक को, प्रान्त के एक निश्चित क्षेत्र में काम करना था। पुलिस की जानकारी में १९ मार्च १९१५ तक, विदेशों से लौटे हुए ३१०५ आदमी पञ्जाब पहुँचे। पञ्जाब सरकार ने उनके मामलों की जाँच करने के लिए प्रभावशाली मिक्को की म्यागीय कमेटी को बिसोपस में नियुक्त की थी और जाँच के फलस्वरूप १८९ आदमियों को जेल में रखा गया, ७०४ आदमियों पर अपने गाँव से बाहर न जाने के लिए रोक लगाई गई और २२११ आदमियों को नही भी जाने-जाने की स्वतन्त्रता दी गई।<sup>१</sup> इन प्रति-बन्धों के कारण, विदेशों से लौटने वाले लोगों की योजनाएँ चौंकर हो गईं किन्तु कुछ समय बाद पिंगो और रामविहारी बोन की महापता में नई योजनाएँ बना ली गईं। इस बीच में, आवश्यक निधि सग्रह करने के उद्देश्य से लूट और हत्या का क्रम आरम्भ कर दिया गया। २७ नवम्बर १९१४ को १५ आदमियों के एक दल ने मोगा तहसील के खजाने पर धावा बोला। एक थानेदार और एक जिलेदार ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, पर वे दोनों मारे गए। गाँववालों ने और पुलिस के आदमियों ने डाकुओं का पीछा किया जिसके फलस्वरूप दल के दो आदमी मारे गए, सात पकड़े गए, बाकी भाग गए। २८ नारीब की अमृतसर जिले के एक गाँव में एक दल और इक्का हुआ लेकिन पुलिस और घुड़नवारों के आ जाने के कारण वे भाग भाग गए। ८ दिसम्बर १९१४ को एक पुलिस-अधिकारी पृथो राजपूत नामक एक मुस्लिम देशान्तरागामी को गिरफ्तार करने गया किन्तु उस पर हमला किया गया और उसे अचानक कर दिया गया। १७ नारीब को हिसार जिले के पीपली गाँव के एक ब्राह्मण ने लगभग २२००० हजार रुपये लूट लिए गए।

पंजाब सरकार ने इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार से एक नया, कठोर अध्यादेश बनाने के लिए कहा। एक ओर सरकार अध्यादेश बनाने में लगी हुई थी, दूसरी ओर विदेशों से लौटे हुए लोग अपनी योजना के अनुसार हड़तियों और हत्याओं के कार्यक्रम में लगे हुए थे। दिसम्बर १९१४ में और जनवरी तथा फरवरी १९१५ में पंजाब के केन्द्रीय जिलों में कितने ही ठाके डाले गए और रेलों की पटरियाँ उखाड़ने तथा पुलों को उड़ाने के प्रयत्न किए गये। इन कामों के अतिरिक्त, पंजाब के तीन महत्वपूर्ण सैनिक केंद्रों में २१ फरवरी १९१५ को एक समकालिक व्युत्थान का पड़पन्ना भी रखा गया।

यह पड़पन्ना, लाहौर पड़पन्ना के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी योजना, पिगले और रासबिहारी बोस ने बड़े पल्लवों के साथ की थी। दिसम्बर में बम बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोली गई थी, लेकिन आन्दोलन का प्रधान केंद्र लाहौर में था और रासबिहारी बोस उसके मुख्य निर्देशक थे। उन्होंने "उत्तर भारत की विभिन्न छावनियों से निवृत्त दिवस पर सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, इन छावनियों में अपने दूत भेजे। उन्होंने विद्रोह के लिए, बहुत-से बाँवबाजों के दलों का संगठन भी किया। बम बनाए गए, हथियार इकट्ठे किए गए, सड़े तैयार किए गए, युद्ध की घोषणा लिखी गई, पटरियाँ उखाड़ने और तारों को काटने के औजार इकट्ठे किए गए। इन लोगों ने लाहौर, श्रीरोजपुर और रावलपिण्डी में समकालिक व्युत्थान की योजना बनाई थी, बाद में यह प्रसंग हुआ कि उनका कार्य-क्षेत्र और भी ज्यादा बड़ा था।" एक शुक्रवार से सरकार को इस योजना का पता लगा और सरकार ने रासबिहारी बोस के प्रधान केंद्र पर छापा मारा।" तेरह आदमी पकड़े गए और चार मकानों की तलाशी ली गई। बारह बम पकड़े गए जिनमें से पाँच बम बगाली नमूने पर बने हुए थे। रासबिहारी और पिगले भाग गए लेकिन एक महीने बाद मेरठ छावनी में पिगले को पकड़ा गया और उसके पास कुछ बम भी पाए गए।"

इस प्रकार व्युत्थान की योजना को आरम्भ में ही कुचल दिया गया लेकिन राजनैतिक हड़तियों और हत्याओं का क्रम कुछ समय बाद तक चलता रहा। सरदार चन्दासिंह और सरदार बहादुर अठर सिंह जैसे प्रमुख सिक्ख सहयोगियों की हत्या की गई। पहले लाहौर पड़पन्ना कमिशन के एक गवाह कपूर सिंह की भी हत्या की गई। अगस्त १९१५ तक आन्दोलन ठंडा पड़ गया और ३१ जनवरी १९१६ को पंजाब सरकार ने लिखा — "विदेशों से लौटे हुए सिक्ख

१ विस्तृत वर्णन के लिए देखिये—Indian Sedition Committee Report 1918, pages 152-53.

२. उक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १५४

अब व्यवस्थित होने जा रहे हैं और साधारणतया निम्नों की भावनाएँ हम सब जितनी मनासप्रद हैं उतनी पिछे कटे वनों में नहीं गयीं।<sup>१</sup>

पंजाब सरकार के बनाने में परिवर्तन के दो कारण थे। १९११ के 'मान ग्ला एक्ट' के अन्तर्गत सरकार ने बटागना से काम लिया था। और साथ ही प्रान्त के राजमस्तगों का अपने पक्ष में लड़ना था।

७०

जैसा कि पहले कहा जा चुका है पंजाब सरकार ने दिसम्बर १९१४ में बाटन राय के विचाराय एक्ट अध्यादेश का मनविदा प्रस्तुत किया था। उनका उद्देश्य विदेशों से लोटे हुए लोगों के राजनैतिक अपराधों के लिए, स्थिति अनिर्णीत निर्णय की व्यवस्था करना था। उनके द्वारा 'सशस्त्र परिस्थितियों में शस्त्रों का बहाना' एक्ट बनाया, पृथक् अपराध बनाया गया, और स्थानीय सरकार की अनुमति में "(अ) राजनैतिक अपराध अथवा अर्ध-राजनैतिक अपराधों के लिए न्याय-युक्ति के निराकरण की, (ब) ऐसे अपराधों में अपील के निराकरण की, (स) सम्बन्धित स्थितियों में वर्तमान पद्धति की अपेक्षा एक शीघ्रतर पद्धति में उमानत लेव की, (द) कानूनीकारियों को धरण देने वाले ग्रामवासियों और गाँव के अधिकारियों को सुरक्षित रख देने की" व्यवस्था की गई।<sup>२</sup>

भारत-सरकार ने इस सम्मन्ध में सुरक्षा ही एक अध्यादेश बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की, लेकिन पंजाब सरकार आप्रहृ करती रही और २१ फरवरी को लाहौर पदपत्र का पता लगाने के बाद यह आप्रहृ और ज्यादा बढ़ गया। भारत सरकार इंग्लैंड के डिफेंस ऑफ़ रीएन्स ऐक्ट के दृष्ट पर डिफेंस ऑफ़ इंडिया (भारत-रक्षा) ऐक्ट बनाने का विचार कर ही रही थी। अतः पंजाब और बंगाल की विशेष परिस्थितियों का मानना करने के लिए, भारत-सरकार ने, पंजाब सरकार के प्रस्ताविका मनविदे की धाराओं को उस ऐक्ट में सम्मिलित करने का निश्चय किया।

इस पृष्ठ भूमि में यह स्पष्ट है कि १९१५ का भारत रक्षा ऐक्ट केवल युद्ध की ही परिस्थितियों का मानना करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका उद्देश्य राजनैतिक अपराधों का दमन करना भी था और उनके लिए देश के साधारण प्रोत्साहनीय कानूनों का अधिकतम करने की व्यवस्था की गई। यही मंत्र, परिपक्व में, इस विषय पर विवाद के सिलसिले में माननीय प. मदन मोहन मालवीय ने प्रकट किया था। इस ऐक्ट को माझा-सीध विधान परिषद् की एक ही बैठक में (१८ मार्च

१. Indian Sedition Committee Report, 1918, page 157.

२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १५१.

१९१५ को) बनाया गया और उसने विभाग न ३ के अनुसार, "किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराध पर प्राणदंड, निर्वासन-दंड अथवा सात वर्ष तक कारावास दंड" दिया जा सकता था।" इस पर प. मालवीय ने कहा, "इस विभाग के द्वारा साधारण अपराधों के अभियोध-निर्णय के लिए फौजदारी पद्धति संहिता को धाराओं का दस्तुत अन्त किया जा रहा है।"२

देश अथवा साम्राज्य के सैनिक और समुद्री हितों के संरक्षण से सम्बन्धित धाराओं का परिपक्व में कोई भी विरोध नहीं किया गया। मग्न ही उच्च राजनैतिक अपराधों के दंड और दमन से सम्बन्धित धाराओं का भी कोई विरोध नहीं किया गया। किन्तु बहुत से गैर-सरकारी सदस्य न विषय न्याय समझों को रचना उनके विधान, ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोगों के निर्णय और प्राणदंड देने के लिए उन न्याय समझों के अधिकारियों से सम्बन्धित धाराओं का प्रबल विरोध किया।

यह मत प्रकट किया गया कि जिन अपराधों का देश की रक्षा से सम्बन्ध हो, उनका अभियोग निर्णय (इंग्लैंड के ढंग पर) सैनिक न्यायालय द्वारा होना चाहिए और अन्य अपराधों का निर्णय साधारण न्यायालया द्वारा होना चाहिए। किन्तु विभाग न ४ के अनुसार, ऐक्ट के अन्तर्गत सभी अभियोगों का निर्णय विरोध न्याय समझों द्वारा होना था। प्रत्येक न्याय समझ में स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त, तीन कमिशनर होने थे। बहुत से गैर-सरकारी सदस्यों के अनुसार कमिशनरों के लिए जो अर्हता निश्चित की गई थी, वह अप्रतिपक्ष थी। उनका मत यह था कि विरोध न्याय-समझों के सदस्य हाईकोर्ट के जज हान चाहिए, किन्तु ऐक्ट के अनुसार सैरान्स (सन-न्यायालय का) जज अथवा अतिरिक्त सैरान्स जज भी कमिशनर नियुक्त किया जा सकता था और न्याय-समझ के तीन कमिशनरों में से केवल दो के लिए ही विधिवत ज्ञान अथवा न्यायिक अनुभव की आवश्यकता थी।<sup>३</sup> सम्राट के खिलाफ युद्ध का पक्ष्य रखने के उद्देश्य से अथवा सम्राट के शत्रुओं को सहायता देने के उद्देश्य से, ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियमों अथवा ऐक्ट की आज्ञाओं का किसी प्रकार भी उल्लंघन करनेवाले अभियुक्त को, न्याय समझ के कमिशनर प्राण दंड दे सकते थे। पंडित मालवीय ने कहा, "युद्ध के दण्डियों का नगर-बन्द किया जाता है, क्या विचाराधीन अभियुक्तों को नगर-बन्द रखने से अथवा

१. "Acts of 1915," page 8.

२. Indian Legislative Council Proceedings, Vol. LIII, page 490

३. "Acts of 1910", page 8.



जीवन-भर के लिए निर्वासित करने से, सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय की मांग पूरी नहीं हो सकती ? - प्राण दंड में, एव अपरिवर्तनीय अन्याय की जोखिम होती है। त्वरित एव सक्षिप्त अनियोग-निर्णय की व्यवस्था में यह जोखिम और ज्यादा बढ़ जाती है", विशेषकर ऐसे समय जब उच्चतर न्यायालय में अनौष्ठ करने की व्यवस्था न हो। ऐक्ट के विभाग न ६ के अनुसार बमिशनरी का निर्णय 'अन्तिम और अपरिवर्तनीय' था।<sup>१</sup>

१३.

सन् १९१५ के भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत, विशेष न्याय-प्रमात्री में, लाहौर पट्टन और अन्य राजनैतिक अपराधों में सम्मिलित लोगों पर अभियोग चलाए गए। इन अभियोगों को ९ जत्थों में बांटा गया था किन्तु यहाँ पर तीन 'लाहौर पट्टन' अभियोगों को मक्षिप्त<sup>२</sup> चर्चा करना ही पर्याप्त होगा।

पहले अभियोग के जत्थे में ६१ अभियुक्त थे। इस जत्थे में आन्दोलन के लग-भग मारे नेता सम्मिलित थे और उनमें पिंगले और भाई परमानन्द भा थे। भाई परमानन्द १९१३ में भारत वापिस लौट आए थे और वे अमेरिका में हर्दयाल के प्रमुख मद्योगी माने जाते थे। विशेष न्याय-महा के निर्णय के अनुसार वे "पट्टन-कारियों के नेता थे", अतः उन्हें प्राण-दंड दिया गया। वाइसरॉय ने इस दंड को घटा कर, आजीवन निर्वासन-दंड दिया, बाद में इसको भी दाना कर दिया गया।

दूसरे अभियोग में ७४ अभियुक्त थे। २१ फरवरी की योजना के असफल हो जाने के बाद भी, विदेशों ने लौटे हुए लोग अपना नातिकारी काम करते रहे। उन्होंने विद्यार्थियों में और भारतीय सैनिकों में नातिकारी प्रचार का प्रयत्न किया और इन दोनों के अनिरिक्त वे लोग कई हत्याओं और उकैतियों के लिए भी उत्तरदायी थे।

तीसरे लाहौर-पट्टन अभियोग में कुल १२ अभियुक्त थे पर वे लोग सब जर्मन योजना से सम्बन्धित थे जिसके अनुसार बर्मा की ओर से भारत पर आक्रमण किया जाना था। आक्रमणकारियों का केन्द्र बेंगल में था जहाँ पनाहा से लौटे हुए कुछ भारतीय नातिकारी एकत्र हो गए थे और जर्मन-अभिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

इन पट्टन-अभियोगों में अत्यन्त कठोर दंड दिए गए। कुल १७५ व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था "जिन में से १३६ अभियुक्तों के अपराधों के लिये

१ "Acts of 1915", page 9.

२. विस्तृत वर्णन के लिए देखिये—Indian Sedition Committee Report 1918, pages 157-160.

चन्दा इकट्ठा किया गया और मौंगना जाफर अला उसका एक किन्त देन के लिए स्वयं ही वस्तुनिर्माणा गए। मुन्तान न इन नोट को वृत्ततापूर्वक स्वीकार किया और उमन १९१४ के आरम्भ में लाहौर का बादशाही मस्जिद के लिए एक तालान बना।

तुर्किस्तान में मौंगना जाफरखानी के लौटन पर पन इस्लामिस्ट समाचार पत्र ब्रिटिश नीति की ओर भी स्वादा नाबी आलाचना करन ग्य। पञ्चाव सरकार न १९१३ में जमादार की जमानत जख्त कर ली। दुवारा जमानत मागर्ग और दी गई लेकिन पत्र की नीति में कोई अंतर नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय बाद सरकार न प्रम और जमानत दोनों को जख्त कर लिया। महायुद्ध आरम्भ होन पर मौंगना जाफर अला और दोनों अंगी बधुओं को उनके गावों में मजबूरबन्द कर दिया गया।

महायुद्ध में तुर्किस्तान के शामिल होने पर बर्लिन के भारतीय क्रांतिकारियों ने पूर्वीय देशों में मुस्लिम व्यत्यान के लिए पन इस्लामिक भावनाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से महदप्रताप और बरखतुल्ला का बाबूल भजन का निश्चय किया। महदप्रताप उत्तर प्रदेश के एक धनी जमींदार ह और एक निरक्षर राजघरान में उनका विवाह हुआ था। महायुद्ध आरम्भ होन के कुछ ही समय बाद वे स्विट्जरलैंड चल गए और वहाँ हरदयात के सम्पर्क में आए। वहाँ से उन्हें बर्लिन ले जाया गया और एक प्रभावशाली भारतीय नरेश के रूप में उनका परिचय दिया गया। बरखतुल्ला भूपातक रहन बाक ध और १९०९ में टोकियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे। जापान पहुँचन पर उन्होंने इस्लामिक फर्नान्डी नामक एक पन निवाला आरम्भ किया। सन १९११ में वे मिथ तुर्किस्तान और रूस गन और वृष्णवमा के सम्पर्क में आए। जापान लाटन पर उनका पत्र बन्द कर दिया गया और १९१४ में उनको प्राफगर के पद से हटा दिया गया। तब वे सन कतिस्का पहुँच कर हरदयात के सहयोगी और मदर पार्टी के नेता हो गए और बाद में उनके साथ बर्लिन चले गए। वहाँ से एक तुर्क जमान मडक के साथ उनको और महदप्रताप का बाबुल भजा गया। इन लोगों ने और मडक के बाबुल जान का उद्देश्य दोहराया—अफगानिस्तान के पासन की फोर्मा और उत्तरा भागन में क्रांति कराना।

पञ्चाव में पन इस्लामिक आन्दोलन जड़ पकड़ गया था। मुस्लिम तरण वय उत्तर्जित थे। एक गुप्त संगठन प्राक्विकारी काम के लिए विद्यार्थी समुदाय में से अपन सदस्य भर्ती करन का प्रयत्न कर रहा था। उनमें अहौर से १५ विद्यार्थी भर्ती किए जो बालका में पढ़न थे। इनके अतिरिक्त पेगाबर और कोहाद न ना कुछ विद्यार्थी भर्ती किए गए और इन लोगों को बड़ टड मड रास्तों से भारत का

उत्तरी पश्चिमी सीमा के बाहर भेजा गया, जहाँ बहादुरी समुदाय का ब्रिटिश-विरोधी प्रचार केन्द्र था। इस केन्द्र में ये लोग काबुल गये, जहाँ आरम्भ में तो उन्हें नजरबन्द रखा गया पर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और कुछ धनार्थ पर वहाँ भी थाने-जाने की स्वतन्त्रता दे दी गई।<sup>१</sup> इन लोगों का 'निक केटर' पत्रिका से सम्बन्ध था। "इस पत्रिका की योजना भारत में बनाई गई थी। और उसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य का अन्त करना था। योजना के अनुसार, उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत पर आक्रमण होना था और उम्मीद समय पर देश में मुस्लिम व्यापार होना था। इस योजना को वायांनिक करने के उद्देश्य से अगस्त १९१५ में उर्वदुल्ला नामक एक मौलवी अपने तीन साथियों—अब्दुल्ला, फतेह मुहम्मद और मुहम्मद अली—को लेकर अफगानिस्तान पहुँचा।<sup>२</sup> उर्वदुल्ला, बेगमन्द के एक मजहबी मकान का मौलवी था और उसने उस मकान के बड़े मौलवी मुहम्मद हसन को भी ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं में भर दिया था। "१८ सितम्बर १९१५ को मुहम्मद हसन ने उर्वदुल्ला का अनुकरण किया और वह, मुहम्मद मिर्जा और कुछ अन्य मित्रों के साथ अरब चला गया।<sup>३</sup>

मुहम्मद हसन के दल ने अरब में अपना काम शुरू किया और उनमें हड़जाब के तुर्की सैनिक गवर्नर शालिब पाशा से जिहाद की घोषणा भी प्राप्त कर ली। सन् १९१६ में मुहम्मद मिर्जा, 'शालिबनामा' (जिहाद की घोषणा) को लेकर भारत लौट आया। उसने इस घोषणा की प्रतियों का भारत और सीमा प्रान्त में वितरण किया और बाद में वह काबुल पहुँच कर उर्वदुल्ला के दल में सम्मिलित हो गया। 'शालिबनामा' में तुर्कों और मुजाहिदीन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था; उसके बाद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुसलमानों की तैयारियों का हाल बताया गया था; और अन्त में भारतीय मुसलमानों से यह अपील की गई थी— "मुसलमानों, जिस ईसाई सरकार ने तुम्हें गुलाम बना रखा है, उस पर आक्रमण करो। . . . दूढ़ निश्चय से, प्राणपण से प्रयत्न करो और शत्रुओं का संहार करो और उनके प्रति अपनी घृणा और घृणा को जना दो।"<sup>४</sup> 'शालिबनामा' ने भारतीय मुसलमानों से यह भी कहा कि वे मुहम्मद हसन का विश्वास करें और उनकी "पक्ष और जय में हर प्रकार की सहायता करें।"<sup>५</sup>

इस काम के लिए काबुल में केन्द्र बनाया गया। उर्वदुल्ला और उसके मित्र वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे और उन लोगों ने तुर्क-जर्मन मंडल में, बर्लिन के

१. Indian Sedition Committee Report, 1918, page 175.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७६.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७७.

४. Indian Sedition Committee Report, 1918, page 178.

भारतीय प्रांतिकारियों से और भारत के मुहाजरीन विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित कर लिया था। सन् १९१६ में रास्ते में 'गालिबनामा' की प्रतियाँ बाटते हुए, मुहम्मद मियाँ भी काबुल पहुँच गया। इन सब लोगों ने मिलकर बड़े यत्नपूर्वक अपनी योजना बनाई। एक 'सामयिक सरकार' की स्थापना की गई और महेन्द्रप्रताप को उसका अध्यक्ष तथा बरबतुल्ला को उसका प्रधान मंत्री बनाया गया। इस 'सामयिक सरकार' ने रूसी तुर्किस्तान के गवर्नर के पास एक पत्र भेजा और साथ ही एक पत्र तत्कालीन जार (रूस नरेश) के पास भी भेजा—यह पिछला पत्र एक साने की तश्तरी पर लिखा गया था और उसमें रूस से यह कहा गया था कि "बहु अग्रजों के साथ अपनी मित्रता तोड़ कर भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दे।" 'सामयिक सरकार' ने मौलाना मुहम्मद हसन के जरिये से तुर्किस्तान सरकार के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। मौलाना मुहम्मद हसन को दो पत्र लिखे गए—एक पत्र उर्वदुल्ला ने लिखा और दूसरा पत्र मुहम्मद मियाँ ने लिखा। ये पत्र धीले रेशमी कपड़े<sup>२</sup> पर लिखे गए और उन्हें हंदराबाद (सिंध) के शेख अब्दुल्लाह के पास भेजा गया, और एक पृथक् पत्र में, उनसे यह कहा गया कि वे मक्का में मौलाना मुहम्मद हसन के पास उन रेशमी पत्रों को या तो किसी विदवात्तपत्र आदमी के जरिये से या खुद ही पहुँचा दें।

“मुहम्मद मियाँ के पून में, जर्मन और तुर्क मंडल के आने की, जर्मन मंडल के वापिस चले जाने की,<sup>३</sup> तुर्क मंडल के ठहरने की, वायकम के अभाव की, भागे हुए विद्यार्थियों की, 'गालिबनामा' के प्रचार की, प्रस्तावित 'खुदा की फौज' की और 'सामयिक सरकार' की चर्चा की गई थी। प्रस्तावित फौज में भारतवासियों की भर्ती की जानी थी, इसके अनिश्चित इस्लामी शासकों में ऐक्य स्थापित करना था। मुहम्मद हसन को ये सब बातें तुर्किस्तान सरकार को बतानी थी। उर्वदुल्ला के पत्र में प्रस्तावित सेना का सूचीबद्ध विवरण दिया गया था। मदीना में सेना का प्रधान केन्द्र होना था और स्वयं मुहम्मद हसन को उसका मुख्य सेनापति बनना था। स्थानीय सेनापतियों के आधीन कुस्तुन्तुनिया, तेहरान और काबुल में केन्द्र बनाने थे। काबुल में उर्वदुल्ला को सेनापति बनना था। सूची में अन्य सैनिक पदों के लिए बहुत से लोगों के नाम दिए गए थे। लाहौर के विद्यार्थियों में से

१ Indian Sedition Committee Report 1918, पृष्ठ १७९

२ इसी कारण यह योजना, रेशमी पत्र (ज्यातु सिल्क लेटर) पड्यत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

३ सन् १९१६ के आरम्भ में जर्मन मंडल, काबुल से वापिस चला गया क्योंकि उसे वहाँ अधिक ठहरना निरर्थक प्रतीत हुआ।

एक को मेजर जनरल का पद मिलना था एक को कर्नल का और छै को लेफ्टिनेंट कर्नल का ।”<sup>१</sup>

कानून पढ़नेवाले मुहाजरीन विद्यार्थियों में पंजाब के उप-गवर्नर के मित्र, एक खान के दो लड़के भी थे । इन लड़कों के साथ एक नौकर भी काबुल गया था और उन्होंने इस नौकर के हाथ खान के पाम सदेश भेजे—और खान ने उन लड़कों के प्रत्यागमन के लिए भर माइकेल ओ’ हायर से प्रवन्ध कराना चाहा पर उसे सफलता नहीं मिली । अस्तु, ‘रैसमी पत्र’ (सिलक लेटर्स) इसी नौकर के द्वारा भारत भेजे गए थे और वे उसके कोट के अस्तर के अन्दर मिले हुए थे । खान से मिलने आने से पहले वह उस कोट को एक भारतीय रिपामन में छोड़ आया था । खान को हाल में कुछ काला दिखाई दिया और उसने नौकर को ठरा धमका कर सारा भद मालूम कर लिया । अन्त में कोट भेजाया गया और खान ने उन ‘रैसमी पत्रों’ को निकाल कर अपने विभाग के कमिश्नर को सौंप दिया और उसन उन्ह उप-गवर्नर के पास भेज दिया ।<sup>२</sup>

इस प्रकार ‘सिलक लेटर्स’ पड़्यन का पता लगा और पंजाब सरकार ने उस पड़्यन को साकार न होने देने के लिए उपयुक्त प्रवन्ध कर लिया ।

## उन्नीसवाँ अध्याय

# वैधानिक आन्दोलन

## १

दमन और सुधार की दोहरी सरकारी नीति के कारण भारत का राजनीतिक जीवन निरुद्ध हो गया था । बंगाल में जहाँ आन्दोलन अत्यन्त उग्र था और जहाँ दमन भी अपने चरित्र पर था, मावज्जनिक जीवन मुग्न धाराया में ढकेल दिया गया था और उसके फलस्वरूप बहुत से नान्तिकारी अपराध हुए थे । अन्य प्रान्ता में, उचित प्रेरणा के अभाव में, राष्ट्रीय सत्ताएँ मुरझा गई थी । तिलक, भाण्डेले में एक लम्बी अवधि के लिए कंद व और बाबू अरविन्द घोष स्वयं ही राजनीति को बन से उठा हो गए थे । इन दोनों बातों ने ‘उग्र दंड’ को सन्तुष्ट नृत्त्व से वञ्चित कर दिया था । मुसलमान और नरम दल के लोग मौलें मिटो मुधारों में फँसे हुए थे और अपन पार्षिक अधिवेगता में, पुरानी दिक्कतों को दूर करने के सबब में कुछ प्रस्तावों का पारण करने के अतिरिक्त, सार्वजनिक कामों से दूर थे ।

१ Indian Sediton Committee Report, 1918. page 178

२. O'Dwyer India as I Knew it, page 178,

सबसे पहले मुस्लिम समुदाय में पुनरुत्थान की चप्टा प्रकट हुई। शिक्षित मुसलमानों के तरुण वर्ग ने यह अनुभव किया कि अन्य दवावासियों के हितों से, उनके हित मूल्य में भिन्न नहीं थे। इसने अतिरिक्त अन्य इस्लामीय देशों—विशेषकर तुर्किस्तान और ईरान—के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने उनका प्रभावित किया और उनमें राष्ट्रीय भावनाएँ भरी। उसी समय दो ऐसा बात और हुई जिनके कारण भारतीय मुसलमान ब्रिटिश कमचारीत न से विमुख हुए और अपने देश के अन्य निवासियों के अधिक निवृत्त आए—पहली बात थी अंगरेजों की निपोली और शास्त्र के सिद्धांत में तुर्किस्तान विरोधी नीति, और दूसरी बात थी तुर्किस्तान के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के व्यवहार का संबंध में मुसलमानों के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों का सहानुभूति। अस्तु मुस्लिम तरुण वर्ग भारतीय राष्ट्रवादियों का साथ सधान के लिए प्रयत्न करने लग और सन् १९१३ में इस दिशा में पहला कदम उठाया गया।

तरुण नेताओं ने उद्योगालयों की नए नए सविधान बनाने के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य में दिसम्बर १९१२ में कांकात में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद् की मीटिंग करने का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में मुस्लिम समुदाय के सभी प्रगतिशील नेताएँ आए और इनमें मि० मुहम्मद अली जिन्ना भी थे जो अब तक लीग में दूर रह चुके थे। उस समय के एक बड़े वाक्तावीर और उन्होंने एक विपुल रूप से साम्प्रदायिक संस्था (मुस्लिम लीग) का सदस्य होने से इन्कार कर दिया था। इस मीटिंग ने वाक्तावीर के राष्ट्रीय भावों को स्वीकार किया और लीग के लिए एक नए सविधान का मसविदा तैयार किया जिस २२ मार्च १९१३ को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में यह उत्साहपूर्वक अंगीकार किया गया। यह अधिवेशन बलुच में हुआ था और सर इमाम रहमतुल्ला उसने सभापति थे।

नए सविधान में लीग के उद्देश्यों की इस प्रकार व्यवस्था किया — (१) इस देश के निवासियों में ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति राजनैतिक की भावनाओं का पोषण करना और उनका प्रोत्साहन देना (२) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक एवं अन्य अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना, (३) भारत के अन्य समुदायों और मुसलमानों में एकता प्रोत्साहन देना और पारस्परिक मित्रता बढ़ाना (४) उपयुक्त उद्देश्यों को किसी प्रकार की शक्ति पहुँचाए बिना

१ इस मीटिंग में उपस्थित हान वाठ अन्य प्रगतिशील नेताओं में सर इमाम रहमतुल्ला मीराना मुहम्मद अली मजिद हक हसन इमाम मुहम्मद सफी और वज़ार हसन थे।

२ लीग के नए सविधान का पुराने नेताओं ने प्रबल विरोध किया था।

ब्रिटिश राजमता के अन्तर्गत वैधानिक उपायों द्वारा भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन-व्यवस्था प्राप्त करना और इस उद्देश्य के लिए जय वाता के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकात्मता को प्राप्त करना, कर्मचारी वर्गों की व्यवस्था में सुधार करना और भारत के निवासियों में सामाजिक भावना का प्रसारण करना तथा उक्त उद्देश्य के लिए परस्पर सहयोग का प्रतिपादन देना।<sup>१</sup>

मुस्लिम लीग के आदेश तथा उसकी नीति में इस परिवर्तन का वास्तव में हृदय से स्वागत किया और अपने अपने कराची अधिवेशन (दिसम्बर १९१३) में उसकी ध्वज के लिए एक विशेष प्रस्ताव का पारण किया। इस अधिवेशन का समापन नवाब सयद मुहम्मद बहादुर ने किया था।<sup>२</sup> अस्तु उक्त प्रस्ताव में यह वाक्य प्रचलित की गई कि विभिन्न समुदायों के मतानुसार, राष्ट्रीय हित की मर्यादा में सत्यता के साथ ही एक समुक्त राष्ट्र-पद्धति अपनाते के लिए पुराना-नया प्रयत्न करेंगे।<sup>३</sup>

राष्ट्रीय एकात्मता और समुक्त राष्ट्रवाद की दिशा में दूसरा बड़ा मील का पत्थर और उनके साक्ष्य न उठाया—उहाय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन कायस अधिवेशन के साथ एक ही जगह करने के लिए कहा। दिसम्बर १९१५ में दोनों संस्थाओं के अधिवेशन बम्बई में एक ही समय पर किए गए और उन वाक्यों के मतानुसार लीग के इस अधिवेशन का देश के लिए हाल में प्राप्त तात्कालिक उत्साह और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। अस्तु युद्धोत्तर भारत के लिए दोनों संस्थाओं ने परस्पर मिलकर एक सुधार योजना बनाने का और उस योजना को कार्यान्वित कराने के निमित्त सरकार पर दबाव देने का निश्चय किया। दोनों संस्थाओं ने इस उद्देश्य के लिए कमेटियाँ नियुक्त कीं। इन्होंने कार्यक्षेत्र में और बाद में (दिसम्बर १९१८ में) प्रत्येक में अपनी बैठक की जहाँ कुछ ही समय बाद लीग और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होने वाले थे। सुधारों की एक समुक्त योजना सूत्रित की गई और उसमें भारत के विभिन्न विधान-मंडलों में सुसंयोजित को विशेष प्रतिनिधित्व देने के नियम द्वारा हिन्दु मुस्लिम प्रश्न को ली जाया गया। यह प्रतिनिधित्व मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से नहीं अधिक था। अस्तु कांग्रेस और लीग, दोनों ने अपने अधिवेशन में इस योजना का साक्षात् अनुमोदन किया और यह समझौता कांग्रेस लीग योजना

१ Indian Year Book, 1914, page 476

२ राष्ट्रीय एकात्मता की दिशा में मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च नेताओं के साहित्यिक एवं दार्शनिक पुण्य कृत्य की सराहना ने शरीर स्वरूप उन वर्ष के लिए नवाब बहादुर का विशेष रूप से छाया गया था।

३ Besant How India Wrought for Freedom, page 564

के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भारत की दो बड़ी जातियों ने और दो बड़ी राजनैतिक सस्थाओं ने 'एक कार्यक्रम' अपनाया, और इस रूप में उनके द्वारा—विशेषकर उसी वर्ष नरम और उग्र पक्षों में फिर से ऐक्य हो जाने पर—ब्रिटिश भारत की राजनीतिक दृष्टि से जगो हुई सारी जनता का प्रतिनिधित्व हुआ।

२

सन् १९०७ में सूरत-विच्छेद के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एक विदाइ रूप से नरम-शली सस्था हो गई थी और उसके फलस्वरूप देश में उसकी प्रतिष्ठा घट गई थी। लेकिन उस सस्था ने अपनी आन्तरिक दृढ़ता और सामर्थ्य के बल पर, सन् १९१४ के अन्त तक, फिर देश के राजनैतिक जीवन में अपनी विगनवालीन प्रतिष्ठा और प्रधानता प्राप्त कर ली थी। इसके कई कारण थे और इनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि उग्र पक्ष ने किसी प्रतियोगी सस्था की स्थापना नहीं की थी और सरकार की दमन नीति के फलस्वरूप उग्र दल बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया था। इन परिस्थितियों में, देश में जो कुछ भी राष्ट्रवादी राजनैतिक जीवन था, उसे कांग्रेस का मध्यम मिला और कांग्रेस के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति हुई। विच्छेद के बाद कांग्रेस के नए सविधान में उसके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए थे और कार्य पद्धति के निश्चित नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया था। यह कांग्रेस सन् १९०८ के बाद प्रतिवर्ष किसी बड़े शहर में अपना अधिवेशन करती थी और राष्ट्रीय परिववादों को दूर करने के लिए हलचल करती थी और स्वदेश तथा उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति के सुधार के लिए मांग करती थी। इसके अधिवेशनों में राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति—जैसे फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, नुरेग़ नाथ बनर्जी, डी० ई० वाचा, मदन मोहन मालवीय, राजपतराय, सत्येन्द्र सिनहा, भूपेन्द्रनाथ बनसु, अम्बिकाचरन मजूमदार, कृष्णस्वामी ऐयर, एन० सूबा राव, सकरम नैयर, मुहम्मद अली जिना, जमरूल हक, ए० रसूल, हसन इमाम, सैयद महमूद, मोतीलाल नेहरू, धीनिवात धास्नी, सी० वाई० चिन्तामणि, सच्चिदानन्द सिनहा, तेज बहादुर सपरू, विरान नारायण दर, हरकिशनलाल गोबरन नाथ मिश्र—भाग लेते थे। इन लोगों के अतिरिक्त कांग्रेस में भाग लेने वालों में, धीमती एनी बीसेन्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे, 'पियर्सोल्सफिक्ल सोलरस्ट्री' के प्रेसिडेंट थीं और भारत के धार्मिक, सामाजिक और शिक्षण क्षेत्रों की अग्रणी थीं। उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना था और १९१४ तक वे उसके धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षण विषयक पुनरुत्थान के कामों में व्यस्त थीं। किन्तु महायुद्ध के प्रथम वर्ष में उन्होंने राजनैतिक जीवन में प्रवेश करने का निश्चय किया और पहली बार (दिसम्बर १९१४ में) कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुईं—और जैसा कि प्रवेक्षित था, उन्होंने



तुरन्त ही काग्रस सभलन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। अगले चार वर्षों में वे काग्रस को परिणामों में और ब्रिटिश भारत के राजनैतिक जीवन में अग्रणी रखी और सन् १९१७ के दिसम्बर अधिवेशन में उन्हें काग्रस का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। भारतवासियों की राजनीतिक तलाश को दूर करने का और सक्रिय काम के लिए उन्हें संगठित करने का श्रेय, श्रीमती एनी बीसेन्ट के अतिरिक्त केवल लोकमान्य तिलक को ही दिया जा सकता है। और यद्यपि श्रीमती बीसेन्ट के ही प्रयत्न और प्रभाव का परिणाम था कि सन् १९१६ में काग्रस के नरम और उग्र पक्षों का ललनऊ में सम्मिलन हुआ और श्री तिलक और उनके समर्थकों का काग्रस में पुनः प्रवेश हुआ।

३

सन् १९०८ और १९१६ के बीच काग्रस की कार्य-प्रवृत्ति बढ़ी रही जो सन् १९०५ से पहले थी—किसी प्रमुख नगर में प्रतिवर्ष बड़ा दिना की छुट्टियाँ में काग्रस-अधिवेशन होता था और उसमें सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर सामान्य प्रस्तावों का पारण किया जाता था। सन् १९१४ में भारतीय परिवारों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में ब्रिटिश जनमत जागृत करने के लिए एक शिष्ट मंडल इकट्ठा भजा गया। इस मंडल के सदस्य थे—  
मि० भूपेन्द्रनाथ बनू एम० ए० जिन्ना एन० एम० समर्थ एस० सिन्हा मजबूत हक, माननीय बी० एन० शर्मा और लाला लाजपत राय। यह शतवर्ष की व्यवस्था को समाप्त करने की बात को छोड़कर काग्रस की आय मांगी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसके अन्य परिवार यथावत् चल रहे। इन आठ वर्षों में (जब काग्रस पूर्णरूप से नरम दल वादों के आधीन था) उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति और राजनैतिक सुधारों की संयुक्त योजना जो देश की दो बड़ी राजनैतिक सम्भावनाओं को मान्य थी। विषय के निष्पक्ष विवेचन के हित में यह कठु सत्य कहना अनिवार्य है कि सन् १९१६ की सामुदायिक एकता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय जीवन के एक मौलिक सिद्धान्त का हनन किया गया था। वाग्रम न मुसलमानों के लिए पक्ष निर्वाचन क्षम बनाने के प्रस्ताव का बराबर विरोध किया था। यह सच है कि काग्रस मुसलमानों को और अन्य अल्पसंख्यकों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता अनुभव करती थी किन्तु उसने पक्ष निर्वाचन क्षमों को देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए घातक बताया था, और उनमें उनकी व्यवस्था की अराष्ट्रीय और अलोकतंत्रीय कह कर निजा की थी। किन्तु सन् १९१६ में काग्रस ने राजनैतिक जगहों में ऐक्य प्राप्त करने के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को गृह्यता का सिद्धांत

१ बहुत से काग्रसी, सामुदायिक निर्वाचन क्षमों के दुष्परिणामों के प्रति पूरी तरह सजग थे, किन्तु उनकी दृष्टि में स्वराज्य के लिए यह मूल्य देना अनिवार्य

का और विधान-काय में साम्प्रदायिक निषेधाधिकार को स्वीकार किया। इन तीनों रियायतों के मौलिक सिद्धान्त गलत थे और वे बहुत में काप्रसिया की आवन भर की निष्ठा के विरुद्ध थे। ये रियायतें काप्रस लीम योजना में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा आपत्तिजनक थीं। किन्तु यह भाग्य का व्यंग्य है कि सरकार ने एक ओर तो योजना के विधानिक भाग को अस्वाकार कर दिया और दूसरी ओर उसी योजना के साम्प्रदायिक समन्वयों को १९१९ के सुधारों का अनिवार्य अंग बना दिया।

सन १९१६ के काप्रसियों के पक्ष में यह कहना आवश्यक है कि उनका दृष्टि में ये रियायतें अस्पायी थीं। उन लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार यह विश्वास जमा दिया गया था कि थोड़े ही समय में पथक निर्वाचन क्षत्र की व्यवस्था का अन्त हो जायगा और उनके स्थान पर वास्तविक राष्ट्रीय एवं लोकनग्रीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा।<sup>१</sup> अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त प्रत्यागा अत्यन्त अस्वाभाविक थी और उसका निराशा में परिणत होना अवश्य नावी था।

४

विचाराधान यग में असन्तोष प्रोध और अवमान की भावनाओं को सबसे ज्यादा उत्तजित करने वाला विषय था—दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाना वाला दुर्व्यवहार। दक्षिण अफ्रीका की उस अवस्था की चर्चा की जा चुकी है<sup>२</sup> जिसमें महात्मा गांधी को (काठे वानून के नाम से प्रसिद्ध) एगियाटिक रजिस्ट्रान एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने को विवग किया था। यह एक्ट मार्च १९०७ में ट्रांसवाल पार्लियामेंट में बनाया था। जब सत्याग्रह के फलस्वरूप महात्मा गांधी सहित लगभग १५० आदमी जेल पहुँच गए तो सरकार ने सधि चर्चा की। महात्मा गांधी और जनरल स्मट्स में समझौता हुआ और इसके अनुसार भारतीयों को स्वच्छापूर्वक अपना निबधन कराना था और सरकार को 'दाला शानून' रद्द करना था।<sup>३</sup> किन्तु जब महात्मा गांधी ने अपने साधियों के विरोध के होते हुए और साथ ही अपने प्राणों को जोखिम में डालकर<sup>४</sup> अपनी ओर से सबधित समझौते के

वाय था। उन्हें यह आशा थी कि स्वराज्य के बाद साम्प्रदायिकता का बालान्तर में अपने-आप अन्त हो जायगा।

१ सन १९१६ के काप्रस-लीग समन्वय के सवध में इस पुस्तक के पहले अंगरेजी संस्करण की आलोचना का गयावत रखा गया है।

२ इसी पुस्तक का बारहवाँ अध्याय देखिये।

३ जनरल स्मट्स ने महात्मा गांधी से कहा था 'अधिकारों' को स्वच्छापूर्वक निबधन कराने पर मैं एगियाटिक एक्ट को तुरन्त रद्द कर दूंगा। Satya-graha in South Africa page 242

४ Gandhi Satyagraha in South Africa, page 306

भाग को पूरा कर दिया था जनरल स्मट्स ने 'काले कानून' को रद्द करने से इकार कर दिया। इसी बीच ट्रांसवाल पार्लियामेंट ने एक ऐक्ट पारित कर दिया था जिसके अनुसार प्रत्येक नए भारतीय को वहाँ बसने से रोक दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, विवाद होकर फिर सत्याग्रह आरम्भ करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। इस बार यह सत्याग्रह दोनो एक्टों के विरुद्ध होना था। सरकार को अन्तिमरेखम दिया गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काला कानून रद्द नहीं किया जाता और यदि इस विषय में सरकार का निष्पक्ष एक नियत दिनांक तक प्राप्त नहीं होता तो भारतीयों द्वारा प्राप्त किए हुए निबन्धन-पत्रों को जला दिया जायगा और वे लोग उसका फल भोगन को तैयार रहें। १६ अगस्त १९०८ को एकत्र किए हुए निबन्धन पत्रों को (जिनकी संख्या २००० से अधिक थी) जला दिया गया और सत्याग्रह फिर आरम्भ कर दिया गया। बहुत से लोग जल गये—बहुनों को भारत के लिए निर्वासित कर दिया गया। जल में हर प्रकार की कठोरता बरती गई—एक आदमी ठंड लगने के कारण न्यूमोनिया से मर गया। एक जल में सत्याग्रहियों को विवाद होकर भूल हड़ताल करनी पड़ी। मिस्टर गांधी और सेठ हाजी इब्नी खां जो शिष्ट मजदूर इकट्ठा हुए थे, वह भी खाली हाथ लौट आये। जेल जानेवाले सत्याग्रहियों के बेटों के लिए मिस्टर गांधी ने मि. कैपेनबार्ड की जमीन पर टालसटाइल फार्म को आरम्भ किया। सर्वत्र चलता रहा और जब तक एक-दो सत्याग्रही जेल जाते रहे।

दक्षिण अफ्रीका में दुबारा सत्याग्रह आरम्भ होने पर भारत के लोगों में हलचल हुई। देश के विभिन्न भागों में सभाएँ की गईं। सघर्ष जारी रखने के लिए चन्दा इकट्ठा किया गया और दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। फरवरी १९१० में मि. गोखले ने साम्राज्यीय विधान परिषद् में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके द्वारा नैटाल उपनिवेश के लिए 'सतबंद' मजदूरों की भर्ती रोकने के लिए सन्धारिड गवर्नर-जनरल को अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की। उस प्रस्ताव का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश में भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए वहाँ की सरकार पर दबाव डालना था। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया और नैटाल के लिए 'सतबंद' मजदूरों की भर्ती पर रोक लगा दी, पर वांछित फल प्राप्त नहीं हुआ। मि० गोखले ने दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए और वहाँ की वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत-मनी की सहायता मांगी। अक्टूबर और नवम्बर १९१२ में मि० गांधी के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न भागों का दौरा किया। उन्होंने वहाँ के मजदूरों से भी काफी लम्बी बातचीत की। जनरल बोपा से यह आश्वासन मिल जाने पर कि 'काला कानून' रद्द कर दिया जायगा और ३ पोंड

वा टैक्स समाप्त कर दिया जायगा, मि० गोखले नवम्बर १९१२ में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए।<sup>१</sup>

जनरल स्मट्स ने फिर वचन भंग किए और ३ पौंड के टैक्स को रद्द करने के लिए विधान प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया और यह कारण बताया कि नैटाल के सदस्य उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध थे। विरुद्ध होकर सत्याग्रह के कार्यक्रम में इस टैक्स को रद्द करने की मांग को भी शामिल किया गया।

इस समय तक सत्याग्रहियों का छोटा-सा दल लगभग निपट चुका था। किंतु शीघ्र ही एक नया परिवाद उठ खड़ा हुआ और उसके कारण महात्मा गांधी को सत्याग्रह को फिर एक सक्रिय रूप में चलाने का अवसर मिला। और इस बार उन्होंने स्त्रियों से भी सहयोग देने के लिए कहा। १४ मार्च १९१३ को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मि० सर्लें ने एक निर्णय द्वारा ऐसे विवाहों को जिन का निबन्धन नहीं हुआ हो और जिन को ईसाई उग पर न किया गया हो, अमान्य घोषित कर दिया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की यूनिफन सरकार से प्रार्थना की कि इस सम्बन्ध में भारतीयों के लिए एक विशेष विधान बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब महात्मा गांधी ने भारतीय पुरुषों और स्त्रियों से इस विषय पर सत्याग्रह करने के लिए कहा। स्त्रियों के सब से पहले जल्ये में फोनिक्स आश्रम में रहनेवाले १६ स्त्रियाँ थी जिन में श्रीमती वस्तूरवा गांधी भी थी। इन सब को तीन महीने का कठोर कारावास दंड दिया गया। दूसरे जल्ये में ११ स्त्रियाँ थी जो सन् १९०८-९ के सद्य के दिनों में टालस्टॉय फार्म में रही थीं। इन स्त्रियों ने न्यूकैसिल की खानों में काम करने वालों को भड़काने के लिए नैटाल की सीमा में प्रवेश किया। धमिकोने (जिन की सख्या लगभग ६००० थी) वर्तमान की पुकार पर ध्यान दिया और हड़ताल कर दी। इन ११ स्त्रियों के गिरफ्तार हो जाने पर हड़तालियों के नेतृत्व के लिए महात्मा गांधी स्वयं न्यूकैसिल पहुँच गए।

खानों के मालिकों ने हड़तालियों के साथ कठोर व्यवहार किया। हड़तालियों को उनके मरानों में से निकाल दिया गया और उन लोगों को अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ खुले मैदान में रहना पड़ा। टालस्टॉय फार्म की स्त्रियों के कारावास के कारण वे लोभ और ज़्यादा चिढ़ गए थे और खानों में काम पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय परिवादों को दूर कराने के उद्देश्य से मि० गांधी ने उनके साथ ट्रांसवाल की सीमा पर आकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया।

न्यूकैसिल से ट्रांसवाल के लिए इस 'शान्ति पूर्ण' सेना को ऐतिहासिक यात्रा २८ अक्टूबर की आरम्भ हुई। इस सेना का उद्देश्य टालस्टॉय फार्म पर पहुँचना था।

१. Gandhi . Satyagraha in South Africa, page 408.

लेकिन सीमा पर हड़तालियों के गिरफ्तार कर लिए जाने का डर था। इस सेना में २०३७ आदमी, १२७ स्त्रियाँ और ५७ बच्चे थे। मि गांधी को मार्ग में तीन बार गिरफ्तार किया गया—दो बार जमानत पर छाड़ दिया गया लेकिन तीसरी बार उन्हें डरवत ले जाया गया और उनपर अभियोग चलाया गया, जिस क फरवस्वरूप उन्हें ९ महीने का बठोर कारावास दंड दिया गया। १० नवम्बर को हड़तालियों की भी गिरफ्तारी की गई और उन्हें तीन स्पेशल रेलगाड़ियों में भरकर न्यूकैसिल भेज दिया गया। वहाँ उनपर अभियोग चलाया गया और उनको जेल भेज दिया गया। वित्तु साधारण जेलों में रखने के स्वाम पर उन्हें खानो के बाड़े में बाटेदार तारों के घरे में रखा गया और खानो के यूरोपियन भीकरी को उनका रक्षक बनाया गया। मि गांधी ने लिखा है—‘ये मजदूर बहादुर आदमी थे और उन्होंने खानो में काम करने से साफ इन्कार कर दिया, जिस के फरवस्वरूप उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जबतक उन्हें मजदूरों में ठीकरें मारी, उन्हें गालियाँ दी और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार किए और उन गरीब मजदूरों ने इन बन्दों की शांति-पूर्वक सहन किया।’ दक्षिण अफ्रीका के अन्य भागों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों ने, न्यूकैसिल के मजदूरों के प्रति सहानुभूति के कारण, अपने यहाँ भी हड़ताल की। कुछ स्वानों पर गोलियाँ चलाई गईं और कुछ भारतीय मजदूर मारे भी गए। बहुत-सी स्त्रियों ने सत्याग्रह किया, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और दंड दिया गया। उनके साथ बड़ी निन्द्यता का व्यवहार किया गया और थलियल्ला मुदालियर नामक एक सोलह वर्ष की लड़की को जेल में बंधार हुआ और बाद में जेल से छोड़े जाने पर वह शोच ही भर गई। दक्षिण अफ्रीका का सारा भारतीय समुदाय उड़न यूरोपियनों के जातीयतपूर्ण सगठित अत्याचार का सामना करने के लिए, एक समुक्त निकाय के रूप में उठ खड़ा हुआ।

दक्षिण अफ्रीका की क्रूर एवं अन्यायपूर्ण सरकार के विरुद्ध वहाँ के भारतीय समुदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशंसा की गई। सारे देश में धिराद् सभाएँ की गईं। और उनमें भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ्रीका की सरकार के दुर्व्यवहार का विरोध किया गया। कूट में पड़े हुए अपने भाइयों के साथ भारतवासियों ने हार्दिक सहानुभूति प्रकट की। सत्याग्रहियों की सहायता के लिए चन्दे इकट्ठे किए और उद्यम देखी नरेशो और गरीबो, सभी ने सहयोग दिया। सत्याग्रहियों के प्रति भारतवासियों की सहानुभूति में लार्ड हार्डिज ने अपना और अपनी सरकार का योग दिया। भारत सरकार के लिए यह एक असाधारण बात थी। २४ नवम्बर १९१३ को लॉर्ड हार्डिज ने महाजन सभा, भद्रास में एक व्याख्यान में कहा—‘हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका

१. Gandhi : Satyagraha in South Africa, page 476.

म आप के देग नाइयो न वहाँ के कानूनों को जिन्ह वह गृहित और अन्यायपूर्ण समनते ह तोड़न के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध करने का साठन किया है। वहाँ के कानूनों के प्रति उन लोगों के जो नाब ह उनने हन लो भी असहमत नहीं हो सकते। वे योग कानूना को तोड़न के परिणामा स नली नाति परिचित हैं और ब वीरतापूर्वक सारे दंड सहन के लिए तयार ह। उनके इस सपथ में भारत की प्रबल हार्दिक सहानुभूति ह। यद्यपि म स्वयं भारतीय नहीं हँ चिन्तु उनके प्रति आपके साथ ही मेरी सहानुभूति भी है।<sup>१</sup> लाड हाडिज न व्याख्यान के अन्त में इस बात की मा की कि इस सारे विषय की निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा जांच की जाए और जांच करनेवाले कर्मियों में भारतीय हिता को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी बीच मि गोयले न जिन्ह समुद्री तार द्वारा दक्षिण अफ्रीका के सपथ के दैनिक समाचार मिलते रहते प मि एडिडिज और मि पिअसन से नँटाल और ट्रांसवाल में भारतीयों की सहानुता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जान को कहा। भारत सरकार न भारतीय परिवारों को दूर परान के लिए सर दरमिन राबटसन को भजा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार न एक जांच कमीटी नियुक्त की, लेकिन उसकी रचना असंतोषप्रद होने के कारण सत्याग्रहियों न उसके सामन गवाही दना अस्वीकार कर दिया। सरकार और मि गांधी में एक सामयिक समझौता हुआ जा सन् १९१३ के गांधी-स्मट्स सम्मेलन के नान से प्रसिद्ध है। इसके अधिका भाग को सन् १९१४ के इडियन्स रिलीफ एक्ट में रूप दिया गया। एक्ट न तीन पीड के गृहित टैक्स को रद्द किया भारतीय विवाहों को मान्यता प्रदान की (चिन्तु एक पत्नी और उसके ही बच्चा को वैध माना जा सकता था) और विनाजन निश्चित होने पर अधिवासी प्रमाणक (Domicile Certificate) के आधार पर मुनियन में प्रवेश करने के अधिकार को स्वीकार किया।<sup>२</sup> मि गांधी और जनरल स्मट्स में पत्र व्यवहार द्वारा अन्य बातें तै की गई। जनरल स्मट्स को मि गांधी न अपन अन्तिम पत्र म लिखा, 'इडियन्स रिलीफ विधायक के कारण स और इस पत्र व्यवहार ने उम सत्याग्रह सपथ का अन्त हो गया है जिन का आरम्भ सितम्बर १९०६ में हुआ था और जिस के कारण भारतीय समुदाय को आर्थिक क्षति क अतिरिक्त बाँझों शारीरिक बर्ष उठान पड ह और सरकार को काफी चिन्ता और परेशानी का सामना करना पडा है।'<sup>३</sup>

जिस समय दक्षिण अफ्रीका में सपथ हो रहा था, उना समय एक निष्कर्ष-

१ Modern Review, December 1913, page 638

२ Gandhi Satyagraha in South Africa, page 505

३ म्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५०६

मडल भारत का दौरा कर रहा था। यह मडल कनाडा से आया था और कनाडा के भारतवासियों की स्थिति और उनके कष्टों के सम्बन्ध में जनमत जागृत कर रहा था। इस मडल के सदस्य थे मि नन्दसिंह नारायण सिंह और बलवन्त सिंह। कनाडा में भारतवासियों की दशा के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है और वहाँ के विनियमों से बचने के लिए सरदार मुरदीत सिंह के प्रयत्न और कोमागाटा मारु की यात्रा का भी वर्णन किया जा चुका है।<sup>१</sup> अस्तु, सन् १९१७ के साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मडल ने स्वशासक उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति के प्रश्न को विचारार्थ प्रस्तुत किया। सर सत्येंद्र ने इस विषय पर एक अत्यन्त योग्यतापूर्ण डग से लिखा हुआ ज्ञापन सम्मेलन के सामने रखा। विस्तृत एवं निस्संकोच रूप से विचार हुआ और उसके फलस्वरूप पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगले वर्ष सम्मेलन ने एक विस्तृत प्रस्ताव का पारण किया। और इस अधिकार को मान्यता दी कि प्रत्येक देश को अपनी जन रचना विनियमित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए किंतु भ्रमण, वाणिज्य और अध्ययन के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिकों पर एक दूसरे देश में आने-जाने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। सन् १९१८ के प्रस्ताव ने अन्त में यह निश्चय किया —“अन्य ब्रिटिश देशों में पहले से वसे हुए भारतीयों को (भारत से) अपनी स्थियों और बच्चों को लाने का अधिकार होना चाहिए किंतु (अ) उक्त प्रत्येक भारतवासी की एक पत्नी और उसके ही बच्चों को सम्बन्धित उपनिवेश में प्रवेश करने का अधिकार होगा और (ब) प्रत्येक प्रवेश करने वाले को अपने विभाजन के लिए भारत-सरकार का प्रमाणक प्रस्तुत करना होगा।”<sup>२</sup>

इस प्रकार १९१८ के प्रस्ताव ने स्वशासक उपनिवेशों में भारतीयों की समस्या का सामयिक हल दिया। यह हल वस्तुतः एकामी और भारत के लिए अहितकर था। उपनिवेशों में ऐसे बहुत से प्रदेश थे जहाँ कोई आबादी ही नहीं थी अथवा बहुत छितरी हुई आबादी थी। भारतवासी पिछले कितने ही वर्षों से इन स्थानों में बसने अथवा नौकरी करने के अधिकार के लिए प्रयत्न और बलिदान कर रहे थे। उक्त समझौते के अनुसार यह अधिकार उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया। बदले में भारत सरकार को अन्य उपनिवेशों के लोगों को भारत में बसने से रोकने का अधिकार दिया गया—यह एक ऐसा अधिकार

१ इसी पुस्तक के १८ वें अध्याय का नवौं विभाग देखिए।

२ Resolution of the Imperial War Conference of 1918, quoted by “Emigrant” in “Indian Emigration” page 35

था जा बिल्कुल निरर्थक था। तथापि, सन् १९१८ के प्रस्ताव के पारण से, स्वशासन उपनिवेशों में पहुँचे से बने हुए भारतीयों की स्थिति में, निश्चित सुधार हुआ।

५

पहले महायुद्ध के दिनों में, ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए भारतवासियों के देशान्तरगमन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, और अन्त में भारत सरकार को विवश होकर गृहिन 'घर्तबंद धर्म व्यवस्था' को समाप्त करना पड़ा। सन् १८३३ में दास-प्रथा तोड़ने के बाद यह व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। उपनिवेशों का रोपक समुदाय भारत में अपने अभिवर्त्ताओं द्वारा साधारणतया पाँच वर्ष के लिए नियत वेतन के आधार पर मजदूरों को भर्ती करता था। इस घर्तबंद प्रथा में पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद मजदूरों को भारत लौटाने की अपवा उपनिवेश में स्वतन्त्र नागरिक की तरह बसने की अपवा फिर भर्ती कर लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

आरम्भ से ही यह स्पष्ट था कि देशान्तरगमन की उक्त घर्तबंद प्रथा अवाञ्छनीय थी। मजदूरों की भर्ती करने में जबरदस्ती और जालसाजी से काम लिया जाता था। बहुत-से अनभिन्न लोगों को धोखा दिया गया, बहुत-सी विवाहित स्त्रियाँ को लुभाया गया, युद्ध माताओं और पिताओं के अकेले लड़कों को लालच दिया गया, स्त्रियों और तीर्थ स्थानों पर भीड़ में बिछुड़े हुए सबंधियों का अपहरण किया गया, और एक गाँव से दूसरे गाँव को जानेवाले लोगों को बहकाया गया। ये लोग भर्ती गादामों में ले जाए जाते थे और वहाँ पर इन लोगों से घर्त के पत्रों पर हर प्रकार के उपायों को काम में लाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे।<sup>१</sup> इन लोगों को न तो यात्रा की रातों ही ठीक-ठीक बताई जाती थी और न यह ठीक-ठीक बताया जाता था कि वे लोग किन रातों के अनुसार उपनिवेशों में रहने अपवा काम करेंगे। उपनिवेशों में इस व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूरों पर जुमाने होते थे, उनको पीटा जाता था, कैद किया जाता था। भर्ती किए जानेवाले मजदूरों से इन बातों की कोई चर्चा नहीं की जाती थी। सारी व्यवस्था धोखे और जालसाजी पर टिकी हुई थी।<sup>२</sup> यह सच है कि भारत-सरकार ने स्थिति सुभालने के लिए प्रयत्न किया था और भर्ती के सबंध में कुछ प्रतिबंध<sup>३</sup> लगाए थे किन्तु जैसा कि २० मार्च

१ इस सबंध में विस्तृत वर्णन के लिए देखिए—Report of Messers Andrews and Pearson on Indentured Labour in Fizi.

२ श्री गोखले के अनुसार यह व्यवस्था योभत्स थी और घूर्तता पर टिकी हुई थी—देखिए—Speeches of Gokhale, page 520

३ इस सबंध में जो कानून बनाए गए, उनके सक्षिप्त इतिहास के लिए



१९१६ को साम्राज्यीय विधान परिषद् में १० मासकीय ने कहा, भर्ती करनेवाले पूर्ण अभिकर्ता बड़ी रकमों के लालच से<sup>१</sup> उनको निष्फल कर देते थे। समुद्री यात्रा का प्रबन्ध अत्यन्त असन्तोषप्रद होता था। बहुत-से लोगों को थोड़ी-सी जगह में भर दिया जाता था, खाने और सोने का उचित प्रबन्ध नहीं होता था। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता था कि बहुत-से लोग बीमार पड़ जाते थे और उनमें से बहुत-से लोग मर भी जाते थे। उपनिवेशों में और भी ज्यादा खराब हालत होती थी। मितने ही मजदूर पागल हो गये और कुछ ने आत्महत्या भी की। सन् १९०८-१२ के वर्षों में दत्तबन्द भारतीय मजदूरों की आत्महत्या का अनुपात, प्रति दस लाख ९२६ था<sup>२</sup> जो साधारण परिस्थितियों में आत्महत्या के अनुपात की तुलना में भयंकर प्रतीत होगा। बहुत से मजदूर भ्रष्ट और पतित जीवन व्यतीत करते थे।<sup>३</sup>

जब भारतवासियों को उपनिवेशों में रहनेवाले अपने देशभाइयों की दशा का पता लगा तो उन्होंने उस गहिरे 'दत्तबन्द' मजदूर व्यवस्था का अन्त कराने के लिए हलचल की। काँग्रेस ने वार्षिक अधिवेशनों में गवाह्यान् दिए गए और प्रस्ताव स्वीकार किए गए। समाचार-पत्रों ने आन्दोलन दिया और साम्राज्यीय विधायिका सभा के निर्वाचित सदस्यों ने इस परिवाद को दूर करने के लिए सरकार पर जोर दिया। सन् १९१० में श्री गोल्ले ने साम्राज्यीय विधान परिषद् में इस विषय पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसकी चर्चा की जा चुकी है। ४ मार्च १९१२ को मि गोल्ले ने विधान परिषद् में एक और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके द्वारा भारत में 'दत्तबन्द' मजदूरों की भर्ती को पूर्ण रूप से वर्जित कर देने के लिए

देखिये—“Indian Emigrant” by an Emigrant, pages 15 to 25.

१ यू. पी. के पश्चिमी जिलों में एक पुरुष-मजदूर भर्ती करने की फौस ४५ रुपए थी और एक स्त्री-मजदूर भर्ती करने की फौस ५५ रुपए थी। Proceedings of the Imperial Legislative Council, vol. LIV page 400.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०४

३ श्री एण्ड्रिऊ और श्री पिअर्सन ने फिजी की हालतों का इस प्रकार वर्णन किया है—“हम फिजी की कुली वस्तियों के अपने पहले दृश्य को भूल नहीं सकते। स्त्रियों और पुरुषों—सभी के चेहरे से उनके ग्रन्थ जीवन का निश्चित परिचय मिलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि पतित जीवन की महामारी का प्रकोप हुआ है। वैवाहिक ग्रन्थ की पवित्रता का कोई स्थान नहीं था—सर्वत्र पाशविनता का राज्य था। स्त्रियाँ अपने पतियों को बदरती रहती थीं और लड़कियों का वध-विषय होता था।”—उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०६

उनको पद-ग्रहण करने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार अधिवाग सदस्या के मनोनीत लाजा लाजपत राय को अध्यक्ष पद के लिए छांट जान से रोक दिया। ऐसी दशा में यह विचार किया जाता था कि बम्बई अधिवान अनुच्छेद न० २० में सन्तोषन करना अम्बोबार कर देगा और उग्र पक्षवाग का अपना पक्ष सगठन बनाना होगा। किन्तु बाग्स अधिवेशन से कुछ ही सप्ताह पहले सर फारोबराह का दहान्त हो गया। श्री गोखल की बड़ी महीन पहल मूल्य हो चुकी थी। अस्तु, श्रीमती बीसन्ट और उनका समर्थक न बग्स में उग्र पक्ष के पुनरागमन के लिए बाधित सन्तोषन सरलता में स्वाकार करा लिया। दिसम्बर १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में उग्र पक्ष के लोगो ने पूरी तरह भाग लिया और उत्तम तिलक को अत्यन्त उत्साहपूर्ण स्वागत और अपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ।

७

सन १९१७ में राजनैतिक आन्दोलन अपने शिखर पर पहुँच गया। लोकमान्य तिलक और श्रीमती बीसन्ट ने बड़ यत्नपूर्वक पिछले तीन चार वर्षों में उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर लिया था।

जैसा कि हम अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है दमन और मुधार की दाहरी नीति ने देश के राजनैतिक जीवन को अत्यन्त सिधिल कर दिया था। धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से स्थिति में मुधार हुआ लेकिन श्री गांधी के प्रखर नतृत्व के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से उसको विराप प्रोत्साहन मिला। दक्षिण अफ्रीका और अन्य उपनिवेशों में भारतीयों की अपमानजनक स्थिति से लोगो को साम्राज्य में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चला और उनको इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया कि जब तक वे स्वयं अपने देश के मालिक नहीं हों तब तक विदेशों में अच्छा व्यवहार प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती—केवल स्वशासन से ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती थी।<sup>१</sup> सन १९०६ के बल्यत्ता अधिवेशन में श्री दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्ष पद से इस बात को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त भी किया था किन्तु उस समय स्वराज्य का आदेश उग्र-पक्षी नेताओं के अनुरार भी बहुत दूर माना जाता था। युरोपीय महायुद्ध छिड़ने पर सारी स्थिति बदल गई और मुद्दर भविष्य का आदेश निकट भविष्य में व्यवहार्य दिखाई देने लगा।

१ यह बात श्रीमती बीसन्ट ने इस आग्रह भारतीय आलोचना के उत्तर में कहा थी कि भारतीय नतागण युद्ध की परिस्थितियों का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। देखिए Annie Besant 'The Future of Indian Politics'—pages 52 to 66

महायुद्ध ने स्वशासन की माँग को जन्म नहीं दिया वरन् उसकी पूर्वस्थित माँग को एक नई महत्ता, अविलम्बता और वास्तविकता प्रदान की। युद्ध ने भारतीयों को दासता के अपमान और उनकी वीर्यशून्यता के प्रति फिर से सचेत किया और उन्हें स्वशासन और स्वतन्त्रता का सच्चा मन्त्र बताया। यदि जर्मन सेनाओं ने इंग्लैंड जीत लिया तो क्या दशा होगी? इसके उत्तर में अगरेज राजनीतिज्ञ जो चित्र खींचते थे, वह इतना भयंकर होता था, कि उस विपत्ति को रोकने के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं मालूम पड़ता था। उस अवधि में दूसरी बात यह थी कि अगरेज राजनीतिज्ञों ने अपने पक्ष के लिए सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उस युद्ध को 'संसार में लोकतन्त्र की सुरक्षा करने के निमित्त' बताया। भविष्य में प्रत्येक बड़े अथवा छोटे राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना था, और किसी भी राष्ट्र को चाहे वह किना हो छोटा अथवा दुर्गल क्यों न हो, ऐसी दासता-व्यवस्था के अन्तगत, जिसका वह राष्ट्र अनुमोदन न करता हो, रहने के लिए विवश नहीं करना था। भारतीय नेताओं ने इन धारणाओं को यथावत् स्वीकार किया और भारतीय स्वशासन के लिए उनका उपयोग किया। श्रीमती एनी बेसेण्ट ने सदास प्रेसीडेन्सी में और श्री तिलक ने बम्बई प्रेसीडेन्सी में होम-रूल (स्वराज्य) के लिए जोरों से प्रचार किया। श्रीमती बेसेण्ट और लोकमान्य तिलक, दोनों ही चतुर राजनीतिज्ञ थे—दोनों ही महायुद्ध में हर प्रकार की सहायता करने के लिए उत्सुक थे, किन्तु दोनों ही का यह मत था कि महायुद्ध ने भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक दैवी अवसर प्रदान किया है और उसका लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। जब उनको अथवा उनके साथियों को युद्ध-सम्मेलनों में बुलाया जाता था तो वे स्वशासन और समान प्रतिष्ठा का प्रश्न सामने ले आते थे और उसको युद्ध की सहायता के प्रश्न के साथ जोड़ देते थे।<sup>१</sup> लेकिन अन्य भारतीय नेताओं की निष्ठा दृढ़तर थी—उन्हे चपचापा नूरत सेवा करने और धर्मपूर्वक पुरस्कार की प्रतीक्षा करने की नीति में विश्वास था। उनमें से कुछ को बाद में यह अनुभव हुआ कि उनकी निष्ठा गलत थी, किन्तु दुर्भाग्य से उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी।

श्रीमती बेसेण्ट सन् १९१४ के आरम्भ में कांग्रेस में सम्मिलित हुई थी और उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा और संगठन की सहायता से औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा

१. मि. तिलक और उनके साथियों का यह मत था कि युद्ध में सहयोग देने के लिए भारतीयों को सेना में बराबरी का स्थान दिया जाना अनिवार्य था। उन्हें इस बात का निश्चय होना चाहिए था कि युद्ध के बाद वे एक स्वतन्त्र भारत में लौटेंगे।

डोमिनियन स्वराज्य प्राप्त करने की आशा की थी।<sup>१</sup> किन्तु सीधे ही वह इस निर्णय पर पहुँची कि नरम दली कांग्रेस में आगे बढ़ने और सर्वसाधारण को शिक्षित तथा संगठित करने के साहस का अभाव है। अतः उन्होंने 'न्यू इंडिया' नामक एक दैनिक पत्र को और 'कामनवेल' नामक एक साप्ताहिक पत्र को निकाला और एक नई राजनैतिक सस्था की स्थापना की। इस नई सस्था को अखिलम्व स्वराज्य की माँग के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वसाधारण में सारे वर्ष काम करना था। किन्तु होम रूल लीग स्थापित करने से पहले, उन्होंने कांग्रेस को वही काम करने के लिये अवसर देना स्वीकार किया और नियत समय बीत जाने के बाद ही सितम्बर १९१६ में होम रूल लीग का मद्रास में उद्घाटन किया गया। अप्रैल १९१६ में लोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी और वे दैनिक 'केसरी' और साप्ताहिक 'महर्द्रा' की सहायता से महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे। जेल से छूटने के समय से ही श्री तिलक राष्ट्रवादी (उग्र) पार्टी को फिर से संगठित और दृढ़ करने के लिए काम कर रहे थे और उनके प्रेरक एवं योग्यतापूर्ण नेतृत्व में पार्टी का बल और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। पूना और मद्रास दोनों ही स्थानों की होम रूल लीगों ने मिलकर देश में होम रूल के लिये प्रबल प्रचार किया। दिसम्बर १९१६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने मुधारों को एक संयुक्त योजना स्वीकार की और उन्होंने देश में उसके प्रचार के लिए होम रूल संगठन के उपयोग करने का निश्चय किया। सन् १९१६ के लखनऊ (कांग्रेस) अधिवेशन के बाद श्रीमती बीसेण्ट और श्री तिलक ने 'कांग्रेस लीग योजना' के समर्थन और देश की राजनैतिक एवं राष्ट्रीय जागृति के लिए और भी ज्यादा जोरों से प्रचार का काम किया।

बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियों में होमरूल-आन्दोलन से उन प्रेसिडेन्सियों की सरकारों को परराहत हुई और उन्होंने श्रीमती बीसेण्ट और श्री तिलक की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाकर उन तए आन्दोलनों का परोक्ष रूप से दमन करने का प्रयत्न किया। मई १९१६ में, मि. तिलक के विरुद्ध कायंबाहो की गई और होमरूल-सभाओं में उनके कुछ व्याख्यानों पर आपत्ति की गई; और उनसे एक वर्ष तक सद्व्यवहार के लिए २०००० रुपये की एक व्यक्तिगत बाण्ड भरने की और इतनी ही रकम की दो जमानतें जमा कराने की आज्ञा दी गई। बाद में, बम्बई हाईकोर्ट में अपील के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट की आज्ञा रद्द कर दी गई। लगभग इसी

१. श्रीमती बीसेण्ट ने सर प्रोरोजसाह और अन्य कांग्रेसियों के समक्ष अपना सारा कार्यक्रम रखा था जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षण विषयक कार्यक्रम भी सम्मिलित था, किन्तु उन लोगों ने धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम को अपनाने से इकार कर दिया था।

समय ( २६ मई १९१६ को ) 'न्यू इंडिया' से २००० रुपए की जमानत मांगी गई, जो २८ अगस्त को ज्वन कर ली गई। दुबारा १०००० रुपए की जमानत मांगी गई और वह तुरन्त ही दे भी दी गई। श्रीमती वीसेण्ट ने जव्ती की आज्ञा के विरुद्ध मद्रास-हाईकोर्ट में अपील की और बाद में प्रिवी कौंसिल में भी अपील की, पर कोई सफलता नहीं मिली।

श्री तिलक और श्रीमती वीसेण्ट के राजनैतिक कामों पर सरकारी रोक का, बिल्कुल उलटा प्रभाव हुआ। सन् १९१७ में उन दोनों ने राष्ट्रीय प्रचार के काम में अपने आप को पूरी तरह—नन मन से—लगा दिया और होमरूल का आन्दोलन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया। सन् १९१७ के आरम्भ में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके फलस्वरूप लोगों में असन्तोष की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई और होमरूल की मांग और ज्यादा जोरदार हो गई। सरकार ने सक्रिय निरुत्साहन और साधारण दमन की नीति अपनाने की आवश्यकता अनुभव की। एक आज्ञा द्वारा स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को होमरूल-सभाओं में सम्मिलित होने से रोका गया। प्रान्तोष गवर्नरों ने होमरूल के प्रचार को निरुत्साहित करने के लिए व्याख्यान दिए और आन्दोलन के नेताओं को चेतावनी दी। मद्रास-सरकार और भी आगे बढ़ी और उसने श्रीमती वीसेण्ट और उनके दो सहयोगियों को नजरबन्द करने की आज्ञा दी। राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार सरकार ने अ-ग्राहकों को होमरूल विरोधी आन्दोलन आरम्भ करने में सहायता दी और प्रेसीडेन्सी में साम्प्रदायिकता की ज्वाला को भड़काया। अस्तु, श्रीमती वीसेण्ट, श्री वादिया और श्री एरण्डेल की नजरबन्दी से सारे देश में विरोध और रोष का ज्वार उमड़ पड़ा और देश के विभिन्न स्थानों में विरोध-सभायें की गईं। राष्ट्रवादी नेतागण जो अबतक होमरूल संगठन से अलग रहे थे, अब उसमें सम्मिलित हो गए और उसके दायित्वपूर्ण पदों पर काम करने लगे। जुलाई में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी मीटिंग में होमरूल लीगा के काम की सराहना की और श्रीमती वीसेण्ट और उनके सहयोगियों की नजरबन्दी के सम्बन्ध में सरकारी कार्यवाही की निन्दा की। उसने श्री तिलक की प्रेरणा से वाइसरॉय और भारत-मन्त्री के समक्ष दृढ़ एवं गम्भीर प्रतिनिधित्व किया, भारत-सरकार की दमनकारी एवं प्रतिक्रियावादी नीति की निन्दा की और तुरन्त ही स्वराज्य की एक बहुत बड़ी किस्म प्रदान करने की मांग की। कमेटी ने कहा कि एक राजकीय उद्घोषणा द्वारा भारतीय राजनैतिक भाँगों को स्वीकार किया जाए और नजरबन्द नेताओं—श्रीमती वीसेण्ट और उनके सहयोगियों—को मुक्त किया जाए। कमेटी ने सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी कि यदि उक्त कार्यवाही जल्दी न की गई तो देश में १ इसी पुस्तक के संहर्षे अध्याय का सातवाँ विभाग देखिए।

असन्तोष और अशान्ति की बड़वार बराबर होती रहती । थोमती बीसेण्ट का १९१७ के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पद दिया गया, और थोमती बीसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के छुटकारे के लिए प्रयत्न जारी रखने का निम्न किया गया ।

जुलाई और अगस्त १९१७ में भारतीय राजनैतिक आंदोलन चोंगे पर पहुँच गया । इन्ही दिना (जुलाई १९१७ में) मेसोपोटामियन कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसने इंग्लैंड तथा भारत दोनों ही देशों में सलबली भवा दो और उसके फलस्वरूप भारतीय राजनैतिक सुधारों को विशेष समय और बल प्राप्त हुआ । लार्ड हार्डिज की सरकार और भारत मंत्री मि० चम्बरलेन ने जिस प्रकार मेसोपोटामिया के युद्ध का संचालन किया था वही न उसकी तीव्र आलोचना की थी । लार्ड नर्वन ने अपने एक व्याख्यान द्वारा लार्ड हार्डिज ने दोष के अधिकांश भाग को ब्रिटिश युद्ध विभाग के सिर मढ़ दिया किन्तु मि० माण्टगु ने, जो पहले उप-भारत मंत्री रह चुके थे हाउस ऑफ कॉमन्स में मेसोपोटामियन कमिशन रिपोर्ट पर अपने (१२ मार्च १९१७ के) प्रसिद्ध व्याख्यान में तत्कालीन भारत सरकार की बड़ी तीव्र आलोचना की । उन्होंने कहा कि हमारे आधुनिक उद्देश्य को दृष्टि से भारत सरकार अत्यन्त जड़, अत्यन्त निश्चेष्ट और अत्यन्त असमर्थ है ।<sup>१</sup> उन्होंने यह मत प्रकट किया कि बाइसराय को काम करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए भारतीय विधायिका सभाओं को आंशिक नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाना चाहिए, इंडिया ऑफिस के व्यय का बोझ भारतीय राजस्व पर नहीं होना चाहिए और भारत परिषद् के अधिकारों को घटाकर, भारत-मंत्री को वास्तविक दायित्व सौंपा जाना चाहिए । इसी सम्बन्ध में उन्होंने इंडिया आफिस (भारत मंत्री के पूरे कार्यालय) के ढाँचे में सुधार करने के लिए कहा और तत्कालीन इंडिया आफिस की इन शब्दों में निन्दा की— प्रविधानीय व्यवस्था के अनुसार इंडिया आफिस की कार्य-वृद्धि में इतना धुमाव फिराव है और इतने बाग़जाल की सानापूरी करनी पड़ती है कि साधारण नागरिक उसका स्वप्न में भी अनुमान नहीं कर सकता ।<sup>२</sup> मि० माण्टगु ने इस भारतीय भाँग का समय किया कि ब्रिटिश नीति तुरन्त पोषित की जानी चाहिए और भारत की ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए । अब कृतज्ञता का तर्क भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि मेसोपोटामिया की पापलेबाजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत सरकार अबुशल है ।<sup>३</sup> उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, "यदि आप भारतवासियों की राजभक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें अपने भाग्य

१. The Indian Annual Register, 1919, page IX

२ Ibid page XI

Indian Annual Register, page XII.

नियंत्रण के लिए अधिक अवसर दीजिए—असमर्थ परिपक्व के रूप में नहीं बल्कि स्वयं कार्यकारिणी के अधिकाधिक नियंत्रण के रूप में।”<sup>१</sup> अन्त में उन्होंने कहा — “यदि आप आधुनिक अनुभव के आधार पर इस एक शताब्दी पुराने और प्रतिरोधपूर्ण ढांचे में परिवर्तन नहीं करण तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भारतीय साम्राज्य के नियंत्रण का अधिकार खो देंगे।”<sup>२</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष ने प्रचार के लिए मि० मॉण्टेगु के व्याख्यानो का लाभ उठाया। उसकी प्रशंसा की गई और उसको विस्तृत रूप से उद्धृत किया गया। देश की सरकारी व्यवस्था में सुगन्त परिवर्तन करने की आवश्यकता बताने के लिए उसका उपयोग किया गया। इस प्रकार होम-रूल और मजूरज्ज्व नेताओं की मुक्ति के आन्दोलन का प्रयत्न प्रोत्साहन मिला।

इसी बीच यूरोप में युद्ध स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई और इंग्लैंड को भारत से अधिक सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता हुई। भारतवासी सहायता के लिए तैयार थे किन्तु इस बात का निश्चित आश्वासन चाहते थे कि निकट भविष्य में उन्हें स्वराज्य मिल जाएगा। मि० लॉयड जॉर्ज व समय के प्रवाह को अनुभव किया और मि० चैंम्बरलैन के स्थान पर (जिन्होंने मेसोपोटामिया की सीमाएँ रिपार्ट से सम्बन्धित आलोचनाओं के कारण त्यागपत्र दे दिया था), मि० मॉण्टेगु को भारत मंत्री नियुक्त किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अन्य कामों में व्यस्त होते हुए भी, भारतीय नीति की नई घोषणा का मसौदा तैयार करने का काम हाथ में लिया और साथ ही श्रीमती बोसेण्ड और उनके सहयोगियों को छानने के सम्बन्ध में भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी की। इसके अतिरिक्त सरकार ने सेना के ‘कमीशंड’ पदां पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में रोक हटाई और ९ व्यक्तियों को, जिन्होंने युद्ध में ब्रिटिश सेवा की थी, उक्त ‘कमीशंड’ पद प्रदान किए। २० अगस्त १९१७ को, मि० जार्ज रॉबर्ट्स के एक प्रश्न के उत्तर में मि० मॉण्टेगु ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह ऐतिहासिक घोषणा की — “साम्राज्य सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक साथ लिया जाए और स्वशासन सत्ताओं का प्रमत्त विकास किया जाए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में कमसे-कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके।”<sup>३</sup> यह और बहना चाहेगा कि इस नीति की प्रगति प्रमत्त कई किस्मों में हो सकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन पर भारत के विभिन्न लोगों की उन्नति और भलाई का उत्तरदायित्व है प्रत्येक किस्म के समय और परिमाण का निर्णय करेगी जिसमें वे इस बात को

१ Ibid, page XIII.

२. Ibid, page, XIV.

ध्यान में रखगो कि जिन लोगो को सेवा के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनमें कितना सहयोग प्राप्त हुआ है और उन पर उत्तरदायित्व का कितना बोझ डाला जा सकता है।”<sup>१</sup>

उसी समय भारत मन्त्री न यह भी बताया कि सम्राट्-सरकार न उनको परामर्श और जाँच के उद्देश्य से तुरन्त ही भारत भ्रमण का निश्चय किया है।

२० अगस्त १९१७ को घोषणा से भारतीय राष्ट्रवादियों के दिल में फिर एक बार फूट पड़ो। नरम पक्ष के राष्ट्रवादियों ने उस घोषणा का ‘भारत के मंगला कार्ता’ के रूप में स्वागत किया, उन्होंने सरकार से उससे उद्देश्यों को साई के रूप में, नजरबन्दों को छोड़ने की माँग की और भारत-मन्त्री के अभ्यागमन के लिए लोगों को जागृत करने के निमित्त अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करने का निश्चय किया।”<sup>२</sup> दूसरी ओर उग्र पक्ष के मतानुसार उक्त घोषणा, भाषा और तत्त्व-दाना ही की दृष्टि से असन्तोषप्रद थी और उन्होंने नजरबन्दों के छुटकारे के लिए और साथ ही भारतीय आवाकाश और माँग की श्रवण मान्यता के लिए आन्दोलन जारी रखने का निश्चय किया।

नजरबन्द नेताओं के छुटकारे का आन्दोलन कुछ<sup>३</sup> अंश में सफल हुआ। ५ मितम्बर १९१७ को भारत सरकार ने नजरबन्दों के छुटकारे के निमित्त मद्रास-सरकार से इस शर्त पर सिफारिश करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की कि ‘वे नेतागण युद्ध के अवशिष्ट समय में राजनैतिक आन्दोलन के लिए उग्र एवं अवैधानिक उपायों को काम में नहीं लाएँगे।’<sup>४</sup>

दोना होम-रूल संस्थाओं ने भारत में राजनैतिक जागृति और प्रचार के अपने कामों को जारी रखा और साथ ही इंग्लैंड में भी प्रचार-कार्य करने का निश्चय किया। श्री तिलक और श्रीमती बीसेण्ट, दोना ही इस अवसर पर इंग्लैंड में जनमत शिक्षित करने की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे और उन्होंने पुराने वापसिया पर इंग्लैंड में एक सिष्टमडल भेजने की वाछनीयता पर जोर दिया। सन् १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में वापसिया ने एव सिष्टमडल भेजने का निश्चय किया था, किन्तु बाद में सर विलियम वेडरबर्न की मन्त्रणा से उसका विचार छोड़ दिया गया। इस बीच इंग्लैंड में निरुत्त आङ्ग-भारतीयों तथा अन्य प्रतिनिधियों ने भारत-

१. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 1.

२ India in the years 1917-18, page 37.

३ अली-बख्श ने सरकार को आश्वासन देने में इन्कार कर दिया था, अतः उनको मुक्त नहीं किया गया।

India in the years 1917-18, page 41.



विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया। इन लोगों ने सुधार-नीति का विरोध करने के लिए इंडो ब्रिटिश-एसोसियेशन की स्थापना की और लाड सिडनहैम को उसका अध्यक्ष बना दिया। अस्तु, श्री तिलक ने इंग्लैंड के मजदूर दल के सम्पर्क स्थापित करने के लिए और वस्तुस्थिति देखने के लिए मि० ब्रैण्टिस्टा को इंग्लैंड भजा। इसके अतिरिक्त एक होम रुल शिष्टमंडल भजन के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने महाशय का व्यापक परिचय किया, इसी प्रकार भीमती बोसेष्ट ने भी प्रयत्न किया। दोनों होमरूल लीगो ने सन् १९१८ के वसंत में अपने शिष्ट मंडलों को इंग्लैंड भजन का निश्चय किया। और सरकार ने आवश्यक पारपत्र भी प्रदान कर दिए। पहला शिष्टमंडल माच में चला गया और दूसरा शिष्टमंडल कोलम्बू से प्रस्थान करने वाला ही था कि ब्रिटिश युद्ध कॅबिनेट के आदेशानुसार पार-पत्र रद्द कर दिए गए। इस प्रकार होम रुल लीगा को ब्रिटिश अनुरा के समक्ष अपने दृष्टि-कोण ध्यस्त करने से रोक दिया गया और उनसे इंडो ब्रिटिश एसोसियेशन के कुटिल प्रचार का प्रत्युत्तर देने में अवसर को छीन लिया गया।

१० नवम्बर १९१७ को माण्टगु मिशन भारत आया और उसने परामर्श और जाँच का काम आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप भारतमन्त्री और वाइसराय ने सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की जो मिशन के अन्य सदस्या—लाड डॉनोमोड, सर विलियम ड्यूक मि० (बाद में सर) भवेन्द्रनाथ बसु और मि० चार्ल्स टॉवर्ट स—को भी मान्य थी। इसी योजना को बाद में सन् १९१९ के गर्वन मेण्ट ऑव इंडिया एक्ट में रूप दिया गया।

### दोसरा अध्याय

## मॉण्टफोर्ड सुधार

१

मॉर्ले मिण्टो सुधारों का उद्देश्य भारत में सासद्-व्यवस्था स्थापित करना नहीं था। यह बात स्वयं लाड मॉर्ले ने लॉर्ड भवन के अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दी थी। दूसरी ओर सन् १९१९ के सुधारों के संयुक्त प्रवर्तकों के अनुसार उन (मॉर्ले मिण्टो) सुधारों का उद्देश्य एक ऐसा विधान बनाना था, जिसके जारों ओर पिछड़े हुए विचारों के प्रतिगामी लागू एकत्रित हो सकें और भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का विरोध न करे।<sup>१</sup> लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिण्टो दोनों ही, शासन में केवल ऐसे भारतीयों को साथ लेना चाहते थे जो भविष्य में शक्ति के संतुलन को बदलने का और भारतीय संस्थाओं के लोकतन्त्रीकरण का विरोध करेंगे।<sup>२</sup> किन्तु भारत के नरम

१. The Report of the Indian Constitutional Reforms, 1918, page 48

पक्ष के राष्ट्रवादी बड़ी आशाएँ लगाएँ बैठ थे और उनका यह विश्वास था कि लार्ड माल्ले का प्रत्याख्यान लाइ भवन में विरोध छान्त करने के लिए था और सुधारों से सरकारी ढाँचे में परिवर्तन होगा और निर्वाचित सदस्यों को शासन में उत्तरदायित्व-पूर्ण सहयोग का अवसर मिलेगा ।<sup>१</sup> श्री गोसले ने यह आशा की थी कि वितीय विषयों में भारत सरकार के नियंत्रण का स्थान परिषदा की आलोचना और विवेचना के नियंत्रण को मिलेगा ।<sup>२</sup> जातीय दृष्टिकोणों को पृष्ठभूमि में रखा जाएगा और सर्वोच्च परिषदों में प्रत्यक्ष प्रश्न के भारतीय दृष्टिकोण को उचित महत्त्व प्राप्त होगा ।<sup>३</sup> और प्रान्तों में ऐसा कोई विधान नहीं बनाया जायेगा जिसके विषय में गर-सरकारी बहुमत हो और निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय विषयों पर प्रभाव डालने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा ।<sup>४</sup> विन्तु एक्ट के लागू होने के बाद कुछ ही महीना में श्री गोसले के विचार बदल गए । अगस्त १९१० में उन्होंने साम्राज्यीय विधान परिषद में कहा — श्रीमान् ! अब हम इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि जब सरकार एक बार कोई निश्चय कर लेती है तो परिषद् के गर-सरकारी सदस्य चाहे जो कहे विन्तु उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता ।<sup>५</sup> प्रान्तीय परिषदों को दया भी उपादा अच्छी नहीं थी क्योंकि निर्वाचित सदस्यों का कहीं पर भी कारण बहुमत नहीं था और इसके अतिरिक्त लगभग सभी विषयों में अन्तिम सत्ता साम्राज्यीय सरकार के हाथों में थी ।

इस प्रकार माल्ले मिण्टो सुधार भारत के अत्यन्त नरम पक्षी राजनीतिज्ञ को भी सन्तुष्ट न कर सके । इसके कई कारण थे । सबसे पहला कारण तो यह था कि साम्राज्यीय विधान परिषद में एक ठोस और दृढ़ सरकारी व्यूह था । इस व्यूह से बचन, उसको तोड़न अथवा बधन का कोई उपाय नहीं था । सरकार और गर-सरकारी भारतीयों के बीच यह व्यूह चीन की दीवार की भाँति स्थायी रूप से जमा हुआ था । परिषदा में जो चर्चा होती थी वह वस्तुतः निर्जीव होती थी और उसमें से वास्तविकता और उत्तरदायित्व की भावना को दूर कर दिया जाता था । सरकारी सदस्यों के मस्तिष्क में अन्तःकरण और अनुशासन के बीच एक तीखा संघर्ष था, और गर-सरकारी सदस्यों के मस्तिष्क में विवशता और विरासा की भावना तीखी हो गई थी और उसमें नरम पक्ष के लोगों को उग्र पक्ष वालों के साथ एक होने को विवश कर दिया था । सारे विषयों में जातीय भेदभाव को प्रधानता दी

१ The Report of the Indian Constitutional Reforms, 1918, page 64

२ उपयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६५

३ Proceedings of the Imperial Legislative Council Vol XLIX, page 29

जाती थी। मि० कर्टिस के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता था कि सारी व्यवस्था का उद्देश्य जातीय भावनाओं को कुपित करना और जातीय भदभावों को बढ़ाना था।<sup>१</sup>

यह बात केवल साम्राज्यीय विधान परिषद् में ही नहीं थी जहाँ सरकारी सदस्य का बहुमत था, वरन् यह बात प्रान्तीय परिषदा में भी थी, जहाँ गैरसरकारी सदस्य बहुमत में थे और बगल में भी, जहाँ निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। इसका एक कारण तो यह था कि गैर-सरकारी बहुमत केवल नाममात्र का था। जैसा कि मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है, 'अनुपस्थित रहने वाला गैर-सरकारी सदस्यों की अपेक्षा गैरसरकारी सदस्य अधिक होते थे और इस प्रकार गैर-सरकारी बहुमत निरर्थक हो जाता था।'<sup>२</sup> दूसरा कारण यह था कि नामनिर्देशित और यरोपियन सदस्य साधारणतया, सरकारी पक्ष की ओर रहना अपना कर्तव्य समझते थे। तीसरा कारण यह था कि सरकारी सदस्यों को केवल समुक्त रूप से ही काम नहीं करना पड़ता था वरन् उन्हें केन्द्रीय सरकार के निर्णयों की रक्षा करनी होती थी, चाहे वे निर्णय प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण के विरुद्ध हो क्या न हो। भारत मंत्री के अनुसार उस व्यवस्था का सिद्धान्त यह था कि 'भारत के लिए एक ही शासन-व्यवस्था है अतः स्थानीय (प्रान्तीय) सरकार का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने में, भारत सरकार के निर्णय का यथाशक्ति समर्थन करे।'<sup>३</sup>

विन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि गैर-सरकारी सदस्य का शासन अथवा विधान कार्य पर कोई प्रभाव नहीं था। बहुत-से विषयों में विधेयकों का अन्तिम मस-विदा बनाने और प्रशासनीय निर्णय करने से पहले उनसे परामर्श किया जाता था। परिषदा में प्रस्तुत हो जाने के बाद भी कितने ही प्रस्तावों में गैर-सरकारी सदस्यों ने महत्वपूर्ण संशोधन कराया था। निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में यही बात हुई थी—इंडियन कोर्ट फीस (एमेण्डमेण्ट) बिल (१९१०), इंडियन फंड्रीज बिल (१९११), इंडियन पेटेंट्स एण्ड डिजाइन्स बिल (१९११) रिमिनल ट्राइब्स बिल (१९११), लाइफ एश्योरेन्स कम्पनीज बिल (१९१२), और इंडियन (बोमस डिप्रीज) मेडिकल बिल (१९१६)। विन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय सदस्य केवल उन्हीं विधेयकों में संशोधन कराने में सफल हुए थे जो सरकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे अथवा जो मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 'देश की शान्ति और सुरक्षा'<sup>४</sup> से सम्बन्धित नहीं थे। प्रशासनीय विषयों में भी सरकार

१. Curtis : Dyarchy, page 372

२. Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 62

३. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ५८

४. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६०

पर सरकारवारी मत का कुछ हद तक प्रभाव पड़ा था—जिस कुछ उपनिवेगों के लिए 'नवद' मजदूर व्यवस्था का अन्त समुक्त प्रान्त में कायपात्रिका परिषद की स्थापना पंजाब में हाई-कोर्ट की स्थापना जल-सासन की जाँच और उस पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति और ओकसेवा आयोग तथा औद्योगिक आयोग की नियुक्ति।<sup>१</sup> सही अनुदष्टि के लिए यह कहना उचित होगा कि सन् १९१७ के अंत तक साम्राज्यीय विधान परिषद् में १६८ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उनमें से सरकार ने केवल २४ को स्वीकार लिया ६८ प्रस्ताव वापिस ले लिए गए और ७६ रद्द कर दिए गए।<sup>२</sup>

माउंटबेट्टे सुधारों की असफलता का दूसरा कारण यह था कि प्रान्तीय सदन कारो पर भारत-सरकार का नियंत्रण कम नहीं हुआ और साथ ही सावजनिक नीति रियासत में भारतीयों की भर्ती के सम्बन्ध में अत्यन्त अनुदार नीति का अनुसरण किया गया। स्थानीय सभाओं में कोई उन्नति नहीं हुई प्रान्तीय विधानों की स्वतन्त्रता नहीं मिली और सावजनिक नीतियों में भारतीयों की सहायता में कोई विचार वृद्धि नहीं हुई।<sup>३</sup> भारत सरकार अब भी ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी थी और वह प्रान्तीय शासन और विधान में अपना नियंत्रण कम नहीं कर सकती थी। विधान और शासन से सम्बन्धित वह क्षमता जिसमें परिषद सरकारी कामों पर प्रभाव डाल सकती थी अत्यन्त समुचित था। बार-बार स्थानीय (प्रान्तीय) सरकारों को यह कहना पड़ता था कि प्रस्तुत विषय उससे अधिकार से बाहर है। प्रान्तीय बजटों के कारण व सरकार राजस्व के क्षेत्र में कोई नया कदम नहीं उठा सकती थी। भारत-सरकार के नियंत्रण के कारण उन्हें प्रशासकीय क्षेत्र में काम करने की स्वतन्त्रता नहीं थी अतः वे भारत सरकार के समक्ष परिषद का दृष्टिकोण ही प्रस्तुत कर सकती थी।<sup>४</sup>

माउंटबेट्टे सुधारों की असफलता का तीसरा कारण यह था कि उनकी योजना के अन्तर्गत जो निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई थी वह विस्तृत अप्रत्यक्ष थी उसमें विभिन्न समुदायों के साथ भेदभाव किया गया था और उसका मौखिक सिद्धांत गलत था। एक ओर तो मुसलमानों के लिए पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे और अन्य हिता को विषय प्रतिनिधित्व दिया गया था किन्तु दूसरी ओर आम जनता को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। प्रस्तुत संवैधानिक प्रणाली के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इतनी समुचित और ठीकी थी कि उससे न तो ओमा की राजनीतिक जागृति

१ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 61.

२ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ६१

३ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ६५

ही हो सकती थी और न उससे उन योगों में उत्तरदायित्व की भावना भरी जा सकती थी। यह बचन आज दिया हुए तथ्या से स्पष्ट हो जाएगा—साम्राज्यीय विधान परिषदों के लिए माधारण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की औसत संख्या केवल २१ थी और एक क्षेत्र में तो यह संख्या कुछ ९ थी। 'परिषद्' के सारे निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होने वाले कुल वोटों की संख्या ४००० से अधिक नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को औसत में लगभग १५० वोट प्राप्त होने थे। संयुक्त प्रांत की विधान परिषद् के सदस्यों को प्राप्त होने वाले कुल वोटों की संख्या लगभग ३००० थी और प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को औसत में १४३ वोट प्राप्त होते थे।<sup>१</sup> प्रान्तीय परिषदों के लिए साधारण जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्वामाय मंत्रों के सरकारों द्वारा सदस्य करते थे और साम्राज्य परिषद् के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के सरकारों द्वारा सदस्य करते थे। इसका परिणाम यह था कि आज मतदाता और विधान परिषद् के उसके प्रतिनिधि में कोई सम्पर्क नहीं था और उस मतदाता को वोट का विधान परिषद् की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं था।<sup>२</sup> सन् १९०९ के भारतीय परिषद् ऐक्ट की इस निर्वाचन-व्यवस्था को मि० कर्टिस ने एक बचना बताया है।<sup>३</sup>

ऐसे मौखिक दोषों के हानि हुए राजनतिक मुधारों के प्रश्न का अनिश्चित रूप से स्थगित करना संभव नहीं था और महाकुल से सम्बन्धित कामों में व्यस्त होने पर भी सरकार को विचार होकर इस ओर ध्यान देना पड़ा। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर लार्ड बिंथले ने भी गोखले से एक मुधार-योजना तैयार करने के लिए कहा जिसे उन्होंने मार्च १९१५ तक पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह योजना का गोखले के राजनतिक मृत्युकेल<sup>४</sup> के नाम से प्रसिद्ध हो भूतजात थी। श्री गोखले की दृष्टि प्रान्तीय स्वायत्तता पर थी—जिसका अर्थ केवल यह था कि उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता हो। उसमें उत्तरदायित्व प्रदान करने की समस्या पर विचार नहीं किया गया था। यही दाप उस नापन<sup>५</sup> में जा जा साम्राज्यीय विधान परिषद् के उनीस भारतीय सदस्यों का प्रस्तुत किया जा और यही दाप उस योजना में भी था जिसे १९१६ में वायस और

१ Curtis Dyarchy, Page 368

२ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, Page 54

३ Curtis Dyarchy, Page 368

४ इस योजना के लिए देखिए—Keith Speeches and Documents on Indian Policy Vol II Page III to 116

५ इस ज्ञापन के लिए देखिए—उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ११६ से १२४ तक।

मुस्लिम लीग न सयुक्त रूप से, बड़े यत्नपूर्वक बनाया था।<sup>१</sup> उत्तरदायी सरकार की क्रमशः स्थापना करने की दृष्टि से भारतीय समस्या का हल करने वाली सबसे पहली सुधार-योजना वह थी जिसे मि० लामोनल कर्टिस के नेतृत्व में 'इंग्लिश राजपूट टाउन्स ग्रुप' ने तैयार किया था। इस योजना में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था।<sup>२</sup> इसी द्वैध प्रणाली के आधार पर मि० मॉण्टगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अपनी योजना बनाई और उसको भारतीय वैधानिक सुधारों पर (१९१८ की) अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया।

मि० कर्टिस ने भारतीय जनता को सम्बोधित करते हुए कई पत्र प्रकाशित किए और उनमें यह बताया कि 'स्व शासन और उत्तरदायी शासन' में एक महत्वपूर्ण अन्तर था। यह बात सच थी। भारत को स्वशासन तो अविलम्ब प्रदान किया जा सकता था। सरकारी ढाँचे को चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की मर्यादा पर्याप्त थी। किन्तु अपठित ग्रामबासियों को उत्तरदायी सरकार के लिए शिक्षित करना मामूली काम नहीं था और उसे जल्दी नहीं किया जा सकता था—विशेषकर ऐसी स्थिति में जब वे लोग भाषा, धर्म और दूरी से विभाजित थे। इस बात का लार्ड कर्जन जैसे चतुर व्यक्ति अच्छी तरह जानते थे और सन् १९१८ के सुधारों के कार्यान्वित होने के बाद यह बात प्रकट हो गई थी कि २० अगस्त १९१७ की प्रसिद्ध घोषणा का मसविदा तैयार कराने में लार्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ था। वस्तुतः कांग्रेस-लीग-योजना की अस्वीकार करने का वास्तविक कारण यह था कि उसमें भारतीय हाथों में बहुत ज्यादा अधिकार सौंपने की राह की गई थी।

'कांग्रेस-लीग-योजना' के अनुसार केन्द्र और प्रान्ता, दोनों ही की परिपक्व विसृष्ट होनी थी, नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या कुल के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी थी, पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर परिपक्व में मुमलमानों को निश्चित अनुपात में स्थान मिलने थे, प्रान्तीय विधान मंडलों का विधायिका एवं वित्तीय नियंत्रण का पूर्णाधिकार मिलना था, उन्हीं मंडलों की प्रस्ताव द्वारा प्रान्तीय कार्यकारिणी सरकार का निर्देशन करने का अधिकार मिलना था, और रक्षा, विदेश एवं राजनैतिक विभागों से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में एमे ही अधिकार केन्द्रीय स्तर में दिए जाने थे। उस योजना में प्रान्तीय एवं केन्द्रीय कार्यपालिका सरकारों का ढाँचा बदल दिया गया, उनके अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होने थे जो सिविल सर्विस के सदस्य न हों, और कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्य भारतीय होने थे जो विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

१ Keith : Speeches and Documents on Indian Policy, Vol II, pages 124-132

२ Curtis Dyarchy

धुने जाने थे। साधारणतया कार्यकारिणी परिषदों में सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्ति नहीं होती थी। ऐसी दशा में वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उक्त योजना का, जिसमें भारतीयों को इनमें विस्तृत अधिकार सौंपने की मांग की गई थी, आल-भारतीय कर्मचारीतन्त्र ने विरोध किया, उसकी तीव्र आलोचना की गई<sup>१</sup> और उसे १९१८ के मुधारों के संयुक्त प्रवर्तकों ने अस्वीकार कर दिया।

३

भारत-मंत्री और चाइमरस की संयुक्त रिपोर्ट उस मुधार योजना पर अवलम्बित थी जिसे इंग्लिश राउण्ड टेबल ग्रुप के सदस्य सर विलियम ड्यूक और उस ग्रुप के नेता मि. कर्टिस ने तैयार किया था। सर विलियम ड्यूक उस समय भारत परिषद् के सदस्य थे, उससे पहले वह बंगाल के उप-गवर्नर रह चुके थे और बाद में वे माण्टेगू मिशन के सदस्य होकर भारत आए। मुधारों के मध्य में सर विलियम की तीन धारणायें थीं :—(१) अब वह समय आ गया है कि भारतीयों की उत्तरदायी प्रामाण्य की कला में शिक्षित करना चाहिए और इसके लिये कुछ ऐसे विषयों को जिन में कोई जोखिम न हो, लोक-नियंत्रण के अन्तर्गत कर देना चाहिए, (२) कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं (जैसे पुलिस विभाग) जिनकी दृढ़ता और जिन की क्षमता सरकार के लिये अपरिहार्य है, उनको वर्तमान स्थिति में लोक-नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता<sup>२</sup>; और (३) प्रत्येक प्रान्त में कुछ जन-जाति क्षेत्र हैं जिनमें सरकार का प्रामाण्य बचाव रहना चाहिए। इन धारणाओं को

१. ये आलोचनाएँ संक्षेप में इस प्रकार थीं (१) कार्यकारिणी सरकारों का विधान इसलिए अयुक्तप्रवाद था कि उनमें सिविल सर्विस वालों को दूर रखा गया था। इन्हीं लोगों को सरकारी काम की सबसे ज्यादा जानकारी और उसका अनुभव था। अध्यक्ष को कार्यकारिणी बनाने में अपने निर्णय में काम लेने से वंचित कर दिया था। (२) कार्यकारिणी की स्थिति जोखिम में भरी हुई थी। कार्यकारिणी के सदस्य पाँच वर्षों की नियुक्ति होते थे; उनपर विधायिका की कठोर निगरानि दिया गया था। ऐसी दशा में कतिविरोध स्वाभाविक था। (३) विधेयाधिकार का संरक्षण निरर्थक था। (४) योजना में राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। (५) योजना अव्यवहार्य थी। *The Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 104—113.*

२. *Curtis : Dyarchy, page 18. The Duke Memorandum was first published in India in 1920 in Dyarchy by Lionel Curtis.*

मान लेन पर दूध प्रणाली के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी जिसके अनुसार प्रांत का शासन दो भागों में बांटा जाना था—एक तो वह भाग जो जनता के प्रति उत्तरदायी होना था और दूसरा वह भाग जो भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होना था। सर विलियम के शासन में बंगाल सरकार को दो भागों में बांटा था—(१) स-परिषद् गवर्नर के आधीन सरक्षित विभाग और (२) हस्तान्तरित विभाग जिनका संचालन गवर्नर की अध्यक्षता में कुछ सदस्यों के मंत्रिमंडल के हाथ में होता था। तुरन्त हस्तान्तरित किए जानेवाले विभाग थे— शिक्षा स्थानीय स्वाशासन एवं समाजन। शीघ्र ही इन में ये पांच विभाग और जोड़ दिए गए—निबंधन सहयोग आकलन कृषि वन और सावजनिक निर्माण। हस्तान्तरित विभागों का सच चयन के लिए कोई पृथक् अथवा विषय व्यवस्था नहीं थी किन्तु यह सुझाव दिया गया था कि आवकांगी की आय का उपयोग किया जाए और नए टक्स लगाए जाएं।

यह शासन सन् १९१६ के आरम्भ में ही तैयार हो गया था। उसके कुछ समय पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय होकर आ गए थे। मई १९१६ में उस शासन की एक प्रति वाइसराय के पास भेजी गई और अक्टूबर १९१६ में इंग्लिश राजपट्ट टबेनस के नेता मि. कर्टिस उस योजना के मौलिक विचारों का प्रतिपादन करने के लिए भारत आए। कुछ समीक्षण करने के बाद वह योजना एक संयुक्त संवोधन के रूप में भारत मंत्री और वाइसराय के समक्ष (नवम्बर १९१७ में) प्रस्तुत की गई। इस संयुक्त संवोधन में ६४ यूरोपियनों के और ९० भारतीयों के हस्ताक्षर थे। नवम्बर १९१७ में प्रकाशित होने पर यूरोपीय और भारतीय दोनों ही प्रकार के समाचार-पत्रों में उसका तीव्र आलोचना की।

४

मि. मांटगु अपने मिशन के सदस्यों के साथ १० नवम्बर १९१७ को दम्बई में आए। प्रकटत उनका उद्देश्य भारत की राजनतिक दशा की जांच करना था, भारतीय जनता और उच्च सरकारी अधिकारियों के मत से परिचित होना था, और वाइसराय के सहयोग से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत मंत्री के भारत जान का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। भारत जान से पहले ही उन्हें कांग्रेस-लीग-योजना और डब्लू. शासन दोनों का पता था और उन्होंने अपनी योजना कम से कम उसकी रूपरेखा निश्चित कर ली थी। भारत जान के उनके दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि वे इस ढंग से काम करना चाहते थे कि मानो मुंधारा की सारी योजना भारत सरकार द्वारा ही बनाई गई है।<sup>१</sup> इस दृष्टि से वे अधिकांश रूप में असफल रहे। उन्हें वाइसराय की कार्यकारिणी-परिषद् से,



प्रान्तीय सरकारों के अध्यक्षों से विनयकर पंजाब के सर माइकेल ओ डायर और मद्रास के लाड पेण्ट्रिड से और यरोपीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई। विरोधी बग के लिए उन्हें बहुत-सी रियायत करनी पड़ी। सिविल सर्विस के लोगों को उन्हें यह आश्वासन देना पड़ा कि उनके वेतन में काफी वृद्धि की जाएगी। गवर्नरों को उच्च पदा पर पहुँचाने के लिए उन्हें अधिक अवसर प्रदान किये जायेंगे और उन्हें सरक्षण मिलेगा जिसमें उनके नए अधिपति—मंत्रिगण—हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। भारत-सरकार को प्रसन्न करने के लिए प्रान्तीय स्वायत्तता पर प्रतिबन्ध लगाय गए और प्रान्तीय जनता को प्रदान किए जानेवाले उत्तरदायित्व को घटा दिया गया। इस प्रकार योजना का आ अन्तिम रूप सामने आया उसमें मौलिक योजना की इस भव्यता का अभाव था जिसे बनाए रखने के लिए मि माटगु बड़ उत्सुक थे। भारत आन पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री को अपने पहले पत्र में उन्होंने लिखा था— मेरे भारत आन का अर्थ यह है कि हम लोग कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। मैं इंग्लैंड लौट कर कोई खोल अपने नहीं दिखा सकूँगा वह बात युवा-तरकारी होनी चाहिए जैसा वह निरर्थक है वह भारत के भावी इतिहास की केन्द्रशिला होनी चाहिए।<sup>१</sup> मैं इंग्लैंड के अपने साथियों को यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि हमारे परामर्श के फलस्वरूप कोई ऐसी योजना बनी है जो अत्यन्त सङ्कुचित और कृपण है तो यह छलपातक होगा—क्याकि वे लोग फिर कभी हमारा विश्वास नहीं करेंगे—उस देश के लोग जिसका इतिहास हमारा गौरव है।<sup>२</sup>

किंतु रिपोर्ट पूरी होने पर अब लायड जाज की सूचना दी गई तो उस समय भारत मंत्री की भाषा बिल्कुल भिन्न थी। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह अपेक्ष्य नहीं है उसमें एक सिद्धान्त है प्रस्तावों में सुधार के लिए बहुत गुंजाइश है किन्तु रिपोर्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तथापि इस योजना को यदि शीघ्र ही कार्यान्वित नहीं किया जाता तो वह समयानुरूप नहीं रहेगी।<sup>३</sup> ब्रिटिश सरकार को आवश्यक विधान बनाने में डेढ़ वर्ष लगा और उसके बाद सुधारों को कार्यान्वित करने में एक वर्ष और लगा। फरवरी १९२१ में मन्त्रिमंडल के ड्यूक ने नियमानुरूप साम्राज्यीय विधान सभा का उद्घाटन किया और उस समय तक देश में असहयोग आन्दोलन पूरा जोर पकड़ गया था। मार्च मई के सुधारों की भाँति माष्टफीड सुधार भी कार्यान्वित होने के समय तक पुराने पड़ गए थे।

१ Montagu An Indian Diary, page ३

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १० और ११

३ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ३६२

मि माण्टगु को अपन दूसरे और तात्कालिक उद्देश्य में अधिक सफलता मिली। सन १९१७ के बीच के महोनों में भारतीय स्थिति अत्यन्त मनोर हो गई थी। उसी समय यूरोप में युद्ध की स्थिति भी अत्यन्त सकटग्रस्त थी। ब्रिटिश सरकार के मतानुसार यह अत्यन्त आवश्यक था कि भारत की स्थिति सुधरे और वहाँ से युद्ध के लिए अधिक सहायता प्राप्त हो। २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मि माण्टगु के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोग का ध्यान आन्दोलन की ओर से हटा और उन्होंने भारत में भी उनके साधियों पर जोर डालने का प्रयत्न किया। १८ फरवरी १९१८ को मि माण्टगु ने लिखा— युद्ध के अत्यन्त सकटपूर्ण समय में मैं भारत की ७ महोनों तक गान्त रखा हूँ। मैं राजनीति को अपन मिशन के अतिरिक्त और किसी विषय पर ध्यान ही नहीं देना दिया।<sup>१</sup> उन्होंने एक और बड़ी बात की थी। उन्होंने अपन पक्ष में भारतीय नेताओं के एक दल का संगठन कर लिया था। इन नेताओं को उनके उद्देश्य की सच्चाई में विश्वास था और वे उनको पूर्ण सहयोग देने को तैयार थे। मि माण्टगु के विचार से यह बात आवश्यक थी कि हमारा समर्थन करने के लिए एक दल हो। अन्यथा मैं मन्त्रिमण्डल को इस बात का विश्वास कल दिला सकूँगा कि भारत में हमारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई समुदाय तैयार है।<sup>२</sup> १२ दिसम्बर १९१७ को अपनी योजना में उन्होंने निम्नलिखित बात को एक पृथक स्थान दिया— भारतीयों की एक नई संस्था बनाई जाए जिस सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता दी जाए। यह संस्था हमारे प्रस्तावों के पक्ष में प्रचार करे और हमारी सहायता करने के लिए इंग्लैण्ड को प्रिण्ट मशीन भेजे।<sup>३</sup> उन्होंने इस विषय पर मि (बाद में सर) भये ब्रनाथ बसु और सर (बाद में लार्ड) सत्येन्द्र सिन्हा से बात की— हमें ज़रूर एक मध्यम दल बनाने के बारे में वार्तालाप किया। वे लोग बड़े उत्साही प्रतीत हुए और समाचार-पत्र निकालने के बारे में कहा। मेरे विचार से वे सबकुछ कुछ करना चाहते हैं।<sup>४</sup> और उन्होंने काम किया। कुछ ही महोनों में माडरेट पार्टी अस्तित्व में आई। उसका पृथक् संगठन बना और उसने अपन प्रान्तीय एवं अखिल भारतीय सम्मेलन पृथक् रूप से किए।

५

भारतीय वधानिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ को

१ Montagu An Indian Diary, page 288

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १३४

३ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०२-१०४

४ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०४

५ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ २१७

प्रकाशित हुई। किन्तु काम पूरा करने के लिये तीन कमेटीयाँ नियुक्त की गई—लाइ सल्लोवों को अध्यक्षता में मनाधिकार कमेटी मि रिचर्ड फ्रीम की अध्यक्षता में कार्याधिकार कमेटी और लाइ विल्ड को अध्यक्षता में गृह प्रशासन कमेटी। इन कमेटीयों को रिपोर्ट जून १९१९ में प्रकाशित हुई। इन रिपोर्टों के आधार पर सन १९१९ का गवर्नमेन्ट ऑव इंडिया विधायक का मसविदा बनाया गया। ५ जून १९१९ को मि माण्टगु ने विधायक के दूसरे वाचन के लिए कहा। दूसरे वाचन के बाद दोनों भवनो ने विधायक को एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपन का निणय किया। लाइ सल्लोव इस प्रवर-समिति के अध्यक्ष थे और उनके अतिरिक्त उस समिति में सात हाउस आब कामर्स के सदस्य थे और सात लाइ भवन के सदस्य थे। इस संयुक्त प्रवर-समिति ने बहुत-से—सरकारी और गैर-सरकारी अवरोध और भारतीय—साक्षियों का परीक्षण किया। उसने एक बड़ी योग्यतापूर्ण रिपोर्ट तयार की जिसे हाउस ऑब कामर्स ने स्वीकार किया और विधायक ने तदनुसार परिवर्तन किया गया। ५ दिसम्बर को हाउस आब कामर्स ने उसका पारण किया १८ दिसम्बर को हाउस आब लाइस ने उसका पारण किया और २३ दिसम्बर १९१९ को उसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। किन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए अनुपूरक नियम बनने थे। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय समीकरण के सबब में सरकार को परामर्श देने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने की भी आवश्यकता थी। वित्तीय सबब कमेटी ने जिसके अध्यक्ष लाइ मेस्टन थे अपनी रिपोर्ट ३१ मार्च १९२० को प्रस्तुत की। भारत सरकार ने २० जुलाई १९२० को एकदम के अन्तर्गत बन हुए नियमों को प्रकाशित किया। नए विधान मंडल के लिए नवम्बर में निर्वाचन हुए और १ जनवरी १९२१ को भारत में सुधारों को कार्यान्वित किया गया।

✓✓  ६

सन १९१९ के सुधारों ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास में तीन नई और महत्वपूर्ण बातों को—उत्तरदायी शासन का आरम्भ किया देशी नरेशों को भारतीय शासन में—विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में—साथ लिया और द्वेष शासन व्यवस्था का प्रवर्तन किया।

२० अगस्त १९१७ को जिस नीति की घोषणा की गई थी उसे व्यवहार में लाने के लिए भाष्टफोड रिपोर्ट ने चार बड़-बड़ सिद्धांत निर्दिष्ट किए थे। इनमें से पहला सिद्धान्त यह था—

स्थानीय संस्थाओं पर जहाँ तक संभव हो, पूर्ण रूप से लोक नियंत्रण होना

चाहिए और उन्हें बाहरी नियंत्रण से ज्यादा से ज्यादा स्वतन्त्रता होनी चाहिए।”<sup>१</sup>

इस विषय पर भारत सरकार ने मई १९१८ के प्रस्ताव<sup>२</sup> में अपनी नीति पहले ही निश्चिन कर दी थी किन्तु प्रत्येक प्रान्त को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उस नीति को कार्यान्वित करने का काम नई प्रान्तीय सरकारों के लिए छोड़ दिया गया था।

मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के दूसरे भूख में दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था—प्रान्तीय सरकारों के प्रति सत्ता का निष्पण और प्रान्तों में आर्थिक उत्तरदायित्व का आरम्भ। दूसरे सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के लिए प्रान्तीय सरकारों का दो भागों में विभाजन होना था—एक भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी और दूसरा प्रान्तीय मन्त्रालयों के प्रति। इस प्रकार मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ने २० अगस्त १९१७ की घोषणा की नीति को रूप देने का प्रस्ताव किया। ऐक्ट की प्रस्तावना ने इस नीति को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया और भारत के उन्नत राष्ट्रवादियों को ‘आत्म निषेध’ की भाँति को अस्वीकार किया और साथ ही पूर्ण सार्वभौमता और उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की भाँति दी। उसमें यह भी कहा गया—“भारत-वासियों की उन्नति और बलाई का दायित्व पार्लियामेंट पर है और केवल वह पार्लियामेंट ही इस बात का निर्णय कर सकती है कि (उत्तरदायित्व की) प्रत्येक किस्म कब दी जाएगी और कितनी बड़ी होगी।”

७

इस प्रकार मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के केन्द्रीय प्रस्ताव ने प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए दो महत्वपूर्ण बातें भारत को—उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतन्त्रता और जनता के प्रति जवाबदारी का हस्तान्तरण।

प्रशासन के विषयों और आय की मदों को दो—केन्द्रीय और प्रान्तीय—बगों में बाँटा गया। अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्रीय विषय ये थे—रक्षा (इसमें सना, नौसेना और हवाई सना की गणना थी), विदेश-सम्बन्ध, देशी राज्यों से सम्बन्ध, रेलों (कुछ अपवादों को छोड़कर), सैन्य महत्व के संचार साधन, डाक और तार, मुद्रा और टकरान, सामाजिक श्रम, सामान्यीय राजस्व की मदें, दीवानी और फौजदारी कानून और पद्धति, पारिषद (चर्च आदि से सम्बन्धित) व्यवस्था, अखिल भारतीय नौकरियों, राजनितिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्थाएँ, और ऐसे सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रान्तीय विषय घोषित न किए गए हों। महत्वपूर्ण प्रान्तीय विषय ये थे—स्थानीय स्वशासन, शिक्षा (कुछ अपवादों को छोड़कर);

१. The Report on the Indian Constitutional Reforms 1918 page 123.

२. इसी पुस्तक का १७ वाँ अध्याय देखिए।

चिकित्सा विभाग, समाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण जैसे सड़क, भवन, छोटी रेलवे लाइनें, कृषि, उद्योग-वधो का विकास, आवकारी, पशु चिकित्सा विभाग, मनिलेख और सहयोग गमितियाँ, दुर्भिक्ष सहायता, माल-गुजारी प्रशासन, सिंचाई बन, न्याय पुलिस जल, फँकट्री निरीक्षण और श्रम-समस्या, प्रान्तीय श्रृण, और ऐसे काम जिन्हें अभिकर्ता के रूप में करना हो।

कार्याधिकार का यह विभाजन इतना निश्चित और कठोर नहीं था जैसा कि संप्र-व्यवस्था में होता है। यदि कभी इस बात पर सन्देह होता कि कोई विषय केन्द्रीय है अथवा प्रान्तीय, तो उस प्रश्न का निर्णय स-परिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा होता था और यह निर्णय अन्तिम था। दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार किसी भी विषय को (जो सूची के अनुसार केन्द्रीय हो) स्थानीय महत्त्व का बताकर, उसे प्रान्तीय विषय घोषित कर सकती थी। अन्त में कुछ प्रान्तीय विषयों पर विधान बनाने के लिए स-परिषद् गवर्नर-जनरल को पूर्व-अनुमति लेना आवश्यक था।

इसी प्रकार राजस्व की मदों को दो वर्गों में बाँटा गया था और विभाजित शीर्षकों की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया था, किन्तु केन्द्रीय सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए प्रान्तीय असादान की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार को अपना सारा व्यय चलाने के लिए नई मदों से राजस्व आय को जल्दी से जल्दी बढ़ाना था और उपर्युक्त असादान व्यवस्था केवल उसी समय तक के लिए थी।

राजस्व की मदों का बटवारा मेस्टन कमेटो की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। राजस्व की निम्नलिखित मदें प्रान्ता को सौंपी गई थी—मालगुजारी आवकारी, सिंचाई, बन, स्टाम्प और निवन्धन। स; प्राग्भवीय राजस्व मदों में सीमा-शुल्क, आयकर, रेले, डाक और तार, नमक और अफीम की गणना थी। अन्य मदें भी इसी तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच विभाजित थी। बम्बई और बंगाल को आपत्ति को कुछ हद तक दूर करने के लिए, आय-कर की अतिरिक्त उगाही में से उन्हें २५ प्रतिशत का भाग दिया गया था, बशर्ते कि वह अतिरिक्त उगाही, आय के निर्धारण में वृद्धि के कारण हो।

मेस्टन कमेटो ने यह अनुमान किया था कि राजस्व की मदों के नए बटवारे के कारण केन्द्रीय वजट में सन् १९२१-२२ में ९८३ ०६ लाख रुए का घाटा होगा। दूसरी ओर कमेटो ने यह अनुमान किया था कि प्रान्ता की कुल आय में १८५० लाख की विशुद्ध वृद्धि होगी। अतः कमेटो ने केन्द्रीय घाटे को पूरा करने के लिए प्रान्ता का आरम्भिक असादान निश्चित करने का आधार उनकी 'नई व्यय-सामर्थ्य' को बनाया। यह बात स्वीकार की गई कि यह आधार वस्तुतः साम्यामूलक नहीं था और आदर्श आधार 'देने की सामर्थ्य' पर होना चाहिए था। अतः इस बात का प्रस्ताव किया गया कि सात वर्षों के अन्दर वास्तविक असादान आदर्श आधार के

अनुसार हो जाना चाहिए। इस बीच भारत सरकार को अपनी वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार करनी थी कि वह प्रान्तीय असादान की आवश्यकता से जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए। भारत सरकार द्वारा निश्चित आरम्भिक और मानक असादान इस प्रकार थे —

प्रान्त	बड़ी हुई व्यय-सामग्र्य (लाख रुपया में)	सन् १९२१-२२ का आरम्भिक असादान (लाख रुपया में)	आरम्भिक असादान का अनुपात (प्रतिशत)	भारत सरकार द्वारा निश्चित मानक प्रतिशत
मद्रास	५७६	३,४८	३५३	१७/९०
बम्बई	९३	५६	५३	१३/९०
बंगाल	१,०४	६३	६३	१९/९०
संयुक्त प्रान्त	३,९७	२,४०	२४३	१८/९०
पंजाब	२,८९	१,७५	१८	९/९०
बर्मा	२,४६	६४	६३	६३/९०
बिहार तथा उड़ीसा	५१	X	X	X
मध्य प्रान्त	५२	२२	२	५/९०
आसाम	४२	१५	१३	२३/९०
कुल जोड़	१८,५०	९,८३	१००	९०

भारत के ८ बड़े प्रान्तों में (जिनका उपर्युक्त तालिका में नाम दिया गया है) एक-सी शासन-व्यवस्था व्यवहार में लाई गई। इस समय बर्मा को छोड़ दिया गया था किन्तु १९२२ में बर्मा में और १९३१ में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में उसी व्यवस्था को कार्यान्वित किया गया। ये सब 'गवर्नरो के प्रान्त' कहलाते थे।

मॉण्टफोर्ड सुधारों के फलस्वरूप, प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में व्यवहार में आने वाली व्यवस्था, ट्रैप-प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। प्रान्तीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था—'सरक्षित' और 'हस्तान्तरित'। हस्तान्तरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज-सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, उद्योग-धंधों का विकास, आचाराय, पशु-चिकित्सा, मोन धेन और सहयोग समितियों की गणना थी। सरक्षित विषयों की सूची में निम्नलिखित विभाग थे—बित्त, मालगुजारी; दुग्ध सहकारिता; न्याय, पुलिस, जेल, मुफारालय, जन-जाति, समाचार-पत्रों, छात्र-शाला और पुस्तकालय का नियंत्रण; सिंचाई और जल-मार्ग, फंक्शनों का निरीक्षण, खाने, बिजली, गैस, बॉइलर, मोटर गाड़ी, धर्म-हित और औद्योगिक झगड़े, अपराजित क्षेत्र और सार्वजनिक मेवाए, और

अभिकर्ता के काय । सरक्षित विषयो के उचित प्रबंध के लिए प्रांतीय सरकार (१९१९ के एक्ट के अनुसार) भारत मंत्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंग्लैंड की जनता के प्रति उत्तरदायी थी । हस्तान्तरित विषयो में सुशासन का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधान-परिषदों द्वारा प्रांतीय मतदानाओं पर था । ऐसी परिस्थितियों में प्रांतीय सरकारों को उच्चतर सत्ता के नियंत्रण से मुक्त करना संभव नहीं था । अतः केवल हस्तान्तरित विषयो के क्षेत्र में ही भारत मंत्री और भारत सरकार के नियंत्रण में कुछ वास्तविक कमी हुई ।

सरजन प्रवर-समिति ने यह मत प्रकट किया था कि सरक्षित विषयो के प्रशासन के संबंध में प्रविधानीय रूप से नियंत्रण कम करना न तो वांछनीय था और न उसकी कोई आवश्यकता ही थी । किंतु उसने यह सुझाव दिया था कि व्यवहार द्वारा एक ऐसी परंपरा डाली जावे कि जब प्रांतीय सरकार और विधान मंडल किसी विषय पर सहमत हो तो साधारणतया उनके दक्षिण को मान्यता दी जावे और ऐसे अवसरों पर भारत मंत्री और भारत सरकार हस्तक्षेप न कर जब तक कि किसी केन्द्रीय विषय की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक न हो ।<sup>१</sup> हस्तान्तरित विषयो के संबंध में संयुक्त प्रवर-समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि भविष्य में भारत मंत्री और भारत सरकार का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए ।<sup>२</sup> इस उद्देश्य से प्रविधानीय नियम बनाए गए जिनके अन्तर्गत केवल निम्नलिखित बातों के लिए सपरिषद गवर्नर जनरल में अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण के अधिकार निहित किए गए —

(१) केन्द्रीय विषयो के प्रशासन के रक्षण के लिए

(२) संघर्षित प्रांतों में मतभेद होने पर उनके प्रश्नों का निपटारा करने के लिए और

(३) एक्ट की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् एस २९ए एस ३९ (१ए) भाग ७ ए के संबंध में अथवा उनके उद्देश्य से अथवा उनके अन्तर्गत भारत मंत्री द्वारा अथवा उसकी अनुमति से बनाए हुए नियमों के अनुसार सपरिषद गवर्नर जनरल के निहित अथवा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करने के लिए ।<sup>३</sup>

उपरोक्त तीन विषयो के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विषयो में भी भारत

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents Part II page 524

२ Sapru The Indian Constitution pages 21 & 22 एक्ट के इन निर्दिष्ट विभागों का ठको नियुक्तियाँ और हार्ड कमिश्नर द्वारा उगाहे हुए प्रांतीय ऋणों आदि से सम्बंध था ।

नियुक्त किए जाते थे और अन्य पाँच प्रान्तों के लिए साधारणतया ज्येष्ठ लोक-सेवक छांटे जाते थे जिनके सम्बन्ध में प्रविधान के अनुसार गवर्नर-जनरल से परामर्श करना आवश्यक था। कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती थी। उनका कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए निश्चित था और उनका वेतन भी ऐक्ट द्वारा निश्चित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट ने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या चार निश्चित की थी किन्तु समुक्त प्रवर समिति का यह मत था कि अधिकांश प्रान्तों में दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रविधान के अनुसार परिषद् के लिए कम-से-कम बारह वर्षों के अनुभवों एक लोक-सेवक की नियुक्ति करने का नियम था। कार्यकारिणी परिषद् में किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति के लिए कोई प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की गई थी, किन्तु यह बात उपलक्षित थी कि उक्त दो सदस्यों में से कम-से-कम एक सदस्य गैर-सरकारी भारतीय होगा। समुक्त प्रवर समिति की सिफारिश के अनुसार कार्यकारिणी के लिये दो यूरोपियनों की नियुक्ति होने की दिशा में दो गैर-सरकारी भारतीयों की भी नियुक्ति होनी थी।

गैर-सरकारी व्यक्तियों में से गवर्नर द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होनी थी, जिनके लिए यह आवश्यक था कि वे प्रान्तीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य हों अथवा नियुक्ति के बाद छ महीने के अन्दर ही निर्वाचित सदस्य हो जावें। समुक्त प्रवर समिति के अनुसार ऐसे ही व्यक्ति मंत्री नियुक्त किए जाने थे जिन्हें विधान-परिषद् का विश्वास प्राप्त हो सकता था और जो उसका नेतृत्व कर सकते थे। मंत्रियों की प्रतिष्ठा बही होनी थी जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की थी और उन्हें वही वेतन मिलना था जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को मिलता था—किन्तु विधान-परिषद् आवश्यक समझने पर बोट द्वारा उस वेतन को घटा सकती थी। ऐक्ट के अनुसार “इस प्रकार नियुक्त किए हुए मंत्री का कार्य-काल गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त था।”<sup>१</sup> प्रविधान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निश्चित नहीं की गई थी, किन्तु समुक्त प्रवर समिति का यह मत था कि “किसी भी प्रान्त में दो से कम मंत्रियों की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ प्रान्तों में अधिक मंत्रियों की आवश्यकता होगी।”<sup>२</sup> गवर्नर के स्वविवेक पर कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों और मंत्रियों की सहायता के निमित्त परिषद् कार्यवाह नियुक्त करने के लिए ऐक्ट में व्यवस्था की गई थी। परिषद् कार्यवाहों की नियुक्ति विधान-परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों में से की जानी थी

१. Mukherjee : The Indian Constitution Part I. page 228.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५१२.



और उनको विधान-परिषद् द्वारा निश्चित वेतन मिलना था ।

सरक्षित विषयो का शासन, गवर्नर द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार स-परिषद् गवर्नर द्वारा होना था । कार्यकारिणी परिषद् में मतभेद होने पर विषयो का निर्णय बहुमत के अनुसार होना था । परिषद् में समान मत होने पर अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णायक वोट देने का अधिकार था । किन्तु यदि गवर्नर के मतानुसार, "उसके प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा अथवा हिंसा पर मौलिक प्रभाव पड़ना हो" तो वह अपनी परिषद् के बहुमत के निर्णय का प्रविधान के आधार पर उल्लंघन कर सकता था ।"

गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट १९१९ के अनुसार हस्तान्तरित विषयो का शासन गवर्नर को अपने मंत्रियों के परामर्श से करना था किन्तु उसको मंत्रियों की सलाह को अस्वीकार करने और अपने निर्णयानुसार काम करने का अधिकार था । दूसरी ओर मंत्रिगण त्याग-पत्र दे सकते थे । "अन्तिम स्थिति में गवर्नर अपनी विधान परिषद् का विलोपन कर सकता था और नए निर्वाचन के बाद नए मंत्री छांट सकता था, किन्तु नभुवन शर्मा का मत है कि यह आचार्य ब्रह्मचारी का ही है कि इस कर्ण को अपनाने पर गवर्नर एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएगा कि विलोपन के विषय पर वह नए मंत्रियों के विचारों को स्वीकार कर सकेगा ।" किन्तु आपात की दशा में, जिसके लिए गवर्नर-जनरल के पास सत्यापन करने का नियम था, गवर्नर को इस बात का अधिकार था कि वह मंत्रियों के रिक्त स्थानों को पूर्ति न करे और हस्तान्तरित विषयो के शासन को अस्थायी रूप से अपने हाथों में ले ले । यह अधिकार, इस सम्बन्ध में बनाए हुए एक नियम के कारण और भी सबल हो गया था, जिसके अनुसार भारत मंत्री की पूर्ण-अनुमति से गवर्नर-जनरल किसी हस्तान्तरित विषय का निश्चित समय के लिए विलम्बन कर सकता था ।

यह एक विविध बात है कि मॉडफोर्ड सुधारों में मंत्रियों की संपुक्त सभा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । गवर्नरों को जो अनुदेश दिये गये थे उनके अनुसार गवर्नर के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मंत्रियों के संपुक्तरूप से परामर्श करे अथवा मंत्रियों को एक मंडल के रूप में सभा करे । एक्ट के अनुसार गवर्नर द्वारा विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति पृथक् रूप से होनी थी और वे विधान-मंडल में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने थे । यह बात पूर्ण रूप से गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ दी गई थी कि वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति एक ही राजनैतिक पार्टी में से करे अथवा विभिन्न राजनैतिक दलों में से करे अथवा वह ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त

१ Mukherjee The Indian Constitution Part I, page 226.

२. उपर्युक्त पुस्तक, भाग २ पृष्ठ ५१२.

कर लेन पर विधान मंडली में सुधार करने का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने प्रान्ता में दूसरे (विधायिका) भवन स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया किन्तु इस बात का प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक प्रान्त में एक विस्तृत विधान परिषद होनी चाहिए विभिन्न प्रान्तों की परिषदों का आकार और उनकी रचना भिन्न होनी चाहिए उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुत बड़ा बहुमत होना चाहिए और उनमें आवश्यक साम्प्रदायिक और विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए।<sup>१</sup>

एक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों के अनुसार गवर्नरों के प्रान्तों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थी—बाल १३९, बम्बई १११ मद्रास १२७ यू पी १२३ पंजाब ९३ बिहार तथा उड़ीसा १०३, मध्यप्रान्त ७० आसाम ५३। माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की थी कि सरकारी सदस्यों की संख्या कुल के २० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७० प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ वर्गों और हिजा की प्रतिनिधित्व देने के लिए गर सरकारी व्यक्तियों का नाम निश्चित होना था। इन सिफारिशों को संयुक्त प्रवर समिति और पार्लियामेंट ने स्वीकार किया और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों में रूपा दिया गया।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने यथासंभव विस्तृत मतधिकार पर अवलम्बित प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था अपमान की सिफारिश की थी। किन्तु कुछ समुदायों और विविध हितों के लिए साम्प्रदायिक और विविध निर्वाचन क्षत्र बनाने के लिए कहा गया था। माण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रवक्तों को इस बात का विश्वास था कि पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षत्रों की व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के विकास के लिए होगा में नागरिक भावना की वृद्धि के लिए और पिछड़ी हुई जातियों की प्रगति के लिए घातक थी। उस व्यवस्था के पल्लव रूप पिछड़े हुए समुदायों के स्व-आवास और प्रगति के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था और उसमें विभिन्न समुदायों के तत्कालीन पारस्परिक सम्बन्धों के स्थिर हो जाना का डर था। तथापि मि० माण्टगु और लार्ड चेम्सफोर्ड ने मुसलमानों के लिये वही व्यवस्था बनाय रखना आवश्यक समझा और माल्टे मिण्टो सुधारों के समय दी हुई प्रतिज्ञा को उसका कारण बताया। किन्तु उन्होंने लिखा कि प्रान्तों में मुसलमान मतदाताओं का बहुमत है वही साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए हम कोई कारण

दिखाई नहीं देता ।"<sup>१</sup> अन्य समुदायों ने—जैसे पंजाब में सिक्खों ने, मद्रास में अ-ब्राह्मणों ने, भारतीय ईसाइयों ने, आग्ल-भारतीयों ने, यूरोपियनों ने और बम्बई में लिगायतों ने<sup>२</sup>—मॉण्टेगु मिशन से, स्वाभाविक रूप में इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों की भांति उनके लिए भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनाई जाए । मॉण्टेफोर्ड रिपोर्ट के लेखक साम्प्रदायिक व्यवस्था को साधारण-तया विस्तृत करने के विरोधी थे और उन्होंने एक अपवाद (सिक्खों) को छोड़ कर इन समुदायों की मांगों को अस्वीकार कर दिया । उनका यह मत था कि "पंजाब के सिक्खों का पूरा और महत्वपूर्ण समुदाय है, भारतीय सेना को उस समुदाय से साहसी एवं महत्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है, किन्तु वे सभी जगह अल्पसंख्यक हैं और अनुभव से यह प्रकट हुआ है कि उन्हें लगभग कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । अतः हम सिक्खों के लिए भी और केवल उन्हीं के लिए उस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं जिसे मुसलमानों के सम्बन्ध में अपनाया गया है ।"<sup>३</sup> किन्तु जब मुसलमानों और सिक्खों के लिए एक धार उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तो उसे अन्य समुदायों के लिए अस्वीकार करना असंभव था और मताधिकार कमेटी ने निम्नलिखित समुदायों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था अपनाने की सिफारिश की—मद्रास में भारतीय ईसाइयों के लिए बम्बई, मद्रास, बंगाल, यू पी, बिहार तथा उड़ीसा में यूरोपियनों के लिए, और मद्रास तथा बंगाल में आग्ल-भारतीयों के लिए । कमेटी ने मद्रास के अ-ब्राह्मणों के और बम्बई के मराठों के सम्बन्ध में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इस बात की सिफारिश की कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में एक से अधिक सदस्य चुने जाने हों उनमें उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएँ ।

इस प्रकार १९१९ के ऐक्ट के अंतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और आग्ल-भारतीयों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और अ-ब्राह्मणों और मराठों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए । नियमों में जमींदारों, वाणिज्य और उद्योग, रोपक और खनिज हिस्सों के लिये और साथ ही विश्वविद्यालयों के लिए विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की । दलित वर्गों, धर्म आदि के लिए नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई । किन्तु स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि विदेशियों के लिए इस कोमल विषय पर निर्णय करना उपयुक्त नहीं समझा गया उसका निर्णय नई, मुश्किल हुई परिपदों के लिए छोड़ दिया गया ।

१ The Report on Indian Constitutional Reforms  
1918, page 149.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १५०

अनुपात विभिन्न प्रान्तों के लिए विभिन्न था—सबसे ज्यादा यू० पी० में ११८ और सबसे कम बिहार तथा उड़ीसा में ३९।<sup>१</sup>

२ इस तालिका में शहरी और ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन को प्रकट किया गया है—

विधान परिषद् का नाम	शहरी निर्वाचन क्षेत्रों से				ग्राम्य निर्वाचन क्षेत्रों से				कुल (शहरी और ग्राम्य सदस्यों की संख्या)
	मुस्लिम	हिन्दू	गैर-मुस्लिम	कुल	मुस्लिम	हिन्दू	गैर-मुस्लिम	कुल	
१ मद्रास	२	..	९	११	११	..	५६	६७	७८
२ बम्बई	५	..	११	१६	२२	..	३५	५७	७३
३ बंगाल	६	..	११	१७	३३	..	३५	६८	८५
४ यू० पी०	४	..	८	१२	२५	..	५२	७७	८९
५ पंजाब	५	१	७	१३	२७	११	१३	५१	६४
६ बिहार तथा उड़ीसा	३	..	६	९	१५	..	४२	५७	६६
७ मध्यप्रान्त	१	..	९	१०	६	..	३१	३७	४७
८ आसाम	..	..	..	१	१२	..	२०	३२	३३

मतदाताओं की अर्हतायें विभिन्न प्रान्तों के लिए, शहरी, ग्राम्य और जमोदार निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए भिन्न थीं। किन्तु अनर्हतायें सभी जगह एक ही थी अर्थात् कोई भी व्यक्ति जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन न हो अथवा (२) स्त्री हो, अथवा (३) अधिकारी न्यायालय के निर्णयानुसार बिरुद-मस्तिष्क हो, अथवा (४) २१ वर्ष से कम आयु का हो, तो वह अपना नाम निर्वाचक-नामावली में लिखने का अधिकारी नहीं था। छ महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के सबंध में अथवा कदाचार के कारण अभिलिखित व्यक्तिता को पाँच वर्ष तक मत-धिकार से वंचित कर दिया गया था। प्रान्तीय सरकार को प्राधिकार दिया गया था जिसके अनुसार वह अल्पमत अनर्हता को और देशी राज्या के शासक और उनकी प्रजा के सम्बन्ध में अनर्हता को दूर कर सकती थी। प्रान्तीय विधान-मंडल विशेष प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को मतधिकार प्रदान कर सकते थे।

यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनर्हता न हो और उसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सारी अर्हतायें प्राप्त हो तो वह उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली

१ Report of the Reforms Enquiry (Muddiman) Committee 1924, page 129.

में अपना नाम निबन्धित कराने का अधिकारी था। साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों की अहंताएँ य थी — (१) निर्वाचन-क्षेत्र में पिछले बारह महीना से निवास और चुगी को कम से कम ३ रुपये<sup>३</sup> प्रतिवर्ष के टैक्स का भुक्तान, अथवा (२) ऐसे मकान का निवास अथवा स्वामित्व, जिसका वार्षिक किराया ३६ रुपये<sup>३</sup> अथवा उससे अधिक हो, अथवा (३) कम से कम २००० रुपये प्रतिवर्ष की आय पर आय-कर निर्धारण, अथवा ग्राम्यक्षेत्रों में एभी कृषि व भूमि का स्वामित्व जिसका वार्षिक निर्धारित मूल्य कम से कम १० रुपये हो। विभिन्न प्रांतों में यह पिछली रकम १० रुपये से लेकर ५० रुपये तक थी।<sup>३</sup> सभी प्रांतों में मताधिकार के लिए संन्य-सेवा को अहता दी गई थी और पंजाब तथा मध्य प्रान्त में गांव के मुखिया अथवा लम्बरदार को भी मताधिकार दिया गया था। जमींदारों के निर्वाचन-क्षेत्र की मुख्य अहता यह थी कि वह व्यक्ति इतनी जमीन का मालिक हो जिसकी निर्धारित मालगुजारी ५०० रुपये हो। विभिन्न प्रांतों के लिए यह रकम भी भिन्न थी और वह पंजाब में ५०० रुपये से लेकर ५०० पी० में ५००० रुपये तक थी। विश्वविद्यालयों के निर्वाचन क्षेत्र में ७ वर्ष से अधिक अवधि के सभी स्नातकों को मताधिकार दिया गया था। अन्य व्यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र के लिए उन विशेष हितों की संस्थाओं को—जैसे वाणिज्य मंडल (चैम्बर ऑफ कॉमर्स), मिलमालिका की संस्थाओं, रोपक संस्थाओं आदि को—मताधिकार दिया गया था।

प्रान्तीय विधान मंडलों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष अहतायें निर्दिष्ट नहीं की गई थी। उनके लिए केवल दो बातें आवश्यक थी। एक तो यह कि उनको, जिस निर्वाचन-क्षेत्र से वे सड़े हो रहे हों उसके मतदाता<sup>४</sup> की सारी अहतायें प्राप्त होनी चाहिए और उनकी आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त अनर्हताओं के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनहतायें थी—जैसे दिवाला, बकालत से निलम्बन आदि।

निर्वाचन और उनकी निर्दोषिता के सवध में बहुत से नियम बनाए गए थे। कदाचार को रोकने के लिए कठोर नियम निर्दिष्ट किए गए थे। निर्वाचन सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए, गवर्नर द्वारा कमिश्नरों की नियुक्ति करने की १ बड़े सहरा—जैसे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई—के लिए यह रकम इससे बहुत ज्यादा थी।

२ बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा में मुसलमानों के लिए काफी कम रकम निर्दिष्ट की गई थी।

३ यू० पी० में यह रकम २५ रुपये थी।

४ निवास सम्बन्धी अहंताएँ बम्बई, पंजाब और मध्यप्रान्त के अभ्यर्थियों के ही लिए थी।

व्यवस्था को गई थी। इस सम्बन्ध में गवर्नर को आज्ञाएँ कमिश्नर को रिपोर्ट के अनुसार होनी थी और वे आज्ञाएँ अन्तिम थी।

इस प्रकार नई विधान-परिषद् निर्वाचन सत्तारें थी, किन्तु निर्वाचन व्यवस्था विगुद्ध रूप से प्रादेशिक नहीं थी। सरकारी गुट का अनुपात अवश्य कम था किन्तु वह महत्वपूर्ण नहीं था। नाम निर्देशित सदस्य और विराप तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की सहायता से वह गुट काफी प्रभाव डाल सकता था।

गवर्नर के प्रान्त की विधान-परिषद् ३ वर्ष के लिए बनाई जाती थी। किन्तु आवश्यकता हान पर उसका विरोध तीन वर्ष की अवधि से पहले भी किया जा सकता था। विराप परिस्थितियों में गवर्नर विधान-परिषद् का जीवन अधिक से अधिक एक वर्ष तक के लिए बढ़ा भी सकता था। परिषद् के आह्वान, सत्रावसान और विलोपन का और साथ ही उसकी सभा के स्थान और समय के निर्दिष्ट करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया था। गवर्नर विधान-परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता था किन्तु वह उसको सम्बोधन करने का अधिकारी था। परिषद् के अध्यक्ष की पहले चार वर्ष के लिए नियुक्ति और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुष्टि, गवर्नर को करनी थी।

विधान-परिषद् को प्रान्तीय मन्त्रालय और शान्ति के लिए विधि बनाने का साधारण अधिकार दिया गया था। किन्तु इस अधिकार को कई प्रकार से परिमित कर दिया गया था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सब से पहली बात तो यह थी कि निक्षेपण नियमों के अनुसार बहुत से विषयों में गवर्नर-जनरल की पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक था। दूसरी बात यह थी कि गवर्नर, विधान-परिषद् द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को सरक्षित विषयों के शासन सम्बन्धी अपने दायित्व के नाम पर निर्वाणित कर सकता था। तीसरी बात यह थी कि गवर्नर किसी भी विधेयक अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में चाहे वह परिषद् में किसी भी स्थिति में क्यों न हो, विचार करने पर रोक लगा सकता था—यह कारण बता कर कि उससे प्रान्त अथवा उसके किसी भाग को सुरक्षा अथवा शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अन्तिम बात यह थी कि विधान-परिषद् द्वारा स्वीकृत विधेयकों को निषिद्ध करने का अधिकार गवर्नर और गवर्नर-जनरल दोनों में ही विहित था—साथ ही किसी भी विधेयक को परिषद् के समक्ष द्वारा विचार करने के लिए लौटाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सम्राट् को प्रांतीय विधान-मण्डल के किसी भी ऐन्ट को अस्वीकार करने का अधिकार था।

१ माण्टफार्ड ने इस बात की सिफारिश की थी कि स्वयं गवर्नर ही विधान-परिषद् का अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष भी यथासम्भव सरकारी व्यक्ति ही हो।

२ इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिए।

प्रान्तीय विधान-मंडलों की विधायिका शक्ति पर ये बहुत बड़े प्रतिबन्ध थे, किंतु उनमें से कुछ द्वंद्व शासन-व्यवस्था की विचारधारा में आनुपमिक थे।

सरक्षित विभागों के लिए स-परिषद् गवर्नर द्वारा आवश्यक विधान बनाने के सम्बन्ध में मॉण्टफोर्टे रिपोर्ट ने कई पद्धतियों का परीक्षण किया और अन्त में उस काम के लिए बड़ी कमेटियाँ बनाने की सिफारिश की जिनमें सरकारी बहुमत हो। किंतु संयुक्त प्रवर समिति ने उस योजना को अस्वीकार किया क्योंकि उसके अनुसार उस व्यवस्था से सरकारी गृह के दोष स्थायी होने का, स-परिषद् गवर्नर के दायित्व के ठक जाने का और संकट के समय में विधान सुरक्षित न बन सकने का डर था। अतः कमेट्री ने यह प्रस्ताव किया कि गवर्नर को इस बात का स्पष्ट और प्रत्यक्ष दायित्व दिया जाय कि यदि विधान-परिषद् आवश्यक विधान का पारण न करे तो वह स्वयं ही अपने उत्तरदायित्व पर सम्बन्धित विधान बना दे। 'गवर्नर के निजी दायित्व पर बने हुए ऐक्ट, गवर्नर-जनरल द्वारा सम्राट की 'कृपा' के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ।' इस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट १९१९, के तैरहवें खंड में रूप दिया गया।<sup>१</sup>

सरक्षित विषयों से सम्बन्धित व्यय और आपातकालीन व्यय के लिये भी ऐक्ट में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, १९१९, के अनुसार विधान-परिषद् में, प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना था और अनुदान सम्बन्धी मांगों के रूप में राजस्व के विनियोग के लिए प्रस्ताव रखे जायें थे। "परिषद् किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, अथवा प्रस्तावित परिमाण को घटा सकती है . . . ,<sup>२</sup> किंतु (१) गवर्नर द्वारा इस बात का निबन्धन हो जाने पर कि उस विषय पर उसका उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उक्त व्यय आवश्यक है, प्रान्तीय सरकार को सरक्षित विषयों के सम्बन्ध में उस मांग के प्रत्यानयन करने का अधिकार होगा; (२) आपातकाल में प्रान्तीय शान्ति और सुरक्षा के लिए गवर्नर को जितना परिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागों को अधिकृत करने का अधिकार होगा<sup>३</sup>, और (३) राजस्व के विनियोग सम्बन्धी सारे प्रस्ताव गवर्नर की सिफारिश पर ही पेश किए जायेंगे।

ऐक्ट के खंड नं २ (३) से विधान-परिषदों के वित्तीय अधिकार और भी ज्यादा परिमित हो गए थे। इसके अनुसार व्यय के निम्नलिखित शीर्षकों से सम्बन्धित प्रस्ताव परिषदों में प्रस्तुत नहीं किए जाने थे —

१. India in 1919, pages 242 and 243.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४०.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४१.

(१) सपरिषद् गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, और

(२) ऋणों की व्याज और निक्षेप-निधि, और

(३) ऐसा व्यय जिसका परिमाण किसी विधि के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत निश्चित है, और

(४) सम्राट् द्वारा उसके अनुमोदन से अथवा सपरिषद् भारत-मन्त्री द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के वेतन और निवृत्ति, वेतन, और

(५) प्रान्त के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और साथ ही प्रान्तीय महाधिवक्ता का वेतन ।

विधान-परिषदों के सदस्यों की परिषद् के स्थायी नियमों के अन्वयानुसार ये अधिकार प्राप्त थे—वे प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, स्पष्ट प्रस्ताव और मन्त्रियों के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव रख सकते थे और विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे । परिषद् के नियमों में उचित कार्यपद्धति और प्रान्तीय सुरक्षा तथा शान्ति के हित में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए थे ।

भारत सरकार ने प्रांतीय विधान-परिषदों को कार्य-पद्धति के सम्बन्धमें नियम बनाए थे । इन नियमों की अनुपूर्ति आरम्भ में सपरिषद् गवर्नर की स्थायी आज्ञाओं से हुई किन्तु इनमें परिषदों बाद में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती थी । इन नियमों के अनुसार स्थायी समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई ताकि सदस्यगण सरकार की वास्तविक समस्याओं के सम्पर्क में आ सकें । उनका काम केवल परामर्श देने का था और उनका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षणात्मक था । इनमें विद्यमान समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी जो नये व्यय के सारे प्रस्तावों पर परामर्श देती थी । उसके विलुप्त रूप में सार्वजनिक सेवा समिति थी जिसकी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्ति होती थी । नियमों में उसकी रचना और उसके कार्यों को निश्चित कर दिया गया था । अध्यक्ष सहित उसके कुल सदस्यों की संख्या १२ थी, अर्धरात्रि स्वयं वित्त सदस्य होता था । इस समिति के दो तिहाई सदस्य, विधान-परिषद् के गैरसरकारी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनुसार चुने हुए होते थे । समिति को विनियोग के खातों की परीक्षा करनी होती थी, इस बात को देखना होता था कि घोट किए हुए धन का उपयोग विधान-मंडल की इच्छानुसार हो किना गया था और उस अपनी जांच की रिपोर्ट परिषद् को देनी होती थी । इस प्रकार विधान मंडल यह जान सकता था कि उसके निर्णयों का उचित रूप में पालन किया गया अथवा नहीं ।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, १९१९, ने प्रान्तीय क्षेत्र में उपयुक्त परिवर्तन किए । उनके द्वारा उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला कदम उठाया गया ।



स्वयं ऐक्ट के अन्दर ही इस बात की व्यवस्था की गई थी कि दस वर्ष बाद एक प्रविधानीय कमीशन नियुक्त किया जाय और उसके सदस्यों को सम्म्राट्<sup>१</sup> तथा पार्लियामेंट के दोनों भवनों के अनुमोदन से छाँटा जाय। इस कमीशन को ब्रिटिश भारत की व्यवहृत शासन व्यवस्था, शिक्षा की वृद्धि और प्रतिनिधि समस्याओं के विकास और अन्य सम्बन्धित विषयों की जाँच करनी थी और निम्नलिखित बातों पर रिपोर्ट देनी थी—उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को मान्यता देना वांछनीय है अथवा नहीं, यदि वांछनीय है तो किस हद तक मान्यता दी जाय, तत्कालीन उत्तरदायी शासन को विनष्टा विसृत, संशोधित अथवा परिमित किया जाय, और दूसरे विधायिका भवनों की स्थापना करना वांछनीय है अथवा नहीं। इन बातों के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत और प्रान्तों से सम्बन्धित अन्य बातों का सम्म्राट् द्वारा कमीशन को उसके विचारार्थ सौंपा जा सकता था।<sup>२</sup>

## ९

यद्यपि मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केन्द्रीय शासन का स्वरूप बदलने का अथवा केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था आरम्भ करने का कोई उद्देश्य नहीं था, तथापि केन्द्रीय व्यवस्था को भारत में अथवा इंग्लैंड में यथावत् छोड़ना संभव नहीं था। अतः मॉण्टफोर्ड सुधारों ने भारत और इंग्लैंड दोनों ही स्थानों में सरकारी ढाँचे में कुछ परिवर्तन किए और भारतीय लोक सेवाओं तथा देशी राज्यों के साथ सम्बन्ध की समस्या पर भी प्रकाश डाला।

२० अगस्त १९१७ की घोषणा में यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति, “शासन के प्रत्येक विभाग में अधिवाधिन भारतीयों को साथ लेने की है।” किन्तु मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दी। “किसी सेवा में भ्रान्तक ही नये अथ की ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए कि उसका सारा स्वरूप ही एकदम बदल जाय” और प्रतिवर्ष भर्ती किये जाने वाले भारतीयों की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनको “उस सेवा के पुराने सदस्य उचित रूप से शिक्षित

१ ऐक्ट में अथवा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे भारत मन्त्री पर कोई ऐसी रोक हो कि कमीशन के लिए पार्लियामेंट के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश न की जाय।

२ Clause 41 of the Act. India in 1919, page 513. इस बात में सन्देह है कि देशी राज्यों से संबंधित प्रश्नों को उस कमीशन को सौंपना वैध था। १९१९ के ऐक्ट के अनुसार केवल ब्रिटिश भारत से सम्बन्धित विषय ही उसे सौंपे जा सकते थे।

वर सक और उस सेवा की भावना से प्रेरित वर सक।<sup>१</sup> अतः यह प्रस्ताव किया गया कि जिन सेवाओं के लिए इंग्लैंड में भर्ती होनी थी उन सेवाओं के लिए भारत में भर्ती करने के निमित्त एक नियत अनुपात निश्चित कर दिया जाय। उदाहरण के लिए इंडियन मोबिल सर्विस के ३३ प्रतिशत पदां के लिए भारत में भर्ती की जाय।<sup>२</sup> विभिन्न लोकसेवाओं में भारतायकरण की गति प्रगति बढ़ाई जानी थी।

सन् १९१९ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने स-परिषद् भारत-मंत्री को प्राधिकार दिया कि वह इंडियन सिविल सर्विस<sup>३</sup> में भारत के अधिवासी लोगों की नियुक्ति के नियम बनाव और साथ ही भारत की सिविल नौकरियों के वर्गीकरण के लिए उनकी भर्ती की प्रक्रिया के लिए उनके बतन, भत्ता व्यवहार और अर्थात्स के विनियमन के लिए नियम बनाव।<sup>४</sup> ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर भारत-मंत्री नियम आदि बनाने के अधिकार को स-परिषद् गवर्नर जनरल को अथवा प्रान्तीय सरकार आदि को सौंप सकता था। १९१९ के एक्ट ने स-परिषद् भारत-मंत्री द्वारा एक लाक-मवा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की। इस आयोग में अ-पक्ष-अहित पाँच से अधिक सदस्य नहों होंगे और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पाँच वर्ष का था किन्तु उसकी दुबारा नियुक्ति भी हो सकती थी। यह लोक सेवा आयोग भारत में लोक-सेवाओं की भर्ती और नियमन के संबंध में वह सारे काम करेगा जो स-परिषद् भारत-मंत्री द्वारा नियमों के अनुसार उसे सौंपे जायगा।<sup>५</sup>

स-परिषद् भारत-मंत्री द्वारा निमित्त नियमों के अनुसार भारत में सम-वार्तिक प्रतियोगितापूर्ण परीक्षाओं की व्यवस्था कुछ ही वर्षों में अपनाई गई, साथ ही विभिन्न समुदायों और प्रान्तों का आत्म-सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्दान की व्यवस्था भी हुई। किन्तु सिविल सेवाओं से संबंधित सारे प्रश्नों को जिसमें प्रांतीय सदस्यों के बतन बढ़ाने का प्रश्न भी सम्मिलित था, सन् १९२२ में एक राजकीय उन्माद की सीमा पार कर गया। इस उन्माद के अन्तर्गत यह भी था।

मास्टकोड रिपोर्ट के संक्षेप रूप में भारत-सेवाओं के पूर्णतः सदस्यों के

१ The Report on Indian Constitutional Reforms 1919 page 200

२ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ २०१

३ Section 37 (1) of the Act India in 1919, page 252

४ Section 36 (2) of the Act, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ २५१

५ Section 38 (2) of the Act, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५२

सबध में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी और केवल उनके वेतन तथा भत्त में वृद्धि के लिए और वैधानिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण उनकी क्षतिपूर्ति के लिए ही सिकारित नहीं की थी वरन् नए विधान में उनको प्रबल संरक्षण देने की व्यवस्था भी की थी। इसी उद्देश्य से १९१९ के ऐक्ट में तीन महत्वपूर्ण धाराओं को स्थान दिया गया : पहली धारा में उनको जो संरक्षण दिया गया था उसके अनुसार मन्त्रिगण उनको पदभ्यूत नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर मन्त्रियों के लिए उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बनाये रखने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। दूसरी धारा के अनुसार इन सदस्यों को मन्त्रियों का अतिक्रमण करके गवर्नर से सिकायत करने का अधिकार दिया गया। तीसरी धारा के अनुसार उनके वेतन, भत्ते आदि का पूर्ण संरक्षण किया गया। यदि इन संरक्षणों के बावजूद, सिविल सेवाओं के कुछ सदस्य "ऐसा अनुभव करें कि वह द्वैध प्रणाली के अन्तर्गत उपयुक्त रूप से काम नहीं कर सकते" तो संयुक्त प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया कि सम्राट् सरकार, यदि उसके लिए यह शक्य हो, तो उन सदस्यों को अन्यत्र समान पद प्रदान करे अथवा उनको आनुपातिक पेंशन पर निवृत्त<sup>१</sup> कर दिया जाय।

१०

मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट का तीसरा सूत्र यह था—

"भारत सरकार, पार्लियामेंट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, और इस उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, प्रान्तों में आरम्भ होने वाली नई व्यवस्था के अनुभव-काल में, उस (भारत सरकार) का मौलिक विषयो में अधिकार निर्विवाद है। इस अवधि में भारतीय विधान परिषद्, विस्तृत और अधिक प्रतिनिधिपूर्ण की जानी चाहिए और सरकार को प्रभावित करने के उसके अवसर बढ़ाए जाने चाहिए।"<sup>२</sup>

इस नीति को गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट, १९१९ के भाग २ में और इस सबध में भारत सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों में रूप दिया गया। दो भवनों के एक नए विधान मंडल की स्थापना की गई और वाइसरॉय की कार्यकारिणी-परिषद् की रचना में थोड़ा-सा संशोधन किया गया। कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता के सबध में अधिवर्तमान सीमा के प्रतिबन्ध को दूर कर दिया गया,<sup>३</sup>

१. Mukherjee: The Indian Constitution; part II, page 526.
२. The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 124.
३. Clause 28 (1) of the Act, India in 1919, page 248.

भारतीय उच्च न्यायालया के १० वर्ष से अधिक की स्थिति के पक्षीत उत्तरे सदस्य नियुक्त किए जा सकते थे<sup>१</sup> और भारतीय विधान-परिषद् के सदस्य में से परिषद्-वायवाह नियुक्त करने की व्यवस्था की गई।<sup>२</sup> कार्यकारिणी परिषद् के तीन सदस्य के लिए पूर्ववत् मर्यादा को अहता आवश्यक थी—अर्थात् वे तीन भारत में कम से कम दस वर्ष तक सभा के सदस्य रहे हों। कार्यकारिणी परिषद् में भारतीयों की नियुक्ति करने के संबंध में कोई प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की गई थी किन्तु संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर तीन भारतीयों की परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया।

नए केन्द्रीय विधान मंडल में दो नए लोग थे—राज्य-परिषद् और भारतीय विधान सभा। राज्य परिषद् स्थापित करने के लिए माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने मुख्यतः इस उद्देश्य से सिफारिश की थी कि यदि किसी अनिवार्य विधान की अधिक लोकाधिमत प्रथम भवन स्वीकार न करे तो भारत सरकार उसका राज्य-परिषद् से पारण करवा सके। अतः उसने इस बात का प्रस्ताव किया कि राज्य-परिषद् में कुल ५० सदस्य हों जिनमें से आठ, सरकारी व्यक्ति हों, ४ नाम-निर्देशित गैर सरकारी व्यक्ति हों और शेष २१ निर्वाचित व्यक्ति हों—जिनमें से १५ सदस्य प्रान्तीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों और ६ सदस्य जमादारों, मुसलमानों और वाणिज्य मंडलों द्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित हों। रिपोर्ट के लेखक ने कहा “राज्य-परिषद्, सारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भारत का सर्वोच्च विधायिका सत्ता होगी और उसे सारे भारतीय विधानों की दोहराने का अधिकार प्राप्त होगा। अतः हम उसकी ओर देश के सर्वोत्तम उपलब्ध व्यवस्था को आकर्षित करना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि वह विकसित हो और उसमें वे सब विद्यमान हों जो दोहराने वाले भवना के लिए आवश्यक और उच्चतम समझी जाती हैं।”<sup>३</sup> संयुक्त प्रवर समिति ने इस बात की आवश्यकता अथवा वांछनीय नहीं समझी कि “राज्य-परिषद् को सरकारी विधान के लिए उपकरण बनाया जाय।” समिति ने इस बात की सिफारिश की कि “आरम्भ में ही उसकी वास्तविक द्वितीय भवन के रूप में रचना की जाय।”<sup>४</sup> मताधिकार कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया था कि राज्य-परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों का वही मतदाता निर्वाचन करें जो विधान सभा के लिए निर्वाचन करते हैं, किन्तु

१ Clause 28 (2) of the Act. India in 1919, page 249.

२ Clause 28 (1) of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४९.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७९.

४ Mukherjee The Indian Constitution, Part II, page 520.

संयुक्त प्रवर समिति ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और उसने भारत सरकार को यह सिफारिश देने की सिफारिश की कि वह राज्य परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र बनावे।

भारत सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार राज्य-परिषद् में ६० सदस्य होने थे जिनमें से एक सदस्य की गवर्नर-जनरल द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जानी थी। सेप ५९ सदस्यों में से, २५ नाम निर्देशित होने थे—१९ सरकारी और ६ गैर-सरकारी, ३४ निर्वाचित होने थे—२० साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, ३ यूरोपीय वाणिज्य-मंडल से और ११ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से (१० मुस्लिम क्षेत्र से और १ सिक्ख क्षेत्र से)। राज्य-परिषद् को पुनरीक्षक भवन के रूप में काम करना था और उसे विधान के सबंध में प्रथम भवन के बराबर अधिकार प्राप्त थे।

प्रथम भवन का नाम था भारतीय विधान-सभा और इसमें—सभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त—१४३ सदस्य होने थे। अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा पहले चार वर्षों के लिए की जानी थी। अन्य सदस्यों में से, ६० नाम-निर्देशित होने थे—२५ सरकारी और १५ गैर-सरकारी, और १०३ निर्वाचित होने थे—५१ साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से, ३२ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से (मुसलमानों द्वारा ३० और सिक्खों द्वारा २), और २० विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से (जमींदारों द्वारा ७, यूरोपियनों द्वारा ९ और भारतीय वाणिज्य वर्ग द्वारा ४)। मताधिकार कमेटी ने भारतीय विधान-सभा के लिए परोक्ष निर्वाचन-व्यवस्था की सिफारिश की थी, क्योंकि उसके मतानुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था वांछनीय होते हुए भी अव्यवहार्य थी—प्रान्तीय मताधिकार के आधार पर बने हुए निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े और बोलसल होंगे, सकीर्ण मताधिकार “अयुक्त” और “राजनैतिक दृष्टि से अवांछनीय” होगा।<sup>१</sup> संयुक्त प्रवर समिति ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और इस बात की सिफारिश की कि भारत सरकार से इस सबंध में नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाय।

इस प्रकार केन्द्रीय विधान-मंडल के लिए निर्वाचन-व्यवस्था, मताधिकार और विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना के प्रश्न, भारत सरकार के निर्णय के लिए छोड़ दिये गए थे। भारत सरकार ने केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों भवनों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के पक्ष में निर्णय किया। राज्य परिषद् के निमित्त उन लोगों को मताधिकार दिया गया जिनकी आय-कर से निर्धारित वापिक जाय १०००० रुपये से कम न हो। (विभिन्न स्थानों अथवा समुदायों में यह

विधियों पर अथवा संयुक्त राज्य के विधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो कोई अधिनियम नहीं था।

य प्रतिबंध ब्रिटिश पार्लियामेण्ट की प्रभुता यथावत बनाय रखने के लिए लगाए गए थे। इनके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद को श्रेष्ठता और सत्ता बनाय रखने के लिए नेट्रोम विधान मंडल पर और बहुत स महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए थे। सबसे पहला प्रतिबंध यह था कि निम्नलिखित बातों पर प्रभाव डालने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर-जनरल ही पूरा स्वीकृति लेना आवश्यक था—

(१) सांख्यिक ऋण अथवा भारतीय सांख्यिक राजस्व अथवा भारतीय राजस्व पर किसी परिवर्धन का भार अथवा

(२) भारत को ब्रिटिश प्रजा के किसी वर्ग के घम उसकी रीति अथवा परंपरा अथवा

(३) सम्राट की जल स्थल और वायु सेना के किसी भाग का अनुशासन, अथवा

(४) सरकार का विदेशी नौसेना अथवा रियासतों से संबंध, अथवा [सा कोई प्रस्ताव—

(अ) जिससे ऐसे प्रान्तीय विषय अथवा ऐसे किसी प्रान्तीय विषय किसी भाग का विनियमन होता हो जो इस एक्ट के अन्तर्गत बन हुए नियमों के अनुसार भारतीय विधान-मंडल के विधान क्षेत्र के अधीन न हो, अथवा

(ब) जिससे प्रान्तीय विधान-मंडल का कोई एक्ट रद्द या संशोधित होता हो, अथवा

(स) जिससे गवर्नर-जनरल द्वारा बनाया हुआ कोई एक्ट अथवा अध्यादेश रद्द अथवा संशोधित होता हो।<sup>१</sup>

दूसरा प्रतिबंध यह था कि यदि गवर्नर-जनरल के मत से किसी विषयक अथवा उसका किसी भाग से ब्रिटिश भारत अथवा उसका किसी भाग की शान्ति अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो<sup>२</sup> तो वह उस विषय या उसके संशोधित भाग पर चाह वह किसी भी बदन में और किसी भी स्थिति में क्या न हो उर्दा करने का सबंध में रोक लगा सकता था।

१ Section 67 clause (2) of the Consolidated Act See Mukherjee The Indian Constitution, part I, pages, 281 and 282

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ २८२

केन्द्रीय विधान-मंडल की सत्ता पर सीसरा प्रतिबन्ध यह था कि यदि गवर्नर-जनरल के मत से 'ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति सुरक्षा अथवा उसके हित के लिए' <sup>१</sup> किसी विधि का बनाना अनिवार्य है और यदि दोनों भवनो ने उसे बनाने से इन्कार कर दिया है तो उसे प्राधिकार था कि वह उस विधि का विधान कर दे अर्थात् प्रचलित संसदीय मंडल में उसका निबन्धन कर दे। ऐसे प्रत्येक ऐक्ट के लिए संसद् की स्वीकृति लेने का नियम था किंतु 'इससे पहले यह आवश्यक था कि उसकी प्रतियाँ पार्लियामेंट के प्रत्येक भवन के समक्ष अधिवेशन के कम-से-कम आठ दिनों तक रखी जावें।' <sup>२</sup> यह व्यवस्था संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश से, मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट की उस मौलिक योजना के स्वान पर अपनाई गई थी जिसके अनुसार मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रस्तावित द्वितीय भवन को अनिवार्य विधान बनाना था। समिति की दृष्टि में यह उचित नहीं था कि गवर्नर-जनरल अपने दायित्व को छिपावे और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित राज्य-परिषद् के सरकारी गुट से इसका काम निकाले। इस सम्बन्ध में पहले भी ध्यान आकषिप्त किया जा चुका है।

केन्द्रीय विधान-मंडल के अधिकारों पर चौथा प्रतिबन्ध यह था कि गवर्नर-जनरल को आपातकाल में "ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति और उसके सुशासन के लिए अभ्यादेश" <sup>३</sup> बनाने का अधिकार था। गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए अभ्यादेश की उतनी ही विधिक मान्यता होनी थी जितनी कि भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाये हुए किसी ऐक्ट की। कोई भी अभ्यादेश छे महीने से अधिक के लिए जारी नहीं किया जा सकता था।<sup>४</sup>

पाँचवाँ प्रतिबन्ध यह था कि गवर्नर-जनरल को केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों भवनो द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पहले, फिर विचार करने के लिए मंडल के पास वापिस भेज देने का अधिकार था।

अन्तिम बात यह थी कि भारतीय विधान मंडल को किसी भी विधि के विधायन के लिये गवर्नर-जनरल की स्वीकृति अनिवार्य थी। उसे अधिकार था कि उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे अथवा उसे संसद् की कृपा के त्रिए सुरक्षित कर दे। संसद् को भारतीय विधान-मंडल अथवा गवर्नर जनरल द्वारा बनाय हुए किसी भी ऐक्ट को अस्वीकार कर देने का अधिकार था। संयुक्त प्रवर समिति ने

१. Section 37 B of the Consolidated Act Mukherjee  
Indian Constitution, Part I, page 293

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९८, २९९

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९९

इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गवर्नर-जनरल का निषेधाधिकार वास्तविक था और उत व्यवहार में लान का उद्देश्य था ।

गवर्नर-जनरल की अनुमति के लिए किसी विधायक को उसके पास भवने से पहले यह आवश्यक था कि विधान मंडल के दोनों भवना ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी हो। यदि किसी विधायक का एक भवन न स्वीकार कर लिया है किंतु उस भवन के स्वीकार कर लेने के छे महीने के अन्दर ही उस विधायक को उसी रूप में अथवा संशोधना के बाद (जो पहले भवन को मान्य हो) दूसरे भवन से स्वीकृति नहीं मिलती तो गवर्नर-जनरल स्वविवेक से उस विधायक के निर्णय को दोनों भवना के संयुक्त अधिवेशन का सौंप सकता था ।<sup>१</sup> इस प्रकार दोनों भवना के गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी ।

दोनों भवना के सदस्या को निश्चित नियमों के अनुसार प्रश्न पूछने का, अनुप्रश्न प्रश्न पूछने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, और विधान के प्रश्न प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था । सदस्या को भवना में भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार भी दिया गया था ।

गवर्नर-ऑफ इंडिया एक्ट, १९१९ के अनुसार, गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद् का वित्तीय विवरण, भारतीय विधान-मंडल के दोनों भवना में प्रस्तुत किया जाना था । सरकार को—केवल गवर्नर-जनरल की ही सिफारिश पर—अनुदानों की माँग के रूप में राजस्व-विनियाम के प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे । व्यय के निम्न-लिखित शीर्षकों को छोड़ कर, राश सब प्रस्तावों पर भारतीय विधान सभा को अपना मत प्रकट करने का अधिकार था ।

- (१) ऋणा की व्याज और निःशेष निधि सम्बन्धी परिव्यय, और
- (२) ऐसा व्यय जिनका परिमाण किसी विधि द्वारा निश्चित हो, और
- (३) सम्राट् द्वारा अथवा उसके अनुमतिन न अथवा मपरिषद् भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त किये हुए लागा के वन और निवृत्ति-वतन और,
- (४) मुख्य कमिश्नरों और न्यायिक कमिश्नरों के वेतन, और
- (५) ऐसा व्यय जिन की मपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार निम्न-

लिखित वर्गों में गणना हो—

- (अ) धर्म (चर्च) सम्बन्धी,
- (ब) राजनैतिक,
- (म) सुरक्षा सम्बन्धी ।<sup>१</sup>

१. Section 25 of the Act of 1919, "India in 1919" page 249.



दोनों में से किसी भवन में बिना गवर्नर जनरल के निर्देश के उपयुक्त मरदा पर तो चर्चा भी नहीं की जा सकती थी।

व्यय की अन्य मदों पर विधान सभा अपना मत प्रकट करती थी—वह किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुल मांग को घटाकर किसी मांग के परिमाण को घटा सकती थी किंतु गवर्नर जनरल को, यह घोषित करने पर कि विधान सभा द्वारा अस्वीकृत मांग उसके उत्तरदायित्व के प्राप्ति के लिए आवश्यक है उस मांग के परिमाण को यथावत रखने का अधिकार था। आयातकाल में ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल को जितना परिमाण बहु ठीक समझ उतने के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागों का प्राधिकृत करने का अधिकार था।<sup>१</sup>

इस प्रकार भारतीय विधान मंडल केवल एक प्रभुता रहित विधायक निकाय ही नहीं था बरन वह कार्यकारिणी के समक्ष आवत भी था। प्रशासनीय विधानीय एवं वित्तीय सभी क्षेत्रों में संपरिपद गवर्नर-जनरल का पूरा अधिकार था। कार्यकारिणी विधान मंडल स्वतंत्र हो नहीं थी बरन इसको लगभग सभी विषयों में उसका उत्प्रेषण करने का अधिकार था। तथापि कुछ सदस्यों को स्थायी समितियों के द्वारा कार्यकारिणी विभागों के संचालन और प्रशासनीय समस्याओं के निवृत्त-सम्पर्क में आन का अवसर मिल जाता था। सभा की स्थायी समितियों में वित्त समिति और सावजनिक सेवा समिति अधिक महत्वपूर्ण थी। सभा के सदस्यों को भारत सरकार की वास्तविकता प्रकट करने का भी अवसर था—यह जतान का कि सरकार देश के लोगों की इच्छाओं और उनके हितों के विरुद्ध काम कर रही थी। भारतीय विधान सभा और चाहे जो कुछ करने में समर्थ या असमर्थ हो किंतु उसे भारत सरकार का असली स्वरूप प्रकट करने का अधिकार अवश्य था।

१२

१९१९ के एक्ट ने भारत की गृह सरकार में भी कुछ परिवर्तन किये। सब से पहलें बात तो यह हुई कि प्रान्तों को आर्थिक उत्तरदायित्व देने के कारण संपरिपद भारत मंत्री को नियंत्रण कम करने का अधिकार दिया गया। सुरक्षित विभागों के संबंध में अथवा भारत सरकार के संबंध में प्रविधानीय रूप से नियंत्रण कम करना सम्भव नहीं था क्योंकि इनके लिए पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व था। किंतु समयन प्रकार समिति ने ऐसी परम्परा डालने का सुझाव दिया था कि असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसे विरुद्ध रूप से भारतीय विषयों में नियंत्रण कम करने का अधिकार और भारतीय विधान मंडल सहमत हो भारत मंत्री हस्तक्षेप न करे। यह बात आर्थिक विषयों के संबंध में विधि रूप से आवश्यक

१ Section 25 of the Act of 1919 India in 1919 page 249

अनुभव की गई क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति इस बात का सदह दूर करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थी कि भारत की आर्थिक नीति ब्रिटन के व्यापार के हित में व्हाइट हाल से निर्दिष्ट होती है। यही कारण है कि इस दृष्टि से व्यवहृत नीति आर्थिक स्वायत्तता परंपरा के नाम से पुकारी जाती थी।

१९१९ के एक्ट ने यह सरकार के संबंध में दूसरा परिवर्तन भारत-परिषद् के संविधान में किया। भारतीय जनमत ने भारत-परिषद् का तोड़ने की मांग की थी और क्रिज्वे कमटी का मत बराबर बढ़ा हुआ था। किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-परिषद् को बनाए रखने की सिफारिश की जिस १९१९ के एक्ट ने स्वीकार किया और उसमें कुछ साधारण संशोधनों के अतिरिक्त भारत-परिषद् को पूर्ववत् बनाए रखा। परिषद् की सदस्यता की अधिकतम सीमा को १४ में घटाकर १२ कर दिया गया और न्यूनतम सीमा को १० से घटाकर ८ कर दिया गया। अविष्य में तो सदस्यों के स्थान पर परिषद् के आधे सदस्यों के लिए हा सवा की अहता आवश्यक थी। नये सदस्यों का नाम बाल सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया। सदस्यों के लिए १२०० पौंड का वार्षिक वेतन निर्दिष्ट कर दिया गया किन्तु भारतीय सदस्यों को इस वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंड का वार्षिक भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई। परिषद् की मीटिंग कम-से-कम प्रति सप्ताह के स्थान पर प्रतिमास होती थी। गण-भूति के संबंध में प्रविधानाय व्यवस्था नहीं की गई, उसको सच्चा स्वयं भारत मंत्री का निर्दिष्ट करने की थी। वाय सचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार स-परिषद् भारत मंत्री का दिया गया। इस संबंध में इस बात की ओर ध्यान उचित होगा कि संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-परिषद् की उपयोगिता बढ़ाने के लिए विभाग व्यवस्था अपनाए की सिफारिश की थी।

तीसरी बात यह थी कि माण्टफाड मुद्दारा ने स-परिषद् भारत मंत्री के अधिकरण कार्यों को प्रासनीय एवं राजनतिक कार्यों से पृथक् करने का व्यवस्था की थी। क्रिज्वे कमटी का यह मुद्दा था कि स-परिषद् भारत मंत्री के अधिकरण-वाय भारत के हाई कमिश्नर का (जिसको इसा उद्देश्य में देने में नियुक्ति की जावे) सोप दिय जान चाहिए। एक्ट ने सम्राट् का अधिकार दिया कि संयुक्त राज्य में भारत के हाई कमिश्नर का नियुक्ति के लिए उसके वेतन विनि यतन अधिकार वत्तव्य और उसकी नवा का गतों के लिए परिषद् आदेश द्वारा व्यवस्था कर और उसका व नये अधिकरण वाय सोप दन की व्यवस्था कर जा पहल सपरिषद् भारत मंत्री द्वारा दिय जान । साथ ही व नों

निश्चित कर दें जिनके अनुसार उसे स-परिषद् गवर्नर-जनरल अथवा प्रान्तीय सरकार की ओर से नाम करना होगा।"<sup>१</sup>

सन् १९२० में भारत के हाई कमिश्नर<sup>२</sup> की नियुक्ति की गई और उसको पण्य विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग और भारतीय व्यापारिक कमिश्नर के कार्यों के निरोक्षण और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कमरा इंडिया ऑफिस के सारे अधिकरण-कार्यों को लन्दन के भारतीय हाई कमिश्नर को सौंपने का उद्देश्य था।

संयुक्त प्रवर समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि इंडिया आफिस के सारे राजनैतिक और नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के व्यय का भार (इसमें भारत-मंत्री का वेतन भी सम्मिलित था) ब्रिटिश राजस्व पर होना चाहिए और केवल अधिकरण-कार्यों के व्यय का भार भारतीय राजस्व पर होना चाहिए। अतः १९१९ के एक्ट ने व्यवस्था की कि 'भारत मंत्री का वेतन उसके उपमंत्रियों का वेतन और उसके विभाग का अन्य व्यय भारतीय राजस्व से न दिया जाकर, पार्लियामेण्ट से दिया जावे और यह व्यय इसी प्रकार दिया जाएगा।'<sup>३</sup> इस धारा के अनुसार इंडिया ऑफिस ने नियंत्रण सबधी और राजनैतिक कामों के व्यय का भार साध ही भारत मंत्री और उसके उपमंत्रियों के वेतन का भार ब्रिटिश राजस्व पर डाल दिया गया।

१३

इस प्रकार १९१९ के सुधार केवल प्रान्तीय स्तर तक ही सीमित नहीं थे उन्होंने केन्द्रीय सरकार और गृह सरकार पर भी प्रभाव डाला। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारतीय नरेशों को भी अपनी परिधि में लिया। नरेन्द्र मडल (बम्बर आँब प्रिसेज) और उसकी स्थायी समिति की स्थापना द्वारा ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सहयोग-व्यवस्था को सुधारन का प्रयत्न किया गया। ब्रिटिश भारत की सरकारों और देशी राज्यों के आपसी झगड़ों को और देशी नरेशों के सबध में कदाचार ने आक्षेपों को जांच कमीशन के सिपुर्द करने की व्यवस्था भी की गई।

मि मॉण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का यह मत था कि ब्रिटिश भारत के वैधानिक परिवर्तनों से देशी राज्यों पर भी प्रभाव पड़गा और इसी कारण उन्होंने

१ Section 35 of the Act, India in 1919, page 251.

२ सर विलियम मेयर को सबसे पहला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। सर मेयर कुछ ही समय पहले भारत सरकार के वित्त-सदस्य के पद से निवृत्त हुए थे।

३ Section 30 of the Act, India in 1919, page 249.

देशी राज्या सः सवध क प्रश्न का परीक्षण किया।<sup>१</sup> उन्होंने देश नरेशों को इस बात का आश्वासन देने की आवश्यकता अनुभव की कि ब्रिटिश भारत में चाहे जो परिवर्तन हो किन्तु सधिया सनदा और व्यवहार के अनुसार उह जो अधिकार प्रतिष्ठा और विभागाधिकार प्राप्त ह उनम किसी प्रकार की कमी नही होगी।<sup>२</sup> वस्तुतः एम किसी आश्वासन की आवश्यकता नही थी क्योंकि माण्टफोर्ड रिपोर्ट न जिन परिवर्तना की सिफारिश की थी उनसे देशी राज्या के साथ सवध के प्रश्न पर कोई प्रभाव नही पड़ता था। किन्तु कुछ देशी नरेश इस अवसर से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुधारन के लिए और अपन परिवारों और अपनी असमर्थताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थ।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट न कहा गया था— देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रही ह। आरम्भ में देशी राज्यों को अपनी परिधि से बाहर हस्तक्षेप करने का अधिकार नही था, उसके बाद लाड हेस्टिंग्स की नीति के अनुसार देशी राज्य अधस्थ और विक्षिप्त हो गए। इस नीति का स्थान उस वर्तमान नीति न किया जिसके अनुसार देशी राज्या का सर्वोच्च सत्ता स सहयोग और एक्य का सवध ह।<sup>३</sup> किन्तु इस सवध में इस बात की ओर ध्यान दिखाना आवश्यक ह कि देशी राज्या और ब्रिटिश सरकार में जो सहयोग था, वह बराबरी की हतिमत से नही था। लाड वर्निंग न समय स लार्ड रीडिंग न समय तक भारत की ब्रिटिश सरकार न देशी नरेशों की अवस्थता और अपनी भ्रष्टता पर बराबर जोर दिया—यहाँ तक कहा गया कि उसको प्रभुता का शब्दा द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहा गया जा सकता, उस पर कोई प्रतिबंध नहा था, और ब्रिटिश सत्ता को सधिया, सनदा आदि स स्वतन्त्र रूप स, देशी राज्या व सभा विषया में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार था। अस्तु, माण्टफोर्ड रिपोर्ट में उनकी स्थिति इस प्रकार व्यक्त की गई — देशी राज्या का बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त ह, सर्वोच्च सत्ता उनकी ओर से देशी और विदेशी राज्या के प्रति काम करती ह और जब उनका प्रदशा का आन्तरिक शान्ति पर कोई बड़ा सबट होता ह तो हस्तक्षेप करता ह। दूसरी ओर विदेशी सरकारों के साथ उनका वही सवध ह जो सर्वोच्च सत्ता के ह, सुरक्षा में उनका समान दावित्व ह, और उन पर अपन प्रदशा की समृद्धि और उनके

१ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 193

२ उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १९६।

३ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 190

मुद्रासन का दायित्व है।”<sup>१</sup>

पिछले सत्तर वर्षों में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के सम्पर्क-बिन्दु काफी बढ़ गए थे और बहुत से कामों के लिए भारत के ये दोनों भाग लगभग एक इकाई बन गए थे। मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के अनुसार—‘भारत के दोनों भागों के परस्पर घुलमिल जाने की दिशा में अब प्रक्रिया काम करती हुई दिखाई देती है। अकाल के अवसरा पर हमने देशी राज्यों की सहायता की है, हमने उन्हें ब्रिटिश भारत के अनुभवों अधिकांशों की सेवाएँ निम्नलिखित कार्यों में प्रदान की हैं—उनकी मालमुजदारी अथवा वित्तीय व्यवस्था को दोहराने अथवा उसका निरीक्षण करने के लिए अथवा उनके प्रदेशों में कृषि और सिंचाई की दशा सुधारने के लिए। बहुत से देशी राज्यों ने दीवानों और फौजदारी पद्धति के स्वयं में हमारी सहायता को अपनाया है। कुछ देशी राज्यों ने हमारी शिक्षण-व्यवस्था का अनुकरण किया है और उसे आगे भी बढ़ाया है। पुलिस और न्याय के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। हमारी रेलवे और तार-व्यवस्थाएँ बहुत से देशी राज्यों में भी काम करती हैं। भारतीय सीमा शुल्क का सभी देशी राज्यों से सम्बन्ध है जिनमें वे राज्य भी सम्मिलित हैं जिनके अपने निजी बन्दरगाह हैं।”<sup>२</sup> इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के दोनों भाग बहुत से विषयों में एक दूसरे के बहुत निकट आ गये थे। किन्तु देशी राज्यों की राजनैतिक जागृति, ब्रिटिश भारत की अपेक्षा कहीं कम थी। विभिन्न देशी राज्यों में भी यह जागृति एक-सी नहीं थी। अतः यह कहा गया, ‘देशी राज्य विकास की विभिन्न सीढ़ियों पर हैं। कहीं सामान्य गति है, कहीं कुछ अधिक उन्नति हो गई है, और कुछ राज्यों में प्रतिनिधि सभाओं का प्रारम्भ हो गया है। इन सभी राज्यों की, जिनमें सबसे जगदा उन्नत राज्य भी सम्मिलित हैं, यह एक विशेषता है कि उनमें से प्रत्येक में उसके नरेश का व्यक्तिगत राज्य है और उसका विधान, न्याय और शासन पर नियन्त्रण है।’<sup>३</sup>

अस्तु देशी राज्यों की स्थिति क्रमशः सुधरती रही। विद्रोह के बाद के वर्षों में अंगरेजों को देशी नरेशों पर अविश्वास था और उन्हें इस बात का डर था कि अवसर मिलने पर वे सब अंगरेजों के विरुद्ध एक हो जाएँगे। अतः उस समय ब्रिटिश नीति देशी राज्यों को विच्छिन्न रखने की थी और देशी नरेशों के परस्पर मिलने के अवसर यथासंभव सीमित कर दिये गये थे। किन्तु

१. लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिज और लॉर्ड रीडिंग ने देशी राज्यों की अधस्त स्थिति के स्वयं में विशेष रूप से जोर दिया था।

२. The Report on the Indian Constitutional Reforms 1918, page 191.

ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने पर, देशी नरेशों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ; और उन का समर्थन प्राप्त करने की ओर देश के शासन में उनको साथ लेने की नीति का प्रमत्त विकास हुआ। ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों की मांगों के विरुद्ध देशी नरेशों की दृढ़ दीवार का उपयोग करने की सम्भावनाओं की ओर सब से पहले लॉर्ड लिटन का ध्यान आकर्षित हुआ था। इसी कारण उन्होंने बड़े देशी नरेशों की एक भारतीय प्रिन्सीपल कौंसिल बनाने की सिफारिश की थी। जैसा कि अन्वय<sup>१</sup> कहा जा चुका है। उस प्रस्ताव का केवल इतना ही फल हुआ कि देशी नरेशों के नाम के साथ "साम्राज्यी की परिषद् के सदस्य" की सोसल्टी उपाधि जोड़ दी गई। लॉर्ड कर्जन ने फिर उसी विचार को उठाया और "देशी नरेशों की परिषद्" की स्थापना करने का प्रस्ताव किया। किन्तु ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों में, राष्ट्रीय शक्तियों से सकट का सामना करने के उद्देश्य से परस्पर सहयोग के विचार को सक्रिय रूप देने का काम लॉर्ड मिटो ने किया। जैसा कि नरेन्द्र-मंडल के विरोध संगठन-विभाग में 'दि ब्रिटिश प्राउन एण्ड दि इंडियन स्टेट्स' में कहा है :—“ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि से लॉर्ड मिटो धबरा गए थे.....और उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध देशी नरेशों के संगठन में एक दृढ़ दीवार दिखाई दी।” उन्होंने बताया कि “इस सारी व्यवस्था की केन्द्रीय बात यह है कि साम्राज्यीय सरकार और देशी राज्यों के हित एक हैं; अतः उनके प्रदेशों के आन्तरिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिये।” अस्तु, “सारे भारत—प्रान्तों और साथ ही राज्यों—की भलाई से संबंधित विषयों पर देशी नरेशों से परामर्श करने की परंपरा भारत की गई।”<sup>२</sup> लॉर्ड मिटो ने आरम्भ में साम्राज्यीय मन्त्रणा-परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव किया और बाद में देशी शासकों की साम्राज्यीय परिषद् बनाने का सुझाव दिया किन्तु दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को रूप नहीं दिया गया। लॉर्ड हार्डिज ने उस नीति को एक कदम और आगे बढ़ाया और देशी राज्यों में उच्चतर शिक्षा के सुबध में विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। देशी राज्यों के हितों से संबंधित प्रश्नों पर परामर्श करने की परंपरा को भी लॉर्ड हार्डिज ने जारी रखा और नरेशों को परस्पर परामर्श करने के लिए प्रोत्साहन दिया। सन् १९१४ तक कुछ प्रमुख देशी नरेश भारत की भावी नीति में देशी राज्यों की

१. See Introduction of Singh : Indian States and British India : Their Future Relations; particularly pages 56-57.

२. Quoted in Singh : Indian States and British India : Their Future Relations, page 56.

स्थिति सुरक्षित रखन के बारे में विचार करना लग था । लाड चेम्सफोर्ड ने अपने दो पूर्वाधिकारियों की नीति को जारी रखा और केवल देशी राज्यों से संबंधित और साथ ही देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत से संयुक्त रूप से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए देशी नरेशों के वार्षिक सम्मेलन किए । किन्तु देशी नरेश वस्तुस्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे और जब मि. माष्टफोर्ड तथा लाड चेम्सफोर्ड ने सुधारों के सिलसिले में जाँच करने के लिए देश का दौरा किया तो देशी नरेशों ने एक मिष्ट मंडल द्वारा अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए । उन्होंने तीन मुख्य दिशाओं में परिवर्तन करने के लिए कहा । डा. रशब्रुक विलियम्स के गद्दानुसार वे यह अनुभव करते थे कि अखिल भारतीय नीति निश्चित करने में उनका कोई स्थान नहीं था । उन का दूसरा परिवार यह था कि देशी राज्यों और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पगड़ों का निपटारा करने के लिए कोई निष्पक्ष व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अधिकांश मामलों में भारत सरकार स्वयं फैसले हुई होती थी और वही निष्पक्ष रहती थी । अन्त में उनका यह विश्वास था कि राजनतिक विभाग प्रायः सधियों की उपेक्षा करता था और साधारणतया उसका व्यवहार स्वेच्छापूर्ण होता था । <sup>१</sup>

इन दोषों को दूर करने के लिए देशी नरेशों ने एक ऐसी सभा बनाने की योजना रखी जिसमें वे परस्पर मिल सकें और अपने सम्मान्य हितों पर विचार कर सकें और जिस के द्वारा वे अखिल भारतीय विषयों पर ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के साथ मिल कर परामर्श कर सकें । इसके अतिरिक्त उन्होंने एक योजना का प्रस्ताव किया जिसके अनुसार विवादास्पद विषय निम्न के लिए एक निष्पक्ष 'याया' को सौंपे जायेंगे । अन्त में उन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की कि राजनतिक कायदा का उनकी एक समिति के साथ सम्पर्क हो ताकि विभाग की साधारण नीति देशी नरेशों की इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जा सके । <sup>२</sup>

माष्टफोर्ड रिपोर्ट ने देशी नरेशों के मुख्य प्रस्तावों को स्वीकार किया । रिपोर्ट में कहा गया— हम परामर्श के उद्देश्य से एक स्थायी निकाय स्थापित करना चाहते हैं । कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका देशी राज्यों पर साधारणतया प्रभाव पड़ता है

१ Quoted from the British Crown and the Indian States in Singh Indian States and British India Their Future Relations, page 58

२ Singh Indian States and British India Their Future Relations, page 59

साथ ही एक प्रश्न भी है जिनका पूरे साम्राज्य से अथवा ब्रिटिश भारत और दूरी राज्यात समान संबंध है, हमारा यह विचार है कि उन प्रश्नों पर प्रस्तावित निकाय का मत अत्यन्त मूल्यवान् होगा। वाइसरॉय उन प्रश्नों को उस परिपद् के विचारार्थ भेजेगा और हम को उनका सुचिन्तित मत जानने का अवसर मिलेगा। हमारे विचार से वाइसरॉय द्वारा अनुमादित कार्यावली पर विचार करने के लिए उस परिपद् की सहाये नियमित रूप से —साधारणतया वर्ष में एक बार—हानी चाहिए।<sup>१</sup> इस प्रकार माष्टफोर्ड रिपोर्ट ने दूरी नरेशों की एक स्थायी परिपद् स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। हमारा दूसरा प्रस्ताव यह है कि दूरी नरेशों की उस परिपद् प्रति वर्ष एक छोटी स्थायी समिति नियुक्त करे जिसमें वाइसरॉय और राजनैतिक विभाग द्वारा परपरा और व्यवहार के विषया पर अभिप्रेत किया जा सक।<sup>२</sup> रिपोर्ट में कहा गया कि इस समिति में परिपद् की इच्छानुसार दीवाना अथवा मन्त्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अन्त में रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि जिन विवादों में निष्पक्ष जांच बाधनीय हो, वाइसरॉय एक कमीशन नियुक्त करे जिस में एक हार्डकर्ट का न्यायाधीश और उसके अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि हो। यदि उस कमीशन की रिपोर्ट वाइसरॉय को मान्य न हो तो उस भारत-मन्त्री के निर्णय के लिए अभिप्रेत किया जावे।<sup>३</sup>

सन् १९१९ की जनवरी के अन्त में दूरी नरेशों के एक सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया, किन्तु यह सम्मेलन प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँच सका। उन सम्मेलन ने नरेशों की परिपद् की योजना का अनुमोदन किया और यह सुझाव दिया कि उसे नरेश मंडल के नाम से पुकारा जावे। इस सम्मेलन की सफारिशों भारत मन्त्री के समक्ष रखी गई, और वाइसरॉय ने भारत मन्त्री के परामर्श से नरेश मंडल स्थापित करने की योजना का मसविदा तैयार किया जिसे नवम्बर १९१९ में दूरी नरेशों का दूसरा सम्मेलन के समक्ष रखा गया। सम्मेलन ने इस योजना का अनुमोदन किया और कार्यपद्धति, पंच न्यायालय और जांच कमीशन के नियमों का मसविदा बनाने में वाइसरॉय की सहायता करने को एक कमीटी नियुक्त की। ८ फरवरी १९२१ का ड्यूक ऑफ वेन्डोर्ट ने नरेश-मंडल का नियमानुसार उद्घाटन किया।

१ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 195.

२. जर्नल पुस्तक, पृष्ठ १९५-१९६

३. जर्नल पुस्तक, पृष्ठ २९६.



१४

ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में सहयोग के लिए इस नई व्यवस्था के सबध में सन् १९१९ के गवर्नमेन्ट आब इंडिया एक्ट में कोई धारा नहीं थी। नरेन्द्र-मंडल की स्थापना का निर्णय एक राजकीय उद्घोषणा द्वारा व्यक्त किया गया था।

नवम्बर १९१९ में देशी नरेशों के सम्मेलन में लॉर्ड चेम्सफोर्ड न शासक नरेशों और 'शासक सामन्तों' में विभेद किया था। शासक नरेश देशी राज्यों के वे शासक थे जिनको राजप्रतिष्ठा के आधार पर सौंपी की सलामी मिलती थी, जिनको अपने प्रदेशों के आन्तरिक शासन का लगभग पूर्ण अधिकार था और जिनको स्वयं ही नरेन्द्र-मंडल का सदस्य होना का अधिकार था। अन्य सब केवल शासक सामन्त थे। अन्त में नरेन्द्र मंडल की रचना के अनुसार केवल १०८ देशी नरेशों को व्यक्तिगत सदस्यता का अधिकार दिया गया। अन्य देशी राज्यों को दो समूहों में बाँटा गया—वे राज्य जिनको नरेन्द्र मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया—एसे १२७ राज्य थे और उनको १२ प्रतिनिधि सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया था, और वे राज्य जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और इन की संख्या ३२७ थी। इस प्रकार नरेन्द्र-मंडल में १२० सदस्य थे—१०८ शासक नरेश जो अपन अधिकार के बल पर उसके सदस्य थे, और १२ प्रतिनिधि जो शासक सामन्तों द्वारा चुने गए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने नरेन्द्र मंडल के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दी थी, —“पहली बात तो यह थी कि मंडल में उपस्थित होता और बोट देना, सदस्यों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा”, “दूसरी बात यह थी कि मंडल में परामर्श किया जावेगा किन्तु उसकी कोई कामकारिणी सत्ता नहीं होगी, और” तीसरी बात यह थी कि मंडल की स्थापना से भारत सरकार और किसी देशी राज्य के सीधे सबध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक देशी राज्य का, चाहे उसे मंडल में प्रतिनिधित्व हो अथवा न हो, भारत सरकार से सीधे सबध बनाम रखने का अधिकार यथापूर्व रहेगा।” अन्त में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा — ‘इस सबध में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि मंडल में किसी राज्य-विशेष के आन्तरिक मामलों की अथवा किसी व्यक्तिगत शासक के कार्य की चर्चा नहीं की जावेगी।’”

इस नरेन्द्र-मंडल की, वाइसरॉय की अध्यक्षता में, उसके द्वारा अनुमोदित कार्यवाही पर विचार करने के लिए साधारणतया वर्ष में एक बार सभा होती थी। मंडल को अपने लिए एक चांसलर का निर्वाचन करना होता था जिसे वाइसरॉय की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का पद ग्रहण करना होता था। वह स्थायी समिति का

१ देशी नरेशों के सम्मेलन में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के व्याख्यान से अनूदित—

देखिये The Indian Annual Register, 1920, page 88.

ना अध्यक्ष होता था जिसमें उनके अतिरिक्त चार या पांच सदस्य और होते थे। स्थायी समिति के सदस्यों का इन बातों में अभ्यधीन प्रति वर्ष निर्वाचन होता था कि उनमें—राजपूताना मध्य भारत बम्बई और पंजाब—प्रत्येक क्षेत्र के दली नरेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

मदन के बाजों और उनके अधिद्वारा पर प्रतिबन्धों को राजकीय उन्मादना में इस प्रकार व्यक्त किया गया —

साधारणतया देगी राज्यों के प्रदेशों में संबंधित विषयों पर और साथ ही उन विषयों पर जिनका ब्रिटिश भारत अथवा मेरे पास साम्राज्य के साथ उन प्रदेशों पर भी सख्त रूप में प्रभाव पड़ता है मेरा बाइसराय निस्संकोच परामर्श करेगा। उसका किसी व्यक्तिगत देगी राज्य अथवा किसी व्यक्तिगत नरेश के मेरा सरकार के साथ संबंध में लगाव नहीं होगा और उसका देगी राज्यों की वर्तमान व्यवस्था और उनकी वाय-स्वतंत्रता पर किसी प्रकार से प्रतिबल प्रभाव नहीं पड़ेगा।<sup>१</sup>

स्थायी समिति की भारत सरकार के वेदों में प्रति वर्ष दो या तीन बार मांग्य हाती है और उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम यह है कि वह एक विषयों पर जिनका देगी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों के गानन में साथ संबंध है, सरकार के विभिन्न विभागों के साथ विचार विनिमय करती है।<sup>२</sup>

१५

मालफाट रिपोर्ट ने देगी राज्यों के संबंध में दो विषयों पर और निर्देश किया था उनका संपूर्ण विवरण देना आवश्यक है। रिपोर्ट के लक्ष्य में कहा — हमारे दो अवशिष्ट प्रस्तावों का ब्रिटिश भारत की संविधानीय यात्रा में प्रत्यक्ष संबंध है। हम इन बातों को निष्कारण करते हैं कि साधारण सिद्धान्त के रूप में भारत सरकार के साथ सार महत्वपूर्ण देगी राज्यों के मोक्ष राजनितिक संबंध हान चाहिये।<sup>३</sup> इस बात की केवल कुशलता और वाय-मन्त्रालय में ग्राह्यता का ही दृष्टि से नहीं बल्कि साधारण नाति के आधार पर भी— अखिल भारतीय

१ Singh Indian States and British India Their Future Relations, page 61—के एक उद्धरण का अनुवाद।

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६३।

३ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918 page 197 इस निष्कारण के पन्थस्वर्ग्य वस्तुन का परिचयन हुए उनमें निम्न दमिच—Singh Indian States and British India, Their Future Relations, page 53 and 54

महत्व के विषयों को प्रान्तीय विषयों से अलग करने के लिए—उसकी आवश्यकता थी। अन्य देशों राज्यों के साथ में रिपोर्ट के अनुसार न कोई निश्चित सिफारिश नहीं की। उन्होंने लिखा — भारत सरकार इन राज्यों में सीधे संबंध स्थापित कर सकती है अथवा इस समय उनको प्रान्तीय सरकारों के साथ साथ बनाए रखने का छोड़ सकती है। किन्तु दूसरी स्थिति में हमारे विचार से प्रान्तीय अध्यक्ष को देशी राज्यों के साथ अपने संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिवर्तन के रूप में काम करना चाहिए और देशी राज्यों के साथ प्रान्तीय संबंध इस अर्थ में प्रान्तीय विषय नहीं माने जाने चाहिए कि अभी भी वे विधान परिषद् के नियंत्रण के अन्तर्गत आ सकते हैं।<sup>१</sup>

मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट का दूसरा और अंतिम प्रस्ताव देशी नरेशों और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों द्वारा देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों से संबंधित विषयों पर संयुक्त रूप में परामर्श करने की व्यवस्था के संबंध में था। राज्य-परिषद् में कुछ नरेशों को उस समय सम्मिलित करने का प्रस्ताव अव्यवहार्य था। अतः रिपोर्ट के लेखकों ने इस बात को सिफारिश की कि वाइसरॉय एस. अवसरों पर राज्य-परिषद् और नरेश-परिषद् अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त परामर्श का प्रबंध करे।<sup>१</sup>

## इसकीसवीं अध्याय

# विच्छिन्नता की वृद्धि

१

मॉण्टफोर्ड-योजना भारतवासियों के लिये वस्तुतः सड़क की जड़ सिद्ध हुई। यह यत्न और बलिदान के बाद क्रमशः जो एक स्थापित किया गया था वह बिना किसी विशय प्रकट प्रयास के, लगभग तुरन्त ही नष्ट कर दिया गया। इस वर्ष अलग रहने के दावें राष्ट्रवादियों के नरम और उग्र पक्ष जो पुनः एक हो गए थे, उनको मॉण्टफोर्ड-योजना ने एक बार फिर विभाजित कर दिया। कई सामुदायिक और साम्प्रदायिक समस्याएँ अस्तित्व में आईं अथवा दृढ़ की गईं। उनका उद्देश्य प्रस्तावित मुद्दों में अपने वर्ग अथवा समुदाय के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना था। दिसम्बर १९१६ में ग्वालियर में जो हिन्दू मुस्लिम एकता हुआ था उस पर अक्टूबर १९१६ में आरा (बिहार) के साम्प्रदायिक दंगों के कारण इतना तनाव पड़ा कि वह टुकड़-टुकड़ होने लगे।

१ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 198

दंगा वा तात्कालिक कारण यह था कि २९ सितम्बर १९१७ को इब्राहीमपुर (जिला मुहायाद) के मुसलमानों ने अपने समझौते को तोड़ कर गाय वा बलिदान किया था। निवटवनी ग्राम्य क्षेत्रों के हिन्दू गाय वा बलिदान सदा के लिए बन्द कर देने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था क्योंकि उनके लिये गाव बड़ी धृष्टता की चीज थी। ३० सितम्बर की सुबह को हिन्दुओं के बहुत बड़ दल न—अनुमानत २५००० आदमियों ने—इब्राहीमपुर और निवट के कुछ गाँवों पर आक्रमण किया। उसे तितर-बितर करने के लिए पुलिस को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस अथम पर काफी लूट मार भी हुई और एक घाने पर आक्रमण किया गया। तुरन्त ही उस जिले को सैन्य-पुलिस भेजी गई और ३६ घण्टा तक प्रवृत्त शान्ति रही। किन्तु २ अक्टूबर को जिले के अधिकांश भाग में फिर एक-साथ दंग आरम्भ हो गए और ६ दिन तक न्याय और व्यवस्था का अभाव रहा। ९ अक्टूबर का झगड़ा गया जिले में भी फैल गया। बहुत-से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। “भारत-भुरक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये हुए विराय न्यायालया में उन पर अभियोग चलाया गया और लगभग एक हजार आदमियों के दाप मिट्टे हुए और उनका विभिन्न अवधियों के लिए कारावास-दंड दिया गया।”\*

आग व इन उपद्रवों को सारे भारतीय समाचार-पत्रों ने तीव्र निन्दा की किन्तु डा. रंगनूत विलियम्स ने लिखा है कि कुछ हिन्दू समाचार-पत्रों ने “सम्भार के सिर दाप करने का प्रयत्न किया और अनभिज्ञ देहानी जनता की धर्मापत्ता की चर्चा नहीं की।”\*

इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घायला के बाद, हिन्दू-मुस्लिम-सोहादे के होते हुए भी, भारत में एक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हुआ। और यह एक विचित्र बात है कि भाण्टफोर्ड-रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भी देश में भीषण दंगे हुए। १८ सितम्बर १९१८ को यू. पी. के महारनपुर जिले में, बटारपुर नामक गाँव में एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ। गाय वा बलिदान रखने के प्रयत्न में हिन्दुओं द्वारा लगभग २० मुसलमान मारे गए। बहुत से हिन्दू गिरफ्तार किये गए और उन पर अभियोग चलाया गया। “१७५ अपराधी मिट्टे हुए, ८ का प्राणदण्ड दिया गया, १३५ का आजीवन दग-निर्वासन दण्ड दिया गया और २ का मात्र वर्ष का बटार कारावास।”\*

१. India in 1917-18, page 39

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६०।

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६०-६१।

४. Lovett: A History of the Indian Nationalist Movement, page 180.

इन दंगा के कारण हिन्दू-मुस्लिम एक्य की प्रबल परीक्षा हुई और यदि कुछ बाहरी कारण न होते जिनके फलस्वरूप मुसलमान ब्रिटिश सरकार<sup>१</sup> के विरुद्ध हो गए थे तो वह एक्य सम्पादित हो गया होता। वस्तु महामा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की खिगाफत और तुर्किस्तान के मध्य में मुस्लिम भाग्य के प्रति सहानुभूति के कारण साम्प्रदायिक एक्य दृढ़तर हुआ। राजनतिक दृष्टि से जय हुए बहुत से हिन्दुओं ने खिगाफत के प्रश्न और शान्ति-सम्मेलन में मुस्लिम विरोधियों के प्रति अधि गतों के सबब में मसख्तमाना का पूरा समझना किया।

२

हिन्दुओं के इस भाव ने हिन्दू-मुस्लिम-मौहान बनाने में रखा। तथापि भाण्ट फाड रिपाट के प्रकाशन से साम्प्रदायिक भावनाओं और भेदा का बढ़ावा मिला। १९१६-१७ में अ-ब्राह्मण आन्दोलन मद्रास में आरम्भ हो गया था। डा. नयार के योग्यतापूण एवं आनामन नतुत्व में उसने बड़ी गतिशीलता से प्रगति की थी। उन लोगों का यह धारणा थी कि उनके आन्दोलन के प्रति सरकार की सहानुभूति थी। वस्तुतः राष्ट्रवादियों का इस बात का पूरा विश्वास था कि सरकार प्रेरणा से ही सारे आन्दोलन का संगठन किया गया था और उसका उद्देश्य होमरूल आन्दोलन का विराम करना था।

मद्रास प्रसोदन्मी में बहुत समय से ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी प्रभावपूर्ण और प्रतिष्ठित थी और मुख्यतः उन्हा के हाथों में गति केन्द्रित थी — किन्तु सम्पत्ति मुख्यतः अ-ब्राह्मणों के हाथों में थी। अपनी गति विद्या और श्रद्धा के अभिमान में ब्राह्मणों ने गतिगति से इतर जातियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया था। यद्यपि कुछ प्रगतिगति ब्राह्मण समाज-सुधार के काम में लग गए थे और इतर

१ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीखी भावनाओं की कलकत्ता के साम्प्रदायिक दंगों में अभिव्यक्ति हुई। यह दंग ९ और १० सितम्बर १९१८ को हुए। सरकार ने मुस्लिम-सम्मेलन करने पर रोक लगा दी थी। उस सरकारी आदेश का रद्द कराने के लिए एक मुस्लिम जलूस गवर्नमेण्ट हाऊस की तरफ जा रहा था। उसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रयत्न किया और उसके फलस्वरूप उपद्रव आरम्भ हो गया। जलूस को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोली चरानी पड़ी। अगले दिन स्थिति और ज्यादा बिगड गई। मित्र मजदूरों ने उपद्रवियों का साथ दिया और एक फोरमन को बरी तरह पीटा। लगभग दो हजार मुसलमानों ने कलकत्ता नगर में बलात प्रवेश करने का प्रयत्न किया। इन लोगों को तितर बितर करने के लिए फिर गोली चरानी पड़ी।

जातियों को ऊपर उठाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे तथापि ब्राह्मणों और अ-ब्राह्मणों के संबंध बहुत असंतोषप्रद थे—एक ओर श्रेष्ठता का अभिमान था और दूसरी ओर आत्म-दैन्य था। लॉर्ड पैण्टलैण्ड की सरकार ने थोमसी बीसेण्ट के भारतीय होमरूल के संगठित प्रचार का सामना करने के लिए, उस स्थिति का चतुरतापूर्वक उपयोग किया। १९१७-१८ में अ-ब्राह्मणों ने होमरूल की मांग के विरुद्ध प्रचार किया और जिसे वह 'ब्राह्मणराज्य' कहते थे उसे अस्तित्व में न आने देने के लिए, ब्रिटिश राज्य को बनाये रखने की मांग की। अ-ब्राह्मणों के पक्ष को व्यक्त करने के लिए और भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण का विरोध करने के लिए, डा. नैयर इंग्लैंड गए।

मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट ने, पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा अथवा समुक्त निर्वाचन-क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों द्वारा अ-ब्राह्मणों को विरोध प्रतिनिधित्व देने की मांग को अस्वीकार किया क्योंकि अ-ब्राह्मण वर्ग प्रेसिडेंसी में बहुसंख्यक थे। इसका अ-ब्राह्मणों ने, जो 'जस्टिस पार्टी' के रूप में संगठित थे, प्रबल विरोध किया। उन्होंने काफी हलचल मचाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान रखने की उनकी मांग को समुक्त प्रचल समिति ने स्वीकार कर लिया।

३.

मद्रास के अ-ब्राह्मणों की अपेक्षा पंजाब के सिक्खों का पक्ष कहीं अधिक प्रबल था। यद्युक्त सिक्खों का ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों की वही व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता अनुभव की जो मुसलमानों के संबंध में अनाई गई थी।

सन् १९१९ तक सिक्खों का कोई पृथक् राजनैतिक संगठन नहीं था। उस समय तक उन्होंने अपना ध्यान धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया था और उनके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रयत्न किया था। १८८८ में 'गालगा दीवान' नामक एक मुखार-मग्धा लाहौर में स्थापित की गई थी—और उनकी सारे प्रान्त में 'मिह मभा' नामक धार्मिक शाखाएँ थीं। गालगा दीवान का उद्देश्य, सिक्ख समुदाय में अंध-विश्वास और हिन्दू कर्मकाण्ड को दूर करना था और उनके स्थान पर सिक्ख रीतियों को प्रोत्साहन देना था। गालगा दीवान के प्रयत्नों का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि १८९२ में अमृतसर में गालगा-कालिज स्थापित किया गया। किन्तु योग्यता बनाव्दी के आरम्भ होने तक गालगा दीवान का संगठन मूलतः हीन था। दूसरी ओर, लगभग उन्नीसवें वर्ष अमृतसर में 'श्रीक गालगा दीवान' नामक एक दूसरा केंद्रीय संगठन अस्तित्व में

जाया। यह दीवान अब भी वनमान हैं और महत्वपूर्ण शिक्षणात्मक कार्य कर रहा है। सन् १९०८ के बाद उसकी शिक्षण समिति ने प्रति वर्ष सिक्ख शिक्षणात्मक सम्मेलन का संगठन किया है और उसने प्रान्त में बहुत-सी शिक्षण संस्थाओं को बराबर आर्थिक अवलम्ब दिया है।

सिक्खों की धार्मिक सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी उन्नति को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त इस दीवान ने सिक्ख समुदाय के राजनैतिक हितों पर भी ध्यान दिया है। दीवान की राजनैतिक नीति को कोई प्रबल समर्थन नहीं मिला है क्योंकि सिक्ख तरुण वर्ग की दृष्टि में वह नीति अत्यन्त नरम अथवा पिछड़ी हुई और सरकार के पक्ष में है। रिकावगज (मई दिल्ली) के महत्वादे की दीवार पर सगड के मन्त्र में दीवान बहुत अप्रिय हो गया—क्योंकि सरकार के प्रति उसका भाव कठोर नहीं था। तथापि यह दीवान सिक्खों के राजनैतिक हितों का संरक्षण करता रहा और समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करता रहा। माण्टगु मिशन को उसने एक लिखित ज्ञापन दिया और एक शिष्ट मंडल का संगठन किया जिसने भारतमन्त्री और वाइसरॉय से भेंट की।

सिक्ख ज्ञापन ने प्रान्त के राजनैतिक और आर्थिक जीवन में सिक्खों की महत्वपूर्ण स्थिति पर जोर दिया और महायुद्ध तथा व्युत्थान के समय में उनके महान बलिदानों को ओर ध्यान आकर्षित किया। महायुद्ध के समय में पंजाब में कुल जितने सैनिक मर्त्यों किए गए थे उनमें से एक तिहाई सिक्ख थे और साधारण मनसब में कुल भारतीय सेना में २० प्रतिशत सिक्ख सैनिक होते थे। इसके अतिरिक्त वे पंजाब के शासक रह चुके थे और प्रान्त के कुलीन और प्रतिष्ठित जमींदार वर्ग में आधे से अधिक लोग सिक्ख थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रान्त के बहुसंख्यक समुदाय की अपेक्षा उन्होंने अधिक प्रगति की थी। इन तथ्यों के आधार पर ज्ञापन में यह माँग की गई कि पंजाब-परिषद में उन्हें एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जावे और सेवाओं में उन्हें उचित भाग दिया जावे।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने अनुपात के प्रश्न को नहीं छड़ा किन्तु मुसलमानों के आधार पर सिक्खों की पृथक प्रतिनिधित्व की माँग को स्वीकार कर लिया। पंजाब सरकार ने सिक्खों को अधिक स्थान देने की माँग का समर्थन किया — प्रान्त में उनकी प्रभावशाली स्थिति कुछ हद तक ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों पर कुछ हद तक उनकी संघीय प्रतिष्ठा पर और कुछ हद तक केन्द्रीय जिलों तथा नहर उपनिवेशों में उनके आर्थिक महत्त्व पर अवलम्बित है। उस स्थिति के कारण

१ पंजाब में सिक्खों की जनसंख्या कुल ११ प्रतिशत थी किन्तु वे ४० प्रतिशत मालगुजारी और नहर की आवश्यकता देते थे।

यह उचित हो है कि उनकी मर्यादा की ओर ध्यान देकर उन्हें वांछी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।<sup>१</sup> किन्तु पञ्जाब-परिषद् ने उनके विषय पर विचार करना अस्वीकार किया और एक प्रस्ताव द्वारा केवल हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए 'कायम लोग राजना के स्थान विभाजन का अनुमोदन किया' क्योंकि उस राष्ट्रीय समझौते में सिक्खों का कोई स्थान नहीं था। मताधिकार कमिटी ने सिक्खों का पञ्जाब-परिषद् में ५४ में से कुल ८ स्थान प्रदान किए जिसके कारण उनमें प्रबल अनन्त्या हुआ और उन्होंने अपना हितों की रक्षा करने के लिए एक पक्षी राजनैतिक समस्या संगठित करने की आवश्यकता अनिवार्य की। लालपुर जिले के सिक्खों का बड़े और उन्होंने अन्य जिलों के तरणों के सहयोग में सिक्खों की स्थापना की। इस लोग का पहला अधिवेशन अमृतसर में कायम-मज्हा में किया गया और उसके अध्यक्ष सरदार गज्जनाम सिंह थे जो पञ्जाब विधान-परिषद् के सदस्य थे। सिक्खों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था लोग ने उस अपवाप्त बनाया और पञ्जाब-परिषद् में एक तिहाई निर्वाचित तथा नामनिर्देशित स्थानों के लिए भाग ली।

सिक्खों की ओर चीफ़ स्याल्मा दीवान, सिक्खों का प्रतिनिधित्व बजाने के लिए हलबल करते रहे और उन्होंने भारत मंत्री तथा ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक सिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा, किन्तु उसका कोई विशेष फल नहीं हुआ। अन्त में जो राजना स्वीकार की गई उनमें कुल ९१ निर्वाचित तथा नामनिर्देशित स्थानों में से सिक्खों को १० स्थान दिये गए। निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ७१ थी जिसमें से ३० मुस्लिम निर्वाचित-क्षेत्रों में, २० साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में, ३ विधायक निर्वाचन-क्षेत्रों में और १० सिक्खों निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाने थे।

८

मुधारा के प्रश्न ने साम्प्रदायिक भावना का केवल अ-शास्त्रणा और सिक्खों में ही नहीं बसाया बल्कि यूरोपियन, आर्य-भारतीयों और भारतीय इत्यादि में भी बसाया। "काफी समय से गैर-सरकारी अखेडन-नमुदाय भारतीय राजनीति में कोई काम दिलवती नहीं लेता था। लगभग तीन वर्ष पहले इत्तफाक अहमदाली के समय में जो यूरोपियन डिपें एमनियेशन स्थापित की गई थी, उसका प्रभाव बहुत पट गया था और उसकी संख्या बहुत कम हो गई थी।<sup>२</sup> किन्तु मुधारा की नई नीति के कारण यूरोपीय नमुदाय अपना संगठन दृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव करने लगा।

१. The Gurudwara Reform Movement and the Sikh Awakening, page 75

२. India in 1917-18, page 43.



सन् १९१३ में यूरोपियन डिफेंस एसोसियेशन का नाम केवल 'यूरोपियन एसोसियेशन' हो गया था और १९१७ में उस एक नए आधार पर संगठित करने का प्रयत्न किया गया। "सारे भारत में उसकी शाखाएँ बनाई गईं और कलकत्ता में एक नया केन्द्रीय संगठन स्थापित किया गया। अंग्रेजों के अधिकांश पत्रा का समर्थन पाकर, कुछ ही समय में उसकी सदस्यता ७०० अथवा ८०० से बढ़कर लगभग ८००० हो गई।" जब मि. मॉण्टगु भारत में आए तो यूरोपियन एसोसियेशन ने भारत मंत्री और वाइसरॉय के सामने अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। भारत पर सुधार लादने के परिणामों के सबब में उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की और राजनैतिक प्रगति के सिलसिले में तबरा की नीति का तीव्र विरोध किया। उसने सरसम्बन्धी यूरोपीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की। मॉण्टगो-रिपोर्ट ने यूक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये यूरोपियनों की मांग को अस्वीकार किया किन्तु यूरोपीय हितों के संरक्षण के लिए सरकार को विशेष अधिकार देने की और साथ ही यूरोपीय वाणिज्य, उद्योग, खनिज तथा रोपक हितों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की। यूरोपियन एसोसियेशन इससे सन्तुष्ट नहीं हुई और उसने यूरोपीय व्यापारिक हितों को दिए हुए विशेष प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त, यूक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये मताधिकार कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों की मांग को भी मॉण्टगो-रिपोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने भी मताधिकार कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इन तीनों समुदायों की यूक् प्रतिनिधित्व की मांगों को मताधिकार कमेटी और संयुक्त प्रवर समिति, दोनों ने स्वीकार किया और १९१९ के सुधारों में उनकी (जिन प्रान्तों में उनकी काफी महत्ता थी) यूक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

५

यद्यपि सुधारों की नीति का भारत की यूरोपियन एसोसियेशन ने प्रबल विरोध किया है, किंतु वह इंग्लैंड की इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन के दृढ़ विरोध की तुलना में बहुत कम था। इस एसोसियेशन की २० अगस्त १९१७ की घोषणा के कुछ समय बाद ही लन्दन में स्थापना की गई थी और उस का उद्देश्य सरकार की नई नीति का विरोध करना और ब्रिटेन में भारत-विरोधी जनमत जगृत करना था। किंतु प्रकट उसका उद्देश्य "भारतीय जनता के ऐक्य और उसकी उन्नति" को प्रोत्साहन देना था। इस दिशावटी उद्देश्य की आलोचना करते हुए हिंदू हार्डनेस महाराजा बीकानेर ने कहा — "इस एसोसियेशन की व्यवस्था, उसके तर्क और

विभिन्न बायों ने उनके प्रदर्शित उद्देश्य पर एक जाल डाल रखा है और हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि एम मित्र ने हमारी रक्षा की।"<sup>१</sup>

इंडो ब्रिटिश एमोसियेशन का संगठन कुछ निवृत्त आंग्ल-भारतीय अधिराज्या न किया था, लाई सिडनहैम उनके नेता थे। माट्यू मिशन के भारत पहुँचने के कुछ ही दिन पहले ३० अक्टूबर १९१७ को उसका उद्घाटन हुआ। उसने आरम्भ में ही भारतीय वाणिज्य में सम्बन्धित ब्रिटिश व्यापारियों के पास एक गुप्त पत्र भेजा और उनसे एमोसियेशन की निधि के लिए उद्घाटनपूर्वक अग्रदान देने के लिए कहा और उन्हें यह बताया कि उनका दान भारत में ब्रिटिश हिता के बोझ को भीति होगा।<sup>२</sup> इस पत्र में अग्रदाता के स्वार्थों और हिता का उल्लेख किया गया। लन्दन में एक भारतीय पत्रकार को चतुर्गई में इस पत्र का प्रकाशन हो जाने पर एमोसियेशन का वास्तविक रूप प्रकट हो गया।

इंडो ब्रिटिश एमोसियेशन ने ब्रिटिश मीडिया द्वारा सार्वजनिक-विरापी प्रचार किया और उसने इस बात का प्रयत्न किया कि भारत में प्रचलित एमोसियेशन उसका अनुकरण करे। आरम्भ से ही उसने समाचार-पत्र और पुस्तिकाओं द्वारा निरन्तर प्रचार किया है। उनका उद्देश्य भारत की स्थिति के बारे में माध्यम आदमियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना है। उनमें भारत के शिक्षित वर्गों का हर दृष्टि से अवमान किया जाता है—...कभी (अपेक्ष) मजदूर के व्यक्तित्व और वर्ग हित का उल्लेख जाता है और कभी भारतीय व्यापार में लगी हुई कल्पनियों के स्वार्थों का उल्लेख जाता है।<sup>३</sup> उसने, भारतीयों के विरोध में और साथ ही भारत में राजनैतिक मुद्दों की नीति के विरोध में, जतन जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष अवसर से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। उसने इंडियन मिशनरी कमेटी की जीव का लाभ उठाने के लिए "भारत में गहरा—राजशाह और हत्या" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। मनवक दश-ब्रिटिश एमोसियेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं में यह सब से ज्यादा निन्दापूर्ण और अपमानात्मक थी, किन्तु इस दृष्टि की वह कई अनेकों पुस्तिका नहीं थी। सब यह है कि भारत के दल स्व-घोषित मित्र और अनुचितता ने गिहित भारतीयों और इंग्लैंड में उनके समर्थकों का गाली देने में नहीं सीमाओं का उल्लंघन कर दिया था।

१. मकाय हाटल (लन्दन) का १२ मार्च १९१९ का सम्पादन न उद्धृत—रिपोर्ट—

Indian Annual Register, 1919, page 83.

२. The Indian Annual Register 1919, page 83-84.

इंडो ब्रिटिश एसोसियेशन ने माटफोर्ड-योजना का जब मे उसका पहली बार विचार सूझा और जबतक वह कार्यान्वित की गई और उसके बाद भी, अत्यन्त प्रबल विरोध किया। इस एसोसियेशन के सदस्य भारत में स्वशासन सस्यामों की वृद्धि के विचार से अपना मेल नहीं बिछा सके।

६

अंगरेजों का एक वर्ग और या जो मुधारों की नीति का लगभग उतना ही बटुआ विरोधी था जितना कि इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन का अंगरेज समुदाय— और यह वर्ग या इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य का। इंग्लैंड में वैसे हुए सिविल सर्विस के निवृत्त सदस्यों की भाँति ये लोग वैसा ही सार्वजनिक प्रचार करने के लिए स्वतन्त्र नहीं थे, किन्तु अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने यथासम्भव विरोध करने के लिए संगठन किया। मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने उनका विरोध दूर करने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न किया था, और उन्होंने लिखा भी था—“यह कहना अपवादपूर्ण है कि इंडियन सिविल सर्विस ने एक निवाय के रूप में पिछले अगस्त में प्रकट की हुई नीति का प्रतिरोध किया है अथवा वह भविष्य में प्रतिरोध करेगा। उन्होंने उसका स्वागत किया है क्योंकि इस बात को उनसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता कि नीति घोषित करने की कितनी भारी आवश्यकता थी और वे उस नीति को दृढ़ निश्चय के साथ ठीक उसी तरह कार्यान्वित करेंगे जैसे कि उन्होंने सदैव अपने लिए निर्धारित अन्य नीतियों को कार्यान्वित किया है।”<sup>१</sup>

यह सच है कि अन्त में भारतीय सिविल सर्विस के अधिकांश सदस्यों ने १९१९ के मुधारों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया, किन्तु मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ ही समय बाद उन्होंने प्रस्तावों का विरोध करने के लिए और इस दक्षतव्य का लक्षण करने के लिए कि उन्होंने मुधारों का स्वागत किया है, अपना संगठन किया। मद्रास की इंडियन सिविल सर्विस एसोसियेशन ने भारत मंत्री के ममक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ज्ञापन का मसविदा तैयार किया और उसमें कहा गया—“अब हम ब्रिटिश भारत के प्रशासन से संबंधित योजना और प्रस्तावों को आलोचना नहीं करना चाहते, किन्तु इस विषय पर हम यह कहना उचित और वाछनीय समझते हैं कि अंगरेजों समाचार-पत्रों में जो यह सकेत किया गया है कि सिविल सर्विस का सारा समुदाय प्रस्तावित योजना का केवल अनुमोदन ही नहीं करता बल्कि स्वागत भी करता है, वह गलत है।”<sup>२</sup>

१. The Report on Indian Constitutional Reforms 1918, pages 206-207

२. The Indian Annual Register, 1920, page 213

१९१८ में दंग में कई आदमों की मौतें हुईं। सत्याग्रह का सफलतापूर्वक समापन हुआ।  
 एक की विचार में स्थापना की गई। दूसरा की मद्रास में और तीसरी बंगाल में  
 स्थापित होती थी। किन्तु उसके विचार को रूप नहीं मिला। बिहार एसोसियेशन  
 ने अपने सदस्यों के पास एक पुस्तक भेजी थी जो विभिन्न तरह से पटना के  
 सचराइट के हाथों में पड़ गई। और उसमें २० दिसम्बर १९१८ को प्रकाशित  
 किया गया। ऐसा ही एक पुस्तक मद्रास आदमों की मौतें एसोसियेशन के  
 कार्यवाह ने सिविल सर्विस के ब्रिटिश सदस्यों के पास भेजी थी। उसकी एक प्रति  
 मद्रास के न्यू इंडिया नकिमा तरह प्राप्त कर ली और वह पत्र उसमें ११  
 जनवरी १९१९ को प्रकाशित किया गया।

मद्रास के पत्र में भारत में की गई प्रस्तुत किए जाने वाले एक नापस  
 का मतविदा था। सिविल सर्विस के एक सदस्य ने जिसका नाम वह हस्ताक्षर के  
 लिए भेजा गया था। उस पत्र के बारे में यह कहा — हमने मादकता की एक उच्च  
 मात्रा दी गई है। सारा पत्र राजनितिक बयानों से परिपूर्ण है। उसकी विद्रोहपूर्ण  
 भाषा में प्रतीत है।<sup>१</sup>

मद्रास के पत्र से भारतीय राजनितिक क्षेत्र में बड़ी हलचल हुई और  
 इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों के मनोभाव और कार्यों की निंदा करने के  
 लिए देश के विभिन्न भागों में सावजनिक सभाएँ की गईं।

सिविल सर्विस द्वारा माण्डकाइ प्रस्तावों का विरोध अविवशपूर्ण और  
 अग्रणी था। किन्तु साथ ही वह स्वाभाविक भी था। पिछली कई पीढ़ियों से  
 देश के शासन में सिविल सर्विस के सदस्यों का स्थिति अत्यन्त गतिशील और  
 विगलितपूर्ण थी। अतएव ही उन सदस्यों को नवोदय में अपना अधस्त  
 स्थिति का चित्र दिखाई दिया। वे आप से बाहर हो गए और अपनी निराला में  
 उह जो कुछ गूँग पड़ा वहीं करने लगे। मद्रास और बिहार के पत्रों से उनका चिन्ता  
 और परेशान होनी लगी। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सिविल सर्विस के  
 सदस्य मुख्यतः स्थायी नायनाभा से प्रभावित थे। अतः भारत सरकार का बड़ी  
 परेशान हुई और बादशाह ने सिविल सर्विस का प्रशासन करने के लिए उनसे गुण  
 प्राप्त आरम्भ कर दिए और उनका अधिक तथा राजनितिक क्षिति में पूर्ण मर्यादा  
 के लिए बड़ी आशावादी दिया।<sup>२</sup> किन्तु यह चम्पकाइ के व्याख्यान से भारतीय  
 जनमत बनताजा में फिर रास हो गया। उन व्याख्यान का अर्थ था प्रतिनिध्यावादी  
 गतिशीलता की विजय। उसने एक बार ऊँची नोरिया के विद्रोह सदस्यों का

१ The Indian Annual Register, 1920, Page 221

२ ६ फरवरी १९१९ का भारतीय विधान-परिषद् में लॉर्ड चम्पकाइ का व्याख्यान

धमकी दी थी और दूसरी ओर रालेड कमेटो द्वारा प्रस्तावित दमनकारी विधान बनाने के लिए सरकारी निश्चय को प्रकट किया था। वस्तुतः वाइसरॉय के व्याख्यान के बाद तुरन्त ही गृह-सदस्य न भारतीय विधान-परिषद् में उन विधायकों को जो 'काले कानून' के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रस्तुत किया। सरकार की इस दोहरी असन्तुष्टि नीति ने सावजनिक भावनाओं को अत्यन्त खोसा कर दिया और उसके फलस्वरूप देश में एक ऐसी ज्वलन्त हड़ताल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी।

७

इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से भारत के राजनीतिक मतभेद फिर आरम्भ हुए। १९१७-१८ में विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं ने ही अपना फिर से संगठन नहीं किया बल्कि कांग्रेस में दुबारा फट पड़ी और (१९०७ के विपरीत) इस बार अलग होन वाला न अपना पृथक् राजनैतिक संगठन बनाया और उस अखिल भारतीय संस्था के अन्तर्गत प्रांतीय शाखाएँ बनाई और इस प्रकार दोनों पक्षों में फिर से एक्य होना लगभग असम्भव हो गया।

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि मॉण्टगु के भारत आने का एक उद्देश्य यह भी था कि वे भारत में एक माजरेड पार्टी स्थापित करना चाहते थे जो उनकी सुधार-योजना को अपना समर्थन दे और बाद में उसे कार्यान्वित भी करे। भारत से वापिस जान से पहले बंगाल के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध में उनका समझौता हो गया था। और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ समय पहले बंगाल में 'नेशनल लिबरल लीग' की स्थापना हो गई थी। भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिन बाद श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बलकत्ता में इंडियन एमोसियेशन की सभा की और उसमें मॉण्टफोर्ड प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। अगस्त १९१८ में नेशनल लिबरल लीग ने राजा प्यारे मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में बंगाल के मध्यम पक्ष का पहला सम्मेलन किया। राजा साहब बहुत पिछड़े हुए विचारों के आदमी थे और उन्होंने मॉण्टफोर्ड-योजना का केवल हार्दिक समर्थन ही नहीं किया बल्कि भारत में उत्तरदायी शासन आरम्भ करने की कठिनाइयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। "भारत में अस्सी जातियाँ हैं, उनकी इतनी ही विभिन्न भाषाएँ हैं और वे विभिन्न प्रकार के संकटों धर्मों का अनुसरण करती हैं। उनमें कोई ऐक्य और सुदृढ़ता नहीं है।" उन्होंने व्याख्यान के अन्त में कहा—अधिकारियों के राज्य के स्थान पर लोकप्रिय

राज्य स्थापित करने के सङ्गमण का न म जा सबट उपस्थित हात ह । उनस सभी समयदार आदमी स्वाभाविक रूप म डरते ह । जिस योजना को रिपोर्ट म रूप दिया गया ह उसस स्वागसन की दिगा म काफी प्रगति हागी और हम उसका स्वागत करत ह । <sup>१</sup> सम्मन्त्र न एव एम्ब प्रस्ताव द्वारा मि माण्टगु और ग्राड चम्सफोर्ड को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया और इस बात का स्वीकार किया कि माण्टफोर्ड प्रस्ताव म उत्तरदायी गसन की दिगा म काफी प्रगति होगी । योजना के साधारण सिद्धान्त का प्रस्ताव म स्वागत किया गया और साथ ही यह कहा गया कि मावजनिक निकाया व मयाबा का ध्यान म रखते हुए उसम उपयुक्त सङ्गोधन कर दिया जाय । <sup>२</sup>

माण्टफोर्ड रिपोर्ट व प्रकाशन क कुछ ही समय बाद चम्बई क नौ मध्यम दली नेताभा न एव गायन निकाया और उसम मुधार योजना क संबंध म अपन विचार प्रकट किए । वस्तुतः सार दल के मध्यमदली नेताभा व विचार एव-न ध—उह रिपोर्ट व गसबा की मचार सहानुभूति और उनक सदुद्देश्य पर पूरा विश्वास था । उनक अनुसार प्रस्ताव प्रगतिगाठ और तात्विक ध । किन्तु उहान भारत सरकार क संबंध म योजना म मुधार करने व लिए कुछ मुयाव नी दिए ।

काग्रम व वाम-मधी नेता दा वगों म बैठे हुए व । उग्र वग म हामरुल आदर्शन व प्रगतिशील समर्थक व । उनक अनुसार प्रस्तावित योजना भारतीय जनता क प्रति अविश्वास पर अवगम्बित था और मिद्धान्त तथा रूपरेखा म इतनी गृन्त थी कि उसम सङ्गोधन करना अथवा उसका पुधारना अभव था । <sup>३</sup> दूसरी ओर उम व द्वाय वग के अनुसार जा प्रमाण काग्रम पक्ष पर अधिमाधिक प्रमुख स्थान पाता गया प्रस्तावित योजना असन्तापप्रद और अमान्य था किन्तु काफी बड़ सङ्गोधन व बाद वह स्वीकार की जा सकती थी ।

किन्तु काग्रम व व द्वाय वग और माइरेटा की स्थिति म बहुत बड़ा अन्तर था—एव की दृष्टि म माण्टफोर्ड प्रस्ताव असन्तापप्रद और निराशाजनक व और दूसर का दृष्टि में व प्रगतिशील और तात्विक ध । तथापि (और यह बात विचित्र प्रतात हा ती कि) यह अन्तर गार्बिक था वास्तविक नहा । दोनों म वक्त्र दृष्टिकाण का अन्तर था तत्त्व का नहा । दोनों वगों न सङ्गोधन व लिए आ मुनाब दिए <sup>४</sup>

१ The Indian Annual Register, IV, page 131

२ Home Rules Manifesto, July 8 1918, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ११०

३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५५ म ६५ तक

उनमें बहुत बड़ा एक-सा-पन था। दोनों वम के द्रीय आसन में उत्तरदायित्व का अंग चाहते थे। दोनों ही प्रान्तीय म उत्तरदायी आसन का क्षत्र विस्तृत करना चाहते थे और प्रान्तीय अध्यक्षों के अधिकार कम करना चाहते थे। दोनों ने भारत-परिषद तोड़ने की ओर भारत सरकार पर नियंत्रण कम करने की मांग की। ऐसी परिस्थितियाँ में मुझ ऐसा प्रतीत होता है कि यदि माडरेटों ने कांग्रेस के विनाय अधिवेशन से अलग रहने का नियम न किया होता तो माण्टफोर्ड सुधारों के प्रश्न पर वायस म कट न पड़ी होती। किंतु माडरेट नेताओं ने अलग होने का और सुधारों को वार्यावित्त करने के लिए अपना स्वतंत्र दण बनाने का पहले से निश्चय कर लिया था।

माडरेटों के अलग होने की इस नाति के क्या कारण थे? मेरे मत में उसके लिए तीन बातें मक्यत उत्तरदायी थी।

पहला महत्वपूर्ण कारण माडरेटों का यह विश्वास था कि कांग्रेस में होम रुज के सदस्यों की प्रधानता थी जिन्होंने अपने आप को माण्टफोर्ड सुधारों का कट्टर विरोधी प्रकट कर दिया था। उन्हें इस बात का डर था कि कांग्रेस माण्टफोर्ड सुधारों को बिना अधिक विचार किए ही ठकरा वेगी और इस प्रकार उनकी स्थिति बड़ी भद्दी हो जायगी। अतः उन्होंने कांग्रेस के (अगस्त १९१८ के) विनाय अधिवेशन में सम्मिलित न होने का निश्चय किया।

यह सच है कि श्री तिलक श्रीमती बीसेण्ट और अन्य कांग्रेस-नेताओं ने आरम्भ में जो विचार प्रकट किए थे वे असमर्थ थे।<sup>१</sup> किन्तु कांग्रेस के विनाय अधिवेशन के समय तक उनके विचारों में परिवर्तन हो गया था और श्री तिलक श्रीमती बीसेण्ट और पण्डित मदन मोहन मालवीय जैसे विवेकपूर्ण नेतागण माडरेटों को कांग्रेस की परिधि में रखने के महत्व को अनभव करने लग थे। इसी कारण से कांग्रेस की विषय-समिति ने सुधारों के संबंध में एक समर्थ प्रस्ताव अपनाया।

- १ श्री तिलक ने माण्टफोर्ड रिपोर्ट को सूयहीन प्रभात बताया। श्रीमती बीसेण्ट के अनुसार इंग्लैण्ड और भारत दोनों ही के लिए अंगोभनीय थे। माननीय श्री पटेल के अनुसार रिपोर्ट में कुछ हद तक प्रतिपादनी प्रस्ताव किए थे। श्री केकर के अनुसार प्रस्ताव ऋर रूप से निराशाजनक थे। श्री जितेन्द्रनाथ बनर्जी के अनुसार सुधार अनुदार अधिकचरे अपर्याप्त और इसी कारण निराशाजनक और निष्फल थे। डा मुबहाण्य एयर ने अपने देगवासियों को यह सलाह दी कि उन्हें जो अफ्रीम दी जा रही थी वे उसका स्पष्ट भी न कर। *Athalye The Life of Lokmanya Tilak*, page 251 52 से अनूदित

सबसे बड़ा रोष श्री मुरन्दनाथ बनर्जी पर था जिन्हें दिसम्बर १९१७ तक 'काग्रस लीग याजना' का समर्थन किया था और जो एक निम्न अवधि के अन्दर स्वशासन के लिए माँग कर रहे थे ।

दश म माँडरेटा का स्थिति और भी बड़ा खराब थी, दश व आगे न उनकी नि-श की और उनकी विश्वासघाती तथा पद-दोलुप बनाया । अगले कुछ वर्षों में आम जनता में वे बहुत अग्रिम हो गए—सावजनिक सभाओं में उनकी व्याख्याना में विप्लव डाला जाता और बीच में बड़ा शोर मचाया जाता । इस प्रकार काग्रस और माँडरेटा के बीच की खाई पक्की और स्थायी हो गई । और जब प मोती लाल नेहरू ने पञ्जाब की दुःखद घटनाओं की पृष्ठभूमि में—जिनके सम्बन्ध में माँडरेटा और काग्रसिया में लगभग कोई मतभेद नहीं था—उन्हें अनृतमर-अधिबेदान के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने उसमें सम्मिलित होने में इन्कार कर दिया ।

१९१९ के आरम्भ में हमरुल क समर्थकों में भी फूट पड़ गई । उस समय तक श्रीमती बीमट बहुत हद तक माँडरेट हो गई थी । महात्मा गांधी ने रालेड बिदरका के बानून बनाए जाने की दशा में मत्पायह करने का प्रस्ताव किया था । श्रीमती बीमट उस प्रस्ताव के विरोध में थी । और उसी बात पर विच्छेद हुआ । उन्हें इंडियन हामरुल लीग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया किन्तु उनके व्यक्तिगत समर्थकों ने उन्हें राष्ट्रीय होमरुल लीग का अध्यक्ष चुन दिया ।

## ८

इस अध्याय का समाप्त करने में पहले इस बात का संक्षिप्त रूप में उल्लेख करना उचित होगा कि माँडरेटा-रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारतीय विधान-परिषद् के गैरसरकारी सदस्यों की क्या स्थिति थी । सर्वोच्च विधान-मंडल में 'माँडरेट' बहुमत में थे—काग्रस व वामपक्ष के केवल दो सदस्य (मि पटेल और मि खापड़) थे और काग्रस के केन्द्रीय वर्ग के केवल तीन सदस्य (मि जिन्ना, प मालवीय और मि मजबूल हक) थे—गण २० निर्वाचित और पाँच नाम-निर्देशित गैर-सरकारी सदस्य मध्यम पक्ष और पिछड़े हुए विचारों के व्यक्ति थे । ऐसी दशा में माँडरेटा व नेता द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रस्ताव का फल पहले में निर्दिष्ट था ।

६ दिसम्बर १९१८ का श्री मुरन्दनाथ बनर्जी ने भारतीय विधान-परिषद् में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया —

“(१) यह परिषद्, महामहिम बाइमराय और भारत मन्त्री का सुपारा न सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए धन्यवाद देती है और उन्हें भारत में उत्तरदायी शासन की प्राप्ति की दिशा में निर्दिष्ट प्रगति और वास्तविक प्रयत्न के रूप में स्वागत करती है ।



(२) यह परिषद सपरिषद् गवर्नर जनरल ने इस बात की सिफारिश करती है कि इस परिषद के सारे गवर्नर-सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाय जा सुधारों की रिपोर्ट पर विचार करे और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार में अपनी सिफारिश करे ।<sup>१</sup>

प्रस्ताव के पहले भाग का मि पटल जीर मि खापड़ न विरोध किया और उसकी प मालवीय और मि जिता न तीव्र आलोचना की । दूसरे भाग का सारे भारतीय सदस्यों ने समर्थन किया । वाणिज्य मंडल के दो यूरोपीय प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया । किंतु जसा कि प्रस्तावित था प्रस्ताव के दोनों भागों का गवर्नर-सदस्यों से पारण हुआ और माण्डफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने के लिए परिषद के गवर्नर-सदस्यों की एक कमेटी बनी । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी उसके अध्यक्ष हुए और श्रीनिवास शास्त्री उसके कायवाहक हुए । कुछ समय बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं — मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा । यद्यपि योजना में निश्चित प्रगति थी किंतु वह हमारी आशाओं की दृष्टि से कम थी । एक विषय के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से स्पष्ट थी कि द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और इसी बात पर हमने अपनी रिपोर्ट में और संयुक्त प्रवर-समिति के सामने अपनी गवाही और अपने प्रतिनिधियों में खास तौर पर जोर दिया ।<sup>२</sup> जसा कि मि रंगवुक विलियम्स ने कहा है कमेटी के काम का वास्तविक महत्त्व इस तथ्य में निहित था कि भारतीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों के मांडरेट पक्ष ने माण्डफोर्ड योजना को भारत के भावी दधानिक विकास का आधार मान लिया था ।<sup>३</sup>

## बाईसवां अध्याय

# अमृतसर का हत्याकाण्ड

१

सन् १९१९ ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है । सन् १८५७ के बाद १९१९ में पहली बार भारत में ब्रिटिश सत्ता को राष्ट्रीय परिमाण पर चिद्वज्रों की गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में ब्रिटिश

१ Bannerjee A Nation in the Making, page 310

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१४ ।

३ India in 1917-18, page 60

प्रतिष्ठा फिर स जमान के लिए अचन्त नीषण उपाय से काम लिया । लोका के हृदय में आतङ्ग जमान के लिए एक ब्रिटिश जनरल ने सहस्त्रा एकत्र गान्तिपूष नागरिका पर उस समय तक गोली चलान के लिए अपन सैनिका को आज्ञा दी जब तक कि उनकी गालिया ही समाप्त न हो जायें । य लोका एक धरे ग फँसे हुए थे और उससे बाहर निवृत्त का केवल एक ही सक्ता मा था बिधर से कि गोलियां चलाई जा रही थी । इस नीषण हत्याकाण्ड के फलस्वरूप सत्त्वा के धार्मिक केन्द्र (अमृतसर) के जलियाँवाला बाग में कई सौ आदमी मार गए और कई सौ आदमी घायल हुए । प्रान्त के पांच जिला में फौजी कानून घोषित कर दिया गया । लोका को आतङ्गित करने के लिए दो बार हुवाई जहाजा को बाम में लाया गया और ब्रिटिश अधिकारिया ने फौजी कानून को पूर्ण बबरता के साथ लागू किया । तथापि उसी वर्ष प्रान्तों में उत्तरदायी शासन आरम्भ करने के उद्देश्य से गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट, १९१९ का पारण हुआ ।

किन्तु सन् १९१९ में हो स्थायी महत्व की दो घटनाएँ और हुई—

(१) महात्मा गांधी ने देश के सावजनिक जीवन में प्रवेश किया और वे तुरन्त ही अखिल भारतीय नेता हो गए और (२) अत्याचार और परिवाद को दूर करने के लिए लोका को सावजनिक सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया गया ।

२

इस प्रकार सन् १९१९ में भारत में बिगड़कर पञ्जाब में खूबदस्त राज नतिक उथल-पुथल हुई । इस दुःखद परिस्थिति के लिए कई बात उत्तरदायी थी किन्तु उन सबको तीन मुख्य—आर्थिक, प्राकृतिक और राजनतिक शीपका में बाँटा जा सकता है ।

यूरोपीय महायुद्ध को जीतने के लिए भारत ने जन धन और सामग्री के रूप में जो महान सहायता दी थी उन पर्याप्त रूप में स्वाकार किया गया है किन्तु इस बात की बहुत कम लोका को जानकारी है कि युद्ध के कारण भारतीय जनता को नयकर बर्ष उठान पड़ था ।

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उस समय भारत की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी और पहले उध कर्षों में सरकार का कर बडान की आवश्यकता ही नहीं अनुभव हुई किन्तु १९१६ में २६ लाख पौड का घाट का पूरा करने के लिए सीमा शुल्क बडान पड़ । यह वृद्धि नूती माल पर नहीं की गई और बिदरा में आन बाल तथा भारत में बन हुए बपड पर ३३ प्रतिशत का शुल्क बधावन् रखा गया । युद्ध के दिना में पुरान बिवाद का बचन के उद्देश्य में भारत मन्त्री की आज्ञा पर ही नूती माल का छूट दी गई । किन्तु अगल वर्ष और ज्यादा टनस बडान की आवश्यकता

स्थिति में फँस गया और उसकी यद्ध विजय के तिलतिल में भारत के बहिर्दानी में गणना की जा सकती है । <sup>१</sup>

आर्थिक जीवन की अव्यवस्था और दैनिक उपयोग की चीजों की कमी और उनके बढ़ हुए दामों के कारण भारत में गाँव और गाँव दोनों स्थानों में असाधारण कष्ट हुए और उसके कारण देश में अगान्ति बढ़ी । औद्योगिक देशों में मजदूरी की हड़ताल एक साधारण बात हो गई और देश के विभिन्न भागों में कष्टापीत लोग न बाज़ारों को लुटा ।

कृषक अगान्ति के दो प्रदेश—एक चम्पारन (बिहार) और दूसरा खड़ा (गजरात)—विशेष रूप से उत्प्लक्ष्ण है ।

चम्पारन की कृषक-समस्या काफी पुरानी थी किन्तु १९१७ में वह बहुत तात्क्षण्य हो गई । बाज़ार में रासायनिक उद्योग सधन हुए सस्ते रब मिश्रण के कारण नील की खती अभिप्रेत नहीं रही थी किन्तु यूरोपियन रोपका न बन्धोपाजन का एक नया ढंग निकाला था । उन्होंने बग़ाँज काँतकारी एकट की एक धारा का लाभ उठाकर काँतकारी के लगान ४५ से लेकर ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिए और उन्हें नील की खती करने में छूट दे दी । यह बढ़ी जागरहवागी के नाम से परिचित है उन गाँवों में की गई जिनमें गाँववाला का ज़मीन में स्थायी पट्टा था और उसकी कुल रकम लगभग ३ लाख रुपये प्रति वर्ष थी । जहाँ रोपका के अस्थायी पट्टे पर वहाँ उन्होंने एकमुत्त रकम गन पर जोर दिया । बाबू राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है —

बिल्कुल ठीक आबड ता नहीं मिल सके किन्तु इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि केवल इसी मद के अन्तर्गत जा रकम वसूल की गई थी वह १६ और २० लाख रुपये के बीच में थी । <sup>२</sup>

लगान में बढ़ी और एकमुत्त रकम की भाँग के कारण चम्पारन के किसानों का जिनसे अब अवधि रकम बलात ली जाती थी बढ़ी भारी कठिनाई हुई । रोपकण विभिन्न प्रकार के अववाव लेते थे <sup>३</sup> किसानों में बहुत कम मजदूरी पर बग़ार करते

१ Rajendra Prasad The Agrarian Problem in Champaran, Hindustan Review July 1918, page 52

२ उपर्युक्त भाषिक पत्र पृष्ठ ५२

३ निम्नलिखित अववाव बग़ार गिन जानें — पाना खर्चा (सिंचाई काटक्स) पाँडा खराबन का खर्चा (पाँडाही) हाथी मरोदन का खर्च (हथियाहा) माँटर खराबन का खर्च (माँटरही अथवा हवाही) - तेर अथवा ईश क काटू खराबन काटक्स (काटूआवन) बाटू खराबन का खर्च (बाटू खपार)

ये और उनकी गाड़ियों और उनके जानवरों से काम लेते थे । १९१६ तक किसानों के कष्ट असह्य हो गए । बिहार विधान-परिषद् में उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया किन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ । कांग्रेसी नेताओं से हस्तक्षेप करने की अपील की गई । अन्त में मि गांधी ने चम्पारन जाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के लिए कहा गया ।

मि गांधी अप्रैल १९१७ में चम्पारन पहुँचे और किसानों की शिकायतों की विस्तृत रूप से जाँच आरम्भ की । उन्हें उस जिले को छठा दिन के लिये सरकारी सूचना दी गई जिसको उन्होंने उपेक्षा की, किन्तु बाद में प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से वह सूचना वापिस ले ली गई ।<sup>१</sup> मि गांधी की छानबीन के फलस्वरूप<sup>२</sup> सरकार ने एक जाँच कमेटी नियुक्त करने का निश्चय किया जिसमें मि गांधी भी एक सदस्य थे और सर फ्रैंक स्लाई उसके अध्यक्ष थे । कमेटी ने अपना काम ठीक ढंग से किया और सभी सदस्या द्वारा अनुमोदित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । उसी के आधार पर १९१८ का चम्पारन क्रुपक-ऐक्ट बनाया गया । तिनकठिया प्रथा का अन्त किया गया, शरहबशी २० से लेकर २५ प्रतिशत तक कम की गई और जो एकमुदत रकमें ली गई थी उनका २५ प्रतिशत भाग किसानों को वापिस दिलाया गया और माघ ही अबबाव लेना बर्जित कर दिया गया । कार्यकारिणी अधिकारियों को अपराधी जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्राधिकार दिया गया ।

चम्पारन जाँच कमेटी का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि महात्मा गांधी को अपने प्रान्त में जाना पड़ा । १९१७ में अतिवृष्टि के कारण जिला लडा (गुजरात) में फसलों की बहुत बड़ी क्षति पहुँची थी । इस क्षति के परिमाण के सन्निध में सरकारी और गैरसरकार आगणन में काफी अन्तर था, और भालगुजारी में छूट उस परिमाण के आधार पर ही होनी थी । पट्टीदारों के आगणन से फसल चौपाई हुई थी और भालगुजारी में २३ लाख रुपये की छूट की आवश्यकता थी । दूसरी ओर जिले के कलक्टर ने केवल १७५००० रुपये की छूट दी थी । सरकार के समक्ष कई बार प्रतिनिधित्व किया गया कि पट्टीदारों के साथ न्याय किया जाय

उत्तराधिकार के समय पर सामन्तवादी नजराना (बपाही पिताही), विधवा विवाह ( सगौग ), और दधहरा, चेतनवमो बादि पर नजराना ।

१ इसका पूरा वृत्तान्त महात्मा गांधी की आत्म कथा में दिया गया है — My Experiments with Truth Vol II pages 355 to 407

२ मि गांधी ने लगभग १३०० किसानों के बयान एकत्र किए ।

Hindustan Review, July 1918, page 51

वित्त उसका कोई फल नहीं हुआ। महात्मा गांधी लिखते हैं — जब सारी प्रापनाओं और निवेदनों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो मन सहयोगियों से परामर्श करने के बाद पन्नादारी की सत्याग्रह को गरण लेने की सलाह दी।<sup>१</sup> इस प्रकार मि गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आरम्भ किया।

खंडा के विमर्शना से यह प्रतिज्ञा करने का कहा गया कि वे सरकार का मालगुजारी नहीं दें तथाकि फसल चौमाई में भी कम हुई थी। वित्तु यदि सरकार सारे जिले में दूसरी निर्धारित कित्त की उगाही छोड़ने का तयार हो जाए तो वे लोग जिनके लिए यह संभव हो अपना पूरा अवकाश मालगुजारी देंगे।<sup>२</sup>

२८ मार्च १९१८ को सत्याग्रह आरम्भ किया गया। सर गकरन नगर में लिखा — सरकारी मालगुजारी का भुगतान नहीं किया गया। घरेलू बतना दुधारू गाया और अन्य सम्पत्ति को आसजित किया गया। सरकार ने उमीन का उध्व करने की आज्ञा जारी की और सरकारी अधिकारियों ने मालगुजारी वसूल करने के लिए सभी सनव उपायों में काम किया। १२ अथवा १३ अप्रैल को स्वयं कमिश्नर ने किसानों की एक सभा को और उनको सरकारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए समझाया। उत्प्रेषण करने की बातों का भयंकर परिणामों की धमकी दी और उनसे कहा कि वे अपने सलाहकारों, हामरुल बाबा की बातों पर ध्यान न दें जिन्हें मालगुजारी न देने के फल स्वयं नहीं भागने पड़ें। वित्तु किसान अपने निश्चय पर जम रहे।<sup>३</sup> यहाँ तक कि गाँव के मुखिया भी सरकारी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया। २५ अप्रैल को सरकार ने मालगुजारी की उगाही का निश्चय कर दिया और इस बात का आश्वासन दिया कि केवल वही लोग जिनके लिए संभव हो उस समय मालगुजारी दें और अन्य सब लोग अगले वर्ष उसका भुगतान करें। वित्तु विचित्र बात यह है कि उनके आना ३ जून तक प्रचारित नहीं की गई। उस समय तब सम्पत्ति का कुर्की और अन्य सरकारी बायबाहियाँ का प्रेम जारी रहा।<sup>४</sup> मि गांधी को स्वयं विमानों से सरकारी नियमों का पकड़ ही पता लग गया और अधिकारियों के अमृतोपद्रवों के हाथ हुए भी सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त कर दिया।

१ Gandhi My Experiments with Truth Vol II page 430

२ उपर्युक्त पत्रिका पृष्ठ ४३१।

३ The Indian Annual Register 1919 Part IV, page 83

४ The Indian Annual Register 1919 part IV, page 84

यद्यपि महात्मा गांधी आन्दोलन के फल और किसानों के भाव से सतुष्ट नहीं थे तथापि उनके मत से खड़ा-आन्दोलन देश के लिए पराक्षर रूप से बहुत लाभदायी था और उससे गुजरात के किसानों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। “खड़ा-सत्याग्रह से गुजरात के किसानों की जागृति और उनकी सच्ची राजनैतिक जिज्ञा आरम्भ हुई। गुजरात के सावजनिक जीवन में नई शक्ति और नए साहस का संचार हुआ। पटीदार किसानों की अपनी शक्ति का बोध हुआ। सावजनिक मस्तिष्क पर इस पाठ की अमिट छाप पड़ी कि लोगो का उद्धार उनके त्याग और चरित्रानुसार की सामर्थ्य पर निर्भर है। खड़ा आन्दोलन से गुजरात में सत्याग्रह की जड़ मजबूत हो गई।”<sup>१</sup>

सन् १९१८-१९ में अनाज प्लेग और इन्फ्लुएन्जा की दैवी विपत्तियाँ न उपयुक्त आर्थिक कारणों के साथ मिलकर लोगो के कष्टों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।

## ३

सन् १९१८-१९ में भारत में वर्षा १९ प्रतिशत कम हुई। ऐसा कोई प्रान्त नहीं था जहाँ वर्षा की थोड़ी या बहुत कमी न हुई हो और इसका परिणाम यह हुआ कि फसल बहुत खराब हुई—यहाँ तक कि पिछली दशाब्दी में इतनी खराब फसल नहीं हुई थी।<sup>२</sup> सरकार के सारे प्रयत्नों के होते हुए भी बढ हुए दामों और नाज की कमी के कारण लोगो को भवणनीय कष्टों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों की सब से प्रबल चोट निम्न वर्गों पर हुई और साथ ही उन लोगो पर भी जिनकी अल्प और निश्चित आय थी और जो शहरों में रहते थे।<sup>३</sup>

१९१७ की भाँति जहाँ-तहाँ उपद्रव हुए और बाजारों में लूट मार भी हुई।<sup>४</sup>

इस दुर्दशा के वातावरण में प्लेग और इन्फ्लुएन्जा की महाभारियों का प्रकोप हुआ। (संभवतः) अतिवृष्टि के कारण १९१७ में प्लेग अत्यन्त उग्र रूप में प्रकट हुआ और जुलाई १९१७ से जून १९१८ तक देश में प्लेग के कारण ८ लाख से अधिक व्यक्ति मर गए। देश के विभिन्न भागों में मलरिया और हंजा फैल जाने के कारण यह मृत्यु-संख्या और भी ज्यादा हो गई। सन् १९१७ में ही भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की साधारण दशा काफी बुरी थी किन्तु १९१८ में वह और भी

१ Gandhi My Experiments with Truth Vol II pages 44-42

२ India in 1919, page 64

३ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६७

४ India in 1917-18, page 90

जगदा विगड गई। अस्तु जून १९१८ में इंग्लैण्ड के प्रचंड रूप का पता लगा।<sup>१</sup> यह महामारी बम्बई में आरम्भ हुई और कुछ ही समय में सारे देश में फैल गई। चार-पाँच महीने के अन्दर ही देश में इस महामारी के कारण ६० लाख से अधिक व्यक्ति मर गए।

यद्यपि मृत्यु-सम्बन्धी उपर्युक्त आकड़ अत्यन्त भयावह हैं तथापि उनसे लोगो के वास्तविक चष्टो का चित्र प्रस्तुत नहीं हो सकता। महामारी से जो लोग प्रभावित हुए थे उनका अनुपात कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से लेकर अस्सी प्रतिशत तक था किन्तु चिकित्सा का प्रबन्ध अत्यन्त अपर्याप्त था। लोगो को आर्थिक स्थिति भयावह थी। नाज के दाम लोगो को बिसात के बाहर थे और चारे की कमी के कारण दूध का प्राप्य परिमाण बहुत कम हो गया था — 'पोषक भोजन बम्बल और गरम कपड़े के दाम बहुत ज्यादा बढ़ हुए थे।' फलतः जो लोग बीमारी से ठीक हो गए थे वे बहुत समय तक अपना साधारण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सके। इन सब कारणों ने लोगो के विशेषकर पश्चिमी उत्तरी और केन्द्रीय भारत में लोगो के चष्टो को अत्यन्त तीक्ष्ण कर दिया।

४

इस प्रकार १९१७ और १९१८ में भारत भयंकर विपत्तियों का सामना कर रहा था, और उन विपत्तियों के कारण सारे देश में असाधारण तीखापन था। राजनैतिक कारणों से यह तीखापन कई गुना बढ़ गया।

देश में, विशेषकर बंगाल में सरकार की दमनकारी नीति के कारण प्रबल असन्तोष था। शान्तिकारी अपराधों का दमन करने के लिए भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत से नवयुवकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। नजरबन्दा का साथ दुर्भवाहार के और उन्हें अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में रखने के आदेश दिए गए। तीन मामलों में सम्बन्ध में—गारे देश में—विशेषकर बंगाल में—बड़ा रोष फैला। पहले दो मामले एक-सं थे—उनमें से एक प्रोफ़ेसर ज० सी० घोष से संबंधित था और दूसरा मि एस एन गठ से। प्रो० घोष का एक एक्जाल्ट वीठरी में बंद कर दिया गया था जिसके कारण उन्हें बड़े चष्ट उठान पड़ बाद में वे पागल हो गए। यही बात मि० गठ से मामला में हुई। तीसरा मामला बहुत विचित्र था। बाकुरा ज़िले के पुत्रिस सुपरिस्पेण्डेंट से तार द्वारा यह कहा गया कि वह शाहबाजपुर बाँव के नामनवीय पोष के मजान में मिथुवांग देवी की गिरफ्तारी कर ल—जिसका नाम और पता एक 'भयंकर' शान्तिकारी के नागड़ा में एक पर्व पर गिना हुआ पाया गया था। उस अधिकारी का नामनवीय घोष से मजान तो नहीं मिला पर उस कुञ्जपोष

नामक व्यक्ति के यहाँ एक सिधुवाला नामक स्त्री का पता लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिधुवाला से यह पता लगा कि उसकी भाभी का नाम भी सिधुवाला था। गलती का कोई अवसर ही न हो, इस विचार से पुलिस सुपरिन्टेंडेंट देवेन्द्र घोष के गांव गया और उसने दूसरी सिधुवाला को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों स्त्रियों को बाकुरा ले जाया गया जहाँ वे रात में ग्यारह बजे पहुँची और उन्हें थाने तक पैदल चलने को बिबश किया गया। दूसरे दिन, ६ जनवरी १९१८ को उन्हें जेल भेज दिया गया। पन्द्रह दिन बाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं था और वे भूल से गिरफ्तार कर ली गई थी।

जिले के दो विभिन्न गाँवों से, बिना निश्चित सूचना के और बिना आवश्यक जांच किए हुए, दो पर्दानशीन स्त्रियों को गिरफ्तारी से, चारों ओर क्रोध का उफ़ान आया। कलकत्ता में और अन्य स्थानों में विरोध-सभाएँ की गईं और इस सत्रध में बंगाल विधान-परिषद् में भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सारे देश में, विशेषकर बंगाल में बड़ा भारी तीखापन छाया हुआ था और सरकार ने असतोष का शमन करने के उद्देश्य से, नज़रबन्दों के अभियोगों के पुनरीक्षण के लिए एक कमेटी नियुक्त की—मि० जस्टिस बीच फ्रीफ्ट और मर नारायण चन्दावरकर इसके सदस्य थे।

बीच फ्रीफ्ट कमेटी ने कुल ८०६ मामलों का पुनरीक्षण किया। इनमें से १०० बन्दीयों के मामले सन् १८१८ के विनियम न० ३ के अन्तर्गत थे, ७०२ व्यक्ति भारत रक्षा संकेत के अन्तर्गत नज़रबन्द थे; और ४ व्यक्ति 'भारत प्रवेश' अध्यादेश के अन्तर्गत बन्दी थे।<sup>१</sup> कमेटी इस परिणाम पर पहुँची कि सरकार के पास जो प्रमाण थे उनके अनुसार ८०० व्यक्तियों की नज़रबन्दी न्याय्य थी। कमेटी ने शेष छैः नज़रबन्दों को छोड़ देने की सिफारिश की।

किन्तु बीच फ्रीफ्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहिले ही, अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन के नाम सर मुबद्दाय्य ऐयर के पत्र के मामले ने भारतीय क्षेत्रों में सनसनी पैदा कर दी।

यह पत्र जून १९१७ में लिखा गया था और दो अमेरिकन चियांसोफिरटो—होचर दम्पति के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। उस पत्र में कहा गया था कि यदि भारत को स्वतन्त्रता का वचन मिल जाय तो युद्ध के लिए भारत से १ करोड़ आदमियों को भर्ती हो जायगी। पत्र में ब्रिटिश राज्य की तीव्र आलोचना की गई थी। वाइसराय और भारत-मंत्री ने, राजनैतिक सुधारों के सिलसिले में सर

१. See Lowett: A History of Indian Nationalist Movement, page 196.



मुद्रहण्य एयर के उनसे भेंट करने पर, उनमें बड़ी फटकार लगाई। यह बात भारत-मन्त्री न इस सबब में पार्लियामेन्ट में प्रश्न पूछे जाने पर व्यक्त की।

इस पर सर मुद्रहण्य न समाचार-पत्रों में एक पत्र प्रकाशित किया और उन्होंने अपना निवृत्ति वेतन छोड़ देने की तत्परता प्रकट की। उन्होंने मद्रास सरकार के मुख्य वायेंवाह को एक पत्र लिखा और वे० सी० आई० ई० तथा दोथान बहादुर की अपनी उपाधिया का परित्याग कर दिया।

इस घटना से भारत में बड़ी हलचल हुई और सारे देश के राष्ट्रवादी पत्रा न सर मुद्रहण्य की प्रशंसा की।

५

लोक-सेवाओं के सबब में इन्स्टिट्यूट नमोशन की रिपोर्ट और बंधानिक सुधारों के सम्बन्ध में माण्टफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होने पर राजनैतिक असन्तोष और उपादा बढ़ गया। सन् १९१८-१९ में सर्वसाधारण यह अनुभव करने लगा था कि 'युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारतीय आकाशाओं और विशेषकर राज-नैतिक सुधारों के प्रति, सरकारी और गैर-सरकारी यूरोपीय समुदाय का भाव बदल गया था।' १ प्रान्तीय गवर्नरों और बाइसराय के व्याख्यानों में यह धारणा दृढतर हो गई। उसी समय जातीय उद्दता और असहिष्णुता की कई घटनाएँ हुईं। मि. हुसैन इमाम बलबत्ता हार्डवोट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे और अगस्त १९१८ के विशेष कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मि. कलेटन आई सी एस ने (जो बिहार सरकार के एक उच्च अधिकारी थे) और जो मि. हुसैन इमाम के साथ रेल में एक पहली धोनी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, उनको गालियाँ दी और उन पर हमला किया। इस घटना में सारे देश में तीखापन बढ़ना स्वाभाविक ही था। किन्तु प्रोच और तीखापन का शिखर तब पहुँचाने का काम रॉलिट-रिपोर्ट और रॉलिट-विधेयकों ने किया। भारतीय सैनिका को मित्र राष्ट्रा के राजनीतिज्ञों ने अपने व्याख्यानों में बहुत-सी आशाएँ दिलाई थी। भारत लौटने पर उन्हें दूसरा ही दृश्य दिखाई दिया। जब वे पंजाब में अपने घर पहुँचे तो उन्हें अकाल, बंठनाई और निरन्तर राज्य का वातावरण मिला। राउट-विधेयकों के रूप में उनका स्वागत करने की तैयारियाँ की जा रही थी। ऐसा प्रतीत होना था कि ये विधेयक खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए जा रहे थे—रॉलिट बमेटी ने स्पष्ट बतलाया कि बिदेसों से बहुत बड़ी सैनिका में सैनिका के लौटने पर जो परिस्थिति सम्भवत उत्पन्न हो सकती थी, उसी का सामना करने के लिए विशेष दमनकारी बानूना की आवश्यकता थी।

किन्तु रॉलिट-रिपोर्ट और विधेयकों के सबब में चर्चा करने से पहले, खिलाफत

क प्रश्न पर मुस्लिम आदोइन और पजाब में सर माइकल आ डायर क उग्र गतिन में उत्पन्न विगप परिस्थितिमा क कारण कुछ विवरण देना उपयुक्त होगा।

तुर्किस्तान के आमंत्रण भाग्य और खरीफा की स्थिति पर उसके प्रभाव के संबंध में भारतीय मुसलमानों में बड़ी उद्विग्नता थी। तुर्किस्तान-सहित अथ वंश्रीय गतिनया को परास्त करने में भारतीय मुसलमानों ने भी पूर्ण हाथ बैठाया था। ब्रिटिश राजनोतिन द्वारा उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि युद्ध समाप्त होने पर गण्ट्रीयना और आम निगव के मिद्वान्ता का तुक प्रदत्ता पर भाग गिया जाएगा और खरीफा की स्थिति के संबंध में यूरोपीय गतिनया कोई हस्त रय नहीं करेगी। किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद विभिन्न प्रकार की बात सुनाई पड़ी कि तुर्किस्तान को कई भागों में बांट दिया जाएगा और उन प्रान्तों का जिनमें मुसलमानों का धार्मिक स्थान था और मुस्लिमों के आधिपत्य में रखा जाएगा—और इन सब बातों के साथ खिगफन का प्रश्न मिग हुआ था। ये सारी बात भारतीय मुसलमानों को चिन्ता में डाल हुए थी और उनमें मुसलमानों में असंतोष बढ़ रहा था। मि माण्टगु के अनुसार भारत की दुष्टटनाओं का पहला राजनितिक कारण तुर्किस्तान के संबंध में मुस्लिम दृष्टिकान था।<sup>१</sup>

किन्तु भारतीयों के अनुसार उन दुष्टटनाओं का अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पजाब में सर माइकल ने अपने उग्र गतिन से प्रबल असंतोष फैला दिया था।

पजाब के युद्धरागीन उप-मवनर को कठोर व्यक्तिगत राज्य में दंड बिश्वास था। उसके अनुसार सरकार का मुख्य काम कानून और व्यवस्था को देनाए रचना था। उसे कानूकारिणी परिपदा और राजनतिक सुधारों में कोई बिश्वास नहीं था। गेना की उच्च राजनतिक आकांक्षाओं के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी। जिन नौकरियों और अधिकारों के लिए शार मचान का शिक्षित वग उसे बुरे मागूम होत था और उनसे महत्व को घटाने के लिए वह प्रत्येक अवसर का काम उठाता था। यद्ध के दिनों में उसने निदयतापूर्वक दमन किया और रुहमाय सिक्क और श्री विपिनचंद्र पाठक जस प्रतिष्ठित नेताओं के प्रात में प्रवेग करने पर रोक लगा दी। और उसकी यह बहुत बड़ी आनाक्षा थी कि युद्ध जीतने के लिए अथ प्रान्तों की अथ उस प्रान्त में जन धन और सामग्री का संग्रह अधिक समाधान हो। किन्तु इस उद्देश्य के लिए बहुत से अवसर पर बलात् भर्तों की गई

१ Speech of Mr Montagu on 22nd May 1919 in the House of Commons The Indian Annual Register, Part II, page 123

और लोगों को बड़ कष्टों का सामना करना पड़ा। जना कि मुजफ्फराबाद के नर न्यायाधीश मि कोल्डस्पीन ने लिखा— 'मुझे सच उाहने के लिए और मुनिका का भर्ती करने के लिए जा उपाय काम में लाया गए व बहुधा अनधिकृत आपत्तिजनक अत्याचारपूर्ण और सरकार की इच्छा के विरुद्ध थे। दूर के जिला में वे लाया की असह्य थे।' गाहपुर जिले में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। वहाँ के एक प्रति उत्साही तहसीलदार सचद नादिर हुसैन ने अल्पसंख्यक आपत्तिजनक<sup>१</sup> और अत्याचारपूर्ण उपायों में काम लिया और स्वयं सर माइकेल के अनुसार उनका डरा बलात् भर्ती की तरह था। साथ ही न बरे हुए लाया न उसकी हत्या कर दी। प्रान्त जिले के लिए मुनिका का मर्यादा मुद्रा और चंदे की रकम निर्दिष्ट कर दी गई थी और उस सत्या अथवा रकम का पूरा करने के लिए हर सम्भव उपाय का काम में गया गया। और सबसे ज्यादा चुनन वाली बात यह थी कि लाया को इन गिकायतों के विरुद्ध आवाज उठाने को आना नही था। उसकी राजद्रोह में गिनता थी और सर माइकेल की सरकार उसका निदयतापूर्वक दमन करने पर तैयार हुई थी। माइकेल ही ज्ञान के बाद १९२२ में भीमती बोसलेट ने लिखा— 'सर माइकेल का कठोर और अत्याचारपूर्ण गानन, बलात् भर्ती और मुद्रा का उगाही और मारे राजनैतिक नेताओं का निष्ठुर अदन—य सब बातें ऐसी थी जिहान तीक्ष्ण की चिन्तारिया का जाबित रहा जिनमें आ की लपट बिभी नी समय फूट सकता था। बम्बई में १९१८ के विषय अधिवान में पञ्जाब के प्रति निधिया ने हम बताया था कि प्रान्त के लाया एक ज्वालामुखी के ऊपर रहे रहे थे जो जिनो नी असाधारण अत्याचार के काम में फूट सकता था। इस कारण जब १९१९ में उनी प्रान्त में उपद्रव हुए तो हम कोई आश्चर्य नही हुआ।'<sup>२</sup>

६

१९१९ में नावजनिक उन्नाड का ताल्कालिक कारण था—रॉलिट अथवा बाल विषयका का कारण। १९१७ के अन्त में न्यायाधीश एस ए टी रॉलिट का अध्यक्षता में भारतीय राजद्रोह कमेटी नियुक्त की गई थी। उनमें अप्रैल १९१८ में अपना रिपोर्ट दी। कमेटी ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए उन नार प्रमाणों का जांच का जिनके आधार पर भारत रक्षा एक्ट के समान हीन पर दान्तिवारा अपराधों में निपटने के लिए विषय विधान बनाने का कहा गया था। कमेटी ने अपना नारा काम गुप्त रूप में किया। अस्तु मि माण्डू ने एन विषय विधानों के मकल के

१ Congress Punjab Inquiry Committee Report, vol I Page 18

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १९।

३ Besant The Future of Indian Politics, Page 236

प्रति मि रॉगिट को सावधान कर दिया था और उस सबध में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को स्वीकार करन के बारे में चेतावनी दे दी थी। मि माण्टगु न लिखा है — मन उहे बताया था कि नजरबन्दी और पुलिस की सहायता से सरकार का काम चलाय के दंग से हम सम्भवत अपन उत्तराधिकारियों के लिए परेगानियों पदा कर दंग और मन यह आगा प्रकट की थी कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना में से वह उसी बात को स्वीकार करण जो सासदिक रूप से रक्षणीय हो।<sup>१</sup> किन्तु राउट कमटी इस निष्पत्ति पर पहुची कि नान्तिकारी अपराधों से निपटन के लिए साधारण फौजदारी कानून अपर्याप्त था और उसमें दो प्रकार के बिगप बिधान बनान की सिफारिश की—एक दण्डात्मक और दूसरा प्रतिबन्धक। भारत सरकार ने कमटी की सिफारिश को रूप देने के लिए दो विधयक बनाए। सभी जगह विरोध प्रकट किया गया सरकार को सावधान बिया गया किन्तु सरकार ने उन विधयकों को एक्ट बनान के सयध में अपना निश्चय नहीं बदला। अन्त में उनमें से केवल एक विधयक ही एक्ट बना किन्तु उसके कारण एक देशव्यापी उथल-पुथल हुई जो उस समय तक भारतीय इतिहास के लिए नई चीज थी।

इस कानून का सरकारी नाम था—अराजकतापूण और नान्तिकारी अपराध एक्ट। यह एक्ट सामाजिक अधिकार और भारतीय राजनतिक जीवन दोनों ही का दमन करने के लिए बनाया गया था। किन्तु दूसरे पक्ष के मतानुसार इस एक्ट का उद्देश्य राजनीति का गोधन<sup>२</sup> और अराजकता तथा नान्ति से लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना था।<sup>३</sup>

यह एक्ट पांच भागों में बांटा गया था। पहला भाग दण्डात्मक था दूसरे और तीसरे भाग प्रतिबन्धक थे चौथे भाग में उन अपराधी लोगों को एक्ट के अंतर्गत लाया गया था जो पहले से ही सरकारी नियन्त्रण में थे और पांचवें भाग में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि यदि एक्ट अथवा उसका कोई भाग किसी बिगय क्षण में गमून रहे तो भी जो आवश्यकियाँ पहले ही जारी हो गईं हों उन्हें पूरा कर दिया जाय।

१ Montagu An Indian Diary, page 156

२ Speech of Sir William Vincent See Punjab Unrest Before and After, page 5

३ Speech of Sir Michael O'Dwyer of April 10, 1919 Pearey Mohan The Imaginary Rebellion and How it was Suppressed, page 13

पहले भाग में अपराधों के संवर्धन में शीघ्र अभिनयों निषेध की व्यवस्था की गई थी और उसके विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं था।<sup>१</sup> किसी प्रान्त में पहले भाग के लागू कर दिए जाने पर हाईकोर्ट के तीन जजों का एक विधायक न्यायालय बनना था जो अपना काम कहीं भी और साथ ही गुप्त रूप से कर सकता था। इस न्यायालय में ऐसे प्रमाण भी मान्य थे जो इंडियन एविडन्स ऐक्ट के अनुसार ग्राह्य नहीं थे। निषेध जजों के बहुमत से होता था और वह अन्तिम था। किन्तु प्राणदण्ड देने के लिए सारे जजों का एकमत होना आवश्यक था।

दूसरे भाग के अनुसार प्रान्तीय सरकार का अधिकार था कि यदि उस किसी व्यक्ति के बारे में यह विश्वास हो कि उसका किसी ऐसे आन्दोलन से संवर्धन है जिससे राजसत्ता के विरुद्ध अपराध होना की संभावना हो तो वह उसको अमानत देने के लिए अथवा अपना पता देने के लिए अथवा किसी विशेष स्थान में रहने के लिए अथवा किसी निर्दिष्ट काम से दूर रहने के लिए अथवा धान में अपनी हाजिरी देने के लिए आज्ञा दे सकती थी।<sup>२</sup> आरम्भ में यह आज्ञा केवल एक महान के लिए होती थी किन्तु जॉन कमटो की रिपोर्ट पर वह एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती थी। इस जॉन कमटो में (प्रत्येक मामले के लिए) सरकार द्वारा तान संदस्था की नियुक्ति होना थी। कमटो का काम गुप्त रूप से होना था और संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर सफाई पत्र कर सकता था किन्तु उस वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं था।

तिसरा भाग और भी ज्यादा कठोर था। उसमें किसी भी स्थान की तलाशी और बिना वारण्ट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी और उस किसी नियत स्थान में निश्चित गतों के आधीन रहने की<sup>३</sup> व्यवस्था थी। आरम्भ में इस नज़रबन्दा की अवधि एक वर्ष तक सीमित थी किन्तु बाद में यह तीन वर्ष तक हो सकती थी। दूसरे भाग का तरह इसमें भी जाच-बमडा की व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार के अनुसार भारत में अराजकनावादी और प्रान्तिकारी अपराधों का सामना करने के लिए एकट की उपयुक्त धाराएँ अत्यावश्यक थी। सन् १९०९ और १९१८ के बीच प्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण ३११ अपराध अथवा अपराध के प्रयत्न हुए थे जिनमें १०३८ व्यक्ति संबंधित थे। भारत रक्षा एकट में अपराधों की संख्या घटाकर १० प्रतिवर्ष कर दी थी और १९१८ के

१ Punjab Unrest Before and After, page 3

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ८।

३ Section 34 (I) of the Act, India in 1919, page 213

पिछले तीन महीनों में कोई शान्तिकारी अपराध नहीं हुआ था ।”<sup>१</sup>

भारतीय विधान-परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों ने विधेयक की सामर्थ्य पर सन्देह नहीं किया किन्तु उन्होंने शान्तिकाल में कार्यकारिणी को राजनैतिक जीवन का दमन करने के लिये असाधारण अधिकार देने का और सदस्य व्यक्तियों को चुले और विधिवत् अभियोग निर्णय से बचित करने का प्रबल विरोध किया। शान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए, पहले से ही विस्तृत अधिकार मिले हुए थे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि समस्या का वास्तविक हल, निर्दयतापूर्ण दमन के स्थान पर राजनैतिक सुधार था। स्वयं लॉर्ड मार्ले के अनुसार ‘सिन फोन से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय, आयर्लैण्ड को स्वशासन देना था।’ गैर-सरकारी सदस्य ने सरकार से अपील की कि वह “पिछले कुछ दिनों से बराबर बिगड़ती हुई स्थिति पर ध्यान दे, वह स्थिति भविष्य के लिए सफ़टपूर्ण थी।” सर तेजबहादुर सप्रू ने कहा — “श्रीमान् सारे देश में रोष छाया हुआ है, विभिन्न स्थानों पर विरोध सभाएँ हो रही हैं।

इस नीति से देश एक भयंकर आन्दोलन की भवरा में फँस जायगा ।”<sup>२</sup> किन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के समुक्त विरोध के होते हुए भी—जिनमें से चार सदस्यों ने विरोध में त्याग-पत्र भी दिया —सरकार ने कानून बनाया जिसके परिणामा पर सर्वत्र द्योत प्रगट किया गया।

७

जिन दिनों भारतीय विधान-परिषद् में रॉलिट विधेयको पर विवाद हो रहा था, उन्ही दिनों महात्मा गांधी ने बाइसराय को पत्र लिखा और यह स्पष्ट कर दिया ‘कि सरकारी नीति के कारण मेरे लिये सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया है।’<sup>३</sup> कम्बई में सत्याग्रह सभा बनाई गई, सत्याग्रह की प्रतिज्ञा का मसबिदा तैयार किया गया और सदस्यों ने वह प्रतिज्ञा की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरम्भ करने का निर्णय समाचार-पत्रों में अपने एक पत्र द्वारा व्यक्त किया, जिस में सत्याग्रह शपथ भी थी। वह शपथ इस प्रकार थी —

“अपने अन्तःकरण से यह अनुभव करने के कारण कि ये विधेयक स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध, और व्यक्ति के प्रारम्भिक अधिकारों के लिए घातक हैं हम यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि उनके कानून बनने पर और उनके रद्द न होने के समय तक हम उन कानूनों की ओर साथ ही उन

१ Punjab Unrest: Before and After, pages 2 and 3.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५५।

३ Gandhi: My Experiments with Truth, Vol. II. page 482.

सब कानूना की जो नियुक्त की जान वाली कमेटी उचित समय, सविनय अवज्ञा करण और हम फिर यह बूढ़ निश्चय करते हैं कि इस सपप न हम सत्य का पूर्ण रूप में अनुसरण करण और जीवन व्यक्ति अपना सम्पत्ति के प्रति हिंसा से दूर रहण।<sup>१</sup>

किन्तु गर-सरकारी सदस्या की चेतावनी की तरह सत्याग्रह-सभा के इस नियम का सरकार पर कोई प्रभाव नही हुआ और विधायक का सरकारी डाटा से १८ मार्च १९१९ को पारण हुआ और वह २१ मार्च को कानून बन गया। उस समय महात्मा गांधी भद्रास म थे। एक स्वप्न में उन्हें सत्याग्रह करण का विचार आया और दूसरे दिन प्रातः काठ श्री राजगोपालाचारी स जिनके यहाँ वे ठहरे हुए थे, उन्होंने अपन स्वप्न को बताया — पिछली रात मुन स्वप्न में यह विचार आया कि हम सारे देश से सावजनिक हडताल करण के लिए कहना चाहिए। सत्याग्रह-आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया है हमारा सपप पवित्र है और मुन यह उचित प्रतीत होता है कि उसका आरम्भ आत्म-शुद्धि के किसी कार्य से किया जाय। अतः सारे भारतवासी उस दिन अपना साम्राज्य छोड़कर उपवास और प्रार्थना करें ”<sup>२</sup>

श्री राजगोपालाचारी और अन्य व्यक्तिया न उस विचार का स्वागत किया और महात्मा गांधी न एक पत्र द्वारा उसे सवसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। ‘पहले तो हडताल के लिए ३० मार्च (१९१९) निर्दिष्ट की गई, पर बाद में तारीख बदल कर ६ अप्रैल कर दी गई।’ उस दिन (अर्थात् ६ अप्रैल को) सारे देश में, शहरो और गाँवा में सभी जगह शान्तिपूर्ण सफल हडताल हुई।<sup>३</sup>

किन्तु कुछ स्थान एस थे जहाँ हडताल की तारीख बदल जान का देर से पता लगा और इसलिए वहाँ पर ३० मार्च को भी हडताल हुई। इन स्थानों में दिल्ली नगर भी एक था और वहाँ पर ही विचाराधीन वय की दुःखद घटनाएँ सबसे पहले हुईं।

३० मार्च को दिल्लीवासिया न उपवास किया और हडताल की। हण्टर-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लोगो की एक भीड़ न रेल्व उपाहार-गृह बन्द करण की ज़िद की और वही स सगडा आरम्भ हुआ। रेल्व-मुलिस न हस्त-प्रणम किया और भीड़ में स दो आदमिया को गिरफ्तार कर लिया। इसल लोगो में प्राथ फल

१ Punjab Unrest Before and After, page 34

२ Gandhi My Experiments with Truth, Vol II, page 486

३ Gandhi My Experiments with Truth, Vol II, page 487

गया और उन्होंने तितर बितर होन से इन्कार कर दिया और साथ ही दोना आदमियों को छोड़ने की माँग की। पुलिस पर ईंटे भी फेंकी गई। अन्त में भीड़ पर गोली चलाई गई और उसे निकट के क्वीन्स गार्डन में खदेड़ दिया गया। इस पर भीड़ टाउन हाल के सामने जमा हो गई और वहाँ अधिकारियों ने फिर गोली चलाने की आवश्यकता अनुभव की। "इसके फलस्वरूप उस दिन मोलियों से मारे जाने वाले आदमियों की संख्या ८ हो गई। अस्पताल में लगभग एक दर्जन घायल व्यक्ति पहुँचे किन्तु उनकी वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा थी।" उसके बाद कोई शगडा नहीं हुआ और तीसरे पहर सार्वजनिक सभी शान्तिपूर्वक समाप्त हो गई। ६ अप्रैल की हड़ताल भी शान्तिपूर्ण रही। किन्तु मि. गांधी की गिरफ्तारी के कारण १० से लेकर १७ अप्रैल तक बराबर हड़ताल रही। पुलिस ने दुकानों की बलात् छुलवाने का प्रयत्न किया जिसके कारण विल्लीमाराम में १७ तारीख को शगडा हो गया "पुलिस की आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। लगभग अठारह आदमी घायल हुए जिनमें से बाद में दो मर गए।"<sup>१</sup>

३० मार्च की घटनाओं के बाद, दिल्ली के स्थानीय नेताओं ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाया। उन्होंने ६ अप्रैल की हड़ताल के बाद आने की स्वीकृति दी। अस्तु ७ अप्रैल की रात को वे बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बीच पंजाब के उप-गवर्नर और दिल्ली के चीफ कमिश्नर के परामर्श से भारत सरकार ने पंजाब और दिल्ली में मि. गांधी के प्रवेश पर रोक लगा देने का निश्चय किया और एक आज्ञा जारी की गई जिसमें उनसे बम्बई प्रेसीडेन्सी में ही रहने का निर्देश किया गया। पलवल स्टेशन पर उन्हें यह सरकारी आज्ञा-पत्र दिया गया जिसका पालन करने से उन्होंने इकार कर दिया। फलतः पलवल स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की अभिरक्षा में उन्हें बम्बई वापिस भेज दिया गया।

१० तारीख की सुबह को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की सूचना अहमदाबाद पहुँची, जहाँ उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था और जहाँ उनके प्रति लोगों में असाधारण श्रद्धा थी। उस समाचार से बड़ी उत्तेजना हुई। हड़ताल घोषित की गई। दो यूरोपियनों से सवारी छोड़ कर पैदल चलने के लिए कहा गया और उत्ती सम्बन्ध में शगडा हो गया किन्तु जिला-मजिस्ट्रेट मि. चैट फील्ड ने स्थिति को अपनी कुशलता से संभाल लिया। दूसरे दिन कुमारी अनसूया साराभाई की गिरफ्तारी के समाचार से लोगों का कोप और ज्यादा हो गया। मिल मजदूर आये से बाहर हो गए और उन्होंने आगजनों और हिंसा के कई काम किए। कई बार भीड़ों पर गोली

१ Disorder Inquiry (Hunter) Committee Report, page 3

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४।



चलानी पड़ी और १२ तारीख की सुबह को एक सैनिक घोषणा जारी करनी पड़ी। १३ तारीख को कुमारी साराभाई और महात्मा गांधी दोनों ही अहमदाबाद पहुँच गए, 'और उन्हें नगर में फिर से व्यवस्था स्थापित करने के काम में सहायता देने के लिए अनुमति दी गई। १४ को घोषणा वापिस ले ली गई।' मि गांधी ने एक बहुत बड़ी सभा में भाषण दिया, लोगों के हिंसापूर्ण कामों की निन्दा की और इनसे अपना काम करने के लिए जोर दिया। इस भाषण का वांछित प्रभाव हुआ और अहमदाबाद के झगड़े १४ अप्रैल को लगभग समाप्त हो गए।<sup>१</sup>

“सगडा के सिलसिले में.....उपद्रवियों में से २८ आदमी मारे गए और १२३ घायल हुए, यह संभव है उनकी संख्या अधिक हो।.....अहमदाबाद नगर में आठ जगह और निक्ट के अन्य स्थानों में १४ जगह तार काटे गए। अहमदाबाद में उपद्रवियों ने लगभग ९३ लाख रुपये की सम्पत्ति लूट की..... संभवतः इसका मुख्य कारण यह था कि मि गांधी और कुमारी साराभाई के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण उपद्रवी आपे से बाहर हो गए थे। उन लोगों को अपने बीच में स्वतन्त्र देख कर, साथ ही मि गांधी का भाषण सुनकर, उनके मस्तिष्क में से अव्यवस्था जारी रखने के विचार दूर हो गए।”<sup>२</sup>

१० अप्रैल की दोपहर तक पंजाब में कोई उपद्रव नहीं हुआ। रॉलिट-विधान के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में विरोधकर लाहौर और अमृतसर में सभाएँ हुई थी। ६ अप्रैल को सारे प्रान्त में सफल और शान्तिपूर्ण हड़ताल हुई। अमृतसर में ३० मार्च को भी। सारे प्रान्त में प्रबल असंतोष था और कुछ उत्तेजना भी थी। रॉलिट-ऐक्ट के विरुद्ध भावनाएँ जगी हुई थी, साथ ही राजनैतिक सुधारों और शिक्षित वर्गों के प्रति उप-नवर्नर के भाव के कारण प्रान्त में बड़ा भारी तीखापन था। किंतु कोई आतंककारी आन्दोलन नहीं था—उसे १९१६ में ही दबा दिया गया था। प्रान्त के सभी नेताओं का आन्दोलन के लिए शान्तिपूर्ण एवं बंध उपायों में विश्वास था। किंतु सर माइकेल की सरकार, प्रान्त में हर प्रकार के आन्दोलन और राजनैतिक जीवन का दमन करने पर तुली हुई थी। ७ अप्रैल १९१९ को सर माइकेल ने पंजाब विधान-परिषद् में, पंजाबियों की सराहना करते हुए, सार्वजनिक नेताओं को यह धमकी दी—“इस प्रान्त की सरकार का यह दृढ़ निश्चय है और वह निश्चय भविष्य में भी बना रहेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था जो मुझ बाल में

१. बम्बई ले जानर महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया; कुमारी साराभाई को गिरफ्तारी का समाचार मल्ल था।

२. The Disorders Enquiry Committee Report, page 13.

३. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १३.

सफलतापूर्वक कायम रखी गई थी वह शांति-काल म भंग नहीं होगी। इसीलिए भारत रक्षा एक्ट के अन्तगत लाहौर और अमृतसर के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कायबाही की गई है। रालेड एक्ट के विरुद्ध लाहौर और अमृतसर दोनों ही स्थानों में जो प्रदर्शन हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि अनभिन्न और सहज विश्वासों लोगों को किस प्रकार सरलता से बहकाया जा सकता है। जो लोग उनको बहाना बाले हैं उन पर एक विकट उत्तरदायित्व है जो लोम तक के स्थान पर अनभिज्ञता से अपील करते हैं उनकी भी एक दिन खबर ली जायगी।<sup>१</sup>

अगले कुछ दिनों की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि उक्त घमकी खोजनी नहीं थी।

<

अमृतसर में ३० मार्च और ६ अप्रैल की हड़तालों में पूरा शांति रही थी। दो स्थानीय नेताओं—डा सत्यपाल और डा किचलू—को भारत रक्षा एक्ट के अन्तगत मावजनिक सभाओं में बोलन से रोक दिया गया था तथापि हड़तालों में कोई भी उपद्रव नहीं हुआ था। ९ अप्रैल को रामनवमी थी उस दिन एक विराट जलूस निकाला गया जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित हुए। यह उसका भी शांतिपूर्ण रहा। हष्टर-कमेटी न लिखा है— यह निश्चित है कि उस दिन शांति रही और यूरोपियनों ने साथ कोई छड़ छाड़ नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर स्वयं भीड़ में फँस गया और बाद में उसने इलाहाबाद बक के बरामदे में से सारे जलूस का दखा। उसका कहना है कि साधारणतया लोगों का व्यवहार शिष्टतापूर्ण था। जलूस की प्रत्येक कार मेरे सामने रुकी और बड़ न गाड़ सेव दि किंग बजाया। उसी दिन सरकार ने डा सत्यपाल और डा किचलू के अमृतसर से निर्वासन की और उन्हें धर्मशाला नामक स्थान में नजरबंद रखने की आज्ञा जारी की। यह आज्ञा भारत रक्षा एक्ट के अन्तगत दी गई थी। दस तारीख को सुबह दस बजे उन्हें चुपचाप कार से धर्मशाला ले जाया गया और स्थानीय काम कारिणी अधिकारियों ने सिविल स्टेशन पर भीड़ न घुसने वन के उद्देश्य से सैनिक और पुलिस प्रबन्ध कर दिया। लगभग साढ़ ग्यारह बजे निर्वासन का समाचार सारे शहर में फैल गया। हड़ताल घोषित कर दी गई और दोनों नेताओं को छोड़ने की मांग करने के लिए लोग जलूस बना कर डिप्टी कमिश्नर के मकान की तरफ बढ़। हष्टर कमेटी के वचन के अनुसार भीड़ के पास लाठियाँ भेजी और कोई लड़न की चोख नहीं थी और उनमें रास्ते में यूरोपियनों के साथ कोई

छेड़छाड़ नहीं की।<sup>१</sup> रेल के फाटन के पास भीड़ को रोना गया और उसे शहर की तरफ बलात् लौटाया गया। इसी प्रयत्न में दो बार गोरी चलाई गई। भीड़ घुड़ और उग्र हो गई और उसने हत्या लूटमार और आगजनी शुरू कर दी। रास्ते में दो यूरोपियन—स्वी अथवा पुरुष—मिल उहे बुरी तरह पीटा गया। नरानल एंड एलायस बैंक<sup>२</sup> की इमारत में आग लगाई गई उसके यूरोपियन मैनेजर की हत्या की गई और बैंक के गोदामों को लूट लिया गया। टाउन हाउस और अन्य सार्वजनिक इमारतों में भी आग लगाई गई। तार काट गए और मिस् धारवड नामक एक ईसाई प्रचारिका को बुरी तरह पीटा गया और उस मरा हुआ समझ कर एक गली में छोड़ दिया गया जहाँ से बाद में कुछ हिन्दुओं ने उस अस्पताल पहुँचाया। तुरन्त ही शहर में फौजी टुकड़ियाँ भजी गईं और शाम तक भीड़ गायब हो गई। १० अप्रैल को सैनिका की गोली से मरे हुए लोगों की सत्या लगभग १० थी, घायलों की संख्या अधिक होगी।<sup>३</sup>

११ अप्रैल को, लोगों को मृत व्यक्तियों की दाह प्रिया करने की अनुमति दी गई। एक बहुत बड़ा जलूस निकाला गया और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। उसी शाम को जनरल डायर अमृतसर पहुँचा और उसने शहर की सैन्य-टुकड़ियों का संचालन अपने हाथों में ले लिया। १२ अप्रैल को बहुत-सी गिरफ्तारियाँ की गईं और एक घोषणा द्वारा सारी सभाएँ और भीड़ वर्जित कर दी गई। हण्टर-नमटों ने लिखा है — यह प्रकट नहीं होता है कि उस घोषणा के प्रकारान के लिए क्या व्यवस्था की गई। जिन स्थानों पर घोषणा (जो अंगरेजी में थी) पढ़ी गई, उनका नक्शा देखने से यह प्रत्यक्ष है कि शहर के बहुत से भागों में घोषणा नहीं पढ़ी गई।<sup>४</sup>

दूसरी ओर १२ अप्रैल की ही शाम को इस बात की सार्वजनिक सूचना दी गई थी कि १३ अप्रैल को शाम के साढ़े चार बजे जाटियावाला बाग में एक सार्वजनिक सभा होगी। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया किन्तु उसने सभा आरम्भ होने के कुछ ही दर बाद अपनी फौजी गाड़ियाँ और अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच कर बिना चेतावनी दिए हुए उस समय तक उन सैनिकों का गोली चलाने की आज्ञा दी जब तक कि उनकी गोलियाँ ही समाप्त

१ The Disorders Inquiry Committee Report, page 22

२ चार्टर्ड बैंक का अधिक धन नहीं पहुँची और उसने यूरोपियन मैनेजर और उपमैनेजर का पुत्रिन ने उन स्थानों में न निकाला, जहाँ वे छिप गए थे।

३ The Disorders Inquiry Committee Report, page 29

४ डायर रिपोर्ट पृष्ठ ३०

न हो जायें। सर क्लफ्टाइन् शिरोऊ न इम दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया है —

जिहोन जालियाँवाला बाग नहीं देखा है उनके लिए उस दृश्य की भयकरता का अनुमान करना बठिन होगा। किसी समय वह एक बाग था वित्तु आजकल वह एक खाली जगह है जहाँ अक्सर भेजे होते हैं अथवा सावजनिक सभाएँ होती हैं उसका विस्तार टुफालमर स्वायर के बराबर होगा। यह बाग चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है जिनके ऊपर चारों ओर के मकानों का पिछवाड़ा दिखाई देता है। मैं उसी सड़की गली से गया जिससे जनरल डायर अपना पचास सैनिक लेकर गया था। मैं उसी उठे हुई जमीन पर खड़ा हुआ जहाँ खड़े होकर उसमें बिना चेतावनी दिए उगभग सौ गज की दूरी से एक घनी भीड़ पर जो उस घरे के एक निचले भाग की ओर थी और जहाँ मंच से व्याख्यान दिए जा रहे थे गोली बरसान की आवाजें थीं। उसके अनुसार भीड़ में लगभग ६००० आदमी थे और लोगों के अनुसार जन समूह १०००० से अधिक था। ये सब लोग निहत्थ और बिल्कुल घिरे हुए थे। बरबराई हुई भीड़ नुरत फट पड़ी किंतु लगातार दस मिनट तक गोलियाँ बराबर बरसती रहीं—कुल १६५० बार किए गए—उन लोगों पर जो चूहों की तरह पिंजड़ में फस गए थे जो बाहर निकलने का निरर्थक प्रयत्न कर रहे थे और जो गोलियों की बीछार से बचने के लिए जमीन पर लट गये थे। जहाँ भीड़ घनी थी वहाँ गोलियाँ चलाने के लिए जनरल डायर ने व्यक्तिगत रूप से निश्चय किया। उसी की गंदाबली में निशान अच्छे थे। दस मिनट बाद जब गोलियाँ समाप्त हो गईं तो वह अपने सैनिकों के साथ उसी भाग से गौट गया था जिससे वह आया था। सरकारी आकड़ों के अनुसार जो कई महीनों बाद बताए गए जनरल डायर ने ३७९<sup>१</sup> आदमियों को जान से मार दिया था और लगभग २००<sup>१</sup> घायल आदमियों

१ कायस जाच कमटी ने लिखा है — मृत्यु सख्या के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अपने कयनानुसार २९ अगस्त (अर्थात् हत्याकाण्ड के चार महीने बाद) तक आकड़ों की छानबीन आरम्भ नहीं की। मि. धामसन ने उस समय कहा था कि २९० से अधिक व्यक्ति नहीं मरे थे। अब उहाँ ने वास्तविक छानबीन के आकड़ों को — अर्थात् ५०० की मृत्यु सख्या को — स्वीकार कर लिया है। ये आकड़ वास्तविक छानबीन पर आधारित हैं और मृत्यु सख्या इनसे कम किसी भी हालत में नहीं हो सकती। वास्तविक सत्या का कभी भी पता नहीं लग सकता किंतु वही सचधानी से जाच करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि लाख गिरधारी लाठ कड़ अनुमान—अर्थात् १००० की मृत्यु सख्या—किसी भी प्रकार से अतिरिक्त नहीं हो सकती है (रिपोर्ट का पृष्ठ ५७)। लाख गिरधारी अलग उस को अपनी जाखो में देखा था और गोलियाँ चलना बंद होने के

को जमीन पर पड़ा छोड़ दिया जिनके लिए (उसी की सम्भावनी के अनुसार) उसने रत्ती भर भी ध्यान देने को अपना कर्तव्य नहीं समझा।”<sup>१</sup>

सर वेंलेण्टाइन ने लिखा है — “यदि स्वयं जनरल डायर का हृष्टर-कमीशन के सामने दिया हुआ कर्तव्य न होता, तो सम्भवतः यह कहा जा सकता था कि सिविल सत्ता के अचानक लुप्त होने पर उसे अपने असंतुलित निर्णय से चारा ओर खून दिखाई दिया। किंतु उसी के कथन से यह पता लगता है कि अपने सैनिका के साथ जालियाँवाले बाग को जाते हुए उसने जान बूझ कर ऐसा निर्णय किया था और यदि सकरे रास्ते में उस अपनी मजीनगने पीछे छोड़ने को विवश न किया होता तो उसने और भी ज्यादा बड़ा हत्याकाण्ड किया होता। उसने बताया कि उसका उद्देश्य सारे पंजाब में आतंक जमा देना था।”<sup>२</sup>

घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचे थे।

१ लाला गिरधारी लाल पंजाब वाणिज्य मंडल के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने एक मकान में से जहाँ से बाग दिखाई देता था सारा हत्याकाण्ड देखा था। उनके विश्वसनीय, आँखों-देखे, विवरण को उद्धृत करना उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा — “मैंने मकड़ों लोगों को वहाँ मरते हुए देखा। उम दृश्य की सब से बुरी बात यह थी कि दरवाजे से भागने का प्रयत्न करनेवाले लोगों पर, निर्दोशता द्वारा गोली चलाई जा रही थी। चार या पाँच सक्ती जगहें ऐसी थी जहाँ से निकला जा सकता था। वहाँ पर गोलियाँ बस्तुतः बरस रही थी और बहुत से लोग भागने वाली भीड़ के पैरों तले कुचले गए उनमें से कुछ मर भी गए। खून बुरी तरह बह रहा था। जो लोग जमीन पर लेटे हुए थे वे भी गोलियों से नहीं बचे। मरे हुए अथवा घायल लोगों को देखने के लिये अधिकारियों ने कोई प्रबन्ध नहीं किया मैंने बहुत से घायलों को पानी दिया और उस समय जो कुछ सहायता सम्भव थी वह मैंने की। मैंने चारों तरफ का चक्कर लगाया और सब को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। वही-वही पर लोगों के ढेर बन गए थे। मृत शरीर बड़ी उम्र के लोगों के थे और उनमें बच्चे भी थे। कुछ लोगों की खोपड़ियाँ फट गई थी, कुछ की आँखें बाहर निकल आई थी बहुत-से लोगों की नाक, छाती अथवा हाथ-पैर चूर-चूर हो गए थे मेरे विचार से उस समय बाग में १००० से अधिक मृत शरीर थे बहुत-से लोग मरे हुए शरीरों को भी नहीं उठा सके इस डर में कि वहाँ ८ बजे बाद दुबारा गोली न चलाई जाय।”

pages 56-57 of The Congress Inquiry Committee Report में अनूदित।

२. Chirol : India . Old and New, pages 177-78.

९

पंजाब के अन्य स्थानों में १० और १५ अप्रैल के बीच जो दुर्घटनाएँ हुई, उनका विस्तृत विवरण देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। हण्टर-बमीशन की रिपोर्ट में और अन्यत्र उनका विस्तृत वर्णन किया गया है।<sup>१</sup> यहाँ केवल लाहौर बसूर और गुजरावाला की दुःखद घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा कर देना ही पर्याप्त होगा।

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिलने पर १० अप्रैल को लाहौर में हड़ताल की गई। एक जलूस बनाया गया और उसमें शोक प्रकट करने की दृष्टि से एक कागज झंडा साथ लिया गया। अनारकली से भाल को और जान के समय<sup>२</sup> उस जलूस को रोका गया और उससे तितर-बितर हो जान को कहा गया। कहा यह जाता है कि लोग बहुत उत्तेजित थे, उन्होंने तितर बितर होने से इकार कर दिया और उस समय उन पर गोली चलानी पड़ी। १४ अप्रैल को बहा के लोकप्रिय नेताओं को—मंडित रामभजन दास साग हरकिशनलाल और लाला बुली चन्द को—निर्वासित कर दिया गया। फलतः १० अप्रैल से १७ अप्रैल तक हड़ताल रही। १८ अप्रैल को फौजी कानून के अन्तर्गत दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने के लिए विवश किया गया। लाहौर में भीड़ ने हिंसा के कोई काम नहीं किए।

बसूर में उसकी उल्टी बात हुई। वहाँ भीड़ उग्र हो गई और उसने दो यूरोपियनों को मार डाला सार्वजनिक इमारतों तथा रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई और संचार-साधनों को तोड़-फोड़ की। ११ अप्रैल को हड़ताल आरम्भ हुई और दूसरे दिन भी जारी रही। बसूर में कसाइया और चमड़ा का काम करनेवालों का एक उपद्रवी दल है,<sup>३</sup> उसने १२ अप्रैल की सुबह को स्वतन्त्रता दिवस का जलूस निकालने का आयोजन किया। यह जलूस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा और

१ Disorders Enquiry Committee Report के पृष्ठ ३६ से ७३ तक देखिए। इसके अतिरिक्त Pearey Mohan The Imaginary Rebellion and How it was Suppressed देखिए पृष्ठ ५५ से ९४ तक। साथ ही Congress Punjab Inquiry Committee Report, 1919-20 के पृष्ठ ४५ से १५५ तक भी देखिए।

२ The Disorders Inquiry Committee Report, page 39

३ Quoted from the Punjab Government Report by Pearey Mohan The Imaginary Rebellion and How it was Suppressed, page 69

अधिकाधिक उत्तेजित होता गया। पंजाब सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है — “इस समय तक केवल उग्र प्रदर्शन का ही उद्देश्य था। स्टेशन पहुँचने पर भीड़ ने काफी क्षति पहुँचाई, दरवाजे तोड़े, खिड़कियों पर पत्थर फेंके वित्तु भीड़ स्टेशन के अन्दर नहीं गई और उसने पटरियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। कुछ देर बाद भीड़ लौटी वित्तु अपने नेताओं के भड़काने पर वह रुक गई और उसने बहुत बड़े परिमाण में तोड़-फोड़ का काम आरम्भ किया। उसने एक तेल के गोदाम में आग लगाई, रेल के सिग्नल को नुकसान पहुँचाया, तार काटे, मेजों और कुर्सियों को ताड़ और टिकट के दफ्तर में लूटमार की।”<sup>१</sup> उस समय तक कुछ स्थानीय नेता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए समझाया। इसी बीच स्टेशन पर एक गाड़ी आई जिसमें कुछ यूरोपीय यात्री भी थे। भीड़ ने यूरोपियनों पर आक्रमण किया। उनमें से अधिकतर लोग बच गए— कुछ लोगों ने उन्हें रेलगाड़ी से उतार कर बिन्ही भारतीयों के यहाँ शरण लेने के लिए समझा दिया था। वित्तु दो यूरोपियनों ने गाड़ी से उतरने से इकार कर दिया और उन्होंने अपने रिवाल्वरों से गोलियाँ चला कर अपनी रक्षा की। उन पर पत्थर फेंके गए। बाद में भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें धमकाने लगे छोड़ दिया गया क्योंकि उसी समय पुलिस आ गई और उसने गोलियाँ चला कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

गुजरावाला में भी जबदस्त हमला हुआ। वहाँ के रेलवे स्टेशन के दोनों सिरों पर दो पुल थे, १४ अप्रैल को उन पुलों पर बड़ी हुई गाय और बड़ा हुआ मूअर लटका हुआ देख कर लोगों में बड़ी उत्तेजना हुई। लोगों का यह विश्वास था कि पुलिस ने हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा कराने के लिए गाय को (साध ही मूअर को भी) बाट कर लटका दिया था।<sup>२</sup> भीड़ ने पुलों में आग लगा दी। बाची पुल पर पुलिस ने गोली चलाई और कुछ लोग घायल हो गए। इस पर भीड़ क्रोध में पागल हो गई और उसने सार्वजनिक इमारतों और संचार-साधना को ताड़-फोड़ की। उसने तहसील, डाक बंगला, जिला न्यायालय, चर्च और रेलवे स्टेशन में आग लगा दी। लगभग ३ बजे शाम को लाहौर से हवाई जहाज आए और उन्होंने शहर पर बम गिराए। बाद में फौजी टुकड़ियाँ भी आ गईं। हण्टर-कमिशन ने लिखा है — “गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर वनेल ओ’ ब्रायन ने हमें बताया कि जहाँ तक पता लग सका है, १४ अप्रैल का पुलिस की गोलियाँ ने कुल ११ व्यक्ति मारे गए और २७ घायल हुए।”<sup>३</sup>

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०

२. The Disorders Inquiry Committee Report, page 48.

३. The Disorders Inquiry Committee Report, page 58.

१०

१५ और २४ अप्रैल (१९१९) के बीच में पंजाब के पाँच जिलों में मार्शल लॉ (फौजी कानून) की घोषणा की गई। यह फौजी कानून ११ जून तक लागू रहा, किंतु रेलवे मार्गों पर तथा स्टेशनों के क्षेत्रों को इस कानून से २५ अगस्त का छुटकारा मिला।

फौजी कानून घोषित करने और उसे इतने समय तक लागू रखने अथवा उसे इतनी शक्ति से व्यवहार में लाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में हटर कमेटी में मतभेद था। किंतु सभी भाग्यवासियों ने एवमत्त स उस ढंग की निन्दा की, जिससे १९१९ में पंजाब की स्थिति को समझा गया था और जिससे उस प्रान्त में फौजी कानून की व्यवहार में लाया गया था। फौजी कानून के कुछ प्रशासकों ने असाधारण निर्दयता और बबरता से काम लिया था। इन लोगों की बबरता के व्यक्तिगत कार्यों का वर्णन करना न तो संभव है और न उससे कुछ लाभ ही है। किंतु इस सम्बन्ध में तीन प्रतिनिधिपूर्ण सम्मतियाँ व्यक्त करना उपयुक्त होगा— एक सम्मति सर बैलेण्डाइन विंगेल की है जिन्हें भारतीय आकांक्षाओं का विरोधी माना जाता है, दूसरी सम्मति भारत-मन्त्री मि माटगु की है और तीसरी सम्मति एक भारतीय मॉडरेट राजनैतिक सर सिवास्वामी एयर की है जो १९१९ के मॉडरेट सम्मेलन के अध्यक्ष थे और जो सत्याग्रह कार्यक्रम के विरोधी थे। उन सम्मतियों के अन्तर्गत १९१९ में पंजाब में फौजी कानून के प्रशासन का सही चित्र मिल जाता है। सर बैलेण्डाइन न लिखा है—

तब, जलियाँवाला बाग के दो दिन बाद पंजाब में फौजी कानून की विधिवत् घोषणा की गई। यद्यपि इसके बाद जलियाँवाला बाग जैसे बाग नहीं हुए किंतु विद्रोह का सबूत (चाहे आरम्भ में वह बिल्कुल सच्चा ही क्यों न रहा हो), समाप्त हो जाने पर भी, तुच्छ एवं प्रतिकारात्मक कृत्यों की नीति बराबर कार्यान्वित की गई जिस के फलस्वरूप जातीय तीखापन बढ़ना स्वाभाविक था। यह सच है कि सर माइकेल ओ' डायर ने जनरल डायर की 'रेग कर चलन की बीभत्स आज्ञा' का विरोध किया था<sup>१</sup> और वह आज्ञा शीघ्र ही रद्द भी कर दी गई थी। किंतु और बहुत-सी 'आज्ञाएँ' थी जो रद्द नहीं की गई थी। लोगों में अविशिष्ट और सामूहिक रूप से कोड़े लगाए जाते थे<sup>२</sup> और विभिन्न प्रकार के 'मनमाने' बड़

१ १० अप्रैल को अमृतसर में मिस डेरबुड पर जो आघात किया गया था, उसकी चर्चा की जा चुकी है। १९ अप्रैल को जनरल डायर ने यह आज्ञा दी कि जिस गली में मिस डेरबुड गिरी थी उसमें से जानेवाले लोग हाथों और पैरों के बल रंग कर निकलें। यह आज्ञा २६ अप्रैल को रद्द कर दी गई थी।

२ हटर कमेटी की 'अल्पसंख्यक' रिपोर्ट के अनुसार २५८ लोगों पर साधारण



दिए जाते थे<sup>१</sup>—किसी व्यक्तिगत विद्रोही को दंड देने के लिए नहीं बल्कि लोगों को आतंकित करने के लिए और उनका अपमान करने के लिए। फौजी कानून के अन्तर्गत न्यायिक व्यवस्था<sup>२</sup> का कोई स्थान नहीं रहा था।<sup>३</sup>

हण्टर कमेट्री की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारत मंत्री को भी विवश होकर अपने राजपत्र में यह लिखना पड़ा — एक ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में इस निष्कर्ष पर न पहुँचना असंभव है कि लाइड हण्टर की कमेट्री के बहुमत ने अपने विचारों को उस रूप में व्यक्त नहीं किया जैसा कि तथ्यों की दृष्टि से केवल उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक था। कमेट्री ने जिन घटनाओं का अपनी रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है उनको दाहराना अनावश्यक है। साथ ही उन आनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत अधिकारियों के दोषों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु सम्राट-सरकार इन आनाओं और दंडों की तीव्र निन्दा करती है। कमेट्री ने जो उदाहरण दिए हैं उनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पञ्जाब में फौजी कानून के प्रशासन में साधारणतया तो नहीं किन्तु दुर्भाग्य से बहुत हद तक काफी एक ऐसी जातीय भावना ने काम किया है कि जिसका उद्देश्य भारतीय समाज का अपमान करना और उसे बर्णन पहुँचाना था। बहुत से अवसरों पर अन्याय किया गया और औचित्य तथा मानवता की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया।<sup>४</sup>

सन् १९१९ के अखिर भारतीय माइनेट सम्मेलन में सर गिवास्वामी ने समापति के पद से अपने व्याख्यान में कहा — हण्टर कमेट्री के समक्ष प्रमुख

रूप से कांड उठाए—कुछ विषय उदाहरण नीचे। साधारणतया यह डाँटा अपनाया गया था कि उस आदमी के कपड़े उतार कर उस एक चौखट से बांध दिया जाता था। और तब कोड़े मारे जाते थे। प्रत्येक आदमी को ५ से ३० तब कोड़े मारे गए। (Page 162 Disorders Inquiry Committee Report से अनूदित)

१ ७८९ व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया और जिनपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया—उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ १६६

२ १०८ व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया और ३६५ व्यक्तियों का दण्ड निवानन-दंड दिया गया। बाद में सरकार ने इन निषयाओं को दाहराना और तब कब २३ व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया और दाँतों का दण्ड निवानन दंड। इन आँकड़ों में फौजी न्यायालया के प्रशासन का पता चला है।

३ Chutrol India Old and New, page 179

४ Punjab Unrest Before and After, page 159

यूरोपियन छात्रियों के वस्त्रों में जो तथ्य प्रकट होते हैं उनका और ध्यान देना उचित होगा। जर्मियावाले बाघ में भीड़ का निरंतर बितर हाग का अवसर नहीं दिया गया और सकुड़ा निहत्थे लोगों का कर-जाम किया गया। मंगानगना का गार्गिया में जो सकुड़ा जादमी घायल हो गए थे जनरल डाक्टर ने उनकी दगा पर ध्यान देना अपना कर्तव्य नहीं समझा। गंगा में खुल जाय कांड गंगाए गए हाजिरा के नाम पर हथियार विद्याधिया का प्रति दिन १६ मात्र पदल चलन का बिदग किया गया ५०० विद्याधिया और प्राफमरा को गिरफ्तार करके नजरबन्द रखा गया ५० वर्ष का आयु के स्कू के बच्चा का थड का संगमा दन के लिए परड में बुलाया गया फौजा कानूना के विनापना को मरति रखन का विम्वारी सकान मार्किता पर डाला गए एक बरान के जलूम पर कांड बरनाए गए डाक को छात्र कर दखा गया एम गंगा को जिन्हान राजमता का सवाएँ का था अकारण गिरफ्तार किया गया और नजरबन्द रखा गया इस्लामिया स्कू के ६ मने में बड लडका में इमलिए कोड लगाए गए कि वे स्कू के ठक ध और बड गडने ध गिरफ्तार जादमिया को बंद करने के लिए खुग विजडा बनवाया गया विविध प्रकार के दंड दिए गए राग कर चरन का आना दी गद वन-स लोगों को एक नाथ रस्सी में बांध कर १५ घंटे तक एक खुनटक में रखा गया हवाई जहाज का उपयोग किया गया संपत्ति बर्त और नष्ट का गइ हिंदू-मुस्लिम एकन के विरोध में नोष प्रदर्शन करने के लिए हिंदूबा और मुसमाना का जाग में हथकडिया पहनाइ गद भारतीयों के घरा का बिजली काट दा गई और नष्ट बंद कर दिए गए भारतीयों के घरा में बिजली के पल निकाल कर यूरोपियना के उपयोग के लिए दिए गए और एभी ही वन-सी बात और हुइ जिन से पजाब में आतंक छ गया।<sup>१</sup> यहाँ तक कि श्रीमती बीमट ने भी जिन्हान अमृतसर की भांडा के काम की उग्र गंधा में निंदा की थी और जिन्हान अपयान्त प्रमाण के आधार पर पजाब की नीडा के काम का नातिकारिया के सिर मडा था २१ न्मिम्बर १९१९ को यह गिखना आवश्यक समझा — हण्डर-कमटी के सामन मनिक अधिकारिया के वयाता को पठकर मुक्त अत्यन्त दुःख हुआ है। उन्होंने अपन मुह से जो कुछ स्वीकार किया है बर्जियम में जमानवासिया ने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया।<sup>२</sup>

१ The Indian Annual Register 1920, page 397

२ उन्होंने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का लिखा था — तार काटना पटरिया उखाड़ना स्टेशन में आग लगाना वका पर हमला करना जर्मिया का आजाद करना — ये सब सत्याग्रहिया के काम नहीं हैं और न ये उपद्रविया के ही काम हैं — बल्कि उनमें नातिकारिया का हाथ है।

३ Disorders Inquiry Committee Report, page 125

जब फौजी बालून और रोक के दूर होन पर पंजाब की नीपण घटनाओं के समाचार भारत के अन्य भागों में पहुँचे तो सर माइकल ओ' डायर के शासन और लाड चेम्सफोर्ड की सरकार के विरुद्ध ज़ारदार आवाज़ उठाई गई। राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों में इस बात की भाव की गई कि लाड चेम्सफोर्ड का वापिस बुलाया जाय और सर माइकल ओ' डायर पर तथा माराल ला के अत्याचारपूर्ण शासन के लिए उत्तरदायी अन्य लोग पर अभियोग चलाया जाय। वहाँ की घटनाओं ने जनता को श्रुद्ध और दुःखी कर दिया था। सारे देश में भयंकर असंतोष था। माडरेटों ने भी पंजाब की आतंकवादी नाति और राजनैतिक सुधारों की ओर प्रतिप्रियावादी भाव के कारण सरकार की तीखी आलोचना की। सरकार के विरुद्ध केवल राष्ट्रवादी पत्रों में ही नहीं बल्कि माडरेट पत्रों में भी इस बात की आलोचना की गई कि आरम्भ में सुधार-योजना की जो रूप रेखा थी वह बाद में काफी दबा दी गई थी। १

किन्तु राष्ट्रीय विराध को एक गम्भीर पत्र द्वारा, भारत के सर्वोत्तम कवि श्री रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने व्यक्त किया, उन्होंने इस पत्र द्वारा 'सर' की उपाधि का परित्याग कर दिया—

पंजाब में हमारे भाइयों ने जो अपमान और कष्ट सहें हैं उनके समाचार, राधक प्रतिबन्धा की दीवारों में से रिस कर भारत के प्रत्येक भाग में पहुँच गए हैं और उनके कारण हमारे देशवासियों के हृदयों में जा व्यापक रोष-वदना हुई है, उसकी हमारे शासकों ने उपेक्षा की है। सन्वतः उन्होंने अपने-आप को इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने (अपनी दृष्टि से) शासिता का हितकर पाठ पढ़ाया है। यह जानकर कि हमारे निबन्धन निरपेक्ष हुए हैं और प्रतिकार का मनावेग हमारी उस सरकार के, जो अपनी नैतिक शक्ति और नैतिक परम्पराओं का अनुरूप उदारता प्रदर्शित कर सकती थी, उत्कृष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण को आवृत्त किए हुए हैं, मैं जो कम-से-कम कर सकता हूँ वह यह है कि मैं सारे परिणामों की ओर उनकी जातिम का अपने ऊपर लूँ और अपने एन बराडा देगवासियों के, जो आतंक से हतबुद्धि और मूक हो गए हैं विराध का व्यक्त करूँ।

अब वह समय आ गया है कि सम्मान के प्रतीक, अपमान के अनगढ़ सुदन में, हमारी निलज्जता को सुस्पष्ट कर दें और मैं स्वयं विनिष्ट होकर न विहीन होकर अपने उन देशवासियों के बराबर खड़ा होना चाहता हूँ, जिनका उनकी

कथित तुच्छता के कारण ऐसे अवमान सहन पड़ते हूँ जो किसी भी मानव-गरीर के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन्हीं कारणों ने मुझे श्रीमान् से उचित आदर के साथ यह कहने को विवश किया है कि मुझे 'सर' की उपाधि से छुटकारा दे दिया जाय।<sup>१</sup>

महान्वित रवाइनाथ द्वारा उपाधि के परित्याग का अग्रजों के मस्तिष्क पर गम्भीर प्रभाव पड़ा और उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने माटफोर्ड मुधारा की योजना का सजीव आग बढाया। इस बीच पंडित मदनमोहन मालवीय और उनके सहयोगियों के अथवा प्रयत्न के फलस्वरूप अधिकांशिक तथ्या पर प्रकाश पड़ा। पंडित मालवीय ने अप्रैल १९१९ की पंजाब की दुःखद घटनाओं के सम्बन्ध में ९२ सूक्ष्म और अन्तर्भेदी प्रश्न<sup>२</sup> तैयार किए और भारतीय विधान परिषद के वायवाहक को सूचना दी कि तु गवर्नर-जनरल ने उनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। वाइसरॉय ने परिषद में अपने आद्य भाषण में एक जांच कमिटी नियुक्त करने की घोषणा की थी जिसमें अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। मालवीयजी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कमिटी के स्थान पर एक राजकीय कमिशन नियुक्त करने की मांग की क्योंकि कमिटी को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देनी थी जो स्वयं इस मामले में फंसी हुई थी। किंतु पंडित मालवीय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और गेड हण्टर की अध्यक्षता में जांच कमिटी नियुक्त कर दी गई। इस कमिटी के सदस्य थे—मि जस्टिस रजिन मि राइस मजर जनरल मेजर जाज बरो सर चिमनलाल सितारवाद और साहबजादा मुल्तान अहमद। बाद में पंडित जगत नारायण और मि टामस स्मिथ को भी इस कमिटी में सम्मिलित कर लिया गया। कमिटी ने अक्टूबर १९१९ में अपना काम आरम्भ किया और मार्च १९२० में अपनी रिपोर्ट दी। वायसी और अन्य बहुत से सरकारी व्यक्तियों ने हण्टर-कमिटी के काम में सहयोग नहीं दिया क्योंकि उसका अभिप्रेत क्षेत्र अत्यंत संकुचित था और उसने अतिरिक्त पंजाब के नेताओं में जो जंग में बंद थे परामर्श करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

किंतु अभी कमिटी का काम आरम्भ ही नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने उन अधिकारियों को जिनके व्यवहार के संबंध में हण्टर-कमिटी को जांच करनी थी अभियोग्यता में बचाने के लिए भारतीय विधान-परिषद् में एक विधेयक<sup>३</sup>

१ The Indian Annual Register, 1920 pages 50-51

२ इन प्रश्नों के लिए देखिए— Punjab Unrest Before and After Appendix pages 1-23

३ १९१९ के इस एक्ट के ६ संश्लिष्ट विभाग थे। विभाग नं० २ के अनुसार व्यवस्था पुनः स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किसी काम के संबंध में

प्रस्तुत किया। गैर-सरकारी सदस्या न सुझाव दिया कि हण्टर-जमटी की नियुक्ति का कारण, उस विधेयक को स्वीकृत कर दिया जाय। १० मदनमाहन मालवीय ने उस अवसर पर एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया जो लगभग पाँच घंटे में पूरा हुआ। इस व्याख्यान में उन्होंने सारे घटनाओं का वर्णन किया, सारे विधिक और वैधानिक स्थिति की विवेचना की और विधेयक का स्वीकृत करने के सहायन का समयन किया। किन्तु परिषद् के भीतर और बाहर सावजनिक विरोध के हाव हुए भी, सरकार ने सरकारी सदस्या का वादा से विधेयक का पारण कर दिया।

दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने वातावरण को शान्त करने का उद्देश्य से पार्लियामेंट में सुधार-विधेयक का जल्दी से पारण कराया और उस पर मग्राट् की स्वीकृति ली जिसकी राजकीय उद्घोषणा दिसम्बर १०१० के वाक्य (अभूतसर) अधिवेशन के अवसर पर जारी की गई।

राजकीय उद्घोषण में सुधारों की घोषणा की गई, महाराज और मेल के लिए अपील की गई और वाइसरॉय को राजनैतिक अपराधियों के प्रति कृपाभाव दिखाने के लिए निर्देश किया गया। उसमें कहा गया — 'दम समय भरी यह उत्कट इच्छा है कि मेरी प्रजा और मेरी सरकार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के बीच जो कुछ तीखापन बच रहा हो वह पूरी तरह दूर कर दिया जाय।—एक नया युग आरम्भ हो रहा है। मेरी प्रजा के लोग और मेरे अधिकारीगण, सभी यह निश्चय कर लें कि ये एक सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिल कर काम करेंगे। अतः मैं वाइसरॉय को निर्देश देता हूँ कि वह मेरे नाम से और मेरी ओर से राजनैतिक अपराधियों के

---

किसी सिविल अथवा सैनिक अधिकारी का दंड नहीं दिया जा सकता था। विभाग न० ३ के अनुसार सरकार के वायबाह का प्रमाण पत्र यह निश्चय करने के लिए पर्याप्त था कि कोई काम सरकार के अधिकारों की आज्ञा न व्यवस्था स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किया गया था। विभाग न० ४ में उन व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें फौजा कानून के अन्तर्गत दंड दिया गया था। विभाग न० ५ में एक लाना की व्यवस्था की क्षतिपूर्ति की गई थी जिसका सम्पत्ति में निम्न अधिकारियों द्वारा काम में लाई गई थी। See pages 159-160 of "Punjab Unrest Before and After" for the Act——Also pages 161 to 174 for speech of the Home Member explaining the provisions and the Government Position.